#### DUE DATE SLIP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

DUE DTATE SIGNATURE

KOTA (Rai )

Students can retain library books only for two weeks at the most BORROWER'S

No.		
		1
		1
	l	}
		1
		1
		1
	1	
	1	1
		1
	i	1
		1

# भारतीय शासन ऋौर राजनीति

हाँ० जे० ए० एल० नोहा, एन० ए, एल एल० बी०, पी एव० डी० (विक्रम)

भारतीय वासन श्रौर राजनीति

Published by Madhya Pradesh Hindi Granth Academy under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and literature in regional languages at the University level, of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhs.

## भारतीय शासन ऋौर राजनीति

डॉंठ जेठ एठ एलठ नोहा, एस० ए०, एल एल० बी०, पी एच० डी० विभागापक्ष एव प्राप्यायक, राजनीति विभाग, इन्दौर विशिच्यन महाविद्यालय, इन्दौर, स० प्र०



ग्पूदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 🛭 मोपाल

## भारतीय शासन भौर राजनीति

#### प्रकासक

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्य ग्रकादमी, ६७, मालवीयनगर, भोपाल

0

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ सकादमी,

त्रकम संस्करण ११७३

.

भूल्य पुस्तकालय सस्करण १२ रुपये ४० पैसे साधारण सस्करण १० रुपये ४० पैसे

> मुद्रक पर्वेतीय मुद्रणालय

१८ राय रामचरन दास रोड, इलाहाबाद-

## प्रस्तावना

वस्तुत मारतीय सविधान एव उसने प्रयोगात्मक पक्ष से सर्वान्यत प्रत्य है। मारतीय जनतत्र में बालिंग मात्र नो मतायिकार प्राप्त है। वैचारिक प्रमिष्यिकि की स्वतत्रता के साथ मिलनर इस निर्वाचनाधिकार ने प्रतेन राजनीतिक पाटियों को श्रीतत्वत्व म ला दिया है और प्रत्येक दल को सविधान की सीमा के भीतर नायं करने की पूरी स्वतत्वता है। हमारा सविधान स्वत्य विरोधी पदा को न केवल सहन करता है, प्रपितु बेसे शासन का सजग प्रहरी मी मानता है। इस दृष्टि से विभिन्न राजनीतिक विश्वासों भीर वादों के बीच चतने वाले मारतीय सासन

डा॰ जे॰ ए॰ एल॰ नोहा द्वारा लिखित "मारतीय शासन मौर राजनीति"

विभिन्न राजनीतिक विश्वासी और बादों के बीच चलने वाले भारतीय शासन के कई मनोरफ्क पहुंच हैं। डॉ॰ नोहां की पुस्तक इन सब पर प्रवाश डालती हैं। भारतीय सिवधान इंग्लैंड थ्रीर धमेरिका के सविधानों ने श्रेष्ट धसो की लेनर बना है। ये सविधान वई सी बयीं से परीक्षित और प्रयुक्त होते साथे हैं। इंग्लैंड का सविधान तो विश्व का प्राचीनतम सविधान माना जाता है। फ्रैंव

इस्तष्क का सावपान ता विश्व का प्राचानतम सावपान माना जाता है। अने साधों को इस बात पर झामित है कि मारतीय सिवपान कि हि साथों के सिवपानों का पिछलागे बनकर क्यों रहे। कमी कभी तो यह विरोध काफी प्रमुद्ध वर्ग की भीर से झाता है। हमारे सविवान से विषायिका, पातिका भीर स्वाधिव वर्ति के बीच स बाता है। हमारे सविवान के विषायिका, पातिका भीर स्वाधिव वर्ति के बीच स बुतन बनाये रखने का प्रयत्न विचा गया है। इसम कोई किसी से पटकर नहीं है। कि सुकारों के सोच की से पटकर नहीं है। कि सुकारों के साथों की से पटकर नहीं है। कि सुकारों की से पटकर नहीं स्वाधिवान की साथों की स्वाधिवान की स्वाधिवान की साथों की साथों की साथ साथों साथों की साथों की साथों की साथ साथों साथों

राष्ट्रीयकरण धौर मुल्की कानून के न्यायिक फैसली एव नदी योजना विवादों ने इस

बात को और भी जंबागर कर दिया है। जनमत के दबाव के कारण भी संविधान में संबोधन हुए हैं भीर स्वामानिक है, कि उससे सब पद्ध स तुष्ट। नहों नोई सविधान स्वय पूर्ण नहीं होता भीर न कोई वासन प्रणाली ही सबवा निर्दाण हो सबती हैं। फिर भी भारतीय वासन अर्थात् संविधान और उसके उद्देश्य निम्मतम विवादा-स्वद प्रचलों को खुते हैं। देश के प्रायः सभी राजनीतिक स्क जनत्म में विश्वास रखते हैं। पुष्पाला निर्वाचन के साथदश्य हैं जिनसे इन हुनों की शक्ति और प्रमान

रच्य अपना का खूत है। स्वा के प्राया क्या राजनातिक दल जनतन में निस्पात रखते हैं। पचसाला निर्वाचन वे मापदण्ड हैं जिनसे इन दलों की शक्ति भी रामात का मूल्याकन होता रहता है। जनतत्रीय प्रणाली के प्रति समित्त होने के कारण हो इस देश को स्वतत्रता के बाद स्थायों एवं सुदृढ सरकार मिल सकी है।

हो इस देग को स्वतत्रता के बाद स्थायो एव सुदृढ सरकार मिल सकी है। शायद भारत हो एक-पात्र विकासमान देश है जिसमे बान्तिकारी राजनीतिक प<sup>रि</sup>वतन नहीं हुए ग्रीर न कभी कोई ऐसा श्रान्दोलन हुग्रा, जिससे जनतत्र की भीव हिली हो, इस देश की परम्परा, विधान-निर्मालाकों की सूम-दूम, सावत स्वानेवालों को व्यावहारिक दसता, बनवा की सहिष्णता और प्राविध्यता स्वानेवालों के व्यावहारिक दसता, बनवा की सहिष्णता और प्राविध्यता स्वानेवालं के स्वानेवालं स्

ना नरवाल नहां बने पढ़ों ।

मार्योग सविधान, केवल जासको तथा राजनी ित्रों ने मार्गदर्शन के लिये ही

नहीं, बेल्कि मारल के प्रलेक नावरिक के विमिन्न-सरिकारों को दृष्टि ने सावस्थक

हैं। प्रस्तुत माय्यय में, जिसका सीर्पक भारतीय गासन कीर राजनी ति है, मारल
के सविधान के सर्गत सर कथा राज्य सहराये के स्वच्य सर्थन, घौर कारों,
के स्वचिधान के सर्गत सर कथा राज्य सहराये के स्वच्य सर्थन, घौर कारों,
के स्वचिधान के सर्गत सर्थ का स्वच्य स्वच्य क्षेत्र के स्वच्य स्वच्य,
के प्रतिच्या देशों की सुमेश्य, जाविश्व में मूल सर्पक्य मारतीय मारत एव राजकीर्ति की मुद्धियों की स्वाच्या करते हुए, उनको दूर करने के लिए रक्तारमक
सुमान दिने गई हैं।

तथापि, यह स्मरण रक्षना धावनक होवा वि मृततः भारतीय सविनान के दायरे में ही, मिलया में, भारतः मर्गत कर तक्ता है और विवन ने बटै तथा समुद्रामादी राष्ट्रों में प्रमुख्य विकार स्थान करा करता है। यदि राष्ट्रीय मर्गादी में रक्षावटें माती है, तो जैसा डॉ॰ दी॰ धार॰ घावेददर ने सविमान-निर्माण के समय कहा था, एक्षवा वारण यह नहीं होगा कि सविमान हुए है परणु यह वि मानव इट है।

हुत सब बाठों के अकास ने स्विट हम बर्तमान नारतीय सासन-मर्दान सीर राजनीति का प्रस्पतन करें हो सनेकों मनोरंजक तस्य सासने साकेंगे। कीं नौहां के सपनी कृति में इस तस बाठों पर सुक्ते सन के विचार किया है। उनकी यह इति विचारियातपीन सुप्यतन के क्षेत्र में सहत्वपूर्ण गोयदान कें।

y. c. > 9.20

(डॉ॰ प्रभुदयालु ग्रानिहोत्री) संबाधक मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी

## विषयानुक्रमणिका

प्रस्तावन	7						
मारतीय	सविघान	ৰা	निर्माण	तया	उसके	मूल	सिद्धान्त
नागरिक	ता						

٤.

5

नागरिकों के मूल ग्रविकार

राज्य नीति-निर्देशक तस्व भारत में संसदात्मक प्रणाली

भारत में संघवाद शीर संसदीय प्रजातंत्र

७ सघीय कार्यपालिका :---न-राप्टपति.

ल-सधीय मन्नी परिचद ८ सधीय ससद

सधीय कार्यपालिका एवं ससद के सवय भारतीय ससद मे प्रतिपक्ष दल

११. भारतीय सर्वोच्च न्यायासय १२ राज्य-सरकार

र--राज्यपाल.

स--राज्य-मशी-परिपद.

१३. राज्य-विधान मण्डल

सदमं प्रन्यो, पत्रो, पत्रिकाग्रो की तालिका

१६ लोक सेवा ग्रायोग

१४. राज्य न्यायपालिका १५. सम तया राज्य-सवध

... 352

300

300 370

333

83

२०

ž o

193

e¥

् ० ७

288

१३७

१४३

\$ E o

288

283

२६७

335

305

## भारतीय सविधान का निर्माण तथा उसके मूल सिद्धान्त

स्वतन भारत वे सविधान वा निर्माण-वार्य 'विधीनेट मिणा-योजाा' वे धर्गतंगत स्वतनता प्राप्ति वे नी माह पूर्व प्रारम्य हो गया था। सविधान तमा वे सदस्यो वा चुनाल, १६४६ म प्रान्तीय विधानन्तमाधी द्वारा धानुपातिव प्रतिनिधित्य यद्वति के जापार पर विचा गया। इस सविधान निर्मानी समा में पुत्त सदस्य-सह्या २६६ थी, जिसम वाग्रेस वे २०४, मुस्सिमलीग वे ७३ भीर १= स्वतन्न प्रतिनिधि थे।

सविधान समा ना प्रथम प्रधिवेशन ६ दिसम्बर, १६४६ नो बा॰ सच्चिदान्द सिन्हा नी प्रस्वायी प्रध्यक्षता में सम्बर्ध हुसा । तदुवरान्त ११ विसम्बर, १६४६ ने प्रधिवेशन में इस सविधान निर्माणी समा में स्वायी प्रध्यक्ष में पर स्वर्धाय बा॰ रिजेन्द्र प्रसाद प्रासीन हुए। २२ जनवरी, १६४७ वो सविधान समा में प्रपता चर्चच प्रस्ताव (Objectives Resolution) धारित निर्धा । यह प्रस्ताव प्रजास्ताव निर्माणार्थ पर जाहरूसालजी नेहर द्वारा प्रस्तुत चिंदा गया । इसमें सविधान निर्माणार्थ पौच सम्बन्धित उद्देश्य मानुसार इस प्रवार के —

१—मारत म स्वतंत्र एव सार्वभीम गणराज्य की स्थापना सौर झपना सविधान निर्माण करना ।

२ — भारतीय सघ एव सघ भी इनाईयो ( राज्यो ) मे समस्त सार्यमीम सत्ता भा स्रोत जनता होगी।

३—भारत ने समस्त निवासियो को (1) सामाजिन, प्राप्तिन तथा राजनीतिन न्याय (11) पद, प्रवसर एव नानून ने समक्ष समानता तथा (111) विचार, सावण, प्रिमिय्यक्ति भीर विश्वास राने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

४—प्रत्पसरयना, पिछडे वर्गो तथा अनुसूचित जातियो मे हितो मी रक्षा मे सिए व्यवस्था नरना। गया था, तिन्तु इसमें भारत के सभी राजनीतिक दलो, वर्गी तथा विभिन्न हितो ना पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। भारतीय रियासतो ने भी प्रतिनिधि इसम सम्मितित विषे गय थे। इसने प्रतिरिक्त, चूँनि वेचल भाग्रेस ही एन राष्ट्रीय दल था, भीर नाग्रेस नो सविधान सभा ने २६६ सदस्यों में से स्पष्ट बहुमत (२०१ स्थान) प्राप्त हुआ था, यह वहा जा सनता है नि नाग्रेस हारा सविधान-सभा म राष्ट्रीय हितों ना व्याप्त प्रतिनिधित्व था। प्रतिएव, सविधान-सभा ने जो सविधान पारित निया, उसनो एक लोगतात्रिन सविधान माना जा सनता है।

य—यदि सर्विधान की अस्तावना के पहले और धन्तिम वाग्यों के उपयुक्त धर्मों को जोड़ा जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेका कि स्वय सर्विधान की अस्तायना में इस विषय पर बल दिया गया है कि सर्विधान वास्तव में जनतात्रिक है। प्रस्तान्त्रका के पहले वाक्य का उपयुक्त हिस्सा है — 'हम आरत के सोग', भीर धन्तिम वाक्य का उपयुक्त हिस्सा है, — 'इस सर्विधान को स्वीवृत्त, निमित एव प्रात्मापित करते हैं, यह न दोने हिस्सों की साथ-साथ बोड़ा जाये तो पूरा वाक्य इस प्रकार होगा '—

'हम मारत के लोग इस सविधान को स्वीवृत, निर्मित एस धारमाधित करते हैं। ' दूसरे बारदों में, मारतीय-सविधान मारतीय जनता का, जनता के लिए, जनता (जनता के प्रतिनिधियों) बारा निर्मित सविधान है। यह मारतीय जनता की सार्वमीनिक्ता को प्रतिविध्यान करता की सार्वमीनिक्ता को प्रतिविध्यान करता की सारम की एक से मी लगभग ऐसे ही बच्चे ना प्रयोग किया यथा है। ममेरिका के सविधान के प्रताबना के सारम की के सविधान के प्रताबना के सारम की के सविधान के प्रताबना के सारम में वे सविधान के प्रताबना के सारम में वे सविधान के प्रताबना के सारम में वे सवद हम प्रवाद है:—

'हम अमरीना ने सोग', एव प्रन्त मे 'इस अमरीनन सविधान नो निर्दिष्ट एव स्वापित नरते हैं'। अमरीनी सविधान नी प्रस्तावना ने इन दोनो मागो नो जोडा जाये तो बानव यह होगा :—

'हम ग्रमरीना ने लोग, इस ग्रमरीनी-सविधान नो निविष्ट एव स्थापित न रते हैं। प्रत स्पष्ट रूप से यह ग्रमरीनी-सविधान ने लोनतात्रिन स्वरूप का सूचन है।

इसने प्रतिरिक्त, भारतीय-संविधान द्वारा नागरिनो को वयस्क मताधिकार दिया गया है, भौर प्रत्येक नागरिन को ससद या निसी राज्य-विधान सम्रा ने छिए उम्मीदवार के रूप में, चुनाव लडने का भी प्रधिकार है।

सर्विचान के प्रध्याय तीन में बारत के नागरिनों के सात मूल धीमनारों का उठलेस है। ये प्रधिवार है—(१) स्थानता का धीमनार, (२) स्वतन्नता ना प्रधि-गार, (३) शोषण ने विरुद्ध धीमनार, (४) धानिन स्वतन्ता का ध्रविकार, (४) सम्पति ना प्रधिकार, (६) सास्ट्रीतन तथा शैद्धिक प्रधिवार और (७) सर्वे- धानिक उपचारो का अधिकार । इन अधिकारो से भारत में राजनीतिक लोकतंत्र ना प्राप्तामन प्राप्त है।

सविपान ने बध्याय चार में विभिन्न बार्षिक सिद्धान्तों ना उल्लेख है, जिननो राज्य-नीति निर्देशक तत्वी की सजा दी गयी है, क्योंकि भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ग्रपने कार्यों में इन सिद्धान्तों के मार्ग दर्शन में बलना धावश्यक है। इनका उद्देश्य मारत में व्यक्षित लोकतत्र की स्थापना करना है, जिसमें किसी की मागरिक ने साथ सामाजिक तथा व्याधिक बन्याय नहीं होगा ।

ससेंप में, सुविधान न केवल स्वम सोक्ताविक है निन्तु इसका उद्देश्य मार्ग में सोवतत्र को नीव को शक्तिशाली करना है।

प्रस्तानना में इस विषय पर बन दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य पारत में एक सार्वभीय लोकत्त्रीय गणराज्य की स्थापना करना है। 'सार्व-भीम' रुप्द का प्रयोग किया जाना इस बान का द्योतक है कि नारत के ग्रान्तरिक तथा बैद्रशिक मामलो म भारत सरकार सार्वभीम तथा स्वतंत्र है। 'सोनतन' राष्ट्र का प्रयोग इस बाद का छोतक है कि मार्खाय-सविधान के धन्तर्गत सार्वमीमिकता अनुता में निष्टित है। आरनीय अनुताका, दयस्क मनाविकार के आधार पर अपनी इच्हानुसार सरकार-निर्माण करने का स्वतंत्र अधिकार है, जो आन्तरिक तथा बाह्य दोनो मामलो मे पुरानचा सार्वमीम तथा स्वतत्र होयी ।

'गणतव' मान्य का उपयोग इस विषय पर प्रकाश ठासवा है, कि दी प्रकार की सोक्तकीय व्यवस्थायो-कशान्यत शीक्तक तथा शीक्तकीय गण्नक, में से मार्ताय-मविधान के बन्तर्गत लोकतत्रीय गणनत्र को धारनाया गया है।

बंगानगर लोगतन के बन्दर्गंद राष्ट्राध्यक्ष किसी दिश्यिट क्या का होता है, वो प्राना पर बंगानुषत सिदान के बाबार पर वाप्त करता है, किन्तु राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह केवल नाममात्र का शामक होता है। उदाहरण स्वरूप इंगलैंग्ड में सबैधानिक-धाननव मा सीक्जानिक-साबनन है, क्योंकि वहां के साष्ट्राध्यक्ष ( सम्राट या मझाज्ञां ) को अपना पद वशानुस्त प्राप्त होता है।

सोतन्त्रीय-रणतत्र में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जनना द्वारा प्रापक्ष या भप्रत्यक्ष रूप में विचा दाता है, अमाँत बाह्यानिक राज्य में राष्ट्राध्यक्ष को भपना पद बनता द्वारा उसके निवांचन के एउ स्वरूप शाफा होना है। एदाहरण स्वरूप समरीका एवं भारत म राष्ट्राज्यक्ष का निर्वाचन जनता करती है। सतएवं भारत वया मनरीका दोना बणवात्रिक-राज्य है।

भारतीय-मंत्रियान की अन्तावना स तका संविधान के अध्यास तीन से धर्म-निरदेश राज्य के सिद्धान्त पर सम दक्ष रूप से दल दिया क्या है। प्रस्तादना में भारत ने समन्त नागरिको की विक्तित प्रकार की स्वत्य साम्यो एए प्रकार साला राजा है।

पर्म-निर्पास राज्य के सन्दर्भ में, प्रस्तायना म उल्वेपिन नामरिय में विश्वाम, पर्म तथा उपासना सम्बन्धी स्वतयना वो त्यान से रमना भावयपन है। इसी प्रकार, मियान के प्रव्याय तीन अनुन्देद २५, २६, २६, २६ और २४ मिननीत मारत स समी व्यक्तिया नो वामिन स्वत्यता प्रदत्त नी है। इसी प्रवार सामानता ने मूल प्रविवार से सत्य में साविधान में यह प्राव्यान निया गया है कि राज्य नागिरियों में मध्य पर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी भाषार पर मेदसाव नहीं करेगा। पर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी भाषार पर मेदसाव नहीं करेगा। पर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वा इनमें से किसी मी नागिरिक को सावंजितन पूजा ने स्थान ने उपयोग से नहीं रोवा जायेगा। गैंडिणिक तथा सावंजितन पूजा ने स्थान ने उपयोग से नहीं रोवा जायेगा। गैंडिणिक तथा साव्हित प्रविकार के धन्तर्गत प्रयोग से नहीं रोवा जायेगा। गैंडिणिक तथा साव्हित प्रविकार के धन्तर्गत प्रयोग से नहीं रोवा जायेगा। गैंडिणिक तथा साव्हित प्रविकार के धन्तर्गत प्रयोग से नहीं रोवा जायेगा। गैंडिणिक तथा साव्हित प्रविकार के धन्तर्गत प्रयोग से नहीं रोवा जायेगा। यह साव्याम स्थानिक स्थानित स्थानित वा धिकार है। इसके धितिराज धनलसरको से धपनी गाया के सुरक्षित रसने का तथा स्थानिक सम्यास्था के स्थापित करने वा प्रविवार है।

बस्तुन प्रस्तावना ध्रीर सविधान के ध्रष्याय तीन में, सारत में निवास करने बाले समस्त व्यक्तियों को, जो धामिन स्वतन्नता वा धिवनार प्राप्त है, उसको मारत में धर्म निरिक्ष राज्य का ठोस धामार माना जा सकता है, वयोकि धर्मनिरफेश राज्य की सजा उस राज्य को दी जा सकती है, जिससे सभी व्यक्तियों का समान रूप से धामिन स्वतन्नता का धिधवार उपलब्द है, धर्यान्, राज्य की वृद्धि मसभी घर्म समान हैं और सार्वजनिक धामयों का सवालन दिसी विशिद्ध धर्म के सिद्यान्तानुमार न वर लोकनानिक सिद्धानता पर किया जाये।

मारतीय सर्विधान की प्रस्तावना में तथा सिंवधान में घटवास चार में, जिसमें विमिन्न राज्य-नीति-निर्देशक तत्वों ना उल्लेख हैं, खोर-गटवाणनारी राज्य वा विचार दृष्टिगोचर होता है। दूसरे घट्टो में, मारतीय विवास के ग्र-तर्गन लोग कराजनारी राज्य ने सिद्धाल की मानवता दी गई। मानत-कीवन के शासाजिक, प्राधिक, राजनीतिक, एव घामिक पढ़ा महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य ने बरिवरत के सामाजिक, प्राधिक, राजनीतिक, एव घामिक पढ़ा महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य ने बरिवरत के सविगीण विकास हेतु उसको जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण रहलुयों के लिए मुद्धि- पाएँ उपनन्ध होनी चाहिए। लोक-नद्याणगारी राज्य का प्राथमिक उद्देश हैं में मानव-जीवन के इन सहत्वपूर्ण पहलुयों से सविष्ठ समस्त मुद्धिवायों के लिए प्राधिक राज्य के इन सहत्वपूर्ण पहलुयों से सविष्ठ समस्त मुद्धिवायों के लिए प्राधिक राज्य होते की स्वर्थ मानविष्ठ के इन सहत्वपूर्ण पहलुयों से सविष्ठ समस्त मुद्धिवायों के लिए प्राधिक राज्य हो सवे।

मारतीय-सविधान नी प्रस्तावना में समस्त नायरिको नो सामाजिन, राजनीतिन, तथा धार्मिक न्याय ना धारवासन दिया या है। मारत ने नागरिको नो जीवन ने तिमान थोनों में न्याय का धारवासन दिया गया है। जागरिको को जीवन ने विमान क्षेत्रों में न्याय उपलब्ध नरी के लिए सविधान में विशिष्ट सापनो

भारतीय जासन भीर राजनीति

का उल्लेख है। सामाजिक न्याय का व्ययं है—समी नायरिको को सामाजिक क्षेत्र में समान महिनार प्राप्त हो।

(१) सामाजिक न्याय का बास्वासन, जो सर्विधान की प्रस्तावना द्वारा दिया गया है, नागरिको ने समानता ने मूल अधिनार पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नानून के द्वारा समान सरक्षण का प्रधिकार प्रदत्त किया गया है। इसके चुनिरिक्त, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वश, जाति, सिंग, जन्म स्यान प्रथवा इनमें से विसी भी धाधार पर मेदमान नहीं करेगा। इसी प्रकार हिसी भी नागरिक को केवल धर्म, वज्ञ, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, भपवा इनमें से क्सी एक बाधार पर, (क) दुवानो, सार्वजनिक मोजनालयो, होटलो, बौर सार्वजनिक मनोरजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जायेगा: (स) पूर्ण मा भाशिक मामार पर राज्यनिधि हारा बने हुए या जनता के लिए बनवाये गये कुथो, तालाबो, स्नानघाटो, सडको तथा सार्वजनिक स्थानी के उपयोग करने से नहीं रोका जायेगा । समानता के प्रधिकार के धन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को राज्य के धर्मान किसी

भी पद पर नियुक्त किये जाने के लिए समान श्रवसर प्राप्त होंगे भीर किसी भी नागरिक के साथ धर्म, बन्न, जाति, लिय, उत्पत्ति या जन्म स्थान प्रयवा इनमे हैं। किसी भी कारण से भेटभाव नहीं किया जा सकता है । समानता के प्रधिकार के अन्तर्गत सामाजिक न्याय उपलब्ध करने के लिए यह भी

प्रावधान किया गया है कि चत्पस्यना का धन्त कर दिया गया है धीर जो ध्यक्ति प्रस्पायना से उत्पन्न विभी वयोग्यता की लागू करता है, वह दण्ट का पात्र होगा । (२) राजनीतिक न्याय का आये है, सभी नागरिको को राजनीतिक क्षेत्र में

समान मधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय का मान्यासन प्रस्तावना म दिया ग्रहा है; इसके व्यावहारिक स्वरप मुख्यत हो बाभारो पर बवतस्वित है। ये साधार हैं—

(न) नागरिको के विभिन्न मूल अधिकार, विशेषकर, स्वतंत्रना, तथा सर्वेप्रानिक जपकारों के चयिकार चौत

(स) प्रत्येक भारत के शागरिक को दयस्क मनाधिकार के सिद्धान्तानुसार

भत देने के मधिकार। संशेष में सारत के प्रत्येक नायरिक को भ्रयने विचारों की

प्रसिव्यक्ति करन, सगटन बनाना । भारतीय प्रदश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने तथा प्रथनी पमन्द के

प्रत्यामी के लिए मन दने की स्वनवना है।

(३) माधिर न्याय का बर्व है, कि भाषिक क्षेत्र म सभी नागरिकों को समान मधिकार तथा भवसर प्राप्त हा। भारतीय नागरिको को को मार्थिक न्याय का माश्वासन सविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, उसके जियान्वयन हेन सविधान

में तीन भाषार है।

- (क) समानता दे अधिकार के आ तर्गत प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधीन पद प्राप्त करने हेतु समान अधिकार प्राप्त है।
- (स) स्वतंत्रता के प्रधिकार के धन्तगत प्रत्येव नागरिक को किसी भी अवसाय, वृत्ति ब्यापार तथा घ वा करने की स्वतंत्रता है।
- (ग) सदिवान के प्रत्याय चार म नितपय राज्य नीति निर्देशन तत्वा का उद्देश्य देश म प्रत्यक नागरिव को श्रायिक न्याय प्रदस्त करना है। उदाहरण स्वरूप य

राज्य नीति निर्देशन तस्य इस प्रकार हैं --१-समस्त नागरिका, पुरयो तथा स्त्रियो नो अपनी पर्याप्त जीविना सर्जन

करने का प्रधिकार है, २-समाज के भौतिक साधनो का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार वितरित

हो जिससे सामाय रूप से जनहित समय हो, ३-देश की फ्राधिक व्यवस्था का समालन इस प्रकार न हो, जिससे घन का

के द्वीय करण होते हुए सामान्य हित को हानि पहुँचे, ४-पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हा,

५--प्रमिनो, (पुरव एव स्पी) और कम आयु वे वालको ने स्वास्प्य सथा का कोषण न हो और नागरिको को अपनी आर्थिक आवस्यक्तामा को पूरा

सबित का शोधण न ही और नागरियों को अपनी शाधिक शावस्थवतामा मो पूरा करने के लिए उनकी आधु तथा सबिन के दुष्टिकोण से अनुप्युक्त व्यवसायों म प्रवेश होने के लिये बाध्य न होना पड़े,

६-बचपन एव युवाबस्था का शोपण न हो,

७-राज्य श्रम एव प्रमृति सहायता से सबिधत शर्ती की मानवीय स्वरूप प्रदत्त

करने के लिए प्रावधान वरोगा, द-राज्य अपनी आधिव क्षमता के दाबरे के नावरिको के लिए नौकरी, शिक्षा,

एव वृद्धावस्या, वीमारी एव वेरोजवारी की स्थिति में सावजनिक सहायता करेगा, ६-राज्य कानून वा शायिक सगठन द्वारा समस्त श्रीमंत्रों को (कृपि उद्योग,

स्थापक क्षेत्र वा आयक स्थापक द्वारा समस्य आयम क्षा (हाव उद्याग, या ग्रंप कार्यों से संप्रधित) उपयुक्त वार्ये, जीविका, एव वार्यों की शतों ने लिए प्रावधान नरेगा, जिससे जीवन का उत्तम स्तर स्थापित हो।

१०-राज्य न्यु उद्योगो को प्रोत्साहित करेगा।

११-राज्य विशेष रूप से पिछड़े वर्गी तथा धनुसूचित जातियों ने शैक्षणिक तथा शाधिक हिनों ना सरक्षण नरेगा।

जपर्मुक राज्य-नीति निर्देशन तत्वो को सविधान में स्थान इसी उद्देश्य से दिया गया है जिससे भागरिको को भ्राधिक न्याय उपलब्ध हो सके। ये ही तत्व भ्राधिक न्याय के भ्राधार हैं।

(४) राज्य-नीति निर्देशक तस्यो का महत्व भारतीय सविधान मे दिसम्बर, १६७१ में २४ वें संशोधन से और अधिन बढ गया है। सन्नोधन के दूसरे माग मे

भारतीय शासन धीर राजनीति

बहु प्राच्चान निया गया है नि बदि विशो कानून में यह निल्ला है कि उसरा दरेश निनो राज्य-तीनि निरंबक तत्व ना क्रियान्य न रता है और वर्षि उस नानून का मध्ये निनी पून प्रिकार से हैं, जो जन कानून को मध्ये नहीं छहाया जा सनता है। मिर इस प्रनार के नानून का जहेंका साधान्य हिनों के दुरिटनोधा साधान्य न्याय जनत प करना होया जी सातव में यह एक प्रथितीक्ष न राम माना योगी। सनेय में, सविस्तत की प्रस्तावना में, सविधान के इस मूल तिद्वान्त ना

कलेल है कि मारत एक लोक कत्याववारी राज्य होगा जिसमें प्रत्येक नागरित को सामाजित, मार्थिक एव राजनीतिक त्याय उपलब्ध होगा ।

(१) प्रलावना से संस्थितन के एक सन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त का उल्लेख है।
वह यह है कि हमते राज्येय एकत पर तत प्रवान किया गया है। मार्था, में
स्थादि की विकितना के होते हुए भी भारत एक राज्य है। इस सदमें में, प्रस्तावना का महाव हस्तिए प्रतिक हो जाता है कि हसने उन वो विशेष मार्थार पर बक

का महत्व सहातेष्य झांजक हो जाता है कि इसम जन दा विजय पापार पर बन दिया गया है, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एनता बृढ होती है! सर्वेत्रपम, अलावना में स्थिति हो जिल्हा तथा महत्व पर बन दिया परा है। स्थाति को, लोकतन नी एक महत्वपूर्ण दशाई मानते हुए, राष्ट्रीय एनता का एक महत्वपूर्ण साध्यार माना है। पाप्टीय स्वामिमान की माबना ने जामृति, स्थानि के स्वामिमान की माबना से वाधिन है। परस्य प्रान्ति के स्वामिमान की माबना पाज्य एक समाय में, उसके महत्व की स्वीमार करने पर

निर्भर है। यदि राज्य तथा समाज म व्यक्ति का उसकी उतिन प्रतिष्ठा तथा

न ताला र न व्यं वयुत्व या साहाह वा भावना प्रकासन करणा, जिसस राष्ट्रीय एक्ता दृढ होंगी। इन दो मार्गाय एक्ता यर सर्विषान निर्मानामा ने राष्ट्रीय एक्ना को दृढ बनाने

इन दो प्रापारो पर सर्विपान निर्मानामा ने राष्ट्रीय एकना को दृह बनाने का प्राक्तासन दिया है। उपर्युक्त पाँच सिद्धान्तों के प्रतिरिक्त जिन पर सर्विपान की प्रस्तावना मे

सर्वप्रयम, सविधान ने अनुच्छेद १ ने अनुसार भारत एन सम ( सूनियन ) है। भारतीय-सविदान में सथवाद ना सिद्धान्त अधनाथा गया है, वयोधि इसम राज्य नीतीनो भ्रावश्यनताएँ निहित है, जो ये हैं १-विस्तित सविधान, १-सधीय तथा राज्य सरकारों के मध्य शनिवधों ना विभावन, २-मध और राज्य सरकारों में मध्य सविन विभाजन, सविधान में उल्लेनित तीन सूचियों (ध-यथ मूची, व-राज्य सुधी और सन्तम्बतीं मूची) ने आधार पर चिया मधा है।

सचीय मूची में ६७ विषय है, जिन पर सय सरवार वा क्षेत्राधियार है। राज्य मूची में ६६ विषय है, जिन पर, साधारणतया राज्य सरवारों वा क्षेत्राधियार है। समतवीं सूची में ४० विषय हैं, जिन पर सय तथा राज्य सरवारों वा कि निर्माण में लिए समववीं क्षियार प्राप्त है, विन्तु यदि इस सूची में उल्लेखित किसी विषय पर सचीय भीर राज्य वास्तुन में सपर्प है तो सच वानुन में हो मान्यना दी जायेगी। अतल्य यह स्वष्ट है कि सचीय सरवार में राज्य सरवारों की प्रदेशा प्रमित्र चिन्तानों प्राप्त है। इसके पितरियन, वितयप, विजेष पिरिवर्स तियों में सचीय सरवार को सामार की समीय क्षेत्रा प्रमाण की स्वर्ण प्रमाण की स्वर्ण की सामार है। अति है। इसके पितरियन, वितयप सूची से सवियत हैं, प्राप्त हो आती है। इतका उल्लेख सन्य ध्वाया में निया गया है। प्रतः समीय विवेषताओं ने होने हुए सो मारतीय सर्वियान में एवारवसर प्रवृत्तियों निहित हैं। परवेतु मारत वा सर्वियान मुख्यत सचीय सिद्धान्त पर प्रापारित है।

द्वितीय, सररार ने स्वरूप में दृष्टिशीण से भारतीय सविधान ने भारतर्गत सवस्तार पढ़ित मो भरनाया गवा है। ससदात्मन पढ़ित में नार्यपालिना ने दो भरार होते है, नाममात्र भी नार्यपालिना नो दो भरार होते है, नाममात्र भी नार्यपालिना नो स्वी भरतर में, तथा वास्ति नार्यपालिना जो भरी भरूत के रूप में होती है। मसी भरूत भारति सामूहिन रूप से सबद के निचले सदन ने प्रति उत्तरदावी होना ससदात्मन पढ़ित शा भूत सिद्धान्त है। भारतीय-सिवान के अनुच्छेद ७८ उपवन्य (३) म इस सिद्धान्त नो मान्यता यो गई है। सब के सनान राज्यों के मत्री मण्डल भी अनुच्छेद १६४ (४) के अनुवार सामूहिन रूप से राज्य विधान-समा ने प्रति उत्तरदायी है। अतः यह स्वरूप है कि मारतीय-सिवान के अन्वर्यंत ससदात्मन थढ़ित नो अपनायग्या है।

तृतीय, सविपान के सशोधन के दृष्टिकोण से मारतीय-सविधान ना स्वरूप कुछ मात्रा मे नमनीय है भीर कुछ मात्रा मे नठोर। मारतीय सविधान के विभिन्न प्रावपानों में सबीधन के दृष्टिकोण से उन्हें तीन मागी में विभाजित निया जा सकता है। प्रतिष्ट माण में उन्होंसित सविधान के धावधानों ने सबीधन के तिए एक पृथक सबीधन प्रणाली है। सविधान के ये तीन माग निम्ना-नुसार हैं.—

(क) प्रदम् श्रेणी म सविधान के जो प्रावधान हैं, उनको ससद साधारण बहुमत से विधि निर्माण प्रक्रियानुसार संशीयन कर सकता है। सर्विधान के इन प्रावधानों के दिपय हैं—राष्ट्रपति की पूर्वीनुमति से ससद कानून द्वारा नये राज्यो का निर्माण नर सकती है, सब ने किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है; सब के निसी राज्य के क्षेत्र मानमी या बद्धि कर सकती है, एवं किसी भी संघ राज्य का नाम परिवर्तिन कर सकती है। नामरिकता सबधी प्रावधानों में भी ससद की संशोजन करने का एकाधिकार है। यदि संघ के किसी राज्य में उच्च सदन है निष्तु एसकी बावस्थकता नहीं है तो राज्य की विधान-समा के बनुरोध पर ससद सविधान में बावश्यक सहोयन कर सकती है। बतएव उपर्युक्त विषयो पर सविधान में सरलता से सशोजन विया जा सकता है।

80

(ख) दिनीय थेणी में सविधान के कतियय विधिष्ट प्रावयान हैं, जो बास्तव में सम एव राज्यों, दोना से सद्रधित हैं। इनके समोयनों के लिए समोयन विधेयन को दो चरणा का पार करना होता है। सर्वप्रयम, संशोधन विषेपक की संसद के क्सी मी सदन म प्रन्तुन किया जा नक्ता है। ससद के प्रत्येक सदन में विषेत्रक को सदन की कुल सरमा के बहुमत तथा स्वस्थित व मतदान में हिस्सा लेनेवाले सदस्यों के दो निहाई बट्टमन से पारित किया जाता भावस्पर है।

द्विनीय, मसद द्वारा उपयुक्त प्रक्षियानुसार अव विधेयक पारित हो जाता है तो वह दसरे चरण में प्रवेश करना है, जिसमें उतन मनोधन विधेयक की सब के राज्यों म में कम से कम आये राज्या के विजान-मण्डला द्वारा स्वीवृति मिलना चाहिये । तन्त्रस्वात् राष्ट्रपनि की सहमति से सविधान म बाबश्यक संशोदन लाग्न होगा । मविपान संशोधन की यह प्रतिया सविधान के ८न विभिन्न प्रावधानों के लिए पाषश्यन है, जो निम्नाहित विषया स सब्धित है।

१--राष्ट्रपनि वा निवाचन (धनुन्धेद ५४) २---राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणासी (धनुन्धेद ४४)

१-सप नी बादपालिका प्रक्ति की सीमा (ग्रन्चेट ७३)

४—सप व राज्या की कार्यपालिका शक्ति की मीमा (धनुच्छेद १६२)

१-नन्द्र-प्रशामिन क्षेत्रा न लिए उच्च न्यायास्य (यनुच्छेद २४१) ६—मधीय न्यायपालिका ।

अ-मध के विभिन्न राज्यों में उस्त स्वायासय **।** 

६—सप एव राज्या के व्यवस्थापन सवती प्रावधान (सातको धनुमूची मे सप्र, राज्य एवं समुदर्शि सच्चिती।

६—समद में साम्यो का धनिनिध्यत ।

१०—मविरान के मधोरन की प्रक्रिया, को बनुक्टेड २६८ में निहित है।

भारत के सविधान ने उपयुंक्त प्रावधानों ना संघोधन करने की प्रव्रिया जटिल है जिसके फलस्वरूप इन प्रावधानों को कठोर माना जा सकता है।

(ग) तृतीय श्रेणी में सिवचान के वे समस्त प्रावधान रसे जा सनते हैं जो प्रथम से श्रेणियों में मही हैं। इननी सामिद्य करने के लिए सबद में किसी सदन में सामोधन के लिए वियोवक को प्रस्तुत किया जा सनता है। ससद के प्रत्येन सदन में वियोवक को सदन की जुन सदस्य सरवा के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की पारित किया जाना प्रावध्यक है। तत्यक्वात, राष्ट्रपति की सहमति मिसने पर वियोवक पारित माना जावेगा, श्रीर सविधान में प्रावध्यक सभीवन लागू होगा। यह प्रत्रिया वीडी जटिल है वर्गीक सह सामारण विधि-निर्माण प्रक्रिया से मिस है।

सक्षेप में, सविधान के विभिन्न प्रावधानों में सक्षीधन के सन्दर्भ में यह क्यन उचित है कि मारत का सविधान कुछ मात्रा में नमनीय है, तथा कुछ मात्रा में कठोर है।

चतुर्यं, प्रारत ना सविधान लिखित होने के साथ-साथ देव ना सर्वोच्च नानृन है। प्रमरीकी सविधान ने सद्वा प्रारत्योग्ध सविधान ने सद्वा प्रारत्योग्ध सविधान ने प्रत नानृत प्रारा प्राथारण नानृतों ने प्रिप्त नात्र ते सिद्धान्त के सन्दर्भ में, देव ना सर्वोच्च या प्रत नानृत माना या है। प्रमरीकी सिद्धान्त में अपूर्वेद्ध ६ के सन्दर्यंत सविधान ने देवा ने सर्वोच्च नानृत नी सत्ता दो पई है, विन्तु भारतीय सविधान में ऐसा कोई विधिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि प्रारतीय सविधान में नागित के प्रत अपिकारो एव सप्याद को मान्यता देने के पलस्वक्य सविधान करते देवा ना मूल कानृत (सर्वोच्च नानृत) हो जाता है, जिसके सरक्षण ना दाधिरल न्यायपालिका के बन्यो पर है। प्राय प्रथम में भागे विस्तृत प्रकाश काता गया है।

मारतीय सिवधान नी प्रस्तावना एव सिवधान के अन्य प्रावधानों के अध्ययनोपरान्त हम सिवधान के अधीलिबित उल्लेखनीय सिद्धान्तों ना आसास होता है .--

१—मारन के सविधान वा स्वरूप लोच तत्रतात्मक है, बयोचि न केवल इसका निर्माण जनतात्रिक पद्मितनुसार विया गया है, ख्रिपतु इसके खाधारभूत सिद्धान्त भी जनतात्रिक है।

र-भारत के सविधान के ब्रन्तर्गत भारत नो एन सार्धभौम लोकतशीथ गण-राज्य के रूप में ब्रागीकृत निया गया है।

रे सर्विधान के श्रन्तगंत एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है।

४—नारतीय सविधान लोन-नत्याणनारी राज्य के सिद्धान्तो पर आधारित है। ५—नारतीय सविधान द्वारा राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त को मान्यता दो गई है।

भारतीय शासन धौर राजनीति 23

६-मारतीय-सविवान में सघवाद को मान्यता देने के साथ-साथ कतिपय एकारमक प्रवृतियों को भी स्थान दिया गया है। ७-- मारतीय-सविधान के धन्तर्यंत संधीय एवं विभिन्न राज्य-मरकारें, सस-

दारमक पद्धति के सिद्धान्त पर ग्राघारित हैं।

 मारत के सिवधान में नमनीय एवं कठोर खशों का समावेश है। मारत का सविवान निवित्त होने के साथ-भाय देश का मूल या सर्वोच्य

कानुन है।

## नागरिकता

१६४७ मे मानत के दो सार्वमीय देशों से विमाजित होने के कारण, मारत तथा पाकिस्तान में प्रविक वहीं सह्या में नागरिकों का देशातर हुमा । प्रतिव मारतीय सविधान निर्माताओं को भारतीय नागरिकता नो पिरिमाया को निर्मारित करने में कुछ कडिनाइयों का सामना करना पढ़ा । उदाहरण स्वरूप, पाकितारित करने में कुछ कडिनाइयों का सामना करना पढ़ा, अग्य पुछ सीग पाकिस्तान से माना चाहते थे, किन्यु नागरिकता सवधी अधिनियम के निर्मत होने सव उनको मारत माने का प्रवस्त मानत से पाकिस्तान चले गये थे, किन्यु नागरिकता सवधी अधिनियम के निर्मत होने सव उनको मारत माने का प्रवस्त प्राप्त नहीं हुमा था, मन्य नुख लोग मारत से पाकिस्तान चले गये थे, किन्यु कुछ समय पण्यात् में पास्त लोट प्रार्थ, और प्रन्त में, बुछ लोग विदेशों में रह रहे थे, किन्यु वे भारत की नागरिकता को प्रहण किये रखना चाहते थे। मत, इन सभी वर्मों के लिए नागरिकता सवधी व्यवस्था चरना सविधान समा की प्रारप्त समिति के लिए एक प्रस्थिक कठिन कार्य था।

इस सदमें में सविधान में, सविधान लागू होने के समय केवल इसका उल्लेख किया गया कि, नामरिकता के लिए किन-किन योग्यामों की मावयकता है। नागरिकता से सवध्य में समस्त मामले, जैसे नागरिकता को प्राप्ति एवं नागरिकता का सुप्त होना, सविधान के अनुच्छेद ११ के अनुसार सप ससद-कानून द्वारा तय करेंगी। जिन व्यक्तियों को सविधान के लागू होने के समय से नागरिकता प्राप्त हुई है, से उस नागरिकता के अधिकार को प्राप्त क्यें रहेंगे, किन्तु ससद को इस वियय पर कानून, निर्माण करन का पूर्ण प्रियम रहे। यत सोवधान में नागरिकता के सवध में कोई स्थामी व्यवस्था नहीं की गयी है।

सर्विपात के प्रारम्भ होने के समय पांच श्रेणियों के नागरिकों को मान्यता प्रदक्त की गई। ये श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं।

श्री सारतीय उद्भव के समस्त व्यक्ति धर्यात जो स्वय या जिनके माता-पिता मारत में उत्पन्न हुए हैं तथा वे समस्त व्यक्ति जो मारतीय क्षेत्र मे ध्रविवाडी रहे है या वे समस्त व्यक्ति जो सविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की हम से नम पाँच वर्ष की धर्माय तक भारत के निवासी रहे हो । ध्रिथकाश मारत के नागरिक इसी श्रेणी के है । १६४८ से इस प्रकार देशान्तर के लिये अनुसाधन प्रणाली प्रारम्प की गई थी। दे वे व्यक्ति जिन्होंने चाकिस्तान से मारत को जुलाई १६, १६४८ के परवाल् देशांतर किया, भीर चारत में सा माई निवास करने ने परवाल् उनने मोदेन पत्र देने पर योध्य प्राधिकारी हाथ कवियान के लागु होने से पूर्व

उनका पत्रीकरण कर लिया गया है। चूँकि ऐसे व्यक्तियों को कम से कम

२ वे व्यक्ति जिन्होंने पाषिस्तान से मारत को जुनाई १६, १६४८ से पूर्व देशावर बिया तथा को देशावर करने ने पत्नात् मारत मे निवास कर रह है मीर ने या उनके माता-पिता से से कोई एक या उनके पितामह प्रविज्ञानित मारत में पैदा हुए हो। इस खेगी से धमिनाश हिन्दू तथा तित्रस है जिनको भारत विमानन के पत्नात् पाकिस्तान से मारत धाना पड़ा। एतपई १६.

मारतीय जासन धौर राजनीति

छ माह तक शविधान के प्रारम होने के पूर्वे, मारत में निवास परना आवायक है, जात यह स्मन्द है कि मारत में जनवा निवास जुनाई २४, १४१६ के बाद नहीं भारत हुया हो।

४. सामरणता वे व्यक्ति जिन्होंने मारत से पानिस्तान मार्च १, १६४७ के बाद देशावर किया है वे मारतीय नार्यास्ता के योग्य नहीं होंगे, परन्तु इतने के जिननो पुर्तानक दिया मार्च कर तीटने के निवास मुगारिक प्राप्त के अन तीटने के निवास के अप सामा के प्रमुगारिक दिया मार्च के अन्ति के जा सन्ती है, वसते वे उन नगी को पूरा करते हैं, जो उन व्यक्तियों के निवास होंगे हैं विन्हाने पानिस्तान के सारत की जुनाई १६, १६४७ के पबता है याजत किया गई सावधान जम सामान परिवारों के निवास प्राप्ता के प्राप्त की सामान विकास स्वाप्ता के सिवास स्वाप्ता के सिवास स्वाप्ता कर सामान परिवारों के निवास प्राप्ता सामान स्वाप्ता कर सामान परिवारों के निवास प्राप्ता सामान सामान स्वाप्ता कर सामान परिवारों के निवास प्तापा सामान सामान सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता की सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता के सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता के सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता के सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता कर सामान स्वाप्ता कर सामान सामान

बाधकारी परिस्थितियों के नारण भारत छोड़नर चले गये थे, मदापि उनकी मारत छोड़ने नी बिल्कुन इच्छा नही थी। इस नारण, भारत सरकार ने उनको बापस लौटने की धनुमति दे दी थी। इन कोगो भी

सरवा दी बा तीन हवार ने बाियर नहीं थी।

१ विदि दिरोगों में यह ऐहे मारतीय उद्भव के व्यक्ति खिवयान के भारत होने

ने पूर्व मां उत्तर प्रेमान मारतीय के मारत खाँचे के प्रति हों है भीर मारतीय
दुतावात द्वारा उनका वजीवरण कर निया जाता है, यो उनको मारतीय
नामारित्वा प्राप्त हो आयेगी। कोई भी व्यक्ति विवाने दिसी दिवेशी
राउन में नामारित्वा खहण कर सो है बहु सारत वा नामारित नहीं हो।
सन्त है।

समाप्यतः नागरिक के तीन बाबार होते हैं। सर्व प्रयम, रक्त सुवधी सिद्धात (जस संगवितिस) नागरिकता का एक बाबार माना जा सकता है। रक्त सबधी सिद्धान ने प्रमुक्तार नागरिनना निसी ध्यक्ति नो उसने माता-पिता नी नागरिनता के प्रमुक्तार प्राप्त होनी है। इस सिद्धात ने प्रतर्गत नागरिनता प्राप्त नरने ने लिए जन्मस्यान या निवास ना नोई महत्व नहीं है। पान एवं इटनी पादि देशा में नागरिनना रक्त मिद्धान ने आयार पहां नियपित नी जाती है। इस दृष्टिनाज के प्रान्तीसी या इतालवी माता पिना वी सतान ना, उनना जन्म नाह नहीं नया न हुया हा, प्राप्त या इटली ना बसस्स नागरिन हो साना जायगा।

द्विनीय, जम्म भूमि मिद्धाल नायरिकता प्रदान करने वा दूसरा माधार है। जम्म-भूमि सिद्धात (जम सात्री) वे धनुमार विभी व्यक्ति की नागरिकता उमके जम्मन्यान के माधार पर निर्धारित की जायगी। दूसरे अध्या में, एक व्यक्ति उम देश का नागरित है, जहाँ उपका जम्म हुखा है।

तृतीय, बिनय देशा न रक्त सबबी एव जन्मपूमि भवशी, दाना मिद्धाना में मुनार नागरिका। निर्धारिक मी जाती है। बदाहरण स्वरूप, दिटन मे बाना निद्धानी से मानवाद दी गई है। ब्रिटिश माना-पिना ही सानार दिना कराम विदेश में हुआ है, ब्रिटिश नागरिक हो माने जाविं। इसके धारिक्त, विदेशिया सी सानार जिनका जन्म कि है। सान जाविं। इसके धारिक्त, विदेशिया सी सानार जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है, सो भी ब्रिटिश नागरिक माना ज्ञावेगा।

मुक्यन भारतीय पवित्रात निर्मातामा ने नामरिक्ता के जन्म-स्थान-मिदात (जस सोती) को ही मान्यना प्रदत्त की है, क्योंकि, प्राथमिक रूप मे भारतीय सर्वित्रात द्वारा नामरिक्ता निम्नतिस्तिन श्रीषया के व्यक्तिया को प्रदत्त की गई है।

- (क) को व्यक्ति भारत के स्वायी निवासी हैं, और वे या उनके माता-पिना भारतीय भूभाग में पैदा हुए हैं, वा
- (स) वे ब्यक्ति जो मानारमतया नारतवर्षमे क्यामे कम पाँच वर्षतक निवास कर चुके हैं।

त्तवारि, नुद्ध मात्रा म जारतीय-सिवधान द्वारा नागरिनता के रान सबधी मिद्धान को भी अपनाया गया है। दिन्सी व्यक्ति की नागरिनता के निवे सिवधान के प्रनार यह नही प्रावश्य है कि वह व्यक्ति स्वय मारत में पैदा हुमा हो, दिन्तु पदि उसके माता-पिता या उनमें से विमी एक या उसके पितामह का जाम भारत में हुमा हो तो, उत्त व्यक्ति को नागरिनता मिन सकती है। इस दृष्टिकोण से यह कहा उसिन होगा कि कुछ मात्रा में, बारतीय-सिवधान के प्रतर्गत नागरिकता के रक्त सबधी सिद्धान को स्वीहत किया गया है।

सिवयान के नागरिसमा सबयी प्रावधान प्रतिम नहीं है। सविवान वे मनुस्केद ११ के धनुसार नागरिसता ने विषय पर ससद को विस्तृत शक्तियाँ प्रदत्त नी गई हैं। प्रनएव १६५५ में ससद ने मारतीय नागरिसता श्रीयनियम, १६५५ पारित

भारतीय जासन ग्रीर राजनीति १६ किया, जिसमे नागरिकता की भाषित, समाध्ति एव अन्य सर्वाधत विषयो का विस्तृत

रुप से स्पष्टीकरण किया गया है। मारतीय नागरिकता अधिनियम १६५% का अवस्थक विस्ततिविक महो के ग्राचार पर किया जा सकता है :

 नगरिकता को प्राप्ति— भारतीय नागरिकता अधिनियम १६५५ के बनर्गत नायरिकता पाँच प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं

अन्म के द्यापार पर—

जनवरी २६. १९४० को या इसके पश्चात जो ब्यक्ति भारत में पैदा हमा है, उसको भारत का नागरिक माना आयेगा । किन्तु विदेशी युतावास के उन लोगी की जो भारत के नागरिक नहीं हैं, सवान को भारतीय शागरिक नहीं माना

जायेगा । इसके चतिरित्त, विदेशी शबु हारा करना किये हुए क्षेत्र में पैदा हुए शब् की सनान को भी मारत का नागरिक नहीं माना आमेगा । उदभव या बशायिकार के बाधार पर-

प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म अनवरी २६, १९५० को या इसके पत्र्यात मारत के बाहर हुआ है, परन्त उसके जन्म के समय यदि उसके पिता मारत के नागरिक रहे हो, उसको मारत का नागरिक माना आयेगा।

पंजीकरण द्वारा∕— पबीकरण द्वारा निम्नलिखिन पाँच प्रकार के व्यक्ति भारत की नागरिकता

प्राप्त कर सकते हैं।

(क) मारतीय नागरिको से विवाहित स्त्रियाँ । (स) मारतीय नागरिको की नावासिक सन्तान ।

(ग) देव्यक्ति जो साधारणतया भारत में तिवास कर रहे हो भीर जा

पक्रीकरण कराने हेतु आवेदन पत्र देने संपूर्व कम से कम छ माह में भारत में रह रहे हो।

(प) वे मारतीय जो मिवमाज्य मारत के बाहर किसी देश या स्थान में

माधारपत निवास कर रहे हो। (इ) राष्ट्र महनीय राष्ट्री तथा ग्रायरलैंड के यदनव के बयस्का

नागरिकीकरता द्वारा-

नागरिकीकरण या देशीयकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सक्ती है। नागरिकीकरण के लिए धावेदन देना बावध्यक होगा। क्षत्रध्यान,

१७

सभ सरनार प्रपते निर्णयानुसार नागरिकता प्रदत कर सक्ती है। नागरिकीकरण के लिए किसी विदेशी को निम्नलिसित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(क) वह व्यक्ति वासिग हो।

(स) वह जिस देण ना है, उसनी नामरिनता नो उसने त्याग दिया हो मीर इसनी मुनना भारत सरनार को दे दी हो।

(ग) भागरिनोकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से तत्नाल पूर्व नम से कम एक वर्ष भारतवर्ष में निवास कर चुका हो या मारत में किसी सरकार की भीवरी भे रहा हो, या भारत में निवास या नोई नौकरी करते हए कल एक वर्ष पर्य कर लिया हो।

(प) उपर्युवत उल्लिखित एव वर्ष से पूर्व सात वर्ष तव मारत में रह चुका हो या मारत में किसी सरकार के प्रयोग वार्य वर चुका है प्रयवा मारत में निवास करने और मारत में किसी सरकार के प्रयोग कार्य करते हुए कुल सात वर्ष पूरे कर लिये हो ।

(ड) वह ऐसे देश का निवासी या नागरिक नहीं हो जहाँ मारत के नागरिको का, कानून या व्यवहार के ग्रनसार नागरिकीकरण विजत है।

(व) उस व्यक्ति का चरित्र उत्तम हो।

(छ) उस व्यक्ति को विसी एक मारतीय मापा का जान हो।

(ज) वह व्यक्ति भारत मे निवास करना या भारत मे किसी सरकार के प्राचीन या किसी श्रतक्षेत्रीय सस्या मे, जिसका भारत सदस्य है, या भारत मे स्यापित किसी सस्या मे या क्ष्मती मे नीकरी करने का इच्छुक हो।

यदि आवेदन ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, क्ला, साहित्य, विश्वताति एव मानव-प्रगति के क्षेत्र म विशिष्ट सेवा की हो तो बारत सरकार उपर्युक्त समी या क्सी शर्त को उस व्यक्ति ने सवध मे समाप्त कर सकती है।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति नो, जिसना नागरिकीकरण हुआ है जारतीय सविधान के प्रति निष्ठा की शपय प्रहुण करना आवश्यक है तथा उसको यह भी ग्रूपय लेनी होने कह जारत के नागूनो एव प्रपत्ते (भारत के नागरिक के रूप में) क्रांच्यों का पानत निष्ठार्युक करेगा।

#### भारत में किसी क्षेत्र के निगंबन द्वारा—

यदि किसी क्षेत्र का निर्ममन मास्त क्षेत्र मे हो जाता है तो भारत सरकार धादेश द्वारा यह पोषित कर सकती है कि उस क्षेत्र के किन व्यक्तियो को नागरिक साना जायेगा। ऐसे व्यक्ति घोषणा की तिथि से मास्त के नागरिक माने जायेंगे।

सारतीय जासन घोर राजनीति ŧ۵ ६ जालीकता ही समाध्य-

मारताय नागरिकता स्विधितयम १६४५ व सतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार से नागरिकता का श्रव हो सकता है। स्वार दारा-

मारत का काई भी नागरिक जो किसी विदेश का भी नागरिक है घोषणा

द्वारा मारत का नागरिकता स्थान सकता है। अब इस धायणा का पजीकरण, सविधित प्राधिकारी द्वारा कर लिया जाता है, इस दियि से वह व्यक्ति मारत का मागरिक नहीं रहेगा।

समाप्ति राग-

यदि मारत का कोइ नागरिक नागरिकीकरण पत्रीकरण या किसी धाय तरीके से किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जायगा !

नगारिकता से बचित करके-

मारत सरकार को निम्नानिसित व्यक्तियों को नागरिकता से बचिन करने भा समिकार है। यदि किसा व्यक्ति ने घोले या फुठ से या तथ्या को छिए। कर नागरिकता

धाप्त की है तो मारत सरकार उसकी नापरिकता स विजन कर सकती ₹ या यदि कोड नागरिक धपने व्यवहार या मायण द्वारा मारताय सविधान के

प्रति धपन का मान्याहीन तया होहा प्रदर्शित करता है ता मारत सरकार उसको नागरितका से बचित कर सकती है, या यदि किसा नागरिक न एन युद्ध म जिसम भारत सम्मिलित है, शत्र से

भवैभानिक रूप स ब्यापार या सम्पक किया या एसक ज्ञात होत पर भी कि वह कार पत्र को युद्ध म सहायता पर्नेवायता. उसम माप निया या यदि मारताय नागरिकता प्राप्त करन क पान वर्षों स दश क किसी न्यासान सम द्वारा उस कम-स-कम दो वय का दण्ड मिला हो. या

मदि माइ नामरिक सात वर्षों तक समातार साधारणत भारत स वाहर निवास करना रहा हो और इस समयाविध म भारत के बाहर विदेश म विसा ग्रैकाणिक सस्या म विद्यार्थी नहीं रहा हा या भारत म निसी सर कार या निसा बतर्राष्ट्रीय सस्या न, जिसका भारत एक सदस्य है, प्रधीन सवा म न रहा हो, भौर न ही उसन भारत के नागरिक कर रहन के लिए िंदेग म भारतीय दूतावास म पत्रीव रण वराया है, तो ऐसे व्यक्ति वो

विसी मारतीय नामरित को उसको नामरित ता स विवत गरने के पूर्व भारत सरागर को उसको लिखित बोटिस देना आवश्यक होगा, जिसमे उस नामरिक को, नामरितता से विवत गरने के कारण बतलाय जाना भाव-स्पन है। मारतीय नामरित्ता स्रीयनियम में एन खोच समिति के लिए प्राथपान विचा मया है, जो ऐसे मामनो की जीव गरेगी। साधारणतः मारत सरकार इस विषय पर जीव समिति है प्रतिवेदन के समुतार प्रपना

भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ डारा राष्ट्र महलीय नागरिकता के लिए भी प्रावधान विया गया है। इस अधिनियय नी पारा ११ के अनुनार प्रत्येक व्यक्ति को जो जिटेन, आस्ट्रोलया, नगाडा, लगा, ज्यूनीकैण्ड पानिक्तान, रोडेबिया एव ज्यासालैण्ड सव तथा आयरलैण्ड में गणनत्र भा नागरिक है, इस अनार की नागरिक सव तथा आयरलैण्ड में गणनत्र भा नागरिक है, इस अनार की नागरिकता के आधार पर मारत में राष्ट्र मण्डलीय नागरिक माना जायेगा। इसके अधिरादक इस अधिनियम की आधार १२ के अनुनार मारत सरकार परस्पर सम्बन्धों ने शाधार पर उपयुक्त राष्ट्र मडलीय देशों के नागरिकर ने मारत ने नागरिक की समल एव हुछ अधिनारों नो देने के लिए प्रावेश डारा प्रावधान कर समती है।

मारत में सिविधान में अवस्ति नेवल एन ही नायरिकता ने लिए प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण देश ने लिए भारतीय सिविधान एनल नायरिकता मो ही माग्वता देश हैं, और बाँच प्रावदाय सिवधान एनल नायरिकता मो ही माग्वता देश हैं, और सार्वाधान प्रवद्या है। संयुक्त राज्य अमरीना एव सिवध्यरिक्त में, वो सम्म राज्य है रोहरी नागरिकता को अपनामा गया है, सम नागरिकता और सम के जिस राज्य में एक ज्यनित अधिवासी है, उस राज्य में नागरिकता। मारत में आंतिय एवं सकीर्ण मान्ताधी नो रोगों तथा राज्येयता एवं देश मिनत की मानताधी नो सक्वन नरते हेतु संविधान में एक लाग-रिकता को हो मान्यता दी गई है। इसने भविदिक्त प्रयंत्र नागरिक को मारत के संविधान ने अवस्ति समान अधिवार एवं वर्त्तव्य प्राप्त है।

## नागरिको के मूल ऋधिकार

सामान्यत , एव जनतानिक राज्य की दो मूल धावस्थरताएँ होनी है ! सर्वेपम यह धावस्थ है कि करकार के तीन समी—नार्यपानिका, व्यवस्थापिका एक व्यवस्थापिका पर क्षिणे के प्रकार धार्माराचे ने मूल धार्माराचे ने स्थापकारों के सम्बन्ध प्रधानारों के सम्बन्ध प्रधानारों के सम्बन्ध स्थापकार ने स्थापकार नीर्याचिका व्यवस्थापिका विवस्थापिका विवस्थापिका व्यवस्थापिका व्यवस्यापिका व्यवस्थापिका व

"एन नानुनी धर्मनार एक ऐसा दित है जिसना सरक्षण नानुन डारा होता है और जिसने न्यायानय नाजू करते हैं। जबनि एन सामरण नानुनी धर्मनार ना सरक्षण धरे लागू करता देन के साधारण नानुन डारा होता है, एक मूल अधिनार ना सरक्षण धरे साहाय नरना देन के साधारण नानुन डारा होता है। इन मूल अधिनार ना सरक्षण धरे साहाय धर्मनार ने निविद्य नाविधान डारा हाता है। इन प्रियारी ना साथा धर्मनार ना स्वाच है। इन प्रियारी ना सावधान धर्मा का अध्यक्षणार्थना डारा साधारण विधि-निर्माण प्रविद्यानुसार वर्षणार्थन किसी अवना है निर्माण का सनता है नहीं पर मूल धर्मनार ने निर्माण का सनता है। हमारी धरे मूल धर्मनार का स्वाच हमारो ना स्वच हमारो हम

सकता है भीर इस प्रवार वा वोई भी राज्य-वार्य जो मूल ग्रपिवारा वे विरुद्ध है ग्रवैष होना चाहिये।"

यह स्पष्ट है िन विसी भी अधिनार नो मूल अधिनार नहीं नहां जा साता है यदि व्यवस्थापिना वा कावपालिना उसना उल्लंधन नरती है भीर सिवधान है अन्तर्गत इसके लिए नोई सर्वधानिन उपचार न हों। मूख्य-व्याधाधीश श्री शास्त्री ने भोषातन बनाम महास राज्य के प्रवरण म इस विषय पर पहा या— मूल प्रिवकार के सिवधान ने आरम्भ के और साथ म ब्यवस्थापिना ने इन अधिनारों म हस्तक्षेप के सब्य मे एवं विशिष्ट मुमानियत (अनुच्छेद १३) रतना और इस मुमानियत को लागू करने ने लिए व्याधिन पुनरावलीनन ना सबैधानित प्रावधान (अनुच्छेद १३) करना इस बात ना स्पष्ट छोतन है वि यह प्रिवकार साधारण कानृतों म सबीचन है। "व

एक लिखित जनतात्रिव सविधान में भून अधिकारा के लिए प्रावधान करने के निम्नलिखित कारण होते हैं, जिनसे भूच अधिकारों की महत्ता मी स्पष्ट हो जाती है।

सर्वप्रदम, सविधान मे मूल प्रिष्कारों को रखने के पीछे यह तक है कि जनतप्र मे प्रयोक क्यांकि की प्रपानी महत्ता होती है। बारत्व मे जनतात्रिक राज्य का
समस्त दर्शन प्रयोक व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता पर सावारित है। इस पारणा
के मनुसार राज्य का उद्देश व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हुए समस्त
समाज के करता भी प्राप्ति करना है। परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी समस्
है जब प्रयोक नागरित को उसके प्राप्ति के उपयोग के निए समान मबसर
प्राप्त हो और इन प्राप्तकारों की सुरक्षा का सबसे प्रमावशासी प्राण्वासन इनकी
सविधान में दक्षना है।

डितीय, मूल प्रिम्कारों को सविषान में स्थान देने से क्यक्ति मी स्वतंत्रता का एक विशिष्ट क्षेत्र स्थापित होता है। "सविषान म मूल प्रिप्यार यह यत्र है निनने द्वारा सरकार की निरक्तिता है।" सविषान म मूल प्रिप्यार यह यत्र है निनने द्वारा सरकार की निरक्तिता है। "विश्व स्वतंत्र से सुरक्षित किया जाता है।" राज्य द्वारा इस क्षेत्र में प्रतिकृत्य नित्र विश्व स्वतंत्र से सुरक्षित किया जाता है।" राज्य द्वारा इस क्षेत्र में प्रतिकृत्य नित्र में स्वतंत्र में प्रतिकृत्य होगा। विशेषकर, मास्त्र में प्रही एक राजनीतिक दल ना विशास बहुमत है जहाँ कोई प्रतिपक्षी दल इस

१ डी॰ डी॰ वसु-'कमेन्ट्री घान द कान्स्टोट्यूशन ग्राफ इंडिया', भाग-१, १६६५ पु॰ १२६ ।

२ शास्त्री—गोपालन बनाम मद्रास राज्य ।

३ सी० जै० फाइडिक्-'कान्स्टीट्यूशनस गवमेट एण्ड डेमोक्रेसी', १६४०, पृ० ४२६ :

स्मिति में नहीं है कि केन्द्र में बैकल्पिक सरकार का गठन कर सके, सरियान में जिल्लाखित मूल ग्राधिकार ही प्रतिपक्षी दत्तों के लिए उस हचियार के रूप में हैं, जिनके भाषार पर भपने विचारों तथा सामण की स्वतंत्रता द्वारा, वे सनास्त दल की निर्वश प्रवृति को रोक सर्वेषे । प्रयृति और जनकत्वाप के नाम में सतास्य दल ऐसे नई नार्य नर सनता है जो नागरिन के समिनारों के विरद्ध हो। सनएव, मूल ग्रविकारों को सर्विधान में रखना तथा उनकी सर्विधान में उल्लिखित संग्रीधन-प्रक्रिया के अनुसार ही सरोधित करना, नागरिको को, मूल अधिनारों के लिए एक ठोस आस्वासन है कि सरकार में परिवर्तन के बावजूद मी, उनके अधिकारो में दिना संशोधन-प्रशिया को उपयोग में शाय हुए, परिवर्णन नहीं किये जा सकते हैं। की एम॰ सो॰ छागला ने ठोंक ही बहा है—"मारत में एक बीर डर है, हमारे यहाँ प्रनिपक्षी दक्ष का एक जनताजिक शोधक के रूप में सन्ताब है ≀ हमारी संसदीय यहां प्राप्तश्चा वा का एक जनतात्रक भावक करूप न समाब है। हुमारी खंदाशंक हिस्साओं है। हैक की शक्ताओं पर कार्यादित हों ने ने एपाएन ती, वृक्ष सबयों के परि ने एपाएन ती, वृक्ष सबयों के परि नहीं है। हमारे यहाँ एक राजनीतिक बात का जातान है। जिसके क्यार पर प्राप्त बता नहांदर हो सबना है। जिसके क्यार पर प्राप्त बता नहांदर हो सबना है। निरुद्धा तथों में स्वीतिक स्वाराजनीत कुछ तथा के हुई हो जो जनतात्रिक साबराज है। एक निरुद्धा तथा के मार्था है। एक निरुद्धा तथा के मार्था हो हो। एक निरुद्धा तथा के मार्था है। एक निरुद्धा तथा की मार्था हो। एक निरुद्धा तथा निर्माण की मार्था हो। एक निरुद्धा तथा निर्माण की न न विसों ने बरने की, न पछवाने की आवस्त्रकता है, धतएव हमारे सविभान निर्माताची को धेय देना चारिये कि उन्होंने ध्यवस्थारिका की, जो एक श क्त्यांसी दल के बाविपाय में है, सम्मानित निरक्शता के विरुद्ध रक्षा के लिए प्रावधान किया s<sup>23</sup>

सुद्धीय, नागरिकों के मूल श्रीयकारों को श्रीविधान में रचने का एक महत्वपूर्ण साम यह है कि सविधान में, जो देश का सर्वोच्छ कानून है, मूल प्रीविधारों के रावे से इसको राजनीतिक कान्यों है। "श्रामी के स्वार्थ से उच्चर टटा दिया जाता है। "श्रामी के धीरन, स्वत्रका, में सम्मानका, पूजा करने की धीर दशहू होने की स्वत्रना, सम्मान तथा माध्या केने की स्वत्रका श्रीर श्राम मूल प्रयिवार मनदान के निया प्रस्तुत नहीं विधा सम्मान स्वार्थ से स्वत्रका से स्वत्रका स्वार्थ से धीर स्वार्थ में धीर स्वत्रका से स्वार्थ से स्वत्रका स्वार्थ से स्वार्थ से धीर से से स्वार्थ से धीर से स्वार्थ से धीर से से स्वार्थ से धीर से स्वार्थ से स्वार्य से स्वार्थ से स्वार्य से स्वार्थ से स्वार्थ से स

नागरियों के पून प्रनिवारों को सबियान में रखने के निये उपरोक्त वर्गों के दृष्टि-रोम हैं स्वानाविक रूप में मह प्रश्न खड़ा होता है कि द्विटेन में, मूल प्रविसारों को निनित एवं स्पष्ट रूप से क्यों नहीं रखा गया है ? ब्रिटेन में निनित सबियान

एम० सी० झायला—'द इनीइविज्ञुल एन्ड द स्टेट', १९१६ पृ० ११ ।
 ने० जेवसन—'देस्ट वर्जिनिया राज्य शिला बन्डल बनाम धानेंट', २१६,

पूर एसर ६२४, १६४३ १

नहीं है। बास्तव में विदिश सविधान के सिद्धान्तों वा विकास ऐतिहासिव रूप से विदिश नागरियों के मूल प्रांपवार व विधि शासन में निहित है। इनलैण्ड म सिव्धान के सिद्धानत सविधान में (जो लिखित सविधान नहीं है) पैदा नहीं होते, परन्तु स्वय सविधान के उत्पत्ति तथा प्राधार मूल प्रांपवारों में है।" दिदिश नागरिकों के प्रांपवार के प्रांतित के विदिश राजनीतिक प्रणासी में हती प्रांपवार महत्ते विधान सहते के हिंदि के सुरितार स्वांपवार के विद्या सामार स्वांपवार के प्रांपवार के प्रांपवार के पर महत्ते प्रांपवार के स्वांपवार है पर महत्त के प्रांपवार के पर महत्त के के प्रमावशाली करम उठाने नाहिय।

मारत मे मूल प्रधिकारों के घरितरल को ब्रिटेन की तरह वीई काल्यनिव या भावास्त्रक प्राधार पर नहीं छोवा जा धकता था। धतरुव मारत ने संविधान में नागरिकों के मूल प्रधिकारों को एक विवेध स्थान दिया गया है, मेर साथ हो स्थामपत्रिका को इन प्रधिकारों के संस्था का उत्तरसायित्व सौंग गया है।

## मुल भविकारों के प्रकार

मारतीय सविधान के तीसरे घट्याय में मारत के नागरिकों के सात भूत प्रधिकारों का उल्लेख किया गया है। वे हैं १-समानता का सधिकार, २-स्वतत्रता का प्रधिकार, १-योपण के विरुद्ध प्रधिकार, ४-यामिन स्वतत्रता का प्रधिकार, १-सामिन स्वतत्रता का प्रधिकार, १-सम्पत्ति का प्रधिकार, प्रौर ७-सव-धानिक त्यवारों का प्रधिकार ।

उपर्युक्त उल्लिखित मूल मधिकारो को दो श्रीणियों में उनके स्वरूप ने माधार पर रखा जा सकता है।

प-पृथक् सत्तापूर्णं या सकारात्मक प्रियकार, वीते १-समानता का प्रियकार, २-चवत्रता का प्रियकार, ३-बोयण के विरुद्ध प्रियकार, ४-धामिन स्वतत्रता का प्रियकार ५-सास्कृतिक और वीत्रीयक प्रियकार, ६-सम्पति का प्रियकार । इनमें प्रयोक प्रियकार का स्वरूप सकारात्मक है, वयोकि इनके प्राध्यम से मागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है । इसके प्रतिरिक्त, इसमें से प्रयोक प्रियकार एवं प्रतिरुद्धि से व्यक्तित्व के । व्यक्ति प्रयाक्ति स्वति है । इसके प्रतिरिक्त, इसमें से प्रयोक प्रियकार की प्रयक्त सत्ता एवं प्रतिरुद्ध है ।

व-उपचार सबयी या वार्धाविषक प्रधिवार । भारत के सिवधान में सात्वें प्रधिकार, सबैधानिक उपचारों के प्रधिकार का स्वरूप इस प्रकार का है । इसका उद्देश्य नागरिकों के सकारात्मक या पृषक सत्तापूर्ण प्रधिकारों के उत्लघन होने पर एक विशिष्ट कार्य विधि के प्रमुखार पर्योग्त उपचार प्रदत्त करना है ।

जबकि सकारात्मक या प्रमुक सत्ताचारी अधिकारी द्वारा नागरिको के लिए ऐसे क्षेत्र का निर्धारण होता है, जिससे सरकार कोई ऐसी पक्षपात पूर्ण कार्यवाही

१. जी० एन० जोशी-'द कान्स्टीट्यूशन झाफ इंडिया', १९५२, पृ० ६१।

नहीं कर सक्ती, जिससे इन प्रथिकारों का उल्लंघन हो, सबैधानिक उपचारों के ग्रविकार के ग्रन्तर्गत उस कार्यविधि को निर्धारित किया गया है जिसके प्रमुसार राज्य ना, नागरिको ने निसी सनारात्मक अधिकार ने उल्लंघन होने की स्थिति म, यह क्तंब्य होना कि भीडित नागरिक ने लिए उपचार की व्यवस्था करे। मारत ने सविधान के अन्तर्यंत सर्वधानिक उपचारों का अधिकार एक प्रभावशाली ग्रीयधि के रूप में है, जिसके उपयोग से किसी भून अधिकार के उल्लंपन के परि-णाम स्वरूप पीटित नागरिव की पर्याप्त उपचार तुरन्त प्राप्त हो सकेगा । मत-सबैधानिक उपवारों का अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के समयत. दुरुपयोग पर, जिससे नागरिकों के श्राधिकारों का हतन हो, एक महत्वपूर्ण अवरोध है।

उपर्युक्त भ्रष्टयम से स्पष्ट हो जाता है कि मारतीय सविधान निर्माताओं ने भपनी दूरवर्शिता एव विद्वता का परिचय देते हुए राज्य एव नागरिकों के उपर्युक्त सबधी भी पृष्ठभूमि में, राज्यसत्ता पर दो महत्वपूर्ण अनतात्रिक सबरोधी की रखा, जिससे नागरिकों के मूल ग्रधिकारों को सूरक्षित रक्षा जा सके।

सर्वप्रथम, नागरिको के मूल अधिकारी को सविधान में रखते हए इन अधि-कारों की मौतिकता पर प्रवाश ढाला गया है। सविधान म इन अधिकारी की एक विशेष स्थान देने के फनस्वरूप इनको सर्विधान की पवित्रता एवं सर्वोज्यता का सरक्षण प्राप्त तथा है।

दितीय, सबियान निर्मानामी ने मूल ग्रायिकारों को सविधान में रखने के ग्रात-रिक्त, क्तिपय प्रावधानो द्वारा स्पष्ट आया में यह निर्धारित किया है कि इन ग्राधिकारी का, राज्य सत्ता के दरपयीय द्वारा उल्लंचन न हो । अनुकट्टित १२ के धन्तर्गत राज्य से तात्वर्य है भारत सहकार एवं भारतीय ससद, प्रत्यक राज्य भी सरकार तथा राज्य विधान-समा, तथा मारत में स्थानीय या घन्य प्रधिकारी। इस प्रकार मनुच्छेद १२ द्वारा 'राजसत्ता' का उपर्यक्त सर्व बतलाया गया है। मनु-क्छेद ११ के धतुसार राज्य (जिसका अर्थ अनुक्छेद १२ म दर्शाया गया है) बारा निमित कानून जो मूल ग्राधकारों के विरद्ध है, शबैध माने जायेंगे । शनुकोद १३. छपवरन र के धनुसार कोई कानून राज्य द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है, भी वि सविपान द्वारा प्रदक्त अधिकार नो समाध्य करना है या उसन विघटन करता है भीर इस प्रकार का कानून खबैष होगा। "सविधान के प्रष्याय तीन में निहित मूल भषिकार, राज्य के समस्त ग्रंगा के विरुद्ध किले की दीवार है। 'राज-सत्ता-व्यवस्थापन, वार्यपालिका एव न्यायपालिका सत्रयो - पर यह वर्द प्रवरोधो वें रूप म निमित किये बये हैं।"

१. एम० सी॰ कायजी-'कान्स्टीट्युसन खाफ इच्डिया', १६१८ पृ० १४६।

२७ फरवरी, १९६७ को सर्वोच्च न्यायालय ने गोलरनाय बनाम पजाब राज्य वे प्रवरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके धनुसार संसद को मून प्रियारा म संशोधन करने का ग्रीयनार नहीं रहा । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाय प्रकरण में दिया गया निर्णय, उसने पूर्व ने दो निर्णया ने विरुद्ध था, जो शवरी प्रसाद बनाम मारत सथ एव सज्जनसिय बनाम राजस्थान राज्य व दो प्रवरणा में दिये गये थ और जिनम सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था वि ससद को सवियान म उल्नेसित मूल अधिकारा का सशोधन करने का अधिकार है। धतएव जब फरारी १९६७ म सर्वोच्च न्यायालय ने गोलवनाय प्रवरण म यह निर्णय दिया वि ससद को सविधान के अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत मूल प्रधिकारा म सशोधन वरने का ग्रधिवार नहीं या, राजनीतिज्ञा तथा विधिवास्त्रज्ञों ने, विशेषकर श्रीनायपाई ने मुभाव दिया कि सविधान के अनुकेद्देद ३६८ को सशीधित कर इसम स्पट्ट रूप से यह प्रतिरिक्त प्रावधान जोडा जाये वि सविधान के प्रध्याय तीन म उल्लियित मूल ग्रधिकारो को संशोधन करने का ग्रधिकार संसद की प्राप्त है। ग्रन नवस्यर ५, १६७१ को सविधान का २४वाँ संशोधन पारित किया गया, जिसके प्रनुसार अनुरुद्धेद ३६= मे यह प्रावधान बोड दिया गया है कि ससद को मुल ग्रधिकारों में सक्षोधन करने का अधिकार है । सर्विधान के २४ वें सक्षोधन के फलस्यरूप ससद को पून मूल मधिकारों के संबोधन का यह मधिकार प्राप्त हो गया है जो उसको सर्वोच्य न्यायालय के गोलकनाथ प्रकरण म दिये गये निर्णय ने पर्वप्राप्त था।

मूल प्रिपकारों वे सवय में यह भी याद रराना धावश्यन है ति यह प्रिपेशर प्रसीमिन नहीं हैं। यह एन राजनीतिन सत्य है नि प्रसीमित प्रिपेशरों पा जन-तानिन राज्य में नोई स्थान नहीं हो सकता है। विवेधवर, यह बिटिया एव प्रमरी मी सिवियानों ने प्रन्तांत स्थापित जनतानिन व्यवस्थायों के सन्दर्भ में सत्य है। प्रमरीना ने नागरिनों ने सीमित प्रियेशरों ने सिद्धान्त नो प्रमरीनी सर्वोच्च न्यासाय ने मायवानी सीमित प्रियेशरों ने सिद्धान्त नो प्रमरीनी सर्वोच्च

मारत में भी नागरियों ने सीमित प्राधिनारों ने सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। मुन्य न्यामाधीण दास ने, घोषावन बनाम महास राज्य के प्रकरण में वहां है— 'नत्त वार्य केने को एवं व्यक्ति की स्वत्ववा पर प्रतिवन्य तथाना, बास्तव में पीडित होने वाले व्यक्ति की स्वत्ववा प्राप्त करना है। धत्यव स्वतव्वता पर प्रतिवन्य तथाने की कोच ने बेचल कर्ति पर क्षत्व स्वत्वता पर प्रतिवन्य तथाने की जीवन वेचल कर्ति पर कृति की स्वता निर्मा कर्ति पर क्षत्व स्वत्वत्वता पर प्रतिवन्य तथाने की जीवन वेचल क्षति पर कृति की साना चाहित, प्राप्ति पर क्षति स्वय म सामू विये बाने से विदित होता है, नी साना चाहित, प्राप्ति पर क्षति स्वय म सामू विये बाने से विदित होता है, नी साना चाहित, प्राप्ति पर क्षति स्वय म सामू विये बाने से विदित होता है, नी साना चाहित, प्राप्ति पर क्षति स्वय म सामू विये बाने से विदित होता है, नी साना चाहित, प्राप्ति पर क्षति स्वय म सामू विये बाने से विदित होता है, नी साना

१. ऐडकीन्स बनाम चीलरनस हास्पिटल, १६२३, २६१ यू० एस० ५२५ ।

परक दृष्टिकोष से भी कि इसके द्वारा श्रीषक संख्या में व्यक्तियो को स्वतंत्रता भाष्त होती है। 129

धत जब कि राज्य सता पर एक धोर नावरिको के जून प्रधिकारों के सन्दर्भ में सीमाएँ सरिवाल डाटा सवाई वई हैं, दूसरों घोर नावरिको ने भून प्रधिकारों पर भी सर्वपनिक भीमाएँ सवाई वई है, जिससे जनतव एव राज्य का प्रस्तित्व विद्यान रहें।

ध्व पहाँ जिलत होगा कि मारतीय सविधान द्वारा सात भूल श्रीवशारी का विस्तार पूर्वेश मध्ययन किया जाये ।

#### समानता वा मधिकार

स्तियान के समुख्येद १४-१८ में नागरिकों के ग्रमानता के स्रिमकार का विवरण दिया नहा है। इस स्विकार के सम्बर्ध में राजवाता पर वितय विकेष स्वरोध लागू किये गये है। राजवाता के प्रकार के वृत्यिकोण ने समानता का स्विक कार निर्मेशास्तक है। इस मुदे गर निर्मेश्यर समुख्येद १४, १४, व १६ में बल दिया गया है, जो निम्नितिकत हैं।

धनुष्टेंद १४ के अनुमार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समा-नता का या नानून द्वारा समान सरक्षण के अधिकार का, भारतीम प्रदेश पर, निषेप मही किया जीवेगा ।

सनुन्धेद ११ (१) के प्रमुक्तार राज्य विसी नागरिक के विरक्ष धर्म, बग, जाति, निग, जगम के स्थान सम्बद्ध इनमें से निसी भी प्राचार पर मैदनाब नहीं करेगा। प्रमुचेद १३ वे उपकाय २ के स्थान्तर पर्म, बग, जाति, निग, एव जगम स्थान राज्य रुपमें से विश्वी एक भी प्राचार पर नागरिक के जिरद्ध निम्मणिखित मामसी में मैदनाब नहीं विशा जायेगा —

१-दूरानो, सार्वजनिक मोजनालयो, होटलो, सार्वजनिक मनोरजनगृही में प्रवेश के सबय से !

२-पूण या धानिन धावार पर राज्य निधि द्वारा बने हुए या जनता ने लिए बताय गये नुष्रें, तालाव, स्नानधाटो, सडनो तथा सार्वजनिन स्थानो ने उपयोग ने सबंध में ।

भनुन्देद १४ वे दो घषधाद हैं। सर्वप्रमम, राज्य हित्रयो तथा वच्ना की प्रगति ने लिए विशेष नदम उठा सनता है। द्वितीय, धनुन्देद १४ में उहिलांतित किसी भी प्रावधान से या धनुन्देद २८ वे उपबन्य २ से राज्य को हिशा एव

१ गोदासन बनाम मदास राज्य, १६५०, एस० सी० धार० ८८, (२६२)।

सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्गी एव घनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए काई विशेष व्यवस्था करने म किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।

अनुच्छेद १६ (१) वे अनुसार समस्त नागरिना को सरकारी पद पर निमुक्ति है तिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। अनुच्छेद १६ (२) वे अनुमार वेवल धर्म, वस, जाति, लिग, उत्पित्त, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक को सरकारी नीकरी या पद से बचित नहीं चिया जायगा और न मेदभाव किया जायेगा। सहोप से अनुच्छेद १६ राज्य पर एक स्तिक्य के नहुत्त है, जिसक लाएंग सरकारों नीकरी या पदा के सबस म धर्म, बझ, जाति, जिंग, उत्पति एवं जन्म स्थान के कारण भेदसाव नहीं चिया जा सबता है। परन्तु इसके सदस मंकतियस अपवाद हैं जो निम्नलिखित हैं।

- (क) ससद विधि द्वारा राज्य-सेवाझा से सप्रधित पद या स्थानीय पद का बहाँ के निवासियों के लिए झारक्षित कर सकता है।
- (त) यदि राज्य की राम में पिछंडे हुए वर्ग के नागरिका मो राज्य सेवामों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो राज्य इतके लिए नियुक्तियों या पदों को सारिशत कर कबता है। परन्तु अनुरुद्धेद ३३४ द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पिछंडे क्यों की नियुक्ति करते समय प्रवासन की कुशतता को स्थान में एकता आवश्यक है।

समानता ने अधिनार ने सन्दर्भ में सन्तियान के अनुच्छेद १७ के अन्त-गंन अस्त्रुयता का अन्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अस्त्रुयता से उत्तरप्र की गई निर्माणता को सागू करना अधराध होगा, जो कानून के अन्तर्गत देखनीय है।

ससद ने, १९४५ मे, समानता ने अधिनार को प्रशासकाली रूप से लागू करने के लिए धरपुरस्ता प्रशराम अधिनियम १९५५ पारित दिया, जिसना उद्देश्म प्रनु- सूचित जातियों ने साथ किये जाते वाले मेहसाव को अवैध घोषित करना और उचित देश्य प्रशास के विधार के निवार के निवार के स्वार के स्वर के स्वार के स्वर के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार

ग्रन्त मंग्रनुच्छेद १८ के श्रनुसार उपाधियों को समाप्ति ने लिए निम्नलिसिट प्रावधान विथे हैं —

विधान विधाद है — १—सेना या शिक्षा संबंधी उपाधि के सिवाय ग्रन्थ कोई उपाधि राज्य द्वारा

प्रदान नहीं की जावेगी।

२--मारत ने किसी नागरिक द्वारा विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीनार मही की आयेगी !

नहां का जापना । ३ — कोई विदेशी जो भारत में ,राज्य के अयोन साम के विसी पद पर हैं, राष्ट्रपति की सहमति के बिना निसी विदेशों राज्य से कोई उपाधि स्त्रीकार नहीं

कर सकता है। ४--- मारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई मेट या उपलिध या पद

राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नही कर सकता है।

किसी देश की जपाधि स्वीकार वर सकता है।

तावापि, जनवरी २६, १२४० को राष्ट्रपति ने वह षादेश प्रसारित किया कि राष्ट्रास (कामनवेश्य) के निसी भी देश ने नागरिक की विदेशी नहीं समझ णावेता, जब तक कि वह बात सबद हारा यापित किसी विधि के विदेश हो। प्रत्युत इस बादेश के फलावक्य भारतीय नागरिक राष्ट्र सब (सानवेश्य) के

मारत ने नागरिकों के समानता के पिनकार ने दुव्हिकोंच, राज्य की भूमिका में दो पहुन् हैं। सब अवम, राज्य की अपनी कातियों का उपयोग सीमित एम से सावध्यक होना, निमसे जमके द्वारा नागरिकों को कानून के सभा समानता या नानून के द्वारा नमान रूप से जरहर सरसाच की वर्म, नब, नती, तिग, तथा जम्म स्थान मक्दा इनमें से किसी एक के खाधार पर भेद-मान के कारण प्राथात न पहुँच। द्वितीय, राज्य नी सरनारी सेवाधों म निवृक्ति करने के तिए प्रपत्ने प्रशिक्षा का उपयोग नामरिकों ने धनसर से समानता ने घरियनार ने धनुकृत ही उपयोग में साना होगा।

समानता के प्रधिकार के स-तर्यंत बारतीय नायरिकों को एक विनेय कर्तव्य, समानता के प्रधिका क्या है जो कि प्रमुख्या निनारण से सविधा है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता की स्थापना करता है। अस्तुत प्रश्युक्ता-निवारण सबसी प्राचमा वन व्यक्तियों के प्राचरण पर समयत. एक सहस्वपूर्ण अपरोध के रूप में रहे गय हैं जो सनिवान ये निहित क्याजिक मुख्यों — स्वतम्बत, समानता तथा नामा का, पून खात के व्यक्तार से, विनादक स्वत्य का प्रथम करते

#### स्वतंत्रता का ग्रधिकार

भारतीय सर्विषान ने अनुच्छेद १९ से २२ में नागरिनों की स्वतंत्रता के श्रीध-कार का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। "एक प्रकार से इनको व्यक्ति के नागरिक प्रविचार माना जा सकता है परन्तु एव दुव्दियोण से इनवी राजनीतिय महत्ता प्रत्यिवन है नयोचि वे व्यक्ति एव जनतन ने लिए प्रति भावश्यन हैं भीर जनतन इनके माध्यम से तथा इनवे भाषार पर ही जीवित रहता है। जब एर व्यक्ति नो समुदाय एव राजनीतिक दस निर्माण करने वा अधिवार है, प्रपेने विचारा को प्रतारित करने वी स्वतनता है और विना सत्तास्ट दस ने हस्तरोप में नुनाव जीतने तथा सरमार निर्माण करने वा अवसर है, तब ही हम जनतन ने प्रास्तित्व की करना कर प्रवस्त है प्रदे हम अनतन ने प्रास्तित्व की करना कर प्रवस्ते हैं प्रत वे (स्वतन्त्रता ने प्रधिवार) सविधान या जीवन और प्रास्ता है। '

भारत के नामरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार में दो पहलू हैं। सर्वेत्रयम नागरिकों को सविधान द्वारा सात मूल स्वतंत्रताएँ प्रधान की गई हैं। अनुस्टेह १६ (१) के प्रवृक्षार इन सात स्वतंत्रतायां का उत्सेख किया गया है, जो निम्न-

लिप्रित हैं।

१-वाक् स्वातत्र्य तथा ग्रमिव्यक्ति की स्वतत्रता।

२-मान्ति पूर्वं एव अस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता । ३-समुदाय और संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता।

४-भारतीय प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वन असल करना ।

५—मारतीय प्रदेश के विसी भी हिस्से में निवास करने तथा बसन की स्वतनता।

६-सम्पति के झजँन करने, रखन और वेचने की स्वतत्रता। ७-कोई व्यवसाय, वित, व्यापार या धन्या करने की स्वतत्रता।

१. बी० के० राव-धार्तियामेन्टरी डेमोब्रेसी इन इण्डिया, १६६१ पृ० १४६-१४७।

२ वही-पृ० २११।

ही यह भी स्पष्ट है कि इस स्वतत्रता पर राज्य द्वारा यक्तियुक्त सीमाएँ भी रखी जा सकती हैं और राज्य जिस कानुन द्वारा इन सीमाओ को लागू करेगा, वह कानुन न्याय-योग्य' होगा, श्रयात उक्त कातून को न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। बस्तुत जिन सीमाओं को राज्य द्वारा अनुज्देद १६ ने अन्तर्गन स्वतन्तरा के श्रिधिकार पर लागू किया जायेगा, वे निरकुण नहीं परन्तु युक्तियुक्त होगी। इस न्यायिक सक्या के कारण व्यवस्थापिका, स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकेगी।

ग्रसीमित तथा ग्रनियमित स्थतपता ग्रवश्य ही उच्छुललता मे परिवर्तित हो सक्ती है ग्रीर इसके परिणाय स्वक्य न केवल ग्रन्य व्यक्तियों की स्वनत्रता की हानि पहेंचाती है परन्त इससे राज्य की सुरक्षा एव श्रस्तित्व को भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए स्वतंत्रता का सही बिभिश्राय ऐसी स्वतंत्रता से है, जो कानून से नियमित है, क्योंकि कानून जनतानिक राज्य म जनता की इच्छा का ठीस रूप होता है। दूसरे शन्दों से कानून द्वारा ही अनतात्रिक राज्य में अनता की इच्छा का क्रियान्वय समव है। अतएव जनतात्रिक पद्धति से निर्मित कानून के दायरे में ही ध्यक्ति की स्वतनता समन है, जिससे अन्य व्यक्तियों की स्वतनता का हतन न हो सके । परन्तु इसके साय ही यह प्रावश्यक है कि राजसत्ता का उपयोग भी सीमित तथा जनतानिक रूप से किया जाना चाहिये, विशेषकर जब कि राजसत्ता के उपयोग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया जाता है ! इस दृष्टि से नागरिकों के श्रीवहारों का सवियान में संबंध उन्तेन करना राजसता पर ग्रावहपुक सीमाएँ निर्धारित करना है, जिनका राज्य सत्ता द्वारा उल्लापन करना स्पष्ट कर से अवैधानिक होगा। मारतीय सविधान में मूल प्रविकारी के उल्लेख करने के साथ उन सीमाधी की स्थापित किया गया है जिनसे ये घांघारा सीमिन रहेग । हमारे सविवान से प्रश्त मूल घविनार खनएन चसीमिन नहीं हैं। "प्रत्येत मामले मे श्रविवार, त कि सीमाएँ मूल हैं और देश मे सर्वोच्च न्यायालन तथा अन्य न्यायालया का यह वर्नव्य है कि इन अधिकार। की उत्साहपूर्वक श्रीकसी भीर रक्षा करे।"

नागरिना के स्वतवता के खिवनार में निहित सात स्वतवताओं पर इस दृष्टिन नोण सं भावश्यक युक्तियुक्त सीमाएँ सवियान द्वारा लवाई यई है, जिनका उरेश्य मारत मे नागरिको की स्वतवता और राजसत्ता के मध्य मे जनवानिक सन्दुलन स्यापित करता है। नागरिको की स्वतंत्रता पर इस प्रकार की सीमाएँ, प्रत्येक स्वस्य समाज में पाई जानी हैं, जिनके विना समाज का श्रस्तित्व नहीं रह सकता.

१. एस० दवाल-'द कान्स्डीट्युशन झाफ इन्डिश', १६६४ पूर १०२ ।

है। बोई राज्य प्रपते नागरिकों वो प्रशीमित स्वतन्नता नहीं दे सकता है। मारतीय सिंदियान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की यह एक विशेषना है कि इनके सबय में सिंदियान में हो युत्तियुक्त शीमाधा वी प्रावस्थलता पर बल दिया गया है। किन्धु यह जात करने के लिए कि किसी बानून द्वारा लगाई स शीमाएँ ज्यायावित है या नहीं न्यायपालिका वो अनिम अधिकार प्राप्त है। सारतीय नागरिक का स्वनुक्दद १६ के प्रत्यंतर्गत प्रदत्त सात स्वतन्तामा पर निक्तावितित शीमाएँ है।

१—बाक् स्रतत्रता तथा ध्रमिष्यक्ति भी स्वतत्रता पर सीमाएँ। वार स्वतत्रता तथा ध्रमि प्रक्ति की स्वतत्रता के ध्रमाय में अनतत्र वा की ई मून्य मही है। ध्रतः प्रवक्त जनतानिक सविधान के ध्रम्यगंत वार् स्वतत्रता एव विवारा की ध्रमित्यक्ति की स्वतत्रना की मान्यता दी जाती है। परन्तु जैसा देवा जा चुना है, प्रसीमिन स्वतत्रता न केवल प्रपर्दीन हो आयेगी किन्तु यह जनता के सामान्य हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होंगी।

- (एक )—विदेशी राज्यों से मित्रता पूर्ण सुद्रध रखने के जिल
- (दो)-सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ग्रौर,
- (तीन) अपराध को न प्रोत्साहित करने के लिए।

सम्नेप में, राज्य नागरिको के बाक् तथा विचारो को भ्रमित्र्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नविज्ञित सात विषयो के सन्दर्भ में प्रतिबन्वे लागू कर सनता है। (१) प्रापमान सेख, (२) न्यामानय की दिन्दा (३) शिष्टाचार तथा नैतिनता (४) राज्य की मुख्ता, (५) विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण-सवध (६) सपराघों के सम्बन्ध में (७) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए।

२-इन सीमाओ को मुस्तिमुक सीमाएँ इस्तियं माना गया है कि यदि विसी उपयुक्त-सायासय की सम्पंध से व्यक्ति क्षानृत मा सायेक द्वाप पुलिएनेन प्रतिवस्त, वाक् व विचारों को धानिव्यक्ति की रत्ततत्वता पर सामृ विचे गये हैं, इनते मंत्री माना वा सदत्त है। अत्यक्त नावरियों की स्वतत्वता पर सीमाएं नामित काने संवी माना वा सदत्त है। अत्यक्त नावरियों की स्वतत्वता पर सीमाएं नामित काने संवी स्वार्ध की सीविया की आविव्य की आविव्य की क्षाविया नहीं है। अशोक त्यापातिकां का मारीविया सीव्यान ने धानरियों ने धानरियों की ब्याविया की आवेच तहा साववादिकां है मही नायेवातिकां के कारीविया की धानरियों की सीव्यान की धानरियों है। यह नायावत्व की साववादिकां के साववादिकां के साववादिकां की साववादिका

२—सानिव्युवंक तथा धरनरिष्ठ सम्मेतन वरन की स्वतनता भारत के नागरिकों को सिधान के धनुन्धेद १६ प्रारंग प्रस्त है। इस प्रकार नागरिकों ने एक्सोनिक या बाय प्रकार के मानेसन करने ना सिहनर है, परवृत्त यून सानिव पूर्वंक होना चाहिये जिससे सार्वंकित सुरक्षा को धायात न पहुँचे । महुन्द्रद १६ उपस्तम ३ के प्रतृत्तार राज्य की नागरिका के इस प्रियमर पर सार्वजित्त पुरक्षा के कि में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वांकित के सिक में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वांक का कि में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित के प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित के प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित के प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित में प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित के प्रतिप्तर सीमार्ग सार्वंकित में स्वर्ण सार्वंकित में प्रतिप्ति सीमार्ग सार्वंकित सीमार्ग सीमार्ग सीमार्ग सार्वंकित सीमार्ग सीमार्ग सीमार्ग सीमार्ग सीमार्ग सीमार्ग सार्वंकित सीमार्ग सीमा

— समुदाय एव सप निर्माण नरते नी स्वतन्ता भारतीय नागरिना नी स्विधान के मुत्रुच्देर १६ (१) (ती) द्वारा प्रवत्त है। इस प्रवार नी स्वतन्त्रता सिंधामार पर नागरिन की रावनीतिक तत्त्र आपार सम् और समाधी न निष् स्वारमा नरते ना प्रधिनार है। इस प्रवार की स्वतन्त्रता एवं सुन्धेद १६ उपवन्त्र (४) के सम्वर्गत राज्य सार्वजनिक मुरक्षा एवं नीतवन्त्रा के दिन में पुनित्रुवन सीमाएँ सगा सवना है। इस दृष्टिकोण से यदि नीई सपठन निसी नाजन के विधायन में एतं हो हो सार्वजनिक में स्वतन्त के दिन से प्रवार सार्वजनिक सीमाएँ सगा सवना है। इस दृष्टिकोण से यदि नीई सपठन निसी नाजन के विधायनयन में एतं होण वर्षा हो सार्वजनिक नीतवनता के विरुद्ध है, तो राज्य द्वारा जन समरत की स्वतन्त्र के विरुद्ध है, तो राज्य द्वारा जन समरत है।

४ — मारतीय प्रदेश में एक हिस्से से ग्रन्थ हिस्से में अमण करने की स्वतंत्रता मारत के नागरिकों को सविधान के धनुच्छेद १९ (१) (ट्रों) के ग्रन्तांन प्राप्त

१. डो॰ डो॰ बनु-'पूर्वोक्त पुस्तर', पृ॰ १६३ ।

है परुतु इस स्वतत्रका पर भी राज्य 'युक्तियुक्त सीमाएँ' लगा सरता है। ये सीमाएँ प्रमुच्छेद १६ (५) ने घन्तर्गत सार्वजनिन या घनुमूचित जनजातियो में हित मे राज्य द्वारा लगाई जा सनती हैं।

५—सारतीय प्रदेश ने निसी भी हिस्से म निवास नरने तथा वसने नी स्पतप्रता धनुन्देद १६ (१) (६) ने धन्तमत भारत ने नामित्वों नो प्रदत है। परन्तु अनुन्देद १६ उपवन्य ५ ने अनुसार सार्वजनिन या जनजातिमा ने हितों में बृद्धिनोग से, इस स्वतप्रता पर भी राज्य द्वारा 'बृषितयुक्त सीमाएँ' लगाई जा सनती है।

६—सम्पति वा धर्णन वर्तने, रसने धौर अवने वी स्वतंत्रता, मारत के नाग-रिको को सविधान के अनुच्छेद १६ (१) (एक) के धन्तर्गत प्राप्त है। परन्तु इस स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद १६ (४) डारा यह युन्तियुक्त सीमा लगाई गई कि इस स्वतंत्रता वा उपभीग सार्वक्रमित्र धौर जनजातियों के हिता वो धन्मा में रस्वर ही गिया जा सकता है। उदाहरेखाओं जुमा घर, धनपिकृत सर्द्रियों राज्य डारा जन्त की जा सक्ती हैं। यहाँ उपलेखनीय है कि सम्पति प्रजित करने तथा रसने का यह धिकार धनुच्छेद ११ (ग) या (२) के भन्तर्गत राज्य के व्यक्तियत सम्पति गो लेने के अधिकार के ध्वपीन है प्रचांत परि भन्तर्भद्देद ११ के स्वर्णत राज्य रिसी व्यक्ति की सम्पति वो प्राप्त वरता है तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद १६ (१) (एक) डारा प्रदत्त सम्पति प्रजित करन एय रसने के प्रधिकार को प्रभाव वो अनुच्छेद ११ डारा प्रदत्त स्वर्णत सम्पति प्राप्त करने के प्रधिकार के प्रधीन माना जायेगा।

७ —िवसी व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या धन्या वरने वी स्वतप्रता मारतीय नागिरियो हो अनुष्ठेद १६ (१) (जी) के ग्रस्तगंत प्राप्त है। विन्तु यह स्वतप्रता प्रमुच्देद १६ उपवन्य (६) के अनुसार राज्य द्वारा, सार्वजनिक हिता वे दृष्टिकोण समुद्धेद १६ उपवन्य (६) के अनुसार राज्य द्वारा, सार्वजनिक हिता दे दृष्टिकोण से ग्रुतितपुरत, सीमाध्या के साम्यम से सीमित्र की जा सक्वती है। इसने प्रतिदित्त, नागिरियो मी इस प्रवार की स्वतप्रता से राज्य के इस ग्राधिकार पर, वि वह मित्री को ध्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या पत्रचे के सन्तय म नानृत द्वारा व्यवसायित या तक्वीनी योग्यता निर्धारित करे, कोई रोज्य नही सत्राती है। राज्य को स्वस्तायित्य व तननीकी याग्यता निर्धारित करने, कोई रोज्य नही सत्राती है। राज्य को स्वसायित्य व तननीकी याग्यता निर्धारित करने, कोई रोज्य मार्वजनिवर्धिय, न केयल इत्तमे पार्य हो कि प्रतेक व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय, न केयल इत्तमे नायंत्र व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय, न केयल इत्तमे नायंत्र व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय, न केयल इत्तमे नायंत्र व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय, न केयल इत्तमे नायंत्र व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय नायंत्र कार्या स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय, न केयल इत्तमे सम्बन्ध जनता से स्वाप्त व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय, न केयल इत्तमे सम्बन्ध जनता से स्वाप्त व्यवसाय, विशेषकर पिकिन्सा या इन्जीनिवर्धिय स्वाप्त स

मारतीय नागरिको ने स्वतत्रता के ग्राधिकार का दूसरा पहलू विशिष्ट रूप से यानून एव स्वतत्रता के सम्बन्धा पर प्रकाश डालता है। यह वर्णन ग्रानुक्छेद २० 38

से अनुरुद्धेद २२ तक में दिया गया है। वस्तुत: इन तीन धनुरुद्धेदों में भारतीय सविधान में ब्रिटिश सविधान के संदुध 'विधि-शासन' के सिद्धान्त पर प्रकाश दाला गया है।

प्रो॰ डायसी ने ब्रिटिश सविधान के अन्तर्गत विधि शासन के तीन सम्बन्धित द्वार्थ निदिष्ट किये हैं, जो निम्नानसार हैं,

१-- विसी नागरिन को न हिरासत में लिया जा सकता है भौर न ही उसके जीवन एव सम्पति पर अतिक्रमण ही निया जा सनता है, जब तक कि उस नाग-

रिक ने किसी शानुन का उल्लंघन न किया हो,

२-- नानून की दृष्टि में समस्त नागरिक समान हैं; एव 3-सविधान के सामान्य सिद्धान्त ऐसे न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे विभिन्न प्रकरणो में, जो न्यायालयों के समझ लाये गये थे, नागरिकों के ग्राधिकारी

भा निर्धारण किया गया है। विटेन में विधि जासन के अन्तर्गत नागरिकों के अधिकारों के अस्तित्व की मान्यता देने और कानन तथा नागरिय के अधिकारों का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए, यह स्पष्ट दिया गया है कि राजसत्ता का उपयोग, नागरिक के प्रधिकारों से सन्दर्भ

में तभी होगा, जब वि नागरिक न किसी कानून का उल्लंबन दिया है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद २० से अनुच्छेद २२ तक में यह स्पष्ट किया

गया है कि नागरिकों ने अधिकारों ने लिए कानून की भूमिना नया है। यह तीन प्रकार की है।

सर्वप्रयम, बनुच्छेद २० (१) के बनुसार कोई व्यक्ति विसी धपराध के लिए दौषी सिद्ध नहीं माना जायगा, अब तक कि उसने अपराध करने के समय किसी स्यापित कानुर का स्रतिक्षमण न दिया हो और न ही कोई व्यक्ति उससे स्रधिक इण्ड का पात्र होंगा जो उसको अपराध करने के समय स्थापित कानून के झंदीन टिका जासकता या।

मतुरुदेर २० (२) के भनुसार विसी भी व्यक्ति की एक ही प्रपराय के लिए एक बार स भिनक भिनयोजिन तथा दण्डित नहीं किया जा सकता। इस भनुष्येद में 'दण्ड से अभिप्राय न्यायात्रय हारा दिया गया दण्ड है, न कि किसी विमाग द्वारा दिने गय दण्ड से है। सनएव निसी प्रशासकीय कर्मनारी को न्यायालय द्वारा दण्ड मिलन ने प्रतिस्तिन, उसने विरुद्ध सरनार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर,

दण्ड दे सकती है। मनच्देद २० (३) वे मनुसार विसी व्यक्ति को को कि विसी भपराध के लिए ममियुना है, स्वय के विरुद्ध साक्षी देने ने लिए बाध्य नहीं किया जायेगा ! यह प्रविकार सारत मंदीवानी ग्रीर फीजदारी दोनो प्रकार के सामलों के लिए

है, जद कि भ्रमरीका में यह केवल फीजदारी मामलों के लिए है।

हितीय, भगुन्देद २१ वे धनुसार नोई व्यक्ति भ्रपते जीवन भीर व्यक्तिस्वतास से 'विधि सम्पन्न प्रतिया' द्वारा, न नि निसी भ्रन्य प्रतिया से, यणित निया जायेगा । सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन बनाम महास राज्य वे मामते में 'विधि सम्पन्न प्रतिया' ना भ्रवं स्थाट परते हुए, यह निर्णय दिया नि यदि व्यक्तियाप समा, जीवन भ्रोट व्यक्तिगत स्वतत्रता से विध्व करने ना पानून पारित करती है तो स्थायलय इस बानून ने चुनीते नही दे सर्वे । मुग्य स्थायाधीम कानिया ने निर्णय देते हुए बहा- "विधि सम्पन-प्रतिया" बस्दो पो भ्रपान से परिवास स्वरुप, सविधान द्वारा व्यवस्थापिता समा को बानून निर्णारित परने में भ्रमितम अधिवार दिया गया है।" "

पतिषय लेतको ने ज्यवस्थापिका समा के हाथ भ इम विषय पर प्रतिमा प्रिमित्तार छोड़ने के प्रौतिकत पर भावा ज्यवत भी है। प्रो० धीनियागन गा न'दन है—"विधि सम्पन्न प्रश्निया शब्दों का उपयोग, ज्यितिवास, स्वतनता में रहास्सर प्रावधानों को शीण पर देते हैं, बयोनि एक ज्यवस्थापिना विसी प्रतिया ना जो कि व्याय के सिद्धास्तों में पिरद्ध है श्रयनी सीमाधों में ही रहकर बार्य परते हुए, निर्धारण पर सकेशी।" द

यह सस्य है जि भारतीय सविधान में 'विधि सम्यय प्रतिमा' (प्रीसीजर इस्टेसिल्सट वाय ला) अध्यो ने उपयोग ने बारण न्यायपालिया को ध्यवस्थापिया द्वारा वार्रित कानून के सम्तर्वेशी गुण स्नीर दोव ने स्नाधार पर वानून में सम्तर्वेशी गुण स्नीर दोव ने स्नाधार पर वानून में सम्तर्वेशी गुण स्नीर दोव ने स्नाधार पर वानून में सम्तर्वेशी पर पहुँचती है कि स्मयस्थापिया ने सर्वधानिया के मनु-सार मानून पारित किया है, तो उन्तर बानून को बंध मानना ही होगा। इससे मार्ग स्माय प्रतिका नहीं जा सकती है भीर बानून को बंध मानना ही होगा। इससे मार्ग स्माय स्

१. गोपासन बनाम महास राज्य-ए० छाई० धार०, १९५०, एस० सी० २७।

२. एत० श्रीनियासन—डेमोक्रेटिक गर्वमेन्ट इन इंडिया, पृ० १७३, १६४४ ।

प्रमरोता है, सविधान के पाँचवें और पौरह्वें सशीधनों में 'वैधिक प्रतिमां' (ह्मूप्रोक्षेत्र प्राप्त सा) जब्दों का उपयोग, अस्तिमत स्वत्रका के सर्पण के विष् तिमा गया है। 'विधिक प्रतिमां' के बहुनाह प्रमर्थाकी सर्वोच्च प्रयासान की, अस्तिमत स्वतन्त्रता के सरसाम के लिए, अस्तिम अधिकार है। स्वीति, समरीकी सर्वोच्च व्यासान्त्र 'विधक प्रक्रिया' के सत्यमें में विसी भी वानून की जीच दो क्सीटिंग के साधार पर कर सत्वता है।

सर्वप्रथम, ग्रमसीकी सर्वोच्च न्यायालय कानून की आँच इस घाणार पर कर सकता है कि क्या व्यवस्थापिका समा ने अपने क्षेत्राधिकार के मन्तर्गत कानून परित किया है।

द्वितीय, यदि व्यवस्थापिका ने कानून कपने सर्वेशानिक क्षेत्राधिकार के प्रत्यांत पारित क्षिया है तो सर्वोच्च न्यायाच्य यह भी जोच कर सकता है कि उनन कानून के प्राकृतिक न्याय के सन्दर्भ में क्या कन्त्रवंती मुख और दोग हैं। यदि इस दृष्टि-कोण से बानून में दोग हैं, तो अमरीको सर्वोच्च न्यायास्त्रय उसे प्रवेध पोपित कर सहता है। यहाँ पर समरीकन सर्वोच्च न्यायास्त्रय, 'वेषिक प्रक्रिया' के प्रनुसार ही, प्राकृतिक न्याद को कहीटी पर स्थान संस्कृति का उपयोध करेता।

प्राहातक त्यान का क्सारा पर प्रयम् आपकारा का उपवास करना । स्यान स्थान स्थान के स्थान स्था

सथापि, महा पर यह प्रका उत्तव्य होना है कि सविधान के धनुष्ठेत २१ में विधि सम्मा प्रविज्ञा ने प्रावधान करके नया वात्तव से सर्विधान निर्माना अस्तितात उत्तरना ने सम्बन्ध में अरवस्थापित नो प्रतिस्य स्तित प्रयान करना चाहते में, ज्विके प्रसरकरूप नामिता में स्वतन्ता के मूल स्विधार का सन्तित्य

स्थापित को इन्छा पर ही निर्मर रहे।

समिए, ऐता प्रतीव होता है कि 'विवि सम्पद्ध प्रक्रिया' को प्रपनाने से ध्यवस्थापित ने प्रांगित शक्ति होता है कि 'विवि सम्पद्ध प्रक्रिया' को प्रपनाने से ध्यवस्थापित ने प्रांगित शक्ति हो।
स्थापित के प्रवाद के नहीं पूर्व बाता चाहित्र कि ध्यवस्थापिता स्थय सिवाम से
प्रायमान द्वारा वित्त है। वतपूर्व, ध्यवस्थापिता स्थानो स्थित का उपयोग सर्विप्राप्त में जिल्लांका प्रत्यिया के प्रवृद्ध हो कर सकेशी। स्थानिए व्यक्तिगत स्वत्यना
का जीवन के मूल प्रशिवन के स्वत्यन में, स्विचाय के कुन्दुवेद २२ में जब प्रदिवा
ना स्थय रूप से उन्हेंस है जिल्ले ह्यासार पर ही केवल जारिक को उसमी
व्यक्तिगत स्वत्य की अपने के मूल ध्यविकार से वित्त हिया हा सत्ता है।
यह प्रदुष्ट २२ से 'प्रतियासन-कानुक्त' (शीवेकरस-का) को समानेशित विया
गया है स्वादि सम्पद्ध प्रक्रियां के प्रदुष्टार ध्यवस्थापित्व ने व्यक्तिन्तर

स्वतत्रता ग्रीर जीवन के मूल ग्रधिकार के सम्बन्ध मे जो शक्ति प्राप्त हुई, उसनो द्रधित किया जाये ।

ग्रनुच्छेद २२ में निहित 'प्रक्रियात्मक वानुन' इस प्रकार सर्विधान का, जो कि देश का मूल कानुन है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है भीर जिसरी साया-रण विधि द्वारा व्यवस्थापिका परिवर्तित नहीं कर सक्ती है । अतएव, यह साब्ट है कि, व्यवस्थापिका द्वारा जो भी प्रक्रिया, नागरिक को उसक स्वतवता ग्रीर जीवन के मूल अधिकार से बचित करन के लिए निर्धारित की जाती है, उसका ग्रनुच्छेद २२ मे उल्लिखित प्रक्रियात्मर कानून व ग्रन्बून ही होना चाहिये। तो यह नहीं कहा जा सक्ता है कि व्यक्तियत स्वतंत्रता और जीवन ने प्रतिरार के सम्बन्ध में ब्यवस्थापिका की शक्ति धमीमित है।

म्रनुच्छेद २२, उपबन्ध १ के मनुसार यदि विसी व्यक्ति को बन्दी विया गया है, उसको बन्दीकरण के कारणो से यथाशीझ भवगत कराये विना हवालात मे रोका नहीं जायमा और न ही उसको इस अधिकार स बचिन विया जायेगा नि वह ग्रंपनी पसन्द के बकील से परामणें करे तथा ग्रंपना बचाय करवाये ।

भनुच्छेद २२, उपबन्ध २ के भनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसको यन्दी किया गया है और हवालात में रखा गया है, बन्दी बनाये जाने के २४ घण्टे के अन्दर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश विधा जायेगा, और वाई ऐसा व्यक्ति जिना न्यायाधीश की सहमति के उक्त अवधि से अधिव समय तक हवालात में नही रखा जायेगर ।

मनुच्छेद २२, उपबन्ध ३ के अनुसार, उपबन्ध १ एव २ में चिल्लिखित नोई वात निसी विदेशी शतु या किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस निवारन निरोबी भ्राधिनियम के घन्तर्गत बन्दी बनाया गया है, लागू नही होगी।

सक्षेप मे, अनुच्छेद २२ के द्वारा प्रक्रियात्मक नियमो का निर्धारण किया गया है जो कि कार्यपालिका भ्रौर व्यवस्थापिका पर लागू है। यह निम्नसिखित है।

 १—वन्दी व्यक्ति को बन्दीकरण के कारणा से अवगत कराया जाना चाहिये।

२--बन्दी व्यक्ति को ग्रपने पसन्द के वकील की सलाह सेने तथा बचाव कर-वाने का ग्रधिकार है।

र-किसी व्यक्ति को बन्दी करने के २४ घण्टे की भवधि मे निकटनम न्याया-धीश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

४-वन्दी को, बिना न्यायाधीश की अनुमति के २४ घण्टे से अधिक समय तक हवालात में नहीं रखा जायेगा।

मनुच्छेद २२ मे निहित, उपर्युक्त 'प्रक्रियात्मक कानून' मे कतिपय त्रुटियाँ

है, जिनके फलस्वरूप अभियुक्त को कदाचित न्याय प्राप्त न हो । य दुटियाँ निम्नलिखित है।

 सविधान में यह प्रावधान नहीं है कि मुक्दमें की सुनवाई जल्दी और सार्वजनिक रूप से हो, और न ही यह प्रावधान है कि भ्रमियुक्त को ग्रपने बचाव के लिए ग्रंपील करने का अधिकार है।

अब कि प्रत्रच्छेद २२ के उपयन्य १ एव २ का विषय साधारण बन्दीकरण है, एस धन्बदेव के उपव व ४ से ७ तक का विषय निवारक निरोध है। निवारक निरोध मारतीय स विधान का एक बत्यन्त मतभेदपूर्ण विषय है, जिसकी कडी श्रालीकना हुई है। यह नदाचिन अजीव-सा समना है कि निवारन-निरोव-जैसा विषय सविवान के तीसरे बच्याय म, जिसमे नागरिकों के मूल चविकारों का उल्पेल है, सम्मिलित किया गया हो । परन्त निम्नलिलिन दो तकों के बाघार पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसा बयो शिया गया ।

. सबैप्रयम, राष्ट्र की सुरक्षा एव एक्ता के विशिष्ट महत्व के कारण, संविधान निर्माताको ने निवारक-निरोध सम्बन्धी प्रावधान हमारे नविधान में रखे। विना राज्य के ग्रस्तित्व के मूल अधिकारा की कल्पना करना, बेमतलब होगा। मूल प्रिवरो को प्रसीमित नहीं होना चाहिये, किन्त राज्य की मुरक्षा एवं प्रायण्डता के दिष्टकोण से युविनयुक्त सीमाओं में ही इनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। स्वतन मारत ने इतिहास से विदित हाना है, कि इसकी आन्तरिक और वाह्य क्षतरों का सदा सामना करना पड़ा है। विलक्ष आज य खनरे विकराल रूप धारण निमें हुए हैं। विशेषकर १६६२ म चीनी आक्रमण, नत्यश्वान् १६६४ मे पाकिस्तानी भारमण भीर बागला देश ने सन्दर्भ में, पानिस्तान से हुए युद्ध के रूप में देश की एक निरन्तर खतरे का सामना करना पढा है। "जनतादिक स्वतन्ता मारत मे एक नये तथा कोमल पौथे के सद्ज है जो उन तत्वो ने प्रत्यक्ष या ध्रप्रत्यक्ष स्रति-हमणो से स्वय की रक्षा करने में असमर्थ समन्त है, जिनको जनतानिक स्वननना एवं प्रगति से कोई सहानुमृति नहीं है, कठिनाई से प्राप्त राष्ट्र की स्वनप्रता को क्षाड पाड करने वाले और हिसात्मन तत्वो से बचाने के लिए चौक्सी की ग्राव-श्यनता है। जब तक प्रत्येक दल या संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबैयानिक साधनों को स्वीकृत नहीं कर सेना है, निवारक-निराय-जैस विशेष प्रावधान भारत के लिए ब्रावस्थक हैं।""

द्वितीय, यदि निसी व्यक्ति को निवारत निरोध में रखने की ग्रावश्यकता हो, तो यह सविपान म उल्लिखिन प्रक्रिया के अनुमार ही निया जाना चाहिये, जिससे

१ एम० वो॰ पायसो—'इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन', १९६२, पृ० १०५।

ध्यबस्यापिका या नार्यपालिका सर्वैयानिक क्षेत्र से बाहर जाकर सत्ता वा निरकुण हुरूपयोग न कर सकें। इसी कारण ढा० अम्बेटकर ने सविधान समा के सदस्यों वा ध्यान इस ग्रोर ग्राकपित कराया। वे निवारच निरोध के अन्तर्गत बन्दी व्यक्ति के 'प्रक्रियास्मक' धिषकारों 'वो सविधान से सुरक्षित रस्ता बाहते थे। परन्तु साथ ही उनका ध्यान राज्य की सुरक्षा नो बोर भी था। इसलिए जहाँ अनुच्छेद २२ से राज्य की सुरक्षा पर वल दिया गया है, वही साथ ही बन्दी में प्रश्चितस्य प्रथि-कारा वो मो स्पट वर दिया गया है, जिससे उक्षवो न्याय प्राप्त हो मने।

धनुरुद्धेद २२ के उपवन्त्र (४) के धनुसार निवारक-निरोध सम्यन्धी कोई कानून द्वारा तीन माह से धिषक समय तक दिसी व्यक्ति को हवालात में रउने के लिए प्रिवृद्दत नहीं विया जा सकता है, तिवाद निम्नविदित परिस्थि-नियों में :—

म—णव एक परामधं मण्डल ने, जितके सदस्य ऐसे व्यक्ति है, जो उच्च स्वायालय के त्यायाधीण है, या रहे हैं या त्यायाधीण के पद पर नियुक्त होने भी योग्यता रखते हैं, उपयुक्त उल्लिखित तीन माह की झवधि समाप्त होने के पूर्व, यह प्रतिवेदन दिया है कि बन्दी के निरोध के पर्याप्त बार्पण विवामान है। परन्तु उपवस्य (७ व) वे झन्तर्यत ससद द्वारा निर्मित बानून द्वारा जो वन्तीकरण की प्रविकत्तम सीमा निर्मारित की जायेगी, उससे झिषक समय तब वन्दी को निरोध भे नहीं रखा जायेगा। या,

ब-जब बन्धी को ससद द्वारा, अनुब्हेद २२ उपवन्य (७ म्र) के मनुसार एव (व) के मन्तर्गत बन्धी रखा जा रहा है।

प्रनुच्छेद २२ उपबन्ध (५) के प्रमुसार जब किसी व्यक्ति का निरोध, निवा-रम-निरोध कानून के धन्तर्गत किसी आदेशानुसार किया गया है, जिस प्रधिकारी द्वारा यह भादेश दिया गया है, उसका यह नर्तव्य है कि बन्दी व्यक्ति को उसके बन्दीकरण के नारण शीध्र बताये जिससे वह उस धादेश के विरुद्ध गीध्रातिमीध्र प्रभिवेदन कर सके।

भनुन्छेर २२ उपवन्स (६) के धनुसार उपवन्य (५) में किसी विषय पर भ्रादेश देने वाले प्रधिकारों के लिए उन तम्यों को प्रकट करना ध्रायस्यक नहीं होगा जिनकों वह जनिहत के विरुद्ध समभता है।

अन्त मे, अनुच्छेद २२, उपवन्य (७) के अनुसार ससद कानून द्वारा यह निर्धा-रित कर सकती है कि

क-िंत परिस्थितियों में और किस प्रकार की श्रेणी या श्रेणियों के प्रकरण में एक व्यक्ति का निरोध तीन माह से अधिक समय के लिए निरोध-निवारक कानून के अन्तर्गत परामर्श मण्डल की सम्मति के बिना किया जा सकता है। Yo ल-किसी व्यक्ति का निरोध, निवारक निरोध कातन के बन्तर्गत किस थेणी

या श्रेणियो के प्रकरण में ब्रधिक से अधिक कितनी बनधि किया जायेगा । ग-परामर्श मण्डल द्वारा उपवन्छ (४ छ) के बन्तर्गत निस प्रक्रिया को

श्रपनाया जाये ।

सक्षेप मे, सविधान द्वारा सध और राज्यों की सरकारों को, व्यक्तियों का निवारक निरोध, सविधान मे उल्लेखिल प्रक्रिया के बनुसार करने का प्रधिकार प्रवत्त किया है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का निरोध करते हुए यदि झन् ब्हेद २२ मे उल्लिखिन कानूनी प्रक्रिया की सीमाझी का पालन नहीं किया जाना है, यह बन्दी के मूल धयिकारों के विकद होगा, जो उसको धनुच्छेद २१ भीर २२ उपबन्ध ५ द्वारा प्राप्त है। निवारक निरोध सम्बन्धी अधिकारों का सरकार द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय सविधान में निम्निसिस्त सबैधानिक धवरोधों के लिए प्रावधान किया गया है।

१--साधारणतया, किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाकर तीन माह से प्रधिक समय के लिए निवारक-निरोध में, विना परामर्श मण्डल की सम्मति के नहीं रखा जा सकता है, जिसमे एक उच्च न्यायात्व का न्यायाचील है और शेप दो सदस्य ऐसे होगे जो कि उच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश रह चुके है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। यदि परामर्श मण्डल की राय है कि किसी ब्यक्ति को निवारक निरोध के लिए बन्दी बनाये रखने का कोई नारण नहीं है तो उस व्यक्ति को तत्काल रिद्धा करता होगा । बस्तर के महाराजा प्रवीणसन्द्र भजदेव को परामर्श मध्दल के निर्णयानमार बन्दी रखने के कोई कारण नहीं थे. मत जननो रिहा कर दिया गया । सविधान मे परामशै मण्डल के लिए प्रावधान ग्रत्यात महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह सरकार की निरंकजाता के विद्या एक ठीम धारवासन है।

२---निवारक निरोध में रखे गय किसी व्यक्ति को, धनुच्छेद २२ उपबन्ध ४ के भनुसार उसके बन्दी बनाये जाने के कारणों की जानकारी देना आवश्यक है। इसके मितिरक्त बन्दी को शोझातिशोध यह श्रवसर प्रदान किया जाना चाहिये, जिससे वह निरोध के विरुद्ध प्रमावपूर्वक अभिवेदन कर सके। इस उद्देश्य से कि वन्त्री प्रपने निरोध के विरद्ध प्रमावपूर्वक ग्रामिनेदन कर सके, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि "यह प्रश्न कि बन्दी को उसके निरोध के सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी दो गई है या नही दी गई है, एक न्यायिक प्रक्त है मौर इस विषय पर न्यायपालिका को निष्य देने का सधिकार है।"1

१ शिब्बनलास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० आई० आर०, १६५४, एस० e see off

प्रताप्त निमी व्यक्ति का निरोध करने वाते अजिवारी का यर वर्तव्य है कि वर्ग्यों को साम निरोध करने का कारणों का स्मष्टता पूर्वक वत्ताय, प्रत्यका बन्दों के प्रका निरोध के प्रिक्त प्रसिवेदन करने के प्रिविचार का वर्ग्य मूल्य नहीं होगा। न्यायपालिका को यह निर्योध करने के कारण विक्रिय और स्पष्ट हैं या नहीं है। यदि वन्दी का जा जानकारी उसके निरोध के सम्मरक्त या की प्रदे हैं वह प्रतिचिचत है ता उसका निराज म नहीं रूपा जा सामा है।

३—ध्रनुच्द्रत २२ उपप्रत्य (७ ए) व ध्रनुसार ससद वा वानून द्वारा यह निर्वारित वरन वा ध्राप्तिकार है वि विन परिस्थितिया म ध्रीर निस श्रेणी या श्रेणियो में प्रकरण म विनो व्यक्ति को निवारत-निराध म, तीन माह से प्रियम ध्रविष च लिए परामर्थ मण्डन को सलाह व निना रखा जा सरमा है। इसी प्रवेण सा श्रेणिया व प्रकरण व ध्रमी प्रता तिवार के निराध म रफ्ते च प्रता व प्रकरण व ध्रम्मित निवारक निराध म रफ्ते च विष् ध्रविकतम समयायिव निर्वारित कर सम्ती है।

इसी प्रवार, ससद धनुष्टेद २२ उपवन्य (७ वी) व धनुसार िएसी व्यक्ति के विसी प्रवरण के प्रत्येत निरोध के निष्ट प्रधिवत्तम समय की सीमा निर्मारित नर सन्ती है। ससद उम प्रक्रिया का भी निर्मारण कर पवनी है, जिमर प्रमुत्ता परामर्थ मण्डल को अपन वार्ध करने होंगे। साधारणतया, ससद को निवारण-निरोध के सम्बन्ध में आ अतिवार्ध प्रवस्त की गई हैं, उपयुक्त हैं, परस्तु ससद में एक दन का ठीस प्रमुत्व है, और प्रतिवर्धीय दलो की स्थिति का निरीक्षण करते हुए यह जात होना है नि कोई भी प्रतिवर्धीय दलो की स्थिति का निरीक्षण करते हुए यह जात होना है नि कोई भी प्रतिवर्धीय दलो के स्थित का निरीक्षण करते हुए मह जात होना है नि कोई भी प्रतिवर्धीय दले हुए एक वैक्टियन सरस्वार प्रनिवर्ध के रूप में कि प्रतिवर्धी दलों का स्थाप में वह एक वैक्टियन सरस्वार का निर्माण कर सो । प्रतिवर्धी दलों का सरकार पर प्रतिवर्धी दलों का स्थाप अधिक प्रमावर्ध नहीं ही सकता है और इसरे 'क्लब्वर्स, इस सम्मावना के, दृष्टि से व्योक्त नहीं निया आ सकता है कि ससद एक ही राजनीतिक दल के प्रमुत्व में रह नर ध्रमती क्षित्यों वा इस्परीण करें।

४—"डॉ॰ घम्बेटवर के ध्रनुसार सबसे बढ़ा सुरक्षण यह है कि निवारफ-निरोध कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। यह कार्यपालिका की इच्छानुसार नहीं किया जा सकता है।"⁵

इन सब बचाव या सुरक्षा के प्रावचानों के होने हुए भी निवारर-निरोघ सम्बन्धी मनिन ग्राववयक होते हुए भी खतरनाव है। इस विचार को स्पट्ट करते हुए

१. एम० बी० पायली—पूर्वावत पुस्तक, पृ० १०३-१०४ ।

हों। एसन पीन समी वहले हैं— "स्थापित सरवारों की यह अवृति हो सबसी है कि वे उनके स्थापित रहने के अन्य को से साम्य के स्थापित एसने के अन्य को से साम्य के स्थापित एसने के अन्य को से साम्य के स्थापित हों। साम के अपने अन्य का नहीं है, पर यह अपने अन्य को से सिमार है। है, पर यह अपने अने हैं कि उनसे तथा अतास्त्र उन के किसीपासी सम्वत्र विचा जात, और यह जातिक वा को विचा मुग्त है के साम के स्थापित साम मा बिक्वाय वर्ष हैं। इतनी ही स्वत्र को के पार है। हिन्दी मा सिमार कर के साम के सिमार के

85

सही यह बल्लेल करना धावस्थन है कि ननना और सबद की सतर्जना के बारण निवारन-निराज बालून १६४० क ब्रन्नर्वन चारण म बेन्द्रीय धोर राज्य सरकार को निर्मी स्थित का निवारन-निर्मेष करने का स्विचार है, यदि दलकी सन्तोप हो नाता है कि उस स्थान में रू-भागात की सुराता (केस में के सम मारत के सन्दान या, २ —राज्य की मुस्ता एवं सानित या, १ —राज्य के निर्मे ह सावस्थन बानुको त्या नेवाला को बनाज राजने के विरद्ध कार्य निर्मे हैं।

स्वावस्य वन्नुयां त्या मयाया वा वनाम रचन के व्यवस्य वा वस्य है। 
१६५० के मुद वन्नुय के प्रवाद उर्जुवन केवल दीयारे का के मान्यंत्र मयी 
निर्मे हुए धर्मन्या के लिए परामर्थ मण्डत नी उपयान निया जा सकता था, जब 
कि प्रमम प्रोर कृतन वर्ण के व्यवस्ति वर्णात विवाद का सकता था, जब 
कि प्रमम प्रोर कृतन वर्ण के व्यवस्ति वर्णात वर्ण व्यवस्था में दे हुषिया 
नोग सैं गई भी। इन बन्नुत हारा निवासी (निरिनुत्य सिन्तर्दृत्र) एवं वरमण्डतीय न्यायाधीन (सब विश्वनत्स मण्डिट्ट) अत्याद पर्यमुंत वन्नुत महित्यकृत्यार विभा व्यवस्त कार्यी करण वा धर्मवाद या। योपानन वन्नाम महास्यप्रयाद नामन प्रवत्स मंत्रीच्या व्यवस्ति का वा धर्मवाद निवास निवासनिरोत व्यविनियम की धारा १८ वर्षय भी वर्षानि इसके द्वारा निवास करते के 
वारणा की बन्तन्ताना वर्जित किया प्रवास की वर्ष्य के प्रवास के 
वारणा की बन्तर्साम प्रवास के 
प्रार्थ किया प्रयाद प्रविनियम १९६० के सम्बन्ध में ब्रायंत ध्यानिय ध्यान 
विभा प्रया। विवास के प्रयाद स्थानियम विभा व्यवस्त के 
वर्षा वरण किया के स्थानियम वर्षा के स्थानिय मित्रा प्रवास 
विभा प्रया। वर्षा के स्थान के स्थान स्थान 
वर्षा वरण के स्थान के स्थान स्थान 
वर्षा वरण के स्थान स्थानिय स्थान 
वर्षा वरण के स्थान स्थान 
वर्षा वरण के स्थान स्थानिय स्थान 
वर्षा वरण के स्थान स्थान 
स्थान वर्षा वरण के स्थान स्थान 
स्थान हिंस स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान 
स्थान स्थानिय स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान 
स्थान स्थान 
स्थान स्थान करण करण स्थान 
स्थान स्थान 
स्थान स्थान 
स्थान स्थान करण स्थान 
स्थान स्थान करण स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान करण स्थान 
स्थान स्थान करण स्थान 
स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
स्थान स्थान

रै एम॰ पी॰ शर्मा—ह गर्वमेन्ट श्लाफ द इंडियन रिपल्पिक, १६६९ पूर्व ४७९

दे सके। यदि परामर्श-मण्डल वी राग मह है वि विसी व्यक्ति वो बन्दी रसने के वोई कारण नहीं है तो सरकार उस व्यक्ति वो रिहा बर देगी। कियो भी व्यक्ति को प्रिपितियम वी घात (११९) वे फ्रनुसार बन्दी बनाये जाने वो तिथि से १२ माह से प्रिप्त समय के लिए बन्दी नहीं रसा आ सकता है। हमी प्रवार निरोप प्रादेत वी समयाबिश समाप्त होने के पत्रवान् उसी व्यक्ति वे निराम वे विष् नया प्रादेश नये तथ्यो वे स्नामार पर ही दिया जा सवेगा।

इसने वाबजूद की न्याधिक पुनरवलोबन का क्षेत्र निवारक-निनाध के दृष्टि-कोण से सीमित है, विन्तु न्यावपालिका टस सामले में विव्हुल कमहाम गरी है। न्यायपालिका निवारक-निरोध सम्बन्धी बादेण का पुनरवजीरन ब्रामिनित माधारों पर कर सकती है।

क—यदि निवारत-निरोध सम्बन्धी धादेश थे लिए यह बहा जाना है कि यह प्रप्तारी (मेलेकाइड) है। धादेश ने प्रपत्तारी हाने से प्रव्र नास्पर्य है पि यह निवार निरोध धीपनियम ने उद्देश्यों ने विरुद्ध है, ऐसी स्थिन में धादेश दा खबैध विया जा सनता है।

ख-न्यायालय इस बात भी भी जांच कर सकता है कि जो नियारण-निरोध के कारण बतलायें गये हैं, वे उतने प्रतिनिक्त हैं कि उनको प्रयक्ति गांत जाय। वे या जनका स्वरंप इस प्रकार का है कि व्यक्ति के इस प्रतिकार का हकत होता है। वे बन्दी व्यक्ति का यह धापिकार है कि उसको बन्दीनरण ने कारण बतलायें जायें।

बतनाय जाय ।

ग—म्यापालय इस बात की भी जांच कर सकते हैं कि क्या नियारक-निरोध के कारणों का विकेवपुत्रत सम्बन्ध निवारक-निरोध के उद्देश्यों से, सविधान या निवारक-निरोध अधिनियम के अन्तर्गत है या ग्रही। भें भिंद न्यायालय द्वारा सह निर्धारित कर दिया गया है कि इस प्रकार का विवेवपुत्रत सम्बन्ध नहीं है तो बन्दी को खुटकारा प्राप्त हो जायेगा।

ष — न्यायानथ इस बात की भी जीच कर सकते हैं कि निवारक-ितरोध के लिए कानून हारा जिस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, उसना निवारर-

१. गोपालन बनाम मदास राज्य-ए० ब्राई० ब्रार०, १६५०, एस० सी० २७।

र. शिब्यनलाल बनाम उत्तर प्रदेश—ए० बाई० ब्रार०, १९५४, एस० सी० १७६।

गोपालन धनाम महास राज्य, ए० माई० मार०, १६५०, एस० सो० २७।
 शास्वनलाल बनाम उत्तर प्रदेश--ए० माई० मार० १६५४, एस० सो०

<sup>1 309</sup> 

निरोध श्रादेग जारी करते हुए पालन किया गया है या नहीं। यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया थया है तो बन्दी को रिहा किया जाना चाहिये।

#### शोषण के विरुद्ध ग्रधिकार

मारिनेय परिचान के अनुन्येद २३ तथा २४ शोधम के विरुद्ध धिमार के सरामध्य में हैं। जनदानिक मुख्यों के अनुकृत यह अधिकार असाज में शरित की सितंता इस महत्व र पाये देता है। अन्दुत यह मानवात के उस सिव्यादातुमार है जिस पर वर्षन धारांचेवाची बार्केनिक बान्ट ने इन कच्यों में प्रकाश काला है कि मानव के व्यक्तित्व को सामन के कहा में नहीं बिरुक उद्देश्य सरका मानजा माहिसी। पुरुक्तिर २३ (१) हाता मानव का प्रकाश बधीर आपने प्रचास मानजा साम्य बारवातीर ध्या पॉनन किया गया है और काय ही यह भी प्राथमान किया गया है कि उन्देशन प्राथमान के उत्तवन के किए कानुन के सत्यारेत, उच्च दिया गया है कि उन्देशन प्रथमान के उत्तवन के किए कानुन के सत्यारेत, उच्च दिया गया। इस तरों के सिर्वान में भी विश्वान के विरुद्ध स्वीमान द्वारा ऐसा ही प्राथमान किया गया है, जितके चनुवार न तो बात प्रचा और न ही बाध्यकारी अस का, दिखाय एक धारपा के फनवनक्य जितके लिए सह चक्च दिया गया है,

सारत के सरियान में इस अधिकार को समावेशित करने का कारण यह पर कि इसके द्वारा भारतीय सनाज में से बाध्यकारी अग की नुरी सामन्तवादी प्रया को समान्त किया जान । इसके मातिरिका, इस प्रीयकार वा उद्देश्य दिवसी एवं बच्चों का सरक्षण करना है, जिससे उनके सा कोई कार्य करने या वृत्ति अपनाने के तिस् बाध्य नहीं किया जा सके, जो नैतिकता के विकट हो ।

परम्पु मनुष्हेद १२ (१) में सार्वजनिक उद्देश्यों के सन्दर्स में एक प्ररवाद का उन्होंना है, जितने धनुनार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की शूर्ति के लिए धनिवार्य तैया की धन्यस्था कर सवता है। धन्यिंस धनियान म, 'बार्वजनिक उद्देश्य' का स्प्योक्तरण नहीं है, किन्दु दूसना प्रमें धिनिक-सेवा एवा पाट्ट निर्माण वर्ग से सत्व-यित है। परन्तु सार्वजनिक उद्देश्य की शूर्ति के लिए राज्य द्वारा धनिवार्य तेयाधी मी व्यवस्था करते हुए, धर्म, वक्ष, जाति, वर्ष या इनमे से किसी एक के कारण में स्वयस्था करते हुए, धर्म, वक्ष, जाति, वर्ष या इनमें से किसी एक के कारण

भ्रमुन्देद २४ के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु ने बच्चो को कारखानी, खदानो, या ऐसे कार्यों म जिनसे जनके बारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को सतरा

९. परमॉसह बनाम पताब राज्य—ए० ब्राइ० बार०, १६४८, एस०सी० १४२ ।

है, नियुक्त नहीं दिया जायेगा। सक्षेप में शोषण के विग्द क्रांघिकार के प्रत्येत न बेबल राज्य परस्तु क्रन्य नागरिकों के कतिपय क्लेंच्यों का स्पष्ट रूप से उल्केग्र किया गया है।

### धार्मिक म्बनप्रता का ग्रधिकार

मारतीय सविधान द्वारा धर्म निरमक्ष राज्य की स्थापना नी गई है। पर्म-निरमेन राज्य का ग्रम्मं है, वह राज्य जो किसी धर्म विनेष के सिद्धान्त। पर प्राधा-रित न हो कर न्याय, क्वानता, समानता एक पारस्परिक सीहाद ने सिद्धान्तो पर प्राधापित है जो जनतक के सिद्धान्त हैं, मारत के सिज्यान म धम-निरमन राज्य के दो प्राज्यार है।

सर्वप्रयम, सचिपान भी प्रस्तावना म न केन्द्र भारतीय गणतम के प्राचारभूत सिद्धान्तो का, जैसे न्याय, स्थानकता समानता एव भातृस्व ध्वादि, उत्काद निया गया है, बरत यह भी म्यप्ट रूप से नताया गया है कि प्रत्येव नागरिक को प्रत्य स्वतत्त्रतायों के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धान्ता म विक्यास धीर उपामना करते की भी स्वतन्ता प्राप्त है।

दितीय, सविधान में भी निरीक्ष राज्य का दूसरा प्राचार नागरिका थे पामिक स्वतन्ता के मूल क्रिकार के रूप में हैं। सविधान बाउन्देद २५ स २० नागरिता के घामिक स्वतन्ता के मल क्रिकार का उरलेग करते हैं।

धनुष्देव २४ (१) वे धनुसार समस्त व्यक्तिया को स्वनन्नतापूर्वक किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करन तथा प्रचार करन का ध्रश्विद्य प्राप्त है किन्तु इस अधिकार का उपभाग सार्वजनिक कान्ति, नैतिकता ध्रीर स्वास्थ्य तथा ध्रम्याय तीन के ध्रम्य प्रावधानों के ध्रमीन रहकर ही बिया जायगा। मानुष्देव २५ (२) के अनुसार राज्य निस्नितितित विषयों पर कानून निर्माण कर सहता है।

- (म) जिससे विसी धार्मिन प्रथा से सम्बद्ध प्रायिन, विसीय, राजनीतिन या प्रम्य मिनी नार्रवाई को नियन्त्रित या सीमित किया जा सके, और
- (ख) जिससे सामाजिक-करयाण एव सुवार या सार्वजनिक स्वन्य की हिन्दु पामिक मस्याघो म समस्त वर्गो के हिन्दुयो के प्रवेश के तिए व्यवस्था की जाये:

ग्रनुच्देर २६ के ग्रनुसार प्रत्येन धार्मिक इनाई या उसके निसी हिस्से को सार्वजनिक सान्ति, वैतिकता तथा स्वास्थ्य की सीमाग्री के ग्रायीन निम्नलिखत अधिकार हैं।

व-धर्म ग्रीर दान के उद्देश्यों से सस्याग्रों का निर्माण ग्रीर पोपण वरना.

ग—चत्र एव ग्रचल सम्पत्ति के स्वामित्व और प्राप्त करने का ग्रधिकार, ग्रीर

प-इस प्रकार की सम्पत्ति का संवालन कान्न के अनुसार करना।

श्रनुच्छेद २० ने श्रनुमार किसी व्यक्ति का ऐसे मन ने लिए कर नहीं देना होगा जा नि क्सी धर्म विजेष या पामिक इनाई, की प्रवृति या पोषण पर सर्वे हता है।

प्रतान प्रमुच्देद २८ (१) के जनुजार जिल जिला संस्थान की सम्पूर्ण खर्च राज्य निष्ठा से पान हो रहत है, नहीं कोई परिक निषदा नहीं से जायेगी। अनुच्छेद १८ (२) के जनुसार किसी जिला संस्थान ना प्रणासन ने प्राप्त का नहीं है निकारी रहा है पान निस्ता का प्राप्त के से स्थानना एक ऐसे पर्माण-ज्यास द्वारा की गई है जिलारी कर्त है कि जनन सस्थान से पानिक विकास सी जाये, नहीं अनुक्षेत्र २८ (१) नहीं तानू हागा, प्रणान जन जिला सस्थान से पानिक किया सी सा सक्षेत्रों। प्रमुचेद २८ (१) के स्तुनार वाहि किसी जिला संस्थान की निवेद, राज्य वारत मानवता प्राप्त है या उसका राज्य निश्चित के अनुसान मिल रहा है, किसी व्यक्ति को नी बहुँ एक रहा है, प्राप्तिक विकास, की नहीं से जा रही है, या उस सस्या में या उससे सस्यान जनहों की जाने सा वाहि की लिए वाष्ट

हा ता उसके प्रणिमानक ने सहसाति थी है।

पह रमन्द है कि फारत में पर्य निरुपेत राज्य की मीन, सविधान की प्रस्तासना प्रीर नागरिकों के प्रामिक स्वत्रवात के मूल प्रश्विकार में निर्मित हैं। इत-सेना प्रापायों पर स्थित है, नागरिकों नी 'सनाम स्था से प्राप्य धार्मिक स्वत्रता'।

पारत म राज्य की घर्म निरुपेक्षता इसी से विदित होती है कि राज्य के बिना
हरनक्षेत्र के प्रयोज नागरिक नो समान क्य से प्राप्य स्वत्रता सा

मही किया का सकता है, सिवाय, जबकि उस व्यक्ति ने बरीर यदि यह व्यस्क न

मारत म राज्य की पर्व निरक्षिता इसी से विदेश होती है कि राज्य के बिना हुत्तभेष के प्रदेक नागरिक को समान कर से धार्मिक क्वनजा का प्रक्रिकार प्राप्त है प्रौर जो यो सीमाएँ नागरिक के धार्मिक स्वत्वस्तः के प्रियकार पर सर्वि-भाग हारा रही गई है, वे समस्त नागरिकों के विश्व समान है। मारनीय नागरिकों का धार्मिक क्वतज्ञता का अधिकार भ्रमीनित नहीं है।

ारांचा निर्माण ने पामिल स्वतंत्री को बाक्कार स्वतंत्री नहीं हैं। सिनाम के मन्त्रीद रेश वर्ष के उन कारणों का करोबा है, जिनते प्रामार रर मार्मिक स्वतंत्री को मन्त्रीद रेश वर्ष के उन कारणों का करोबा है। जिनते प्रामार संपर्मिक स्वतंत्री के सिनाम के सिनाम करता है। उदाहरण स्वरूप किसी भी पामिक स्वतंत्री के हिंदी में प्रीमार के स्वतंत्री के सिनाम है। प्रताह से प्रामाण के सिनाम का मिलाम के सिनाम के सिनाम

सकते है। यह स्पष्ट है नि राज्य द्वारा पामिन स्वतन्नता नै अधिकार पर समाज के हित में, सिवधान ने अनुसार प्रतिबन्ध सवाये जा सनते हैं। इस प्रनार पामिन स्वतन्नता ने नारण निसी स्वतिक नो, इस पर भी नि मानव-वित्तान निसी धर्म द्वारा स्वीकृत है मावन-वित्वान करने नहीं दिया जा सबता है। (जैसे नृद्ध तमें में) या गाई ऐसा नार्य जो नाना ने अन्तर्गत एन अपराध है, या गिसी वर्ग नी अधिन मानवन्धा पा जानवृक्तकर द्वापात पहुँचान। 1 अत जैसे भी टीप ना कथन है— पामिन या अन्त करण नी स्वतन्नता पर आधुनिक समाज म विशेषन र भारतीय समाज जैसे विविध-स्वरूपी समाज में, सीमाण ध्रवस्थमायी है।" भ

# सास्कृतिक एव शैक्षणिक अधिवार

मारतीय सिंधान में साहरतिक और जैशिषक अधिकारी को रनते का उद्देश प्रस्करत्यका है हिना की रक्षा करता है। मारत एव बहु पर्म, भीर वहु-मारी राष्ट्र है, अताएव भारतीय कणतत म अस्वस्वस्थको नी विषेष क्षिण की स्वाप्त के सुक्त है। के अता के अता के सिंधा के सिंधा कि सिं

घनुक्छेद २६ (१) वे धनुसार भारत या भारत ये विसी भी भू-भाग मे रहने यांते नागरिनो वे विसी मी ऐसे जन-समृह वो जिसकी धपनी पृथव माया, तिषि या सस्कृति है, यह अधिगार है कि वह अपनी भाषा, निर्ण या सस्कृति वो बनाये रहे। धनुन्छेद २६ (२) वे धनुसार यदि कोई शैक्षणिक सस्या राज्य द्वारा या राज्य की सहायता से सचानित की जा रही है सो उससे प्रवेश हेतु वश, जाति, मर्म और भाषा या हामे से निसी एक के धाधार पर मेंद-भाव नही किया जा सकता है।

भ्रस्प सरपनो ने हित मे अनुस्केद २० (१) द्वारा यह प्रावधान जिया गया है कि समस्त प्रत्पसस्यनो को चाहे वे घमें या मापा सम्बन्धी भयो न हो प्रपने इच्छा की मैदाणिन सस्याचो ना सजालन वरने ना अधिनार है। धनुष्टेद ३० (२) वे अनुसार शैक्षणिन सस्याचो नो अनुसान देते समय राज्य इस नारण

१. डो॰ डो॰ वसु---पूर्वोक्त पुस्तव, पृ॰ १५४।

२, टी० के० टोपे---द कान्स्टीट्यूशन झाफ इच्डिया, १६६३ पु० १३३।

मेद-मान नहीं करेगा कि किसी बौक्षणिक सस्या का सचालन किसी घमें या मापा सम्बन्धी घल्यसध्यको भी इकार्ड के हाथों में हैं !

नागरिकों के शैक्षणिक और सास्कृतिक मूल अधिकारों की एक अन्य विशेषता यह है कि राज्य तथा नागरिक के साम्बन्धों के सन्दर्भ में यह अधिकार असीमित है अर्थात् इन अधिकारों को राज्य को बिना किसी सीमा के बाध्यकारी इप से मानना होगा

### सम्पति का ग्रधिकार

सामन प्रधिकारों भें, जीवन, स्वतंत्रता एवं सम्पति के स्रीक्तार जायन्त महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चित्रता में प्राचीन समय से इन प्रधिकारों ने महत्व पर स्तप-माम पर बन दिया गया है। सम्बति वा प्रधिकार, बास्त्र से उद्ध पत्र के एवं में है, त्रिसारे मानव व्यक्तित्व का विकास होता है, अवरस्तु जो राजनीति स्रोत ना जनक माना गया है, व्यक्तियत सम्पत्ति को मानव व्यक्तित्व से मिनसा से नित्र प्रसावकार सम्भाग है।

इंग्लैंग्ड, समरीना, जांस, झांसरलेख सारि देशों के सर्वसातिल लागून से स्वाद्य हांसा है। इसी प्रसाद मारतीय संविधान के सब्दुन्देहा (१) (एक) के महान्य रहेता है। इसी प्रसाद मारतीय संविधान के सब्दुन्देहा १६ (१) (एक) के महान्य र प्रसाद मारतीय संविधान के सब्दुन्देह १३ के सल्तर्गत प्रस्तेक संविधान है। इसके सर्विध्यत, मारतीय संविधान करने, रणने सीर व्याद करने, स्वाद है। इसके सर्विधान संविधान किया ने स्वाद का सुन्तर है स्वाद के सुन्तर दिशों भी व्यादिन ने सिव्धान कामून के सनुवार दिशों भी व्यादिन संविधान किया गया है कि किसी भी सम्पति नी राज्य केवल सार्वजनिक के स्वाद स्वाद की स्वाद मार्था के स्वाद स्वाद की स्वाद के स्वाद के स्वाद केवल सार्वजनिक के स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद के सिव्धान के स्वाद स्वाद

मन यह स्पष्ट है कि मुखावजें का निर्धारण करने में व्यवस्थापिक समा को ही मन्तिम मधिकार है।

ो सन्तिम प्रसिवार है। सन्नेप मे अनुरूक्षेद ३१ (१) व (२) डारा निम्नलिखित तीन मुद्दों का

उत्सेल किया गया है। १-किसी भी व्यक्तिको बिना कानून के उसकी सम्पति से बन्तित नहीं विया जा सकता है। २—सरकार किसी व्यक्ति या सस्या की सम्पत्ति को 'सार्वजनिव उद्देश्य' में लिए प्रजित वर सकती है भीर इसके लिए उसे मुधावजा देना होगा।

३— मुक्षावजे नी राशि का निर्धारण व्यवस्थापिना द्वारा होगा धौर न्यायाक्षय को इसे उचित या धनुचित ठहराने ना धीषनार नहीं है। धमरीना में सरनार द्वारा सम्पति प्रजित करने पर जो मुखावजा दिया जाता है, उतने सम्बन्ध में स्थायालयों को प्रथिकार है कि यह निर्धारित करें नि मुखावजा उचित है बा

अनुन्देद २१ (२) ने अनुसार विद निक्ती राज्य नी विधानसमा द्वारा ऐसी विधि, जिसका उल्लेख अनुन्देद २१ (२) मे निवा गया है, निमिस नी गई है, तो यह तब तन प्रमाची नहीं होगी, जब तन नी राष्ट्रपति ने उक्त विधि नो अपी

स्वीकृति न दे दी हो।

सनच्छेद २१ (४) ने अनुसार भी यदि नोई विषेधन निसी राज्य विधान सप्ता में समक्ष सविधान ने सामू होने ने समक रखा गया है, और उपत विधानि, मा बारा पारित होजर उसे राष्ट्रपति नी स्त्रीहत प्राप्त हो जाती है, सो उना विधि पर दिसी स्थामत्त्व में समक्ष हम नारण आपश्चि नहीं नी जासेगी ति यह अनुचेद २१ (२) ने निष्ठ है।

समुच्देद ३१ उपप्रथम ५ के अनुसार उपवग्य २ में उस्केखिन सुम्रावजे सम्प्रमी कातृत का निम्मत्रिमित विषयो पर कोई प्रमान नहीं होगा ।

प-- विसी भी स्थापित बानून पर, बैबल ऐसे बानून को छोडरर जिस पर अपबन्य ६ लाए होता है।

प--ऐसा बानून जो राज्य द्वारा निम्नलिखित विषयो पर निर्मित हुमा क

१--- मोई कर या श्रयं १ण्ड लगाने के लिए।

?--सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नत करने प्रयक्षा जीवन या सम्पनि के सहर के निवारण के निष्

३--ऐसे समफीतो नी शर्नो को पूरा करते के लिए जो मारतीय डोमीनिया की प्रथवा मारत सरकार एव किसी घन्य देश की सरकार के मध्य किया गया है, प्रथम निष्यान्त सम्पत्ति से सर्वाचा कानून ।

अपुन्देद २१ (६) के ब्यनुसार यदि बोई कानून सविवान के लागू होंने के १८ मार से प्रिक्त समय पूर्व राज्य द्वारा बनाया गया है, तो तीन महिने के प्रचर उक्त बानून की राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणिन करा देता है, तो कियो ज्यायालय मे उक्त बानून की राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणिन करा देता है, तो कियो ज्यायालय मे उक्त बानून पर इस ब्रावार पर ब्रामित नहीं की जावेगी कि वह उपयन्य २ के विद्ध है।

Υo

सर्विधान लागू होने के पश्चात् यह धनुमव किया गया कि धनुच्छेद ३१ के विभिन्न उपबन्ध मारत मे विभिन्न सरकारी द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके श्रतिरिक्त, जब विभिन्न राज्यों की, जैसे-बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सरकारी ने जमीन्दारी उन्मूलन के लिए कदम उठाये, न्यायालयो ने इसे प्रनुचित ठहराया । पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार-भूमि-सुधार ग्राधिनियम १९५० को इस कारण अवैध घोषित निया गया कि वह शनच्छेद १४ द्वारा प्रदल कानन के धनुसार समानता के अधिकार के विरुद्ध है। इसके फलस्वरूप सर्विधान संशोधन अधिनियम १६५१ द्वारा सर्विधान में संशोधन कर दो नये ग्रनच्छेदो ३६ (ग्र) भीर ३१ (ब) एव एक मन्य प्रनुसुबी (नवी) को जोडा शया ।

श्रनुच्छेद ३१ (श्र) के श्रनुसार यदि किसीकानून द्वारा किसीसम्पति के स्वामी या जमीन्दार के चयिकारी की सीमित या समाप्त किया जाता है तो उक्त कानून को केवल इस कारण अवैध नहीं माना जायेगा कि उसके द्वारा अध्याय तीन मे प्रदत्त मूल अधिकारो मे कभी कर दी गई है या उन्हे समाप्त निया गया है। धनच्छेय ३१ (ब) नवी धनसूची में उस्लिखित स्विधिनयम इस सामार पर श्रीय नहीं ठहराये जा सनते हैं कि अध्याय सीन के अनुच्छेदी एवं नियमी का उल्लंघन करते हैं। चौर किसी भी न्यायालय के विपरीत निर्णय, डिकी या मादेश के बावजूद भी इनकी बैध माना जायेगा । अनुच्छेद ३१ (व) द्वारा स्पापित नवी मनस्यों में इस प्रकार के १३ ग्रामिनियम है।

परन्त राज्य द्वारा व्यक्तित की हुई सम्पति के लिए, जमीदारी सम्पति को छोडकर मुमावजादेने के लिए अभी सी कठिनाइयाँ थी। सन् १६५४ मे जब सरकार ने घरमानी रूप से शोलापुर के सती मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया. सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस धाषार पर धर्वम ठहराया कि कोई सुमावजा नही दिया गमा था । इसके फलस्वरूप सविधान संशोधन स्थितियम १६४४ (शीवा सशोधन) पारित विधा गया, जिससे उपर्यक्त उल्लिखित कठिनाइयो की दूर किया जा सके । चौरे संशोधन अधिनियम १६५५ के अनुसार निम्नुलिखित प्रावधान किये गये।

(१) जो सम्पति धनिवायंत अजित की गई है उसके लिये मुझावजे का निर्यारण राशि के रूप में निर्धारित निया आये या विशिष्ट सिद्धान्ती का निर्धारण निमा जाये जिनके साधार पर मुझावजा दिमा जायेगा। विसी भी कानून को जिसके द्वारा राज्य भनिवाय हुए से सम्पति का सर्जन करता है विसी न्यायालय में इस कारण चुनौती नहीं दो जायेगी कि समावजा पर्याप्त नहीं है।

- (२) जहाँ पर कानून द्वारा राज्य को सम्पति ने प्रमुख ग्रीर रखने का ग्रामिकार हस्तान्तरित नहीं किया गया है, विन्तु केवन प्रवन्य करन वा ही प्रमिक्तार दिया गया है, उदाहरण स्वरूप बोलापुर मिल प्रनरण में, वहीं यह नहीं माना जायेगा कि उस कानून द्वारा सम्पति ने मनिवार्य ग्रनिन के लिए प्रायशान किया गया है, यह उक्त कानून द्वारा कियी व्यक्ति नो उसकी सम्पति से मनिवार्य माने हैं प्रीर ऐसी स्मित से मुमाबक ना प्रकर पदा नहीं होगा।
- (३) जो उन्मुक्त अनुन्धेद ३१ (अ) के द्वारा जमीदारी उन्मूलन के कानूनों को न्यायालपों के क्षेत्राधिकतर से, ऐसे कानूनों को मौलिक प्रधिकारों से समर्थ में होन की स्थिति म, दी गई थी, उस प्रकार की उन्मुक्ति को निम्नलिखित विषयों के लिए भी लाग किया गया।
- (न) कोई कानून जिसके द्वारा राज्य निसी सम्पति या उसस सम्बन्धित ग्रीवकारो को ग्राजित करता है या जिसके द्वारा ऐस श्रीवकारो को समाप्त या परिवर्तित करता है, या,
- (ख) कोई कानून जिसके डारा राज्य विसी सम्पति का प्रवन्य अपने हाय में सेता है, या,
- (ग) ऐसा क्षानून जिसके द्वारा दो या अधिक निगमों को सार्वजनिक हित मे या इनमें से किसी निगम के उचित प्रबन्ध के लिए साथ मिलाया जाता है, या,
- (प) कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी प्रवन्यक प्रशिक्ती, सचिव मा निगमों के प्रवन्यकों के प्रयिकारी को समाप्त किया जा सकता है, या,
- (ह) कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी ऐसे स्रियनारों को समाप्त या परिषत्तित किया जाये, जिनकी उत्पत्ति किसी समझीते, पट्टे या लायसेत्स से क्षित्र परार्थ या सनिव तेल लोजने और प्राप्त करने से हुई है, या ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी समझीते पट्टे या लायसेन्स को उसकी समयाबिए पूरी होने के पूर्व ही समाप्त किया गया है।
- सन १६५५ के भीथे सर्विधान सभीयन के फलस्वरूप नवी प्रमुक्ती में उस्तेखित १३ प्रीयिनियमों की सस्या में वृद्धि करके कुल २० प्रयिनियम कर दिय गये।

सर्वेप में, १९११ में चौथे सर्विधान संबोधन प्रधिनियम के लागू होने के कलस्वरूप राज्य द्वारा सम्पति प्रधिगृहीत करने पर मुखाबचे के प्रस्त पर प्रधिप्रहण कानून को ज्यायालय म चुनोती नहीं दी जा सकती है। मुपाबचे के विषय पर स्ववस्थापिक का निर्णय प्रतिन्य होगा। "यदि सम्पति का प्रधिकार ज्याय्य नहीं है तो अब वह मुन प्रधिकार नहीं रहा है। क्योंकि मुल प्रधिकार की विशिष्टता मह है कि इसको न केवल कार्यपालिका की स्वेच्छावारिता किन्तु विधायी बहुमत को निरकुतता के विरक्ष भी अत्यामुत किया जाता है। यह पहलू मन सम्पति के प्रीपनार पर, जो मूल प्रियक्तरों के प्राथम में निहित है, कम लागू होता है। दूसरे शब्दों में जहीं तक सम्पति के प्रीपकार का सम्बन्ध है, ससद ही सम्बन्ध में हैं।

ХŞ

सत्त्व सनुष्हेद २१ के सन्तर्गत यदि राज्य निश्ची सम्पति को सार्वजनिक द्वीरम के लिए स्पिन्हेंनिक करता है, तो १९५५ के जीवे साधोपन प्रियनित्तम के प्रमुक्तर कुमावजे के प्रमुक्त पर न्यायामय मे चुनीती नहीं सी जा सकती। पर का सहस ने जब वेक राज्येयकरण कानून पालित क्या तो हर कानून को सर्वोच्छ ग्यायासय के समक्ष चुनीती सी गई थी। सर्वोच्च न्यायानय ने प्रमुच्छेद २१ की ज्यास्था मरते हुए निर्मय दिया कि मुखाबना अनपुरक नहीं होना चार्थि मुखाबजे के निर्मारण से न तो गणत सिद्धान्तों को लागू करना चाहिये और न ही सही विद्वानते की उपेका परणी चाहिये।

सर्वोच्य नामाणना ने यह निणंच भी दिया चि मुखायने के प्रश्न से सम्बाध्य से में सेक्स प्रमुख्य ११ परन्तु धानुष्येद ११ (१) (एक) शरी धानयमन्त्राभी भी भी मूरा निया जाना चारिय । सनुष्येद ११ (१) (एक) प्रारंव मार्गाफा के सम्यति प्रश्न के प्रारंविक मार्गिक को सम्यति प्रश्न के प्रारंविक प्रश्न स्वाध्य स्वध्य स्वाध्य स्वाध्य स्वध्य स्वध्य स्वाध्य स्वध्य स्वाध्य स्वाध्य स्वध्य स्वध्य

बच्चीक्षर्वे संघोणन के दो मुख्य भाग हैं। यहले माग ना उद्देश्य ११ में संघोषन करता है। जेता देवा जा चुका है, अनुव्येद्ध ११ के ब्रावर्क्त यदि राज्य सार्वर्जनिक उद्देश्य ने नित्त सम्पर्धि धर्मितन करता है तो उसके लिए मुख्यस्वा देता होता। व्यक्ति, मुसाववा स्माय नहीं होता। पच्चीक्षर्वे संघोषन धर्मित्यम के धनुसार

१ एम० वी० पायसी—'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० १३०।

सविषान म से 'मुझावजा' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'राशि' शब्द रसा गया है।

पच्चीसये सथोधन प्राथिनयम ना दूसरा भाग अनुच्छेद ३१ म एन नई धारा ३१ (सी) जोडता है। इस नई धारा ३१ (सी) वे अनुसार यदि निसी नानून म यह निला है कि इसका उद्देश्य उन राज्य नीति निर्देशन तत्वा नी विमानयम करना है जिनका उन्देश्य उन राज्य नीति निर्देशन तत्वा नी विमानयम करना है जिनका उन्देश्य हमाज में मीतिन सापनो ने विताय हारा सामान्य हिन भी आदि नरना पढ़ेश्य माज में मीतिन सापनो ने विताय हारा सामान्य हिन भी आदि नरना एवं धन तथा उदायदन के साधनों ने एवंधीवरण वो रोगना है तो निसी व्यक्ति में यह प्रधिवार नहीं होगा नि ऐसे वानून को अनुच्छेद १४, १६ एव ३१ के प्रायार पर चुनीनी दे। इसने प्रतिर्देश, इस अवार ने वानून को, जिसरा उद्देश्य उपर्युक्त राज्य नीति निर्देशन तत्वों का क्रियान्ययन करना है, किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनीनी नहीं दी जा सवेगी कि उसने द्वारा उक्त नीनि मा क्रियान्ययन नहीं किया गया है।

पच्चीसर्वे संशोधन अधिनियम की कडी आलोचना की गई है, जिसके निम्न-लिखित पाषार हैं।

१---इसके परिणाम स्वरूप मूल प्रधिवारी की वस्तुस्थिति यह हो गई है कि इनको राज्य के कीति-निर्देशक सरवो के प्रधीन कर दिया गया है।

२—इस संगोधन अधिनियम हारा थारा ३१ (सी) जोडने से एक ऐसी विधित्र स्थिति हो गई है कि बदापि मूल अधिकार सविधान मे तो है, परन्यु सात्तव म इस नई ३१ (सी) धारा की झाड मे मूल अधिकारो को यम या समाप्त विया जा सकता है।

यह विचित्र-ता लगता है नि जबनि किसी मूल प्रविकार में सशोधन के लिए साद के उपित्रवा और सतदान वरी वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत भावस्यन है, प्रमुच्छेद ३१ (सी) वे अन्तर्गत कानून, जो मूल प्रविकारों के विवद्ध ही सनता है, व्यवस्थापिना समा वे केवल साधारण बहुमत से पारित निया जा सकता है।

४—ऐसे कानून को, जिसका उद्देश्य राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो का क्रिया-न्वयन व रता है नागरिक इस घाघार पर चुनौती नही दे सकता है कि वास्तव मे उक्त कानून द्वारा नीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन हो सकेवा या नहीं। समवत इसका परिणाम यह हो सकता है कि ऐसे कानून से यदि मूल अधिकार राजनीति निर्देशक तरवो को क्रियान्वित करने के प्रयत्न में समाप्त होते हैं परन्तु वास्तव में राज्य नीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन नहीं हुमा है, तो जनता की एक साम दो ग्रन्थायो को सहना होगा।

५--- पारा ३१ (सी) के बनसार राज्य विघान समाएँ मी ऐसे कानून पारित कर सकती हैं जिनसे मूल अधिकारो का हनन होगा । यद्यपि साधारणतया किसी राज्य विचान समा को एक मूल अधिकार में भी सशोधन करने का अधिकार नहीं है, किन्तु घारा ३१ (सी) वे बनुसार यदि कोई विधान समा ऐसा भानून पारित ब रती है जिसमे यह लिखा है कि उक्त कानून का उद्देश्य किसी मीति-निर्देशक हरव का क्रियान्वयन करना है, तो इसके बावजूद कि यह कानून मूल मिनकारी का इनन करता है, वह वैध होया ।

६--- मन्त मे, पच्चीसर्वे संशोधन अधिनियम से धल्पमतो के अधिकारो पर जो कि सबिधान के अनुरुद्धेद २५ से ३० में निहित हैं, धाधात पहुँच सकता है। धन तथा भाधिक सत्ता के नेन्द्रीयकरण को रोकने के बहाने भल्पमती के विभिन्न प्रविकारी का कानून द्वारा प्रतिक्रमण किया जा सकता है।

ग्रत: प्रचीसर्वे सविधान सकोधन के फलस्वरूप, सम्पति के प्रधिकार का धिस्तत्व पर्णे रूप से व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्मर हो गया है।

#### सबैधानिक जपचारों का स्रधिकार

नागरिको के उपर्युक्त छ. भूल व्यथिकार जिनका बच्ययन किया गया है. प्रथक सत्तापूर्ण या सकारात्मक अधिकार हैं। परन्तु नागरिको को प्रवत्त सातवाँ मूल प्रथिकार, वास्तव में 'प्रक्रियात्मक अधिकार' है क्योंकि इस श्रीयकार के प्रन्तर्गत, . मन्य किसी अधिकार के लिए उपचार प्राप्त नरने के लिए नागरिक उपयुक्त न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस अधिकार के अनुसार सविधान में जिल्लाखित प्रक्रियानुसार नागरिक अपने किसी मूल श्रविकार के उल्लंघन होने की स्थिति मे न्यायालय मे जाकर उपचार प्राप्त कर सकता है। इस सन्दर्म में प्रमुच्छेद ३२ (१) के अनुसार नागरिकों को अपने मूल ग्रविकारी को लागू परवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाने का ग्रामिकार है। ग्रनच्छेद ३२ (२) के धनुसार, मूल अधिकारों के लिए उपचार हेतू सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, मादेश या रिट जारी करने का मधिकार है। यह रिट विभिन्न प्रकार को है।

१—बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रमुक्त कर Habras Coupus लेटिन माना के कब्द का अर्थ है, 'शरीर दो !' यदि किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया गया है, तो न्यायालय इस प्टि द्वारा बन्दी व्यक्ति को पेश करने की श्राजा देता है। श्रत यह प्टि बस्तुत बन्दी बनाने वाले व्यक्ति को न्यायालय के एक श्रादेश के रूप में है कि बन्दी व्यक्ति को २४ घण्टे मे न्यायापीश ने समक्ष उपस्थित किया जाये।

भारत मे इस रिट वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जारी वर सनताहै।

२—परमादेश (Mandamus) परमादेश के लिए प्रमुक्त शंदर Mandamus सैटिन मापा का शब्द है, जिसका प्रयो है—'हम आजा देत हैं।' इस दिट द्वारा उपयुक्त न्यायालय किसी व्यक्ति या सस्या को यह मादेश दे सक्ता है कि वह सपने हानून द्वारा निर्धारित कर्तव्यो तथा द्वायत्वो का समुचित, रीरयानुसार निर्वाह करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी मिल मे अपना कार्य करते हुए कोई अमिक हताहुत हो जाता है तो मिल अपिकारियों को अमिक को प्रमिन कानूनों के मन्तर्गत उचित मुजाबना देना चाहिये। यदि सुप्रावजा नही दिया जाता है हो बच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी कर मिल अधिकारियों को इचित मुजाबना देने के लिए बाध्य क्या जा सकता है।

३---प्रतिषेष (Prohibition) यह दिट एक उच्च न्यायालय हारा निम्न-न्यायालय के लिए निम्नलिखित कारण वशा जारी की जा सकती है।

(1)--यदि निम्न स्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, मा,

(11)--प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है।

यह रिट किसी ऐसी सस्थाके विरुद्ध भी जारी नी जा सनती है जिसनी भर्देग्यायिक ग्रविकार प्रदक्त हैं।

Y--उरप्रेषण (Certiorar) Certiorar। शब्द का धर्ष है---'पूर्णतम सूचित होना ! इस रिट के श्रद्भार विसी उच्च न्यायालय द्वारा निम्न स्यायालय या ग्रद्धं न्यायिक प्राधिकारी को गह आदेच दिया जाता है कि वो मुक्दमा उसके समझ विचारार्थ पड़ा है उसे उच्चतर न्यायालय के सम्मुख सेज दे। उरप्रेयण रिट को जारी करने के दी नारण है।

(क) यदि किसी निम्न न्यासालय या प्राधिकारी नो कानून के झन्तर्गत मुकदमे पर विचार नरने का प्रधिकार है, या

(ख) यदि भन्याय होने का डर है।

५—प्रिंघकार पृच्छा (Quo Warranto) Quo Warranto का प्रयं है— 'किस मिषनार से।' इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को, जो निसी पद पर कानून के बनुसार निर्वाचित या नियुक्त नहीं हुमा है, परन्तु जो उस पद वो ग्रहण निये हुए है, या उस पर दावा करता है, यह धपने दावे का समर्थन करता है। घत यह स्पष्ट है कि ग्रविकार-पुच्छा रिट नो लागू करने का उद्देश्य किसी पद के अवैधानिक रूप से धारण किये जाने की रोकना है।

सर्वेषानिक उपचारो का मूल अधिकार दो प्रकार के आश्वासन देता है। सर्वप्रयम, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका पर सविधान मे इस प्रधिकार के

होने से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक खबरोध है जिसके कारण वे नागरिको के मूल प्रियकारों का उस्लघन करने वे लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। द्वितीय, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकार का व्यवस्थापिका या कार्य-पालिका के कार्यों द्वारा हनन होता है तो पीडित नागरिक को सबैधानिक उपचार

का भारवासन है। "जो रिट (लेख) हमारे सविधान मे उल्लेखित हैं, वे मूल हैं।

यह व्यवस्थापिका पर एक सीमा के रूप मे हैं। सविधान द्वारा सर्वोच्च न्यामालय की यह प्रधिकार प्रदत्त निये गये हैं, और इन दिट को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि स्वयं सर्विधान का संशोधन ऐसे साधनों द्वारा जो व्यव-स्थापिका को प्रदत्त है, नहीं किया जाता है।"? नि सदेह सबैधानिक उपचारो का धरिकार सबसे महत्वपूर्ण प्रियकार है।

यह मधिकार सबसे महत्वपूर्ण मधिकार है। यह मधिकार मन्य मधिकारों का पोषक है। सविधान समा में, अनुन्धेद ३२ के सम्बन्ध में अपने विधार प्रकट करते हुए डा॰ प्रम्बेदकर ने कहा--"यदि मुक्त से सविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के लिए पूछा जाय-ऐसा धनुच्छेद जिसके जिना सविधान निर्यंक हो जायेगा. तो में सिवाय इस अनुच्छेद के किसी अन्य अनुच्छेद की धोर सकेस नहीं कहेंगा । यह संविधान की खारमा है. जसका हदय है।"<sup>3</sup>

१. एम॰ जी॰ युप्ता—बास्पेक्ट्स बाफ द कान्स्टीट्युसन बाफ इण्डिया, पृ० ११८, सन् १६६४ ।

२। बी॰ प्रार॰ शम्बेदकर-कालरीट्रएन्ट झसेम्बली डिबेट्स, प्राग-६ स॰

¥ E

<sup>1</sup> ER3 OF FF

## राज्य नीति-निर्देशक तत्व

प्रापृतिक युग म लोक्तन ने सन्दर्भ म राजनीति कितान ने प्रन्तगैत यह सत्य है कि लोक्तन ने दो पहलू होन हैं (1) राजनीतिक सौर (11) प्राध्मि । साधारणतया एक लोकजानिक संविधान का उद्दर्श राजनीतिक लोक्तन ने स्था-तरा करता होना है निन्दु धाविक समानता को धनुपस्थित म राजनीतिक स्व-तत्रता का कोई मूल्य नहीं होगा । मत्यूच राजनीतिक लोक्तन ने लिए सविधान मे प्रावधान प्रपन्ने धाप मे पर्योग्न नहीं हैं । इस कारण राजनीतिक लोक्तन की कही नी सत्तक करने के लिए धार्यिक लोक्तन का होना प्रत्यत्त प्रावध्यक है। जिस देगा म राजनीतिक लोक्तन ने सवस्तक करने के लिए धार्यिक लोक्त नहीं है वहाँ निरकुमता को स्थापना में निक्ष्य ही देर नहीं होगी । यदि मूल प्रविकारी द्वारा मारन म राजनीतिक लोक्तन का प्रावधासन दिया गया है तो राजनीनि निर्देशक तरव भारत में वास्तविक लोक्तन के विकास के लिए धारवासत दिया गया है जिसने उसकी (राजनीतिक लोक्तन के विकास के लिए धारवासत दिया गया है जिसने उसकी (राजनीतिक लोक्तन के निए सबस यहां धारवासन दिया गया है जिसने उसकी राजनीतिक लोक्तन के निए सबस यहां धारवासन है।"

प्रव प्रस्त यह है नि राजनीतिक सोनतत्र ना क्या धर्ष है ? राजनीतिक सोनतत्र ना क्या धर्ष है ? राजनीतिक सोनतत्र ना प्रमिश्यत यहुमत के प्राथात्र एवं सरकार निर्माण ने सिए नागरिका ने प्रायात्र र स्थापित है, प्रयांत्र ऐसी सरकार जिसके निर्माण ने सिए नागरिका ने प्रायात्र व्यक्तित्र धोर राजनीतिक स्वतत्रवाधों ना पूर्ण उपयोग किया है प्रीर जो विधि सासन पर भाषादित होते हुए नायरिको के विचारों को मिश्यतित तथा सगठन निर्माण करने को स्वतत्रता प्रदत्त करती है।

नि सदेह, राजनीतिक सोकतन की धावस्थनताधा को भारत के सविधान के धन्तांत मान्यता दों गई है। परन्तु धाषिक लोकतन के उद्देश्य को पूर्ति के लिए मान्यत मिन्यत्त स्वकारों पर स्विधान के स्वतंत्र में जारताधित करता प्रता निविधान सकारों पर सविधान है। जैसे डा॰ एस॰ सी॰ डेस का कहना है— वामाजिक एव धाषिक सेनो से

१. एम० बी० पायली, 'इण्डियाज कान्स्टीटयुशन, १९६२ पु० १५४ ।

प्रभी भी मारत का गभीर उत्तरवायित्व है। सक्वीतिक लोकतव का समाज की उन सीमाप्यों को जो समाज के विकिन्न वर्गों में भेदमाव स्थापित करती है, दूर किस दिना राजनीतिक लोकवन का कोई खर्म नहीं होगा । इसी प्रकार, गरीबी

तथा जीवन ना ब्रह्मिन निम्न स्नर मास्त की जनता ने राजनीतिक पिठडेपन के नारण थ । मामन्तवादी जमीदार बीर पूजीपति सरलना पूर्वन राजनीतिक प्रिंपिकारों में व्यापार करके जनता के राजनीतिक जीवन को घटन वर सकते हैं.

क्ष नारण यो जासनावादा जनावाद आर पूजायात चरणा पूजा जिलागा है प्रशिकारों में स्थापार करके जनता के राजनीतिक जीवन को अस्ट कर सकते हैं, यदि सात्रारण नागरिक को ध्यनी स्थावस्थकताओं और पूज से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है।"भ

बस्तुन, विद्या धर्माचन लोश्तन के राजनीतिक सोशतन केवल इस्प्रतात के सपूज ही होगा। सोशतक स राजनीतिक स्वनवताएँ प्रयक्ति हैं, जब तक नाम-रिकों का नामान धर्मिक धरवार नहीं प्राप्त है। ये व जबारहाता ने हिए ते सिर्याप पर प्राप्त किया पर स्वाप्त केविक स्व विद्याप पर प्राप्त कियार जबर करते हुए कहा है— हम स्थानका की वर्षा करते हैं, विद्युजन तक धर्मिक स्वनवता नहीं है, तुर्ज तक केवल राजनीतिक

स्वननना ही हुँसे साथे नहीं ने जा सक्दी । वास्तव में, एक व्यक्ति जो जूना मर दहा है या एक देश जो गरीय हैं, उसके लिए स्वनत्रता ना नोई समें ही नहीं हैं।" समाज में साथिक सन्यमनतासों के विश्वसन होने से, राजनीनिक स्विवनर

प्रत्याबहारिक हो जाते हैं। ग्रो॰ हेरस्ट लाम्की का क्यन है— 'दसका तारप्य है कि कम मारनागरी व्यक्तियों की जीतिक तथा बीडिक करिम्पित्या का निरहुक-बाहुक्क निपारण करना। इसका ताराये है सरकारी-यश का नियनका, उनकी हार्कि के तिय करना।"

ण्यमः ग्रांतिरित्त प्रा॰ साम्की कहते हैं—"राजनीतिक समानना वाम्तविक नहीं है, यदि इमके साथ आधिक ममानना नहीं हैं, अय्यक्ष राजनीतिक सत्ता (प्राधिकार)

साबिर सत्ता ने नवर मायन ने रूप य हा जायगी। "" राजनीनिर क्षेत्र म खीवरारा ना नोई उपयोग नही रह जाना है—बल्टि प्राय दुरुपमार ही होना है, यदि भाषरियों नी खाबिर आवारवतायी नो पूरा

प्राय दुरुपनाम हो होना है, यदि शावरिको की आर्थिक शावत्रपकताम्यो की पूरा नहीं क्या आना है। उदाहरण क्यूक्त साम चुनाव के दौरान प्राय पैसा कथन है एमंग सी॰ केस—'क कामटीट्युसन स्वयक्त होन्द्रया', १६६०, पु०

४३२। २. प॰ नेहरू-'द कवीन्टऐसेन्स बाफ नेहरू' (के॰ टो॰ नर्रासह घर द्वारा सम्पादित) ११६६, पु॰ १४६।

३. एवं सास्त्री—'ए बामर ब्रान्ड पालिटिक्स', १६३७ मृ० १६१।

४. एव० सास्त्रो--'पूर्वास्त पुस्तक' पृ० १६२ ।

पर धायिन मारो से लदे हुए गरीब मतदाताओं नी विनिन्न प्रसार ने लोगों से निसी एक पक्ष में मत देने ने लिये प्रमावित तथा अग्द नरते ने प्रयत्न विच जाते हैं, जिससे बुरे परिचाम इस सास नी पुष्टि नरते हैं कि राजनीतिन सोवतत ने सामक बनाने के लिए नामिलने ने धायिन चारपणताओं ने पूरा करते ने नाम में मा प्रावित में सामिल मा अग्वस्ताओं ने पूरा

राजनीति विशान वो इन पारणाया वे सन्दर्भ में जनुतानि विवासी में नागरिको वे राजनीतिक एव स्वायिक स्विपनारो को मुद्दुन्त्रिको इता दिवे। जाना है। इन राजनीतिक एव स्वायिक स्विपनारों के सम्बन्ध में मुर्गिया है दो पूर्वक रूप होते हैं। सविधान म उल्लिखित राजनीतित स्वीयकारा द्वारा पूर्वम क्षेत्र स्वापित निया जाता है, जिसमे राज्य (सर्रगार) का हम्मूण सर्वधान निक्स माना जाता है। अतएव राज्य (सर्रगार) को मूमिका, राजनीतिक स्विपारों के सत्य में नवारा मक है। कुन्तर, एनी परिम्बिन में जब विभी भूत राजनीतिक स्विवार का उल्लियन हुस्ताई, स्वीययोजिका की सुनिया का प्रकर्म पदा होता है।

इसरे विपरीत, सुविधान में चल्लियित विभिन्न ग्राधिन ग्राधिरारो, बदाहरण स्वरूप-मारतीय सर्वियान मे राज्य नीति-निर्देशन तरवी मे निहित ग्राधिक प्रियारो वा क्रियान्यय राज्य सरकार वी सरारात्मक भूमिका से ही समय है। इन प्रधिकारों को समिधान से रधने के फलस्वरूप, राज्य के नागरिकों के प्रति निर्दिषय महत्वपूर्ण नर्त्तस्यो का निर्दारण होता है। "सरकार वा स्वरूप प्राप्तिरः बार विसी उद्देश्य की प्राप्ति के निए बेवल एक साधन ही है। स्पतनना भी में वल एक साधन है, अबिक उद्देश्य है-लोग बरयाल, मानव प्रगति व गरीबी. बीमारी और पीडा को समाप्त करना और प्रत्येक व्यक्ति को मीतिक तथा शीटिक दृष्टि से 'मच्छे-जीवन, व्यतीत बरने का धवसर प्रदान बरना ।" विस्तृत सरकार . एन प्रमिक्रण है जिसका उत्तरदायित्व नागरिको के 'बब्छे जीवन' को सविधान में निहित राजनीतिक, प्राधिक और सामाजिक अधिकारों के अनुकृत व्यापहारिक हम देना है। यह नि सदेह सत्य है कि राजनीतिक स्वतत्रना एव सायन ग्रीर एक भावस्वक सावन है, जिसके द्वारा सामाजिक-मायिक उद्देश्यों को प्राप्त निया जा सकता है। "परन्तु राजनीतिक स्वतत्रता अपने में केवल एक उद्देश्य नहीं ही सकती है। वास्तव में राजमीतिक स्वतंत्रता का इस देश के करोड़ो लोगा के लिए मोई महत्व नहीं जबिर वे गरीवी तथा उससे उत्पन्न विभिन्न सामाजिक बराइयो

१. प॰ नेहरू-'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० १४७ ।

से पीडित हैं और जब तक उनको राजनीतिक स्वतनका में निहित सामाजिक-प्राधिक प्रपिकार प्राप्तासित न किये गये हैं।"ै

राजनीतिक स्वत्यता को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रास्त के सिष्मात निर्मातायों ने सिष्मात ने नामरिकों के राजनीतिक, सामाजिक एव प्राणिक सिकारों ने स्वर्ण पर ने ने देशा जा चुका है, सिष्मात की प्रस्तावना से नामरिकों के ये सिष्कार प्रतिविभिन्न हीते हैं। पुख्यत सिकारों के से सिष्कार प्रतिविभिन्न हीते हैं। पुख्यत सिकारों के स्वर्णाय सीन में निक्क सुवाधिकारों ने गर्व है, उपत्रिक्तिक लोचिक मोलद में प्रतिविभिन्न लोचिक नी नीत स्वर्णाय के महि है। पाननीतिक लोचिक सिकार के सिकार का सिकार के समुख्येद ७४ (३) चीर अपुन्धेद ८१ (१) (ए) में स्वर्ण्य रूप से देशा जा सकता है, जिनके हार कामस्त मणीमदल ने सामृतिक लाखतायां से सिक्राल तथा स्वर्ण है के सिकार करना सुन्धेत है तिए प्रस्ता

इसी प्रकार धार्मिक लोकतन की नीच पुत्रेयत नारतीय सर्विधान के प्रध्याय चार में समावेशित राज्य नीति-निर्देशक दादों के क्य में है। घतएब मारतीय सर्वियान में नागरिकों के दो प्रकार के धियकारों पर कल दिया गया है (१) राजनीतिक तथा (२) धार्मिक एवं सामाजिक। ये एक इसरे के प्रकार है।

निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी गई है।

मारतीय सिम्मान के सम्याय चार में पिल्लिक्त राज्य नीति-निर्देशक सत्त्व किया निर्मात में अध्याय चार में पिल्लिक्त राज्य नीति-निर्देशक सत्त्व किया निर्मात में अध्याय सायरतेण के स्विचान में प्राच्य नीति निर्देशक तथ्य में स्वाच्य के सुनुद्धे ४५ के सायर राज्य सायराज में सम्म नीति निर्देशक तथ्य सायरतेण के स्वीच्यान की तुल्या में, स्विक्त सत्त्व में भीर निर्मात कार सायरतेण के स्वीच्यान की तुल्या में, स्विक्त सत्त्व में भीर निर्मात कार्य के स्वीच्यान की तुल्या में, स्विक्त सत्त्व में भीर निर्मात कार्य करता है, चारता में निर्मात निर्मात कार्य करता है, चारता में निर्मात निर्मात निर्मात करता है। भारता में निर्मात निर्

राज्य नीति निर्वेशक तत्वो द्वारा एक ऐसा सेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमे राज्य (विजित सरकारो) नी सकारात्मक सुमिका सपेक्षित है। सविधान के

र पी बो मनेन्द्रगडकर—सा, सिवर्टी एण्ड सोशल जस्टिस, १६६४, पु॰ १२४–१२४ ।

२. सी । एत्केबेन्डरोविवब-कान्स्टीट्यूशनल हैवलपमेन्टस इन इण्डिया,

got of ax3}

सनुन्देद ३७ के झनुसार ये सिद्धान्त (राज्य नीति-निर्देशक तस्त्व) देश वे प्रशासन में मूल हैं और राज्य का यह नर्तव्य है कि बानून-निर्माण कर इन सिद्धान्तों को सामू करें। भारत के सिवधान निर्माताओं को इस बात के लिए धेय दिया जाना चाहिए है कि प्राधिक लोकतत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने सीन कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए राज्य नीति-निर्देशक तस्तों क्ष्मी साधनों के लिए भी प्रायान किया, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्राप्त विया जा सके। धी दो के टोपे के प्रमुत्तार—"एक लोक कल्याणकारी राज्य को प्राप्त विया जा सके। धी दो के टोपे के प्रमुत्तार—"एक लोक कल्याणकारी राज्य को प्रमुत्त विवास तिला हैं।

- (१) सरकार के कार्य क्षेत्र, मे निजी स्वामित्व की घाषित सस्यामी वे नियन्त्रण के लिए व्यापक वृद्धि ।
- (२) राष्ट्रीय समाज के प्रत्येक सदस्य यो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदत्त करना-सेरोजगारी तथा सेवा निवृत्ति सर्वायत लाम, परिवार सवधी मले, कम रार्च पर गृह-निर्माण, चिकित्सा सेवा धादि ।
- (३) ऐसे उद्योगो एव व्यापार में सरवार के स्वामित्व तथा वार्यों में वृद्धि जिनका सचालन व्यक्तियों या निजी निमनो द्वारा निजी साम प्राप्त करने के लिए हो नहा था, या, होगा।""

राज्य नीति-निर्देशक तत्वो का जिर्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्वापना करना है। इनके द्वारा जनता के प्रति तत्ताक्ष्व तथा क्षम्य राजनीतिक दली के तत्व्यों का स्पर्टीकरण क्षिण क्षमा ग्रा है। "निने द्वारा राजनीतिक दली की प्राप्त कर्त्यों का स्पर्टीकरण क्षिण नामूने पर, जब इनकी सविधान के प्रमुतार सरकार सवाजित करने के लिए प्राप्तनित किया गया है, प्रवरोध समाया जाता है। यह सत्य है कि यह म्याम्य नहीं है, किन्तु ब्रिटेन में मेन्याकारों एव प्रमरीका में स्वत- क्षात के पीएणा पत्र के सदूष इतिहासी की मान्याक्षी स्व, सविधान तथा देश के कानून की व्याख्या करते समय प्रवस्य प्रवालित होते।"

मारतीय सविधान के कौथे घष्णाय से धनुक्छेद १६ से ११ तक विभिन्न राज्य-नीति निदंशक-तद्यों का उत्लेख किया गया है। इनसे मारतीय नागरिकों के वृति-पय महत्वपूर्ण माधिक तथा सामाजिक प्रधिकार निहित्त है। सविधान के धनुसार किन्नीय भीर राज्य सरकारों को प्रपन्ने देकिक अशासन से इन सिद्धान्तों को क्रिया-ज्वित करना सावस्थक है। राज्य नीति-निदंशक तत्व निम्मलिखित है।

१--राज्य, विशेषकर, भ्रपनी नीति का निर्धारण, इस हेतु करेगा कि,

१. टी० के टोपे—'द कस्स्टिट्यूशन आफ इण्डिया' १९६३ पृ० २०० । २. 'वही' पृ० २००-२०१ ।

(क) समस्त नागरिको, पुरुष तथा स्थियो को पर्याप्त जीविका अर्जन करते था प्रधिकार हो;

(स) समाज के मौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार विज-रित हो जिससे सामान्य रूप से जनहित समय हो ।

 (ग) देश की भ्राधिक व्यवस्था का सवालन इस प्रकृप न हो जिससे घन का केन्द्रीयकरण होते हुए सामान्य हित को हानि पहुँचे ।

(ष) पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान बेतन मिले,
 (ङ) श्रीमको, (पुरुष एव स्त्री) तथा कम बायु के बालको के स्वास्थ्य मौर

(इ) श्रीमको, (पुरुष एए स्त्री) तथा कम आयु के बातकों के स्वास्थ्य और स्रीवत का ग्रीपण न हो चौर नागरिकों को वपनी धायिक धावस्थकताभी की पूरा करने के तिए उनकी सायु तथा सन्तिव के दुन्टिकोण से अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए साव्य न होना पढ़ें.

च-वचपन एव युवाबस्या का शोषण न हो, तथा नैतिक एव भौतिक परि-

र्याम से जनका सरक्षण हो (मनुष्केंद ३६) २—राज्य द्वारा भाम-पश्चायतो को संगठित करने की दिशा में करम खठाये जायेंगे भीर राज्य जनको भावस्यक मनिवर्गा प्रदत्त करेगा जिससे वे स्वायत-वासन

की इकाइयों में सद्बा कार्य कर सके 1 (अनुक्देद ४०) ३—राज्य प्रापनी क्षाचिक समतायों के दायरे ये नागरिकों के लिए नौकरी सीर गिक्षा की व्यवस्था करेगा और युदायस्था, बीमारी एव बेरोजगारी या सम

हानि होने पर सार्वजनिक सहायता करेगा (धतु-धेद ४१) ४—राज्य व्यम तथा प्रसृति सहायता से सवधित अर्थो को भानवीय स्वरूप

४—राज्य श्रम तथा प्रसूति सहायता से सर्वायत शेला को देने के लिए प्रावधान करेगा (अनुच्छेद ४२)

२ का ताय भागना करना (महुन्याय - प्रमुक्त प्रस्त थानको को हुनि, उद्योग द्या धन्य नायों से सबवित उपमुक्त जीनिका एव कायों की वार्तों के लिए प्रायमन करेगा विससे जीवन का उच्छा स्तर स्थानित हुते को तथा नायिक सामिक और सामहृतिक धनसरो ना उपयोग कर सकें। राज्य व्यक्तियत और सहुकारिता के सामार पर लम् उद्योगों को प्रोस्ताहित मरेगा। (सनुन्येद ४३)

६---राज्य सम्पूर्ण मारतीय प्रदेश में नागरिकों के लिए एक समान ब्यवहार सहिता उपनन्त्र करवाने का प्रयत्न करेगा । (धनुन्हेंद्र ४४)

प-राज्य सर्विधान के लागू होने के दस वर्षों से चौदह वर्ष तक की झायु के
 समस्त बातकों को प्रनिवार्ष शिक्षा देने के लिए प्रावधान करेगा (अनुच्छेद ४५)

६—राज्य दुर्बल वर्गों के विशेष कर सनुसूचित कातियो तथा पिछड़ी जातियों के, विक्षा धौर शांषिक हिंदों नी उर्जित के लिए व्यवस्था करेगा और उनका सामाजिक प्रन्याय तथा सन्ध प्रकार के शोषण से रह्या नरेगा। (सनुच्छेद ४६) ६—राज्य प्रपनी जनता के प्राहार सबयो एवं जीवन के स्तर को ऊँचा करने के तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मे सुचार करने के वार्यों को प्राथमिक महत्व देवा तथा यह प्रयत्न करेगा कि उन मादक पैयो को छोड़बर, जो चिविरसा में प्रावश्यन हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारव है, उनका निषेष हो। (समुच्छेद ४७)

१०—राज्य कृषि एव पशुप्तालन का धायुनिन धौर वैक्षानिन प्राधार पर सचालन करेगा, विशेष तौर से गोवश के सरराण धौर नहन भे गुपार ने लिए तथा गाय, बखड़े, दूध देने वाले भारवाही पशुष्ता ने वय का निर्धेष करने का प्रयास करेगा। (मनच्छेद ४६)

११—राज्य का यह कलंक्य होगा नि प्रत्येक स्मारन या गतारमन लगा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्यपूर्ण स्वान या वस्तु ना, जिसनो ससदीय नानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व ना निर्धारित नर दिया नया है, सरक्षण नरे। (प्रनुष्टेद ४६)

१२ — राज्य द्वारा न्यायपानिका को कार्यपालिका से पृथव व रते वे लिए कदम उठाए जायेंगे।

१३-राज्य द्वारा निम्नलिखित विषयो के सबध में प्रयत्न किये जायेंगे ।

(क) ग्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ग्रीर सुरक्षा की उन्नति के लिए,

(क्ष) राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण धौर सम्मानपूर्ण सबयों को बनाये रखन के लिए,

प्रा प्रस्तर्राष्ट्रीय विधि और और सिंघयों में निहित क्त्तंच्यों के प्रति
 राप्ट्रों के व्यवहार में झादर बढाने के लिए,

(प) ग्रन्तर्राय्ट्रीय वाद-विवादों को पच-निर्णय द्वारा निबटाने के लिए ।

(प) कराराज्य नार्वाचित्रका स्वयं प्रस्ति के सिक्षा प्राचन नीति-निर्देशक तहने कि स्वयं नागरिकों के सामाजिक तथा प्राधिक प्रियक्तार से हैं। ये प्राधिक प्रियक्तार से सिक्षार से कि से मूल प्रधान है। राज्य नीति-निर्देशक तहन सुल प्रधिकारों से इस दृष्टि से मिन हैं कि मूल प्रधिकार न्याय हैं, प्रयांत् इन के पीछे न्यायालयों की प्रसिक्त हैं, किन्तु राज्य के नीति निर्देशक तहन न्याय्य नहीं है। तथापि, देश के प्रधानत का ये मूल प्राधार है। प्राध्ति संविध्य संविधान में नागरिकों के मूल प्रधानत रेवा राज्य नीति निर्देशक तहन्य भे प्रधानत का ये पूल प्रधानत है। प्राध्तिक समय में जनतत्र के दो सुबक्ति पहनुयों-क्यित तत्रता और लोक कत्या के ने प्रधानता और स्वा राज्य के निर्देश निरु स्वा संविधान के प्रत्यंत लोकता के इन दो पहनुयों के प्रधान के प्रत्यंत लोकता के इन दो पहनुयों के प्राप्ति के सिए प्रदेश निरु स्वा संविधान के प्रत्यंत लोकता के इन दो पहनुयों की प्राप्ति के सिए प्रदेश के लिए निर्देशित साधन, मूल प्रधिकार प्रोर राज्य के नीति निर्देशक तहन, मी एक द्वार के पुरक है क्योंकि इनके माध्यम से ही मारत में सही प्रप्त से साई प्राप्त से सही भारत से सही प्रप्त से सही क्या क्या है। प्राप्त में स्वीनतर स्थापित किया क्या है। प्राप्त प्रच्ये के नीति-निर्देशक तहने साधनतर स्था स्वी

٤¥

ग्रालोचनाको जानी है, कि यदि राज्य इनका पालन नही करता हैं तो इनका क्रियान्वयन न्यायालयों डारा, मूल अधिकारी के सदश नहीं विया जा सकता है। इम देष्टि से, ग्रालोचनो ना नहना है कि इननी सविधान में रखने ना नोई महत्व नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो को न्यायालयों द्वारा लाग नहीं करवाया जा सकता है; किन्त ये सिद्धान्त वर्तमान ग्रीर मिया में मतारह होने वाले राजनीतिक दलों के लिए एक निरन्तर चैतायनी है नि इन सिद्धान्ती का दैनिक प्रमासन में उपयोग होना आवश्यक है, धन्यमा जनता प्रति पाँव वर्ष के बाद ग्राम चनाव के दौरान सत्तारूउ दल को सत्ता से हटा सकती है। ग्रतः यह सहय है कि राज्य नीति-निर्देशक तत्वीं के पीछे न्यायालयो की शक्ति नहीं है, परम्त सत्तारड दल पर इनके जियान्वयन के भदमें में नैतिक तथा मनी-बैज्ञानिक सबरोप हैं, क्योंकि वे सिद्धान्त राष्ट्रीय उहेश्यों के रूप में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ग्रन्त करण के ठोस प्रतीक के रूप में हैं। खिक राज्य नीति-निर्देशक तरकी को लागू करने के लिए व्यायासयों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यह प्रश्न स्वामा-विक है कि इन सिद्धान्तों के पीछे इनके क्रियान्वयन के लिए कीन-कीन सी शक्तियाँ हैं ? इसके लिए मुख्यत: वो शक्तियाँ हैं।

(१) मनदातागण तथा

(२) व्यवस्यापिका समा।

समदीय लोकतन से मनदाताओं की चार्ति शरकार पर एक ऐसे महत्वपूर्ण धाररोध के रूप में मानी जा सकती है जिससे सरकार को सविधान में उहिलालित खड़ेज्यों के विश्व आन से रोका का सकता है। सतदानामी तथा व्यवस्थापिका की भूमिना पर प्रकाश डालते हुए डा० बी० आर० अम्बेदकर ने कहा---"प्रत्येक सरकार दैनिक मामली म तथा एक निश्चित समय पश्चात किसी नसौदी पर रखी जायमी अविव मतदाताओं और निर्वाचकों को सरकार द्वारा दिये गये कार्यों का मुख्यक्त करने का अवसर प्राप्त हीता है अवसि हमने राजनीतिक लोकतत्र की स्थापना की है, हमारी यह भी इच्छा है कि बाधिक लोकतन के बादमें को निर्धारित करें 1" "सविधान निर्माण करने में हमारे दो उद्देश्य रहे हैं राजनीति उद्देश्य तथा सामित तथा सामाजिक न्याय नी उपलब्धि शराना ।"2

सर्वप्रयम-प्रत्यक रूप से परीक्षण ससद में ससद सदस्यो द्वारा निया जाता है। द्वितीय, चुनाव के समय सरकार की नीतिया तथा कार्यों का परीक्षण ग्रीर

मुल्यातन स्वयं मनदाता करते हैं। सरकार की नीतियो तथा कार्यों का परीक्षण १. बी भार. भन्वेदकर-कान्स्टीट्युएन्ट ग्रसेम्बली डिवेट्स-माग ७ पृ० ४६२-

<sup>¥84</sup> I २. वही पु॰ ४१।

(ईय परीक्षण) सिवधान में निर्वारित क्सीटियों ने भाषार पर ही विधा जाता है भी सत क्या जा सनता है कि सरकार की क्या उपलब्धियों या क्या मसकताएँ रही हैं। यदि सरकार ने सिवधान के अनुसार जनता की भावश्यनतायों नो पूरा किया है तो निक्यम ही जनता द्वारा सत्ता की वागडोर पून उसने सीरिन में अबल समावना होगी। किन्तु यदि सरकार ने सिवधान मं उल्लिखित जनता की भावशाम भी भवहेलना की है तो मतदाताया जो सरकार के भियत्ते की मतदाताया जो सरकार की भवताताया जो सरकार की

इस गरण सिध्यान लागू होने वे पश्चात् नेन्द्रीय एव विभिन्न राज्यों की सर-कारों ने इन सिद्धान्ती को व्यावहारित रूप देने वे प्रमत्न नियं हैं। यह प्रयत्न विभिन्न पच वर्षीय योजनाओं में विशेष रूप से प्रतिविध्वत है। सिष्यान के लागू होने के पश्चात् तीन पच वर्षीय योजनाओं म तथा वर्तमान चतुर्ष पच वर्षीय योजना के प्रमतित राष्ट्रीय विकास का जो नमूना है उद्ग सिष्यान म निह्त उद्देश्यों से सर्वाधत है। राज्य मीति-निर्देशन सत्त्वों के धनुस्त जिस तदय को प्राप्त करना है, वह है 'पमाजवारी डीचे पर शायारित समान' और इसनो दूसरी पच वर्षीय योजना में इन शब्दी में स्पट स्थायारित समान' और इसनो द्वारी के स्वाप्त में तिल् परारीटी निजी लाम नहीं विन्तु सामाजिक साम होना चाहिये और वसास ना नमूना तथा सामाजिक पार्षिक स्वयों वा द्वीचा इस प्रवार नियोजित किया जारे विन ने केवल

१ टी॰ के॰ टोपे—'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ॰ १९५।

२ एम० पो० शर्मा—व गर्वमेन्ट झाफ व इण्डियन रिपब्लिक, १९६१, पृ० ६० ।

राष्ट्रीय भाग और रोजगारी में ठौस वृद्धि हो विन्तु लोगो की बाय तथा घन मे अधिकतर समानता हो । आधिक विकास के लाग अधिकतर समाज के पिछडे हुए बर्गों को उपलब्ध हो और आय, घन तथा आधिक सत्ता के केन्द्रीयकरण मे क्रिमेक रूप से कमी होती जाये।<sup>379</sup> द्वितीय पत्र वर्षीय योजना के उपर्यंक्त उद्देश्य तथा राज्य नीति-निर्देशक तलीं

के उद्देश्य भी समानता को देखते हुए, यह निदित होता है कि इन सिद्धान्तों को एक ग्रद्भावहारिक ग्रावमं के रूप में नहीं माना गया है, किन्तु इनकी व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाने के सफल प्रयत्न किये गये हैं । कतिपय उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि वास्तव में इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप

प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। ये उदाहरण निम्नलिखित हैं। (1) पिछले बधी में समाज के भौतिक साधनी को काफी मात्रा में राज्य के नियन्त्रण में लाया गया है। जीवन बीमा तथा बैंब-राप्टीयकरण इसके क्रतिपय जवाहरण हैं। इसके अनिरिक्त, बहुउद्देश्यीय नदी योजनाएँ, जैसे--मानरा-नगल, दामोदर

घाटी योजना, हीराक्ण्ड बाध, मिलाई, राजरकेला धौर दर्गापुर प्रशात कारखाने, विशासापट्रनम का जहाज-निर्माण कारलाना, सिन्द्री साद कारसाना, हिन्दस्थान मशीन टल्स. चितरजन का रेलने इजिन का कारखाना, हिन्दुस्थान ऐयरजापट, बादि द्वारा राष्ट्र के धार्थिक विकास में सहायना मिलती है। राज्य ही इनके सचा-लन तथा प्रवत्य के लिये उत्तरदायी है।

(11) यद्यपि रोजनार की समस्या का समायान नहीं हुवा है किन्तु राज्य द्वारा रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कडम जठाये गये हैं। (111) राष्ट्र के नई हिस्सो मे, सामुदायिक विवास योजनाम्नो को प्रामी की मर्प

व्यवस्था में सुघार के लिए लागू किया गया है, इसका प्रभाव कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्रों में विशेष रूप से देखा जा सकता है।

(iv) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा ने भी शगति हुई हैं।

(v) भाषिक क्षेत्र में पिछड़े हुए वयों की सहायता के लिए क्टीर उद्योगों

को प्रोत्साहन दिया गया है।

(vi) धन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने पचशील के सिद्धान्त के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण योगदान दिवा है।

राज्य नीति-निर्देशक तत्वो में पीछे दूसरी शनित व्यवस्थापिका सभा है। व्यवस्थापिका समा का कार्य, देश में लोक कल्याणकारी राज्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के बाधार पर कानन निर्माण करना

१. द्वितीय पच वर्षीय बोजना वृ०-२२ ।

है। इतने मतिरित्त, चूनि भारत में सम्मदासम् पद्धति नो मनामा गया है, हा वानुनों ने प्रियान्ययन ने लिए नार्यणिसिना को उत्तरमधी दहराते वा प्रस्था मिनार सी अवस्थापिना नो प्राप्त है। सस्वारस्य पद्धति में नार्ययानिन (महोमहाल) व्यवस्थापिना ना एन हिस्सा होती है समा उत्तर प्राप्त होने है। साधारपन्या नार्यणिस्ता का निर्माण ससद ने निर्मान सम्म प्रस्था मिना प्राप्त कि तत्तर प्राप्त के निर्माण स्वयस्थापिन व्यवस्थापिन का प्रस्ता है। जसने परिणाम स्वयन्य प्रस्ता में स्वत्त ने स्वत्त यर उन्त राजनीतिक वेल में मा प्राप्त कि निर्माण स्वयस्थापिन का प्रस्ता है। वृद्धि सिवान के स्वनुन्देद २० वे अनुसार राज्य नीतिन हिण्य साम ने देश वे भागान स्वयस्थ साम प्रया है, जस वन को सान की साम की साम साम स्वयस्थ साम प्रया है, जस वन को सान की आप साम हिणा कर साम प्रस्ता है। इस स्वयस्थ स्वयस्य स्वयस्थ स्वयस्य स्वयस्थ स्वयस्थ स्वयस्थ स्वयस्य स्वयस्थ स्वयस्य स्वयस्थ स्वयस्य स्वयस्थ स्वयस्य स

"यह प्रतिनक्ष में हाथों में एक शक्तिकानी हथियार होगा कि यह सरकार भी निन्दा इस आधार पर परें वि जसका बार्यपानिका या व्यवस्थापा समधी

मोई मार्थ राज्य मीनि-निवेंशन तत्व ने विरद्ध है। '

ध्यनहारत ससय मे प्रनिवक्षीय दलों ने राज्य मीनि-गर्शेवर सरा वे साधार पर सरवार को सम्य-ममय पर कडी स्वीचना की है। उदाहरण स्वस्य हमा तिद्वारती वे क्रियालयन के लिए सरवार के उदारतिव्यंत्व के दृष्टिकोण से ११४० मे लीजगाम में श्री हुपार चर्र्जी (साम्यवादी दल के सदस्य) हारा प्रग्न प्रसाद राजा गाया। इस प्रसाद के वा प्रमाद करने की एक समिति निवृद्धन करने वा गुक्ताव दिया गया, जो यह जीव करती कि वित्त हद तक, राज्य नीति निर्वेषक सरोग सा सरवार के विवास करने कि स्वाम्यत किया गया, जो यह जीव करती कि वित्त हद तक, राज्य नीति निर्वेषक सरोग सा प्रसाद की विवास करने हिंदी स्वाम के स्वाम के

२. द्रिम्पून, सितम्बर १, १६४८ ।

भारतीय शासन श्रीर राजनीत ٤ĸ

नहीं है, किन्तु सरकार न सदैव यपनी नीतियों में इन सिद्धान्तों को समवेशित करन का प्रयान किया है और इन सिद्धान्तों के प्रमादों को योजना सारोग क

कार्यो तथा निर्मायो म स्पष्ट एवं में देवा वा सनता है। निस्मदत न ता मरकार इन निद्धालों के विरुद्ध कोई कार्य करेगी न ही इन मिद्धान्तों न धनिधन रहकर प्रशासन का सचालन कर सकती है। ससद में प्राप्त

मामने पर जा राज्य नीति-निर्देशक तत्वी से सवधित है, सरकार की घरने कार्यी तथा नीनिया का ग्रीकिय क्षतताना होगा, ग्रन्यया सरकार के बिक्द समद में श्रवित्वाम प्रम्ताव पारिन निया जा सकता है। इसके प्रतिरिक्त, सरकार को मनदानाजा का ग्राम चनाव के समय समयंत उस स्थिति में ही मित सकेगा, यदि

सरकार न ग्रंपन कार्यकाल में अनना के हितों को ध्यान में रण कर कार्य किये ! सक्षेत्र में, मनदाता तथा व्यवस्थापिका समा राज्य नीति-निर्देशक त'वो के पींदे धावस्यतः शक्ति है। अनु, इनके पीछे कानुनी नहीं किन्तु राजनीतिक शक्ति है। मारत के महिजान के अन्तर्यन नागरिकों के मुख प्रजिकारों तथा राज्य नीति-निर्देशक तत्वाम मिलता केवल यह है कि मूत स्रिविकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है, परन्तु राज्य नीनि-निद्रेशक तन्वी का

जन्मपन होन या पालन न विधे जाने की स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सक्ती है। तयापि नीति-निर्देशक तत्वी की सविधान में रखे जान के कारण न्यायपालिका इनके सन्ति व से सन्तित रहकर सपने निर्णय नहीं दे सकती है। भारतीय सविधान में, मूल अधिकारों के विशेषकर स्वतनता के मूल अधिकार सवा सम्यति के मधिकारा पर सीमाएँ लगाई गई है। स्वतना ने मुन ग्रामितार ने सवम में सविधान में 'विनियन्त' मीमाग्री राजीना

स्प्याग क्या ग्या है, मम्पति के खितकार के सबप भे यह प्रावधान क्या गया है कि सम्पति का प्रतिप्रहुण राज्य केवल 'मार्वजनिक उद्देश्य' से ही कर सकता है। इस बात को निर्धारित करन क लिए कि 'यक्तियक्त सीमाग्री' तथा 'सार्वजनिक उद्देश्य'

में बचा वारामें है त्याप्रवारिका का निर्णय अतिम होता । इस सन्द्रमें में त्यायपालिका को राज्य नीति निर्देशक तत्वों का सहारा सेना पड़ेगा । शास्तव में, पिछने वर्षों में जब कानुना द्वारा व्यक्तिनन स्वतवता पर सामाएँ सगाई गई, स्यायशानिका ने

यह बौजने ने लिए नि ये सोमाएँ यूक्तियुक्त थी या नहीं, राज्यनीति-निर्देशक त वो का मार्ग दर्जन लिया। न्यायपालिका की यह धारणा उही है, कि जिन मिद्धानों को सविधान द्वारा मान्यना प्रश्त है वे युन्तिरहित नहीं हो मक्ते ह । निमदह मून अधिकारा तथा राज्य नीनि-निर्देशक तत्वी के मार्गदर्शन में, क्रापृतिक मारत में सविधान को लागू होने के समय से ही ज्यायपालिका को एक म यन्त गमोर तथा सह बपूर्ण मुमित्र प्राप्त हुई है, जिससे व्यक्तिगत स्वतत्रता ्द नोन बल्यापनारी राज्य ने मध्य पैदा हुए विरोधों नो दूर कर इन दोनों में समन्यय स्थापित क्या जा सके । दूसरे शब्दों में व्यवस्थापिता तथा वार्यपालिका के मितिरिनत, सविमान द्वारा मारत में राजनीतिक लोकतन्न तथा भाषिक लोकतन को, व्यवहार मे एव दूसरे के पूरव बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालि । रा मो भी सौपी गई है। मुख्यत न्यायपालिका ने इस कार्य को नागरिकों के मूत श्रपितारा तथा नीति-निर्देशक तत्वो के सदमंग किया है। नागरिरा पे मूल ग्रिविकारा द्वारा एक ऐसे क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, जिसम राज्य हस्तर्भेष कर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंधन नहीं कर सारता है। अत यदि अस्याधिक बरसाह म सरवार ने लोव पत्थाणवारी राज्य वे झादर्श वी प्राप्ति वे लिए ऐसा वानन पारित विद्या जिससे विसी मूल प्रधिवार या प्रधिवारो वा प्रतिज्ञमण हुपा तो न्यायपालिका ने ऐसे कानून को अवैध घोषित किया । इसी प्रकार न्यायपालिया ने सविधान द्वारा लोब बल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को व्यान म रागते हुए जत किसी बानुन थी जांच मूल अधिकारो के सन्दर्भ मे इस आधार पर की कि उना कानून द्वारा धनुच्छेद ३१ (२) वे अनुसार सम्पति वा अधिप्रहण राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया था या नहीं, तो न्यायपानिका ने सर्विपान मे उल्लिखित नीति-निर्देशक तत्वो का मार्गदर्शन लिया । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी कातृन को न्यायालय वे समक्ष इस सर्वपर चुनौती दी गई है शि इसमे भनुच्छेद १६ द्वारा अदल मूल अधिनार वे विरुद्ध युक्तिरहित गीमाएँ लगाई गई हैं, तो न्यायपालिया जबत तर्व को स्वीकार नही करेगी, यदि ये सीमाएँ राज्य नीति-निर्देशक तत्वो वे बाघार पर है बयोगि यह मानना स्वामाविक है, जि जिन सिद्धा तो को सविधान मे रखा गया है वे युनित रहित नहीं हो सबते हैं। इस दृष्टि-कोण में कई कानू हो थो, जिनको न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी न्यायपालिका मे सबैधानिक ठहरावा है। उदाहरण स्वरूप, अपुन्छेद ४७ मे निहित मशासन्दी निर्देशक तस्व के ब्राधार पर ऐसे वानूव को न्यायपालिका द्वारा वैष घोषित किया गया जिसके द्वारा मादक द्रव्यों के रखने तथा अय करने पर प्रतिबन्ध संगाया गया षा। मनुष्कुद ४८ मे निहित निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार गो-वय निर्येष के सिद्धान्त पर भाषारित कानून का न्यायपालिका ने वैध माना ।

इसी प्रकार सम्पति के मूल प्रधिकार ने सन्दर्भ में प्रमुच्छेद ३१ (२) के प्रमुखार यदि राज्य निजी सम्पत्ति था सार्यजनिक उद्देश्य ने निए कानून द्वारा प्रधिवहण, प्रमुच्छेद ३१ (व) एव (स) में निहित राज्य नीति-निर्देशय तस्त्री (३१ (व) समाज के मौतिन साथनो का स्वासिस्व तथा वितरण इस प्रकार का

१ मोहम्मव हनोक झौर ग्रन्य बनाम बिहार राज्य झौर ग्रन्य—ए० ग्राई० ग्रार० १६४८ एस० सी० ७३१।

कारतीय जासन चौर राजनीति

हो कि जिससे सामान्य रूप से जनहित हो; ३६ (स) देश की आर्थिक व्यवस्या का सचालन इस प्रकार न हो जिससे घन का केन्द्रीयकरण होते हुए सामान्य हिन को हानि पहुँचे) की प्राप्ति के लिए करता है तो ऐसे कानून को प्रवेध नही

90

मानना चाहिये। इस सिद्धान्त को सविधान संशोधन पच्चीसर्वे प्रधिनियम मे धपनाया गया जो दिसम्बर १६७१ में पारित क्या गया। इस संशोधन के प्रमुसार यदि विसी मानून से यह उल्लिखित कर दिया जाता है कि उक्त बानून का उद्देश्य किस राज्य नीति-निर्देशक तत्व को लागू करना है तो इसके बावजूद कि वह कानून किसो मुख अधिकार के विरुद्ध है उक्त कानून को अवैध धोपित महीं किया जा सकेया । पण्चीसवाँ सशोधन, राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के, विशेष-कर धनुच्छेद ३६ में निहित निर्देशक तस्वों के दृष्टिकोण से ग्रत्यस्त महत्वपूर्ण है। इस समोधन के सनुसार साधारण कानून द्वारा व्यवस्थापिका समा ऐसे नीति-निर्देशक तत्व को जिसका उल्लेख उक्त कान्न में है, मूल ग्रधिकारों से उच्च स्थान

प्रदान कर सकती है जो २१वें सज्ञोधन लागू होने की नीति निर्देशक-तत्वों की पूर्वं विस्ति से बिल्कुल भिग्न है। पञ्चीसर्वे सशोधन लायू होने के पूर्व कानूनी दृष्टि से नीति निर्देशक तत्व मूल ग्रविकारों के ग्रवीन ये । न्यापालिका की इस विशेष भूमिका का महत्व दिसम्बर १६७१ तक रहा जबकि सविधान में पञ्चीसवाँ सशोधन लागू किया गया । सक्षेप में तब तन राज्य नीति-निर्देशक तत्वो के सबय मे न्यायपालिका के दो प्रकार के प्रापकार थे, सर्वप्रथम, यदि राज्य नीति निर्देशन तत्व पर आधारित क्सी नान्त तथा नागरिको के किसी मल ग्राधकार में संपर्ध होता. तो ऐसे कातन को ग्रवंध ठहराना. क्योंकि मुल ग्रधिकार न्याय्य है, राज्य नीति-निर्देशक तस्य न्याय्य नही है, ग्रीर द्वितीय,

कई मूल ग्रमिकार 'युक्तियुक्त सीमाओ' द्वारा सीमित हैं सवा सम्पति के मूल मिमनार के प्रन्तर्गत सम्पति का प्रविग्रहण, 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए ही निया जा सक्ता है। मूल-मधिकारी से सवधित 'युक्तियुक्त सीमाम्रो,' तथा 'सार्वजनिक जरेरप' की व्यास्या करने का अधिकार क्यायपालिका को है और इस कार्य में कि 'मुक्तियुक्त सीमाभ्रो' तथा 'सार्वजनिक उद्देश्य' से क्या तात्वयं है, न्यायपालिका का नीति-निर्देशक तरवो द्वारा पय प्रदर्शन किया गया, जैसा कि कतिपय महत्वपूर्ण प्रकरणों से भात होता है। विहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह नामक प्रकरण मे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री दास ने कहा कि 'सावंजनिक उद्देश्य' से तालपं उस लोन-कत्याण से है, जिसका उस्तेख राज्य नीति-निर्देशक तत्वी मे है। इसी प्रकार हनीफ बुरेकी बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में यह निर्णय दिया पया वि अनुच्छेद ४८ में उल्लेखित योजय सवयो राज्य नीति-निर्देशक तत्य के भनाश में गाय तथा बैस, जो दुधारू तथा उपयोगी हैं ने दघ ना पूर्ण निषेध युन्ति-युक्त है। सक्षेप मे बातून द्वारा सरकार ने नागरिकों के मधिकार पर जो सीमाएँ लगाई, तो यह विदित करने के लिए कि वे सीमाएँ युक्तियुक्त भी या नही, न्यावपालिका ने राज्य नीति-निर्देशक तत्वो का सहारा लिया।

धन्त में यह कहा जा सरता है वि सास्त ने सिवाम में राज्य मीति-निर्देशका तरवों का धाषिक लोनतत्र के साधनों ने रूप में धरवाधिक महत्व है। सविधान ने पच्चीतर्त संत्रोमन (१९७१) से इसका महत्व धीर धायिक हो गया है नयोदि सत्ते परिणाम स्वरूप सरकार ना उत्तरदाधित्व साधिक लोनत्य की प्राप्ति वे लिए स्पष्ट रूप से साथके उपर धाता है। राज्य नीति-निर्देशक तरवां द्वारा सविधान की प्रस्तावना में उत्तिविधान की प्रस्तावना में अपनि स्वाप्ति की प्रस्तावना स्वाप्ति की प्रस्तावन की प्रस्तावन की प्रस्तावन की स्वाप्ति की स्वाप्ति की स्वाप्ति की सिवार प्रस्तावन की स्वाप्ति की सिवार सिवार सिवार स्वाप्ति की स्वाप्ति स्वाप्ति की स्वाप्ति की स्वाप्ति स्

२. एस० थी० प्रव्यय- 'कामरोट्यूमानतित्रम इन इण्डिया' इन स्ट्डीख इम इण्डियन देमोक्रोसी १६६४, प्र० ७६८ ।

## मारत में संसदात्मक प्रणाली

सायुनिक युन से सरकारों के वर्तीकरण का युरन घाचार वरकार के वो सन, ध्यवस्थापिका सना एवं वार्यपानिका-समा, के सबसी के स्वरूप पर सामारित है। इस दृष्टिकोण से जननोविक सरकारों को यो वर्गों में पता जा सकता है।

सु । इस दुन्द्रकाण स जनगावक सरकारा का वा पणा स रखा था सकता हु । सर्वप्रयम, ससदारमक सरकार, जियने कार्यश्रानिका (संवीमण्डल) का उत्तर-द्वाधिक समय के निजन-सदन के प्रति होता है ।

हितीय, अध्यक्षात्मक हात्या है।
हितीय, अध्यक्षात्मक हात्या है।
प्रत्या के दो अवय-प्रत्य कीर स्वतं कार्यवाधिका तथा व्यवस्थापिका समा
महारा के दो अवय-प्रत्य कीर स्वतं अव है। धर्मण्य हम प्रदिश्ति के कार्यप्रतिका और व्यवस्थापिका ने कोई धर्मण्य क्षाय नहीं होता है, जबकि अस्तिकात्म प्रदिति के नार्यवाधिका तथा प्रवस्थापिका का एक हुकरे से इनना घरिन्छ सम्बद्ध होता है कि नार्यवाधिका केवल क्षायस्थापिका के विश्वस्थापिक ही प्रवासीन रह सकती है। साथ ही, वार्यवाधिका (वर्षायम्बद्ध) का कार्यकात व्यवस्थापिका में बहुतन पर निर्मेष रहता है।

बहुमत पर । नगर रहता है। उत्तरसाधी सरकार की खता नी दी जाती है। स्वदालक सरकार के जुन विद्वाल की हम जाना है व वार्यस्थित (सनीमज्ज ) एवं रावस्थानिक कार्यस्थानिक कार्यस्थानिक की हम भी विद्वालय की हम जाने के वार्यस्थानिक स्वार्यस्थानिक वार्यस्थानिक सामानिक कार्यस्थानिक वार्यस्थानिक सामानिक सामानिक कार्यस्थानिक कार्यस्थानिक सामानिक सामानिक सामानिक कार्यस्थानिक कार्यस्थानिक सामानिक सामा

प्रो॰ गेंटेल ने ससदात्वन सरकार को परिमाया इस प्रकार को है—"मधी-मध्यास्थ्य सरकार, यह सरकार है जिससे सम्पत्तिक कार्यवासिका, जिसमें एक प्रपान मनी एक मधीनकड़त का सम्पत्तिक होता है अपने वार्षों के लिए विधिवत रूप से स्वस्माधिका के प्रति उत्तरत्यायों है।"।

t. भार वो वोटल-पोलिटिक्स साइन्स १६४४, पृ० २१।

हा० गार्नर ने ससदातम सरकार की परिमापा देने हुए नहा है—"मंत्री-मण्डलात्मक सरकार बहु प्रणाली है जिसम वास्तविक कार्यणालिका (वेत्रांनट या भंगोमण्डल) प्रत्यक्ष एव विधिवतहण से व्यवस्थापिता या उसके एत मदन के पति (सायारणत्या प्रतिनिधि सदन) भीर आप्रत्यक्ष या अन्तिम रूप से निर्वावको वे प्रति प्रपोर राजनीतिक नीतियो एव कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जबकि स्वजनात्र या नामनात्र को कार्यणालिका (राज्याच्यक्ष) की स्थित उत्तरदायिवहीन होती है।"

## ससदात्मक सन्वार की भावश्यक शर्ते

जर्यांकत परिमापाधो से यह विदित होता है वि सरादारभन सरकार में प्रातांति वास्तिथिक कार्ययात्त्रिया वा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व हीना— इस सरकार वा भूल सिद्धान्त है। व्यावहारिक रूप से इस सिद्धान्त के दो पक्ष है।

प्रथम—बास्तविक कार्यपालिना विधिवत् एव प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिया ने प्रति चत्तरवामी होती है।

हितीय—शप्रत्यक्ष एव अन्तिमरूप से कार्यपालिका का उत्तरदायिस्य मन-दाताओं ने प्रति है।

इन दोनो पहलुयों की ब्यावहारिक सफलता के लिए व वेयल व्यवस्थापिका एव मजदातामों को बपने राजनीतिक कर्तव्यों एव दासिहड़ों के प्रति मतत सजग भीर तक्षम होना मावस्थ्य है, परन्यु यह भी व्यवस्था है कि व्यवस्थापिका समा भीर निर्वाक्ति में (मतदातामों में) वह क्षमता हो, जिसके द्वारा वे कार्ययालिका समा भीर निर्वाक्ति में (मतदातामों में) वह क्षमता हो, जिसके द्वारा वे कार्ययालिका (करकार) को उत्तरदायिक की प्रावना से प्रेरित कर सके । वास्त्रक में सम्बदासक प्रणाली में व्यवस्थापिका एव मतदातागणों का व्यत्यपित महत्व है, व्योंकि इन दोनों में ऐसी पारियों निहित हैं, जो भावस्थक जनतायिक प्रवरोगों में रूप में कार्यपालिका की सक्तियों वो वैयानिक दायरे में सीमित रखते हुए, उसकी निरदुत्र मृदित्यों पर रोज कार्यायालिका की सक्तियों वो वैयानिक दायरे में सीमित रखते हुए, उसकी निरदुत्र मृदित्यों पर रोज कगाती है तथा मतदातागण, व्यवस्थापिका परि कार्यपालिक के मध्य में, ससदीय प्रणाली की आवश्यकतानुसार सनुसन की स्थित स्थापित करती है। इसमें संदेह नहीं कि वार्यपालिका पर यदि बुख निश्चित भीर भावश्यक प्रवर्शन नहीं नो वार्यपालिका निर्मुलता की ब्रोर प्रवर्शन होगी। ससदासक प्रणाली के स्थापता नहीं ने स्थापता में स्वरंगित कार्यों के प्रति सत्ति होगी मान्यन्तिक है। इसमें संदेह नहीं कि वार्यपालिका वृक्ष स्थापता कार्यों के प्रति स्थापता होगी मान्यन्तिक होगी मान्यन्तिक कार्यों के प्रति स्थान होगी मान्यन्तिक है।

१. के० ब्ह्यु मार्कर-विशिवायका लाइना सन्द मधीमाट १६३२ पृ०-३२३ ।

#### भारत में संसदात्मक सरकार

भारतीय सविधान के घन्तमंत केन्द्र धीर विभिन्न राज्यों में सरदारमक प्रणानी के विभाग सही है। "मामन कर स्वरूप केन्द्र धीर राज्यों में विदित्त प्रणानी के सद्द्र समस्यासक उत्तरसाधी सरकार है। सभीच चीर राज्यों की कार्यालीकर विद्वार प्रणानी कि सद्द्र समस्यासक उत्तरसाधी सरकार है। यह मारतीय विदित्त प्रवृति के घनुसार धामुद्दिक रूप से उत्तरसाधी रखी गई है। यह मारतीय परिस्थितों में स्वामाधिक था, क्योंकि भारत किस जनतात्रिक शासन से परिस्थित स्वामाधिक था, क्योंकि भारत किस जनतात्रिक शासन से परिस्थित स्वामाधिक भारतीय क्या मारतीय स्वामाधिक कार्याली के स्वामाधिक प्रणानी कार्याली के कार्यों के माराधिक प्रणानी कार साधी है। इसके धानतीतिक से कार्यों कार्याली कार कर्याली होती है।" भी

हिदिस संसरीय प्रणासी के विचरील जिसका निकास ऐतिहासिक प्रांसार पर गर्ने -गर्ने, मुरन्द अस्तिसमयो के साधार पर हुआ, मारत में समदाराज सरकार में उद्दर्शति लिकित सर्विभाग के विजिद्ध आपवानों पर आधारित है। इस तरव इस हुन जा सकता है कि उसकि इन्योक के संस्ताराजन कराजर मुक्तत, स्वैधानिक स्राज्य सामता है कि उसकि इन्योक के से संस्ताराजन कराजर में स्वत्य स्विधानिक कानूनों पर आगरित है। भरन्तु हत्या धर्म यह नहीं है कि गारत में सस्ताराजन अगाजी में विकास में स्विधानयों के लिए कोई स्थान मही है। तथ्य दो यह है कि गारतीय राजनीतिक अगाजी में सक्तिया करकार के विकास के नित्य विजिन्न विवधी में सक्त से, प्रमित्तमयों के सामता है में बी गारपित व्यावस्थलता है। उदाहरण स्वस्य, सनिधान में यह मही तिकास है कि पारप्रित जानियानक में सामता मार्ने में तिए बाध्य है। यहाँ, निर्मिण्ड रूप से, एक समित्रमाय की सामयन्ता महसूत होती है। 'हमारे सन्तियान ने ब्रिटिश सन्तियान का समुकरण विधा है सीर हमारी समसीय उद्धित और परप्यराएँ ग्रिटिश सक्तीय प्रदित्ति एव परप्यपानी पर

यह निर्मारित करने के लिए कि मारतीय सविधान के प्रान्तांत केन्द्रीय सरकार ना क्या स्वरूप है हमे सविधान के पुछ विशिष्ट प्रावधानी ना भ्रष्ययन

करना होता। मारतीय सविधान के धनुन्धेद ४० के धनुसार वेन्द्र मे एक राष्ट्रपति वे पद की स्थापना की गई है। धनुन्धेद ४३ (१) के धनुकार सथ की काम्पीनिया सविधन समस्य धनियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं धीर इन कनियों की

पिन समस्त क्षांतियाँ राष्ट्रपति से निह्ति की गई हैं और इन क्षांतियों को -----

एन० थीनिवासन-'हेसाइटिक यद्येष्ट इत इष्टिया', १९४४, पृ० १४४ ।
 एव० एम० पटेस--विजिन्ट पर्यमेट्ट इत इष्टिया' (स्ट्रशेन इत इष्टिया क्रिया (स्ट्रशेन इत इष्टिया क्रिया क्र

राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सविषान के धनुसार धपने प्रधीन वर्मचारियों की सहायता से उपयोग से सायेगा। धनुन्देद ७४ (१) के धनुसार प्रधान मंत्री की प्रध्यक्षता में एक मंत्रीमण्डल होगा जो राष्ट्रपति को उसने कार्यों के लिए सहायता एवं सत्ताह देया। धनुन्देद ७५ (१) के द्वारा यह निष्पिति विचायाम है कि मुनेपण्डल सामृहिक रूप से लोकनुमा के प्रति उत्तरदायी होगा। धनुन्देद ७६ के
धनुसार संघ के लिए एक संबद्धानी जिसमें राष्ट्रपति व दो सदन होगे—राज्यसमा
और तोक समा। धनुन्देद ७५ (१) के धनुवार चिंद कोई मंत्री लगातार ६ माह संद तत्तवसमा। धनुन्देद ७५ (१) के धनुवार चिंद कोई मंत्री लगातार ६ माह संद तत्तवसमा। धनुन्देद ७५ (१) के धनुवार चिंद कोई मंत्री लगातार ६ माह संद तत्तव के किसी एक सदन का सदस्य नहीं वनता है तो इस समय के परचात्

मारतीय सविधान के उपर्युक्त शावधानों का ससदात्मक सरकार की परिमापा भीर मावस्यवतामा वे सदमं मे बध्ययन वरते हुए यह निश्चयपूर्वं पहा जा सकता है कि भारतीय सविधान द्वारा ससदात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ससवात्मक सरकार की परिमाया से ज्ञात होता है कि इस सरकार में दी प्रकार की कार्यपालिकाओं का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम-नाममात या ध्वजमात्र की वार्यपालिका, जिसका मूर्तस्य राज्याध्यक्ष होता है। मारतीय स विधान के ५३ (१) के श्रनुसार कार्यपासिका से सवधित शस्तियाँ राष्ट्रपति मे निहित होती हैं भीर इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरप से बरेगा । परन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर यह बहना गलत होगा कि राष्ट्रपति स्विविवेत के अनुसार साधारण स्थिति मे वार्षपालिका—सविधित शक्तियों को रपायवर के अनुसीर साथारण रायात व वायभारवरा — वायभारवरा ना प्रमोग में ता सतता है। अनुच्छेद १३ (१) के खर्वसानिक असे को सही सदर्क में सममने के लिए, इसका आध्ययन अनुच्छेद ७४ (१) धीर अनुच्छेद ७४ (३) के साम करना दावत ही नही अधितु अस्यावस्थक है। यह कहना भी कोई प्रतिययोक्ति नहीं है कि बस्तुत उपर्युक्त में सीन अनुच्छेद सारतीय ससदीय प्रणासी के जीवन-भाषार हैं। मनुब्छेद ७४ (१) के ब्राधार पर सधीय मत्री मण्डल का निर्माण होता है जो प्रधान मनी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह प्रदान करेगा। परन्तु मारतीय ससदीय ढाँचे का रीटरूपी सहारा अनुच्छेद ७५ (३) मे पाया जाता है, जिसके अनुसार मत्रीमण्डल सामूहिन रूप से लोकसमा के प्रति उत्तरदायी है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के प्रमुसार यदि लोकसभा द्वारा बहुमत से, मन्त्रीमण्डल वे विरुद्ध प्रविश्वास प्रस्ताव पारित विया गया है ती मत्रीमण्डल को त्यागपत्र देना आवश्यक है। देश की सरकार और प्रशासन को दक्षतापूर्वक चलाने का सारा उत्तरदायित्व मत्रीमण्डल का प्रत्यक्षरूप से ससद के प्रति ग्रीर भ्रप्रत्यक्षरूप से मतदातागण के प्रति है। सविधान द्वारा सरकार की नीतियो ग्रीर कार्यो का उत्तरदायित्व मत्रीमण्डल के ग्रतिरिक्त किसी ग्रन्य व्यक्ति या सस्या को नही सौंपा गया है। श्रतः सरकारी एव प्रशासकीय श्रुटियो के लिए दोप केवन मुत्रीमण्डल ना ही होगा। घट यह वर्कसमत बात है कि चूँकि सरकार ना नीतियो एव नावों ने सबर म सारी जवाबदारी मुत्रीमण्डल की ही है. राष्ट्र-पर्तत सामारण परिष्यिनयों में केवन नाममात्र का राज्याव्यक ही रहेगा।

दितीय, ससरात्मक सरकार के घटवर्षत वास्तवित वार्षणांचना मुनीपण्डेत.

के रूप में होता है। वार्ष्टासिक कार्यणांचिका की सता मधीनण्डेत को से जिती हैं
करोंक व्यावहारिकता में सरकार को नीतियों एव कार्यों के सित्र, हरका उत्तरशांवित वारतिव है। यह सरव है कि घतुन्चेत २५ ११) के प्रत्येत प्रभान मनी
की निवृक्ति राष्ट्रशति के द्वारा होनी है, और धन्य मभीनण राष्ट्रपति डाण
प्रमानमंत्री के राज्याचेत्रणार निवृक्त होता है। वरल्तु यह केवल एक सीवयासिकता
है स्थीति साधानशमा राष्ट्रपति उद्यो कर्याक को प्रमानमंत्री निवृक्त करता है,
शो लोकनमा में बद्दमत दल का नेना है। इसके धांदिरका, मभी पद के लिए
प्रधानसभी द्वारा मानोलिक व्यक्ति को राज्युश्ति धर्मोहत नहीं कर सकता है।
सामूहिक उत्तरदायित का तिद्याल जो भारतीय संवदीय प्रणालों को पूरी है, दो
मुद्द बागारे पर, ध्यावहारिकता नो इस्ति की सीवर्ष है।

(क) बेचल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति सभी पद पर हो, जिन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत करता है।

(स) जन व्यक्तियों को मजीपद से पदच्युत किया खाये, जिन्हें प्रधानमंत्री मत्रीमण्डल में नहीं रखना चाहता है।

उपमुंत्र मानस्मतामो को स्थान मे रखते हुए राष्ट्रपति, सविवान के ममुसार हो स्वान मनान ने परामधानुसार, एक तर्वसामित प्रधानमधान के रूप में ही बार्य करेगा। यह विद्वार मानस्मता के रूप में ही बार्य करेगा। यह विद्वार मानस्मता के रूप में ही बार्य करेगा। यह विद्वार मानस्मता का ही सासक है सीर मारतीय मनीमण्डल, ब्रिटिश के की बोर सासक के निकत्त सहन का बात उपलिखान है। ममीमण्डल के स्वान्दिक कार्य-सिवार है। ममीमण्डल के स्वान्दिक कार्य-सिवार है। ममीमण्डल के स्वान्दिक सामार्थ के सामार्थ

विमाना ने फ्रप्यक्ष रहनर वार्य न रते हैं। एव सस्या वे रूप मे वे राज्य की विधि-निर्माण एव वित सबसी नीति का निर्देशन करते हैं।"<sup>9</sup>

मारतीय सर्वोच्य न्यायालय ने 'रायसाहुर राम जब्यवा वपूर एवं घाय बााम पजाव राज्य' के प्रवरण म १२ सर्वेत १६५१ म निर्णय देते हुए निम्मदिरित गर्वेश में मारतीय सरकार ने ससदास्मव स्वरूप पर प्रवाण डाला है।

"मारतीय सिवधान व धन्तमत वार्यपानिवा वा जिन सोमाधा वे द्यापर म कार्य करना है, उनवा निर्वारण उस सरवार वे स्वरुप व मदर्भ में विया जा सवना है जिसकी स्वापना सविधान द्वारा वी गई है। हमारा सिवधान सपटनारमा दृष्टि से समीय होने के बावजूद बिटिश सम्बदासक प्रणानी के घाषार पर निर्मान है जिसमें यह माना गया है वि नायंपालिया वा प्राथमिण उत्तरराधित्व मीनि-निर्माण करना तथा उतको कानूनी व्यावहारियता देना है परन्तु इस शर्त पर वि वह राज्य की ब्यवस्थापिका वी विश्वसान्धाय बनी रहे। वार्य-गालिया वा वार्य नीति निर्मार पण एव उसनो कार्यान्वित करना है।"व

यह सिद्ध करने ने पश्चात् कि मारतीय समदीय प्रणाली की स्थापना सनिधान हारा की गई है, जिसके चन्तर्गत राष्ट्रपति साधारणतया नाममात्र वा णासन है भौर वास्तविक गार्थपालिका मनीमण्डन है यह ब्रायक्यन है कि हम इस ससदीय जनतत्र म मतदातागण की भूमिका पर प्रकाश डालें, वयोवि (विसी भी जनस्थ का मल प्राधार उसके मतदातागण हैं) विशेषकर ससदीय प्रणाली मे मतदातागण का महत्व प्रत्याधिक है वयोवि समदीय प्रणाली का मूल सिद्धान्त वार्यपालिका के साम-हिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त-एक निरन्तर जीवित-सिद्धान्त है ग्रीर इस साम-हिन उत्तरदायित की सिद्धान्तरूपी शृखला मे तीन मुख्य वडियाँ जुडी हुई हैं, मनी-मण्डल (बास्तविव कार्यपासिका) शिखर पर, ब्यवस्थापिका मध्य मे प्रीर सबसे नीचे किन्तु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, मतदातागण की है । यदि इन तीनो मे से कोई भी एक सस्या जनतत्र के प्रति उदासीन ही जाती है तो जनतत्र प्रवश्य ही एतरे म पड जायेगा । यह सत्य है कि किसी भी जनता को ऐसी ही सरकार प्राप्त होती है, जिसके योग्य जनता है । यदि मतदातागण ध्रपने क्तंब्यों के प्रति सजग हैं तो सरकार ग्रपने उत्तरदायित्व के प्रति ग्रविक सचेत रहेगी, पर येर्दि मतदाता ग्रपने कर्तव्यो के प्रति उदासीन हैं, तो ऐसी दशा में सरकार पर से वह प्रकृश निकल जाता है, जिससे वह ग्रपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रखी जा सकती है । यह

१ प्रार० जी० गेटेल-पूर्वोक्त पुस्तक पृ० २१८

२ मुकर्जी मृत्य न्यायाधीश—सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस १६११, भाग—१ जुलाई स्रगस्त १६१४ पृ०-२३०-२३७ ।

एव मतदातागण को नायंपालिना ने नियन्त्रण के लिए दैनिक तथा सामिषक शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

मारत मे मतदाताम्रो ना विशेष महत्व है। वास्तव म यह नहा जा सकता है कि भारत में समदीय प्रजातन की सफलता मतदाताओं नी निष्ठा, धमता श्रीर सज-गता पर ही निर्मर है। यह मूमिना, विशेषनर श्राम चुनाबो ने समय म महत्वपूर्ण है, जब देश ने नानून-निर्माताओं शौर शासनो के निर्वाचन ना प्रश्न जनता ने समक्ष माता है। मतदातागण अपने राजनीतिन नार्यों को विस हद तक सफलता-पूर्वक करते हैं, यह इस बात पर निमर करती है कि वे किस हद तक निष्ठावान, सम्मा तथा सक्रिय हैं। मतदातागण यदि मक्मेण्यता, निरक्षरता, जदासीनता मौर माधिक विपन्नता (विषमता) के शिकार हैं तो जनतत्र को विकल कर देते हैं। इन दोपो भीर शृदियों के नारण वे भवने प्रतिनिधियों भीर शासनी वा चुनाव सही रूप से नहीं कर सकेंगे। भारत में सविधान द्वारा ससदात्मक प्रणाली की स्यापना की गई है, इसका श्रीमन्नाय यह है कि यहाँ पर मतदाताओं का शिक्षित, सजग भीर ईमानदार होना नितान्त भावस्थक है। मारतीय सविधान के अनुब्छेद ३२४-३२६ निर्वाचन सम्यो मामला पर प्रकाश डालते हैं। सविधान हारा नागरिको को वयस्य मताधिकार दिया गया है। मारत के प्रत्येक नागरिक की जो २१ वर्ष की मायुका है मत देने का अधिकार है। परन्तु उसकी पागल तथा प्रपराधी नहीं होना चाहिए। इस तरह, स्वय सविधान द्वारा मारतीय मतदातामी के लिए प्रावधान विया गया है। सविधान द्वारा नामरिको को प्रदत्त मताधिकार, विसी भी राष्ट्रीय मान्तीय, तथा स्वानीय कानून द्वारा, सिवाय सविधान द्वारा निर्धारित प्रणाली थे, मपहुत नहीं किया जा सकता है। सविधान द्वारा जनता को प्रदक्त वयस्क मताधिकार, सर्विधान निर्माताओं के उस विश्वास का चौतक है, जिसके बाधार पर भारत मे ससदीय प्रणाली की नीव डाली वई है।

स्वतनता के परवात् भारत में बभी तक पाँच बाम बुनाव (१६५१-५२, १६५७, १६६३, १६६७ एव १६७१) सम्पन्त हुए हैं। इन बुनावों में पूर्व जनता-भिन्न सरस्तर में कार्यप्रणाली ना सारतीयों को वोई ध्रतुमव नहीं था। ध्रत प्रथम प्राम बुनाव के समय यह ध्रतुमव निया स्था कि सारतीय जनता को ने केवल जनता किन समय स्वाप्त के समय यह ध्रतुमव विचाय साम प्रतु यह भी देखा गया कि प्रथिता गया कि प्रथिता राज्य निवाय साम कि स्वप्त कि

भ्रारम्म सही विशा में हुमा। टा॰ नामैन पामर कहते हैं--"जबिक बहुत से उदाहरण, मतदान के उद्देश्यो तथा प्रणाली के न सममने के घौर इनके उल्लघन के पाये गये, प्रथम दो भ्राम नुनाव श्रीयकाश निरक्षर जनता के बुद्धिपूर्ण मतदान करने भी समता के प्रमावजाली प्रदर्शन से ।"

परन्तु इस में कोई सदेह नहीं है कि चार माग चुनावों के मनुभव के माधार पर भारतीय निर्वाचकों की भूभिका में कुछ गमीर चूटियाँ उमर कर सामने माथी, जिनको जनतत्र के हिंत में दूर करना भावस्थक है। इन विभिन्न श्रृटियों को निम्तानुसार प्रस्तुत क्या जा सकता है।

सर्वप्रयम-एर प्रमुख वृटि ना यह धनुमव निया नया कि एक शौसत निर्वाचक भारत मे राजनेतिक परिस्थितियों के धृष्टिकोण से, बास्तविकता से प्रधिक दूर रहता श्चाया है। यह मारतीय जनतत्र प्रणाली का एक गभीर दीप है। इसका केवल आधा हा पह नाराधा जायान ज्यारा की एवं गयार दाया है। इसका क्या यह तारायों नहीं है कि कितने नार्यारक यह देते हैं, पर यह कि वे मत सैने देते हैं। यदि प्रतदान किसी प्रशोधन या दवाव या व्यक्ति-विशोध या सम्प्रदाय के हित पर प्राथमिता हैं तो निक्चय ही यह राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताभी की मास्त-विकताधी ते दूर है और इसके प्रमाव राष्ट्र के लिए वास्तव में मताचिकार के प्रयोग में नहीं लोग के प्रभाव से भ्रापिकार के स्थाप से प्रमाव से भ्रापिक हानिकारक सिद्ध होंगे। जानरीज इस सबर्म में कहते हैं—"मारतीय राजनीति ये एक वरह से वास्तविक्ता की कमी इसलिए है कि जनता की राजि विसी भूल बात में बहुत कम है।" यदापि यह इसाजय है कि जनता का राम किया कुत महन कर महुत कर है। "उपयान यह इस्तर है कि सिवाम के मानू होने के नहें नवें पत्तात तक परिमाण मारतीय निवासको का रज राजनीतिक मामसो के प्रति उपासीन रहा है, किन्तु पिछले वर्षों के राजनीतिक सनुप्रतों के नारण निविश्यों की राजनीति में दिलकासी स्थितक बड़ी है। निन्तु यह विदित्त रहे कि यह दिलकासी प्राय जन मूल पुरुषों से ही सबसित नहीं रही है निज पर राज्यीय दित प्रायारित है, परसु यह भी प्यान देने योग्य तम्म है कि यहि मुद्ध निवासक राजनीतिक जीवन के प्रति उदासीन हैं हो त्राच प्राप्त हो है भी है जिनके प्रपत्त राजनीतिक प्रियेश रहे ता कर्तव्यों के प्रति इन्ह्रा निर्वाणक ऐसे भी है जिनके प्रपत्त राजनीतिक प्रयिवश्यों के प्रति श्वरण केनता की जागृति हुई है। "प्रत्ती कारण है कि प्रव स्वस्तात्मक जनता के मित्रपत्त के प्रति प्राणा की जा सकती है।" इसमें सदेह नहीं है कि पह प्राणा प्राप्तामा निर्वाणकों के प्रपत्ते प्राप्तार एवं करतेयों के प्रति जागरक होने वर निभंर है।

१ एन० पामर—'इण्डियन योलिटिकल सिस्टम,' पृ०२१७, स० १६६१ ।

२ के० रोच-'इण्डियान १९४७ इतेशाल कार्यक्ष, हुण्यान, तार्व, १६ मई, ४७। ३. सार० बर्नेहेम-'यार्तियामेन्ट इन इण्डियन डेमोकेसी' स्ट्डीब इन इण्डियन मोकेसी-प्रस्पर स्रोर श्लीनिवासन १९६४ पु० १७०-७१।

द्वितीय-राजनीतिन जागध्यता के लिए निरक्षरता एव धनिमञ्जता का दूर करना भ्रत्यावश्यक है। निरक्षरता एव धनिमन्नता, मारतीय जनतत्र म उन धुराइया के रूप म हैं जिनसे भारतीय निर्वाचको के जनतन के प्रति स्वस्थ रख के निर्माण म बाधा पहुँचती है । मतदान वे प्रधिवार का उपयोध निर्वाचक की उस कार्ययुगलता एव क्षमता पर निर्मर है, जिससे वह धपने दायित्वा को समक्र सकता है । निर्वाचक की इस योग्यता का विवास जिल्ला एव ज्ञान वे माध्यम से ही विया जा सवता है। चूनि मारत नी अधिनांश जनता आज मी निरक्षर और अशिक्षित है, परिणाम स्वरूप प्रधिवाश निवाचवणण अपन सताधिवार वा सदुपयोग नही वर सकते हैं। इस वारण, मारत वे विमिन्न साम-चुनावो म विठाइयो वो दूर वरन के लिए, निवायन अधिकारियों ने कुछ विशेष चिन्हा और प्रतीको को, निर्वाचका भी सहायता के तिए प्रयुक्त निया है। डा० पामेर का कथन है—''करीय ग्रस्सी प्रतिकृत निर्वाचका की निरक्षरता द्वारा उत्पन्न हुई बुछ समस्याक्षी को दूर करने में लिए चिन्हो एव वहु मतदान पेटियो को रखा गया है। युख राजनीतिक दला मी अन्ह प्रदत्त क्रिये हुए जिन्हों से अधिव साम हुआ। उदाहरणार्थं गाप्रेस दल मो, बैस जोडी वा चिन्ह प्राप्त हुआ जिसके अनेर प्रकार के लामपूर्ण सर्व लगाये जा सकते है। वह भारतीयों को यह समझाया गया कि वे वैसा के विरद्ध मतदान न करें क्योंकि बैल उनकी जीविका, शक्ति, यानावात और कदाचित उनके चामिक विश्वास के चोतक थे। सान्यवादियों को हथोड़ा और हौसिया के लिए सहमति प्राप्त नही हुई, उनको हासिया और मेहूँ नी बाली चिन्ह के लिए सहमति मिली जो भारतीय क्सान में लिए एक बहुत आवर्षक चिन्ह है।" इन पुटियो के बायजूद भी पाँच माम चनायों के आधार पर, यह निश्चियपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत मे जनतत्र सबधी जा परीक्षण हुन्ना, वह पर्याप्त मात्रा मे सफल रहा । परन्तु पूर्ण सफलता में लिए वर्तमान तुटियों को दूर करना आवश्यक है। "वयस्य मताधिकार की नाम सबधी उपयुक्तता को स्वतंत्र एव गुप्त मतदान प्रणासी के प्रन्तगंत जीवने वे लिये प्रद्ध शिक्षित या प्रद्ध प्रगतिशील देशो के दृष्टिकोण से, जिनकी जनता ग्रधिवतर ग्रनपढ रीति-रिवाज से दवी ग्रीर मतदान के विचार तथा व्यामहारिकता भीर जनतत्र ने तरीनो एव सिद्धान्ता से अपरिचित हो, भारत एक महत्वपुण प्रयोग शाला है। 317

तृतीय--राजनीति-विज्ञान ना यह एक सत्य है नि आर्षिक प्रधिनारो की मनुपस्यित म, राजनीतिक प्रथिकार प्रयहीन हो जाते हैं। यह सत्य है नि सरकार

१ एन॰ पार्मर-'पूर्वोक्त पुस्तक' पु॰ २१८।

२ एन० पामर-वही पू० २१६।

के प्रयत्नों के बावजूद भी, एक भौसत नागरिक की मार्थिक स्थिति भारत में दयनीय है।

धार्षिक विपन्तता के कारण नागरिक अपने राजनीविक धिकारों का सही द्रवारों गहीं कर सकता है। धार्षिक विषयाना एवं धारामाना के पहुन से जबहें होते से निर्वार्क में दतना भी ब्याय नहीं मिलता कि कहा बारों प्राचनी राजनीविक धार्षिकारों में स्वस्थ तथा छत्तिका निर्वार केने प्राचन राजनीविक धार्षिकारों में स्वस्थ तथा छत्तिका निर्वार केने से प्रमुक्त कर सके। इसके परिणाम स्वस्थ स्वदान के समय कह पूष्ठ धार्षि दुराइयों का किकार हुं। जाता है। धार्म जुनाव के दौरान घरकर पर है जाता है। धार्म जुनाव के दौरान घरकर पर है जाता है। धार्म अपना के दौरान घरकर है। स्वत्रात्व को स्वयत्व की स्वार्म स्वत्रात की स्वयं स्वार्म है कि निर्वार के दूष समावित होते विद्यास्थित हो हुए स्वर्मित की दूर करना के विद्य समावित होते हिल् सम्बद्ध होते हैं कि स्वर्म के स्वर्म स्वत्रात की स्वर्म स्वत्रात की स्वर्म स्वत्रात की स्वर्म स्वर्म स्वत्रात की स्वर्म स्वर्य स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्य स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्म स्वर्म स

भी सन्धानम का कहना है—"सर्वप्रथम यह प्रावश्यक है कि निर्वावकों को पूर्य देन पर रोक समाई जाये। पूर्व के प्रथमांथी को जात करने और प्रयम्भियों को सत्य देन के सत्य देन से का स्वार्ध को सत्य देन के साम देन देन जान ना चाहिये के साम देन किया जाना चाहिये कि चुनाव-प्रथमी द्वारा या निर्वावकों की सूज सक्ता प्रवाद के सिक्त एक होता प्रवाद के सिक्त के सिक्त

१. एन॰ सन्धानम, 'ट्रानकीशन इन इण्डिया', १९६४ पृ० ६१-६२ ।

स्वतत्रता पूर्वन अनुसरण करने की दामता, तथा हिंसा के खजाय घटिसा सथा जनतांत्रिक सिद्धान्ती और प्रणालियों में बसीम विक्यास चादि प्रायक्ष्यरताओं पर भारतीय जनतत्र का मविष्य और सकतता ग्रामारिन है।

सक्षेत्र में, ससदात्मक पद्धति की सकतता के लिए भारत में निर्वाचकों की ग्रपने राजनीतिक प्रधिकारी एवं कर्तथ्यों नो ईमानदारी और निष्टापूर्वक प्रयुक्त ष'रता अत्यावश्यव है। विशेषवर, जब देश में आम धुनाव वा समय भाता है, निर्वायको के क्षेत्रल मतदान के अधिकार का ही अका नहीं है, परन्त इनसे भी ग्रायिक महत्वपूर्ण जनके इस कर्तेच्य का प्रश्न है कि पिछने पाँच पर्य देश के राज-मीतिर प्रविवारियों ने राजसत्ता अपने हाथ में रखते हुए जा बाये रिये हैं, उनरी निष्यक्ष क्ष्य से समीका बरते हुए मतदान बर्रे । मादान का प्रयोग, इस रूप में विवित्त के हाथ में एवं अपूर्ण के समान होगा, जिससे देश के शागरों के राज शितिव आचरण की नियन्त्रित विया जा सबेसा । धतः मतदान वा अधिवार जनतत्र में एप जातांत्रिक ग्रयरोप वे रप मे है, जिसते व्यवस्थापिया, और व्यवस्थापिया के माध्यम से वार्मपालिया पर, जनता था नियन्त्रण बास्तियिक भीर निरन्तर राता जा सबता है। "बुडरो-पिल्गन पट्टा परते थे, जनतम एव स्त्री गठिन प्रणाली है। यह विदित है वि इसके लिए मुख राजनीतिक परिषकता की सावक्यकता है, पर यह नवार है। देवन तर्युष्ट प्रजानिक विकास निरामित है। हमाने प्रतिहित्त हुए बात प्राच विचास-उन्द्रुप्त देशों में नहीं पाई जाती है। हमाने प्रतिहित्त हुए प्रच में शिक्षा, हुप्त मात्रा में श्रावित सुदृद्धतं, उत्तरदायित्वपूर्ण नेट्रुट और वर्षान्त मागरियता मी मायना विस्तमें जनता लोग नायां में प्रविच हिन्मा ने मने धीर नागारका वा मायना । महाम जनता साच वाया म आपव । हरना ल ाच मार मूस मी वम वर सवे । वे वोई क्ष्यमव वाने नहीं हैं। वट्ट सटी है वि बहुत से नये चमरते हुए देशा वो जनतज वी बुद्ध या सभी मून प्रावश्ववतामी वी प्राचित नहीं है। पर यह विदित है कि इनमें है अधिर वी (वहाँ उदाररण) ने लिए मनेशिया, मारतवर्ष और वितिशीन वा उत्तरेत विचा जा सवता है) जातन मी मुख्य आवश्यवताएँ उपलब्ध हैं। इनवी प्रेरित हिया जाना अधिक आवश्यर है।"

भ्रत्त में यह यहना उचित होगा कि मारत में जनतत्र के सक्त स्थालन के लिए विभिन्न श्रायश्यवताएँ उपलब्द हैं, पर भारत की जनता मीर राजनीतिक नेतृत्व को यह चुनौनी है कि इन झावस्थवताओं का उपयुक्त प्रयोग करे अन्यथा यह समा है रि जनतन की मूल कावश्यक्ताएँ चाहे वे कभी धविक्रशिल इस से ही वयो न हो एउ के पश्चात एक समाप्त होती चली जायेगी।

१. एस० पेडोवर—'व ब्रमेरिकन रिपोर्टर' ब्रगस्त १८, १६६५ ।

٤

सपबाद वह यन है जिसके द्वारा पाज्य की सारी शक्तियों का विभावन दों प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है। ये वो प्रकार की सरकारें — केन्द्रीय और राज्यों की (आप में शहरायों) सहलायों के इस्य में होती हैं। में के शासती ने वर बाद पर प्रकाश जानते हुए कहा है— "यह वह पाननीविन यन है, जिसके द्वारा पाड़ीन एकता और पाज्यों (श्वाहणों) के अधिकारों में सामजस्य स्थापित किया आता है!"

सचवार राष्ट्रीय सार्वमीमिकता और राज्यों (इकाद्यों) के मिकतरों की पुरक मागों में जिस सायन डारा सनन्य और एकता स्वारित्व करता है—वह है निशंक सार्वात, इन्कें कर करते के सार्वमीमिकता सबवी के सिव्यों के विश्वास करते हैं—वह है निशंक सार्वात, इने के कि कर के हैं है एत सिव्यास के सार्वाद के सार्वाद है। बास्त्व में सार्वाद का सिक्राय सीमित सरकार ने मिक्रान में सर्वाद है। सीमित सरकार से तार्वाद है कि सार्वाद है। सीमित सरकार से तार्वाद है। की सीमामों को निष्ठ करते कि सिक्रा सरकार के डारा निर्वाधित कर दिवा बाता है। इन सीमामों से निकर कर सरकारों का प्रयोग करता सर्वाद है। इन सीमामों से निकर कर सरकारों का प्रयोग करता सर्वाद है। इन सीमामों से निकर सर सरकारों का प्रयोग करता सर्वाधित हरी सीमामों को निर्वाद सरकारों सरकारों का स्वारा है। इन सीमामों से निकर कर सरकारों का प्रयोग करता सर्वाधित हों से सीमामों का निर्वाद सरकारों सरकारों है। इसेस सार्वाधित को प्रयोग करता सर्वाध के सुरक्षित कार्वभीनकारों के डारा है निकर्ष सीमामों का निर्वाद इसकी इसकी इसकी इसकी इसकी हमाने ही सर्वाध करता हो सरकार है। सर्वाध सार्वाध के सुरक्षात कार्वभीनकारों के डारा है निकर्ष सार्वाध की सुरक्षात कार्वभीनकारों के डारा है निकर्ष सार्वाध की हमाने है। सर्वाध सार्वाध

की सार्वमीमिकता सीमित होने के बावजूद भी वास्तविक होती है।"?

इस तरह संपवाद के अन्तर्यंत सरकारों के सीमित होने का मूल कारण गति के विभाजन का सिद्धान्त है। यान विद्वित्तर के अनुसार—"स्वीय सिद्धान्त से सैप्स तरायं गति के विभाजन के तरीके से हैं जिससे सामान्य (सर्याय) एवं सेशांपिकारी (राज्ये) सरकारे अपने क्षेत्र म ससाम एवं पृथक होती हैं।"

१. प्रो॰ ए॰ यी॰ डायसी—'सा चाफ द बालटीट्युगन', १६३८ पृ० १३८ ।

<sup>.</sup> २ द्वार॰ मैकाइवर—'मार्डन स्टेट' १९२६ पृ० रेद० । ३. डा० विहितर—फेडरल सर्वेमेष्ट, १९५१ पृ० ११ ।

"सम सरवार वह है जिसमें सार्वनीमिनताया राजसत्ता वा विभाजा मेन्द्रीय एव स्थानीय सरकारी के मध्य में हुआ हो, जिससे दामे से प्रत्येव एवं दूसरे से अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो।" व

यह स्पट है नि सपवाद द्वारा लिखित सिनमान ने दायरे में विभिन्न सरागरी पर सर्वपानिक सीमाम्रो ना निर्यारण होता है। सपवाद द्वारा निर्मित ये सीमार्थ केन्द्रीय एव राज्यो की सरवारो ने सभीय सबयो मे एन भावण्यन सहुतन एव समन्वय स्पापित चरती है, जिसने बिना सारा सपीय द्वीना एक पतीय हो सचता है। सावारणतया नेन्द्रीय सरवार-सविषद सीमाम्रो ना उन्लेख निम्नलिखित है।

्रे हेवल सपीय व्यवस्थापिका सिनयान ना सगोधन नहीं नर साती है। रे-सपीय व्यवस्थापिना को नेवल सविधान द्वारा निर्धारित शेत्र में ही कानून बनाने की समझा है।

३- सधीय वार्यपालिका को भी वेवल सविधान द्वारा सीमित दागरे मे आदेश

तथा डिक्री घोषित वरने वा अधिवार है।

जप्मृत सीमाएँ राज्यो भी विधान समाघो और वार्यपालिवाघो पर मी लागू होती है। इस सदर्भ मे न्याय विभाग की भूमिरा प्रत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इस सदर्भ मे न्याय विभाग को श्रीवार पर स्वरंभ मे ह्याय पित्रा को सिवार वे सरकाण मा प्रीवार हिता है। ग्यांचिम अस्पे स्वरंभ का प्रत्या के स्वरंभ में मा से हिता है। ग्यांचिम अस्पे में स्वरंभ का प्रत्या में स्वरंभ में प्रत्या में स्वरंभ में प्रत्या प्रत्या में प्रत्य में मिल् त्या स्वरंभ में निष्या ग्यायपालिवा में सरकाण भी काव्यक्त होती है। इसना वारण भी काव्यक्त होता है। इस प्रत्या मा प्रत्य प्रत्या में प्रत्य में प्रत्या में स्वर्ग प्रत्या में स्वरंप प्रत्य में स्वरंप स्वरंप स्वरंप स्वरंप मा स्वरंप में स्वरंप मा में स्वरंप में स्वरंप प्रत्य में प्रतिवा में स्वरंप स्वरंप स्वरंप मा स्वरंप में स्वरंप प्रत्य में स्वरंप प्रत्य में स्वरंप स्वरंप स्वरंप स्वरंप स्वरंप में स्वरंप प्रत्य में स्वरंप स्व

स<u>वंत्रयम</u>—सर्वियान का लिखित स्वरूप होना भावनपुर है, जिससे इसमे स्पटता रहे भीर सपीय मामलों में मतमेंद होने की समावना बहुत क्या हो जाये।

१ घार० गेरेन-च रिपोर्ट भाक व रायल कमीसन घान धारद्रेलियन कान्स्टी-ट्युगन ।

२ प्रो॰ ए॰ यो॰ डायसी-'पूर्वोक्त पुस्तक पु॰ १४० ।

सभीय सर्वियान वास्तव में एक मनुबय के रूप में है, विसमें मुद्य ह्वावस्पक रही की, हिर्मिम सभीय इकाइयों को सहमति के, रूटीय एवं राज्यों की सरकारों में शिस्ता में ने उस्लिवित इस परिमापित करने के तिल्ह वित्त का जाते हैं कि इसके स्वत्यान स महत्व सभीय प्रधावों में इस दृष्टिमों से याया जाता है कि इसके सन्तर्गत तथ और राज्यों के सबसे में वह वित्त सिक्त के समावणां नहीं रहते हैं। सावारण कानूनों में तुलना मा निविद्य सिक्यान स्थायों है। इसके द्वारा सावारण कानूनों में तुलना मा निविद्य सिक्यान स्थायों है। इसके द्वारा सावारों के समुद्र मीर नार्यों का सकृत्यों भीर सबसेवात स्थायों है। इसके द्वारा सावारों का सम्प्रण सीर नार्यों का सकृत्यों भीर सबसेवात स्थायों है। इसके सावार त्या सब भीर सावारों का स्थायों के सबसेवात स्थायों का सबसेवात स्थायों के सबसेवात सुकसेवात स्थायों के सबसेवात स्थायों के सबसेवात सुकसेवात स्थायों के सबसेवात सुकसेवात सुकसेवात

सद्दा है सत हो <u>बार-भार संघोधन नहीं करना</u> चाहिये। सर्विधान को निरन्दर संघोधनों की बाद में यह दलेका यथा जो निरूचय ही संधिय हाई के नष्ट होंने के नष्ट होंने के नष्ट होंने के नष्ट होंने के स्वार होंगे के स्वार होंगे के स्वार होंगे के स्वार होंगे के स्वार हैं के स्वार होंगे के स्वार हैं हैं कि निया पात्रों में स्वार संघाधन के ब्रोधन के ब्रोधनों से क्वोर हैं। इन पार्टों में सहियान का संघोधन के स्वार के स्वार्धन के महार हैं। इन पार्टों में सहियान का संघोधन संघाधार कानून निर्माण प्रणासी से नहीं बहिया एक सिर्ण साधित निया नाता है। शो <u>बाद हों की कार्य</u> के कार्य ने पार्टी के स्वार के कार्यूर में। यह स्वार्धन के कार्यूर में। यह स्वार्धन के स्वार्धन किया ना हके यो साधारण स्वारमाधिका समाधों (संधीय सा पार्थों) से सर्वंधा निय हो। "भै

साधुनिक पुत्र में तोव करनावकारी राज्य को मूर्त कर देते के तित् प्राप्त पह साव-स्तक हो आगा है कि सिंद्यान का ससीवक सामाजिक स्वीप के सावाद पर राष्ट्र की सावक्वकनानुसार दिवार वासे । परन्तु सुह स्वाद म राष्ट्रे कि समीव पान्यों में सिंद्यान का समाधन केवत सविधान में दी हुई साधेवत प्रणाली के सनुसार ही हो करेगा । "यह नितंदय है कि जहाँ कही भी सम सरकार है, वहाँ सरकार है कि निर्मात समीव प्रणाली को सिंद्यान रहे के देने को प्राप्तिक महत्व केरे के सम्माज समीव प्रणाली को सिंद्यान रहे के स्वतंत्र सुरक्षित रूप से किसी साधारण स्वत्यापिका समा म निद्धित नहीं को वा सवती है, क्योंकि एस तरह से साधारण स्वत्यापिका समा म निद्धित नहीं को वा सवती है, क्योंकि एस तरह से साधारण स्वत्यापिका समा म निद्धित नहीं को वा सवती है, क्योंकि एस तरह से साधारण स्वत्यापिका समा म निद्धित नहीं को वा सवती है,

सधीय राज्य म अत्येक व्यवस्थापिका समा, सधीय सविद्यान के मन्तर्गत एक भन्नपान विधि निभाषात्मक सस्या है, जिसके द्वारा निमित कान्त, उपनियमों, के

१ प्रो॰ शयसी-पूर्वोक्त वुस्तक वृ॰ १४२।

२ वही पु॰ १४३।

बा प्रगठन एवं शिन्त्रमीं, मोर नागरियों भीर सरकार के जनतादियां से निर्मारिक स्टेंग के निष् विन्यनिस्तित तीन क्रूप्य, सावस्वतार्थ होनी साहिय— (१) सिंक्यान का विनित्त हाना, (स) हिंदियान का सनसमीय या करोर होना, सोर (ग)-वेजन एक प्रविज्ञानी संघीय न्यायानिका मा होना।

मारता में सरकार की साकायवन्तालें—प्रथम प्रकार के सहसे में यहि जारता के छिपात के विभिन्न प्राथमानी की मनीक्षा की जाने, तो उनके साधार पर मह छिपात के विभिन्न प्राथमानी की मनीक्षा की जाने, तो उनके साधार पर मह कितिकारपूरिक कहा जा सक्ता की गई है। परता से सक पात्र की मानक्ष्मा की गई है। एस सुनियान में किता की किता की मानक्ष्मा की मानक

ब्यानहारिका के दुव्यिकोय ने यहाँ मूत्र प्रत्य यह है कि चूँक प्राप्त को सर्विक स्वार 'मूर्तिका ने विक् 'पंत्रपान' की स्वार में यह है, तो बना में विवार के स्वार 'मूर्तिका ने मुनियारी साम्यक्रमार्थ निविद्ध होता साहम्यक है, सिव्यान बाती निवान क सनुवार स्पीय क्षित्रक को निविद्ध होता साहम्यक है, सिव्यान सै यह भीर प्राप्ता की स्वाराय के मान्य क्ष्म क्ष्म को ब्यान्त है निव्यान होता बाति, भीर भाग में, स्वाराय क्षम्यक के सम्यत्त क्ष्मां क्ष्मां वात्रपान हित्य बात होता चाहित, विवार कारक्ष स्वीव्यान को स्वारा किया जा करेगा। भारत के मंदियान में इन सीनी साहम्यकार्यों को मान्यता दी गई है। बात यह है। बात होता कार्यों के साहमान में साव्याक के निवार को भारता प्राप्ता है। स्वार होता कि मार्योंन स्वीव्यान में साव्याक के निवार को भारता प्राप्ता है। स्वाराम सीनी कियानार्थी को होटि से, निवानिविद्य क्ष्म में भारत के सीनयन का विवार कियानार्थी को होटि से, निवानिविद्य क्ष्म में भारत के सीनयन का विवार पर सिवार का स्वता है विक्री इनके स्वीय स्वव्य पर प्रकार दाना पा करे।

१ बी॰ घार॰ घम्बेदकर-दान्ट बान्स्टोटयुशन, भाग ४ ३

मारतीय सपीय सिम्मत व्यवस्था वी प्रथम प्रावययनता, विनित सिव्यान के रूप में निवसात है। निनित सिव्यान में न वेयत स्थ सरवार और राज्यों की सर-सारों ने निए प्रावयान निया गया है, परन्तु इनवें मध्य म सिन्त वा विमानन मी स्टाट रूप से विषय गया है। इसने प्रतिस्तित, राज्य सीर नागिरों ने सज्यों में, मून सिद्धानों ना उस्तेय, विजेषत्रया मांग तीन म धनुच्छेंद १२-१४, मून प्रिय-नारा एव मांग वार में अन्वदेद ३६-४१ तब राज्य नीनि-निदंशक तरता ये रूप म क्यिंग गया है। प्रस्त नागिरा। वे प्रविचार, सिव्यान में इपर-उपर तमावित्यत है। उदाहरण नरकर, नागिरा। वो प्रविचार, सिव्यान से इपर-उपर तमावित्यत एव राजनीतिक न्याय वे प्रयिचार, जिनवा उस्तेय सिव्यान री प्रनाता। म विया पदा राजनीतिक न्याय वे प्रयिचार, जिनवा उस्तेय सिव्यान री प्रनाता। म विया पदा है। संबीय प्रवानों से निद्धान वे प्रनुरूप घारणीय सिव्यान में जिस संबी या प्रनानीयता प्राप्त होनी है। यह संबंदा के लिए प्रायवया है। सदीर में मारत सा सिव्यान विदिश्व है, वह सु एव स्वव्या के लिए प्रायवया है। सदीर में मारत सा सिव्यान विदिश है, विहारे ३६४ प्रकृच्छेंद एव ६ प्रवृत्या विष्या है।

मारत में समीव प्रणाली की डिवीय आवश्यकता सम एय राहे क्या सिनामी का स्टाट और दिस्तृत विभाजन है। सबियान में अनुख्देद २४४-२६३ सम और राजने के मध्य मिनामी के विभाजन पर प्रकास डाउते हैं। "मारत की सविधान में सब और राजने के मध्य सिनामी का सिवाम में सब और राजने के मध्य सता-विभाजन से दो विधायट परन्तु पुषद् सतायन राहन के नो निनाम का स्टाट स्टाट

सिवियान की सात की सनुपूत्री के द्वारा विकारपूर्वक वास्तियों के विमाजन का उल्लेख निया गया है। सिवन-विमाजन के जिस नमूने का सर्वियान में उपयोग किया है, यह मारत सरकार प्रधिनियम १९३१ के धन्तर्गत सक एक इकाइयों के वीमाधिकारों के विमाजन के सदल है जो तीन सूचियों द्वारा निर्यारित निया गया था। ये तीन स्वियों, इस प्रकार सी !

 सपीय सूचि, स राज्य सूचि, और म. समवती मूची। इसी नमूने ने प्राधार पर मार शेथ सवियान की सातवी अनुसूची द्वारा समराज्य व्यवस्थापन सबयी विषयी का उन्तेल कुले ने लिए जिक्नीपातित तीन मुचियो को रसा क्या है।

(व) सधीय सूची—इसने अन्तर्गत हु विषय हैं। सवियान, नेवल सघ ससद को, इस सूची में उन्तेक्षित विषयो पर विधि-निर्माण करने वा अधिकार देता है।

(स) राज्य सूची—इसमें ६६ विषय हैं । साधारणतथा इस गूची में विणत विषयों पर राज्य-विद्यान समाग्रों के क्षेत्राधिकार के होते हुए भी, सविद्यान में कुछ

१ मास्टरगार्ड-डेमोकेसी इन इण्डिया 'इन डायलाग्स माफ डेमोकेटिक पालिटिश्स इन इण्डिया'-सम्पाबित जी० हलच्या द्वारा १९६६ पु० २१७।

२० भारतीय शासन और राजनीति

ग्रपवादों को प्रात्यता प्रदान को कई है, जिनका वर्णन विस्तृत रूप से, झारे किया जायेगा । (ग) समवर्ती मूची—इस सुची थे ४७ विषय हैं, समवर्ती सूची से उल्लिखित

जिपयों पर सबद और राज्यों भी विचान समझों नो समवर्ती शेत्राधिकार प्रस्त हैं। यनुच्छेद २१४ क धनुसार मदि समीय कानून और विसी राज्य कानून में सम-वर्ती सूत्रों से छत्तित्वत विता विचय पर मदाबेद या समर्प होता है तो ऐसी दवा में सभीय कानून को, राज्य नानून की अधेका मान्यता प्राप्त होगी, परुजु यदि राज्य कानून को पूर्वेवत, राष्ट्रपति की शहमति प्राप्त हो गई है तो ऐसी स्थित में राज्य कानून को ही मान्यता प्राप्त होगी।

मारतीय सविधान से सुविधाद कृतिकारों के लिए भी उतिय प्रावधान दिया या है। स्वासाट कितारों से हैं, भी विदिन-विभागन सबसी सुविधों में कितियंत नहीं है। यह मानव चृद्धि के लिए समय गृद्धि हैं कि मविध्य से उत्तर होने साती प्रयोग कामरा या विध्य का सही रूप से मुनुमान तराकर, सिदारा में उनके सित् प्रावधान कर सुवे। इस सावत्व वर सामना करने के लिए प्रतिकार से उनके लिए प्रतिकार के सुविधान के सुविधान के भी स्वत्वारों के लिए कुछ न हुछ प्रतिकार कितार विद्या का स्वत्वार के सुविधान के सुविधान के भी स्वत्वारों के लिए कुछ न हुछ प्रतिकार कितार विद्या का स्वता कि सावता है। बारत के सिदारा में भी स्वत्विक्ट सहितारों के लिए विद्या स्वता है। स्वता के को स्वता निया निया कि स्वता कि स्वता कि स्वता कि स्वता कि स्वता कि स्वता के सित् कि स्वता स्वता कि स्वता

भारतीय सविधान में सांधोपन प्रणाली—स्थिय सविधान नी स्थिरता के लिए सिंधेपत्रस सविधान ने प्राचिन-विवादन स्थापित प्राचिन ने रिस्यरता के लिए सिंधेपत्रस सविधान ने भानिन-विवादन स्थापित प्राचिन ने रिस्यरता के लिए सिंधेपत्रस मंत्रियान ने प्रणालने में त्या स्थापित प्रणालने में त्या स्थापित प्रणालने में त्या स्थापित प्रणालने में त्या स्थापित प्रणालने स्थापित प्रणालने में प्रणालने स्थापित स्थापित प्रणालने में प्रणालने स्थापित प्रणालने स्थापित स्

मारतीय सर्विषान के संबोधन के दृष्टिकोण से इसके विभिन्न प्रावधानों को - रिर्फिन्न रीत श्रेषियों में रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी में रखे ग्रंम सर्विषान के प्राव-

यान सवियान ने अनुच्छेद ३६८ के चिल्लिसित एक विशिष्ट प्रणासी मे अनुसार सभोधित क्यिं जा सकते हैं।

बस्तुत मारत ने सविधान ने अन्तर्गत तीन पृथव् प्रनार नी संशोधन प्रणापी हैं। सविधान सदोधन नी इन प्रणासियों नो सर्वधा प्रावधानी में अनुसार इन प्रनार दर्शाया गया है।

(क) भारतीय सविधान के कुछ प्राथवानों को कैयन संसद में माधारण विधि-निर्माण प्रणाली वे उपयोग द्वारा संशोधित विया जा सकता है। इतवा यह तालाय है कि ससद के द्वारा ऐसे प्रावधाना के संशोधन के लिए केंग्रल साधारण बहुमा में विषेयक पारित करना ही पर्याप्त रहेगा । वह सन्नोयन प्रणाली ब्रिटिश सर्वियान की सशोधन प्रणाली से मिलनी-जुनती है, बवीबि इमलैण्ड में सर्वियान का सशोधन केंबन ससद द्वारा साधारण बहमन द्वारा पारित कानून से विया जा सकता है। उदाहरण स्तरूप, सर्विधान के अनुच्छेद ३ व अनुसार नेच के नये राज्य की स्थापना और राज्यों ने नाम या सीमाओं में परिवर्तन ससद द्वारा पारित क्ये कानून से निया जा सरता है। इसी तरह अनुच्छेद १६६ के अनुसार सम के उन राज्यों में जहाँ दितीय सदन नहीं है, वहाँ उननी स्थापना चौर जिन राज्यों में दितीय सदन है, परन्तु प्रनावश्यकता मे नारण, उनका समापन केवल शरादीय कानून के माध्यम से निया जा सरना है। सजिधान के नागरिक सबधी प्रावधान एवं अनुपूचित क्षेत्री भीर मनुसूचित जातिया सत्रथी प्रात्रवान ससद के कानन के द्वारा ही संशोधित निये जा सकते हैं । भारतीय सविधान के ये प्राप्तधान सविधान में नमनीयता की झलक प्रद-मित वरते हैं क्योति इनवे अनुसार संशोधन सरलनापूर्वक संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। समबाद के दृष्टिकीण है। जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके सशोधन की सन्य निधि है।

(प) समीधन की दूसरी खेणी के अन्तर्गत अस्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधानो को रामा गया है जिनका सबैधानिक एव राजनीतिक महस्य इनने सधीय स्वरूप से प्रदक्षित होता है। वास्तर के सबिधान के वे प्रावधान भारत में सपवाद के जीवन-रक्त के तुल्य हैं। इनमें निस्तनिसित प्रावधान विचारणीय हैं।

१—प्रमुच्छेर ४४ एव ४४ जिनने घाषार पर राज्या की नियान सभामी के निर्वाचित सरम्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्मा ने सकते हैं, प्रमुच्छेर ७३ एव १६२, राज्यों को वार्यपालिकाम्रो के सबभ में, भीर फ्रमुच्छेर २४१, सभीय सू-माग पर स्पापित उच्चतम न्यायालय के सबभ में।

२-सिवधान वे चौथे प्रष्याय वा पाँचवाँ मान, सधीय न्यायपानिता वे सदय में । सिवधान के ११वें मान वा पहला प्रष्याय, सघ और राज्य वे व्यवस्थापन सबसी मामलो के सबय में । ३---मिवधान के वे प्रावधान जिनके ग्राधार वर राज्यों को सहाद में प्रति-

४--सिवयान का प्रमुख्वेद १६८, सशोधन प्रणासी के संबंध में ।

चैकि उपरोक्त प्रावधान, भारत के सविधान के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिन पर भारतीय सथ का सम्पूर्ण ढाँचा श्राधारित है, इनके सशोधन के लिए एक विशेष क्ठीर पद्धति को अपनाया गया है। यह कहता चपयुक्त होगा कि भारतीय सविधान के इन प्रावधानों की संशोधन प्रधाली अमरीकी सविधान की संशोधन प्रणाली से बहुत कुछ मिलती-अलती है, क्वोंकि अमरीकी सविवान में भी समबाद के सिद्धान्त्री को समाबिष्ट विया गया है। समरोकी सविधान के अनुच्छेर १ के अनु-सार कांग्रेस (सधीय व्यवस्थापिका) धपने दो-तिहाई बहमत के बाबार पर संशोधन प्रस्तावित कर सकेंगी या विभिन्न राज्यों के वो तिहाई राज्यों के विद्यामकों की माग पर, सविधान में सशोधन के लिए, एक सम्मेलन बसाया जायेगा । यह विदित रहे कि उपर्यक्त दोनों ही तरीकों में से किसी भी एक के धनसार झमरीकी सर्विधान में सशोधन प्रस्ताबित किया जा सकता है। परन्त यह ब्रमरीकी सविधान की सशोधन का प्रयम घरण ही है। दिलीय या अनिम चरण सविधान में सशोधन को पारित बरता है। जब उपर्यक्त दोनों में से किसी एक करीके के द्वारा संशोधन प्रस्ताबित किया गया है, जिस्मलिखित दो में से किसी एक तरीके के सनुसार प्रस्ताबित सशीयन पारित किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन तीन-चौचाई राज्यों के विधायको द्वारा या तीन-चीपाई राज्यो में तथा सर्वधानिक सम्मेलनो द्वारा पारित किया जा सकेता 1

इसी प्रशार मारतीय सविधान के उपर्युक्त प्रावधान, विशवना बर्गन द्वितीय संपत्ते हैं। इस स्वाधिन अणाती के प्रमुद्धार स्वीधान विध्येस को सहायेस करायेस सप्तते हैं। इस स्वाधिन अणाती के प्रमुद्धार स्वीधान विध्येस को सहायेस के दोगों सप्तती के समस्त सदस्ती के बहुगन से एक उपस्थित स्वीद पर्वेश स्वीद प्रदान हैं प्रावधान है कि समस्त इस्ता परिद्धा कार्या स्वाधान है। इसके प्रकाल पहले में प्रावधान है कि समस्त इस्ता परिद्धा क्या स्वीधान विधिय की स्वाधान के उन स्वाधी उपयोग की विधान सम्माधी की सहस्ति आपन हो। "भारत से सतिकार के उन सप्तरी के सत्त्री में की उपयो (इस्ताइधी) के विधिय स्विध्या स्विध्या है सहित्यों से स्वाधित पहलें हैं, केवल सस्त के एक प्रसीध वार्थ इस्ता स्वीधान किया जा सन्ता है। धी. उद्दी पत्त्री के स्विध्या के स्विध्या एक स्वीधान के स्व

१. एम० पीत शर्मा—द नवंमेंट झाफ दो इच्टियन दिपब्लिक, १६६७ पूर्व

में समारमन विषयों से सबिवत प्रावधानों में सर्विधान की सर्वोच्चना की मसक विशेष रूप से पाई जाती है। सर्विधान की इस विशेषना के सदर्म में श्री जीठ एनठ जोगों का क्यन है कि 'यह प्रावधान संधारमक सिद्धान्त के प्रमुक्त है कि प्रन्तावित संशोधन यदि संधीय प्रधासी के मूल सिद्धान्तों को जिनको मूल संधीय समझौते में मान्यना दी गई है, प्रमावित करता है, प्रान्यों की विधान समामों की सहसित मावस्तक है।"

(ग) सदियान के सजोवन के दृष्टिकाल से हमने उपर्युक्त दो श्रेणिया में निहित सविधान के प्रावधानो तथा उनके सशोधन के लिए दो सर्वधित सशोधन प्रणालिया का प्रध्ययन किया । इन दो थेणियों से संप्रधिन प्रावधानों के प्रतिरिक्त भारत के सविधान में कुछ ग्रन्य प्रावधान शेष रह जात हैं। वस्तुन, इन प्रावधानी को तृतीय भेगी में रखकर हमारे समक्ष प्रत्न यह है कि इन प्रावयानों को जिनको हमने तृतीय श्रेणी में रखा है किस विद्याप्ट प्रपासी द्वारा सभोधिन किया जा सकेगा। सविधान में इन प्रावधानों के सशोधन के लिए जिस प्रणाली का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है कि समद के किसी एक सदन में प्रस्तावित संशोधन के लिए विघेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि इसका उक्त सदमें में सदत की कुल सदस्य सस्या के बहमत से एवं उपस्थित और मतदान करने वाल सदस्यों के दों निहाई प्रशों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उक्त विषेयक की दूनरे सदन में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जायेगा, जहाँ पहले सदन द्वारा पपनाये उपर्युक्त तरीने ने अनुसार पारित होते और राष्ट्रपति नी सहमति प्राप्त 'करने के परवात इसको सबैधानिक कानन का रूप प्राप्त हो जायेगा, जिससे सर्विधान में भावस्थान संशोधन लागू हो सकेगा । यह सशीधन प्रक्रिया थोडी जिटल है, क्योंकि यह कानून निर्माण करने की सरल प्रक्रिया से थोडी मिन्न है, जिसके लिए ससद में साधारण बहमत ही बावस्थक होता है।

भारत के सविधान में सबोबन ने दूरिटकोण से उसे उपयुंक तीन श्रीपयों में विभाजित नियान्या है, जिसने परिपाम स्वरूप प्रथम श्रेणों में उस्तिवित सविधान के प्रावधानों का सबोधन सरस सबोजन प्रणाली द्वारा किया जाता है। सामान्यतः या ति सी सविधान नी सबोधन प्रणाली साधारणाः सरस है तो यह निक्पे निवासा जाता है कि सविधान नो सवद्य हो नमतीय या सचीता होना चाहिया। चूँकि नारन ने सविधान ने दुद्ध प्रावधान, जिनका उत्तेस उपयुक्त प्रथम श्रेणों में कि नारन ने सविधान ने दुद्ध प्रवधान, जिनका उत्तेस उपयुक्त प्रथम श्रेणों में किया गया है, सरस प्रणाली द्वारा सबोधित किया वा सकते हैं, सन. हम यह वह सवदी है कि सविधान नुद्ध हुद तक सचीता है।

१. जी० एन० बोशी—दुशानस्टीट्युशन खाफ इध्डिया, १६१२ प्० ३७४।

धव हमे यह देखना है कि मारतीय चिवचान में सचवाद की तीसरी घीर सिता मादगक्ता के विष्णु क्या मायवान किया गया है। मारतीय सित्यान के मानुक्देर १२ के मानुवार एक सर्वोच्च व्यायालय होगा, जिसका एक गुक्य न्यायां-भीग होगा घीर, जब तक सत्तक कानुल द्वारा गृशे निर्माणित कराते हैं, सात माय न्यायाभीग होंगे। गुपीम कोर्ट सर्विनियम १९५६ द्वारा, पुच्च न्यायाभीग के मति-रिक्त दल क्या न्यायाभीगों के लिए मावयान किया गया है। सविधान के सरकार के क्य में सारतीय सर्वोच्च व्यायालय के सित्यों का स्वायार सविधान में निम्न-विश्वित सो कोरी के क्य में यथा ज्वाता है।

(क) अनुक्षेद्र १३१-१३३ के घलार्गत सर्वोच्च न्यायासय राज्य सूची में उक्तीवत विषय पर सत्तर द्वारा निर्मित नानून को घरेष घोषित कर सकता है। यदि इस कानून का निर्मोण सत्तर ने सविधान के अनुसार न दिया है तो सर्वोच्च साधायाय, व्यवस्थापन सत्त्रो क्षेत्राधिकार की झावश्यकता ने नारण उक्त कानून की अनेपानिकता पर खगता निर्मोण दे सकता है।

(य) अनुन्धेद ३२ (२) ने अन्तर्गंत सर्वोच्न न्यायालय नी न देवल यह प्रिप्रकार् है निन्तु उत्तना उत्तरदायित्व भी है नि नागरिनी ने मूल प्रयिक्तरों की रहा करें।

इसम घरेडू नहीं कि उपर्युक्त वी घतिकारी के कारण सर्वोच्च ग्यायालय मारत मे मर्विचान की घरोंच्या को मुद्द कावि रखते के लिए, एव प्रत्यन्त महत्वपूर्ण मापन है। भत. मुख्त जारतीय स्वयाद वा घतित्व इस न्यायालय की िप्रत्यकूर्ण सर्वीय भूषिका पर ही सप्तार्थत है। इस क्षम्यकृत के मायार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत में संघवाद की तीनो झावश्यक्ताएँ विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित है।

- (क) लिखित सविधान,
- (स) सप एव राज्यों में शक्तियों का विमाजन, और
- (ग) सर्वोच्च सघीय न्यायालय

"मारत का गणराज्य एक सच हैं, परन्तु इसके कुछ विशिष्ट गुण है जिनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के बुद्ध सचीय स्वरूप में कुछ परिवर्तन-सा हुमा है।"<sup>9</sup>

# भारत में संघवाद एवं संसदीय सार्वभौमिकता

समवाद भीर नागरिको के मुख अधिकारो को सविधान में समावेशित करने के फलस्वरूप सविधान देश के सर्वोज्य कानून का रूप धारण कर खेता है। लिखित रूप में सविधान में, सविधान की सर्वोज्यता का कही भी उल्लेख नहीं किया गया है। कवाचित्र विधान निर्माताओं द्वारा सविधान में विशिष्ट रूप में सविधान की सर्वोज्यता के लिए प्रावधान करना दक्षतिए धनावश्यत्र समभा कि सविधान की सर्वा एव राज्यों की सरकारों के विशिष्ट अगो की बिक्रियों एव अधिकारों का लोते है और सम्बद्ध के सिद्धान के अनुकूत सविधान का सर्वोधन नेवल एव विशिष्ट विधि निर्माण करने की प्रक्रिया से संबोधित नहीं किया वा सकता। यह कहना वर्धुक्त होगा कि मारतीय सविधान से विश्वित प्रावधान के न होने पर भी, सविधान देश का सर्वोज्य कानून है और जनता की सार्वशिकता वा दर्गण है।

मारत में सबबाद की मान्यता का महत्वपूर्ण प्रमाव सब भीर राज्य की सरकारों के सीमित सरकारों के रूप में कार्य करता है। सबबाद द्वारा राज्य-क्ता का विभाजन होता है भौर विभाजित राज्य-क्ता का सरकारों एवं उनके विभाज सोमाजित राज्य-क्ता उन सरकारों एवं उनके विभाज सोमाज से सीमित रूप से ही प्रदत्त की जाती है, जिनकी उरप्रति का स्रोत स्वय से विधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय ससद की अवित्यों का सीमित हीना प्रावस्थक है। इता भारतीय सदय की सार्वभीमिकता भीर जिटिस ससद की सार्वभीमिकता ने कि विद्या सविधान की प्रजीविक प्रमाल में मान्यता के सार्वभीमिकता ने कि विद्या सविधान की सर्वभीमिकता में सूर्वभीमिकता से स्वयं से सित्य है। अविद्या सार्वभीमिकता महत्वपूर्ण विधान की सर्वभीमिकता महत्वपूर्ण विधान ही। विद्या सत्य के द्वारा समयानुसार पारित

१. एन० पामर--इण्डियन योलिटिकल सिस्टम, १९६१ पृ० १४ ।

भारतीय शासन घौर राजनीति

सर्वयानिक बानूनों को धाव विटिश्व सविधान का एक हिस्सा माना बाता है। दसिली विटिश्व ससद वर्ष सर्वयानिक बानून की स्रोत है। बास्तम में विटिश्व सद वर्ष स्वयानिक बानून की स्रोत है। वर्ष स्वयानिक बानून की स्रोत है। वर्ष एक निरुद्ध सम्प्रामी सिवान समा है। वर्ष प्राप्त में प्रिष्ट एक निरुद्ध सम्प्रामी सिवान समा है। वर्ष प्राप्त में संस्थान दौर स्वयान की सिवान होरा दी गई है। सिवान दौरा निर्माल केल बुद्धों को सिवान होरा दी गई है। सिवान दौरा निर्माल करने विषे कानून निर्माल वर्ष में सोमाओं का उन्स्थान करने आदतीय सतद के विषे कानून निर्माल करना प्रवेचानिक होता। विटिश्व सिवान का समोचन विटिश्व स्वयान केलावित के निर्माल करने किए एक प्रशीय समिता होते हैं। स्वयान केलावित के निर्माल प्रयोग समिता होते हैं। स्वयान केलावित के निर्माल की स्वयान केलावित केलावित की स्वयान केलावित की सिवान स्वयान की समिता सम्बान सिवान की स्वयान की स्वयान केलावित सिवान की स्वयान की स्वयान केलावित स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान केलावित सिवान की स्वयान की स्वयान केलावित सिवान सिवान सिवान सिवान केलावित सिवान केलावित सिवान केलावित सिवान सिवान केलावित सिवान सिव

### भारतीय सविधान के बन्तर्गत एकारमक तत्व

भारत में सधवाद की स्थापना के साथ ही सविधान के मन्तर्गत वेन्द्रीय सरकार को कुछ विशेष सन्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके कारण यह कहा जाता है कि भारत के सविधान का ढाँचा समारमक है, विन्तु घारमा एवारमक है। मारत के राजनी-तिक इतिहास को सविधान निर्माताको ने धपनी दृष्टि मे रखते हुए ग्रीर इतिहास द्वारा यह सबक भीखत हुए कि जब कभी भी मारत में केन्द्रीय सरशार निर्यल रही मारतीय मुरक्षा एव एवता को भाषात पहुँचा सविधान के बन्तगैत संधीय व्यवस्था के लिए प्रावधान करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ देना मायश्यक या । साधारणतया यह देखा नया है वि ससार वे मुख्य सघ राज्यों म किसी न किसी सरीके द्वारा सबीय सरकार ने राज्यों की शरकारों को श्रपेक्षा स्वयं को शक्तिशाली बनाने में प्रत्यधिक सफलता प्राप्त की है। धमरीका का उदाहरण इस सदमें मे जित है। मूलमूत रूप से सविधान के धनुसार श्रमरीको सथ सरकार को केवल १८ शक्तियाँ ग्रोर ग्रन्य समस्त शक्तियाँ राज्यो की सरकारो को प्रदान की गई है परन्तु यह सर्वं विदित है कि बाधुनिक युग मे ब्रमरीकी सध सरकार ने घपने व्यवस्था-पन क्षेत्राधिकार में मधिक बृद्धि करने में सफ्तता प्राप्त की है। इस दिशा म प्रपने प्रयत्नो मे नाग्रेस (सधीय व्यवस्थापिका) को श्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण सहायता मिली है । सक्षेप मे सर्वोच्च न्यायालय ने धमरीना म निहित शक्तियों के सिद्धान्त ना प्रतिपादन करते हुए, यह निर्णय दिया कि काग्रेस को १८ मूल प्रक्तियो के भ्रन्तगंत सर्विधान के भनुकूल कुछ निहित शक्तियों प्राप्त हैं, जो सर्विधान के दायरे में हैं। नाग्रेस नो इन ज्ञानिनयों ने द्याघार पर विधि निर्माण करने ना पूर्ण श्रिधिकार होगा । फ्लस्वरप माज म्रमरीनी वाग्रेस वा विधि-निर्माण करने के क्षेत्र म सवि-घान द्वारा, १८ मूल शक्तियों ने निर्घारित क्षेत्र में ब्रत्यधिन वृद्धि हो गई है। इसी तरह, ब्राधुनिक समय में सच राज्यों म बेन्द्रीय सरकार की शक्तियों की, जनकरयाण, सुरक्षा ग्रादि महत्वपूर्ण मामला वे दृष्टिवोण से, ग्रधिव वृद्धि हुई है। "सारे सप राज्यो वे माधुनिय सविधानो मे वेन्द्रीयवरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।"

सविधान निर्मातायो पर भारतीय इतिहास का प्रभाव केन्द्रीय सरकार को शक्ति-शाली बनाने के पक्ष मे एक महत्त्रपूर्ण निर्णयायन सत्व या, क्योकि भारतीयों ने लिए इतिहास से जो प्रत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई, वह यह है कि विघटनकारी एव पुथकता प्रवृत्तियों ने देश को प्रारम्भ से ही फूट और दासता की खाई में घवेला। विभिन्न विघटनवारी प्रवत्तियो, उदाहरण के लिए-साम्प्रदामिवता, जातियाद, प्रान्तीयता, भाषाबाद, ने न बेयल बिटिश राज के समय मारत की एकता को नष्ट विया बरन ग्राज भी इन तत्वो ने ग्रपना सिर इतना ऊँचा उठा लिया है वि यदि इनको सरकार विशेषकर सधीय सरकार बुलचने में हिचकिचाहट दर्शाती है तो ये तत्व देश की स्वतत्रता, और एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली रखने के पक्ष में श्री के एम अभी ने सर्विधान समा मे एक ऐतिहासिक सध्य पर प्रवाश डालते समय वहा था .-- "मारत के लिए केवल वे ही गौरवपूर्ण दिन थे जब कि देश में एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार स्थापित रहती थी और सर्वाधिव दुखमय दिन वे थे, जब देश मे एव येन्द्रीय सरकार प्रान्तो के विरोध के कारण नष्ट हो जाती थी।"2

इन मुख्य कारणों के आधार पर सविधान सभा में वाद-विवाद का मुख्य प्रवाह केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में ही था। डा० अम्बेदकर स्वयं शक्तिशाली केन्द्र स्वापित न रने वे पक्ष में थे। उन्होंने नहा-"मै एक शक्तिसाली एवता सम्पन्न केन्द्र चाहता हूँ, जो १९३५ के श्रविनियम के अन्तर्गत निर्मित केन्द्र से अत्यिधिक शनितशाली होगा।"3

भारत के सविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित तत्वी ने एकात्मक प्रवृत्तियों को, ग्रीर उनने पलस्वरूप एवं शक्तिशाली केन्द्र को जन्म दिया है।

१. एन० पामर—पूर्वोक्त पृ० ६५ ।

२ कें एम॰ पुशी—कानस्टीट्युशन ब्रसेम्बली डिवेट्स भाग द पृ० ६२७ । ३. डा॰ सम्बेदकर-कान्स्टीट्युग्रन झसेम्बली डिबेट्स भाग १ पु० ६६ ।

सारतीय जासन धौर राजनीति

٤s सर्वप्रयम-सघ एव राज्यो ने मध्य शनितयो का बँटनारा इस तरह किया गया

है कि सप सरनार को राज्य सरनार की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है। निम्नलिखित-विश्लेयण से यह भौर भविक स्पट हो जायेगा । (क) सविधान के २४३ से २६५ तक के अनुच्छेदों में और सातवी अनुसुनी में,

सघ एव राज्यों ने मध्य में शनिनयों का विशाजन तीन सूचियों द्वारा क्या गया है। (१) सप सूची-जिसके अनुसार सथ को १७ विषया वे प्रधिकार दिये

गमें हैं।

(२) राज्यसूची--जिसके बनुसार राज्या को ६६ विषयो के धनिकार दिये गमें हैं।

(३) समवर्ती मुची-जिसके बतुसार सम व राज्यो, दोनो को ४७ विषयों के समवर्ती अधिकार दिये गये हैं। अनुब्देद २५४ के अनुसार यदि किसी राज्य विश्वान समा द्वारा निर्मित कानून वा कोई माय सब ससद द्वारा निर्मित कानून से सबर्प मे है, राज्य विधान समा द्वारा उनत निर्मित कानून को उस हद तक धर्वेष माना जायेगा, जिस हद तक बह सथीय कानून से सवर्ष भे हैं। सक्षेप म, सब सरकार के प्रिवरार समवर्ती सूची के सबध में, राज्यों की सरकारों 🚪 अपेक्षा सार्वेगीन हैं, इससे यह भी ताल्पयें है कि जब कम ससद १७ + ४७ = १४४ विषयों पर सार्वभीम रूप से नानून निर्माण कर सकती है, राज्य शरकारी ना क्षेत्राधिनार स्वतनतापुर्वक केंत्रल राज्य सूची में उस्लिखित, ६६ विषयो तक ही उपयोग में लाये जा सकते हैं। राज्य सरकारों के मधिकार समवर्ती भुक्षी म उल्लिखित ४७ विषयों पर इस बात पर निमंद रहेगे कि इनका सबर्प सबीय कान्तों से नहीं होना चाहिये। इसके धर्त-रिक्त, मनशिष्ट शक्तियो पर, अनुच्देद २४६ (१) के अनुसार केवल सथ सरकार को ही कानन बनाने का अधिकार है।

(स) सघवाद की कसीटी मूटनत केन्द्र एवं राज्यों में शक्ति विभावन के सिद्धान्त को लाग करना है। जहाँ सथ एव राज्यों की सरकारों में धक्तियों का विमाजन स्वय निवित सविज्ञान द्वारा कर दिया थया है, राज्यों को उनके क्षेत्र में कानून निर्माण करने की पूर्ण स्वतत्रता होती है और साधारणतया राज्यों के क्षेत्र में सुप सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। परन्तु मारतीय सविधान के अन्तर्गत शक्ति विमाजन सिद्धान्त ने सदमें में ही नतिपय परिस्थिमियों ने लिए विशेष रूप 🛭 प्रावधान दिय गये हैं, जो शक्ति विमाजन सिद्धान्त के प्रपत्राद माने जा सकते हैं, ग्रीर जिनके मनुसार सथ सरकार को राज्यों के क्षेत्राधिकार (राज्य सूची) में हस्त-क्षेप करना वैथ है। यह अपदाद निम्नानुसार है।

(१) धनुष्ट्रेड २४६ के धनुसार यदि राज्य समा के दो-विहाई बहमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाये कि राज्य सूची मे धक्ति किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व हो गया है तो सम ससद को उक्त विषय पर कानून निर्माण करने वा भ्रियकार प्राप्त हो जायेगा । इस प्रकार के प्रस्तान की भ्रवधि एक वप से भ्रधिक नहीं होगी परतुराज्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने प्रस्ताव वी भ्रवधि में एक वप के लिए भ्रीर बृद्धि की जा सकती है।

(२) प्रतुच्छेद २१० (१) के अनुसार सप ससद को जब देश म सक्टकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, सम्पूण देश के लिए कानून निर्माण करने का प्रियमार प्राप्त है। सभीय ससद तीनो सूचिया म लिखित किसी सी दियम पर कानून बना सकती है। चूल सकटनालीन स्थिति के रीरान समीय ससद को समस्त विचयो पर कानून निर्माण करने के अधिकार प्राप्त होने यह स्पन्ट हैं कि के द्वीम सरकार का स्वरूप सथात्मक से एकत्यक म परिवर्तित हो जायेगा। राष्ट्रपति द्वारा सविधान के स्मृत्य देश है अ तमत सकटकालीन दिवति के पोपणा द्वारा सप ससद राज्यों के लिए सनच्छेट ११८ के अनुसार विन्नृत सहित्यों को उपयोग में ला सकती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ने अनुसार विन्नृत सहित्यों को सरपाम करने हैं जिसके परिणाम स्वरूप के अनुसार विन्नृत परिवर्तित रहेगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति म सपीय ससद को सियान म उल्लिखित तीनो अवक्त्यापन सबयी सूचियों (सप राज्य एव समवर्ती) पर वानून बनाने वा प्रियम कार रहेगा। अनुच्छेद ११३ ३१४ के अनुसार सब वायपालिका को राज्य की वायपालिका सबयों को उपयोग म साने क सिए निर्देश दिये जा सकते हैं।

इस तरह सकटकालीन पोपपा के दौरान ससद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है चाहे वह विषय सथ-सुची के झतिरिक्त अप्य दोनो सूचियो म क्यो म उल्लिखित हो।

(३) सविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तमत यदि निसी राज्यपाल द्वारा राज्यपित को यह सुबना दी जाती है कि राज्य ना सबैधानिन यन सिवधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है राज्यपित उक्त राज्य में सस्टकालीन घोषणा द्वारा राज्यपित का सामान लागू कर सकता है। ऐसी परिस्थित अ राज्यपित के सकटनालीन घोषणा के दुरगामी कानूनी प्रभाव होंगे क्योंकि सप में द्वारा राज्य की समस्त कायपालिका सबधित बालियों का सहण किया ना सकता है मौर यह घोषणा की जा सकती है कि राज्य की विधान समा की बालियों ससद द्वारा या ससद के प्रयोगस्य उपयोग में लाई जा सकती हैं।

१ सी॰ एल्केजेडरोविकज-कान्सटीट्युशन डवलमेट इन इण्डिया, १९५७, पृ॰ ६२।

१६५० स सविधान के लागू होने के पक्ष्वात् समय-समय पर भारत के कई

राज्यों में राष्ट्रपति ज्ञानन बनुच्छेद ३१६ के बन्तर्गत लागू किया जा चुना है परनु मुख राज्यों में राष्ट्रपति शासन की तीत्र बालीचना की गई है। राष्ट्रपति भागन लागु करने के ग्रीचित्य का प्रशन विशेषकर उस परिस्थिति में उत्पन्न होना है जह बहु एक ऐम राज्य में स्वापित किया गया है जहाँ सत्तारूड दल केन्द्रीय सत्तारह दल से मित है। प्राय. ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की मालाचना का कारण यह होता है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को गिराने क लिए ही राष्ट्रपति भामन लागू विया है। यह स्वष्ट है कि इस प्रकार की स्विति तब ही पैदा हो सबनी है, जब बेन्द्रीय सरकार छीर राज्य सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के नियन्त्रण में हो है आलोचकों का यह तर्क है कि सविधान के धनुक्येद १५५ एव १५६ के अन्तर्गत राज्यपालों की निवृक्ति राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के सलाहानुमार करता है कोर बनुक्छेद ३५६ के बन्तर्गत यदि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति नो यह मुजना दो गई है, कि राज्य की शासन व्यवस्था भग हो चुनी है भीर इसको सविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति उस राज्य में सक्टनालीन स्थिति की घोषणा कर राष्ट्रपति शासन स्थापित कर सकता है भीर चीक राज्यपाल प्राप केन्द्रीय सत्तारूड दल से सवरित रहे हैं, राष्ट्रपति बासन को लागू करवाने में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को घपना सहयोग दिया है। स्त्री नम्बूद्रीपाद ने नहा है नि "वह स्यक्ति जो जीवन पर्यन्त नाग्रेस म रहा है. भाग्ने क्रिया भी निष्पक्ष होने का प्रयत्न करें परन्तु राज्यपाल के रूप में उसे

राजनीतिक दवायों को सहन करना ही होया।"" १६४७ ने माम चुनाव में केरल में, साम्यवादी दल को सबसे प्रधिक मन प्राप्त हए । कुछ निर्देशीय सदस्यों के सहयोग से विवान सभा म बहतम प्राप्त कर साम्यवादी दल ने केरल सरकार नी स्वापना की। जब कांग्रेस की साम्यवादी सरकार को गिराने भे २० महीन तक शफलता नहीं मिली, तब उसन केरल की साम्यवादी सरकार को जिराने के उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रत्यक्ष कार्यवाही को उपयोग में लान का निश्चय किया। इस प्रत्यक्ष कार्यवाही से काग्रेम का सात्पर्य राज्य ने विद्यालया, यात्री-परिवाहना एवं दश्तरों का घेराव करना था। प्रयस्त ६१,६५६ को करल की सरकार के विशोधी दलों ने काग्रेस के नतुल्व म सरकार ने विरद्ध पाग्यालन को और अधिक उप बनाने का निर्णय लिया। राज्य के मवर्तर डॉ॰ रामइएण रामाराव ने बान्तरिक ब्रमान्ति होने की समावना का देखते हुए। राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन भीवा कि राज्य में धान्दोतन की स्थिति इस

100

ई० एस० एस० नम्बुदीपाद—हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, प्रगस्त २२. tere .

स्थिति तक पहुँच चुनी थी निराज्य संशासन एवं सरेकार का सुबाह रूप से चलाना सनव नहीं है।

इस दृष्टिकोण से थहाँ बह देखना आउस्था है हि किन परिस्थितिया स राग्य के क्षेत्र स सत्रीयहम्पक्षेत्र उचित्र साना जा सक्ता है । शश्चिमक के प्रताहन, राग्यों के क्षेत्रा में सभीय हम्पक्षेत्र केत्रत निम्नितियत दो परिस्थितिया में ही उचित्र साना जा सक्ता है।

(1) ध्रमुच्छेद 392 ने अनुमार जब राष्ट्र में गमीर मनट पैदा ही जाये, जिममें राष्ट्र मी मुस्ला पर ध्राधान पहुँचने ना कर रहना है तो राष्ट्र भी मुस्ला में दूष्टिनोज से देन में मनटनमोता नियति मी खर्चा मार्पना मोगा मी जा सनों है। मिसमान ने अन्तर्गत राष्ट्रीय जीवन म यह गमीर मरटनानीन स्पित जन ही मानी जा मनती है, जब देन पर बाह्य खान्नमा हुआ हो या ध्रामित जना हो। यह है वा यदि राष्ट्रपति ने मनानुमार ऐसी स्पित के पैदा होन की ममानना है ता भी राष्ट्रपति मनटनानीन स्पित के पदा समाना है ता भी राष्ट्रपति मनटनानीन स्पित की खद्तीयना कर सानता है।

उपर्युत्त स्थिति से यय सरकार का हस्तक्षेप राज्यों के क्षेत्र में येय माना जा सकता है।

 कर्तेच्य है कि राज्य सरकार की सुरक्षा करें, जो बहुशत पर प्राथारित है भीर विसकी स्थापना सर्वेदानिक रूप से हुई है। सक्षेप में, सम सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रावृक्षेद रेश्व में सतुसार प्रत्येक राज्य सरकार का जो बहुमत पर प्राथारित है, बाह्य धाक्रमण एव भानारिक बखानिक से राहा करें, न कि ऐसी राज्य सरकार को राज्यपित ग्रासन के साध्यम से बखाँस्त करें।

बरनुत उपर्युक्त विषेषना से यह विदित होता है कि राज्यों के क्षेत्रों में राष्ट्र-परित्यासन स्थापित करने के लिए के क्षीय हस्तक्षेत्र केवल हो ही परिविचितियों नहें उचित माना जा सकता है। ह स्व प्रित्येश से यह कहने में कोई मितियोंनित नहें होगी कि १६४६ में जब राज्यपात रामकृष्ण प्रमाशन में केरल के सबय में राष्ट्र-पति की यह अस्तियेशन मेजा कि राज्य सरकार का बासन तज दृह चुका है तो बहु केरल की वास्तिक कर्षवानिक स्थिति के प्रमुक्त नहीं या बयोंक मुक्तमनी गम्बूमीपाद की सरकार को बाकार्य कियों कोने के समय तक राज्य विधान समा में स्थाद कानत प्राप्त था।

म स्पन्द बहुमत प्राप्त था।

प्रत्येक राज्यवाल को पद ग्रहण करने के समय यह शपथ वी जाती है कि 'मैं

अपनी पूरी पांचता से सर्विचान एव कानून के ग्रस्तित्व को बनाये रखूना एव

जनका सरक्षण करूँका ।

इसी प्रकार की शतथ राष्ट्रपति को भी पर पहण करने के पूर्व लेना सावस्यक है। मत यह स्थप्ट है कि राज्यपाल एव राष्ट्रपति वोनों का श्री नम्बूदीपाद के मत्रीनम्बल की रक्षा करना सर्वधानिक करतेव्य या। नि सरेतृ यह कहाँ था सकता है कि श्री नम्बूदीपाद के मजीमण्डल ने सर्वधानिक कारणों के बजाय राजनैतिक कारणों में बरवासत विध्या गया था।

सारत में किसी भी राज्य में, राष्ट्रपति शासन योगित करने में लिए राज्य-पाल की सुमिका का अध्योधन महत्व है। राज्यपाल में तिसुक्ति राज्यपित करने हैं अत दक्ष सन्दे स नजना किन होगा कि राज्यपाल पर नेन्द्रीय सरकार का अभाव नहीं होगा। स्वस्य जनगत तथा जनतान के लिए सह अस्यवस्थम है कि राज्यपान की मिलाग पर इस सब्दे में पुळ नेवानिक प्रकरोध हो। जातता मा, सह सर्वेशानिक प्रकरीय की एक परम्परा ने रूप में मानाना प्राप्त हुई है, जिसका निरुद्धर पात्र करना धारवास्य है। परम्परा में हुई कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य की सरकार, जिससो राज्य विधान सभा में नहुमत है, की सलाहानुसार

४—सपवाद ने सिद्धान्त का एवं अपबाद और सिद्धान्त के अनुच्छेद २३२ (१) में उत्तिखित है, जिसने अन्तिन्त यदि सप के दो या दो से अधिन राज्यों की विधान समाधी के तिए यह वादतीय प्रतीत होता है कि ऐसे विधयों पर जिन पर सिवाय अपुन्धेद २४६ एव २५० के अन्तर्गत सथ ससद को कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार उक्त राज्यों ने सर्वेद से सस सतद को प्रदत्त किया जाये और सिंद इस उट्टेश्य के लिए उक्त राज्यों को विधान समायों में प्रस्ताद गारित किये जाते हैं, तो सच-ससद को ऐसे विधयों के सवय से कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होगा। सरस रूप में यह बहा जा सकता है कि अनुष्टेद २५२ (१) के अन्तर्गत दो या दो से अधिक राज्यों की विधान समायों द्वारा यह प्रस्ताद पारित किया जाता है कि राज्य सूची में उत्तिविधत किसी विधय पर सप-सहद उन राज्यों के लिए कानून निर्माण करे तो सथ ससद राज्य सूची के उक्त विधय पर कानून बना सकेती।

५—प्रप्रत्यक्ष रूप से प्रमुच्छेद २५३ थे प्रत्यंग्य सथवाद का एव प्रत्य प्रथवाद देखा जा सकता है। उक प्रमुच्छेद के प्रत्यंग्य सथ सरकार को किसी देश के साथ की गयी सिंद, समझेते या उपसिष्ठ प्रीत किसी प्रत्यंप्ट्रीय सभा, सस्या या प्रत्य स्वावत द्वारा जिसे गये निर्णय को कार्योगियत कराने वे सिए कानून निर्माण करते का प्रियकार है। इस अनुच्छेद २५३ मे उपयोग मे साथ यथे शब्द 'प्रत्य सगठग' प्रस्य है और इस स्पटता के कारण इनकी व्याख्या एव उपयोग सेस सरकार द्वारा किसी सीमित भीर राष्ट्रविद्योग उद्देश्यो किया जा सकता है। डा॰ व्याप्तित कारण स्वावत प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या है। डा॰ वेनिक का कहता है कि "स्वत्यमेदाविद्यास्थान मण्डल, जो एव ऐसा प्रत्यांच्ये सगठन है, जिसमे बमी तथा लका के महाविद्यास्था सरकार प्रपत्ता सेनाप्रिकार स्वाप्त करती है। 'कामित्रकार एव को से स्वर्ताक्ष्य मान्तर्राष्ट्रीय सगठती है। इस सनुच्छेद ने कतियय बच्चों के रहे जाने से यह राज्यों के प्राप्तिकार कारण प्रतिक्रमण है कि इसकी उपग्रुत्तता सदेहबद सगती है। '''

६—मनुच्छेद २४६ के प्रनुसार सब सरकार को राज्यों के सबब में कुछ प्रशासकीय शक्तियाँ भी प्रदत्त की यई है। इस प्रनुच्छेद के प्रनुसार सब सरकार राज्यों पर प्रपना नियत्त्रण रखती है।

इस अनुन्देद के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग इस तरह से क्या जाना चाहित्रे कि सम ससद के नानूनों को मान्यता मिन सके और सम की नार्यग्रानिका कार्तिकों का जन्यों क हत दृष्टिकोंग हो, राज्यों को निर्देशन देने के लिए किया जा सकता है। अनुन्देद र १५० के अनुसार सम के किसी भी राज्य की कार्यपालिका बक्ति का उपयोग इस तरह से करना चाहिये कि जिससे

१. घाई० जैनिस्ब-'सम केरेक्टरस्टिक्स झाफ दो कान्स्टीट्युशन झाफ इंग्डिया, १९५२ पु० ६६ ।

(11) उन सिद्धान्तो का निर्धारण करने के सम्प्रत्य में, जिनके प्राचार पर सप सरकार राज्यों को मनुदान देशी 1

(m) सघतया निर्मा राज्य ने मध्य निये गयं विसी वितीय समनौते को

नायम रराने या उसमे परिवर्तन नरने ने सम्बन्ध म । (1V) राष्ट्रपनि द्वारा प्रेषित नोई सी विषय जो बित्त नी दृष्टि से महरव-

पूर्ण है।

(१) अनुच्छेद ३६० के अनुसार राष्ट्रपति को विक्त सप्रधी सक्टकालीन स्थिति के लिए हुउ विशेष शवित्रयो प्रवक्त की गई है। यदि राष्ट्रपति धाश्वस्त हो जाता है कि राष्ट्र मे परिस्थित हर स्र अस्त को गई है। गई है कि जिससे मारन या मारत के कि राष्ट्र मे परिस्थित हर सम्वर्ग को गई है कि जिससे मारन या मारत के कि सिंह को पीएणा कर सकता है। इस अकार की सक्टकासीन स्थिति में सम की बायेपारिया कित ना उपयोग राज्यों के विक्ता का करवा है। सुदूव काना के विषय किंदि किये की की कि लिए किये के अस्त की की विश्व किया जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यों को यम की सिंह कि सिंह की की की सिंह की समर्गत राज्यों के यम कि सिंह की सिंह

ततीय-राज्या की स्वावत्तना की एक धन्य कारण से भी हानि पहुँचने की समावना है। राष्ट्रीय मोजना भाषोग की कामेप्रणाली के दिष्टकोण से यह कहा जा सकता है नि इसर्स भी भारत में केन्द्रीयकरण भी भावना तथा एकात्मक प्रवृत्तियो को परित्याली होने में सहयोग मिला है। राष्ट्रीय योजना आयोग की स्वापना १६५० में हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय सामनो का सतुलित उप-योग करते हुए राष्ट्र ना विकास करना है। राष्ट्रीय योजना आयोग की सूमिका जो सामने उगर वर शाई है उसका वर्णने श्री सन्यानम ने निम्नलियिन शब्दों मे क्या है, श्रीर जिससे यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों की किस हुद तम नेन्द्रीय सरकार पर अपनी विज्ञास योजनाओं को सफल बनाने के लिए निर्भर रहना पढना है। उनना कहना है—'कुछ समय पूर्व राज्य समा मे एक केन्द्रीय मत्री के इस वनतव्य को सुनकर मैं बाक्वये-चिन्त हो गया कि यदि राष्ट्रीय योजना श्रायोग विसी योजना को स्वीवृत कर लेता है तो वह भी उक्त योजना को स्वीवृत कर लगा। योजना ब्रायोग का सर्विधान में उल्लेख नहीं, है ब्रीर न ही इसकी स्या-पना निसी ससदीय नानून से हुई है। तब भी इसे केन्द्रीय तथा राज्य सरवारो की सारी योजनामो नो प्रारम्म नरने ने लिए, निर्णय देने की प्रास्ति है। योजनाम्रो को वित्तीय अनुदान देने या न देने से कार्यान्वित किया या नहीं किया जा सकता है। नि सरेह, राज्य सरकार किसी भी योजना को वगैर योजना घामोग के प्रेषित किये, प्रारम्भ कर ककी है, यदि बहु कैन्द्रीय श्रहायका केल प्राप्त होने के, न कैवत उसी योजना के लिए, परत्तु अन्य योजनाओं के लिए भी, वरिणामी का सामता करो को तैयार है।"

चतुर्व-मिवधान के धनवर्षन कुछ प्रतिरिक्त तत्व विश्वमान हैं, जिनसे नारतीय सभीम व्यवस्था में एकास्मक प्रवृत्तियों के दश होने से सहायता पहुँचती है।

उत्तहरूप नजरूप (क) आरत में प्रतिव नारतीय बेनामों के परिकारियों भी नियुनियां तथीय कोच सेवा धायोग के मुक्तानुमार, गृहस्तानय को करते का प्रतिवार है। इस प्रतिवारीयों को नियुन्ति, प्रतिवार प्रतिवार सद पर होंगे है। इस विशेषण के कारण सम्प्रते जात्व सं, प्रतासन के क्षेत्र से समानत क्ष्मा एका

पाई जाती है, जिसने पनस्वरूप वेन्द्रीय मासन को बुटता प्राप्त होती है।

(अ) भारतीय न्यायपासिका ना साठल एव नार्यों वर्षामां की सम्मान की स्थानतीत एवं विश्वासी स्थान की स्थानतीत एवं विश्वासी स्थान की स्थानतीत एवं विश्वासी स्थानतीत है।

स्थानतीत एवं विश्वासी स्थानतीत स्थानतीत स्थानतीत स्थानतीत है।

सामाया दी गई है। सम के अस्पेन राज्य में साविधान के अनुव्येद १२४ के प्रपुत्ता कर प्रमुख्य स्थान स्थान

निर्णेस से सबैपानिक दिवानी तथा फीनदारी सामलो से ब्रंपील की जा सकती है। सही सह स्वष्ट है कि जारतीय व्यायपातिका के संपठन तथा बायों के चरिट-

कोण से, स्माधिक क्षेत्र में एक रूपना स्वापित की गई है।

(ग) आरत ने सहिषान में नेयत एक नागरिकता (जारनीय नागरिकता) का प्राचनात दिया गया है। निस्तानेह इस प्रावस्थान का उद्देश्य आरत की समासक प्रमासी में, मनौर्वतानिक द्विटकीय से समूर्य आरत के प्रति नागरिकों की प्राप्तक को सिक्तानी ननात हुए एका मन प्रवृत्ति के सायारों को मिल्तानी करता है। समरीया म हमने विकरीन को प्रकार की नागरिकता प्रदात हैं (एक सथ की नाग-रिक्ता तथा इसरी सथ के उस सम्बन्ध की नागरिकता जहाँ पर व्यक्ति निवास करता है।

उत्पृत्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हाता है हि चारतीय वध व्यवस्था से एवात्मक प्रवृत्तियों स यत्न प्रतिकाशनी हैं, बरन्तु इमने यह निरुष्ट में निवासना कि इन एवात्मक प्रवृत्तियां द्वारा नारतीय तथा च्यवस्था का संगीय क्वस्य कुल हो गया है, जनत होगा । बाल्य के मारतीय सर्वियान के सन्तर्यंत एक भूष राज्य की स्थापना की भूष है, जिमन मुग्नेंद्र सरकार सर्वत्या मानियांत्री है

१. के व सत्यानमे - द्रान्डीशन दन इण्डिया, १६६४ मूळ २० १

# संघीय कार्यपालिका

पूर्व प्रध्यायों के प्रध्ययन से यह जात हो चुका है कि भारत के सर्विधान के मनुन्देद १३ (१), ७४ (१) तथा ७१ (३) मारतीय ससदीय प्रणाली ने मन ग्राघार हैं। राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के समय भारतीय नेताग्रो का उद्देश्य ब्रिटिश राज्य से स्वतनता प्राप्तकर मारत मे ससदारमक प्रणाली स्थापित करना था। लोक समा मे इस विषय पर १९५७ मे प० नेहरू न कहा या-"हमने इस ससदारमन प्रणाली को सोच समझकर चुना है। हमने यह प्रणाली क्वल इस लिए नहीं चनी है कि पूर्व म हम प्राय इस विषय पर विचार करते रहे, परन्तु हमने यह सोचा कि यह हमारी प्राचीन परम्पराध्ये के बनुकूल है । हमने इसे चुना — जहाँ पर हमे श्रेय देना है, हम देना चाहिये-नयोक्ति हम इसनी कार्य प्रणाली से, जैसी दूसरे देशों में, विशेषकर ब्रिटेन में हैं, सहमत थे।"1

इसी के फलस्वरूप, भारत की ससदीय प्रणाली म सचीव कार्यपालिका के दी माग हैं। (क) भारत का राष्ट्रपति-राष्ट्राध्यक्ष, भौर (ख) सधीय मन्नी परिपद -एक उत्तरदायी मन्नी मण्डल के रूप मे, जिसका सामृहिक उत्तरदायित्व प्रपती नीतियो तथा नायों के लिए ससद के निवले सदन के प्रति है। मारत मे कार्य-पालिका की शक्ति पर सबसे महत्वपूर्ण अवरोध भारतीय ससदीय प्रणाली के अन्तर्गत मत्री मण्डल के सामूहिक उत्तरदायिख का सिद्धान्त है। इस अवरोध की विशेषकर मनिव्यक्ति नार्यंपालिका एव व्यवस्थापिना (ससद) वे सम्बन्धों मे प्रद-शित होती है। यहाँ पर इस विषय को ध्यान म रखना अति भावश्यक है कि सधीय कार्यपालिका वे दोनो हिस्सो (राष्ट्रपति व सत्रीपरिषद) वे सम्बन्ध, सवि-धान की चार दीवारी में, विभिन्न सर्वधानिक प्रावधानी और प्रमिसमयी द्वारा निर्मास्ति तथा निर्मान्त्रत विथे जाते हैं।

सपीय कार्यपालिका का अध्ययन निम्नलिखित तीन आधारो पर किया जा सकता है।

१. प० नेहर-जवाहरक्षाल नेहर ज स्पीचेज खड ३. घणस्त १६५७, पर्वालकेशस डिविडन मिनिस्ट्री झाफ इन्कारमेशन एड बाडकास्टींग ।

१०द भारतीय शासन और राजनीति

१--राष्ट्रपति एव मनी परिषद की स्थिति तथा सम्बन्ध । २--सभीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति तथा मत्री मण्डल) की शक्तियाँ।

3-मत्रियो के जलस्टायित्व का सिद्धान्त ।

मारतीय सर्विधान के अनुच्छेद ५२ के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद स्पापित किया गया है और अनुच्छेद ४४ के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होगा, जिसमे दो प्रकार के सदस्य होते हैं, (क) सप के विमिन्न राज्यों के विचान समाबों के निर्वाचित सदस्य, भीर (ख) संसद के दोनों सदनों के निवांचित सदस्य ! इस निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की समान सल्या मे मत प्राप्त नहीं हैं । यहाँ महदान का सिद्धान्त 'एक व्यक्ति एक मत' ना नहीं है, परन्तु यह है कि प्रत्येक मतदाता की उस प्रमुपात में मत प्राप्त हो, जिसमे कि वह एक विशिष्ट जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

वृंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के वो प्रकार के सदस्य हैं भत. राष्ट्रपति वे निर्वायन के लिमे इन दोनो प्रकार के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने मत प्राप्त हैं, यह जात करने के लिए निम्नलिखित दो सूत्रों को, सविधान के बन्तर्गत मान्यता दी गई है।

(क) राज्य विधान समा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मती की सरुवा =

राज्य की जनसहया राज्य विधान समा के निर्वाचित सदस्यों रे०००

की सम्पर्ण सस्या (ता) ससद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतो की सक्या

समस्त राज्य विधान समाग्री के निर्वाचित सदस्यों को प्रदत्त मतों की सस्या

ससद के सारे तिवाचित सदस्यों की मस्या

राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसा सविधान मे उत्तितित है, मनुपातिक प्रति-निधित्व पद्धति ने एकल सङ्गणीय नत प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान हारा किया जाता है 1

राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी नतीजों को माल्म करने के लिए निस्नतिशित मावश्यकताएँ हैं। सर्वप्रथम, सही गतों को प्रथम विकल्पों के माधार पर ग्रलग-भारत करना भीर प्रत्येक प्रत्याची ने प्रयम वरीयता (विकल्प) के मती की गणना करना ।

१. भारतीय सविधान श्रनुब्देद ५१ ।

२ भारतीय सविधान-सनुच्छेद ७१-७३ ।

दितीय, यह निर्धारित वरना वि निर्वाचित होने वी स्यूनतम मन सत्या वया है ? इस स्यूनतम मत सम्या वो निम्नितियत सूत्र के झायार पर निर्धारित किया जा सक्ता है । उदाहरणायं जहीं यदि सही मतो वी सरवा २०,००० है तो निर्वाचन वे लिए वोटा २०,००० २ १ वे वरावर होगा । इसा । प्रस्ता प्रमं यह है कि विसी मी प्रत्याची वो १०००१ मता वे प्राप्त होने पर निर्वाचित घोषित

यह बिरित रहे वि यदि वेचल दो प्रत्याची राष्ट्रपति पद वे लिये हैं तो उपर्युक्त सूत्रानुतार, दोनों में से विन्ती एक को न्यूनतम मत सब्बा वे रूप में यहुमत प्राप्त हों सक्ता है। परन्तु यदि प्रत्याचियों को सदया दो से प्रयिव है तो यह समय हो सक्ता है नि उनमें से विन्ती को न्यूनतम कोटा न प्राप्त हो। उदाहरणार्थ, यदि चार प्रयाची है, मनो ना विमाजन निम्नलिधित रूप से हो सक्ता है —

यहाँ पर क्लिसी मि प्रश्वाची को न्यूनतम यत सर्या या १०,००१ मन प्रास्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिस प्रत्याची को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, उसके मत जन पर उस्तिखित दूसरी वरीयता वे धाधार पर शेष प्रत्यानियों को हस्तावरित किये जायेंगे।

यदि मान लिया जाये कि दूसरी वरीयता के प्राधार पर यदि प्र को ३००, ब-को २,६०० और स-को १०० मत, द-को ३,००० मतो से से दूसरी यरीयता की प्रनुतार दिये गये हैं तो निम्नतिश्चित स्थिति हो जायेंगी —

$$\pi$$
-  $0,000 + 300 = 0,300$   
 $\pi$ -  $5,500 + 3,500 = 6,000$   
 $\pi$ -  $3,500 + 800 = 3,000$ 

परन्तु भव भी निसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पुन स के मत, क्योंकि इसकी सबसे कम मत भाष्त हुए है, अमली बरीयता के अनुसार, गोप प्रत्याधियों नो हस्तावरित कर दिये जायेंगे । बदि स के ३,७०० मतो में से २,४०० म की, और १,३०० व को अमली बरीयता के अनुसार हस्तांतरित कर दिये जाते है तो स्थित निम्मतिश्चित होगी —

$$a - b,800 + 3,00 + 3,800 = 6,900 = 6,900$$

स- हस्तावरित

द- इस्तातरित

मारतीय शासन भौर राजनीति

220

गरा व को स्पष्ट रूप से, निर्वाचन बोटा (१०,००१) से मधिर मन प्राप्त होने से उसका निवासित घोषिन कर दिया जायेगा, क्योंकि अ-को उक्त कोटे से कम मन प्राप्त हए हैं।

द्या० एम० पी० समाँ ने इस निर्वाचन पद्धति की दो कठिनाइयो पर प्रकाश ब्राला है।

सर्वप्रयम, पराजित प्रस्वाशी को हटाने की प्रक्रिया में कभी ऐसा होता समन है कि सबस कम मन प्राप्त किये दो प्रत्याधी ऐसे हो, जिनके मदी की सहया ममान हो । ऐसी स्थिति म इन दोनों में से उस प्रत्याशी को पराजित मौपिन किया जायपा, जिसे प्रथम करीयना में सबसे कम मन मिलें हों। यदि इन दोनो प्रायाधिया को प्रयम बरीयना के भी समान मन मिले हो, तो इसका निर्णय लाट (चिट) शलकर किया जावेवा ।

दितीय, यदि कुछ मन पत्रा म दिनीय, नृतीय या समनी वरीयना का सल्नेन नहीं है, क्षे एमी स्थिति म शेष प्रत्यागियों की, मदी का इस्तान्तरण धर्समय हो जायगा । जिन मन पत्रा पर द्वितीय, सुनीय या धयली वरीयना ना उन्नेत्व नहीं श्रिमा गया है, उनको समाप्त माना जानेगा ।

सर्विधान ने धनुच्छेद १० ने अनुसार किसी भी ब्राक्ति को राष्ट्रपनि के पद पर निक्रीवित तब तब ही विद्या नायेगा यदि (व) वह मारत का नागरिक हो, (स) १५ वर्ष की उस्र हो, (क) वा सोक्यमा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यक्षा रलता हो, और (याँ) जी मारत सरकार या राज्य सरकार या किमी स्यानीय ग्रायकारी के ग्रायीन किमी बैडनिक यद पर नियक्त न हो । परन्त कुछ पद ऐसे हैं जिन पर यह प्रतिवन्त्र लागू नहीं होता है, जैसे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, नैन्द्रीय एव राज्य सरनारी के मतियों ने पद । राष्ट्रपति कुरु कार्यक्रम पाच साल का होता है। व यदि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की मृत्यु, स्यापपत्र या महामियोग द्वारा रिक्त हा जाता है तो अनुष्टेद ६२ (२) के अनुवार ६ महीने मे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिये। नये राष्ट्रपति के निवांकित होने तक उत्सरध्यति ही राष्ट्रपति क कार्य का करेगा । राष्ट्रपति का बेदन प्रतिमाह १०,००० ६० है। मनद को उनके वेदन, मत्ते तथा विशेषाधिकार के सबज में निर्णंत लेन का धाध-कार है। भवकान प्राप्ति के परवान् उसको प्रतिवर्ष १५,००० र० पेन्सन एव १२,००० द० मत्ते के राव में मिलता है। बार्न पद को बहुण करने के पूर्व राष्ट्र-

२ भारतीय सर्विधान-प्रतुस्केट ५६ (१)

१. एम॰ पी॰ शर्मा—'व गर्वमेष्ट ब्राफ द द्रष्टियन रिपल्लिकः' १६६१ 50 to5 t

# सघीय कार्यपालिका

पति को यह शपय प्रहण करना प्रावस्थन है, "मैं श्रद्धापूर्वक का प्रावन करूँगा तथा प्रपनी पूर्ण योग्यता से सविधान तथा एव प्रतिरक्षण नरूँगा तथा मैं सारत की जनता की सेवा तथा कर्याण म पहुँगा।"

इस दृष्टियोण से, यदि राष्ट्रपति सविषात का उल्लयन करता है तो उस पर महामियोग समागर उसे परच्युत किया जा सकता है। है सबद में कियी भी सदत में महामियोग दस्ताय प्रस्तुत किया जा सकता है। है। सबद में कियी भी सदत में महामियोग दस्ताय पर जा सकता है। है सह है पर हित हो है। इस प्रकार के स्वत्य के प्रकार के स्वत्य के प्रकार के सिंद होने पर महामियाग भी गातें पूरी मानी जाती है। इस प्रस्ताव के सिंद विविध्य नेति हम में से प्रमाविद्य विदाय के सिंद होने प्रकार के से तो तिहाई क्षत्र के प्रकार हो जाता है तो इसका प्रवे हैं कि राष्ट्रपति कर प्रमियोग समा दिया गया है और हमरा प्रकार कर कर में उपस्थित हो अता है तो इसका प्रवे हैं कि राष्ट्रपति कर प्रमियोग समा दिया गया है और हमरा प्रकार कर प्रकार के प्रकार कर कर में उपस्थित हो रूप से सहन के प्रारोपों की जाय करेगा। राष्ट्रपति क्य सहन में उपस्थित हो तहाई बहुमत हारा राष्ट्रपति पर समाये गये प्रारोप तिद्ध हो जाते हैं तो महामियोग का प्रस्ताव सिंद माना जायेगा, भीर फलस्वरूप, राष्ट्रपति हस्ताव स्वीवृत होने यो तिवि से परव्यत हो जायेगा।

राष्ट्रपति की सबैवानिक स्थिति और मंत्री मण्डल से उसका सबध

सभीय वार्यपालिका वी शांकियाँ भारतीय सविधान के अनुक्टेंद्र १३ (१) के अनुकाद राष्ट्रवित में निहित है। अनुक्टेंद्र ७४ (१) के अनुसार एक मंत्री मण्डल की स्वापना राष्ट्रवित को उसने वार्यपालिका संवधी कार्यों में सहायता तथा सलाह देने के लिए की जायेगी। मंत्री मण्डल का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता। परन्तु, भारत में ससदायत प्रवासी का मूल विद्यानत, सविधान के अनुक्टेंद्र ७५ (३) में निहित है। इस सिद्धान्त के अनुसार भंत्री मण्डल साम्रहित रूप से ससद के निकले सदन, जोकसाम, के प्रति उत्तरदायी है—जो ससद का प्रतिनिध सदन है वधीन इसका निर्धानन सार्वजनित यसका मताधिकार के सिद्धान के अनुसार होता है। राष्ट्रपति तथा मंत्री मण्डल के सवधो ने वस्तु रिक्षित ने जात करने के लिए यनुक्टेंद्र ७५ (३) के निहित सामृहिक उत्तरदायिक के सिद्धान की प्रमुक्त

१. भारतीय सविवान-बनुन्देद ६०,

२. वही —शनुस्क्षेद ६१,

एवं महत्व को समफता अति आवश्यक है। सरकार की नीतियों तथा कार्यों के बृध्दिकीण से, मंत्री मण्डल प्रत्यक्षरूप से लोकसमा और श्वप्रत्यक्षरूप से या प्रतिम रूप से मतदातागण के प्रति उत्तरदायी हैं । चूँकि संविधान में स्पष्ट रूप से सामू-हिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है, इसका केवल यह धर्म ही नहीं है कि मंत्रीमण्डल को ससद (लोकसभा) में बहुमत की इच्छानुसार सरकार की नीतियों एवं कार्यों को चलाने का कर्तव्य है, परन्त यह भी ग्रधिकार है कि सरकार की नीतियो एवं कार्यों को अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के धनसार उपयोग ये लाने के लिए इस सिद्धान्त की कार्य-प्रणाली में किसी का हरनक्षेप तब तक न होने दे, जब तक उसे बहुमत प्राप्त है, अन्यया संसदीय सरकार का कोई मुख्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि बास्तव में संसदीय सरकार की झारमा सामृहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। यदि इस सिद्धान्त को नष्ट किया जाता है तो संसदीय पद्धति नष्ट हो आयेगी। साधारण परिस्थितियों में, जब मश्रीमण्डल को लोकसमा के बहुमत प्राप्त हैं राष्ट्रपति केवल नाम मात्र व्यजमात्र का कार्य-पालिका के रूप में संत्रीमण्डल कोसलाह के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि यदि राष्ट्रपति इसके विषयीत कार्य करता है तो मधीमण्डल के समक्ष सिवाय प्रपत्ते राष्ट्रियों देशने विश्व हैं जिकत्य नहीं रहेशा। यदि प्राप्त चुनाव में पुन: पुराने संबो-मण्डल को यहुमत प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति को मत्रीमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य होना होगा। सपीय संबीमण्डल के लोकसमा के प्रति सामू-हिक उत्तरवायित्व को संविधान द्वारा मान्यता देने का कोई ग्रर्थ ही नहीं रहता, यदि मंत्रीमण्डल को लोक समा में बहुमत रहते हुए, सरकार के नीतियो एवं कार्यों के लिए अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। सविधान निर्मातायों की व्यावांक्षायों को सही रूप से व्यालूम करने के लिए, संविधान के बातुच्छेद ७= उपबन्ध (ग्र) एव (स) जिनसे, मंत्रीमण्डल के निर्णय लेने के बाधकार पर प्रकाश डाला गया है, ज्यान में लेना प्रावश्यक है। सनुष्टेद ७० (प्र) के प्रमुसार प्रधान मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की मत्री मण्डल के लिए गये सारे निर्णयों से धनगत कराना आवश्यक है। धनुच्छेद ७६ (स) के धनुसार यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि प्रयान मत्री विसी मुद्दे को जिस पर केवल एक मंत्री द्वारा निर्णय सिया गया है, परन्तु जिस पर मत्रीमण्डल द्वारा विचार-विमर्श नही किया गया है, सारे मत्री-मण्डल के विचार के लिए प्रस्तुत करे, प्रयान मंत्री का यह नतंब्य होगा कारिन-ग-गण्यक के मान्यक के तार्य उनस्कृत कर, अवान भवा का यह नत्यक होगा है जिस हुन है की मंत्री मध्यक के सम्बाद रहे। विविद्यात निवादिता कि स्वृत्येद एक उन्दर्भ (प) एवं (स) दोनों में 'निष्यं में कद का उपयोग किया है, जो इस बात का दोतक है कि 'निष्यं' तेने का प्रिकार मंत्रीमण्यक को ही सींग मात्रा है। यह ने कहा है कि 'हिंदूसरे संविद्यात होगा उपयुक्त ने कहा है कि 'हिंदूसरे संविद्यात होगा उपयुक्त ने कहा है कि 'विद्यार संविद्यात होगा उपयुक्त ने इसके दे यह गारी के समान रखा गया है। यदि ऐसा नहीं हो, तो मंत्रीमण्यक भौर ससद के उत्तरदायित्व के सारे प्रश्न पर भ्रामात पहुँचेगा । ससद सार्व-भीम है।"

सर्विधान ने प्रमुख निर्माता डा० धम्बेदनर ने इसी पक्ष पर वल देते हुए सबि-थान सभा मे चार नवम्बर १६४८ वो यह कहा— राष्ट्रपति वी वही स्थित है जो, राजा की ब्रिटिश सविधान म है। वह राज्य का, न कि नार्यपालिका का प्रध्यक्ष है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वरता है न कि शासन करता है। वह राष्ट्र वा प्रतीक है। शासन मे उसका स्थान उस यत्र के मोहर के समान है जिससे राष्ट्र के निर्णय प्रदर्शित होते है ।"2

भ्रपने मापण मे डा॰ राजेन्द्र प्रसाद ने २६ नवम्बर, १६४६ को सविधान समा में कहा-"स्वय सविधान में ऐसे प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति की मंत्री-मण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य करते है, परन्तु यह मान्य है कि ब्रिटिश सर्विधान की यह परम्परा है कि राजा प्राय मत्री मण्डल के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, इस देश मे भी स्थापित की जायेगी, और राष्ट्रपति सब भागली मे सबैधानिक राष्ट्रपति (प्रध्यक्ष) ही रहेगा।"3

इस दृष्टिकोण से यह कहना उचित है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के पद के सर्वधानिक स्वरूप को सही रूप से समभाना है, तो यह ग्रावश्यक है इस मामले को मारतीय ससदीय प्रणाली के मूल सिद्धान्त- मत्रीमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त ने सदमं मे ही समझा जाना चाहिये। यदि राप्ट्रपति के पद के सबैधानिक स्वरूप की व्याख्या, इस तथ्य से पूचक् रहकर की जाती है कि सविधान द्वारा ससदारमक प्रणाली स्थापित की गई है, तो राष्ट्रपति के पद के बास्त-वित स्वरूप के सम्बन्ध में सही ज्ञान प्राप्त न हो सकेगा । प्रनुच्छेद ७४ (१) मी कठोर तथा सकीणं व्यारया करने से यह गलती हो सकती है कि सविधान द्वारा स्थापित ससदात्मक प्रणाली को ध्यान मे न रखा जाये, और राष्ट्रपति की स्थिनि तमा शक्तियो की केवल अपूर्ण या एक तरकी जानकारी प्राप्त हो। यह सत्य है कि राष्ट्रपति के लिए मत्री मण्डल की सलाह मानने के लिए सविधान में लिखित कोई बाध्यकारी प्रावधान नही है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रीमण्डल की सलाह मानना कानूनी दृष्टिकोण से बावश्यक होगा। जैसे प्रो० डी० एन० बैनर्जी का कहना है— मुदय निषय है वि राष्ट्रपति वानूनत अनुच्छेद ७४ (१) वे अन्तमेत अपने मत्रीमण्डल की सलाह, सारी परिस्थितियों में, स्वीकृत करने के लिए बाज्य है

१ प० नेहरू—हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, ८ जुलाई १६५६ । २ यो० प्रार० श्रम्बेटकर—कान्स्टोट्युप्नट झसेम्बसी डिबेट्स भाग ७ पृ० ३२ । ३ डा० रानेन्द्र प्रसाद—कान्स्टीट्येन्ट झसेम्बली डिबेट्स भाग १०, पृ० ६८६ ।

पर नेहरू में सवियान समा म बहा था कि सौवपान निर्मातामा का उद्देग्य राष्ट्रपति को बास्तविक मन्ति नहीं देश था, परन्तु उसरी स्थित को प्रतिष्ठापूर्ण

यनामा या ।

भीने वा ने सविधान में अनुसार अपनंर जनरन को मुख शिवनयों नर-वियोगनुसार उपयोग में लाने के लिए प्रक्त है और अपन अविनयां ना नह मित्रयों के परामतों पर उपयोग में लाने के लिए प्रक्त है और अपन अविनयां ना नह मित्रयों के परामतों पर उपयोग में लाता है, परन्तु शास्त्रक में की बंध में एवं परम्परा की स्थान्या हो गई है, जिसके अन्तर्गत त्या कर कर सारे आपनी पर—उन मामलों पर मो तो उत्तरे स्विवंत के साव्योग के प्रयास के स्वायं में है, अवीमण्डल की सत्ताह चतुनार अपनों मित्रयु है, क्षेत्र ए लातिस्यों से, इन्ह्र विवेद हैं। इन्लेक्ट में त्रिटिश राजा सैद्धानिन प्रवृत्त मित्रयु है, क्षेत्र ए लातिस्यों से, इन्ह्र विवेद हैं। मुक्ति तिर्वेद सिंद्यान पर अवीने मित्रयु से हिमा से दियान पर अनीमण्डल की सत्ताह अनुसार ही वार्ष पर विवेद हैं। मुक्ति तिर्वेद सिंद्यान पर अपनीमण्डल में हो निर्मा है। जिसने जनस्वरूप, वही राजति में हो मित्र सार्वानिक परिपर्वत सीमत सार्वानिक परव्यामों से ही त्रिटिश राजति यू मारत में राजति में हो मार है, जिसने जनस्वर्ण, वही राजति में स्थानी में उपयुत्त हो पर न्तरपूर्वत के साम अपने हो की सार्वान में सा

हुवीय, सिषपान में विविष्ट बाध्यकारी प्रावधान, बिसवे होने से साद्र्याते नो मसीसण्डल की सलाह के मनुसार समस्य परिस्कितियों स कार्य करना होना, न गानिन् दुर्भान्य नहीं रखा गया कि यदि कियी वरिस्कित से साद्र्याति को हे बत्तवान-पूर्वेय कार्यवाही नरने की सावस्यनता हुई वो यह स्विधान ने मनुबूल ही हों। सवेष में साद्र्याति ने साद्र्य ने हित से स्वतत्रतापूर्वेय वार्यग्रही वरने में नित्य सिंद-

१ प० नेहरू—'कान्स्टीटुएव्ट झसेम्बली डिबेट्स भाग ४ पृ० ७३४ ।

स्यिति की कल्पना बरना कठिन नहीं है, जहाँ सधीय मत्रीमण्डल का मत किसी राज्य की सर्वधानिक यत्र के समाप्त होने के कारण राजनीतिक हो, भीर जिसके भाषार पर वह ऐसा निचन ले जो उसके राजनीतिक हित में हो, पर राष्ट्र के हित साधार पर वह एसा तम्बन ने को उनके राजनात्रिक हित में हु, पर राष्ट्र के हित में न हो। देसे मानने ये पाएपूर्वी कर माराज का के सम्पन्न के कर में सह कर्पम हो बाता है कि वह यह देखे कि राज्यों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार विधा आपे स्रोद केशीय सरकार का निष्यं होंने मानने के सबस्य में राजनीतिक प्रसाद में न किया बाये। हुए होंगे परिवर्णियों के देशियोंक में हैं सरिवान में कीई साध्य-कारी प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे राप्ट्रपृत्व को स्था प्रदीमकृत की सताह के कार्य प्रावधान नहीं एक नथा, अलाव प्रमुप्त न चाव भावनाव्या ना उपाधु क स्वमूबार चना होगा । प्रच्यु वह निष्यत है कि हम तरह वे भीवे हुन नम में होंगे । बालारणामा पायुवित मधीमण्डल की बताह के प्रमुख्तार ही प्रचेत्र कार्य करोगा । इस विध्य के सदम में विनित्यत देशे वे कहा है— "यह समावना समाण नहीं को या सन्त्री है कि पायुवित सर्विधान के सम्बर्धन सरस्त्र तरिन्त्राती चन सके, व ही कि राष्ट्रपति निरकृत हो सके। लोक समा वे प्रत्येक पाच वर्ष के पश्चान मग करने का प्रावधान, राष्ट्रवति पर ससद द्वारा महाशियोग सवाने का प्रावधान, मनीमण्डल व लोकसमा के प्रति सामृहिक उत्तरदायित्व क सिद्धान्त के लिए प्राव-धान. इन सारे प्रावधानी से यह निष्मय-निमाला जा समता है कि शास्त्रपति कठिनता से ही निरदुन हो सरेगा । इस तरह शास्त के सविधान में राप्ट्रपति के निरदुश न होने हुतु न तो उसे अधिक पनिदेशांसी बनाया है 🗷 ही, प्रधान मंत्री एवं मंत्रीमण्डल को देण का प्रशासन उनके राजनीतिक दल के हिलों में न बलाने देने के लिए राष्ट्रपति को कमजोर बनामा है।" राष्ट्रपति एव सपीय मनोमण्डल के सबधो के दृष्टिकीण से, झन्त में भारतीय सर्वोत्तर पर पायन जनावन्त्रत व जना न पून्यत्व एत होते स्वत्व न सारताव सर्वोत्त्व स्वाधानन के राम साहव "राम अन्यता कपूर सौर सम्य बनाम पत्राव राज्य के प्रकरण में दिर स्य निर्मय वो प्रस्तुत किया वा सकता है, 'दारहर में पून्यत्व स्व तुत्य नार्येपालिका को सपने वार्य, ध्यवस्थापिका के नियन्त्रण में रहकर करता है। हमारे सविधान ने धनुन्देद १३ (१) के धनुसार सच की कार्यणालिका शक्तियां

. पान निर्माण न किनी सर्वपानिक कावट को सविधान ये नहीं एका । परन्तु ऐसी परिस्ति निर्मा बहुत कम होयी और राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थिति में सब में सामग्रासिन होना नाहिन कि सावद एवं राष्ट्र दोनी उसके साथ है, और जिसके प्राप्त करने हैं के लिये तलाल साथ पुनाब करवाता साववक होना । ऐसा प्रभीत होता है कि हमारे सविधान निर्माण हता का समिक्र नहीं में कि हमारे सामग्रास प्रमाल के स्वार्ण के समिक्र नहीं में कि हमारे सामग्रास प्रमाल के प्रमाल के स्वार्ण के समिक्र नहीं में कि हमारे हैं स्वर्ण होता है है स्वर्ण होता करने हैं, स्वर्ण राष्ट्र स्वर्ण होता है के स्वर्ण होता है के स्वर्ण होता है हो। ऐसी परि

१ टी॰ वे॰ टोपे-इ बानस्टोट्युशन द्याफ इस्ट्रिया, १६६३ पृ० २५१।

राष्ट्रपति में निहित हैं, परन्तु धनुच्छेद ७४ के धन्नगंत (इसको धनुच्छेद ७४ (१) के साम पढ़ा जाना चाहिये) एक मत्रोमण्डल, जिसका सम्बद्ध प्रधानमत्री होगा, राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देन के लिए होना चाहिय । राष्ट्रपति इस तरह कार्यपालिका का घोषचारिय या सर्वधानिय प्रध्यक्ष है, बास्त्रिवक कार्यपालिका का घोषचारिय या सर्वधानिय प्रध्यक्ष है, बास्त्रिवक कार्यपालिका मा क्षत्रिक या भत्री परिषद में निहित हैं। इस्तिए मानको साद्यक्ष मार्यपालिका है, जिसमें व्यवस्थापिका साम के सादय है, जिसमें व्यवस्थापिका साम के सादय है, जिसमें व्यवस्थापिका साम के सादय हैं, जिसमें व्यवस्थापिका साम के सादय हैं, जिसमें व्यवस्थापिका साम के सावत हैं। अर्थ में द्वारा हो है। स्वर्थ में व्यवस्थापिका साम के सावत है । स्वर्थ में व्यवस्थापिका साम के सावत है । स्वर्थ में व्यवस्थापिका सोर कार्यपालिका यो जोडा धौर बीच जाता है। है।

### सधीय-कार्यपालिका की शक्तियाँ

मारतीय सपीय नार्यपालिका ने ससदात्मन स्वम्प से यह विदिन होता है नि इसकी शक्तियो तथा कार्यों का विश्लेषण इसके दो हिस्सो के प्राधार पर ही निया जाना चाहिए। ये दो हिस्से निम्नलिषित हैं:—

- (न) राष्ट्रपति—जो ग्रीपचारिक नार्यगालिका है, ग्रीर
- (स) मत्रीमण्डल-को वास्तविक कार्यपालिका है।
- (क) राष्ट्रपति की शक्तियाँ—धिटिस सविधान ने प्रत्यंत सिद्धान्त कि राजा कोई 'गलती नहीं कर सकता है', इस प्रसम में उपयोग में लिया जाता है कि राजा कार्नु से परे हैं और अपने सायरण के स्वय्टीकरण ने लिया जाता है कि राजा कार्नु से परे हैं और अपने सायरण में स्वया जा सकता है। वास्त्व में उपित्य होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। वास्त्व में इस विद्यान का धर्म सवैधानित वृद्धिकोण से यह है कि विद्याम मनीमण्डल के सताहां-पुनार राजा प्रपत्न कर-विश्वेशन्ति कार्ति स्व है। विद्यान मनीमण्डल के सताहां-पुनार राजा प्रपत्न कर-विश्वेशन्ति कार्ति है। विद्यान मनीमण्डल के सित्त जो राजा के नाम में विया जाता है, नवीमण्डल को 'निर्णय' तेने ना प्रिचान के सित्त प्रत्य के नाम में विया जाता है, नवीमण्डल को 'निर्णय' तेने ना प्रिचान है मुद्दिस एक (स) के अनुसार मनीमण्डल को 'निर्णय' तेने ना प्रिचान है किस सामानारणत्या, राष्ट्रपति बाध्य माना जायेगा। इस तरह मारतीय राष्ट्रपति विदिश राजा के समान सिवाय मनीमण्डल के सलाहानुसार घोई ऐसा सार्वजनिक कार्य नहीं करीगा, जिसमें उसका स्व-विवेध निहित है। श्री प्रत्यादी इप्पत्वामी स्वयं राष्ट्रपति स्वर्ण स्वर्ण सही हो कहा था कि मनी-पुल्डल लोकसमा के प्रति उत्तरवारी है, धीर यदि वोई राष्ट्रपति, मनीमण्डल के राष्ट्रिक सो को किसमा के प्रति उत्तरवारी है धीर यदि वोई राष्ट्रपति, मनीमण्डल के राष्ट्रिक सो की किसमा के प्रति उत्तरवारी है भीर यदि वोई राष्ट्रपति, मनीमण्डल के राष्ट्र के रूप में प्रतात है तो

२. डी॰ एन॰ वैनर्जी—'सम झास्पेबट्स झाफ द इण्डियन कानस्टीट्युशन' १९९२, पृ० ६९ ।

वह सविषात ना उल्लंघन करने ना दोग्रो होना म्रोर उस पर महामियोग भी लगाया वा मत्ता है। राष्ट्रपति को वो विनिन्न मत्त्रिया सिवागत द्वारा प्रदत्त भी मई हैं, उनका उपयोग वह मत्रीमण्डल के परामर्थाल्यात करेगा। निम्निजित क्षेत्रियों ने मुन्तति दुन शतियों ना म्यायन्त निया वा सकता है।

### १-नार्यपालिका शक्तियाँ

मारत का राष्ट्रपति एक ऐसे राज्य का ब्रध्यक्ष है, अहाँ पर ससदारमक स्वास्त को राज्यात वृष्ट एवं पाठ्य को सम्बद्ध हुं, वहाँ पर सद्धार को स्वापना को नहीं है। वस्तावस्त्र राज्युलीत के नाम हो हो भीमचारिक हव से, सरकार तथा शासन के वार्ष समझ किये जाये है। सबिनात के सतुन्धेद थठ से सहसार नारत सरकार के वार्षपाविकत सद्धार राज्युलीत के नाम से स्वाप्तादित के स्वाप्तादित है के स्वाप्तादित के स्वाप्तादित है। अनुच्येद ७४ के स्वाप्ताद वसीय अभीमण्डल, जिसका सम्बद्ध स्वाप्ताद राज्युली के स्वाप्ताद राज्युली के स्वाप्ताद स्वाप्ताद राज्युली के स्वाप्ताद राज्युली के स्वाप्ताद राज्युली है कि राज्युलीत की स्वाप्ताद स्वाप्ताद राज्युली के स्वाप्ताद राज्युली स्वाप् सबधी प्रस्तावो की सूचना दे, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है। राष्ट्रपति की इच्छा-सबसी प्रस्तावों की मुखना है, यदि राज्यदिव सह बाहता है। राज्यदिव की हज्यामुखार स्थान मनी डारा ऐमें मामले जी बिस पर केवत किसी मजी में निर्णय
स्वित्ता, मसीम्मलक है जियार के सित्त ए राजा या उन्दर्श है। नसी-की मुजीवें
छ स की स्थान्य करते हुए, यह गननज्ञृती हो सकती है कि राज्यिन सरकार
के कार्यों के शेली में सपना कर-विदेव उपयोग से सा सबता है। और एक्लेजगोसिद्दल का बहुना है— "इनुद्धेंद एक वी व्यादास एक यम के करों से कोई
कार्या है, हों हों कि राज्यदिव को सबने स्व-विदेक को उपयोग में साते दिया
आमें, यह (पाज्यित) इस सजुन्दित के सपने स्व-विदेक को उपयोग में साते दिया
आमें, यह (पाज्यित) इस सजुन्दित के सपने स्व-विदेक को उपयोग में साते दिया
आमें, यह (पाज्यित) इस सजुन्दित के सात्र स्व-विदेक को उपयोग में साते दिया
आमें, यह (पाज्यित) के सजुन्दित के सात्र स्व-विदेक को उपयोग में सात्र के कीई मी
क्वम उद्योग के लिए पूर्णवास स्वन्त है।" वरन्यु यह याद रहना आहिने कि
विद्या मोर्गर परिचानों के सजुन्दित एक की न्यायन सम्बद्धान प्रमाणि में मूल
कि सामा प्रदेश में नहीं जो सारकार है। सत्र स्व परस्था, जो इत्तेष्ठ में
स्वर्णिय है कि सामारप्याख्या पाज्यस्था स्वतीयकार की सत्राह के सनुमार ही
कार्य के सामार स्वत्यस्था के स्वी को स्वत्यस्था स्वतीयकार की सत्राह के सनुमार ही चाहिये, बर्योन इस परम्परा ने न होने से जो अननाविक सतुलन संसदात्मक प्रणाली

१. एते ह केन्द्रीविक्ज-कासरीट्यूगनत देवलपमेन्ट्स इन इस्टिया, १६५७ पृ० १३४।

में ग्रीपचारिक एव बास्तविक कार्यपालिका के मध्य होना चाहिये. वह नहीं रह सरेगा । वार्यपानिका सबधी राष्ट्रपति की प्रक्तियाँ निम्नलिखित हैं .-

१--- मध की निम्नलियित मुख्य नियुक्तियों राष्ट्रपति करता है ।

(क्) ग्रन्च्टेद ७१ (१) के श्रनुमार ग्राम चुनाव म विजयी राजनीतिक देत में नेता नी नियुवित प्र<u>यान म</u>त्री के पद पर करता है।

(स) बनुच्छेद ७६ (१) व बन्नगंत महान्यायाधिवत्ता (एटमी जनरल) वी नियक्ति करता है।

(ग) मारन व नियम्प्रक-महालेखा परीक्षप की नियुक्ति अनुवदेद १४८ (१)

मे ग्रन्तर्गन करना है।

(ध) सर्वोच्च न्यायानय तथा राज्या के उच्च न्यायात्रया के न्यायाधीशो की नियुक्ति ग्रनुक्टेद १२४ एव ग्रनुक्छेद २१७ व ग्रन्तर्गन वरना है।

(ड) ग्रामच्छेद २६३ में श्राम्तर्गत, एक ग्राम्तर्राज्यीय परिषद (इप्टर स्टेट मौत्मित) मी नियक्ति मरना है।

(च) प्रनच्छेद ३१६ वे बन्तर्गत सघ लोग सेवा बायोग के बध्यस्तुतया सदस्या की नियक्त करता है। राष्ट्रपति कुछ राज्यों के एक समूह के लिए एक सयक ग्रायोज-नी भी नियक्ति नर सनता है।

(छ) वित्त सायोग की नियुक्ति सन्च्देद २८० के सन्तर्गत करना है।

(ज) चनान थायोग की नियक्ति ३२४ (२) के ब्रन्तर्गत करता है।

(फ) धनुमुचित प्रदेशो पर प्रतिवेदन देने के लिए धनच्छेद ३३६ (१) के घल्तांत मायोग की नियक्ति कर सकता है।

(अ) प्रमृच्छेद ३३० (१) के धनुसार अनुसूचित जातियों तथा धनुसचित जन-जानिया ने लिए एउ विशेष पदाधिकारी की नियक्ति कर सकता है।

(ट) धनुष्टेंद २४० के बन्तर्गत पिछडे वर्गों की दला को जीवने के लिए एक मायोग की नियक्ति करता है।

(ठ) ३४४ (१) के अनुमार भाषा यायोग नियुक्ति वरने का ध्रयिकार रखना है।

भारत म मसदात्मक सरकार के प्रमण म यहाँ यह कहना आवश्यक होगा कि य सारी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति मत्रीमण्डल के परामर्श पर ही करेगा।

२—राष्ट्रपति को सघ के निम्नलिश्चित प्रियकारी गण के पदच्युत करने का अधिशार है --

मनुष्येद ७५ (२) के बन्तर्गत यत्रियो को ।

भारतीय शासन घौर राजनीति

१२० ख---धनुच्छेद ७६ (४) के धन्तर्गत मारन के महाधिवत्ता को ।

घ—मनुच्देद १२४ (४) व २१७ (१) वी के मन्तर्गत सर्वीच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशो को ।

ड-सविधान म उल्नेखिन प्रक्रिया में अनुन्देद ३१७ (३) तथा (४) के धन्तर्गत सथ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को, सवियान में बल्लेखित प्रक्रियानसार ।

# २-सैनिक शक्तियाँ

मारतीय सविधान के अनुरुद्धेद १३ (२) के अनुसार राष्ट्रपति की देश की विभिन्न सेनामी (जल,थल मीर नम) का सर्वोच्च मधिवारी माना गया है। राष्ट्र-पति के द्वारा इस शक्ति का उपयोग विधिवत् किया जाना चाहिये। ससद की ही (बनुस्ची सात, सूची एक विषय क्रमाक १, २, १५ के बस्तर्गत ) सेना, युद्ध सया शान्ति के लिये विवि निर्माण करने का श्रविकार है। ग्रत राष्ट्रपति की उपर्युक्त विषयो पर जो शक्तियाँ प्रदक्त की गई हैं, उनका उपयोग वह ससद द्वारा निर्मित विभि के कनसार जरेगा । असद की धनमति विना, राष्ट्रपनि न तो ग्रह की घोषणा कर सकता है, न ही भारतीय सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। भौपचारिक रूप से युद्ध की धोषणा का अधिकार ससद में ही निहित है। श्रमरीका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ मारत के राष्ट्रपति की तरह विधि द्वारा नियन्त्रित नहीं हैं। बर्चाप भागीकी सविधान में यह उल्लिखित है कि यद की भीपणा भागीकी कांग्रेस ही करेगी, तथापि श्रमरीकी राष्ट्रपति विदेशी मामली के क्षेत्र में कार्यों का सम्पादन इस रूप से कर सकता है कि काबेस के समझ, सिवाय गुद्ध की घीषणा करने के कोई विकल्प ही नहीं रहें। ग्रारम्भ में, जब राष्ट्रपति जानसन ने वियतनाम में भमरीनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने की धावश्यकता महसूस की तथ काग्रेस की भनुमति प्राप्त करने के लिए उन्होंने वियलनाम की टोविन की लाडी के सामले को, जिसमे धमरीको जहाज पर शाम्यवादियों द्वारा धाक्रमण के धारोप लगाये गये मे, नाग्रेस के समझ रखा । इस तरह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वियतनाम युद्ध में प्रमरीकी सैंग्य शक्ति के उपयोग के लिये, नामस की अनुमति लेने में कोई कठिनाई मही हुई 1

भारत में यदाप युद्ध तथा बान्ति सम्बन्धी विषयों के लिए धन्तिम निर्णय लेने का प्रधिकार ससद को है फिर भी बारतीय संधीय कार्यपालिका (संधीय मंत्रीमण्डल) के हाय में घरयधिक शक्तियाँ हैं। अपनी शक्तियों को उपयोग में लाने में मंत्री-मण्डल ऐसी ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित पैदा कर सकता है, जिसमें ससद के समझ यह

नो भोपणा करने के भ्रतावा कोई विकल्प हो नही रहे। धतः युद्ध एव मान्ति के सम्बन्ध में ससर द्वारा धन्तिम निर्णय लेने वा प्रधिवार एक धौपचारिक्ता मात्र है। परन्तु यह विदित रहे कि वास्तविक रूप में इन शक्तियो वा उपयोग राप्ट्रपति नहीं, बल्कि प्रधान मत्री (मत्रीसण्डल के भ्रष्यक्ष के नाते) करेगा।

# ३-राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति के नाम से धन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सारत के वैदेशिक मामलो पर सवालत होता है। उसी के नाम से समस्त ध्रियकारों वा प्रयोग होता है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति धन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधिष्त करता है। विदेशों के राजदूत, वृटनीतिकों तथा वाणिज्य दूतों को धौपवारित्य समारोह में उनके प्रमाण-त्य स्वीकृत कर राष्ट्रपति हो उन्हें मान्यता देता है। विदेशों में राजदूती, वाणिज्य दूतों तथा प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही की जाती है।

झन्तर्राष्ट्रीय सिंघयो तथा झन्तराष्ट्रीय समझीतो के लिथे बाताँएँ राष्ट्रपति के के नाम से ही सचानित की जाती है। इस प्रकार की सिंघयो तथा समझीतो के लिये अनुक्षेद्र ७३ के अनुसार सबसोय अनुसमर्थन आवक्यक है। इगलैण्ड में सससीय अनुमर्थन उन सिंघयो या समझीतो के लिए आवक्यक है, जिनसे राज्य मी मूमि गा हस्तान्वरण होता है या जिनके द्वारा घनराशि का दिया जाना आवक्यक है।

श्रमरीका में सिनेट (वाग्रेस वा उच्च सदन) में, उन संधियों को दो-तिहाई बहुमत से स्वीष्टति होना चाहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने श्रन्य देशों से बार्ता मी है, श्रन्यपा वे श्रवीनीन मानी जायेंगी।

#### ४-राप्ट्रपति की व्यवस्थापन शक्तियां

संविधान के प्रनुक्देद ७६ के प्रनुसार भारतीय सध के लिए सध ससद वी स्वापना का प्रावधान निया बया है, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं। उच्च सदन, राज्य सम्प है, उच्च जिन्नला सदन, सोल सभा है। सत्तर के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में और राष्ट्राध्यत होने के नाते राष्ट्रपति को मारतीय व्यवस्थापन प्रणाती में अवस्थापन सम्बन्धी निम्मालिखत शांतिओं प्रदत्त हैं।

(क) राष्ट्रपति को, अनुन्छेद ६५ (१) (२) (अ) एव (व) के अन्तर्गत ससद को आमित्रत एव स्थगित करने छोर लोकसमा को भव करने का अधिकार है। परन्तु ससद आमित्रत करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की शक्ति का निययण इस शर्त से, को घोषणा करने के घतावा कोई विकत्त हो नहीं रहे । घतः मुद्ध एव गानि ने सन्दर्भ में समद द्वारा धनिम निर्णय लेने का धरिकार एक धीनवारिका मात्र है। परनु यह विदित रह कि वास्त्रीवक रूप में इन बन्तियों का उपरोग राज्यपति नहीं, बन्ति प्रयान मंत्री (मंत्रीसण्डन के घन्यज्ञ के नार्ते) करेगा।

# ३--राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मारत के बैदेशित मामयों का सवाजन होता है। उसी के नाम से समन्त अधिकारों का प्रमोग होता है। राष्ट्राम्यक होने के नाने पाष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देग का प्रतिनिधित्व करना है। विदेशों के पात्रपति, जूटनीतियों तथा वानिस्य दूरों को भौरवारित समार्थेद में उनते प्रमान्यव क्षोहत कर पाष्ट्रपति हो उन्ह मान्यना देगा है। विदेशों में पात्रदूरी, वानिस्य दूरों तथा प्रतिनिधियों की निधुक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही को जानी हैं।

धन्तरीन्त्रीय सिन्धो तथा धन्तरीन्त्रीय समझीनो ने नियं वानित् राष्ट्रपति के ने नाम से ही सवानित की जाती है। इस प्रकार की सिन्धों तथा समझीनों के नियं प्रतुन्देर ५३ के धनुनार सनदोय धनुसनर्थन धाउन्यक है। इगलैंग्ड में समझीय धनुन्देन उन मिण्यों या समझीनों के निए धाउन्यक है, जिनये राज्य की मूमि का हन्नान्तरण होता है या जिनके द्वारा धनरानि का दिया जाना भावानक है।

प्रमधीना में निनेट (कांग्रेस ना उच्च सदन) में, उन सिपयों को दो-तिहाई बहुमत में स्वीहति होना चाहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने प्रस्य देशों से बातों की है, परस्या वे प्रवैदानिक माती जायिंचा।

### ४-राष्ट्रपति की व्यवस्थापन शक्तियाँ

संविधान के सन्नुद्धि ७६ के प्रनुतार भारतीय सभ ने लिए सथ समद की स्थानना का प्रावधान दिया गया है, विसम् राष्ट्रपति तथा दो सदन है। उच्च प्रदन, राज्य समा है, वधा निवना सदन, लोक समा है। असद के एक महत्वपूर्ण हिम्में के इस में और राष्ट्राय्यस होने के नाने राष्ट्रपति को मारतीय व्यवस्थापन प्रमानों में व्यवस्थापन सम्बन्धों निम्मीलवित प्रतिन्ती प्रदन्त है।

(क) राष्ट्रपति को, अनुब्देद ०५ (१) (२) (४) एव (व) के अन्तर्गत सनद को भागतित एव स्वर्गत करने और सोक्यमा को भग करने का अभिकार है। परन्तु सनद भागतित करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की बक्ति का तिमत्रण इस गर्ने से, एउ पासीवत) का मार्च मनुष्वेद १११ के मन्तर्वक यह हो सकता है कि जितने प्रिक समस तक राष्ट्रपति चाहता है। (एक साव एक दि श्रीसंतरण वृजेड) "में राप्ट्रपति के मनतन्त्रत के निषेपाधिकार का बासत्व में, मारतीय सावासक प्रणाली में विशिद्ध महत्व है। यह एक वर्षचानिक, क्यरोपन कि रोते (के हो के रूप में है। इस निषेपाधिकार को राष्ट्रपति को देते हुए सविधान निर्मातायों का स्वाप्तित यह नियार वा कि सवद-वेती व्यवत वर्ष्याएँ यदि राजनीतिक तर्वक सं अमानित होकर कि प्रीत प्रणालक पर पूर्वका विचार राष्ट्रद्रित में नहीं कर सकी हैं तो राष्ट्रपति मार्चक कर में जनता के प्रतिविधिको द्वारा निर्वाधिक राष्ट्रपत स्वाधिक पर प्रमुख्य मार्चक साथ पर विचेवक पर महारा में विचार करने ने उपरालव उपरालव के मार्चका स्वाधार पर विचेवक पर महारा है विचार करने ने उपरालव उपराक्ष कर वे सनता परिवाधक स्वाधार पर विचेवक पर महारा है विचार करने ने उपरालव उपराक्ष कर वे सनता।

समर्राठी सिषपान के सन्तर्गन जब कांग्रेस से विषेयक पारिल होकर राष्ट्रपति के साथक माना है तक राष्ट्रपति कस दिन में अपने विचारों सिंदित है ति एत्या कि सार्यक के सार्यक के सार्यक के सार्यक के सार्यक हो। यहि राष्ट्रपति कपनी सहस्ति है देता है, तो विधेयक प्रतिक स्वाधित को सार्यक है। यहि राष्ट्रपति वपनी सहस्ति है देता है, तो विधेयक प्रतिक स्वाधित का मान्यक कांग्रेस हाय पुत्र पारिल किया जाता है। स्वाधित मान्यक स्वाधित के सार्यक क्षित्र का सार्यक कांग्रेस का स्वित्यक मान्यक जाता है। सार्यक के सार्यक्र का सार्यक का सार्य

(प) मारत के राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के बोत में एक घरवार ही ध्यापन क्रिक्त की गर्द की गई है। विशेषान के धनुक्कि १२३ (१) के धनुकार नव सबद का प्रियेशन ने हैं। दूर हो, राष्ट्रपति धन्यवेश ना हुन कर सकता है। राष्ट्रपति व्राप्त साम्राप्त करा का प्राप्त करा करा कर स्वाप्त की प्राप्त करा साम्राप्त कर प्राप्त करा का प्राप्त की प्रति कर सम्प्रप्त करा साम्राप्त की स्वाप्त के प्रति समय के रोगो सबसे ने साम्राप्त की साम्राप्त की पर वक्तक प्राप्त के साम्राप्त की साम्राप

१. डा० के० बी० राव-'पार्तियामेन्द्री हेनीके सी इन इध्हिया । १६६१ प्र० ४६ ।

समान्त हो जायेगा, परन्तु यदि समद श्रष्ट्यादेश से श्रसहमत नही है तो श्रद्ध्यादेश को, ससद की बैठक के ६ सप्ताह पश्चात् समाप्त माना जायेगा ।

- (ह) राष्ट्रपति को अनुच्छेद ५० (३) के अन्तर्गत राज्य समा के १२ सदस्या को मनोनीन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति इन १२ सदस्यी को उन व्यक्तियों में से मनोनीति करेगा, विनको साहित्य, विज्ञान, क्ला और समाज सेवा वे क्षेत्र में विजेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुमव है। राष्ट्रपति एक्ली-इण्डियन सम्प्रदाय म दा अस्तियों को लेक समा के लिए मनोनीत कर सकता है यदि लोकसमा में उक्त सम्प्रदाय में से कोई सक्स्य निर्वादिक नहीं हुआ है।
  - (क) सघ के राज्यों से सर्वाघन राष्ट्रपति की व्यवस्थापन सबद्यो शक्तियाँ
- (1) सविधान के धनुष्ठेद ३ के धन्तर्गत राज्यनि की धनुमति के विना, किमी
  मचे राज्य का निर्माण था वर्तमान राज्यों की सीमाधों, क्षेत्रा या नामों में पौरवर्तन
  करने के लिए किसी भी विधेयक को समय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है,
  उसकी प्रतुमित के बाद ही उक्त विधेयक पर विचार किया जा सकता है। इस
  समय में राष्ट्रपति के लिए सबधित राज्यों की विधान समाध्यों के विचार जात
  करना भावस्यक है परनु यह राष्ट्रपति पर निर्मर है कि उन विचारों को पालन
  करें या नवरें।
  - (11) राज्यो की विवान समाम्रो में राष्ट्रपति की पूर्व धनुमति के पश्चात् ही कुछ विधेयक प्रस्तुन किये जा सकते हैं, जैसे—अनुक्छेद २०४ के प्रत्तान्त यदि कोई विधेयक जो व्यापार, वाणिज्य या अन्तर्राज्योय सध्यकों पर प्रतिकृष्य लगाता है।
  - (111) राज्य विधान समाप्रो द्वारा पारित ऐसा विधेयन जिसका सबय प्रतुच्छेद ३१ के दृष्टिकोण से सम्पति ने प्रधिग्रहण से हो, उसको राष्ट्रपति की स्वीवृति से ही कानून का रूप दिया जा सकता है।
  - (IV) राज्य विद्यान समान्नो द्वारा पारित ऐसे विदेयक जिनके द्वारा उन वस्तुमो पर वर संगाया गया है, जो ससद द्वारा, अनुच्द्रेद २८६ के प्रन्तगंत पारित विधि के अनुसार सार्वजनिक जीवन के लिए ब्रावश्यक घोषित वर दो गई है।
  - (v) राज्य विधान समा द्वारा, समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर पारित विधेयक—जिसका समर्थ ससद द्वारा पारित किसी विधि से है, धनुच्देद २१४ के प्रस्तृंगत राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाना चाहिये।
  - (ग) जब किसी राज्य का सबैधानिक तन धसफ्त हो जाता है तब राष्ट्रपति उक्त राज्य मे सकटकालीन स्थिति, धनुच्छेद ३५६ के धन्तर्गत, घोषित कर राज्य सरकार के किसी भी खंग की, सिवाय उच्च न्यायालय की, शक्तियों को धपने हाथ

- (क) जहाँ दण्ड किसी मैनिश न्यायालय द्वारा दिया गया है ।
- (स) जहां दण्ड उस नानून के विरुद्ध भनराथ ने लिए है, जो सब की वार्य-पालिका के क्षेत्राधिकार मे हैं।

(ग) जहाँ दण्ड मृत्यु दण्ड वे रूप मे हो।

राष्ट्रपति को मन्तियाँ, इस दृष्टिकांण से सध-सूची तक ही सीमित हैं। "न पित्रपी को समर्वी सूची में जिल्लाखित विषय के सबय में उपयोग म नहीं नाया जा सकता है सिवाय बन मामलों के जिननों ससद ते स्पष्ट रूप में राज्य की कायपालिका मिनन के धवाधिकार से मतन रहा दिया है।

धनुन्छेद १४३ के धन्तगत राष्ट्रपति हिसी भी सावजानन महस्य वे मामसे पर सर्वोच्च न्यायासय की राय मानुम बर सरता है। एव विकिन्द दृष्टिकोण हो, राष्ट्रपति वा यह प्रियकार व्यवस्थापित समा पर एव सर्वपानिक प्रयरोध वे रूप मे रे, बयोवि इस प्रियकार के उपयोग द्वारा राष्ट्रपति विसी विषेयन को, जिसके सर्वपानिक स्वरुप के सबय मे खका है, सर्वोच्च -यायासय की राय लेने के तिल प्रेवनर यह मानुम वर सकता है कि विषयन बास्तव म सविधान के प्रयुक्त है या नहीं है।

इसी प्रकार, राष्ट्रपति व्यवस्थापिक के निसी वाय वे सवध मे यह मालूम करने के लिए कि वह सर्वधानिव है या नहीं है, अयोंच्य न्यायास्य यो राम से सकता है। उदाहरण स्वच्य, उदार प्रदेश की व्यवस्थापिता समा तथा न्याय-गालिका वा मामाला १६६५ में राष्ट्रपति ने सर्वोच्य न्यायास्य वे पास उसनी राम प्राप्त करने के लिए मेजा था। मुख्य न्यायाधिपति भी बनेन्द्र-महकर ने सर्वोच्य ग्यायालय की बहुमत की राय की प्रश्चित्रकारित भी बनेन्द्र-महकर ने सर्वोच्य ग्यायालय की बहुमत की राय की प्रश्चित्रकारित करते हुए, एव महत्रपूर्ण सर्वभानिक विद्वान्त पर प्रकाश हाता। उन्होंने कहा यदि उत्तरप्रदेश विधान सभा वे दाव वो, कि विधान सभा वे दाव वो, कि विधान सभा वे दाव वो, कि विधान सभा वे दाव मोह्यार है प्रीप्त न्यायालय को हस वार्यवाही की वैधता को जात वरने वा प्रविवार हो है, मान्यता ये वाती है, तो इससे न्यायालय वी स्वतप्रता वे भूत विद्वान्त पर प्राप्ता पर्वेचेगा।

भत. यह स्पष्ट है नि राष्ट्रपति अपने इस अधिनार का सविधान ने सरक्षण हेतु उपयोग कर सकता है।

# ५--राष्ट्रपति वी ग्रापत्तिकालीन शक्तियाँ

सविधान के मन्तर्गत, (मनुच्छेद ३५२, ३५६ एव ३६०) राष्ट्रपति वो, तीन प्रकार की मापतिकालीन स्थितियों ना सामना करने के सिए भाषतिकालीन म नेनमी प्रदत्त की वई हैं। प्रत्येक राज्य में सकटकाल में उद्धने मस्तित्य को बनाये रखने के लिए किसी ऐसे शक्त-सम्पन्न श्रीवकारी का होना आवश्यक है, जिसको सकटबालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए सता भावश्यक रूप

दी जासके। 'सधीय देश म यह सत्ता ग्रावश्यन रूप से, राष्ट्रीय सरकार में निहित की जाती है-यहाँ यह भी उल्लेखित किया जा सकता है कि सकटकालीन परिस्थित

का सामना करने ने लिए मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कार्यपालिका वा ही होता है।"३ राष्ट्रीय कार्यपालिका में सकटकालीन परिस्थिति के दौरान ब्रास्थिक शक्तियाँ

निहित कर दी जाती है ग्रव यह समव है कि कार्यपातिका निरकुश रूप धारण भारते का प्रयत्न करे । सर्विधान में इस सदमें ने प्राय कुछ विशेष 'रक्षक-प्रायधान' समावेशित किए जाते हैं, जो कार्यपालिका के निरक्त बनने की प्रवृति पर प्रवरोध के रूप मं कार्य करेंगे। सामान्य रूप से इन एक्षक प्रावधानी का उद्देश्य यह

श्वीता है कि सकटकाल में पाज्य का हस्तक्षेप नागरिकों के ग्रामिकार में न्यून ही बीर सीमितवाल के लिए हो। परन्तु इनके साथ ही यह भी सावप्यक है कि जनता ग्रुपने ग्रीधवारो के प्रति सजग हो । सक्षेप मे, जनताधिक सविधान मे राज्य के ग्रास्तित्य को धनाथे रखने के लिए यदि सकटकाल मे जब एव ग्रीर यह धावत्रयक्ता होती है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका की सकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने हे लिए अधिनजाली किया जाये. तथा नागरिको के संधिकारों से सीमित समय के लिए सीमाएँ लगाई जायें, तो दूसरी और यह स्थीकार करना भी मत्यावण्यक है कि ये सब बाते उन साधनों के रूप में हैं: जिनका लक्ष्य यह है कि जनतात्रिक मुख्यों का शस्तित्व बना रहे ।

भारत के संविधान में निस्नलिखित तीन प्रकार की संकटकालीन परिस्थितियो का उल्लेख किया गया है ---

सर्वप्रथम अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जामें कि राष्ट्र पर सुरक्षा की बाह्य आक्रमण, युद्धावस्था, या आस्तरिक अशान्ति का सकट है तो वह सकटकालीन स्थिति की उदधोषणा कर सकता है। यह उद्घोषणा राष्ट्रपति उपर्युक्त सक्ट की समावना में भी कर सकता है। इस प्रकार की उदयोपणा वा अन्त, यदि जिन कारको से यह की यह यी ने समाप्त हो चके है, राष्ट्रपति दूमरी बद्धीयणा द्वारा कर सकता है। इस बायत्तिकातीन उदधीयणा को ससद ने समझ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उद्घोषणा करने ने दो माह पश्चात, यदि इसके पूर्व ससद के दोनी सदनो हारा इसे सहमति नही दी गई हो,

१. एम० श्रीतिवासन-डेमोकेटिक वर्वमेन्ट इन इव्डिश्न, १६५४ प० ३६६ ।

यह उद्भोषणा समान्त मानी जायेगी । यदि उद्भोषणा के पूर्व लोक समा मग हो जाये या दो माह की अवधि मे गय होती है, तो केवल राज्य समा की स्वीकृति ही आवश्यक है। परन्तु राज्य समा की स्वीकृति मिल जाने के पत्रवात् धापितवालीन उद्भोषणा को नई मोल समा की प्रयम बैठक के तीस दिन के ब्रन्टर स्वीकृति मिल जानी चाहिते, प्रत्यवा उद्योषणा समान्त ही जायेगी।

राष्ट्रपति के, अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत, उद्घोषणा करने के प्रभाव

ल—सथ सरकार किछी भी राज्य सम्कार को, कार्यपालिका की शक्तियों के उपयोग के लिए प्रादेश दे सकती है और सबस सधीय मधिकारियों को राज्या-धिकारियों के किसी भी प्रिणकार तथा कर्राव्य सींग सकती है। ससद को यह प्रिणवार प्रत्येक्षर ३५३ (अ) एवं (ब) के प्रत्यों त्र प्रदत्त है।

ग---राष्ट्रपति वो अनुच्छेद ३५४ के अन्तर्गत यह अधिकार है कि सकटकाल भे, ब्रादेश द्वारा अपनी इच्छानुसार सविधान के अनुच्छेद २६८-२७६ मे निहित आय वितरण प्रणाली के सबअ से परिवर्तन करे, परन्तु यह आदेश ससद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

धतुच्छेद २४८ के धनुबार धापतिकालीन उद्योषणा के दौरान, प्रतृच्छेद १६ मे उल्लिखित स्वतत्रता का अधिकार स्वितित हो जायेगा । इसी तरह, सकरकाल मे राष्ट्रपति के प्रादेशानुसार अनच्छेद ३४६ (१) के धनुबार न्यायालयो हारा मुल ग्रधिकारो केलागुकरने के ग्रधिकार की भी स्थयित किया जासकता है और दम मदमें में स्वायालयों के समक्ष जो कार्यवाही है, वह भी सक्टकाल के दौरान या निद्धिट अवधि तक के लिए स्वगित मानी जायेगी।

सक्षेप म. अन्च्छेद ३२ म उल्लिखित सबैधानिक उपचारों के प्रधिकार को सक्टकाल में राष्ट्रपति ब्रादेश द्वारा स्यमित कर सक्ता है। परन्तु इस प्रकार का द्यादेश ससद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत शिया जाना चाहिये । यह स्पष्ट है कि सबैधानिक उपचारी के ध्राधिकार को स्थामिन करने के सम्बन्ध म राष्ट्रपति का ग्रविकार ग्रतिम नही है, क्यांकि ससद विधि द्वारा ऐसे ग्रादेशों को समाप्त कर सकती है।

द्वितीय, सर्विधान के बनुच्देद ५६ के धन्तर्गत क्लिशे राज्यपाल स यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि राज्य म ऐसी क्लिति पैदा हो गई है, जिसम राज्य सरकार को सबिधान के चनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो उस प्रतिवेदन से सत्रव्य हो जान पर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के समस्त या हुछ कार्य ग्रहण कर सकता है. जिसम सिवाय राज्य विधान समा की शक्तियों के राज्यपाल या राज्य की घन्य सस्या था सत्ता के काय सम्मितित हागे । धाष्ट्रपति राज्य के अन्य न्यायालयो व समिकारो को प्रहण नहीं वर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा यह मी प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य की विधान समा की शिवतयो को ससद या ससद द्वारा ग्राधिकत सत्ता द्वारा उपयोग म लाया जाये। राष्ट्रपति इस प्रकार की उदयोगणा का यन्त या उसम परिवर्तन इसरी उदयोगणा द्वारा कर सकता है। राज्य क सर्वधानिक तत्र के प्रसफ्ल होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई उद्घीयणा को ससद के दोनो सदनो के समक्ष रखना धावस्यान है।

यदि लोकसमा का अधिवक्षन नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की सचित निनि में से व्यय के लिए बादेश भी दे सकता है।

सघ क किसी राज्य म अनुच्छेद ३५६ व अन्तमन सकटकालीन उद्योपणा ने सदम म सब सरकार एव राज्य सरकार के मार्गदर्शन वे लिए निम्नलिलित सविधान क मार्ग्यकंक अनुच्छेदो एव घरम्पराम्रो को ध्यान म रखना छति आवश्यक है।

१--प्रनुच्छेद ३५५ ने अनुसार सथ सरकार ना यह कर्राव्य है कि प्रत्येक सप के राज्य की, बाह्य ब्राह्मयण एव ब्रान्तरिक ब्रशान्ति के समय सरक्षण दें। इस तरह सप सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार सविवान के ग्रनुसार चलायी जाये । सक्षेप में यदि राज्य सरकार का विधान समा म बहमत शास्त है. तो ऐसी स्थिति म सथ सरकार का यह कर्तव्य है कि जनतात्रिक प्रणानी ने प्रनुसार निर्वाचित राज्य सरकार का, जिसको राज्य विधान सभा मे यहमत प्राप्त है, बाह्य आक्रमण एव आन्तरिक प्रशान्ति से सुरक्षा वरे, न कि राज-नीतिन मतनेदों के नारण राज्य सरकार को गिराने का प्रयस्त वरे ।

२--प्रतृच्छेद ३६५ के अनुसार सम सरकार के, सिवधान के धन्तर्गत दिये गये प्रादेगों का राज्य सरकार द्वारा पालन न करने के फलस्वरूप यह सकट-कालीन उद्योगया की जा सकती है कि राज्य सरकार का शासन तन सिवान के प्रनुतार मही चलाया जा सकता है। अत. राज्य सरकार के लिए केवल दिवान समा में यहुमत होना हो धावश्यक नहीं है, अगितु यह मी धावश्यक है कि सम सरकार द्वारा सविधान के धन्तर्गत दिये गये धादेशों का पालन भी करें।

३—सदात्मक प्रणालों में इस परम्परा को मान्यता प्रदत्त की गई है कि यदि प्रमान मनी या मुख्य मनी को यह प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका समा में उसे महमत प्राप्त होने के बावजूद भी थान जनता का रुख उसकी सरकार के प्रति दिविधापूर्ण है, तो प्रधानमनी या मुख्यमनी झाम चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छा मालुग कर सकता है।

केरल मे ३१ जुलाई १८१८ मे, जब राष्ट्रपति सासन सामू िया गया तब सारे देण मे इसके क्षीमलय के सम्मान मे विभिन्न प्रकार के तक प्रस्तुत किये गये। साधारणतः केरत से पाष्ट्रपति सासन सामू करने भी तिवित्र प्रत्योचना की गई। मालोचको का कहना था कि केरल मे राष्ट्रपति सासन राजनीतिक, न कि सर्वधानिक, कारणो से सामू किया गया। डा० एग्च पी० साम का कहना है,—"ऐसी परिस्थितियों से प्राम चुनाव द्वारा जनता को प्रयोग करने के जनतानिक तम भी परण कर देशा जा समरात है। इसके पूर्व कि राज्य के सर्वधानिक तम को उप तरीवे द्वारा सामत्व किया जाये, सचीय प्रधिकारियों का जनता के प्रति यह कर्मक्ष्य है कि उनको, साम चुनाव के दीरान अपने सार्वधीय जनतानिक सतदान के प्रधिकार द्वारा, स्थित को सुवारने के लिए धवसर प्रदत्त करें। यदि प्राम-चुनाव द्वारा मी स्वायी सरकार स्थापित करने से अस्वस्थता मितती है, तो राष्ट्रपति द्वारा सहस्थतिन शक्तियों को उपयोग करने का श्रीचरय प्रश्यापिक प्रयत्य हो स्थारा।"

इसी दुष्टिकोण से डा॰ एस॰ सी॰ डेड का कथन है—"मच्याविष प्नाव जनता की इच्छा, चुनावो के मध्यकाल में, शात करने के लिए बैरोमीटर रूपी यत्र के समान है, और इम्लेंड तथा भारत जैसे देशों में यह सरकार की वृक्ति सुधारने

१. एम० पी० शर्मा-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १२३।

के लिए, जो इन चुनावों से गतदातागण पर बपने प्रमाव को मानूम कर सकती है, उपयुक्त बचरोच है।""

क्षतपृत्व किसी राज्य में यह मालूग करने के लिए कि, बास्तव में, मनुष्टेर ३५६ के प्रदुक्तार राज्य का सर्वेचानिक यम समाप्त हो पुका है या नहीं, उपपूक्त सीत हुदूदों के मार्ग एक्षेत्र में ही सच तथा राज्य के पविकारियों को अपने कार्य कराग वाहिए।

विक्त सबभी उद्योषणां के फलस्वरण संधीय सरकार, राज्य सरकारों को सामिक निवंत से सबनी है, जिनके अनुसार राज्य सरकारों को कृतियम विक्तीय कुल सिद्धानों का पापन करना आक्रमक है। इस प्राचिक निवंती के प्रमुखार राज्य सरकारों हारा राज्य सेवा के सामिक रिजी के प्रमुखार राज्य सरकारों हारा राज्य सेवा के सामिक राज्य सम्बद्धान राज्य सेवा का सकती है। इस निवंशों के प्रस्तात राज्य सिवार समामी हारा पारित दिसा विवेषण को राज्य राज्य सिवार समामी हारा पारित दिसा विवेषण को राज्य राज्य सिवार समामी हारा पारित दिसा विवेषण को राज्य समाम सामिक स्थान सामकाल है।

इस विश्रीय सक्टकातीन निपति के दौरान राज्यति को, संय तेषायों में मूर्विण स्विकारियों तथा वर्षवास्थि के बनन तथा महो को कटोनी के लिए निर्वेण स्विकारियों के स्विकारियों के बल्वेल्व न्यायाल्य तथा उच्च स्थायाल्य के न्यायाधीयों को भी सम्मित्त निया जायेगा पह स्पष्ट है कि विश्वीय सक्ट कामीन उद्योगया के परिणासस्वक्ष, राज्यों की विश्वीय स्वायनग्रा

इंग्लैंड म, युद्ध या धान्तरिक धशान्ति के समय, सक्टकालीन शनियाँ वार्य-यालिका को मयुर द्वारा धायकृत को आती है । धशरीकी सविधान में तिसित रूप से, क्सी के सुद्धीन स्थित का वर्षन भहीं है । तथापि युद्ध के समय प्राय:

१. एस॰ सी॰ डेंश, व कान्स्टोट्युशन भ्राफ इच्डिया, १८६० पृ० १६८ ।

काग्रेस ने राटप्पति को सकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए विधि प्रारित कर, विजेषाधिकार प्रदत्त किये । खत. इन दोनो राप्ट्रो म सकटकालीन शक्तियो, के उपसाम करन के लिए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा ध्रिषकृत किया जाता है।

इंग्लैण्ड तथा अमरीवा म नागरिक वे मौलिव ग्रधिवार पर सक्टवालीन स्पिति वा प्रमाव निम्नलिग्तित रूप म देखा जा सकता है।

इप्लेज्ड म संसद ने कायपालिका को विभिन्न प्रकार को विधिया को पारित कर सदेहास्यद व्यक्तिया को हिरासत म सेने का घषिकार प्रदत्त किया है। उदा-हरण के लिए विफ्रेस साफ रेहम एकट १११४ (Defence of Realm Act 1914) इमरजन्ती पानर विफ्रेस साफ रेहम एकट १११४ (Defence Act 1939) सन इप्लेज्ड म नागरिका के मूल धरिकारा के सदर्भ म ससद को हो प्रतिम शक्तियो प्राप्त है। प्रमरीका के सूल धरिकारा के सदर्भ म ससद को हो प्रतिम शक्तियो प्राप्त है। प्रमरीका के स्विधान के अनुक्तिद १ उपवत्य ६ (२) क प्रमुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण का प्रधिकार, सिवाय धान्तरिक विद्रोह या बाह्य प्राप्त मण की दिवति म, स्विधात नहीं क्या वा सत्ता है। प्राप्तीय सरका प्रधान प्रकार काह्य को हो प्रदत्त है, प्राप्त प्राप्त मण सेने के प्रयुक्त के सा मियार है कि स्थिति म सेन प्राप्त मा प्रदेश के सा प्रमुक्त है सा मही है। प्रमरोक्ती सिवाय म कोई ऐसा प्राथवान नहीं है, जिससे राष्ट्रपति या कार्यस को युद्ध म प्राप्त म प्रदेश प्रमुक्त है सा नहीं है। प्रमरोक्ती स्विधान म कोई ऐसा प्राथवान नहीं है, जिससे राष्ट्रपति या कार्यस को युद्ध म प्राप्त की स्थित म मूल प्रधिकार वा के स्थान कर के सा प्रधान प्रसुक्त है।

मारत म सक्टकाचोन उद्योपणा करने का प्रधिकार सर्विधान द्वारा कार्य-पालिका को प्रवत्त है। इस सदर्भ म, उद्योपणा विका ससद को प्रेपित किये दो माह तक वैष रहेगी जबकि इंग्लैंब्ड तथा अमरीका म सक्टकालीन स्थिति म ब्यवस्थापिका की भूमिना प्रथ्यक्ष एव तत्काल है।

मारत म, म्रुनु-देद ३५२ थे म्रन्तगंत सकटकालीन उदयोपणा ने दौरान राष्ट्रपति म्रुनु-देद २५ म प्रत्त सर्वयानिन उदयारा के प्रधिवार को म्रुनु-देद ३५५ ते मन्तर्गत आदेश द्वारा प्रयत्त नावरिको को विमिन्न सात स्वतप्रताएं स्थागित इयोपणा मुनु-देद १६ द्वारा प्रयत्त नावरिको को विमिन्न सात स्वतप्रताएं स्थागित हा जाती हैं। संवयानिन उपवारा के प्रधिकार को स्थित करने ने मादेश को सविधान ने प्रमुसार राष्ट्रपति ययाश्रीध ससद के समक्ष रखेशा। इससे यह प्रतीत हाता है कि सर्वधानिन उपवारा के प्रधिकार को प्रधातकालीन स्थिति म स्यगित करने ते सिए राष्ट्रपति वो जो शक्तियाँ प्रवत्त हैं, वे श्रान्तम नहीं हैं। इस प्रकार के प्रारंश को राष्ट्रपति द्वारा ससद के समक्ष यथाश्रीध प्रस्तुत करना धावस्य है। परन्तु पहीं सविधान की एक चूटि दृष्टिगोचर है। सविधान निम्हताओ ने राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के मादेश को ससद के समक्ष किसी विशिष्ट प्रस्तुति के

सारतीय जासन घीर राजनीति

रखने ने वजाय राष्ट्रपति ने निर्णय हेतु छोड दिया है कि वह बादेश को 'मयागीध्र'

इसने परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति, यदि उसनी ऐसी इच्छा है तो ससद नो इस मामले से अवगत नरने ने अवसर नो टांतने ने तिए प्रयत्न बर सन्ता है।

सक्षेप में, मित्रपान के घन्तामंत्र प्रदल राज्यान की विभिन्न प्रतियों ने उप-मृत घण्यस्य ने घाषार पर बुख ऐसी समादनाएँ दृष्टियोचर होगी हैं जिनके दुक्तयोग से कपीय नार्यवासिका जिरकुत्त बनने का प्रयल्प कर सबती है। ये एरिकियोगी जिल्लाबिक के

१--सन्दन्तिन घोषणा विना ससद को प्रेषित किये दो बाह तक कैप रहेगी। सहद को दो माह तक सक्टकालीज उद्योषणा के सम्बन्ध म कार्यवाही करने से सलग रला जा सकता है।

२— प्रतुष्केद १६ वे अनुसार सात स्वतनताएँ सवटणसीत उद्भोषणा के पत्तकरण स्पणित हो जायेंची । राष्ट्रपति नागरिको के सर्वपानिक उपचारो के स्विकार को भी, मोदेस द्वारा स्वमित कर सकता है।

१—राज्यों ने सर्वेचानिक तन के सबय ये राष्ट्रपति की मकटकातीन शक्ति का सन्दर्भावीन शक्ति का सन्दर्भावी है। वेदल में सम्पर्क तुक्ति राज्य सरकार की स्पष्ट कहमत प्राप्त है। वेदल म १९४६ में राष्ट्रपति होएं तकट काली वद्योपेया लागू करने ने समय थी नन्त्रीयाद को केरल कियान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हा

हन नृदियों ना निवारण स्वस्थ परस्यरा, सिलमाली जननत, तथा साम से सुदृह विरोधी रहा (सत्ती) हारा दिया वा सनता है। बार पायली ना नगन है, "यह समामित है ति सरवाराधीन होता सरवाराधीन हाम सार्वपालिना सामिता हो जाती है। सरवार की स्वरूप स्वात से सारवार तथा होता कर तथा से सारवार समाम राई जाती है। सस्वाराण प्रचाती दिन देशों में है, जनके समुग्न इस बान ने सोतक है हि ससद सार्वक है और विरोधी रली के सदस्यों के सार्व्यस से वार्य पार्विता ने उन्हों ने उन्हों में कार्य से वार्य पार्विता ने उन्हों ने जाते के सार्व्यस से वार्य पार्विता ने स्वरूप से सार्वक से वार्य पार्विता से सार्वक से सारवार से सार्वक सारवार है। अब नायपालिन समानी है। सब सारवारी स्वरूप से सारवार से सार्वक मारवार से सारवार सारवार में मुम्मा स्वा स्वरूप ने नर देते हैं। सबरवानीन दिवारी से सार्वक से सारवार करने ना सारवार सारवार से सारवार

का प्रयोग किया है तो वे (ससद) मनी मण्डल वो पदच्युत सब वर सबते है ग्रीर उसने स्थान पर दूसरे मनी मण्डल को रक्ष सबने हैं।"

### भारतीय मत्री परिषद ग्रीर प्रधान मत्री

मारत में ससदारमक प्रणाली ने धन्तर्गत मधीय नायंपालिना ना दूसरा हिस्सा मत्री मण्डल है, जिसना प्रध्यक्ष प्रधान मत्री है। सारतीय मत्री मण्डल को उत्पत्ति सविधान के नतियय विभिन्ट प्रावधाना पर आधारित हैं। इस्लेण्ड में, मधी मण्डल का उद्मत एव समस्त नायंप्रणाली प्रलिखित परम्पराधी पर प्रधाधारित है। मार-तीय ताविधान में प्रमुच्छेद ७४-७० में मत्री मण्डल के सग्वन गर्यों तथा मूल विधित्ती का उत्लेख मिनता है। अनुच्छेद ७४ के प्रमुक्तार प्रपान मन्नी भी प्रमुक्त में एक प्रभी मण्डल होगा, जो राष्ट्रपति की उसके कार्यों के लिए सलाह तथा सहायता देगा।

सनुक्षेद्र ७५ (१) में विणत है कि राष्ट्रपति प्रयान सभी की नियुक्ति करता है। मन्य मित्रयो की नियुक्ति प्रयान मनी की सलाह के सनुक्षार राष्ट्रपति परेला। इस मनुक्षेद्र के उपबन्ध र के सनुक्षार मनियो का वार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त रहेगा। इस सक्कें में भारतीय सविधान के अन्तर्वत सिद्धान्त एव व्ययहार में मूल मन्तर पामा जाता है। ससदासक पद्धति के सनुक्षार राष्ट्रपति केवल उत्ती व्यक्ति को प्रयान मनी के पद पर नियुक्त कर सकता है, जिसको ससद के निवले सदम में महत्त प्राप्त है। सबियान के अनुच्छेद ७४ (व) ने अनुसार पत्रीमण्डल भा तासू-हिक उत्तरदायिस्य ससद के निबसे सदन ने प्रति है। सामूहिक उत्तरदायिस्य के सिद्धान्त को सबियान द्वारा मान्यता प्रदत्त नरने के कारण राप्ट्रपति के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं रह जाता है वि उसी व्यक्ति को प्रयान मंत्री के पर पर नियुक्त किया जाय, जिसको ससद के निचले सदन (लोकसमा) में यहमत प्राप्त है। मन्यया, किसी मन्य व्यक्ति को प्रधान भन्नी नियुक्त करने से राष्ट्रपति द्वारा साम-हिंग उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अवश्य उल्लंधन होगा भीर राष्ट्रपति पर सिय-धान के उल्लंधन नरने के कारण महाभियोग संगाया जा सकता है। प्रतत्व, राष्ट्र-पति को प्रधान मनी नियुक्त करने वा अधिकार तो है, किन्तु इस प्रधिकार का उपयोग ससदात्मक पद्धति वे द्वारा निर्धारित सीमाओ वे अन्दर ही किया जाना चाहिये । इसी प्रकार सविधान के ब्रनुसार मतियो का नार्यनाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्मर है किन्तु जब तक मन्नी परिषद को लोकसभा में बहुमत है, राष्ट्रपति जनको सबैधानिक रूप से पदच्युत नहीं कर सकेगा।

१. एम० बी० पायली—'इण्डियात कान्स्टीट्युशन' १६६२, पृ० ३०८।

यदि लोक्समा म बहुमत दल का नेता करना राज्य पत्र दे देता है और यदि बल में नेतृत्व के निष्, क्षमर्थ है, या बल के नेतृत्व के बत्र में किसी एक वरित्र का मान निक्षित नहीं किया जा कब्बा हो, तो ऐसी स्मिति में राज्यपित करने विवेश मा बदनोल पर करेगा । मारावर्ष में बदनेश कर वरित्र की स्मित्र की मारावित्र में एक उन्नात कर हो। हो है है।

सांवतो को निवृत्तित तथा सवी परिवाद के बाउन के निवाद में। बान्द्रीत्पत्रित सह है कि पान्नति प्रवाद कार्यों के पान्यके का पानन करने के निवाद बाम्स है। इन ह्या के नवा के कहे निवाद का बाजुरी कार यह है कि कार्यों व्यक्तियों पानुपत्ति में निहित्त हैं, परन्तु पाननीतिक एवं क्यावरास्ति केन्य यह है कि यदि प्रयान-नवीं नो लोकन्या न बहुनद प्राप्त है, तो ये प्रवित्त स्वान्तव म प्रयान नवीं के ही है।

मिन्सी के मनय ने मिन्नान के कड़ियर धनुष्टेय और हैं, जिनको ब्यान में पत्नी सामग्रह है। सनुबंदे 32 (४) के सनुवार नहीं का पर हहा करने कुन्ने प्राप्तृति इसार की मान कर के नारों को निष्टपूर्वक पर सामग्रीकार से करने गर्म दिनाई नाग्नी। इसी सनुबंद के उत्तक (१) के प्रमुख्य हैं। है में ६ माइ वह नागार मन्द्र के किसी सी वहन का नदम्म नहीं एका है, दी वह प्रस्तुत किसा ना केना। करने से अपूर्णेद 32 (१) के प्रमुख्य की स्विधी के देशन वसा मने समग्रुतगर सबद से विनि द्वारा निर्माश्य निर्मे आदेंसे और जब वह सन्दर देश में स्वतिक्त करें, इनको सविधान को दूसरी सनुसूची म दल्लिका कर से दिना सर्वाण

उन्हें हा नदनी ने दन बात का बहेत दिया जा चुझा है कि जारतीय नती-परेशर की कर्ज प्रमानी का मुच विद्याल—सामूहिक उत्तरसारित वा विद्याल है। इन विद्याल के सहुक, र मर्गानरीरार नोकारमा के वस्ता सपनी उत्तर्ण कार्यो के चिर सामूहिक च्या के उत्तरसारी है। विद्याल निर्मातीयों ने दश विद्याल जा स्वार च्या प्रमुद्धि शर्थ (है) में व्यक्त करते हुए इसे मारतीय कटतीय पदाति की ष्रायार मिला माना है। प्रो० श्रीनिवासन मा नहना है—"परम्परानुगार सरनार ने प्रसन में जिसनी स्थापना सवियान द्वारा नी गई है, राष्ट्रपति नी इच्छा नो सार तथा मतदातागण नी इच्छा—ने बनुसार उपयोग में साना होगा।"

### सघीय मत्री परिषद का सगठन ः मत्रीमण्डल एव मत्री परिषद (केविनेट व मिनिस्ट्री)

इत्लैण्ड मे मनीमण्डल तथा मनी परिषद में अन्तर है। मनी परिषद एवं पृहेर् सहया है जिसमें लगनग १०० सदस्य होते हैं। इसम मनीमण्डल वे सदस्य, अन्यमनी, सत्तरीय सचित्र एक अवर सचिव सम्मित्ति हैं। भारत मं भी मनीमण्डल तथा मनी परिषद में अन्तर है। भारतीय मनी-परिषद में भी समस्त मनी गण तथा सरावीय सचिव होने हैं, जत्रिय मनीमण्डल में वेचल वेतीनेट स्तर वे मनी ही हात है। मारतीय मनी परिषद में चार अवार वे स्तरों के मनियमों को मान्यता दी गई है।

सर्वप्रयम, केरीनेट स्तर के मधी है, जो महत्वपूर्ण मधालयों के प्रस्यक्ष है। इत केरीनेट स्तर के मधियों द्वारा मधीमण्डल (केरीनेट) का निर्माण होना है। ये मधीमण्डल की बैटकों से खिम्मलित होते हैं। इतको २,२४० एपये प्रतिमाह केतन और ५०० एपये प्रतिमाह सत्ता मिलता है। इनके साथ, इनको सन्य मुविधाएँ उपस्तन्त्र है।

द्विनीय, गतिपय राज्य-स्तर के सनी है, जो तिसी न तिसी तिमाग या उप-विभाग के लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु इनवा स्तर के मीनदे स्तर के मिन्नि है। सामाग्यत. ये मनीमण्डल की बैटको से सिम्मिलन नही होने हैं, जब तक कि उनको निभेष सामनण न दिया गया हो। ये ससद के प्रति उत्तरदायी हैं। इनको नेपीनद स्तर के मिन्नि के के समुख्य के शस्त्र २,२४० रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है; परन्तु इनको नोई नता प्राप्त नहीं है।

तृतीय, बतियय मत्री उपमत्री-स्तर ने होते हैं। इनना बार्य मत्रात्य ने बार्य में सहयोग या सहायना पहुँचाना होना है। इनको प्रतिमाह १,७५० रुपये वेतन मिलना है।

चतुर्यं, उपमत्रियों से नीचे ससदीय सचिव होते है। उपमत्री एव ससदीय सचित्र विभी विमाग ने प्रध्यक्ष नहीं होते हैं निन्तु इतका नामें मत्रियों को, जिनने वे सबिपन हैं, प्रशासतीय एवं ससदीय नामों में सहायता पहुँचाता है। ये मत्रीमण्डल की बैठनों में सम्मितिन नहीं होने हैं।

१. श्री एन॰ थीनियासन—'पूर्वोक्त पुस्तक', पृ० २१८।

विभिन्न स्तरों के पश्चियों के वेतन तथा भत्ती ना निर्धारण सक्षद द्वारा पारित मित्रदों के वेतन एक मत्ते ना विभिन्तम १६५२ (क्षेत्रीज) एण्ड ग्रताउन्हेड प्राफ मितिस्टरत् एनट १६५२) द्वारा विचा गया है। भर्मा परिषद प्रथे के सित्तन की त्रोक सभा के बहात समर्थन पर ही अनाये

मंत्री परिषद भपने ब्रस्तित्व को लोक समा के बहुनत समयैन पर ही बनाये रख सकती है, सौन इस तरह अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए लोकसमा के प्रति बाक्नीवक कार्यपालिका होने के नाते सामृहिक रूप से उत्तरदायी बहुनी।

बाननिवन नारंपानिता होने के नाते सामूहिक रण से उत्तरसाथी न्दूरी।
मधी परिपद की बाननिवन कार्यपालिता के रूप से सर्वधानिक रिवारि इस
सात से धीर दृढ़ हो बालो है कि इसने नवस्य सवस्य सदस्य भी होंगे धीर प्ररावत रूप
से सोन समा ने प्रति उत्तरसाथी होंगे। यह देशा आ चुना है, वि प्रधान मनी तथा
स्वय मिरोदों की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, पर-तु इन धीपनार्थ का उपयोग
राष्ट्रपति विकारित के सही कर सकता है। सरपार के नार्यों तथा मीतियों के लिए,
प्रश्वत एव प्राथमिक उत्तररात्वास्य मनी परिषद को है। सद मनी परिषद के
नार्यों एव शांतियों का सम्ययन इसी प्रसत्य ने करना वास्त्रीय ही मही, सिंदु
सावयक भी है। इस दृष्टिकोण से मारतीय मनी परिषद वा दिश्व मनी सम्बन्ध

हार्चक अ, १९१० से हालडेन समिति (विटिंग सरकार के सन पर नियुक्त समिति) ने प्रपत्ता अधिनेदन विटिंग सरकार को अस्तुन क्या, जिससे विटिंग मित्राव्यत के कार्यो एक जातियों का विश्वेषण क्या नया है। यह कहने से कोई सन्तियोशिन नहीं होती कि जारतीय सविधान के सन्तर्यत नशीय मनी परिषद के कार्य द्या साहिता, विटिंग मनीमक्यत के हालडेन समिति डारा उक्लेशित

कार्यों तथा सन्तियों के सद्भ हैं । ये तिम्मितिस्तत है —

(२) राज्येष मीतियों का सन्तिय रूप निर्वारण करनत, जिसके परवात साव के समस पहें एक जा सके । सत्तातास पढ़ियों है हम निषय के सक्य में कोई यो मत नहीं ही सकते, कि किसी राज्येग स्थाप के सवय में, राज्येग प्रमित समित मति हमी राज्येग स्थाप के सवय में, राज्येग प्रमित समी तथा मुद्दात में दृष्टिकरों में मीति के निर्मारण का उत्तरवासित्व मंत्री परिषद का ही हीता है। ताराप्णत्या, किसी राज्येग स्वयं में क्षेत्र के निष् परी मत्त्र का ही हीता है। ताराप्णत्या, किसी राज्येग सवद की क्षेत्र है किए परी मत्त्र अप का मित्र होता है, तराव्यात्य सवद की क्षेत्र है किए, उत्तर मीति की निर्माण होता है, तराव्यात्य सवद को की स्थापित के निष्य कर कर निष्य की स्थाप की स्थाप की की स्थापित करने के स्थाप का साम स्थाप होता है, तराव्यात्य सवद का उत्तर निष्य के साम स्थाप की स्थाप होता स्थाप के स्थाप स्थाप की स्थाप स्थाप स्थाप की स्था स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की

355

निमित किया गया । धौर इसी बानून के बायार पर राज्यों का एक नये बायार पर पुनर्गठन निया गया । करः प्रवासन को सही रण से बताने वे लिए विधि-निर्माण करने की बावस्वना होती है । मनी-परिषद सरकार के सेत्र में बहु कड़ी है जो प्रशासन को तथा ससद को जोड़नी है, बन राष्ट्रीय नीति निर्माण को विधि द्वारा लागू करवाने म मनी परिषय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में सहयोग धौर समन्वय स्थापित करती है । इस दृष्टिकोच से मनी परिषय नाम नदा एक दूसरे पर क्रियस्त पर प्रशासन एक दूसरे पर क्रियस्त पर प्रशासन करती है । इस दृष्टिकोच से मनी परिषय नाम नदा एक दूसरे पर क्रियस्त पर पर विकास के पातार पर समद को कार्यकाहित की निर्मार पर समद को प्रशासन पर साम उद्देश के प्रशासन करती है । समद पर प्रशासन करती है । समद प्रशासन करती है । इस दृष्टिक मनी पर पर पर प्रशासन करती है । समद पर प्रशासन करती है । इस तरह मनी परिषय के कार्यक्र मनी है । इस तरह मनी परिषय ह कार्यक्र मनी हमनी विकास करती है । समद पर पर पर प्रशासन करती है । समद सम्पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद सम्पर पर विवास करती न स्थाप पर स्थापित क्रिया जाता है । समद सम्य पर पर पर पर प्रवास के स्थाप पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर पर स्थापित क्रिया जाता है । समद समद पर स्थापित क्रिया जाता है ।

सतद के प्रधिदेशनों ने दौरान साधारणनया प्रतिदिन, प्रस्त, स्यान प्रका प्रादि रखनर कार्यपालिका (मनी परिषद) पर प्रनिदिन का अवरोध लगाया जा सकता है।

संसदीय प्रणाली म कार्यणालिका पर भूल धररोत या मामपित धरोध मतदातागण द्वारा सामान्यत प्रत्येक पाँच वर्ष वे परचात्, धाम चुनावो के समय उपयोग में लामा जा सकता है, जब मनदानाओं को सरकार के कार्यों प्रकीतियों का परोक्ष भरत का परोक्ष भरिकार प्राप्त होना है। यहि मतदानागा प्रपंत दासियों के प्रति सत्यक्ष हैं, तो सरकार पर जनतातिक व्यवस्था में इससे भ्रिष्क महत्वपूर्ण जनतातिक ध्वयरोत प्राप्त होना किन होगा। प्राम चुनाव के समय मनदानागण न केवल ससद के प्रतिनिधियों का निवाबन करते हैं, परन्तु पिछली मक्षे परिषद (बरकार) के कार्यों तथा नीतियों का मूल्याकन करते हुए यह नियंगित करते हैं हैं विषद्धनी मनी परिषद को पुत्र सत्ता की वागकोर सीपी जायें मान्नी।

(श) मारतीय मसदात्मक पद्धति ये मती-परिषद का एर महत्वपूर्ण कार्य सरकार एव प्रमानन पर प्रमानमाली निकन्नण रस्ता है, जिसमे मती परिषद द्वारा निर्धान क्रोर सम्बद हारा क्यांपण निक्ति करी स्थान हो तते । अरुके नवते, यदि वह एक विमामाध्यक्ष है तो विमाग के नायों के लिए व्यक्तियत रूप से उत्तर-सामी होगा । प्रत्येक मत्री, पर वास्तव से सपने विमाग सम्बद्धी उन नीतियों को नायोंनित करने का उत्तरताखिल है, जिनका समूर्ण मत्री परिषद का समर्थन प्राप्त हो गया है। बस्तुत-सन्ते परिषद का सरकार एव प्रवासन के सारे क्षेत्र में सार्वनीम एव विस्तृत नियन्तण रहता है। नि सदेह सपने क्षित्रमें एक प्रीवनारों का उपयोग प्रस्यक मनी सम्पूर्ण मनी परिपद के निर्देशन में ही करेगा। विभी मी मनी द्वारा इस सिद्धानन के उल्लेषन ने परिणाम स्वरूप सम्बयोग प्रद्वति के प्राथान-मूत दसीय प्रणासी के कठीर अनुसाधन के सिद्धानत पर सामाज पहुँच सनता है मीर उनसे सबसित मनी को आपने पद पर से स्वीका देने के लिए जाप्य निया

280

जा सक्ता है।

(त) मनी परिचद का कुनीय वार्य ज्ञावन के विनिन्न विनामों की दियामों
म सक्त्यन स्थादित करते हुए, इन जिलामों को सीमामों ना निर्माण करना है।
मनी परिचद की यह भूमिना, जसकी साम्तरिक राष्ट्रीय कार्यमानिका होने के
नाते प्रान्त है। यह साथ है कि ज्ञावन के विभिन्न विनाम पुन्क हनाइसी ने क्य
म रहक रचार नहीं कर सकते हैं, म हो इनको ज्ञावान की पृत्क प्रान्त सकता हुन हम माना जा सकता है। मनिवार्यत सरकार के विविध्य विभागों म पारस्थित सहसोग होना मानयक है, प्रयत्मा प्रमासन के विवधित विभागों म पारस्थित सहसोग होना मानयक है, प्रयत्मा प्रमासन के विवधित करते हो सर हो सकता है। प्रसाक्त रूप समूर्य वस्तर है, और हसती सफलता का वार्यालय विभिन्न विभागों के पार-स्थारिक सहसोग एवं सामन्य स्थापित करने को क्षमता पर निर्मार करता है। यहि कतियन परिस्थितियों म में या दो से प्राप्त किया की समायों के सहस्थी में के प्राप्त पार्ट्यीय हित को होना जुड़ेकों की समावना होती है। सावस्थान परिपत्न की बैडक से सवधित विभागों ने सत्तमेश को हुर किया वा सकता है। इसलिए साधारणत्या मतासन के निरोधण, निर्मेशन, एवं नियन्तम के कार्य मनी परिचद

हा गाहत है। उपर्युक्त सीन प्रकार ने कार्यों ने ऋतिरिक्त भन्नी परिषद ने एक सन्य कार्य पर

प्रकास जांमना जियन होगा।
(१) पापु की निलीय स्थारमा को सही रूप से सवाधित करने वा उत्तरसांसित्व मनी परिपार वा है। गण मधी-परिपार, विशेषकर विकास मी वा नियमक प्र राष्ट्र में वित्त स्थारमा पर होना न नेवल स्वामावित है, परन्तु आवश्यक मी है। वित्त मनी प्रति वर्ष बाधिय वजट तथार करता है, विश्वने वित्तीय वर्षके स्थार-प्रय का विश्वन हों हो है। कब बजट तथार के समाद उपविक्ता है, तथा मनी परिपार उपने परिवर्शन वरणे की गांग वर समग्री है। बजट पारित होने के पत्थार्ष इसना विभावस एक समस्त वित्त व्यवस्था ना स्वानन मधी मण्डल करता है। स्त नित्ता वरियानक मधी मण्डल होता है।

#### मित्रयों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व

ससदात्मन पद्धति ना मूल घाषार अत्रियो के उत्तरदायित्व ना सिदाल्त है। वास्त्रव में मत्रियो के उत्तरदायित्व ना सिद्धान्त उस जनतात्रिक अत्र के सदृश है, जो एक घोर तो ससद तथा मत्री मण्डल में और दूसरी और राप्ट्रपति तथा मत्री परिषद मे सत्तरात्मक प्रवालों के प्रनुकूल आवश्यक सन्तुलन स्थापित वरता है। यह लग्द है कि सत्तरात्मन पद्धित में कोई सबैधानिव अवरोध इतना प्रभावशाली एवं व्यापक नहीं है, जितना कि मिनयों व उत्तरदायित्व वा सिद्धान्त है क्योंकि एक जत्रीर के रूप में इस सिद्धान्त होरा, सत्तरीय जनवानिक प्रणाली वे चार स्तान्ता-राष्ट्राध्यस, मंत्री परिषद, सत्तर एवं मतदाताय्य वो पारस्परित जनतानिक सम्बन्धों से जोड़ा जाता है। सत्तरात्म पद्धित में मिन्ययों के निम्नलिखित चार विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व हैं।

### तकनीकी या ग्रीपचारिक उत्तरदायित्व

ग्रीपचारिक रूप से, ससदात्मन पद्धति में प्रत्येव मत्री वा उत्तरदायित्व राष्ट्रा-ग्राप्त के प्रिति होता है। ब्रिटिज ससदात्मक प्रणाली में सम्राट वे प्रधिवारों पर प्रवाण डालते हुए, वास्टर वेजहाट ने वहा या कि सम्राट् वे सरवार वे सबस में केवल तीन प्रवार के ग्रीयकार हैं, (क) परामणं देने वा ग्राधिवार, (स) प्रोत्साहित करने वा ग्राधिवार, ग्रीर (ग) चेतावनी देने वा ग्रीधवार।

सरकार के सबध में ब्रिटिश सम्राट के कोई निर्देशक कार्य नहीं है, परन्तु इसके बावजद मी, मित्रयो ना उत्तरदायित्व श्रीपचारिक रूप से सम्राट के प्रति होता है। ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सम्राट साम्राज्ञी की सरकार कहते है। ब्रिटिश सरकार (मत्री परिषद) अपने पद पर सम्राट्या साम्राज्ञी के प्रसाद-पर्यन्त रहते है। इसी तरह मारत के सविधान के अनुच्छेद ७५ (२) के अनुसार मनी प्रपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त तक ही रहेगे। परन्त ससदातमक प्रणाली में, सरकार तथा शासन ने क्षेत्रा मे राष्ट्राध्यक्ष की प्रसन्नना से तात्मर्थ है, ससद की इच्छा । ग्रनएव मनियों का उत्तरदायित्व राष्ट्राध्यक्ष के प्रति केवल ग्रौपचारिक ही है । ग्रौपचारिक उत्तरवायित्व ने सिद्धान्त का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिविम्त मारतीय सविधान के मनुच्छेद ७६ (म्र) के मनुसार प्रधान मनी का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को मत्री-परिषद के सारे निषयों, जो सघ के मामलो के प्रशासन एव विधि-निर्माण प्रस्तानो के सबध में है, ग्रवगत कराये यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है। इसी भ्रमुच्छेद के उपवन्ध (व) के भ्रमुसार, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है, तो प्रधान मत्री ना यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति नो सघ मामलो के प्रशासन एव विधि सबधी प्रस्तावो पर सूचना दें। इसी अनुच्छेद के उपवन्ध (स) वे अनुसार, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है तो प्रधान मनी का यह नर्तव्य होगा कि किसी ऐसे मामले को, जिस पर एक मत्री ने निर्णय से लिया है, परन्तु जिस पर मत्री परिपद ने विचार विमर्श नहीं विया है, मती परिषद वे विचारार्थ रखे । नि सदेह, अनुच्छेद ७८ उपवन्य (ग्र) (व) एव (स) में ससदात्मक पद्धति की कतिपय मूल परम्पराग्रो को समावेशित किया गया है, जिनके माध्यम से, ब्रिटिश सम्राट् के सदश भारतीय राष्ट्रपति का सरकार के सबब मे परावर्ष देने, श्रीत्साहित वरने तथा नेतावनी देने के प्रथिवार प्राप्त होते हैं। इन प्रशिवारों के बाबार पर राष्ट्रपति सरकार के परावर्षाता, भिन्न, प्रात्तोषक एवं दार्बनिक के रूप में ब्राप्ती श्रूमिका निमा सकता है।

#### व्यक्तिगन उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

इंग्लैंग्ड के ससरासक प्रणाली में, मनिया के व्यक्तिय उत्तर-दामिस्य के सिद्धान्त के सामृद्धि के सामृद्धिक उत्तराधित्व के सिद्धान्त में गूर्व हुई हैं। प्रीके डायती के प्रमुक्ता क्योंकार उत्तरादास्थित के सिद्धान्त ने दो अर्थ हैं। प्रयत्त प्रयं यह है कि कानून की दृष्टि ससप्राट के नागों के सिए उत्तरदायी होना, जिस्से यह सार्थ्य है कि सम्राट्ध डारा कार्यपालिक से सबस्यात किये पर कार्यों के सिर सम्ब्राह के हरणास्थार ने साम्य किया में में हे स्वायत का होना प्रावस्थान है।

द्वितीय प्रयं यह है नि राजनीतिक दृष्टिकोण से मत्री का उत्तरदायिक ब्रिटिश ससद के निजल सदन, कामन्स समा, के प्रति है। फ्लस्वरूप यदि कामन्स समा किसी मनी के प्रति अविषयस व्यक्त करें तो सनी यपने वद से स्तीपा देगा।

भारत के सविधान में, मनियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के लिए कोई घाषार-भूत लिखित प्रावधान नहीं है। मारत के बर्द विकसित देश होने के नाते यह उत्तम होता, यदि सुविधान के निर्माता इस विषय पर सुविधार मे विधिष्ट रूप से प्रावधान रवत । श्व्यक्तियन रूप से मित्रियो पर यह एक महत्वपूर्ण सबैधानिक प्रवरोध होता । चुनि इस विषय पर सवियान म लिखित प्रावधान नही है, इस मारण यह उचित होगा कि इस विषय के सम्बन्ध में एक स्वस्थ परम्परा विकसित हो । परन्त मारत की राजनीतिक प्रणाली से पिछने कुछ वर्षों से, कतिपय उदाहरणों के माधार पर यह वहा जा सबता है कि इस विषय पर श्रत्यन्त ही कम विचार किया गया है। यह सत्य है कि ब्रायुनिक समय मे, सरकार की ब्रियाम्रा की जटिलता एवं स्थापनता व नारण प्रत्येन मनी ने निर्णय ने लिए अन्तविमागीय, विचार-विमर्श ग्रावश्यक है। इस दरिट से मत्री के व्यक्तियत उत्तरदायित्व के प्रकृत की इस ग्रायार पर जाँचना चाहिय कि किस सीमा तक मनी स्वय दोधी है। यदि मंत्री का व्यक्तिगत दोष ससद में स्पष्ट हो जाता है तो उसे स्तीफा देने में कोई सकोच नहीं होना चाहिये। इम्लैण्ड म पिछले बुछ वर्षों म व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ने ब्राचार पर मित्रयों ने व्यक्तिगत भूल, जैसे वजट शस्तुत होने के पूर्व बजट सवधी बानों नो प्रवट करना, व्यक्तिगत अध्दाचार या सरकार की खुली ब्रालोचना के नारण स्तीफे दिये । सर सेम्युल होबर ने, १६३५ के होब्रर-लवाल समकीते मे भूत होने के कारण अपना पद त्याय दिया, क्योंकि वे उस समय विदेश मंत्री थे ग्रीर उन्होंने फ्रान्स के प्रवान मंत्री सवास ने साथ इटली-इयापिया ने मुद्ध के दौरान, यह गोपनीय समक्षीता निया नि मुद्ध ना ग्रन्त नरन ने लिए ग्राया इया-पिया इटली नो टे दिया जाय।

श्री हमुडात्टन न जो बिक्त मत्री थे, बजट प्रस्तुत करन क पूर्व, १६४६ म बजट सबयी कुछ बाता क प्रकट हो जाने व कारण धपना स्तीफा दिया। इसी तरह युद्ध मत्री जान प्राफ्त्यमा का, कीसर काण्ड के प्रस्त म १६६२ म धपना स्तीका दना पड़ा।

मारत म भी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ने दृष्टिनाण स नितपय मित्रया न ग्रपना पद स्वय त्यागनार राजनीतिक नैतिकता, एव परिपक्वता का परिचय दिया । श्री लालवहादूर शास्त्री न एक रेल दुघटना हाने के तुरत बाद रेल मंत्री स त्याग पत दे दिया। श्री चागला न, सररार की मापा सबधी नीति पर मतमेद हान से, शिक्षा मनी का पद त्याग दिया । मारतीय मनिया द्वारा व्यक्तिगत भूल ये कारण ग्रपना पद त्याग करन के मामल ब्रिटिश परम्परा की तुलना म श्रपवाद है, न कि परम्परागत व्यवहार ने बातर है। नइ मामलो म सत्री भूल प्रकट होन पर भी ग्रपन पद पर बिना सकीच के दृढ बन रहे। डा॰ के॰ बी॰ रीव का कथन है-- ' वे कई व्यक्तिगत मलें, जिनके परिणाम स्वरूप इंग्लैण्ड म निश्चय ही मनिया न व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में मिद्रान्त में ग्राधार पर त्याग पन दिय, भारत म द्वा दी जाती है, जब प्रधान मनी (ससद म) खडे होनर घापणा नरता है नि वह सारी जिम्म-बारी अपने कथा पर लेता है। जिसका तात्पर्य यह होता है कि प्रधान मनी के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा उसके बहुमत दल की शक्ति का पूर्ण उपयोग उस विषय पर ग्रागे विचार विमर्श को रावने के लिए विया जायेगा। हम यह महसूस करन है कि सविधान निर्मातामा ने फान्स के चौथे गणतन के सद्ग, यदि सविधान म व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की समावेशित किया होता, तो यह उपयुक्त होता।"१

### पारस्परिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

मत्री परिषद एर इकाई होती है खत , सितयो य पारस्परिक एनता तथा सगठन प्रमित्राय है। बास्तव स मत्री-परिषद का बस्तित्व तब ही बता रह सनता है, जब मत्री गण पारस्परिक सवय वे इस सिद्धान्त वे अनुकृत प्रपत्ता आवरण रखें कि या तो हम यब साप-साथ हो ठेरेंगे या सब साथ ही दूब जायेगे। मत्री-परिषद क सदस्यों में एनता और सहयोग ही उसकी दूबता तथा स्थापित्व का

१. के॰ धी॰ राव-'पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ७०-७१ ।

झाबार है। सम्पूर्ण मती-परिषद वो एक समुक्त मोर्च के रूप में कार्य करना धावन्यत है, धन्यामा पारस्परिक फूट होने से मती-परिषद नियर सहवी है। पारस्परिक उत्तरदाखित्व को मावना से मती-परिषद के झान्टिक संगठन में एक रुत्ता एवं एक्टा स्थापित होती है, वो राजनीतिक मच पर विरोधी दनो के झानता करने के लिए प्रति-धावस्थक है।

## सामहिक उत्तरदायित्व

भनी-परिपद के सामूहिक उत्तरपाधित्व के सिद्धान्त से यह आंक्ष्राय है कि स्ववान्तक पदिनि में नामें निरुद्ध एक इकाई के क्य में वान्त कार्यों तथा गीवियों हे तिए प्रत्यक रूप से सबद के निवादों सतत को स्वता या प्रति में क्य से नवादानायण के प्रति उत्तरपादी है। मंत्री-परिपद के कार्यों का तत्तावार्य के प्रति उत्तरपादी है। मंत्री-परिपद के कार्यों का तेवा जोशा तिया जाता है, जो सत्ताव्द वत पर एक प्रत्यक्त्रण कार्यों का तेवा जोशा तिया जाता है, जो सत्ताव्द वत पर एक प्रत्यक्त्रण कार्यों का त्रियं त्या है। मंत्री कार्यों के स्वताव्यक्त के विद्यान के धायार पर प्रति पेचक प्रविधि के स्वायं के स्वताव्यक को प्रवान के साम्य एक प्रति विद्यान के साम्य कार्यों के स्वत्यं (या प्रति दे कार्यों के स्वत्यं प्रति के साम्य है। प्रति के साम्य के स्वत्यं प्रति के साम्य है। साम्य के स्वत्यं प्रति के साम्य क्षित के साम्य के साम्य के स्वत्यं के प्रति के साम्य के साम्य है। हिंदिस सिवान के साम्य के साम्य के एक स्वत्यं प्रति के साम्य है। सिद्ध सिवान के प्रति के साम्य है। सिद्ध सिवान के प्रति के साम्य के साम्य है। सिद्ध सिवान के प्रति के साम्य के स्वत्यं के एक स्वत्यं कि स्वत्यं के स्वत्यं के साम्य है। सिद्ध सिवान के स्वत्यं के साम्य के साम्य के सिवान के सिवान

यहाँ यह जात करना उपर्युक्त होगा कि किन सामनो द्वारा सामूहिक उत्तर-सामित्व के सिद्धान्त के लागू किया जाता है। बाठ धरोवरण ने इस सदक में सित्यान समा में करा था- जेवत अपना मंत्री के सुनायेश के माज्यस से ही सामूहिक उत्तरप्राधित्व के सिद्धान्त को नार्यान्तित किया जा सकता है। मेरे विचार में, सामूहिक उत्तरप्राधित्व के सिद्धान्त को यो सिद्धान्तों के लागू करने से ही मार्यादिव्य किया जा सकता है। एक से यह कि किसी भी व्यक्ति के, विचा प्रधान मंत्री की सनाह के मनी-परिषद पर मनोनीत न किया जाते । दूसरा विद्धान्त्र यह कि किसी भी व्यक्ति को मनी-परिषद के सदस्य के एम में न रखा साथे, यदि प्रधान क्षत्री कहता है कि उसे वस्त्युक्त वर देना चाहिस। उन परि-न्सितियों में ही जब मनी-परिषद के सदस्यों को उनकी नियुक्तित तथा उन्हें पदच्युत करने ने दोते। मामती में प्रधान मत्री को नियन्त्रण म रखा गया है, हमारे सामृहिक उत्तरदायित्व के धादक को प्रध्त रिया जा सकता है।"ी

इती मुद्दे पर प्रशास हानते हुए टा॰ पायनी का महना है— इस तरह तामूहिन उत्तरदायित्व के सिद्धात का विया वय मियतो को अनकी नियुक्ति भीर पदन्तुति वे सका म प्रयान मत्री के नियापण म रखने के द्वारा ही समय हुमा है। के ससद को बाव प्रयासी के पियम १६८० (दि रूस्त आप प्रोतेकर एण्ड वरदक्द आफ दिवनेसेक) के अनुसार मधी मण्डल के सामूहिन उत्तरदायित्व के तिद्धा स्वित्व प्रतिक्रमात्र करता जा सका है।

भारत म व्यावहारिक दृष्टिकोण से सामुहिन उत्तरदावित्व के सिद्धान्त के सबध में कुछ बाधाएँ हैं। भारत की अधिकाश जनता आपद है। ऐसी स्थिति म मतदात्रामी ती ससदात्मव प्रणाती वे मूल सिद्धान्तो सवधी अनुमिन्नता वे पत-स्वरूप कदाचित ससद मे राजनीतिक संग्तुना सही रूप से ७ रह पाये । उदाहरण स्वरूप ऐसी स्थित ससद में उत्पन्न हो सक्ती है जब किसी एक ही दन की इतना भारी बहुमत ससद मे अप्त हो कि प्रतिपक्ष के दना की स्थिति नाममात्र भी रह जाये । भारतीय राजनीति मे प० नेहरू के समय म १६५० से १६६४ तक देखा गया नि वाग्रेस ने बहुमत ने वारण ससद म दलीय स्विति एक तरफ की श्रमतुलन श्रवस्था मे रही। १६७१ मार्च म हए धाम चुनाव म पुन बाग्रेस की श्रीमती गांघी वे नतृत्व म लोव समा में ऋत्यधिव बहुमत श्राप्त हो गया । स्वस्थ ससदारमण पद्धति वे भनुसार ससद म राजनीतिव दलो वी स्थिति म सन्तानन होना प्रायश्यम है और यह भी श्रायश्यम है नि राजनीतिक क्लो की सख्या तीन से अधिय न हो। यहाँ पर मतदाताओं ने दायिखों के सहस्य का आसास मिनता है बयोनि यदि ये अपने मत वा उपयोग इस तरह गरें, जिससे नि स्यानीय, प्रप्रजातानिक, राष्ट्र-विरोधी बातो तथा धार्मिर चन्च विश्वासो से इवे रहने याने राजनीतिय दलो की अपेक्षा राष्टीय, धर्म निरवेक्ष तथा जनतात्रिक सिद्धाता म विश्वास बरने वाले राजनीतिब दसो की ही उनके मत प्राप्त हो तम ही स्वस्य प्रजातका विकास हो सकता है। ससद में यदि केयत दो या तीत राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि निर्वाचित होते है और सत्तावारी दल का बहमत इतना प्रधिन नही है नि प्रतिपक्ष दल या स्वस्य धानादाामा नो रोंद सके, ऐसी

१ यो॰ मार॰ धम्येदकर—कास्टीट्युशनः धसेम्यली हिसेट्स भाग ४ पृ० ११४९-६० ।

२ एम० बी० पायसी-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १७६।

स्थिति मे भर्ता-परिषद के सामूहिङ जसरवायित्व के सिद्धान्त का सही रूप से उपयोग होगा। धोर सरकार भएने कार्यो तथा नीतियों के तिए सबर के प्रति सन्तर्ग भीर त्यारक रहेवी। परन्तु मार्च १६७१ से सम्पन्न हुए भाग नृतान के गरिणासन्तरूप भीमती वाची के तेतृत्व में कार्यस (नृत्ती) को पुत्र ९० मेहरू के अमाने की ठोत तथा सवाय बहुमन सोक समा में प्राप्त हुन्या है, जबकि प्रतिपद्म संतो को जितनी प्राप्त कर्मचा होने के कारण प्रतिक दल को वाग्रेस की जुना में करता नामान के स्थान नोकवान में प्राप्त हुए हैं प्रतिचान के पापना मान्नेक बतों में विमाणित होने के कारण, मारखीय प्रजनीति ही सबसे बडी हमी सान भी एक स्वस्य एव इब प्रतिचस को सनुप्तिस्थित है। यह विवित्त रहे कि एक स्वस्य एव इब प्रतिचस हारते ही, सबसायलक प्रदित्त मानुहरू कत्तरवाणित के सिद्यान का सार्खिक कर्म के क्रियानव्यन कराया का सन्तर है।

सक्षेप में उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्टप्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के व्यवहारिक उपयोग के लिए निम्नलिशित दो ग्रावस्थरताएँ हैं —

सर्वप्रमम, मनी परिषय के निर्माण तथा विषयन के अधिकार प्रधान मनी में ही निहित हो। प्रधान मनी की इञ्छानुसार ही धन्य सनी नी निपुक्ति तथा पदच्यति की जाय।

दितीय, सरकार को जागकक तथा समय रखने के लिए, जिससे सामूहिक कप से यह यमने चारित्वों को निमा सके, सबद में एक कोत खबा बुद्द प्रतिपक्ष दिरोधों बल हो, निवकी प्रमुखिति में सरकार लागरवाह, शक्स तथा निरकुश न बन मकेशी।

#### प्रधान मत्री एवं मत्री परिषद

मारतीय ससदारम्ह प्रणाशी थे, इम्लैच्ड के समान प्रयान नहीं का मरपियक महत्व हैं। येगी ने वेची म प्रयान नहीं ही सर्वधानिक दिवालि तथा बाहियों में समानता पाई जाती है, परणु जरपति के दृष्टिकोण से सोहो में हुं हु मन्तर है। इंदिर के प्रयान मंत्री के पद की जरपति, विटिच्च सर्वधानिक इतिहास की एक रोजकपूर्ण पटना पर माधारित है। तन् १७१४ में सामाजी ऐन की मृत्यु के परचात् इत्तंत्रक की एक नद्दी होजार के उम्बुद्धार लाग्ने को प्राप्त हुई। जाई, पहनी माधार, पिति रिपाक एक एकनियाल परम्पायी में समित्र से सामाजी ऐन की सामाजी एन की सामाजी की सामाजी सामाजी की सामाजी सामाजी

ब्रिटिण संविधान में लिखित रूप से कही भी नही है। नहीं १६०५ तक इस पद का उल्लेख किसी कानून में पाया जाता है। १६०५ में प्राथमिकता क्रम की निर्वारित करने के लिए एक प्रध्यादेश पारित किया गया, उसके प्रनातंत प्रधान मंत्री को पोचवों स्थान दिया गया। यह प्रधम कानून या जितमें प्रधान मंत्री के पद को सम्बद्ध प्रदार की गई। बेतन निर्यारण के ट्रांटिकोण से ब्रिटिण संसद ने क्राउन के मंत्रियों संबंधी प्रधिनयम १६३० मे प्रधान मनी पद का उल्लेख करते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि प्रधान मनी यह १०,००० पोण्ड प्रति पर्य होगा।

श्रतः इसलैण्ड के प्रयान मत्री के पद का बाबार त्रिटिश सर्विधान की एक परस्परा के रूप में है । जिसके बाबार पर बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंत्री

के पद पर नियुक्ति किया जाता है।

भारतवर्ष में प्रधान संत्री के पद का उल्लेख संविधान के लमुन्छेद ७४ (१) में पाया जाता है, जिसके अनुतार राष्ट्रपति को परामश्रे देने के लिए मभी परिषद का प्रावधान किया गया है। संत्री परिषद की सम्पक्षता का दायित्र प्रधान संत्री

🕔 में निहित किया गया है।

भारत के संविधान के अन्तर्गत, जैसा देखा जा चुका है, प्रधान मंत्रों की निमुक्ति राष्ट्रपति झारा की जाती है, परंन्तु सामारणतथा राष्ट्रपति का यह प्रधिकार नगय है, वर्षों का राष्ट्रपति प्रधान मंत्रों के पद के लिए उसी व्यक्ति की प्रधान नगय है; प्रधात, मंत्रों के पद के लिए उसी व्यक्ति की प्रधान के किया सामा नामा हो; प्रधात, को किस प्रधान मंत्रों के पद पर निमुक्त करना होगा।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के लुस्य, सारत के प्रधान मंत्री का सारतीय संसदासका प्रदात में अव्यक्ति में अविकार के स्वाद है, मंत्री परिवद के जीवन का वह केन्द्र विन्दु है भीर मंत्री परिवद के मृत्यु का केन्द्र विन्दु है। "" व्यक्ति में प्रधान मंत्री, मंत्री-परिवद का केन्द्र विन्दु ही नही है, परत्यु यह सान्युर्व राष्ट्र का केन्द्र विन्दु है, जीय थीन्त्र कहते हैं—"सरकार राष्ट्र का क्वामी है। "" व

प्रधान मंत्री के संबंध में कहा गया है कि वह 'समकतों में सबंधेष्ठ' है (Primus inter pares) परन्तु रेमने मूर का कहना है कि प्रवान मंत्री के लिए

१. एच० जे० सास्की-पार्लियामेन्टरी गर्वमेन्ट इन इंग्लैण्ड, १९३८, पृ० २२८ ।

२. एव० चार० प्रीव्य-'द ब्रिटिश कान्स्टीट्युशन' १९५१ पृ० १०८-६।

उपर्मुक्त फ्रब्द अर्पेहीन साबित होते हैं, अविन उसमें अपने सहयोगियों को नियुक्त तथा प्रच्युत वरने की अस्त्रविक अक्तियाँ निहित है। सर आइवर जैनिन्छ का कहता है कि, " प्रधान संत्री वेवल समक्कों से गर्वेथेप्ट ही नहीं है, वह उन मुर्ये के तत्व है. जिसके चारो ग्रोर नक्षत्र परिसमा करते हैं।"

प्रचान मत्री नी महत्वपूर्ण संवैधानिन स्थिति के सबय मे प० नेहरू ने जुनाई ३०, १६४६, में वहा या-"मैं जानता हूँ कि प्रधान मंत्री के क्या कर्तव्य हैं और मधियान के धन्तर्गन प्रदान मंत्री उस कील के सदृष्ठ है जो सरकार रूपी चक्र की चुरी पर सनी है मोर वह को निरने से रोके रहनी है। "र सर विस्त्रम बर्नन हारकोर्ट में ब्रिटिश प्रधान को जयमवाते सितारों के मध्य करेंगा की उपमा दी है (Inter Stellas Luna Minores) प्रवान मत्री की सर्वयानिक स्थिति का महत्व उसकी विभिन्न शक्तियों के बाबार पर ज्ञान किया जा सकता है । ये निक्न-लिखित हैं।

संश्री परिषद के सबस से — पूर्व में इन विषय पर बल दिया जा चुका है, कि ससदारमक सरकार के मूख सिद्धाल्य मनी-परिषद के सामूरिक उत्तरवाधिक के सिद्धान्त के सही क्रियान्वयन के लिए यह धावस्थक है कि भविमो की नियुक्ति तथा उन्हें पद-पतन करने का अधिकार वास्त्रव में प्रधान मनी में निहित हो। ग्रतः विदेन ने प्रधान सत्री ने लिए यह उचित ही नहा गया है कि वह ग्रपने समह (मत्री मण्डल) ने सदस्यों नो स्वेण्द्रा से ब्रदल-वदल सनता है। बस्त स्थिति यह है कि प्रयान मनी ही मनी-परिपद का निर्माण करता है। सस्राट द्वारा मित्रयों की नियुक्ति का घषिकार नेवर बौपनारिक ही है। परन्तु इस धिकार का उपयोग प्रवान सनी निरकुक्त रण ने नहीं कर सकता है। प्रधान सनी को मित्रयों की निमुक्तियों के सबध में अनेक तत्वों को ब्यान में रखना होगा। खदा-हरण स्वरूप बलीय एकना, भीगोलिक प्रतिनिधित्व परम्पराएँ एव राजनीतिक स्विति आदि तस्वो को मतियो की निवृक्ति करते समय प्रधान मत्री को ग्रापन ध्यात में रक्षता हागा । ग्रन प्रधान मंत्री न्वेच्छा से तो इम श्रविकार का उपयोग पर सकता है, परन्त जैमा डा॰ पाइनर ने कहा है-वह कैसर (अमेनी के निरन्ती शासक) के सद्ध नहीं है, इसम कोई सबेह नहीं है कि अन्तिय निर्णय प्रवान मंत्री के हाय में ही है। विभागों का, अतियों में वितरण करने का अधिकार भी प्रधान मत्री ना ही है उदाहरण स्वरूप श्रीमती गाणी ने मार्च १२७१ के आम चनाव के परवात जिसमें उनकी लोकसमा में विश्वात बहमन प्राप्त हुया विमाण का

१. पाई० जैनिग्ड-केबोनेट गर्वमेन्ट, १८५१, पृ० १८२।

२. प० नेहरू-- द ट्रिब्यून, जुलाई ३१, १८४६।

विवरण प्रयते निर्णयानुसार विया। इस मामले वे प्रस्त में भी प्रधान मंत्री पर वित्तय तस्वो का प्रमाव रहता है। दल ने वित्तय सदस्यों वे प्रभाववासी, एवं जनता द्वारा प्रवल रूप से सर्मायत होने वे कारण, इन सदस्यों वी इच्छाप्रों को ठुकराया नहीं जा सकता है। श्रीमती गांधी की मंत्री परिषद में, जिवना निर्माण मार्च, १६७६, में हुमा, श्रीवगजीवनराम, प्रतिरक्ता मंत्री, श्री चवहाण, दित मंत्री, श्री स्वणसिंह, विदेश मंत्री, एवं श्री फबच्हीन श्रहमद, खाद्य मंत्री, पुन निमुक्त निर्माण प्रमाव का श्र्यान एका जाता है।

प्रधान सभी विश्वी सभी वे वायों या धावरण से प्रसावुष्ट होने वे वारण उससे हमाजन मान सकता है। जैना श्रीसती गांची ने उप प्रधान मनी एवं सहवाली । विस्तानी श्री मोरारजी देसाई वो १९६६ से मंत्री प्रियर वर से हमान नारण से हटा दिया नि वे उनकी विस्त सवयी नीतियों से बात्तुष्ट नहीं थी। गदि सभी प्रधान मनी से सतसद होने पर नी हमाजपत्र नहीं देता है तो प्रधान मनी उस मंत्री को परच्युत करने के सिए राष्ट्रपति वो परामग्रं दे सकता है। वे वेहल वे कार्यवाल में श्री स्थानाप्रसाव मुक्तीं, श्री सीठ डीठ वेषाचुल सोर श्री टेंग टीठ हमाचारी ने सौर सीमती गांगी वे वार्यक्त से श्री चालाल, श्री पुनाचा एवं श्री वयनुप्रताल हांगी सादि मिश्री ने प्रधान सभी से सतमें वे वार्यक्त त्यार पद्य दिये थे।

प्रपान मत्री को विसी भी मत्री की वदोजित वा पदावनित का भी मिषिवार है। श्रीमती गाँधी ने १६६७ के झाम चुनाव के पत्रवात् श्री दिनेशांसिह को राज्य मत्री से कैशीनेट स्तर के मत्री (विदेश मत्री) के पद पर नियुक्त विया।

प्रधान मनी मधी-परिषद का श्रध्यक्ष मा समापति होता है। उसने द्वारा ही मधी-परिषद की कार्य सुची निर्धारित की जाती है। सनी-परिषद की सारी पिति-प्रियक्ष की सारी पिति-प्रियक्ष की सारी पिति-प्रधान प्रशान स्थान स्

## राष्ट्रपति एव मनी मण्डल के मध्य कड़ी के रूप में प्रधान मनी की भूमिका

ब्रिटिश सनदा मर प्रणानी के ग्रन्तर्गत सम्राट के श्रविकारों के सम्बन्ध में ग्रपने विचारों को ध्यक करते हुए माटर वेजहार ने कहा था कि ग्रीपचारिक प्रधान होने हैं नाने, सम्राट् के कैवल तीन ही अधिकार बचे रह गरे हैं। वे अधि-कार इस प्रकार है, १-प्रोत्माहित करने का स्मितार, २-वेतावनी देने का ग्राधिकार, एव, ३-विचार-विमार्ग करने का अधिकार । यह विदित है कि यह प्रिविकार राष्ट्र के सार्वजनिक सामलों के सम्बन्ध में हैं। चुँडि राष्ट्र की प्रगति का उत्तरदायित्व प्रयान मनी के नेतृत्व में मनी मण्डल पर निर्मर स्ट्रना है प्रवः राष्ट्राज्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलो की जानकारी का सब से प्रमावशाली माध्यम प्रधान मनी ही है, जिसके नेतृत्व में मनी मण्डल राष्ट्र की नीतियों एव कार्यों का निर्धारण करता है। ब्रिटेन में प्रधान मंत्री को राजा एवं मंत्री भण्डल के मध्य एक कडी के सदश, परस्परा के बाबार पर, माना गया है। मारतीय सर्वियान में प्रधान मंत्री की इसी प्रकार की सुमिका को अनुक्टेंद्र ७६ के अन्तर्गत मान्यता दो गई है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत मनी मण्डल द्वारा भारत सब सबधी विषयो पर लिये गये निर्णय प्रधान मनी द्वारा राष्ट्रपति को प्रेपिन किये जायेंगे । ग्रतः यह स्पष्ट है कि नारतीय प्रयान मन्नी, राष्ट्रपति तथा मनी मण्डल के बीच की एक महत्वपूर्ण वडी है, जिससे प्रधान मंत्री, सतीमण्डत के सध-सम्बन्धी सामली पर लिये गरे निर्णयों से राष्ट्रपति को ब्रह्मत कराता है।

# शासन के कविषय महत्वपूर्ण पहलुखो से संबंधित प्रयान मत्री की मूमिका

मार्क्याय मनदान्यक पढ़िन ये प्रधान मती शामन का बान्नविक प्रधान है। बान्नव में, बाँद प्रधान मती के बस को मधद के निवस सदन से बहुमन प्राप्त है हो राष्ट्रपति को प्रमान शिक्ता का उत्थोग भनी मध्दत की, जिसका प्रधान प्रधान मती है, ससाहानुसार करना शावस्थक है।

मारत के महान्यायवादी (Attorney-General) का पद सपीय कार्यपालिका सं सबनित है। इसकी निमुक्ति राष्ट्रपति करना है। यह प्रविकारी मारत सरकार का प्रमुख विनि अनिकारी है। केवल उन व्यक्ति की ही निमुक्ति इन पद पर हो सकती है। यो वर्षोक्क नायातव के न्यातातीय के पद के योग्य है। महान्यायवादी का बेवत राष्ट्रपति द्वारा निर्मासित निममों के अन्तर्गत, ४,००० रमये तथा ३४० स्पर्य नती प्रतिमाह स्वाहत है। महान्यायवादी के भारत सरकार के कानूनी मामलों के सम्बन्ध में निम्न-

लिखित नाम हैं --

क--- मारत सरकार को कानूनी मामलो पर परामर्थ देना एव उन कानूनी

नार्यों का सम्पादन करना जो उसको भारत सरकार द्वारा सीपे मये हैं।

स-सर्वोच्च -यायालय के समझ भारत सरकार के समस्त मामतो का प्रति-निषित्व करना ।

ग—सर्वोच्च व्यायालय के समझ नारत खरकार का प्रतिनिधित्त ऐसे प्रच'रणे के सम्बन्ध में करना, जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के धनुष्टेद १४३ के मन्तर्गत प्रेषित किये गये हैं।

ध—महान्यायवादी को ऐसे कार्यों का सन्पादन करना झावश्यन है जो उसको सनिवान या वर्तमान कानन के झन्तर्गत सौंपे गये हैं।

# संघीय संसद

भारतीय सविधान के धनुब्देद ७१ के धनुसार सधीय व्यवस्थापिका समा को सधीय ससद की सज्ञा दी गई है। सधीय सबद के प्रमुख धन राष्ट्रपति तथा दो सदन है। इसमें से निम्न सदन कोकसमा (House of People) धौर उच्च सदन, राज्य समा (Council of States) कहा जाता है। राष्ट्रपति के सधीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने पर भी, जेसे सधीय ससद के सबध में सविधान के धनुसार बुद्ध महत्वपूर्ण कार्य सीरे गये हैं।

#### ससद का सगठन

क—राज्य समा (Council of States) मारतीय ससद के उच्च सदन को राज्य समा नाम दिया गया है जिसमे २४० से स्विक सदस्य नहीं होंगे। इतमें से १२ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष सदस्यों का निर्दाचन सम के विभिन्न राज्यों की विधान समाधों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकत सकमणीय मणांची के मायार पर किया जाता है। अनुच्छेद ८० के अनुसार केन्द्र प्रशासिन क्षेत्रों के प्रतिनिधि ससद द्वारा निर्मित दिखि में निहित प्रक्रियों के म्रनुसार मार्गेगे। राज्य समा के १२ सदस्यों को राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से मनोनीत करेगा जिन्हें साहिरय, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा धादि के क्षेत्रों में विशेष जान या प्रमुचन है।

राज्य समा की सदस्यता के लिए सविधान के अन्तर्यंत निम्नलिखित अहतीएँ होनी चाहिए --

- १. भारतीय नागरिक होना चाहिये,
  - २. तीस वर्ष की ब्रायु होनी चाहिये और
- रे अन्य वे सभी श्रहतीएँ जो ससदीय कानून द्वारा निर्धारित की गई हो। जन प्रतिनिधित्व कानून १६५१ (People's Representation Act 1951) के

प्रनुसार राज्य समा में निर्वाचित होने के लिये एक व्यक्ति को ससदीय निर्वाचक होना प्रावश्यक है, जहाँ से वह राज्य समा के चुनाव के लिए खड़ा होता है। राज्य समा एक स्थामी सस्या है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष प्रयक्तात्र यहण करता हैं। इस तरह राज्य समा के प्रत्येक सदस्य का कार्यशास ६ वर्ष का होता है।

मारत कर उपराज्यित राज्य समा का समापति हाना है। धमरीनी उप-राज्यित ने मदम भारतीय उपराज्यित उच्च सदम ना सदस नहीं है भीर स्मारीनी उपराज्यित के समाना ही सिसाय मतदान की समानात ने सिसति में, क्षेत्र मतदान करने का स्मारान हो सिसाय मतदान की समानात ने प्रतु महत्व-पूर्ण परिकार प्राचा है। कहा किसी भी सदस नो वार-विवास में हिस्सा तैने के सिर्द्ध मियुन कर महना है। कहा कहा ने स्मुजासन नामि उन्हें को सीयुन्दार है। सदन के पटल पर प्रका रचने चौर परिधामों नो चौधित करने ना स्मिक्तर समापति नी है। अनुन्दीद नट (१) के स्मुजार राज्य समा एक ज्यसानाति वार्ष्याद्वारोति । सामापति को प्रमुक्तिया ने या जब समापति (प्राच्य का वपराद्वारीत) राज्यक्ति पर पर है, उपस्थापति राग्य समा नी सम्बज्ञता करता है। सीना—समापति तथा उपसमापति की स्मुक्तियोत में, सदन के निवामों के स्मत्रमत्त राज्य समा समापति तिमुक्त करती है।

ल-लोशसमा ससद के निम्न सदन की, जो जनता का प्रतिनिधि सदन है. लोकसमा (House of People) कहा जाता है । लोक समा के सदस्यों की सल्या. श्रनु®देद द१ के प्रतुसार ५०० निर्धारित की गई बी, परन्तु सातवें सशोधन सन् १९५६ द्वारा यह सत्या वढा कर ५२० कर दी गई है। लोकसभा के सदस्य मत-बातामी बारा विभिन्न राज्यों से ब्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बाधार पर निर्वाचित किये जाते हैं और २ = सदस्य सधीय भू-मागी (Union Territories) और उत्तर-पुषं सीमान्त क्षेत्रों में से ससद द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार चने जाते हैं। सविधान के अनुच्छेद ३२६ के अनुसार लोकसभा के चुनाव वयस्य मताधिकार सिद्धान्तानुसार सम्पन किये जायेगें। सक्षेप मे, इस सिद्धान्त ना यह अर्थ है कि मारत के प्रत्येक नागरिक नो, जो २१ वर्ष की बाय का है और किसी कारण सविधान के घन्छगत षयीग्य नहीं है, लोकसमा के चनाव में मतदान करने का अधिकार है। लोकसभा के प्रत्येन सदस्य का निर्वाचन इस तरह होगा, कि वह ४,००,००० से प्रविक जनसस्या का प्रतिनिधित्व न करे। अनुस्थेद ३३१ के प्रनुसार राष्ट्रपति को स्रोकसमा के लिए दो बाग्ल-मारतीयों को मनोनीत करने का प्रधिकार है, यदि उसके विचार में भाग्त-मारतीय समाज का अतिनिधित्व लोकसमा में पर्याप्त नहीं हैं। इसी तरह मनुन्छेद ३३० (१) ने अनुसार लोनसमा मे निम्नलिसित वर्गी के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं (१) बनुसूचित वर्ष, (२) मनुसूचित जातियो, सिवाय उन जातियो ने जो धासाम ने धनुसूचित क्षेत्र म है, धौर (३) बासाम के स्वायत्त जिलो की अनुसुनित जातियो ।

सोकसमा का कार्यकाल पाँच वर्ष का है, यदि इससे पूर्व यह मंग नही हो जाती है। अनुच्छेद (२) के अनुसार जब देश में संकटकालीन उद्योगणा लागू है तब लोकसमा के कार्यकाल में संसदीय कानून हाया, एक समय में एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकती है। परन्तु किसी भी परिस्थिति में संकटकालीन उद्योगिए। के समाप्त होने के बाद ६ माह से अधिक के लिए यह लागू नहीं की जा सकती है। सोच समा के सहस्य के जुनाव सार्वजनिक ययस्म-मताधिकार के आधार पर सम्पन्न किया जाता है। लोक समा के चुनाव के लिए मतदाता की बीयताएँ इस प्रकार हैं:—

१. यह मारत का नागरिक हो।

२. उसकी म्रायु २१ वर्ष की हो।

यह निर्याचन क्षेत्र में बम से कम १०० दिन तक नियास पर चुका हो,
 भीर समद द्वारा घोषित कोई अयोग्यता उसमें न हो।

लोकसमा की सदस्यता के लिए संविधान के धनुरुष्ट्रेद ८४ के धनुसार परियक सदस्य की प्रधोलिखित धहर्ताएँ पूर्ण करनी होंगी।

१. भारत का नागरिक होना श्रायस्थक है।

२. २५ वर्ष से कम ब्रायुन हो भीर,

३. वे अन्य शहलाएँ होनी चाहिएँ जो संसदीय कानून द्वारा निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद १०२ (१) के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोक समा सदस्य नहीं हो सकता है यदि

(१) यह मारत सरकार या निशी राज्य सरकार के प्रयोग लाग के पर पर है, सिवाय वस पराधिकारी के जिसके संबंध में संसद ने यह कानून पारित निया है कि वह इस प्रयोग्यता से मृतत होता ।

सन् १९४१ में जांच सिमितियों, निगमों तथा घायोगों के सदस्यों, तथा १९४४ में विक्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, संसद के उपप्रधान सचेतकों तथा नेमनल कैंडेट कोर प्रीर क्षेत्रीय सैन्य इस के अधिकारियों को, इस संदर्भ में उपर्युवत अयोग्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

(२) वह किसी न्यायासय द्वारा पावस घोषित किया गया है।

(३) यह दिवालिया है।

(४) मारत का नागरिक नही है अथवा उसने किसी विदेशी राज्य की नाग-रिक्ता प्राप्त करसी है, अथवा वह किसी अन्य राज्य के प्रति मन्ति रखता है।

(४) संगद इरग निमित किसी कानून के द्वारा या झन्तगैत प्रयोग्य न हो । इस संदर्भ में संसद ने १९४१ में कुछ अयोग्यताओं का निर्धारण किया है जो निम्ना-नुसार हैं:—

- (क) यदि उस व्यक्ति ने दिवींचन संबंधी कोई प्रपराध किया है। (स) यदि उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो वर्ष से प्रधिक की सजा
- मिली है तथा दण्ड से मस्ति मिले उसे पाँच वर्ष से अधिक नही हुए हैं। (ग) यदि उसे किसी सरकारी नौकरी में से अष्टाचार के कारण निकासा गया है 1
- (ध) यदि वह सरकार से सबवित किसी बनुबन्य या नारखाने में मागीदार

है । यदि लोकसमा के सदस्य होने के पश्चात उपर्यक्त कारण से कोई व्यक्ति प्रयोग्य हो जाता है तो वह लोकसमा का सदस्य नहीं रह सकेगा। विसी सदस्य के ब्रयोग्यता सदयी भागले का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन ब्रायोग की सलाह से करता है । यदि कोई सदस्य लगातार ६० दिवस तक लोक्समा की बैठको से भनपस्थित रहता है तो उसकी सदस्थता समाप्त हो जाती है।

### सहस्यों के विशेषाधिकार

सविधान के बन्तर्गत ससद के सदस्यों को कतिएय विशेषाधिकार प्रदान किये गर्य हैं। अनुच्छेद १०५ के अन्तर्गत सदस्यों को सदन में या सदन नी किसी सी समिति में मायण दैने की स्वतंत्रता होगी और मायण में अभिव्यक्त विचारों के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दीवानी मामलों के लिए, ससद के ग्राधिवेशन प्रारम्भ होने के चालीस दिन बाद तक, किसी सदस्य की गिरफनारी नहीं की जा सबेगी। परन्त की जदारी मामलों के किए किसी सदस्य को गिरफतार किया जा सकता है। ससद के सदस्यों को वेतन तथा मसे ससद द्वारा पारित विधि के अनुसार दिय जायेंगे।

### लोक सभा का ग्रध्यक्ष (स्पीकर)

लोकसभा के विभिन्न पदाधिकारियों में श्रध्यक्ष (स्पीकर) का पद ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । वास्तव में, भारत में अध्यक्ष पद का विकास, ब्रिटिश कामस्स सभा के ब्रध्यक्ष के पद के आधार पर हुआ है। १६२१ से, जब प्रथम श्रुच्यक्ष सर फेडरिक व्हाइट की नियुक्त केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निचले सदन के प्राध्यक्ष के रूप में मारतीय गवर्नर अनरल द्वारा चार वर्ष के लिये की गई थी, मारत मे वेन्द्रीय व्यवस्थापिका समा के निचले सदन के सात ग्रध्यक्ष हुए हैं, जिन्होंने इस सस्या की स्वतनता एव निष्पक्षता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये ग्रध्यक्ष (स्पीनर) हैं—सर फेडरिक व्हाइट, थी वि० चे० पटेल, थी जी० वी॰ मनलकर, श्री एम॰ ए॰ भ्राय्यवर, सरदार हुकुमसिंह, श्री एन॰ सजीव रेडडी. एव वर्तमान ग्रध्यक्ष श्री गुर दयाल सिंह ढिल्ली । इन्होंने ग्रथ्यक्ष पद के गौरव भीर प्रतिष्टा को अपने अवक प्रयत्नो द्वारा बढावा है ।

गारतीय सविधान के बन्च्छेद ६३ के बनुसार लोकसभा स्वय अपने श्रध्यक्ष का निर्वाचन वरती है। अनुच्छेद १४ (ग्र) वे अनुसार अध्यक्ष को सदन वा सदस्य होना जरूरी है। धनुच्छेद ६४ (स) के धनुसार, ग्रध्यदा को लोकसभा के बहुमत प्रस्ताव से पदन्युत विया जा सकता है, परन्तु इस प्रस्ताव को पारित करने वे पूर्व चौदह दिन की मूचना देनी बावश्यक है । ब्रध्यक्ष स्वय इस्तीफा दे सकता है । सविधान द्वारा उपाध्यक्ष वे पद वा भी प्रावधान विया गया है, जो प्रध्यक्ष की म्रनुपस्थितिम या भ्रष्यक्ष पदने लाली होने पर भ्रष्यक्ष ने नार्यों को सम्पन्न मरेगा । ससदीय कार्य प्रणासी वे नियम १६५० वे अनुसार (नियम ७) ससद वे ब्रारम्म होने के समय या समयानुसार बच्यदा, यसद के सदस्यों म से ६ सदस्यों की एक सूची बना लेगा, जिसमे से एक सदस्य अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की ग्रध्यक्षता बरेगा। यदि इन ६ सदस्या मसे बोई भी उपस्थित न हो तो सदन अपने सदस्यों में से निसी को भी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर सकता है। श्रमुच्छेद १६ (१) के श्रमुसार न तो श्रष्यक्ष, न उपाध्यक्ष उस बक्त सदन की श्रष्यक्षता करेगा, जब उसने स्वय के पदच्यत करने के मामले पर वादिववाद हो रहा है, परन्त ऐसी स्थिति मे अनुच्छेद ६६ (२) वे अनुसार अध्यक्ष या उपध्यक्ष को विवाद में हिस्सा लेन तथा धपना बचाव करने का पूर्ण प्रविकार होगा।

ग्रध्यक्ष ने देतन तथा भरो ना निर्घारण ससद करती है। उसकी भारत की

सचित निधि में से वेतन तथा भरो दिये जायेंगे।

## ग्रध्यक्ष के कार्य तथा शक्तियाँ

थिटेन में, एक सबैधानिक अभिसमय के अनुसार बिटिश अध्यक्ष को समान मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। मारतीय सविधान मनुच्छेद १००(२)ने मनुसार लोकसभा ने अध्यक्ष को समान मतदान नी स्थिति में निर्णायक मत देने वा अधिवार है। लोवसमा वी अध्यक्षता, अध्यक्ष (स्पीकर) ही करता है। वह लोकसमा की कार्यवाही की नियम सवधी आपत्तियो पर निर्णय देता है । उसका निर्णय मन्तिम होता है । लोकसमा मे बाद-विवाद मे हिस्सा लेने रो निए वह सदस्यों को मान्यता देता है। सविधान के प्रमुच्छेद ११० (३) में प्रमुसार प्रायस को इस विषय पर निर्णय देने का प्रथिकार है कि एक विधेयक साधारण है या वित्त विधेयक । वह ससद ने दोनो सदनों नी सयुक्त बैठनों नी मध्यक्षता करता है ।

भ्रष्यक्ष ने कार्यों तथा शन्तियों का विस्तृत रूप से अल्लेख ससद नी कार्य-वाही ने नियम १९५० में निया गया है, जो निम्नानुसार है।

मारतीय शासन और राजनीति 125

१—सदन क नजा की सनाह से राष्ट्रपनि के मापण म उल्लालत विषयो पर बाद दिवाद न लिए बाध्यय द्वारा समय का नियारण किया जाता है। राष्ट्रपति क भावण पर घायबाद प्रस्ताव म संशोवन के स्वस्त का श्रम्य र हा निर्धारित करता ह । ब्राप्त को यह ब्रापकार नी है कि राज्यित क भाषण से सबवित विषयों पर

सदम्बा क निए भाषण की समयाविधि या निजारत करे। २-- पदन के नवा की सवाह अनुसार अन्यत सदन की कारवाइ का क्रम

नियस्य करता है। ३--प्राप्त इस वियय पर नियय लगा है कि सदन क समन प्रस्तान प्रकार

स्वाकार करन यात्र है या नहा । नियम के विरुद्ध प्रथमा की वह अस्वाकृति करता है।

८—किनी मण्यात सावजानक समित पर बार विवाद करन क लिए काम राहा प्रन्तांच मारित करने वं निए धायत की सनुमात सावस्थक है । और एसे वियय पर से बार के निरुष्ध अने द्वारा ही समयाब ये का निवारण किया जाना है।

५--- नाद मानन नजर म किया विवादक के प्रकाशन के मादेश दे दला है ती वस्त विराह का महत मात्र बुत करन का प्रध्याद की भावश्यक्ता नहा हाती है। ६—प्रवर समि। तया (सलेवर कमरीय) व बच्यता की नियुक्ति सम्यत

विभिन्नं समितिया वः सदस्या स स करता है।

 क्सा विजयन पर बाद विवाद स्थानित बरन के लिए प्रस्थान के लिए. ध्रध्यात का सहमात बावश्यक है।

 प्राप्त किमी प्रध्याव को स्वीष्ट्रत करने के लिए निषय सता है। बहु बिल वियम सबनी नारवाइ को पूरा करन के निए प्रावस्थक कदम ले

संबना है। १०-- प्राप्तुन विवया समझ के मध्य सम्पक-साधन का कहा करण

म नाय नरता है।

! १---वह सदन म सदस्या को मायण दने क लिए मा यदा प्रदन करता है। साय ही वह भाषमा का जम भी नियारत करता है। सदन के सदस्य ग्रापस म प्रश्न द्वारा एक दूसर का सवाध्यन न करन हुए अध्यन को हा सवाजित करन हैं।

१२-- प्रध्यन सदत की काववाही की नियम सबबी धारत्विया पर निण्य दता है और उसका निगन यक्तिन होता है।

१३ — मच्यात सदत म बनुसामन बनान रखता है और इस उद्देश की पूर्ति न लिए उत्तरा बावरार बाक्ता भी ठानवा है। विना सदस्य को सदन की व्यवस्था मग करन पर ब्रव्ययः उत्तको चेतावनी दे सकता है। ब्रोर ब्रावस्यकता- नुसार ऐसे सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए बाध्य कर सकता है । यदि सदन में, प्रज्ञान्ति तथा घळ्यबस्या से गंगीर स्थिति हो जाती है तो अध्यक्ष सदन की बैठक को स्थानत करसकता है !

१४-ग्रध्यक्ष सदन में दर्शकों के प्रवेश पर नियन्त्रण रखता है । साथ ही

जनको सदन से बाहर जाने के लिए वह सकता है।

१५--- प्रध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सक्त की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकास दे जो उसके मतानुसार मानहानिजनक, प्रक्षिप्ट या प्रससदीय है।

जाना चाहिये।

अध्यक्ष के उपर्युक्त कार्यों के दृष्टिकाण से उसको सदन के मुलरूप के मुस्य माना जा सकता है। वह सदन के अधिकारों का अभिभावक है और विशेषकर सदन के प्रत्यसंस्थकों के हिनों का रतक है। वह सरकार द्वारा सदन के प्रधिकारों का प्रतिक्रमण करने से रोकता है। जब मंत्री सदन में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में ग्रानाकानी करते हैं या जब उनके द्वारा संदन को प्रयाप्त जानकारी नही दी जाती है, तो सदस्मगण श्रध्यक्ष से सदन के अधिकारों की रक्षा करने की अपील कर सकते हैं। बास्तव में, मारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसमा का प्राप्यक्ष इस संतलन चक्र के तल्य है, जिससे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंधों में जनतांत्रिक सन्तलन स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जैसा देखा जा चुका है, मध्यक्ष में ऐसी शवितयों को निहित किया गया है, जिनसे वह सदन के विरुद्ध कार्यपालिका (शासन) के अतिक्रमणों पर अवरोध लगा सकता है। अध्यक्ष की उपर्युक्त मूमिका को ध्यान में रखते हुए, पं० नेहरू ने, जब वे संविधान समा में श्री बी॰ जे॰ पटेल की तस्वीर का अनावरण कर रहे थे, मार्च द सन् १६४८ की निम्नलिखित ऐतिहासिक शब्द कहे-"सरकारकी और से मैं यह कहेंगा कि हम यह चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष सब और हमेशा सदन की स्वतंत्रता की रक्षा प्रत्येक प्रकार के खतरे से करेंगे—कार्यपालिका के अतिक्रमण के खतरे से मी। यह खतरा हमेशा बना रहता है कि एक राष्ट्रीय सरकार ग्रत्यसंस्थकों के विचारों के दमन करने का प्रयत्न करे और ऐसी स्थिति में ही अध्यक्ष का यह दायित्व हो जाता है कि वह सदन के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक इकाई की एक प्रमुख्यपूर्ण सरकार से रक्षा करे।...विट्ठल माई पटेल ने इन परम्पराम्रों की नीव डाली जी भ्रव भव्यक्ष पद से स्थायी रूप से संबंधित हो गई। —मैं ब्राज्ञा करता हूँ कि यह परम्परा बनी रहेगी क्योंकि भ्रष्यक्ष का पद किसी व्यक्ति-विशेष की प्रतिष्ठा नहीं है। प्रध्यक्ष सम्पूर्ण सदन की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है ग्रीर चुँकि सदन सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है अतः अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जा सकता है । यह उपयुक्त है कि भ्रष्यक्ष का पद निव्यक्ष पद हो,

एक प्रतिय्ठा पूर्ण पद हो और इस पद पर हमेशा विशेष क्षमतावान तथा निष्पक्ष व्यक्ति ग्रासीन हो।"

इस्तैष्ठ म भ्याने निर्वाणन के तुरन पश्चात् नामना समा ना अध्यक्ष दक्तत राजनीति से सन्यास से लेना है, और सबद के सम्पूर्ण नार्धमात तक अपने पर पर रहना है । इस्तेष्य म सम्यक्ष पद से सर्गाणन नृद्ध स्वस्थ तया महत्वपूर्ण परमारामी ना विदाल हुमा है, जो उत्तर्ध पर नो एक मन्ता मर्वसानित एव स्वाधिक महत्व प्रदक्त करती हैं, जिनसे न नेवस बध्यक्ष ने पद नी प्रतिष्ठा वही है परस्तु इनके डारा अध्यक्ष पद को एक ऐसे भागन का कर मिना है जो सन्त के सदस्तों के प्रधिकारी तथा उनकी स्वत्यनायों के रक्षक ने रूप म सक्त मिन्न हिमा है।

मारत में लोकमा के सप्यक्ष पद वो विवेचना करत हुए भूतपूर्व सप्यक्ष स्व॰ भी जी॰ मैं कारण में प्रचेच वार्यक्ष में वहां पा—"मारत म सप्यक्ष मुर्च क्या से राजनीवित्र क्षेत्र के बाहर नहीं हैं. जैसा कि विरंत न सप्यक्ष मार्च का प्रचान के स्वाप्त के स्वप्त क

सतएय मारतीय लोक्सभा का साम्यक्ष राजनीति से सर्वाधव है। बहु एक दल से ताम्यक्ष व्यक्ति है। इस बारण उनके पर की इनती प्रतिच्या नहीं हो सहतती है, जितनी की बिटने की काम्या सता ने बायपत्र की है। ताहम्या के प्रमास के दरगर होने के सीचित्र के चाहे, दिनने तक नयो न दिने आये, यह स्पप्ट है दि इससे मॉबिक सीचित्र उन परम्पय का है जिन्नने प्रमुखा दिनेन का प्रमास निर्देशीय और चनसम्य निष्पक्ष होता है। यह स्वामांविक हो है कि मंदि सम्यक्ष में लोकस्वा के स्विकारी तथा स्वत्ववाधी की उत्तित हम से रक्षा

ती० थी० सवतकर—धास्पेबर्स झाफ इंग्डियन कान्स्टोर्युग्न (एम० जी० गुप्ता द्वारा सम्पादित, १६६४, १० २४६-४७ ३

१६१

बरना है तो उसका निर्देतीय होना ग्रांत-भावश्यक है। सर्विधान के लागू किये जाने के पश्चात सत्तारुढ नाग्रेस दल के लिए यह श्रेयस्कर होता, यदि उसके प्रयत्नी से ध्रध्यक्ष का पद निर्देशीय स्वरूप म विकसित होता । दलगत मामलो नी दृष्टि से ही दिसम्बर १६, १६५४, को ग्रध्यक्ष के विरूद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव पारित करने वा प्रयत्न रिया गया था । भ्रत यह श्रत्यावश्यक है कि निर्वाचन के तुरन्त पश्चात ग्रध्यक्ष यो समस्त दलगत सबधा यो छोडवर दलगत राजनीति से सन्यास ले लिया जाये।

## भारतीय ससद की सार्वभौमिकता एवं सर्वधानिक स्थिति

सचीय व्यवस्थापिका के रूप म मारतीय सघीय ससद के लिए, सविधान के मन्तर्गत मनुच्छेद ७६ मे प्रावधान विया गया है। सविधान के मन्तर्गत ससद को सघीय एवं समवर्ती गुचियों य उल्लिखित विषय पर विधि निर्माण करने वा श्रधिकार है, और नितयय विशेष परिस्थितियों म उन निपयों पर भी जो राज्य सूची मे हैं। ससद नी सार्थमीमिकता ना विचार बिटिश सविधान भी एक मूल विशेषता है। प्रो॰ ए० वी० डायसी के अनुसार बिटिश ससद की सार्व मौमिकता मा विशिष्ट अर्थ निस्निसिखित रूप मे स्पष्ट निया गया है ।

'ब्रिटिन ससद की सार्वभीमिकता का बर्थ, ब्रिटिश सविधान के धन्तर्गत इसको परिमापित करते हुए, यह है कि ससद को विसी मी विधि के निर्माण तथा उसे समाप्त करने का अधिकार है और ब्रिटिश विधि के अन्तर्गत किसी ध्यक्तिया सस्या वो ससद द्वारा निर्मित विधि वे नूचलने या रह वरने वा प्रधिवार नही है। सनारात्मन दृष्टिकोण से. ससद की सावमीमिक्ता इस प्रकार है। ससद के विसी भी अधिनियम या प्रचिनियम ने हिस्सी नो, जिसने द्वारा नई विधि का निर्माण या विसी विद्यमान विधि का राज्डन या सशोधन होता है, न्यायालयो द्वारा मान्यता प्रदान की आयेगी । इसी सिद्धान्त को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये सो इस प्रवार से उल्लिखित किया जा सकता है। 'ब्रिटिश सविधान वे प्रन्तर्गत मोई व्यक्ति या सस्या ऐसे नियमो वा निर्माण नहीं वर सवती है, जो ससद द्वारा पारित विधि मी रहे करे या तोडे या जिनको न्यायालय ससद के कानून के विरोध मे लाग वरे।""

वानूनी दृष्टिकोण से, ब्रिटिश ससद की सार्वमौम शक्तियाँ ग्रसीमित है । परन्तु बिटिश ससद की सार्वभौषिकता की कतिषय नैतिक राजकीतिक एव अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं जिनको जिना ध्यान रखे, वह कानूनो का निर्माण नही कर सकती है।

१ ए० थी० डायसी-ला बाक दी कास्टीट्युशन, १६३८, पृ० ३७-३८ । 88

भारतीय शासन घौर राजनीति

धा, अद्यप्ति ब्रिटिस सत्तद की कानूनी दृष्टि से सार्वन्तीमिकता धर्मीनित है, पर बहु नैतित तत्त्वी अनगत एव धरार्वाप्ट्रीय कानून की घट्षा से सन्तिन रहकर विश्वि निर्माण नहीं कर सत्त्री है। तत्त्राणि के सार्वे सीमार्थ, सामुनित समय से समस्त उत्तराजिक राज्यों ने अवस्थापित समार्थी पर साथ है।

१६२

मारदीय सबद की कार्रमीमिकता उपर्युक्त मामान्य सीमामों के प्रतिरिक्त सुगार विविद्य तविषया के निर्मान प्रावधानों द्वारा सीमिन है क्रियेचर, विवयन क तत्र प्रत्यानों द्वारा जिनके सक्षोत्रत का एक्शिक्शः सबद को नृति है। इन प्रावधाना म स, सच्चार सबसी प्रावधान विवोध कर से उपलेखनीय है। "मारतीय सबद एक गमीय सचियान के बनावंत्र व्यवस्थापिका समा है। बिटिंग सबद के सबूच सकता मन्त्रियों समीमित नृति है।"

सारतीय साद एक निवित्त सविधान का, जो कि देश का साईसीन कानून है, तिग्र है। समरीकी प्रणासी के सहस मारपीय प्रणासी में से प्रकार के कानूनों मूल प्रगट पाया जाता है। सर्वेत्रयम देश के कानून के एक में तिवित्र सविधान, स्रोर प्रितीय, साम्याप्य कानून जिनका निर्माण सविधान के धन्मतेन स्थापिन विधान क्यास्थापिक स्थापित विधान के स्वत्यापिक है। यह यह स्वामापिक है कि स्वित्यान द्वारा स्थापित विधान करकस्थापिक स्थापित के किन्द्र कानून का निर्माण द्वारा स्थापित विधान करकस्थापिक स्थापित है। महीना नहीं कर सकती है। मारपीय सबद तथा धमरीको कार्येस, सोनी ही की, सही स्थिति है। मारपीय मविवाय के अनुक्येद २४५ (१) द्वारा यह स्थय हम

करणा।

वसिर सबर, सनियान द्वारा निर्मारित स्वयंत्रे से सार्वजीम है, परस्तु
विदिश्य सबद की दुरना में इसकी सनियान म है। यदि भारतीय सबद किसी
ऐमें नातृत का निर्माण नरती है, निर्माण किसी मारतीय सांच किसी
मारतीय समें के सामानत समरीमी सर्वोच्च स्वायस्य की तरह, सिरमाण निर्माण
कर्तृत की सर्वे स्वायस्य समरीमी सर्वोच्च स्वायस्य की तरह, सिरमाण निर्माण
कर्तृत की सर्वे स्वायस्य कर्ति स्वतः है। मारतीय सर्वोच्च स्वायस्य रातास्य सांच्या
देना सारवस्य है। इतने प्रतिरंकत, सविधान द्वारा यह भी प्रावधान क्या गया
है हि सर्वोच्च स्वायस्य की सहायना वे सिर्म सर्वे रावनीनिक, मिनिस तथा

है नि सर्वोच्च जिज्ञान की सहायना के लिए सारे राजनीतिक, मिनिस तथा गणित प्रतिसारी कार्य करेंगे।
सिनियन के नाजू हीने के पत्थान कई ऐसे स्वयन्य साने, जबति सर्वोच्च ज्ञानात्वन के नाजू हीने के पत्थान के हैं ऐसे स्वयन्य साने, जबति सर्वोच्च ज्ञानात्वन के सिन्य के सिन्य सहय हारा पारित के नित्य कानूनों को सर्वेच पीरित निजा। इनमें से कुन्न कानूनों को उदाहरण स्वरूप प्रान में निया का मत्या है।

टी॰ वे॰ तोपे~द काल्टीट्युशन भाक दण्डिया १६६३, पृ० २६८ ।

- (१) हमदर्द दवाखाना तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य —संघ संसद ने १६५४ में 'द हम एष्ड मैजिक रेमेडीज' कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य कतिवय, उपचारों के, जिनके लिए यह कहा गया था कि इनमें जादुई गुण है, विज्ञापन पर रोक लगाना था।
- (1) इस सानून की वैवानिकता नो हमदर दवासाना तथा अत्यो ने इस प्राधार पर नृतीती दी कि इसके द्वारा अनुच्छेद १६ (१) (अ), और (१६) (१) (एफ), और (जी) मे जिल्लानित नामिक्नो के मून अधिकारी (माधक एव अभिन्यक्ति की स्वतन्नता और व्यापार-व्यवसाय चलाने की स्वतन्नता) का जल्लावन किया गया। सर्वोच्च स्थापालय ने उपयुक्त बानून में कुछ हिस्सी में अर्थ उहराया। सर्वोच्च न्यापालय के निर्णयानुसार उपयुक्त कानून के माण २ उपसब्ध (दी) ने द्वारा कार्य-पालिका की असीमित अभिनयों प्राप्त पी जो प्रत्यायोजित विधि की दृष्टि से मतत है।
- (1) उपर्युक्त कानून के मान द को भी न्यायालय द्वारा धर्मय घोषित किया गया। इस सबध में न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपातित किया हि "ध्यवस्थापिका कानून निर्माण जनता की धावस्थवताओं की पृति के लिए करती है, धतएय कानूनी का निर्माण वह उनके उद्देश्य के धनवर्षत करती है।"?
- (२) यहाँ एक धम्य प्रकरण का अध्यमन वाधनीय प्रतीत होता है। यह प्रवरण है—ए० के गोपालन बनाम महास राज्य। श्री गोपालन की जो १९४७ से बन्दी थे, निवारक निरोध अधिनितय १९४० जो स्थ तथा राज्य सरकारों को निर्दाय अधिक को बन्दी बनाने के लिए जिसने सरत की प्रति रक्षा, मारत के किसी हिदेश से सबस आप प्राप्त प्रकार के किसी राज्य की सुरक्षा या धाति स्थयस्था और धावस्थ निवाओं को बायम रखने के विरुद्ध कार्य किया है, धादेश जारी करने के लिए अधिकृत बरता है) के अपनांत उनके विरुद्ध प्रादेश जारी किया माया था। इस प्रादेश की वैधवा को थी योपालन ने न्यायालय से सुनीती दी। उत्तक तर्त पा कि निवारक ने पा कि निवारक किया प्रविचान के अपनुच्छेद १३, १६, धीर २१ का उल्लायन किया गया। उपर्युक्त भीवित्यम के विनिन्न प्रति करने था कि निवारक निरोध प्रविचान के अपनुच्छेद २२ का उल्लायन हिमा प्रविचान के अपनुच्छेद रा स्था कि निवारक हुआ प्राप्त है। इसर । स्थायाधीकों ने एकसत होकर नियोद स्था किया नियार कि प्रविचान का प्रविचान का

१ हमवर्षे दवालाना व धन्य बनाम भारत सद्य व अन्य-ए० प्राई० झार० १९६० एस० सी० ५५४ ।

२२ (४) का उत्त्यपन विधा गया था। माग-१४ वे धनुसार न्यायातय पर प्रति-बन्ध सामाया गया कि बन्दी वो भेजी गई सूचना से दिल्लियन बन्दी बनाने के वनारचों के सबय म न्यायानय द्वारा नोई साहय या वक्तव्य नहीं तिया जा सरना है।

इस प्रकरण म यह भी स्पष्ट है कि सबद के द्वारा पारित कानून का नुकरव-लोकन कर सर्दोष्य स्थानाथ ने इसके एक माग को सर्वेव भीवन किया। इसी तरह १६६६ म पारित वैक-टाप्ट्रीयकरण कानून के एक माय को सर्वोच्च स्थाया-सम ने भवेष रहराया।

षठ नारतीय ससद ने सार्वमीमिनका सिवधान द्वारा निर्धारिक सीमाम्रो म ही वैधानिक रूप से उपयोग म साई जा सरवी है। जंसा, ग्यावमूर्ति एस० सार० वास में गोपासन जनाम महाश राज्य में निर्धाद देते हुए कहा था—"हमारे सिवधान द्वारा, विदिश्य सिवधान के विषयंति ग्यावालयों की सार्वोच्यान माम्यसा दी गई है, परन्तु यह सर्वोच्चना मरवान सावन नीमित है वर्धीक यह उस व्यवस्थापन क्षेत्र तक सीमित है, कही व्यवस्थापन कार्य माम्यसा दी गई है, परन्तु यह सर्वोच्चना मरवान कार्यक प्राथम सिवधान द्वार प्रतिपारित सीमाम्रो से निर्धान के स्वस्थाप तक्ष्मण तक्षमण स्वयस्थापन कार्यक सिवधान के तरिवंधा के देवस्था तक्षमण तक्षमण सर्वाच्या सावन सावन स्वयस्थापन कर सब्दे हैं, यदि वानून सर्वधानिक सावरे के बाहर है। इन सीमित सर्वधानिक सीमाम्रो के वायर ने वाहर हुमारी सवद उपा राज्य विधान समार्थ सर्वभावसाय के स्वयस्थापन को सार्वभीम हैं। मारत के म्यायालय के निर्देश सर्विद्यान के सावन से मार्थ के मार्यक स्वयस्थापन के निर्देश सर्विद्यान स्वर्धान स्वयस्थापन से निर्देश सर्विद्यान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान के निर्देश सर्विद्यान स्वर्धान स्वर्यान स्वर्धान स

#### लोकसभा एव राज्यसभा के सम्बन्ध

स्रापुतिक समय म जनतव की सफलता के लिए, विनिम्न देशा ने सता पर विनिन्न प्रकार के जनतानिक प्रवरोधों का उपसेषा किया है। इस वृद्धिकों को स्वस्थापन के सम्बन्ध म दिस्तिकार से स्वस्थापन के साम्या म दिस्तवनात्मक प्रवादी को सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण जन-तानिक प्रवराध माना जा सकता है। यजनीति विज्ञान का धहु एक महत्वपूर्ण संस्थ है कि एक व्यक्ति की निरम्भावा की सुलाना म बहुसव्यक्तों की निरमुत्मना प्रतिक इतिकारत तथा सत्यनाक होती है। वृद्धि जनतानिक राज्य म व्यवस्थापन का मार्च व्यवस्थापन का प्रवाद्धिक स्थापन प्रवाद प्रवाद की है कि सावस्था प्रत

१ ए० के० गोपालन अनाम महास राज्य-ए० चाई० धार० १६४० एस० सो० चार० ६६ ॥

२. एस॰ धार॰ दास॰ योपालन बनाम मदास राज्य १९५० एस० सी०

है कि इन बार्यों ने लिए व्यवस्थापिना का सगठन दिसदनात्मक सिद्धान्त पर हो, नयािक ऐसी स्थिति में बिना पारस्परिक सहमति के दोनों में से एक सदन प्रपत्ती जनात (जा रच्या न प्राप्त नहीं कर सकेंगा। यह सत्य है कि प्राप्तुनिक समय में इन्द्रां कातून के रूप में पारित नहीं कर सकेंगा। यह सत्य है कि प्राप्तुनिक समय में दितीय सदनों की शक्तियों सीमित कर दी गई हैं परन्तु सभी जनतात्रिक देशों में उच्च सदनों का होना इस यात का प्रमाण है कि यह वास्तव में जनतत्र के लिए न उच्च सदनों का होना हुस वात वा प्रभाग है कि सह वास्तव में अन्तर के निष्य के कहत उपयोगी परन्तु भावस्थक में हैं। उच्च सदन का भीचित्य वेचल इसिवए ही नहीं कि यह निम्म सदन हारा जल्दबाजों में पारित बृद्धिएमं प्रस्तावों पर रोक लगते हैं परन्तु भानोबीजानिक इंग्टिकोण से इसके रहने से निचले सदन में यह चेत्रता तागृत रहती है कि विषयि निर्माण में उसका एकाधिकार नहीं है। जान-इस्प्रार्टी मिल में स्थयन्थापिका से सगठन के सम्य य म हिसदनारास्थ प्रणाली मा आवस्थवार पर कहा है कि उसके मत्य में सबसे महरन्युण तक यह है नि दिसद-नातमक प्रणाली की भानुपाल्यित ऐसा चुरा प्रमाल बालेगी जी सत्तारूक व्यक्ति मा नातमक प्रणाला को प्रवृत्तास्थात एसा कुरा प्रभाव बालवा जा सत्तास्व व्यक्ति या सत्या के दिनाग पर इस कारक पहुँचता है कि उनके विचार में उनके सिवाम किसी प्रमाय व्यक्ति या सत्या से सलाह नेने की नीई प्रावस्थरना नहीं है। मिल या यह भी कहना था कि व्यक्तियों के किसी समूह नो विना दूसरा की सलाह के प्रपंत नत को लागू करने का प्रायकार नहीं होना चाहिये। एक तस्या में यदि कुछ व्यक्तियों का यह मत के लागू करने का प्रायकार नहीं होना चाहिये। एक तस्या में यदि प्रायकार के स्वायक्तियों का यह मत स्वायक्तियां का प्रायक्तियां के स्वायक्तियां के स्वायक्तियां के स्वायक्तियां के स्वायक्तियां के स्वायक्तियां के स्वायक्तियां कित्ते के प्रायक्तियां के सिन्दुष्य यन सनते हैं यदि जनको यह विदित रहता है वि जनके कार्यों के तिए जनने प्रस्त सोगो की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।'

जैसा दि देखा जा चुना है मारतीय सभीय सबद द्विसदनाश्मक प्रणाली के सिद्धान्त पर माधारित है। ससद वा निचला सदन खोकसमा, जनता का प्रतिनिधि सत्य है जिसमे जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निवर्शित होते है। ससद के उच्च सदन, राज्यसमा का सगठन सध्याद के विद्यानगृह्यार किया गया है। प्रत्य कर राज्यसमा मारत सप के विभिन्न राज्यों ना प्रतिनिधित करती है। पर दु राज्यसमा भीर समरीकी उच्च सदन सिनेट के सगठन से एक मनतर है, इसके वावजद कि दोनो सदन अपने सप के राज्यों ना प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्य देखें सम के प्रतिक राज्य को सीनेट के दो सिनेटरों को राज्यों की जनसच्या वया मौगोलिक स्थित की मिन्नताओं के बावजुद मो समान रूप से मेनने का स्थित है, जिसके स्थाय या या मौगोलिक कि सिनेट या राज्यसमा भी प्रतिनिधित्व जनस्वया सामान रूप से मेनने का स्थित है, जिसके स्थाय या या मौगोलिक स्थाय से माधार पर निर्धारित किया गया है।

१ जे॰ एस॰ मिल-'रिप्रजेन्टेटिह्य गर्वमेण्ट' १६८४, पृ० ६७-६८ ।

दिसदनात्मन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा होता है कि दोनो सदनी में जिस प्रशार के सम्बन्ध होने चाहिया। क्या दोनो सदनों को समान तथा सम-वर्ती ग्राजिकार होने चाहियाँ निवस उच्च सदन को केवल एक सलाहकार सस्या के रूप म नार्य नरने चाहिय। भारतीय संविधान निर्मानाम्रो ने इन जटिल प्रश्नो ना हल वुद्धिमनापूर्ण समा व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बुध मामलो में लोक्समा तथा राज्यसमा को समान खबिकार प्रदत्त किये गये हैं, परन्तु वित्त सम्बन्धी मामनो न धौर कार्यपालिका के उत्तरदाधि व के सिद्धान्त नो लागू करने में केवन लावसमा को ही अधिकार प्रवत्त हैं। अनएव भारतीय राज्यसमा की स्थिति अमरीकी सिनेट तथा ब्रिटिश लाई समा के मध्य की जा सन्ती है। राज्यसमा न तो समरीकी सिनेट के तुन्य शक्तिशाली है भौर नहीं वह ब्रिटिश लाई समा की मौति कमजोर ही है।

राज्यसमा तथा लोकसमा के विभिन्न सम्बन्धां का बच्यमन निम्नलिखित तीन ग्राघारो पर विया जा सकता है।

## राज्यसभा तथा लोक्सभा की समान शक्तियाँ

(व) सिवास वित्त सम्बन्धी विषयों के धन्य विषयों पर लोक्समा तथा राज्य समा के समान प्रविकार हैं। यन (वित्त) विषेयर को छोडकर ग्रन्य विषय सम्बन्धी विधेयक दोनो सदनो में प्रम्तुत किये जा सकते हैं । वास्तव में यह समानता केवल सैद्धान्तिक ही नहीं है, परन्तु सरकार ने समयानुसार इस समानना को ब्यवहारिक रूप प्रदात करने के लिये राज्यसमा में विधेयक प्रस्तुत किये हैं। उदाहरण स्वरूप हिन्दू विवाह (हिन्दू मेरेज) तथा तलाक सम्बन्धी विषेयक राज्यसमा में ही प्रस्तत क्या गया था। जब तक एक विशेषक दोनो सदनो हारा पारित नहीं हो जाता, उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए नहीं भेजा जा सकता है। यदि दोनों सदनों म किसी सायारण विधेयक पर समर्थ है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनो सदनो की नयुक्त सैंटक बुलवारर सथर्ष का विषटारा किया जा सकता है। सविभान के प्रतुख्देर १०८ के प्रमुत्तार यदि ससद के दोनो सदनों में किसी विवेषक में संशोधन के मक्त में समर्प है या ६ माह से अधिक दूसरे सदन में निर्देशक प्रस्तुत करने के परचान् हो चुने हैं, राष्ट्रपति उक्त विवेयक को विचार तथा मतदान करने के लिए दानो सदना नी सयुक्त बैठक में मेबेगा एवं संयुक्त बैठक में पारित त्रियेयक संसद द्वारा पारित माना जायेगा और राष्ट्रपति ने पास उसनी सहमति ने लिए मेजा जायगा। सर्विधान म सयुक्त बैठन का प्रावधान एक रक्षानली के तुन्य है, जिमसे दोनो सदन विवाद का निपटारा कर सकते हैं।

ल-राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उस पर महानियोग लगाने के लिए लोकसभा तया राज्यसमा को समान ग्रामिकार हैं।

संघीय संसद १६७

ग-संविधान के संगोधन के लिए दोनो सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। प-सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायायाँका, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक त्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदच्युन करने के सबय में दोनों सदनों को समान अधिकार है।

# राज्यसभा की वे शक्तियाँ जिनकी दृष्टि से राज्य सभा लोकसभा से कम शक्तिशाली है

क-वित सबयी यामलों के सन्दर्भ में राज्यसमा में एव लोकसमा नी गिनिनयों में समट रुप से सन्तर है। सविवान के अनुन्धेद १०६ वे अन्तर्भत वित्त विधेयक राज्यसमा में प्रस्तुन कहीं किये वा सकते हैं। वित्त विधेयक वेक्स लोकसमा में प्रस्तुन किये हों। वित्त विधेयक वेक्स लोकसमा में प्रस्तुन किये ला सकते हैं और उन्हें पारित करते ने लिए राज्यसमा की अनुमति सावस्यक नहीं है। अनुन्वर्ध २०६ के अनुसार वित्त विदेयक लोकसमा पारित करती है, उदारे परवात विविध्यक की राज्यसमा के सुम्भावों के लिए मेंना जायेगा। राज्यसमा के लिए यह आवस्यक नहीं है कि राज्यसमा के सुम्भावों को लिए यह आवस्यक नहीं है कि राज्यसमा के सुम्भावों को स्विध्यक रे। यदि लोकसमा राज्यसमा से मेंज हुए वित्त विदेयक सबयी सुमावों से सहस्य है रो विवेधक को राज्यसमा के सुमावों के सहस्य है रो विवेधक को राज्यसमा के साव्य नहीं है कि राज्यसमा जायेगा। यदि राज्यसमा हारा विधे गये सुभाव लोकसमा को मान्य नहीं है तो विवेधक को प्रस्त किया निया निर्म किया न

ल-सिविधान ने अनुसार सधीय मनीमण्डल ना सामूहिक उत्तरशायित्व केवल लोनसमा के प्रति है। राज्यसमा को मनी मण्डल ने सबस म नोई विशेष शक्तियाँ नहीं हैं। राज्यसमा मनी मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं एक सकती है और न ऐसे प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सकती है। परन्तु लोकसमा को सविधान ने प्रत्यांत यह अधिकार प्राप्त है कि मनी मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे स्थानपत्र देने के सिए बाय्य कर सकती है।

राज्यसमा एव लोलसमा भी इन असमानतामों के होने पर मी कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनने द्वारा राज्यसमा सरकार को निश्चित रुप से प्रमानित कर सनती है। वे तत्व निम्मानुसार हैं।

१-मवियान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मिनियों की नियुक्तियाँ राज्य-समा से नहीं को जाये। ब्रतएवं समय-समय पर राज्यसमा से भी मनियों की नियुन्तिन हुई है। जदाहरण स्त्रस्य प० गो० व० पन्त, जो राज्य समा ने ही सदस्य ये मत्री मण्डल में एक महत्वपूर्ण विमान के मत्री ये (मुह्मत्री)। श्रीलानदहादुत्वी हास्त्री के मत्री मण्डल से श्रीमती नागी राज्यसमा के ही सुनना एव प्रसारण विमान मत्री नियस्त नी गई थी।

२--राज्यसमा के महत्व वा बामाख इस परस्परा से मी भाग्न होता है वि केन्द्रीय मत्री प्राय राज्य सभा भे उपस्थित रहते हैं और विवार विमर्श तथा बाद-विवाद में माग लेते हैं।

उपमुक्त जिलाबित तल राज्यसमा को सरकार की नीतिमी तथा कारों पर कहन तथा जनतामिक प्रभाव हालने में मदद पहुँचाते हैं। परानु यहाँ यह ध्याल में राज्य प्राचयक होगा कि सरकार पर राज्यसमा ना प्रभाव तोचसमा नी सन्ता में बहत कम होगा।

#### भागमधा की विवेद वस्तियाँ

पाण्यसमा को सम के राज्या के प्रतिनिधि सदन होने के नाते कतिपय विशेष कतियाँ सविधान द्वारा प्राप्त हैं। ये दो प्रकार की हैं।

१—मनुष्येद २४६ के घननात यदि राज्यसमा यह प्रश्नाव बहुमत हारा पारित करती है कि किसी विषय (राज्य सूची के बल्लिरित विषय पर भी) पर ससद को राष्ट्रीय हिन में विधि निर्माण करना प्रावस्थन है को ससद उक्त विषय पर सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भू-मान या हिस्से में लिए विधि निर्माण का मनी।

२—-राज्यसमा दो तिहाई बहुमन द्वारा किसी अखिल मारवीय सेवा को स्था-पित करने का निर्णय से सकती है।

राज्य सभाकी उपयुक्त दो शक्तियो ने सन्दर्भ में ठा० एन० वी० पायली कहते हैं—'सर्वेषानिक दृष्टि से यह अत्यन्न महत्वपूर्ण हैं।''' इन दोनो विषयो के सबय में राज्यसभा और लोकसमा की शक्तियो की तुनना करते हुए यह नहते

रै बा॰ एस॰ बी॰ पायली—इन्डिया च कान्स्टीट्युशन १६६२, पृ॰ १६८।

है—"अत दोनो मामलो में लोकसमा सामने सब ही आती है, जब राज्यसमा निर्णय से चुकी है, और लोकसमा, राज्यसमा के साथ इन दोना परिस्थितियों में निर्णय सेने के लिए हिस्सेदार नहीं हैं। सिवधान से इन आवधानों द्वारा राज्यसमा को सरकारी मशीनरी के एक महत्वपूर्ण हिस्सो न कि विभूषित ढाँचे या समावयस्य सम के रूप में निर्मित किया गया है। इसका खोटा तथा फलस्वरूप ठीस, आकार इसका स्थायी स्वरूप, जिसके द्वारा इसके विचारों व कार्यों में स्थायित्वता और निरम्तरता प्रान्त होती है, और इसका विस्तृत आधार वाला प्रतिनिध स्वरूप—स्त सबके द्वारा इसके भविष्य म न केवल एक प्रनिष्ठित, परन्तु लामदायक और प्रभावतील सस्या के रूप में, परन्तु जो समा के समान शक्तिशाली नहीं होगी, स्थापित होने से सहायता मिलेगी।" भे

प्राय सभी प्रायुनिक जनतानिक राज्यों में व्यवस्थापिका के सदस्यों के स्वतन्न रूप से व्यायों की सम्यत करने की शवित पर विजय प्रावश्यक जनतानिक प्रवरीषों मा उक्लेस करते हुए मेंकग्राइवर कहते हैं नि "इनमें से एक व्यवस्थापिका के दो सदनों के रूप म है, क्योंकि अरथेक सदन को एवं दूसरे की सहमति प्रावश्यक है। बिना इसके विधि का निर्माण नहीं हो सकता है।"

मारतीय सविधान के अन्तर्गत राज्यसमा तथा लोकसमा भी सवैधानिन 
यानिनयों का प्रध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि भारतीय ससद के दोनों सदन 
प्रावयकतानुसार एक दूसरे के प्रति जनतानिक अववेषों के रूप में भूमिना 
निमा कर नास्त्व म जनता की इच्छा को जासन भी नीतिया तथा कार्यों के 
जाप में भूमिना 
निमा कर नास्त्व म जनता की इच्छा को जासन भी नीतिया तथा कार्यों में 
समन विदित होता है। इस भूमिका का महत्य सविधान में सामोग करिनार है। परनु यदि सविधान के सक्षोधन के लिए दोनों सदनों को समाम 
प्रियमर है। परनु यदि सविधान के सक्षोधन के लिए दोनों सदनों को समाम 
प्रियमर है। परनु यदि सविधान सक्षोधन विध्यक लोकसमा में जलदवाजी और 
उत्तेजना पूर्वक पारित कर दिया जाता है तो उपत्यसमा के सदस्य भप अनुमन 
तथा परियम्बत पार लाग एक चानित्यभ तथा उद्दोजनारहित बातावरण में, जो 
प्राय. राज्यसमा में पाया जाता है, उपयोग में बाते हुए, लोकसमा पर किसी 
मूल सवैधानिक विध्य के सवसे में अवरोध लगा सकते हैं। १६७० में जिस जलद 
याजी से देशी राज्यों के प्रीविधर्य विधेयक को लोकसमा ने उत्तर विध्य पर 
सविधान सभीन करने के लिए पारित किया था, राज्यसमा ने इम विधेयक को 
पादित होने से रोक दिया, क्योंकि उत्त वन्तव जनमत राजाओं के प्रीविधर के सवध 
में पूर्णकप से स्पष्ट नहीं था। मत यह स्वष्ट है कि इन विशेष वादिनमें से राज्य 
में पूर्णकप से सपट नहीं था। मत यह स्वष्ट है कि इन विशेष वादिनमें से राज्य 
में पूर्णकप से सपट नहीं था। मत यह स्वष्ट है कि इन विशेष वादिनमें से राज्य 
में प्रार्थन से सपट नहीं था। सत्त यह स्वष्ट है कि इन विशेष वादिनमें से राज्य 
में प्रार्थन से सपट नहीं सा । सत्त यह स्वष्ट है कि इन विशेष वादिनमें से राज्य 
में प्रार्थन से सपट नहीं था। सत्त सह स्वष्ट है कि इन विशेष वादिनमें से राज्य 
स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य से स्वर्य स्वर्य स्वर्य से स्वर्य स्वर्य से स्वर्य स्वर्य से स्वर्य स्वर्य से स्वर्य स्वर्य स्वर्य से स्वर्य स्वर्य से स्वर्य से स्वर्य से स्वर्य से स्वर्य से स्वर्य स्वर्य से स्वर्

१ डा॰ एम॰ वी॰ पावली—इण्डियाचकान्स्टीट्युशन पृ० १६८ ।

२. मार. मेकझाइवर-'द मार्डन स्टेट, १६२६, पु. ३०५।

तमा को विशूपित करते हुए, मारतीय सविधान निर्मानाधो ने धपनी दूरदिगता तथा बुद्धियता का परिचय दिया। हम को यह विदित्त है कि राज्यसमा भीर लाक्तमा धपने पारस्परिक सवधो में एक दूसरे के शति जनताविक धवरोय के समान तो वार्ष कर सकती है, पपनु राज्यसमा, बोक्समा के रास्ते में एक रीडे के रूप म एक्सर उचित रूप से श्रापन वार्ष को कभी मी नहीं कर सकेगी।

बारतीय जनतातिक व्यवस्था में, ससद के दोनों सदन एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी मही, बरन जनतत्र को सफल बनाने के कार्य में साझदार हैं। सतः यह धावध्यक है कि राज्यसमा लया लोकसमा पारस्परिक सथवीं का निपटारा, इस उद्देश्य को सपन समक्ष रचत हुए वरें, कि इन दोनों को जनता के इन्द्रानुसार व्यवस्थापन के नार्य, प्रान्ति पूर्वक सह अस्तित्व को भावना से प्रेरित होकर करना है। प्रीक सोरिस ओन्स का कथन है—"यह स्वस्ट है कि यदि दोनो सदन समान कार्यों को करने के इच्छ्क हैं तो शान्तिपूर्वक सह-सस्तित्व की मावना बनी रहना कठिन है। साथ ही यदि इन सबनो की भूमिका में स्पष्ट अन्तर नहीं किया गया तो इनमें प्रतिक्रन्दिता की भावना बनी रहेगी ...। प्रतिक्रन्दिना, राजनीतिक क्षमता के लिए प्रत्यन्त हानिकारक है। इसमे जनता की निवाही में समय की प्रतिष्ठा कम हो सकती है।"" कतिपय भामलों से यह यलतकहमी वैदा हो गई है कि राज्य-ही सकता है। "कावपय अपनाश च पह पत्तवक्रका पत्र है। सर्वत्रपम १६५३ सना लाकसभा के प्रतिद्वत्वी के रूप में नाय करना चाहती है। सर्वत्रपम १६५३ के बजट प्रविवेशन के दौरान दोनो सबनो म युगीर सपूर्व हुमा। स्रप्ति २६, १९५३ को राज्य समा ने जायकर (संशोधन) विधेयक पर विचार-विमर्श धारम्म भिया, जो सानसमा द्वारा पारित हो युना था। लोनसमा के अध्यक्ष द्वारा पूर्व में ही प्रसाणित कर विद्या नया था नि यह विषेपक वित्त-विद्ययक था, परन्तु राज्यसमा के कुछ सदस्यों ने भापति उठाई कि यह विषेयक वित्त-विवेयक नहीं था। विधि मत्री थी विश्वास ने, जो कि न केवल राज्यसमा के सदस्य थे, परन्त उसके नेता भी, ऐसी स्थिति में बहा- 'यदि राज्यसमा को बहा जाता है कि लोक-सना के अव्यक्ष ने इस प्रतन का पुर्णक्ष्य से प्रशिक्षण किया है और विजेयक सबची प्रमाण सदन म स्वतंत्रता पूर्वक एव निष्पक्ष रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही दिया गमा है तो राज्यसभा सन्तुष्ठ हो जायेगी। अयले दिन लाक्सभा के एक सदस्य न यह प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया कि विशि मनी का बकाव्य भौजित्यहीन या तथा अध्यक्ष भी प्रतिष्ठा के विरक्ष या । पलस्वरूप लोकसमा के अध्यक्ष ने नहा नि सदन में इस विषय पर बाद-विवाद के दौरान विवि मंत्री की उपस्यिन बाह्यनीय होगी । तत्त्वपश्चात् राज्यसभा मे एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सदन का यह यत है कि सदन के नना को निर्देश दिये जाये कि किसी भी

१. दस्तय् । एवः भोरिस जोत्म-पार्तियामेन्ट दन दरित्रात, १६५७ ए० २५३ ।

हैसियत से वह लोनसमा में उपस्थित न हो। तब लोनसमा में राज्यसमा वे प्राप्यक्ष की प्रोर से एक सदेव पढ़ा गया कि निसी मी, धौर विलेषकर, राज्यसमा के नेता की कमो मी यह इच्छा नहीं भी कि लोकसमा के प्राप्यक्ष को सदता तथा निप्पस्ता पर गना कर वीचक फिरे। इस सदन का उद्देश्य (राज्यसमा का) निप्पस्ता पर गना कर वीचक फिरे। इस सदन का उद्देश्य (राज्यसमा का) हमेशा यह रहा है कि लोकसमा के प्राप्यक्ष की प्रतिष्ठा का, धौर उस सदन के प्राप्यक्ष की प्रतिष्ठा को, धौर उस सदन के प्रयास की प्रतिष्ठा को, धौर उस सदन के प्रयास की प्रतिष्ठा को, धौर उस सदन के प्रयास की सम्मान उसी तरह में करें, जिस तरह हमारी प्रपेश है वह सदन हमारे प्रयास प्रमान करना। विधि मधी ने राज्यसमा के प्रस्ता के प्रताय के प्रति प्रपास कर की। परन्तु लोकसमा के सदस्यों ने राज्यसमा के प्रसाय के इस प्रस्ताव पर घोर प्राप्ति प्रकट की। परन्तु स्वीक्ष समा के सदस्यों ने राज्यसमा के प्रसाय के इस प्रस्ताव पर घोर प्राप्ति प्रकट की। परन्तु का सम्मा के सदस्यों ने राज्यसमा के प्रसाय के प्रताय पर घोर आपत्ति प्रवट की। परने का स्वीक्ष समी के साम माने की प्रयास माने के लीवसमा को प्रयोग करने पर दोनो सदनो म सपर्य समाप्त हुआ।

राज्यसमा तथा लोबसमा में सवर्षे बा दूसरा महत्वपूर्ण मामला, राज्यसमा के कुछ सदस्यो की, राज्यसमा के लिए अपनी प्राक्तस्तन तथा लीरलेखा समितियो की माग सं प्रारम्म हुमा था। उनकी माग थी वि राज्यसमा वे प्रति-निधियों को लोकसमा भी प्राप्तनलन तथा लोकसेखा समितियों में रहा जाये। जनवरी, १६४३ म राज्यसमा ने इस विषय पर एक संयुक्त समिति स्थापित करने के लिए सुफाव लोकसमा को मेजे गय । साय ही यह मी सुफाव दिया गया कि चूँकि लोकसमा की लोकलेखा समिति मे १५ सदस्य तो थे ही समिति में राज्यसमा के, प्रतिनिधियों को और सम्मिलित कर लिया जाये। तत्पश्चात् यह मामला लोवसमा की नियम समिति की प्रेपिन क्या, जिसके समक्ष पहले ही ही लोकलेखा समिति ना प्रस्तान या कि समुक्त समिति, या राज्यसमा ने लिए एक पृथक समिति का गठन करना सविधान में निहित सिद्धान्तों के विरूद होगा। लोग्लेखा समिति वे उपर्युवत प्रस्ताव में इसी बात पर बल दिया गया कि लोग समा के अध्यक्ष को सदन एव लोक्लेखा समिति के अधिकारी का सरक्षण करने के लिए बुछ कदम उठाना तथा राज्यसमाको सुचित करना, ग्रावश्यक है कि उसर सुकाव अवैधानिक है क्योंकि यह लोकसमा के विता सबधी मामलो के क्षेत्र म, जिसम लोव समा नो सर्वाधिकार है, हस्तक्षेप होया। लोक्समा की नियम समिति द्वारा उपर्युक्त बात की पुष्टि की गई। लोक समा की नियम समिति ने यह भी वहा वि वित्त क्षेत्र म लोनसमा का विशेष उत्तरदायित्व है, जिसम यह अन्य किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकती है। अन्त में प्रधान सन्ती ने लोक्समा मे प्रस्तावित विया कि राज्यसमा को लोक्सेखा समिति पर सात सदस्य मनोनीत करने की अनुमति दी जाये । प्रधान मत्री ने लोकसमा को सबो-थित नरते हुए वहा वि इस मामले म लोरसमा की लोकलेखा समिति ना डर वि राज्यसभा वे ग्रधिवारो वा विषटन होगा, आधार रहित है। परिणाम स्वका दिसम्बर, १९४३ ये उपपूर्ण प्रस्तान स्वीकृत हो नावा थीर राज्यसमा में मृतितिनिध्यों को नई लोकलेखा समिति में सम्मितित वर स्वया गया। राज्यसमा सौर लोकस्या के गण्य सपर्य का तीवरा यहत्वपुर्ण सामला १९४५ में हुता। श्री एन० सी० घटकीं, हिन्दू महासमा के लोकसमा में नेता, ने एक मामण के दौरान यह कहा था कि सवद का उच्च सदन जो वास्त्य में बीटा, ठोगों का सदन होना पाहिये, उसके सदस्य अच्छों को सद्दू सामवद्यीन व्यत्तार कर रहे हैं। राज्यसमा के प्राप्यत ने सनिव को इत मामले ने सवध में सारी जानकारी हांगित करते को बहा। राज्यसा में सविव के यी एन० सी० कटकों को पत्र सौनों सदनी की सिक्तार समितियों ने समुद्ध बैजन में कुछ नियमों का निर्मारण किया, जिनके प्रमत्त्रीत किसी भी सदन के सदस्य हारा दूसरे सवन के प्रांतिकारी के उल्लावन के मामले का उचित कथ से नियारण विद्या सा सके ।

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक राज्यसमा तथा लोक समा के सम्बन्ध का प्रथम है, भूल धावश्यकता यह है कि दोनो सदन प्रतिस्पर्धों की मावना स्वागकर सविवान डारा निर्धारित दांधरे में एक इसरे के प्रति सहयोग तथा सामजस्य की भावना के अनुसार अपने कार्य करें। प्रत्येक सदन को, सविधान द्वारा निर्धारित सीमाओ तथा सिद्धान्तो को ध्यान से रखते हुए अपने दायित्वो को उचित रूप से निमाना चाहिये। ऋतः राज्यसमा की जो मी मूमिका सविधान के धन्तर्गत दाली जायेगी, वह किसी स्थिति में लोकसमा के, जो कि जनता का सदन है, प्रविकारों स्था बायरनों के निरुद्ध नहीं हो सकती है। राज्यसमा, जैसा सर सिडनी नो ने ब्रिटिश लार्ड समा ने लिए नहा है—'राजनीति को साघारण धक्रमार्गसे निमाल कर उन मूल सिद्धान्तो तथा दूर ने परिणामो पर ध्यान दें जिनके लिए एक व्यक्त जनसभा और दलीय कार्यपालिका की न ती समय, न विचार है।" पाज्यसमा मे वाद-विचाद के स्तर पर टिप्पणी देते हुए, 'मोह्नर सीज स्टेटमेन', ४ सितम्बर १९५४ के राजनीतिन सम्वाददाता ने महा वि राज्य-समा के पिछले सप्ताह के विदेशी भागली सम्बन्धी वाद-विश्वाद में विपुलता की भलक पाई जाती है, जी दूसरे सदन के लिए एक उपयोगी बादमें हो सकती है। सक्षेप में, जिन विषयों के लिए लोकसमा तथा राज्यसभा को समान घषि-कार है, उनमे राज्यसमा लोकसमा से समान अधिकार की माप कर सकती है, परन्त जिन विषयो के सम्बन्ध में सविधान द्वारा राज्यसमा को लोकसमा की भपेक्षा सीमित शक्तियाँ प्रवत्त की गई हैं या कोई शक्तियाँ नहीं दी गई हैं उनके सम्बन्ध मे राज्यसमा को लोक्समा के साथ प्रतिस्पर्धा करना अनुचित होगा।

१ सिडनी० सो-'द गर्वनेन्स माफ इंग्लंब्ड, १६३१ वृत २५० ।

そひろ

जनतत्र में निम्न सदन, उच्च सदन वी घपेशा चाकिशाती होता है घोर उच्च सदन के घस्तित्व का घोषित्य केवल इसी बात में है जि वह निम्न गदन पर विवेत पूर्ण प्रमाव डाले। घदि राज्यसमा जो इस सूल बात वा घहुसास हो जाता है तो मविष्य में दोनो सदो के मध्य सपर्य की स्थित बहु। बम पैदा होगी।

# सघ ससद की शक्तियाँ

भारतीय सतद की शक्तियों का क्षेत्र संघीय निधित सविधान द्वारा सीमिन है। ससद द्वारा निर्मित कानुना का न्याधिक पुनरावसोकन सर्वोच्छ न्यामालय द्वारा शानन की देशता या प्रवेधता निर्धारित वरने के लिए विया जा सवता है। संयापि तुसनारमक दृष्टि से भारतीय संयीय संसद की शक्तियाँ ग्रम्य संधीय व्यवस्थापिकाची की चपेक्षा अधिव है। अमरीवी वाग्रेस तथा आस्ट्रेलियन ससद राज्य सम्बन्धी विषयो पर वानुन निर्माण नहीं बर सवती हैं। परेन्तु मारतीय ससद को नितियय परिस्थितियों में राज्यों ने लिए नागुन निर्माण राने ना अधिनार है। उदाहरणार्थ, अनु-द्रेद २५३ ने बन्तर्गत निसी सिध या समझौते यो लागू बरने के लिए सप्तद बानून निर्माण कर सबती है, प्रनुच्छेद २५० वे प्रस्तर्गेर सकटवालीन स्थिति मे सप्तद सम्पूर्णदेश वे लिए कानून वा निर्माण गर सकती है। सविधार म मारतीय ससद री शक्तियों का उल्लेख किसी एक प्रध्याय में नहीं विया गया है। सरिधान ने भाग पाँच क अध्याय तीन म जिसमें ससद के सगठन, प्रधिवारियो, सदस्यो की श्रयोग्यताएँ व्यवस्थापन तथा वित्त प्रश्रियाए उल्लिखित हैं, ससद की सारी प्रक्तियो एव कार्यों का उल्केख नहीं है। इन सारी प्रक्तियों को सविधान के विभिन्न हिस्सो के अध्ययन द्वारा ही मालम विया जा सकता है। चूंबि मारत में ससदीय प्रणाली स्थापित भी गई है, अत यह सरलता पूर्वं पहा जा सकता है कि मारतीय ससद के कार्य, उन देशों की ससद के तुल्य हैं. जहाँ ससदीय प्रणाली प्रचलित है।

भारतीय ससद की शक्तियाँ तथा कार्यों का, निम्नलिखित विभिन्न श्रीणयो श रख कर, प्रध्ययन विया जा सकता है।

१—व्यवस्थापन, २—कायपालिका वा ाधननण, ३—न्यायपालिका से सर्वाधित प्रक्तियाँ, ४—वित्त सम्बन्धी शत्तियाँ और १—प्रन्य प्रक्तियाँ।

स्वयस्थापन सम्बन्धी वास्तियाँ—सविवान के अनुम्बेद २४४ (१) वे स्तुसार समह, सवियान के प्रावधाना के प्रावधान सम्पूर्ण मारत या इसके किसी भी हिस्से के लिए, तथा राज्य विधान समा सम्पूर्ण राज्य या इसके किसी भी हिस्से के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। इसी तरह अनुस्केद २४६ (१) के अनुसार समद को सवियान की सातवी अनुसूची से उल्लिखित प्रथम सूची (सय सूची) मे उल्लिखित विषयो पर कानून निर्माण का अधिवार है। १७४

ग्रनुन्धेद २४६ (२) के अनुसार ससद को सविधान की सातवीं प्रनुसूची मे उल्लिखिन तीसरी सूची (समवर्ती सूची) मे उल्लिखित विषयो पर विधि का निर्माण करने का अधिकार है। अनुब्धेन २४६ (३) के अनुसार किसी भी राज्य की विधान समा को राज्य या राज्य के किया मी हिस्से के लिए, सविधान की शातवी प्रमुखी म उल्लिखिन, दूसरी मूनी (राज्य मूनी) मे उल्लिखन विषयो पर विधि वा निर्माण बरन का ग्रविकार है।

सक्षेप मे, मारनीय सविवान द्वारा तीन व्यवस्थापन सम्बन्धी सुचियी का निर्धारण किया गया है, जिनका उल्लेख सविधान की सातवी अनुसूची में है।

(क) सपमुची-जिसमें ६७ विषय हैं. जिन पर केवल सच संसद विधि निर्माण कर सकती है।

(ल) राज्य मुनी-जिसमे ६६ विषय हैं, जिन पर साधारणतया, नेवल राज्य

विवास समा ही विवि का निर्माण कर सकती है । भौर. (ग) समदर्ती सधी-जिसमे ४७ विषय हैं, जिन घर दोनो, ससद तथा राज्य

विधान समा को विधि निर्माण करने का समिकार है। सनुरुद्धेद २४४ (१) के चनुसार यदि राज्य विधान समा बारा निर्मित किसी विधि का, किसी प्रावयान भा, सप ससद द्वारा निर्मित विधि के क्सी प्रावधान से सथयें होता है तो सधीय विधि मान्य होगी और जिस हद तक राज्य निधि का सथर सधीय विधि से है, उस हद तर राज्य विधि को भवैध माना जायेगा । परन्त भनुक्छेद २५४ (२) के पनसार मदि समवर्ती सची में उत्सिक्षित विषय पर निमित किसी राज्य विवि का सपर्य, सभीय ससद द्वारा उसी निषय पर निर्मित विधि से है, धीर ऐसी राज्य विधि को राष्ट्रपति द्वारा सहसति प्राप्त हो गई है तो राज्य विधि को ही सान्यता प्राप्त होगी, परन्त साथ ही उक्त विधय पर निमित राज्य विधि में जोड़ने. सशोवन, परिवर्तन या उसे समाप्त नरने हेतु विधि पारित नरने का प्रविकार समद से जिलित है।

सविधान के ग्रानुक्देद २४६ (१) के बनसार उपरोक्त तीन सचियो द्वारा शक्ति के विभाजन के परवात अवशिष्ट शक्तियाँ सुध संसद से ही निहित है।

निम्नलिखित कुछ विशेष परिस्थितियो में सम ससद राज्य सबी सम्बन्धित

विषयो पर दिधि निर्माण कर सक्की है। क-जिंद राज्य समा द्वारा दो-तिहाई बहमत के बाबार पर प्रतस्टेट २४६

के ग्रनसार प्रमाणित कर दिया है कि राज्य सबी में उल्लिखित किसी विषय का महत्व राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, परन्तु राज्यसमा का प्रस्ताव एक वर्ष से ग्रधिक समय तक नहीं रह संबता है।

स-अनुच्छेद २१० (१) के अन्तर्गत सघ ससद सम्पूर्ण देश या उसके विसीध दिस्ति ने निराद प्रकारतातील विषयि में बातन बाद सकती है ५

ग—म्रनुच्द्रेद २५२ (१) के घनुसार यदि दो या दो से घिषिक राज्य की विधान समामों को वाधनीय है कि उनने सम्बन्ध में, सम ससद राज्य सूची में उन्तिरिदत किसी विषय पर विधि वा निर्माण करें। ससद की उन राज्यों के लिए घोर मिष्टप में ऐसे राज्यों के लिए मी जिनकी विधान समामों में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित निर्मे यत है, विधि निर्माण करने वा धिकार होगा।

मारतीय सविधान ने अन्तर्गत मिक ने विभाजन की विधिष्ट प्रत्रिया अपनाने ने फ्लस्बरूप यह स्पष्ट है नि ससद को अत्यधिक कत्तियाँ आप्त हुई हैं। सविधान ने अनुब्देद २४६, २४६, २४६, २४०, २४१, २४२, तथा २४३, सधीय सिद्धान्त ने वावजूद मी, भारतीय सधीय व्यवस्था ने अन्तर्गत सथ ससद को एक शक्तियाली सस्या बनाने मे सहायन हुए हैं, जिससे राष्ट्र की युनियादी एकता के ढीचे को स्थायी रहा जा सने।

ससद मी व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियों की काल ससद म विधि निर्माण प्रक्रिया में प्रतिनिम्लित होती हैं। सविधान में बिधि निर्माण प्रक्रिया के सन्द्रम्य म कोई विस्तृत उल्लेख नहीं हैं। साधारण विधेषणों को (किस विधेषणों को छोड़ कर) ससद के किसी भी सदन में प्रसृत किया जा सबता है। और एक विधेषण को सद होरा पारित तभी माना जायेगा, जन विधेषण बोनों सदनों म पारित हो चुका है। ससद के किसी भी सदन के समक्ष विचार के लिए विधेषण ससद के क्यांगा होते हों है। ससद के किसी भी सदन के समक्ष विचार के लिए विधेषण ससद के क्यांगा। होन समा के विध्यन से उसके समक्ष जो विधेषण है, या जो उससे पारित होकर राज्यसमा को गया है, समाप्त हो जायेगा। परन्तु ऐसा विधेयन निसकों उपयोग राज्यसमा के विध्यन से समाप्त नहीं होगा। यदि लोकसमा के विचयन से सूर्व राज्यसमा के विध्यन से स्वाप्त से सूर्व राज्यसमा के विध्यन से स्वाप्त होता। यदि लोकसमा के विचयन के सूर्व राज्यसमा के हिस्त तो वियेषण की बैठक बुताई गई है हो विगयन समाप्त नहीं होगा। यदि लोकसमा के विचयन तही होगा।

ससद द्वारा विधि निर्माण करने के लिए सविधान में नेवल उपर्युक्त वातो वा ही उस्तेण है। निर्माण प्रिक्ता के प्रत्यानेन अन्य वातो वो ससद ने नियमों के प्रत्यार निर्पारित विधा गया है। इन नियमों के प्रत्यार निर्पारित विधा गया है। कि नियमों के प्रत्यार निर्पारित विधा गया है। वदन म प्रत्येन विध्येय सान विधि निर्माण प्रत्याय का निर्यारण विध्येय ने तीन वाचन होने चाहिये। साधारण विध्येय ने तीन वाचन होने चाहिये। साधारण विध्येय करने में मस्तुत निया जा सकना है। मनी द्वारा प्रस्तुत साधारण विध्येय सरनार्थी विध्येय ने विधा प्रत्यार विध्येय ने सरनार्थी विध्येय ने विधा प्रत्यार विध्येय ने निर्धि ना स्पारण वरने ने निर्णाय चरने के लिए पाव चरनों को पार चरना होता।

प्रथम बाबन—सदन में रिपेयन का प्रस्तुतीन रण ही प्रथम चरण (स्तर) है। सदन के सर्विदालय नो विषेयन भी एक प्रति सुपुर्द करना होना है। सत्प्रचात श्राच्यक्ष द्वारा विषेवक को किसी निक्क्ति निधि की कार्यवाही की मुची में एत दिया जाता है। उस तिथि को प्रस्तावक अपनी जगह खडे होकर उस विधेयक को सदन म प्रस्तत करन की ग्राज्ञा मागता है। इस पर ग्राध्यक्ष खडे होकर कहना

है नि विधियन मो प्रस्तत निया गया है। साम्नव में विधियन भा प्रस्त्नीन रण एक ग्रीपचारिकता भान है। प्राय परम्परानुमार इस स्तर पर विवेषक के सर्वय म कोई बाद विवाद नहीं होता है। परन्त पूर्व म, कुछ परिस्थितिया में इस स्तर पर विशेवक का विराध क्या गया है। यदि विशेयक का विरोध सर्वधानिक द्याधार पर क्या गया है सो अध्यक्ष बाद-विवाद के लिए धनमति दे सकता है !

विवेपन के प्रस्ततीकरण के पश्चात, उसका प्रकाशन सारनीय गजट में कर दिया जाता है। दितीय बावन-विधेयक के प्रस्तुतीकरण के दो दिन पश्चान ही दितीय वाचन प्रारम्म होता है। यदि अध्यक्ष नी राथ में विषेत्रक ना घत्यधिक महत्व है, तो

प्रस्तिवरण के तरन्त वाद, द्वितीय वाचन प्रारम्भ किया जा भक्ता है । द्वितीय बाचन के दौरान विज्ञेयक सवधी प्राप्त जानकारी तथा सुभाव के सक्षित रूप

महत हे सदस्यों के जपयोग के लिए वितरित किये जाते हैं। यदि धान्यक्ष धनमति देता है तो उस विधेयन पर बाद विवाद हो। सनता है, परन्त यह विस्तृत रूप से नहीं होता है। मह अर्चा नेवल विधेयक के मुल निद्धाली, मुख्य उपवन्धी तक श्री सीमित एती है। प्रस्तावक सदस्य वियेवक को प्रवर समिति मा दोनी सदनी की सपकन समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव कर सकता है। क-समिति स्तर-नारतीय ससद मे नेवल महत्वपूर्ण तथा जटिल विघेषको

की समिति के पास मेजा जाता है । प्रवर समिति के सदस्यों की सहया २० से ३० तक होती है। प्रवर समिति य सत्तास्त्र तथा विपन्नी दली में सदस्य होते हैं। प्राय सतारादल ने सदस्यानी सस्या श्रधिक होती है। समिति मे विजेयक पर गहराई से विचार-विभर्ध होता है। विधेयक के उपवन्धों में संगोधन भी लाय जा मरत है। यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या कागजान की भाव-म्कता होती है तो प्रवर समिति इसकी भाग करती है। अनता या प्रेस प्रतिनिधि अँटको में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अन्त स समिति अपना प्रतिवेदन सदन को भेजती है, जो प्रकाणित किया जाता है।

स-प्रतिवेदन स्तर-जैसा देखा जा चना है, समिति को विवेयक के सबय में अपना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है। सामारणनया प्रतिवेदन की तीन माह के अन्दर भेजना सावश्यक है, परन्त यदि सदन द्वारा कोई समयावीय निर्धारित कर दी गई है तो समिति को उसके अन्दर ही प्रतिवेदन देना होगा । प्रतिवेदन पर समिति के प्रध्यक्ष में इस्ताक्षर होना प्रावश्यक है । पतिनेन्द्र स्तर के तौरान

विधेयक पर गहराई से बाद विवाद होते हैं। विधेयक के प्रत्येक माग पर बाद-विवाद होता है तथा सकोधन प्रस्तृत विये जा सकते हैं। बाद विवाद के पश्चात् विधेया ने प्रत्येक मान और संशोधन पर सतदान होता है। यह मत से विधेयक तथा उसमे विमिष्ट संशोधनो ने स्वीवृत होने पर, विधेयन सदन में विधि-निर्माण-प्रक्रिया थे ग्रन्तिम चरण पर पहुँचता है।

तृतीय याचन-सदन में विधेया पर तृतीय वाचन, उसना अतिम चरण है। इस ग्रन्तिम चरण म विधेयण वे सत्रथ म यह प्रस्तावित विया जाता है वि उसे पारित विया जाये। इस समय विधेयक पर गहराई से विचार विमर्श नही किया जाता है। पर-तु विधेयक के पक्ष या विपक्ष म तक प्रस्तुत किये जाते हैं, सथापि इस स्तर मे लम्बे भाषण नहीं होते हैं। यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विधेयक पारित हो जाता हैं तो उसे सदन द्वारा परित माना जायेगा। भन्त मे विधेयक को इसरे सदन में मेजने के पूर्व सदन के प्रध्यक्ष या सचिय द्वारा विधेयक मा प्रमाणीयरण होना भावण्यय है।

इसरे सदन में भी उसी प्रकार की विधि-निर्माण प्रक्रिया का अनुसरण होगा, जिस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग पहले सदन में किया क्या था। दूसरे सदन के समक्ष दो विकल्प हैं। प्रथम, विधेयन को उसी रूप में पारित करना जिस रूप मे मह पहले से उसके समक्ष काया था। द्वितीय विकल्प विषेयक में सशोपन करना है। ऐसी स्थिति में विशेषक पुन पहले के सदन के समक्ष मेजा जायेगा। यदि दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित सन्नोधन के फलस्वरूप दोनों सदनों में मतमेद उमरते हैं तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति दोनो सदनो वा सबुक्त श्रधिवेशन श्रामत्रित वरेगा, जिसवा समापति लोग समा वा अध्यक्ष होगा। इस अनार की संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत द्वारा ही विधेयव पारित विया जा सकता है। स्पष्ट है वि लोव समा के सदस्यों की संख्या राज्यसमा के सदस्यों के लगमग दुगुनी होने के कारण, लोक समाकामत ही श्रन्तिम होगा।

दोनो सदनो द्वारा पारित होने ने पश्चात्, विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीवृति में लिए मेजा जाता है। राष्ट्रपति ने समक्ष दो विकल्प है। पहला यह उस विषेगक को स्वीकृति प्रदान कर दे जिसके फलस्वरूप विषेयक विषि के रूप में प्रागी-कृत हो जाता है। द्वितीय राष्ट्रपति अपने सुम्प्रावी सहित, विषेयक को ससद के पुनविचार ने लिए सौटा सनता है, परन्तु ऐसी स्थिति मे, यदि विधेयन ससद द्वारा पुन पारित विया जाता है, तो राष्ट्रपति वे सुफाव सहित या बिना उन सुफावो में पारित मरना होगा। ऐसे विघेषकों मो राष्ट्रपति धनुमति देने में लिए बाध्य होगा । राष्ट्रपति की स्वीट्टित से विवेधक, विवि मे परिवर्तित हो जायेगा । साधारण-सदस्य-विधेषक (प्रायब्हेट मेम्बर्स विल) सत्रधी विधि निर्माण प्रत्रिया

भीर उपरोक्त उस्तिखित सरकारी साधारण विधेयक विधि निर्माण मे थोडा-सा ही

प्रनत् है। साधारण-प्रस्त-वियेवक को साधारण-वियेवक समित (प्रायल्हेट विये-यक समिति) के पास में बा बाता है। १९५३ में इस समिति को स्वाधित किया यात्रा मा । इस समिति में भ्रम्यस सितृत ११ सरस्य होते हैं। समिति के भ्रम्यस को सदन के प्रयक्त मनेनित करते हैं। समिति के प्रतिवेदन की प्रतियों को सरम के सदस्यों को विविद्ध किया जाता है। यही वियेवक का सदन में भ्रोप्तापित प्रस्तुनिकरण है। इसके बाद वियेवक को पारित करने के तिए उद्योग में प्रत्या जाता है, जो करनाची सावाण (ध्रमितीय) वियेवकी के लिए उपयोग में सावा जाता है, जो करनाची सावाण (ध्रमितीय) वियेवकी के लिए प्रस्तुनकर्ता को सरकादी सरस्यो के सहस्योग की मिरन्तर प्रावस्यक्त करते हैं। उनके तहस्योग के स्वास सावाण-प्रस्तव वियेवक (बायल्हेट मैम्बर्स विव) के पारित होने के करना यी मही की जा सकसी है।

## कार्यपालिका को नियन्त्रण करने सबधी शक्तियाँ

सत्तद की कार्यपालिका सबबी वालियों के मुख्यत तीन खोत हैं, जिनके झापार पर सत्तद कार्यपालिका का नियन्त्रण करने में समर्थ है। सर्वप्रयम, सनुष्येद १६ के भन्तर्गत सत्तद के निवांचित सदस्य, राष्ट्रपति के

सवस्य, स्राप्त्यत रहे क अत्याधा सत्यक । गवावाचा सदस्य, राष्ट्रपात क निर्वाचन के लिए निर्वाचन सस्या का एक हिस्सा है। बारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ब्राप्तुच्येद ६६ के ब्रान्यगंत, सस्य के निर्वाचिन सदस्य निर्वाचन-सस्या के सहस्य होते हैं।

हिनीय, ससर की एक भग्य, परन्तु सक्रियात्मक तथा प्रमावपूर्ण शक्ति का जल्लेख सिक्यान के भनुकोद ६१ में किया थया है, दिसके धनुकार ससद राष्ट्र-पित की सिक्यान का उल्लेशन करने के लिए महामियीय लगाकर प्रच्युत कर करती है। उपराद्युपति को भी ससद इसी कारण से महासियीय स्थापन्युत कर सस्ती है।

कर सकता हूं।

पूर्तीय, कार्यपालिका को नियम्तित करने की दृष्टि से, सतद को सबसे व्यक्ति

मृहरादूर्ण शनित संधीय मनीमण्डल के सवस में है। अनु-चेद पर (३) के

मन्तर्गत संधीय मनीमण्डल का सामृद्धिक कर से उत्तरस्वाधित सबस के निवर्त्त

सदर नोकसाम के प्रति है। समीमण्डल के सिक्क विकास प्रतिस्ता पारित

बर, नोकसाम उसे स्थान पत्र देने के निष्याध्य कर सन्ती है। इसी तस्ह

सोवसाम मनी मण्डल हाम प्रतावित बबर को भी पारित करने से इन्तार

कर तत्त्वी है निवर्त्त पत्रवस्तालर, मत्री मण्डल को अपना पारित करने से इन्तार

होगा। सविधान के सनु-चेद पर्ध (३) मे, वास्तव म, नह माधारमूत तिद्धान्त

निहित्त है, निवर्त्त भवत्वाव स्त्रवस्ता में कार्योग सरस्य है। इस

किद्यान के सामृत्य पत्रवी मण्डल सोनसाम के अपने सम्मत्ती

सप्तदीप प्रणाली में, अन्नीमण्डल की स्वामी है। सनीमण्डल के लोकसमा वे प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को विभिन्न प्रकार से वार्यान्वित किया जाता है, जैसे मत्रियों से सदन म प्रका पूछ कर, स्थवन प्रस्ताव रसकर, इत्यादि ।

सरकार वे तीनो ध्रमो पर विशिष्ट जनतात्रिक धवरोयो वी आवश्यकता वे सिद्धान्त के ध्रनुसार प्रत्येक ध्रम के सबस मं जनतात्रिक धवरोयो वे रूप में कुछ मित्तयो उपलब्ध होनी चाहिये जिनसे सरकार वे तीन ध्रमो वे पारक्षिण सबयो वा निर्मारण जनतात्रिक ध्राधार पर विया जा सके। मारतीय स्विधान निर्मातात्रों ने इस सिद्धान्त का ध्रमुक्चण करते हुए सच ससर वो ग्यायपालिका वे सबय म हुछ प्रतिनयों प्रस्त वो हैं धीर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सबस भे कुछ प्रविवयों ऐसी टी हैं जो ग्यायिक शक्तियों के रूप म हैं। वे निम्नावित हैं।

(क) सविधान के अनुच्छेद १२४ व धनुसार सर्वोच्च व्यायालय में एक पुरुष-त्यायाधीश तथा सात अव्य व्यायाधीश होंगे। परन्तु ससद को न्यायाधीशो की सस्या मे वृद्धि करने ना आंध्वार है। अत, ससद ने सर्वोच्च न्यायालय मिपितम ११५५ पारित कर न्यायाधीशो की सस्या, मुख्य न्यायाधीश की निसाकर, ११ नियरित कर दो है। न्यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति वस्ता है।

श्यायाधीशों नो पदच्युत करने अ ससद की भूमिना महत्वपूर्य है। विसी
न्यायाधीश को पदच्युत राष्ट्रपति के आदेशानुसार ऐसी स्थिति में ही विधा जा
सकेगा, जब सकद का प्रायेक सदन न्यायाधील नो उपके दुव्यंनहार या प्रतासता
के नारण पदच्युत करने ने लिए सदन की सारी सदस्यता के बहुमत से एक मताय
परित वर दता है। ससद नो अधिकार है कि न्यायाधील ने दुव्यंनहार या प्रतमता को सावित वरने के लिए कोई विधिष्ट प्रतिया का निर्पारण नरे। यहाँ पर
ससद की भूमिना ने दो पद्यो पर बन देना आवश्यन है। सर्वप्रयम, बिना ससद
ने प्रताब पारित किये हुए, राष्ट्रपति न्येच्छानुसार विसी भी न्यायाधील नो पदक्युत नहीं वर मतना है। द्वितीय, ससद नी यह बनित न्यायाधीया ने प्रतुत्तरदायी
व्यवहार की रोकने ने लिए एक प्रनावशील जनतानिक प्रवरोष ने सदस है।

(त) ससद को सर्वोच्च ग्यायालय के क्षेत्राधिकार से, अनुच्छेद १३६ के अनु-सार, बृद्धि करने वा अधिकार है। ससद सर्वोच्च न्यायालय को, सधीय अूची मे उत्तिबंदित किसी भी विषय ने सबय से अतिरिक्त क्षेत्राधिकार विधि द्वारा प्रदत कर सकती है।

यदि मारत सरनार और निसी राज्य सरकार के मध्य सर्वोच्च न्यायालय को निसी विषय के सवस में मितिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदत्त करने वे लिए समक्रौता हुमा है ग्रीर ससद कानून द्वारा अपनी सहमित देती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को उक्त विषय पर क्षेत्राधिकार होगा । अनुच्छेद १३१ के अनुसार ससद सर्वोच्च न्यायालय को, उन उहेल्यों के प्रलावा जो धनु-खेंद्र २२ (२) में विणत है, बन्दी प्रताक्षीकरण, परमादेश प्रतिपंत, उत्तेषण क्षोद ध्यिवनर-पुन्छा धार्रिक लेत, लागू करने वा प्रशितकर प्रदान पर पर पर हम होने है। धन तो, बनुन्देद १९० के प्रतानीत विदि सतद प्रावश्यक या वाश्त्रीय समझती है तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे श्रतिश्वत प्रविवश्य, जो सर्विवश्यक के अनुकृत है, अपने कार्यों को अन्यवपूर्वक वरतों के लिए एनत करेगी।

(ग) राष्ट्रपति पर सनिवान का उल्लयन करने ने लिए महामियोग लगाकर, उसे परप्युत्त करने की जातित सबद नो एक प्रकार की न्यापिक शक्ति है। राप्ट्रपति पर महामियोग चलाने ने लिए सबद के किसी भी सबद इत्तर धारोज प्रमृत्त निये जा सकते हैं। बारोप लयाने के लिए सबद के एक चौथाई सबस्यों के हुस्ताकर सौर १४ दिवस पूर्व नो लिखिल जूचना होना भी प्रावश्यक है। इसके सतिरफ्त, प्रसाब की सहय नी सारी सबस्यता के यो-जिहाई बहुमत से पारित किया आगा चाहिये।

जब धारीप का प्रस्ताव ससद के एक सदन द्वारा पारित हो जाता है सब दूसरा सदन झारीनो की जाच करेगा। राप्ट्रपति को ऐसी स्थिति मे उपस्थित होने हुस्तर स्वत आराश का जाय करणा। राष्ट्रिया का पूथा स्वत्यात में उतास्यत होत मा स्वता प्रतिसिक्त करवा के पूर्ण सरिवार है। शर्थि हुसरे उसन हारों सारोदों के जांच के फलस्वरूप स्वत्य को सारोदों से स्वत्य को बो-तिहाई बहुनत हारा प्रस्ताव पारित दिया जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध सारोद सही है तो प्रस्ताव के पारित विशे जाने के समय से राष्ट्रपति को पर्वज्युत समम जावेगा। राष्ट्रपति को प्रहानिकों में समय कर पड़्युति को प्रहानिकों में समय कर पड़्युति को प्रहानिकों सारोद की प्रदान के स्वत्य कराये हो स्वत्य का स्वत्य के स्वत का ब्यान एक गभीर नृटिकी कोर नहीं धार्त्यत हुआ। इस कारण कतिपय परिस्थितियों में चाप्ट्रपति पर शसद का उपर्युक्त अवरोय प्रभावहोन हो सकता है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तव ही समव है जब ससद की बैठक हो रही है, यदि ससद की बैटक नहीं हो रही है और राष्ट्रपति ऐसे समय सिष्रमान का उल्लंघन करता है तो यह स्वामाविक है कि अपने ऊपर महामियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति ससद की बैठक कदापि नहीं बुलायेगा। प्रमुच्छेद ८४ (१) के अनुसार ससद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। अत यह अत्या-वश्यक है कि इस भदर्भ म सविधान था उचित समोधन किया जाये । अनस्टेट = ५ (१) ना संशोधन वर संसद ना ग्राहत वरने के लिए न केवल एक उचित प्रणाली को प्रपताया जा सकता है, परन्तु कार्यपालिका पर ससद के एक जीवन विहीन सबरोध को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। प्रो० टी० के टोपे का सुमाव है, "तथापि, एक वैधानिक उपबार, सनिधान संशोधन करके और प्रावधान करके कि समद ना अधिवेशन, वर्ष में एक निश्चित दिन स्वत आहत हो, रखा जा

सकता है। यह धमरोनी सविधान में निया गया है। समवत तोर समा वे प्रव्यक्ष को सप्तर ने दोनो सदनों नो ब्राहुन करते ने लिए प्रधिष्टन किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति सप्तर को बैठक को, प्रव्यक्ष की प्रार्थना करने पर भी नहीं कनाता है।"

विसीय शक्तियो-सविचान के सन्तर्गत देश की विक्त व्यवस्था पर ससद का पूर्ण प्रविचार है। जननानिक राज्य स विना व्यवस्था समा (समद) की समुस्ति के कोई कर नहीं सगाया जा सक्या। सारत स समद द्वारा दिस व्यवस्था पर नियन्त्रण, ब्रिटिश ससद के उस देश की विका व्यवस्था पर नियन्त्रण, ब्रिटिश ससद के उस देश की विका व्यवस्था पर नियन्त्रण के सहस्य

सर एरस्तीन मय ससद द्वारा ब्रिटिस बित ध्यवन्या व नियन्त्रण के भिद्धान्त का उल्लेख इस सरह करते हैं— "ब्रिटिस बाउन को मित्रयों की सताह में अनुमार कार्यपालिका अधिन होने के नाते, देश की आध्य और लीरसेवाओं पर ध्यय का प्रवण्य करते का उत्तरशिद्ध हैं। अस आउन सर्वप्रथम, कामन्स सभा को सरकार की नित सबधी आवश्यवत्यों को बूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदत्त करता है। इस तरह आजन हारा वित्त की माग की जाती है और वामन्स समा प्रथमी सहसनि प्रदत्त करती है।"

निर्दिश परम्परा ने अनुकृत सारत में, समद नो नार्यपानिका नी वित्त सम्बी माना नो न्वीकृत नरन ना अधिकार है। समियान के प्रत्यान मत्र्येन वित्तीय वर्ष राज्यित समद ने समझ, नायिक निर्दाय अनुमान प्रम्तुत नरवायेगा, निरुम सच सरकार ने वित्तीय वर्ष ने निष्ठ प्रत्यानिक साय-व्यय ना उन्नेय होता है। व्यय नो दो वर्षों म रक्षा जा सकता है।

(न) मारत नी सचिन निधि में प्रदेशिन व्यय, और (ख) ग्रन्य व्यय । मारत की मधिन निधि में निम्नलिक्षिन विषयो संप्रधी व्यय ना उन्लेप हैं :---

१--राष्ट्रपति पद वे वित्तीय लाम, मत्ते, तथा व्यय ।

२--लोन समा ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राज्यसमा ने समापित तथा उप समापित ने नेनन तथा मरो।

३.—मारतीय सरकार वे ऋण तका उतका व्याज, निषेत्र निथि व्यय, निष्ममण व्यय तथा ऐमे व्यय जो भारत सरकार वे ऋण में सर्वायत हो।

१ टी० के वटोपे—'पूर्वोक्त पुस्तक' १६६३ पृत २५१।

२ टी॰ ई॰ मेय-प्र ट्रीटाइन प्राप्त द ला, प्रिवीलेजेज, प्रोसिडिन्स एण्ड यूजेज प्राप्त पार्लियामेन्ट, १३ सस्टरण, पु० ४६३।

भारतीय जायन धौर राजनीति

५--उन्न म्यायालयो के न्यायाधीओं को दिये जाने वाले वेतन मत्ते भीर सेवा-वृत्तियाँ ।

६-- मारत की स्वतत्रता के पूर्व, भारत क्षेत्र में किसी न्यायालय के न्याया-भीश को सेवावत्ति ।

७---मधीय लोक सेवा धायोग के सदस्यों के वेतन मले तथा सेवार्याल !

 मारत के नियन्त्रक तथा महालला परीक्षक के वेनन, मरो तथा सेवा वृत्ति ।

ससद के सदनों के समापति धौर ध्रध्यक्ष के बेनन नचा घले ।

१०-- किसी न्यायालय या पच न्यायालय के धादेश या निर्णय द्वारा स्थापित दामित्वो नो परा करने के व्यय । ११-सविधान के बन्ध प्रावधानो द्वारा सचित निधि सवधी व्यय, जैसे-

धनुष्टिद १४६ (३) के धनसार सर्वोच्च न्यावासय के प्रशासकीय व्यय । धनुष्टिद १४८ (६) के अनुसार नियन्त्रक तथा महानेसा परीसक के प्रशासकीय व्यय, मनुच्छेद २७३ व २७१ (१) के अनुसार राज्यों की सहायता सवधी व्यय ग्रीर वैशी रियासती के शासको के जिलीपसँ ।

१२-- मन्य व्यय जो सनद द्वारा सचित निधि के चन्तर्गत निर्धारित किया जाये ।

सचित निधि के बन्तर्गत व्यय के लिए ससद की स्वीकृति की बावस्यकता नहीं होती है। यन्य प्रकार के व्यय के लिए ससद की स्वीकृति की मायस्यकता है। सनित निधि मे उल्लिखित व्यय पर ससद मे सतदान नहीं हो सकता है। मन्य भ्यय के लिए प्रनुदान संबंधी मांग संसद में की बाती है । प्रनुदान की मांग मो नीमसमा राष्ट्रपति भी पूर्व स्वीकृत पर ही रखा जा सक्ता है। लोगसमा को अपनी स्वीष्टति या अस्वीष्टति देने या अनुदान की माग मे कभी करने का पूर्ण धविकार है।

बजट को पारित करने का कार्य, ससद का एक मुख्य कार्य है। ससद का वजट अधिवेशन प्रतिवर्ष परवरी के दूसरे सप्ताह ने पश्चात आरम्म होता है। मारत में सर्वप्रयम, रेल मनी द्वारा जोश्समा में रेलवे वजट प्रस्तुन किया जाता है। इसके पत्रचात् वित्त मत्री लोक्समा में वाषिक बजट प्रस्तुत करता है। इस समय यह प्रपते बजट मापण से सरकार की वित्त तया क्यों नीति पर देश की ं व्यवस्था के सदमें में प्रकाश ढालता है ।

बजट की प्रतियाँ ससद के सदस्यों को विचार-विमां के लिए वितरित की जाती हैं। इस प्रवस्था में बजट पर वाद-विवाद विस्तार पूर्वक नहीं होता है। परन्तु ससद सदस्य इस ग्रवसर को, सरकार की नीति तथा गासन के विभिन्न विमान के नार्यों में गासने के विभिन्न विमान के नार्यों में मासने के विभिन्न विमान के नार्यों में मासने हैं।

जैसा देखा जा चुना है, ससद की सजित निधि में उहिलादित व्यय पर मतदान करने का प्रधिकार नहीं है प्रत बाद-विवाद के पश्चात् लोकसमा उन विभिन्न मानो पर मतदान करती है जो सिवत-निधि से सबधित नहीं है। विभिन्न मना-लयों में मानो पर पृथक् रूप से विचार होता है। यहाँ पर सीकसमा को प्रत्येक मनालय के विगत वर्ष के कार्यों तथा नीतियों का मृत्याकन करने का प्रवसर प्राप्त होता है, गोक प्रयोक मनालय के विगत वर्ष के कार्यों तथा नीतियों का मृत्याकन करने का प्रवसर प्राप्त होता है, गोकि प्रपनी मानों के भौचित्य को यतालते हुए प्रत्येक मनालय प्रपने विगत वर्ष के कार्यों से लोकसमा वो प्रवस्त करता है।

मागो की मतदान द्वारा स्वीवृत के पश्चात् वाधिक विनियोग विषेयक लोक-समा द्वारा स्वीवृत मांगो तथा संचित-निधि अवधी व्यय को साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जहाँ वाद-विवाद प्रायः सार्वजनिक मुद्दो तथा सरकारी मीतियाँ तक सीमित रहता है। विशेषचर वाद-विवाद उन प्रमागे पर होता है, जिन पर पूर्व मे विचार नहीं हुमा है। किसी विषय पर याद-विवाद के लिए प्रध्यक्ष की पूर्वापुति सावयक है, और फप्यक चाद-विवाद में भाग केने वाले सदस्यों की पहले ऐसे विषयों के सवय में सुचना देने के लिए मह सकता है।

सके परवात् वितियोग वियेयक को उन सब स्तरो को पार करना होगा जो एक सायारण वियेयक को विधि निर्माण के लिए धावयक है। लोगतमा जब वितियोग वियेयक पारित कर देती है तब धावश प्रभाणित करता है कि वियेयक पत्र वियेयक है। तत्रस्थाल् वियेयक को राज्यसमा के समझ मेवा जाता है। राज्यसमा के तिए, वियेयक पर विधार-विमर्ग कर धपने मुख्यबो सहित, १४ दिन में वियेयक को लोकसमा के पास वाधिस सीटाना आवश्यक है। परन्तु यह लोकसमा पर निर्मार है नि राज्यसमा के मुख्यबों को स्थोकार करे या न करे। वियेयक प्रमान निर्माय सोकसमा का ही है। लोग समा द्वारा पारित होने के परचात् वियेयक राष्ट्रपति के पास जबकी स्थीवत के लिए मेवा जायेगा। राष्ट्रपति की सीटाल भीपनारिक है। वितियोग वियेयक को पुनविचार के लिए बाधिस नहीं कीटाण का सकता है।

यन विषेयक निर्माण वा प्रस्तिम चरण संसद द्वारा विसीय विषेयक पारित करता है। गरनार के नर संबंधी प्रस्ताव धमले वर्ष के लिए वित्त विषेयक के रूप में लोकसमा के समझ प्रस्तुत किये जाते हैं। वित्त विषयक को पारित करते की प्रतिया उपर्युक्त पणित विविधोग विषयक को पारित करते की प्रक्रिया के समान है। सदन में, विशेषकर संगिति स्तर के बाद विषयक पर विस्तार पूर्वक विवार किया जाता है। संशोधन, प्रस्ताव करों को समाप्त करने या घटाने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, पर करो को बढ़ाने के प्रस्ताव प्राय प्रस्तुत नहीं होते । वित्त विधेयक अप्रेल माह में ही पारित किया जाता है बगोकि प्राविजनल क्लेबगन आफ टेक्सेज एस्ट १६३१ के भन्तगंत वित्तीय प्रस्ताव, वाधिक वित्त प्रस्तावों के प्रस्तुत करते ही प्रमावशील हो जाते हैं।

ससद में बित्त प्रक्रिया के बाब्यवन से यह स्पष्ट है कि देश की जिल्ल तथा धर्म क्यबस्थामी पर ससद का पूर्ण नियन्त्रण है। परन्तु यह सोधना गलत होगा कि ससद का नियम्बण वित्तीय विधि निर्माण तक ही सीमित है। अबट के पारित होने के पश्चात भी समद का नियन्त्रण देश की विल एव ग्रंथ ध्यवस्यामी पर लगातार बना रहता है। परन्तु ससद का यह नियन्त्रण अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वास्तव स कार्यपालिका पर ससद के नियन्त्रण का महत्वपूर्ण सामन बित्त है। वित्त व्यवस्था के नियन्त्रण की प्रक्रिया में कनिपय साधनों की ध्यान में रेखा जाना चाहिये, जिनके मध्यम से ससद निरन्तर स्थना नियत्रण कार्यपालिका पर करती है। वे निम्नलिखित हैं।

१-सरकारी लेखो का लेखा वरीक्षण-लेखा परीक्षण वह प्रक्रिया है, जिसका उपयोग लेखों का परीक्षण, उनकी या उनके चन्तर्गत, कार्यों की उपयुक्तना निवित करने के लिए किया जाता है। सक्षेत्र में, लेखा-परीक्षण द्वारा वित्त सम्बन्धी कार्यों का भौजित्य दो भाषारी पर निर्धारित किया जा सकता है।

क-वित्त सम्बन्धी कार्यों की विधि के अनुकृत होना चाहिये, और

स-वित्त सम्बन्धी नावों की वित्त नियमों के प्रस्तवन उपयुक्तना इस दृष्टि-कोण से निर्धारित करना कि बिल सम्बन्धी कार्यों द्वारा चनुष्यक एवं निर्धंक व्यय तीनही हमाहै।

मारतवर्ष में लेखा-परीक्षण के कार्य लेखा परीक्षण विभाग में निवित हैं, जिसका मध्यक्ष नियन्त्रक तथा महानेखा-परीक्षक है। लेखा परीक्षण, एक समीय विषय है। सविधान के मनुष्येद १४१ (१) के मनुसार नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्य तथा शक्तियो को ससद निर्धारित करेगी । नियन्त्रन तथा महालेखा परीक्षक को सप एव राज्यों के द्वारा लगाये करों से सवधित व्ययो का लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, नियन्त्रक तथा लेखा-परीक्षक को सघ तथा राज्यों के अन्य व्ययों का भी लेखा-परीक्षण करने का अधिकार है। "व्यय पर ससद का नियन्त्रण, अपने अधिकारी नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के माध्यम से किया जाता है। वह व्यवस्थापिका की और से लेखों का लेखा-परीक्षण करत । है तथा ग्रपना प्रतिवेदन व्यवस्थापिका को प्रस्तुन करता है।""

१. सीव पीव भागमरी—'पन्तिस एडपिनिस्ट्रेसर्ग १९५० भाग ४ ५० ६२ १

२—ससद की वितीय समितियां—ससद की कार्यपालिका के नियन्त्रण का ग्रन्य साधन, उसकी वित्तीय समितियों के रूप में है। ससद की दो वित्तीय समितियों है।

क-लोक लेखा समिति-ग्रारम्म में सधीय लोकलेखा समिति में १५ सदस्य थे. जिनका निर्वाचन लोक सभा अपने सदस्यों में से करती है। परन्तु १९५३ से राज्य समा के सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जाने लगा । इसका प्रध्यक्ष सत्तारूड दल में से ही लिया जाता है । तोकलेखा समिति, नियन्त्रक तथा महा-लेखा परोक्षत के संसद के समझ प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकारी लेखों का परीक्षण करती है। प्रत्येक मधालय या विमाग का एक भविकारी लोकलेया समिति के समक्ष, समिति द्वारा उठाई नई बापतियो का निवारण या स्पव्टीकरण करने उपस्थित होता है। जिन मशाखयों या विमागों में ग्रनियमिनताएँ हुई है उनके सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी, उसके निष्कर्य तथा सुऋत लोकसमा को समिति-ग्रध्यक्ष द्वारा पहुँचाये जाते हैं। लोकसमा से समिति का प्रतिवेदन वित मवालय को सेज दिया जाता है, जो समिति के सुकावी को सवयित मनालय या विमाग से प्रवयन कराना है। यदि समिति के किसी स्थलव को सरकार भरबीकृत कर देती है तो उसको ऐसा करने के लिए कारण बनलाने होंगे। यह स्रव्द है कि लोक लेखा समिति कार्यशालिका तथा प्रशासन पर निवस्त्रण रखने के लिए ससद को महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाती है। डा० नासँव पामर का कहना है— ''लोकलेला समिति न केवल नियन्त्रक तथा महालेला परीक्षक के प्रतिवेदन, भौर प्रत्य कागजातो की विभिन्न अनियमिनताएँ को जात करने के लिए जांचती है परन्तु साय हो राष्ट्र के वित्त सम्बन्धी प्रशासन से सर्वेवित निर्द्यंक ब्दय, भ्रष्टा-चार, प्रक्षमता एव ब्रन्न त्रुटियों में भी रुचि रखती है। ग्रतएव यह सरकारी लापरवाही तथा अस्टाचार के विरुद्ध ससद के हितों की रक्षक तथा जनता की सरक्षक है। इसके प्रतिवेदन महत्वपूर्ण लेख है।"

लोकलेला समिति की भूमिका के सबय मे ग्रही इसके एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन का उल्लेख करना आवश्यक होगा । यह मामला आरत-चीन मुद्ध-१८६२ से सबिम है। मारत की पूर्वी सीमा पर हवाई-जहाजों के उतरने की हनाई-पट्टी को तैयार करने के लिए गुरुष इंजीनियर ने इन १००,-५५ लाल का ठेका इस मते पर दिया कि सारा कार्य पांच माह मे पूरा हो जायेगा । वासलब मे सारी नार्य का मनुमानता व्याप ०० ६२०३ हवार ही था। इस पर मी ठेकेदार को सारा कार्य पांच माह से भूतर सारा कार्य सार्य का मनुमानता व्याप ०० ६२०३ हवार ही था। इस पर मी ठेकेदार को सारा कार्य साम करने में एक वर्ष से अधिक समय सन गया। निर्माण कार्य

१. एन० डी॰ पामर-'द इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम' १९६१ पृ० १२।

१८६

धारम्म होने से पूर्व ही गोलीबार स्थागित हो चना या। लोक्लेखा समिति के समक्ष भपना साक्ष्य देते हुए सुरक्षा-सचिव ने स्वीकार किया कि यदि युद्ध पुन. मारम्भ होता तो निर्माण नार्य के निर्धारित समय मे समाप्त न होने के फलस्वरूप निश्चित भारतीय बायु सेना की कार्य-दक्षता पर बाधात पहुँचता । समिति ने अपनी ४-वें प्रतिवेदन में, जो लोकसमा के १६ खप्रेल, १६६६, की मैजा था, सुझाव दिया कि धनुमव के बाधार पर सबक सीखते हुए, प्रतिरक्षा के अधि-कारियों के लिए, चविष्य में ऐसे आपत्तिकालीन कार्य, जिसमे जनता का भारपिक यन लगता है. हाय में लेते समय सतकंतापवंड कार्यं करना चाहिये।

ल-प्राहरुतन समिति—"प्राहरुतन समितियाँ स्थायी, तथा निरम्नर कार्म करने वाली मशीनरी के समान है जो ब्यय की दिष्ट से धर्य-व्यवस्था में बचत की समावना की जांच करती है और उसके लिए सुभाव प्रस्तुत करती है।" । भारत में सधीय प्रावनलन समिति के २५ सदस्य हैं जो समद द्वारा एकल

सक्रमणीय मत द्वारा बानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित किये जाते हैं। समिति के अध्यक्ष को लोकसमा का सम्यक्ष मनोतीत करता है। प्रत्येक वर्ष प्राक्तलन समिति कतिपय मत्रालयों के वित्तीय धतुमानों की जांच करके लोक सभा को प्रतिवेदन मेजती है । विशेषकर प्राक्कलन समिति विभिन्न मनालयों में बचत तथा निपूर्णता हासिल करने के लिए सुमाब देनी है । समयानुसार प्राक्कलन समिति ने नई महत्वपूर्ण सुक्षाव दिये हैं। उदाहरण के लिए प्रपने प्रतिवेदन २ में समिति ने भारत सरकार के अधिवालय और विभिन्न प्रजासनीय विभागों के सगठन के लिए सुम्हाव दिये हैं । प्रतिवेदन ६ में कतिपय प्रशासकीय तथा वित्त सबधी सुघारों ने लिए सुमाब दिये हैं । इसी प्रतिवेदन में समिति ने वित्त मत्रालय के लिए समाव दिया है कि बहुत काम एक साथ इक्टरा न हो, विभिन प्रशासकीय विमाग प्रपती योजनाएँ विक्त मत्रालय को कम से कम एक वर्ष पूर्व मेजे। इसी तरह प्रतिवेदन २० में समिति ने सरकार को यह सुभाव मेजा है कि जब भी सरकार ऋण लेने जाये तब ससद को सूचना देना धावश्यक है।

प्रात्रक्लन समिति के समाव सरकार को मेज दिये जाते हैं, जो इनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करती है। समिति की, उसके कार्यों मे, ससद-सचि-वालय द्वारा सहायता मिलती है और विमागीय अधिकारियो को यदि समिति यह चाहती है तो उसके समक्ष उपस्थित होना बावश्यक है । प्रावस्थन समिति सोकलेखा समिति के समान प्रशासन के क्षेत्र में निर्चंक व्यय पर रोक संगती हैं। प्राक्तलन समिति के महत्व के सम्बन्ध मे प्रो॰ मोरिस जोन्स ने वहा है-

१. एम॰ पी॰ 'शर्मा-पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन वियोशी एण्ड प्रेविटश', \$840 go 300

"एक महत्वपूर्ण सीमा तक यह सिमित केवल मितव्ययता या कार्य दक्षता की मावना से प्रेरित होनर हो नहीं परन्तु नार्यपालियर वी निरनुष्ठाता की रोकने के विचार से एक वास्तिका विदोधी दल की एवजी में, महत्वपूर्ण स्थान प्रहम करती है। समझ में एक प्रविकासित देश में इस तरह की व्यवस्था प्रियेश परपुरत है। समझ में एक दक्षितानीय है नि प्रावनतन सिमित न कि लोकरेता सिमित वोचार्यों को करती है, जो भारत म महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रयम, यह सदन के सदस्यों के तिए महत्वपूर्ण प्रविकास के सदस्यों के तिए महत्वपूर्ण प्रविकास क्षमित को प्रतिकेदना का, तदन में तथा सदन वे चाहर वहुत शिक्षित्व मूल्य है। इसकी सहायता में को क्षम के उस तरन हो निमाण हो सन्ता है जो सासस कीर सिसीत वर्गों के मध्य की सास कीर हा सिता वर्गों के मध्य की साह की हुर करने के लिए सदन्त सावव्यक है।"

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि विसीय प्रशासन पर ससद का नियन्त्रण मान्तरिक तथा बाह्य साधनो द्वारा निरन्तर बना रहता है।

ससद को प्रत्य शक्तियाँ—सिवयान द्वारा ससद को नितपय प्रत्य शक्तियाँ भी प्रदक्त हैं, जिनका निम्त्रनिखित वर्गीकरण के भ्रायार पर भ्रध्ययन किया जा सकता है:---

१—सपद की सकटकालीन स्थिति सबधी शक्तियाँ—सिवधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित सनटकालीन उद्योपणा को ससद के समक्ष उसकी सहमति के लिए रजना शावश्यक है। जब देश में अकटकालीन स्थिति है, तब मनुक्छेद २५० के मनुसार ससद को सथ तथा समतर्गी सुनियो के घितरिक्त उन विषयो पर भी विधि-निर्माण करने का प्रधिकार प्राप्त हो जाता है। जो राज्य-मुची में उल्लिखित है। ऐसी स्थिति में ससद को सारायों के प्रशासनीय प्रधिवारियों को सविधान के सन्तर्गत कोई सी कार्य सोंपने का प्रधिकार है।

२—सिवधान में सखोधन का ध्रिपकार—धूर्व में देखा जा चुका है कि सिवधान में सखोधन हैतु, सिवधान के प्रावधानों को तीन वर्षों में रखा जा सकता है। सर्व प्रमम् प्रविधान के ऐसे प्रावधान है, जिनको ससद साधारण बहुनत से विधि पार्टित कर सखोधित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप दस प्रक्रिया-प्रतार नये राज्यों का निर्माण या बतेमान राज्यों के नाम या सीमाधी में, राज्यों की विधान समाधी के मत को जानने के पण्यात् परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों की विधान समाधी में दितीय सदन समाप्त किये जा सकते हैं या जिन विधान समाधी में दितीय सदन समाप्त किये जा सकते हैं या जिन विधान समाधी में दितीय सदन नहीं है, वहाँ दितीय सदन स्थापित किये जा समते हैं, नागरिकता ध्रवसुवित को तियों और

१ डब्ल्यु एच० मोरिस जोन्स-पूर्वोक्त, १९५७ पृ० ३०७-३०८।

नेन्द्रीय-प्रशासित क्षेत्र से सबधित निषयों से सम्बद्ध सविधान के सारे प्रायमान सतद मे तापारण बहुमत के झाधार पर पारित विधि द्वारा सक्षोपित किये जा एकते हैं। दितीय, सक्षोधन की दृष्टि से, सविधान नी द्वितीय येणी मे जो प्रायमान रखें गये हैं, उनका मूल रुप से सवस दीनों, सधीय राज्य सरकारों से हैं। मर्यात् यह

त्वात् संचालन का तुम्द तु क्षत्यान न । हताय संचा मंत्रा भागमा न । भागमा न । पार्च है, जनका मुक्त रूप से सत्य संचीनों, संचीय पार्च रहकारों से हैं। स्पार्च पढ़ संचियान ने ऐसे प्रायमान है, जो शयशब भी युक्टि से महत्वपूर्ण हैं। स्तर्यस् इनके संबोधन ने सत्य तथा राज्यों दोनों को सामीदार बनाया गया है। सम्बान

क पायन पानपालाका —

(क) अनुकोद ४४ तथा अनुकोद ४१ जिनके अनुसार राज्य विधान सभामी
के निर्वाचित सकस्यों को राज्यपित के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अण्डल का एक
हिस्सा साना गया है। अनुकोद ७३ तथा अनुकोद १६२ जो राज्यों की कार्यपालिका प्रास्त्रियों से स्ववीयत है और अनुकोद २४१ जो सथीय श्रीकों में स्थित

जन्म न्यानाव्यों से स्ववीयत है।

(ख) सविवान के पोजर्वे हिस्से के चौदे प्रच्याय के प्रतुच्छेद जो कि समीम ज्यायगिक्ता से सदिश्वत है, सविवान के छुठे मान का पोचवा प्रध्याय जो राज्यों में स्थित, ज्यायालयों से सविवाद है, चौद सविवान के स्वारहर्वे हिस्से का प्रथम

म्राच्याय जो सम राज्यो के सबस पर है।

(ग) राज्यो का ससद में प्र तनिधित्व।

(प) सिवमान का अनुत्येद्ध २ ६५ जिसमे सिवमान सवीरान-दिशा चिल्लिय है। सिवाम के उप्तर्मक्ष उप्यश्निक ऐसे प्रस्ताम हैं, निनसे सम्र तथा राज्यों, सैनी के हित निहित्त है, अत्यत्य हम जाववानी वर तकांध्य करने के तिद्य निर्माणिक प्रक्रियानुद्वार सम्र स्त्रक उद्या कम से कम साथे राज्यों की दिशान समाधी की सहस्ति सावयत्य है। सर्वप्रमान इनम से किस आवधान के संगोपन के लिए सहस्त के प्रदेश तदन म वियोवक, सदन की पूर्ण सहस्या के बहुद देव उपलिया सहस्या के वो तिद्वार्ष्ट वहनुत्व से पारित होगा चाहिय । जब समद ने संगोधन नियंवक उपर्युक्त रूप ने पारित कर तिया, तत्वश्चाद का से कम आधी राज्यों की वियान समाधी हारा वियंवक की सह्या, तत्वश्चाद कम से कम आधी राज्यों की वियान समाधी हारा वियंवक की सह्या तिम्तना धानवण्य है।

हुवीय, सबियान के अन्य प्राथमान (उपर्युक्त दो श्रीष्यायो मे चिल्लिक्त प्रायमानो को छोडकर) ससब के प्रत्येक सदन म सम्पूर्ण सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित सदस्या से दो तिहाई बहुमत के आधार पर समोधित किये जा सकते हैं।

सदस्या से दो तिहाई बहुमत के भ्राधार पर सजोधित क्यें जा सकते हैं। ग्रत यह स्पष्ट है कि ससद का एक महस्वपूर्ण कार्य सविधान का (कुछ प्रावधानों को छोड़कर जिनके लिये भ्राचे राज्यों की विधान सभाग्रों की सहमति

षावश्यक है) संशोधन करना है।

सघीय संसद १८६

३—ससद देश ना सबसे महत्वपूर्ण स्वान है, जहाँ पर जनता की शिकायदों को दूर करने का प्रयत्न, उनके प्रतिनिधियों द्वारा निया जाता है। प्रो० मोरिस जोन्स के प्रनुसार विकायते दूर करने के कई धवसर हैं, पर निस्सदेह प्रश्न क्षमय सबसे महत्वपूर्ण है। पर यह नहीं नहा जा सकता है कि सारे प्रश्नों का उद्देश्य शिकायदों को दूर करना होता है।

उदाहरण स्वरूप ससद के १९४३ ने शरहकालीन अधिवेशन में बीस से प्रियेश प्रका निम्मलिखित विषयों पर पूछे गये — मूती कपडा, चर्खा तथा खादी-उद्योग, इतक-नर्भवारी, सेश, शबरुर, धाकाश्रवार्था, वैज्ञानिक श्रनुस्थान, कोयला तथा खदाने, रेलवे दुर्घटनाएँ, मार्ग, एव सबसे अधिक प्रश्न रेलवे मार्ग पर पूछे गये।

ग्रन्य में हम इस निष्क्षं पर पहुँचते हैं कि मारतीय ससद को, सिंवधान के ग्रन्तगत समवाद की सीमाभ्रों में, महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। इनके द्वारा ससद कार्यगतिका पर नियन्त्रण रखकर, उसे अपनी नीतियों, तथा कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकती है। परन्तु सारत में ससदीय प्रणासी की सफलता निर्वाचक गण तथा ससद में जनता के प्रतिनिधियों की सत्वकता तथा कार्यकुशस्ता पर

निर्भर है।

संदोय कार्यपालिका तथा सवस् के सक्यों का दो सक्यित प्रापारों पर सम्ब-यत करना वरित्त होगा। ये दोनों भाषार, माप्तत में सस्वीय सरकार है सैवानिक स्वा करताहिक तसों ने सक्वित है। धवा मारक में कर्मण्यों तका तसा सदस के सर्वा को सात करने के लिए हमारे बगक मूल वया मार्गदर्गक तथ्य यह है कि सर्वामों से मैद्वानिक कथे में, पाहर्गक कार्यपालिका (क्षेत्र में है । स्वादीय कार्य-प्रमाली से मैद्वानिक कथे में, पाहर्गक कार्यपालिका (क्षेत्र में प्रयत्न) स्वत्व के प्रचलित सहत के प्रति अपरायां है, कलस्वक्य कार्यपालिक (क्ष्त्री सप्तक) सत्त्व के प्रचलित है। परलू ब्याद्रारिक दृष्टिकोल में परि, कार्यपालिका तथा सबत के सम्बर्ध में नितंत्र कर से कार्यपालिका पर नियन्त्रक होने पर भी, व्यवहार में कार्यपालिका

ारनशाला हा पर रूप सन्नेष में संघीय कार्यपालिका (भन्नी मण्डल) तथा ससद के सबघो का घट्ययन

निस्त्रलिखित यो यायारी पर किया जा सकता है।

१--ससीय प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुसार संबीध कार्यंपालिका (मजी-मण्डल) सबस ।

१९७७) सबब र २—सबीय कार्यपालिका (सत्री सण्डल) तथा ससद के ससदीय प्रणाली में

ध्याबहारिक दिष्टिकोण से सबध ।

Q

स—सारविय मणात्री के विद्यालतनुसार संयोध कही मण्यल तथा करद के स्वितालिक रूप है, सारविय प्रणाती के प्रस्तपेत मंत्री मण्यल (शास्त्रविक के प्रतिक रूप है, सारविय प्रणाती के प्रस्तुपेत मण्यति है, वर्षाक नामां मात्र वार्षपालिका) प्रत्या कर है, सवद के निवती सकत के प्रति उत्तरपंत्री है, वर्षों जाना मात्र वार्षपालिका का प्राच तथा है। वर्षों के सार्पपालिका के यो हिस्से होते हैं, प्रत्या नामां के तथा होते हैं। प्रतिक सारविय प्रणाती के सार्पपालिका के यो हिस्से होते हैं, प्रत्या नामां के सारव है।

 (क) मत्री मण्डल (बास्तविक कार्यपालिका) के सवय से ससद की मिनवा—ससदीय प्रणाली का माणार भूत सिद्धान्त भारत सिवधान के मनुष्येद ७५
 (३) म निहित है, जिसके अनुसार भनी मण्डल सामृहिक रूप से लोकसमा के प्रति उत्तरदायी है। सिवधान के इस अनुष्हेद के अध्ययन के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि मनी मण्डल सामूहिक रूप से लोकसमा के प्रधीन है और लोकसमा सामू- हिक उत्तरदायित के सिद्धान्त के प्रधान पर मनी मण्डल का नियम्बण करती है। विभिन्न सामने के माध्यम से लोकसमा मनी मण्डल पर प्रपता नियम्बण रखती है, परितृत सामने के माध्यम से लोकसमा द्वारा मनी मण्डल के विरुद-अधिवयास प्रस्ताव पारित करना है। सासनीय प्रणाती मे मनी मण्डल पर नियम्बण रखने के लिए नियस सरदाय प्रणाती मे मनी मण्डल पर नियम्बण रखने के लिए नियस सरदाय आवश्यक प्रसाव पारित करना है। सासनीय प्रणाती मे मनी मण्डल पर नियम्बण रखने के लिए नियस सरदा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, अतिम तथा सबसे कठोर तरोका है। श्री सालबहादुर णास्त्री तथा श्रीमती गायी ने कार्यशाल मे विश्वक्षी दलो द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वस प्रस्ताव पारित करने के प्रयस्त विश्व स्वार्थ प्रस्ताव पारित करने के प्रयस्त किये परित प्रस्त हमें वे सफल नहीं हुए।

सरकार के विरुद्ध प्रविश्वास प्रस्ताय पारित करने के प्रतिरिक्त भन्य साधा-रण साधन भी है, जिनका उपयोग ससद में प्राय प्रतिदिन मंत्रीमण्डल पर निय-न्त्रण रखने के लिए किया जाता है। आगे लिखे हुए साधनी को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाता।

१-समिति प्रणाली ।

२-ससदीय प्रश्न ।

३--ससदीय प्रस्ताव ।

४-ससद में बहस ।

# समिति प्रणाली

जनतात्रिक राज्य में समितियों को व्यवस्थापिका के कुश्वसता पूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक माना जाता है। समितियाँ, न केवल व्यवस्थापिका के कार्यों को दूरा करने कर लिए भी प्रावस्थक है। सस्तिया के सिता की रक्षा करने के लिए भी प्रावस्थक है। सस्तिया समितियों को किसी लेक ने ससद के—'आंखों तथा कार्यों के क्यां माना है। किसितायों के कार्या करने है। समितियों प्रवासन पर तक्ष्तीकी तथा साथारण जानकारी हासिल करती है। "सस्तिय समितियों प्रवासन पर सहत्वपूर्ण नियम्त्रण एसती है। वे प्रधासन की कार्यवाही की जाँच तथा निरीक्षण भी करती है।'' प्रारतिय सखर में, समितियों को प्राप्ति कार्य महत्व है, व्यों कि एक प्रमावशासी विपक्षी दल की अपूर्णस्थित में, सरकार की निरकुत प्रवृत्तियों पर समितियों है। "इन समितियों में ही विपक्षीय वस सरकार की नीतियों को प्राय प्रमावित कर सकते हैं। इन समितियों के कार्य भारतिय ससदीय

१. सी॰ पी॰ भाम्भरी-लोक प्रशासन, १६६० भाग ४ पृ० ६०।

प्रमासी ने एक मनोध्यनक घट्न हैं। सरकार पर एक प्रमावभागी नियनक पिता सिमियो वा है। ओक भोरिस जोग्य ने मान व पर परो में हुन दूर्य प्रध्ययन में सह मन विभाग ने समा है कि "इस प्रदार ने महिता ने नेवन मित्रप्रधान से सह मन विभाग ने सिमार के प्रदार ने महिता ने नेवन मित्रप्रधान समा बार्युक्त मन ने दिवार के प्रधान के

भारत में ममितियों से एक सङ्क्ष्यूर्ण नाम यह भी है कि सरवार द्वारा प्रसा-विक्त विषयों पर ममितियों में स्वीधक सहयोग मिनने की समावना के साथ विषक्षी कल सरकार को स्वीवक प्रसावित कर सबते हैं।

भसद में एवं नगाँठन तथा प्रमाणवारी विद्यक्षी दन वी धनुतिम्यानि से, घट्ट स्वामानिक में हैं कि नससीय मौसिनियों का महत्व धनिक हों गया है, अने कि ऐसी स्थिति मौसीनियों ने माध्यम के हो स्वाद्यार की निर्मायों का बातों हो, अन क्यांच ने लिए प्रमाणित विद्या था सकता है। उदाहुरण स्वव्य प्रतिमीतिता ही भी और के प्रमायद्य ही होग्युष्ट बाग धीर और बाट नवयी प्रतिमीतिता ही अवास से साई के प्रमाणना मौसीनित सरदार वो अवन नवरी प्रमाणत देती है। साहसामन सीमिंत भरवार यर सन्तर्भता पूर्वक नियाह एक वर उसकी निर्मायन पर पोक लगानी है। इभी तरह स्वायोधिकाविधि सीमित कार्यगानिका हो नियम निर्माण मित पर एक समूत्र ने महत्त है।

मोकमाना को प्रतिमात तथा कार्यवाही के नकारण के नियम १२४७ द्वारा मध्य क्षेत्र मानिक मानिक मानिक मानिक प्रवास किया गया है। इनके दो क्यों में रखा जा सकता है — () क्याची मानिकाई, चीर ()) क्यिंग मानिकां में सित्र मानिकां में निवृत्ति करता के प्रत्यास कर होगी है। समिनियों के स्वयास की निवृत्ति करते के सामिकां के स्वयास की निवृत्ति करते के सामिकां के स्वयास की निवृत्ति करते के सामिकां में निवृत्ति है। जिनके दिवाली तथा सलाइट दर्जों में साम्यास मानिकां में हमानिकां मानिकां में हमानिकां में हमानिकां में हमानिकां मानिकां में हमानिकां में हमानि

१— वर्ग संबंधी बरामाँ समिति—(त्रितिनेम एटवाइडरी करेरी) सरत के प्रिवेशन के वारत्म में कार्र के स्विधित में त्रिति के विद्यान में कार्य के निर्देश के वर्ग के किया के निर्देश के वर्ग के निर्देश के वर्ग के निर्देश के वर्ग के किया के निर्देश के वर्ग के किया के निर्देश के वर्ग के निर्देश के वर्ग के किया के वर्ग के किया के वर्ग के किया के वर्ग के वर्ग

१. घार वर्नहेस-पार्तियामेन्ट एष्ट देमोडेसी इन इरिटया, (इन स्टढीड इन इरिटयन देमोडसी) सम्पादिन एस० पी० धरणर और घार० धीनिवासन, सन् १६६४ पुरु १४=४६।

२-साधारण (प्राय हेट) सदम्य-विशेवक तथा सक्रम्य सबधी समिति (क्रमेटी धान प्राइ हेट मेम्बर्न बिन एन्ड रिजोन्जुशन)-इस सनिति का कार्य सामारन सदन्य-विभेयको को जाँच कर, उन्हें समद के विचार-विमर्श के निए प्रम्तुत करना है। इनन नी १४ सदस्य होते हैं। लोक्डना के ब्रध्यक्ष द्वारा सनिति का ब्रान्यक्ष, इसके मदस्यों न ने मनोरीत किया जाता है। यदि साक्ष्ममा का उपाध्यक्ष समिति का सदम्य है, बह स्वतः समिति का ध्रायक्ष बन जाता है ।

३--प्रवर समिति (सेनेक्ट कमेटी)--प्रवर समिति की नियुक्ति इस दक्त होती है, जब सदन म प्रस्ताब धारित किया जाता है कि विवेदक को प्रवर समिति है ननक्ष रदा जारे। बदन कार्यों हे निए, प्रवर समिति विशेषकों की मन्सति लेती है, बाबस्वकदानुकार साबी सेती है, तथा नागगता ना भी निरीक्षण करती है। प्रवर समिति की सदस्यता सदन में राजनीतिक दला की रास्ति के प्रतुपात में নিনাঁতির কা বাবী है। লাজ্যনা কা অনুল লুনিরি ক অনুল লা নুনানার करता है, परन्तु बढि लोजसभा का उसान्यक्ष समिति का सदस्य है तो वह स्वत. समिति का सामल हो जाता है। महत्वपूर्ण विमेयकों के लिए सम्रद के दोनों सदनों की समुक्त समिति में लोकसभा के दो-तिहाई मौर राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य होते हैं । ममूक्त ममिति के सदस्यों की सच्या, प्राय १० होती है । सामान्यत एक प्रवर समिति में ७ ने ११ तक सदस्य होते हैं।

४-वादिका सबनी समिति (क्नेटी बान पिटांसन्म)-वदन के अभिवेशन के बारन्न में, इस ममिति के सदन्यों को सोक्तना ने बायस द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानिका संबनी समिति के १५ सदस्य होते हैं। समिति का कार्य समकी प्रेपित की गई याचिकायों को जांचता है, यह अपना प्रतिवेदन सदन को देती है। समिति सदन के समझ विजेबन के संबद में बाचिकाएँ बहुन करती है और बाचिक कामों की प्रतिमों की सदत में विरोधक पर दिवार दिनमें करने के पूर्व दिवरित रुरवानी है। इन याविकामी डारा समद के समझ विषेपको पर जनमद का रुव विदित होता है और फलस्वरूप सनद से सादस्यक कार्यवाही की जाती है ।

१-प्रावत्त्रत समिति (एप्टिमेट्म क्मेटी)-प्रसद की दो दिनीय समितियों म ने प्रास्कृतन समिति एक हैं । प्रास्कृतन समिति को नियुक्ति सुसद के प्रयम प्राप्त बेरत के ही बारन्स में प्रतिक्षें होती है। इसके सदस्यों को सस्या ३० होती है, विनका चुनाव लॉकसमा में अनुपातिक धानार पर होता है। "नाक्कलन सनिति हा हामें दिन्तार पूर्वक वज्ट बनुमानों तथा व्यवों की औन करना है, द्वतिए मह सरकार को न नेवन विनीय क्षेत्र में, बरन् क्रन्य क्षेत्रों में भी प्रमादित करते के . लिए मस्तिरानी स्थिति में है ।"१

१. एम. वी पायनी—'इन्डियात कान्स्टीट्यूशन, ११६२, पृ० २१२। \$3

किया जाना चाहिये।

लोकसमा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमो (नियम ३१०) के धनसार

प्रावस्त्वन समिति के चार प्रमुख कार्य हैं।

(१) यह प्रतिवेदन देना कि प्रावस्तन में उल्लिखित नीति के प्रमुक्त किस तरह मिनव्ययिता, संगठन में संघार, कार्यक्रवलता तथा प्रशासन में स्पार लाये

भा सकते हैं !

 (२) प्रशासन में कार्यकुश्चलता तथा मितच्यियता लाने के लिए वैकल्पिक शीतियों का मुफाव प्रस्तुत करना।

(३) यह जीव करना कि प्राथकलन में निहित नीति के धनुसार धन का

उपित दितरण किया गया है या नही । (४) यह मुसाब देना वि प्राक्कलनो को ससद के संग्रह किस क्य में प्रस्तुत

प्राक्तलन समिति के कार्यों के सबय में, प्यान रखने सीय तथ्य यह है कि सप्तर हार बजर के पार्थिक होने के पत्रवाद हमने कार्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। सिति सारे वर्ष सरकार के वित्ती भी विभाव या प्रीवरूप भी तीकर हारे वर्ष जांच का कार्य करती है। प्रावन्तन समिति के प्रविदेवन, सरकार नी दिये यह मुक्ताद के वर में होते हैं। शरकार दनको स्वीहन कर सबती है। परि सरवार रुट्टे सर्वाहन करती है तो सरकार को ऐसा करने के वित्र नारण बतताने होंगे।

मदि समिति भगने गत पर पुढ है तो झन्तिम निर्णय सम्रव के हाप मे होगा। ६—सोकलेका समिति—"लोकनेका समिति प्राक्तन समिति की पुढयां बहुन है। यदि प्राक्तन समिति प्राक्तनतो की जाँच से सबधित है तो लोकलेका

समिति का सबध लोक-निषि के व्यय करते के तरीको तथा गरीजो से है।"" सोकलेखा समिति के २२ सबस्य होते हैं, ११. सोवसमा के सथा ७ राज्य सा में से । ये सबस्य धानुसातिक प्रतिनिधित्य के घायार पर निर्वाणित होते हैं। सोचलेखा सिर्धित के मार्थों का उल्लेख सबस्य की प्रक्रिया तथा कार्यवाही सचानन

के नियमों में किया जाता है, जो निम्नानुसार है।

प्राप्त सरकार के जिल्लीय लेखी और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन भी
जांच करके. लोकनेसा समिति निम्नासिधित बातों जिदित करती है।

(1) तेखों में निस पन राशि का वितरण बतलाया गया है, नया वह वैधानिक रूप से प्राप्त थो मा नही, और जिस सेवा में या उद्देश्य के लिए श्र्य किया गया, नया वह वैधानिन सामार पर किया गया।

१. एम० वी० पायली—'पूर्वोक्त पुस्तक' प्र० २१२ ।

- (11) ब्यय उचित ग्रधिकार के धनुसार है या नहीं ।
- (m) वित्त का प्रत्येव पुनर्विनियोग, इस समय में, सक्षम श्रविकारी द्वारा निमित नियमों के अनुकूल है या नहीं ।
- (14) सोम्लेखा समिति सरकारी निगमा के लखाँ, ज्यापारिक तथा निर्माण योजनाग्रो की जीच करती है।

सोनलेता समिति का सबसे महत्वपूर्ण वार्य नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच कर यह निर्धारित करना है कि ससद द्वारा स्थीहत धन-राशि का उपयोग, उचित रूप से किया गया है या नहीं। समिति के प्रतिवेदन ससद के समक्ष रहे जाते हैं, जो प्राय इन्ह स्वीहत कर लेती हैं।

सोबलेता समिति को भूमिका को प्राय धालोकना की जाती है कि समिति हारा वित्तीय मामलो की जो जोक होती है, वह देर से होने के कारण अपये हो जाती है, क्यांकि इसका कोई प्रमास कही रहता। यह भी कहा जाता है कि समिति के पाये जब-परीशा (पोस्टमार्टेंग) के समान है, क्योंकि प्रम का अपये धा प्रमास कर के स्वांकि के प्रमास कर के स्वांकि के पाये जब-परीशा (पोस्टमार्टेंग) के समान है, क्योंकि प्रम का अपये प्रम का होने के प्रमास है। प्रम जेमा डा० नाम्मरी ने वहा है—"यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि पोस्टमार्टेंग में प्रमास की प्रमास है। प्रम के क्यूय पर समिति हारा निरीशण जन लोगा पर एक यही रोव है जिनको धन क्यांकिन का का से सीपा गया है। वेश्वल हस तथ्य का प्रहसास कि जो मुख किया क्या है, उससे पाये है। विशेष की सिरीशण की सीपा प्रमास होता है, उससे पाये है। यदि जोंच जीवत रूप में हुई है तो इसके हारा प्रधासन में वार्य-मुशनता प्राप्त होती है।"

७—प्रत्यायोजित-विधि सर्वाधत समिति (कमेदी धान इंसिगेटेड सेजीस्सेशन)— इस समिति के सदस्या भी सत्या १५ तन होती है। इन्ह सोक्सवा का प्रध्यक्ष मनौनीत न रता है। इसका कार्य विभिन्न नियमो, उपनियमो घादि की जोंच करके सतद नो प्रतिवेदन देना है, नि यह सतद या सन्विधान द्वारा प्रदत्त शक्ति ने घतु-सार है या नहीं । सतद ने प्रतिवच्चा के रूप में इस समिति ना महत्यपूर्ण कार्य नायंपालिका नी नियमों को निर्माण नरने की शक्ति का सतक्तापूर्ण निर्पालित नरना है, दिससे यह विदित निया जा सके कि नायंपालिका ने प्रपत्न दिसारित तेत्र में रहनर ससद या सविधान द्वारा प्रस्तुम्योजित स्रोत घनुतार विधि निर्माण

१. सी॰ पी॰ भाम्भरी-'पूर्वीकत पुस्तक' भाग ३, पृ॰ ८२ ।

२. जी० थी० मायलकर स्वीचेज एण्ड राइटाज—स्पीच टू पस्लिक प्रकाउन्ट्स कमेटी, प्रप्रेल, १० सन् १६५० पृ० ७६ ।

१६६ मारतीय शासन ग्रीर राजनीति

विया है या नहीं। इन दृष्टिकोण में यह समिति कार्यपालिका की निरकुत्त बनन की प्रकृति पर ऐक प्रमावशाली समुख है। इस समिति पर मत्रियो की निष्नुतिः

नहीं को बा मनती है।

«-विशेषाधिकार समिति(क्मेटो धान प्रिवेतिकेब)-इन समिनि वा गटन लोकस्ता के प्राच्छा द्वारा पदन के व्यविधान के प्रारम्भ में हाठा है। इसके एर सहस्य होते हैं। इस ममिति वा वार्य विशेषाधिकार या विशेषाधिकार उसके सबसो प्रत्या भी जों के ज्ञाही है। व्यविक क्ये के पत्र्याण व्यक्ति प्रपणा प्रतिवेदन सबसो प्रत्या भी जों के ज्ञाही

सबयो प्रश्ना की जांच जरना है। जांच करने के पत्त्वान् समिति प्रपना प्रनिवेदन सदन को देनी है। समिति का सप्यक्त लोकसमा का सप्यक्त होता है। ६—सरकारी धाश्यासनॉ-स्विधत समिति (क्मेटी सामगर्वमेण्ट एशसूरेम्सैम)—

स्त समिति में ११ मदन्य होते हैं। इस समिति का कार्य मित्रियों द्वारा समय में दिये गयं सारमानता तथा वकता को जाँक, इस उद्देश्य में करता है कि मित्रियों द्वारा में कही तक कार्योगित किये गये हैं। यो एयक एतक कीत में इस समिति की मुक्तिन पर अकाश जातते हुए कहा है—"एत स्विमिति में आवाक्षीय कार्य-कूक्सता पर भीकती रातन के साथ पुराणी अव्याती म से कई दोषों को दूर किया है। मत्री, सब सकत देग में सतमें हैं, सीर अवातन हारा दिये हुए सकत पर तक्तात कार्यमही की जाती है। सरकार के मदी सब सबद के प्रति सरने वर्तन्या के प्रति सतम हैं।"

१ -- सबस्य हे प्रमुशिस्या रहने वाले सदस्यों सबसी समिति (प्नेदी धान रेपसेन्द्र सम्बद्ध) -- हम समिति की सदस्य सस्या भी हैं हों है, जिनकी कोकस्या का समस्य एक वर्ष के निरूप क्लोनीत करता है। सदस के सदस्या के, सुपुर्दास्ति है के सदस्य में, प्रावेदन पत्रा को जोन यह मिति करती है। समिति प्रावर ऐस् मानके की जीन करती है, जिनमें लोई सदस्य ६० वा हस्ते भी घरिक रिगो तक दिना धनुमति के सनुपरित्य रहा है। समिति ऐसे मामल में, सदस को प्रतिविद्या जिनकी है कि सम्या की सनुपरित्य साथ की जाये या सनका स्थान रिरूप साथित

११—नियम समिति (श्ला कमेटी)—इस समिति वे १५ सदस्य हैं, जा तोक समा के प्रमास द्वारा मनोनीत निय जात हैं। जोत्त्वमा का प्रमास ही इस समिति का प्रमास हाता है। इस समिति का कार्य सदक की प्रक्रिया तथा लायें-लाही स्वासन के नियमों की जीव करना है, जिससे सदक की प्रक्रिया तथा कार्यवाही स्वासन में साकास्त्र स्थापन विया जा सकें।

मारतीय संसद ये विभिन्न समितियों की भूमिका का भ्रष्ययन वरने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि सबद ये एक सुसंगठित तथा प्रमावशाली दल के भ्रमाव मे समितियों कार्यपालिका पर सतुनित तथा जनतात्रिक रूप से प्रमाव पहुँचाने में सहायक हुई है।

### ससदीय प्रश्न

ससद के हाथों में, सरकार पर नियन्त्रण स्थापित रखने के लिए दूसरा साधारण साधन ससदीय प्रकानों के रूप में हैं। ससद के सदस्यों को प्रतिमा से उनके दिशागों से सबधित यामलों पर प्रकृत पूछने का अधिकार हैं। प्रमृत, ससदीय जनतत्र का एक मुल्यबान साधन हैं। "प्रमृत समय एक तेज प्रकृत वाल सिम्प के समान हैं, जिसका प्रकाश वाल स्थाप हैं। महु एक स्वस्य सदरीय हैं जो मंत्रियों को कार्य करने के लिए बाध्य करता है, जिससे के किसी मी दिन सदन के किसी भी कोने से उठाये यय आलीबनात्मक प्रकृतों तथा प्रतिक्ति प्रप्तान के स्थाप स्थाप हैं। महु सहस्य के सदस्यों को वह प्रवस्त देता है, जिससे हिए साम के स्वस्त के स्वस्त के स्वस्त के सहस्यों को वह प्रवस्त देता है, जिससे हिए प्रमृत साम के स्वस्त के साम के साम साम कर सकें। यह सदन के सदस्यों को वह प्रवस्त देता है, जिससे द्वार म केवल जानकारी हासिल की जा सकती है, परन्तु सत्ता के दुरुर्योग, इसकी प्रसन्तता तथा जानकारी की प्रदेश प्रतिचित्र को प्रपन्ती मागों के लिए के प्रीष्टत नागरिक के लिए को अपने प्रतिचित्र को प्रपन्ती मागों के लिए प्रति प्रत्न के लिए कहता है, जसने प्रतिचित्र को प्रपन्ती मागों के लिए प्रति प्रतिच को स्वपन स्ता है। "

सत्तद में प्रत्येक दिन बैठक के पहले घंटे से प्रक्रन पूछे जाते है। प्रक्रन पूछने के लिए मंत्रालयों को छीन वर्गों में बॉट दिया गया है। प्रत्येक बर्ग के सबंब में प्रक्रम पूछने के लिए सप्ताह में दिन निर्धारित किये यदे हैं। ये तीन वर्ग निम्मा निखित है:—

क-विदेशी मामले, वैज्ञानिक धनुसवान, वाणिज्य-उद्योग कानून तथा पुनर्वास 1

ल-कृपि, मावागमन, खाद्य, रेसवे, खदान, भौर शक्ति।

ग-प्रति रक्षा, शिक्षा, वित्त, स्वास्च्य, गृह-मामले, व सूचना-प्रसार ।

इस तरह प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विषयो पर सप्ताह से प्रस्त दुखे जा सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दो दिन की पूर्व सुचना देना प्रावश्यक है। सदस्यो को, सदन के नियमों के अनुवार अविरिक्त प्रश्न पूछने का जी अधिकार है। प्रश्न,

१. एम॰ पी॰ शर्मा—'व गर्वमेण्ट झॉफ व इण्डियन रिपस्लिक', १९६१ पृ॰ रैन्ह ।

यदि नियमानुसार नही पूछ गये हैं तो इननो सदन की कार्यवाही से घलग निया भा सकता है। सामान्यत प्रकोत्तर मित्रयों के सुधीन अधिकारियों द्वारा तैयार निये जाते

सामान्यत प्रशासर प्रांचम के यथान श्राधकाशिया द्वारा तमार नियं आंत है सौर मनी उत्तरों को यहन से पड़ देते हैं। यदि स्पष्ट या सतीपजनक उत्तर नहीं दिया जाता है तो कोई नी सदस्य प्रतिरिक्त करन पूछ सकता है। मत मनी द्वारा सत्तर तराय निसी भी महत्वपूर्ण नियंत पर जतता ना स्पान प्रानित कर सकते हैं। मन न केवल मनियों को सदस्य पर जतता ना स्पान प्रामानीय प्रक्रिकारियों को भी तत्त ते तथा कार्य प्रमुख होने के लिए बाध्य करते हैं। यदि हुए रीदस्ते क क्षेत्र करता कार्य पर प्रमुख पर प्रकार करते हैं। यदि हुए रीदस्ते क क्षेत्र क्षेत्र के स्वत्य कार्य करते हैं। यदि हुए रीदस्ते क क्षेत्र के स्वत्य कार्य करते हैं। यदि हुए रीदस्ते क क्षेत्र क्षेत्र करते हैं। यदि हुए रीदस्ते क क्षेत्र करते हैं। यदि स्वत्य करते हैं। यदि स्वत्य करते हैं। यदि स्वत्य प्रमुख क्षेत्र मार्ग क्षाचित्र मन का बर है। "

यीपचारिक बृद्धि से समयीय प्रान का उद्देश्य मणियों से जानकारी हासित करना है। परचु वास्तक म प्रान को इस तरह रखा जाता है, कि विषक्षी दक की सरकार को गोजा दिखाते हुए कोई पाननीतिक उपकारित हो, या निवसे प्रशासकीय बुदाई तमा बता के दुरपयोग पर क्यान केंद्रित हो। प्रत समयीय प्रान का यह स्वरूप उपने एक तेज वाद काले प्रत्य के क्य म प्रश्त है, जिसका उपयोग विश्वीय का प्रावस्थिक कर करते हैं।

#### ससदीय प्रस्ताव

ससद में विनिन्न विषयों पर प्रस्ताव पारित करके सरकार को प्रमाधित किया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्ता से निन्न हैं, और उन्ने प्रभावकारी नहीं होति हैं। 'स्पताव प्रमाने से वी तरह से निन्न होते हैं। व्यव्येष्य ये प्रकार के समान प्रतिदेश उपयोग में नहीं आदे हैं। ब्रायप्टें सदस्य विषेषक के समान प्रतादान हारा दक्को प्राप्तमित्ता से जाती हैं। द्वितीय, इनका वहेंग्य वाककारी हासित करना नहीं पारचु सालार को कार्य करने वा मुख्याव देना है।' प्रस्ताव प्राप्तित करने के विए भी पूर्व भूतना देना धात्मकक है। प्रसानों को स्वीष्टत होने का प्रभे यह नहीं है कि सरवार इनको मान्यदा दे, क्यांकि वास्त्रव ये ये गुमावा के रूप म ही सेते हैं।

सतद सरकार पर स्थपन प्रस्ताव पारित कर प्रश्नाव डाल सकती है ! इन प्रस्तावी का उद्देश्य, सामान्य कार्यों को छोडकर किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय

१ एच० गेटस्केल, हेनसार्ड, घवट ० २१,१६४७ ।

<sup>&#</sup>x27; - २ एम० यो० शर्मा—'यूबोंक्त वुस्तक', पृ० १८६।

पर विचार-विसर्ग करना होता है। स्थान प्रस्ताव, प्रश्न—समय समाप्त होने के तत्काल प्रश्नात् किसी भी दिन रखा जा सकता है। तथापि, जो प्रस्ताव विसी सार्वजनिक सहत्व के विषय से सविधत नहीं हैं, या किसी तरह स्पप्ट नहीं है, या सन्य सेशाधिकार से हैं या विसी न्यायालय वे समझ हैं, वे सदन वे अध्यक्ष द्वारा ध्रम्बीजन कर दिये जाते हैं।

स्थान प्रस्ताव ना सदन हारा पारित होना सरकार वे विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित होना है। भ्रतपुर्व सरकार प्राण प्रयत्न व रती है वि स्थान प्रस्ताव पर मनवान न हो।

## ससदीय वहस

ससद मे यहल एक प्रन्य महत्वपूर्ण सायन है, जिसवें द्वारा ससद सरकार पर नियन्त्रण करती है। बहस द्वारा ससद सरकार तथा प्रवासन की नीतियों एव नायों के सबस में आनवारी प्राप्त वरती है। बहस वा महत्व केवल उस समय होता है, जब ससद के समझ किसी नयी विधि के निर्माण या पुरानी विधि में संघोधन या स्पानीत के लिए वियेवन है। बस्तुस्थित यह है हि, प्राप्त सावेजिक महत्व के विषयों पर वहस होती है। 'एव तरह से हम कह सबते है कि ससद के सदन प्राप्त किसी न किसी विषय पर बहस वरते है । विधेयन के प्रयेक उपवत्प, वजट के मुख्य हिस्से, समा प्रत्येव परस्ताव पर विवार-विमर्ण, वास्तव में बहस ही है। एक मुस्पट ससदीय परम्परा के अनुसार प्रधान मंत्री कभी मी विपयी वर वहस करते के निवेदन को प्रस्वीहत नहीं करता है हिसी विषय पर वहस करते के निवेदन को प्रस्वीहत नहीं करता है हिसी विषय पर वहस करते के निवेदन को प्रस्वीहत नहीं करता है हिसी विषय पर वहस करते के निवेदन को प्रस्वीहत नहीं करता है है।

इस प्रवार बहस वा महत्व यह है वि इसके द्वारा सरकार को प्राप्ती नीति के किसी पहलू के स्वर्धकरण और बाबाव करने के लिए वाधित होना पडता है। प्रार उसवो उक्त विवय पर जिन्न मतो को मापने में सहायता मिलती है। "इनके हारा बिपसी कि निर्मत निर्मत के साथ कर करने मुसार के सिए राजनातम्ब मुक्ताव दे सकते है। अदनो म हुए विवार-विमर्थ प्रेम साथ जनता के समक्ष आते हैं। अदनो म हुए विवार-विमर्थ प्रेम साथ जनता के समक्ष आते हैं। जिससे उक्त विषय पर जनमत का निर्माण होता है।" व

ससद में यहल का सबसे महत्वपूर्ण विषय बजट है। जब ससद विचार विमर्श नरने ने दौरान विभिन्न विभागे की वितीय मागों की कडी जांच नरती है, उस वक्त प्रत्येत प्रशासकीय विभागों की नीतियों तथा कार्यों का ससद की निरीक्षण नरने ना भ्रवसर प्राप्त होता है।

१. एम० पी० शर्मा—'पूर्वोक्त पुस्तक', पृ० १६० । २ वही प्र० १६० ।

श्रतएव बजट पर बहुत के समय ग्रत्येक मंत्रानय के कार्य को ससद की कड़ी नगर के समक्ष लाया जाता है। सक्षेत्र के, प्रकारो तथा बहुत हारा, प्रशासन या निरुद्ध रूप सम्पन्न पुनरीका होता है। "होटे-होटे शिव्य के प्रसासिक महरून-पूर्ण परिजास होते हैं। क्योंकि जिपसी दस्तो द्वारा सारा समय, कार्यपालिका की दुनेजासो पर दुख्यित करने में व्यतीत होता है धीर यदि एक नार यह विदित हो जोशे तो विश्वपी तथा उनका ज्यायोग निरुद्ध करते हैं।"

खतः जैसा धन्ते एटली का कचन है- 'जिरे विचार में सदन में प्रान का समय बालाविक जनतज का सर्वोक्षम खदाहरण है- अनियों से प्रान पूछने का, स्रोत संविक्तिक रूप से सदस में पूछे गये प्रानो का प्रमाद खारी लोकसेवा की सहके करना है। ''र

#### ससद की राष्ट्रपति के संबंध मे शक्तियाँ

मारतीय सर्विधान द्वारा ससद को, राष्ट्रपति घर नियन्त्रण के लिए कतियम शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। राष्ट्रपति के सर्वेष में ससद की निम्नलिजित शक्तियाँ है •—

१—राज्य विधान समाधो के निवांचित सदस्यों के साथ मिलकर ससद मि निवांचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निवांचक मण्डल का गठन होता है। उपराद्यति का निवांचन ससद के थोनो सदनो द्वारा किया जाता है।

२—राज्यति पर ध्युण्येद ६१ के अन्तर्गत महानियोग नयाकर ससद उसे परच्युत कर सकती है। परन्यु इस सक्य में, अमेर देशा वा चुका है, एक मार्गर, मृद्धि यह है कि जब ससद का सन नहीं हो रहा है और यदि ऐसे समय राज्यति समियान का उल्लयन करता है तो राज्यति पर महानियोग सनाम समय नहीं होगा क्योंकि सबद सज में नहीं है और ससद के प्रथिवान सामजित करते

को प्रिमित्तर नेवल राष्ट्रपति को हो है। ३ — विधि-निर्माण-मार्ग मुख्य का से सबद का ही उत्तरदाधित है, परन्तु कब समद के दोनो मदनो द्वारा विधेयक पारित होता है। तब उसे राष्ट्रपति की सहमति के विष में जा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर बालो अपनी सहमति

१. एन० वी० गाडमिल, सकाउन्ट्रेबिलिटि झाफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन व इध्डियन जनरल झाफ व पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, न्यू देहली झाथ—१ न० ३, प० १६६।

२. सी॰ एटली—पिसविल सर्विस इन ब्रिटेन एण्ड फ्रान्स, सम्पादित, डब्ल्यु ए॰ रावसन द्वारा—१९५६. प० २० । देता है या सप्तद के पुर्नावचार के लिए वाषिस मेजता है । राष्ट्रपति के निषेधा-धिकार के बावजूद भी सप्तद हो सर्वोच्च है ।

४—प्रतृच्देर १२३ वे प्रत्यवंत जब ससद प्रिष्वेशन मे नही है, तब राष्ट्रपति प्रावश्वता होने पर प्रध्यादेश जारी नर सक्वा है। राष्ट्रपति ने प्रध्यादेश सामू नरते वे प्राप्तादेश कारी नर सक्वा है। राष्ट्रपति ने प्रध्यादेश सामू नरते वे प्राप्तादेश राष्ट्रपति ने प्रध्यादेश सामू नरते वे प्राप्तादेश सामू नित्त के रूप मे है, जिसके हारा सबद प्रथमी बँठक मे प्रध्यादेश को समाप्त गर सकती है। यह सत्य है कि राष्ट्रपति नी प्रध्यादेश जारी नरते भी शनित भी इत्यादेश को रोपे ने ने नित्त साम्य को कुछ शक्ति है परन्तु पह स्पय्ट है कि यह प्रध्यात नही है, नथीन सबद ने स्थापित राजने का प्रधिकतम समय हा माह है प्रीर इस दृष्टि से एक प्रध्यादेश का नार्यवाल ६ माह ना हो सकता है। इस प्रथमित समय मे कार्यकाल समय हा माह है प्रीर इस दृष्टि से एक प्रध्यादेश का नार्यकाल द माह ना हो सकता है। इस प्रथमित साम्य में कार्यकाल में प्रश्नी मी देश में जहाँ सितात सिवधान तमा ससदीय सरकार है खहाँ राष्ट्राध्यक्ष नो इस तरह नी प्रदृत्य वानतायी प्राप्त नहीं हैं।"

राष्ट्रपति द्वारा सध्यादेश जारी करने शी शक्ति वे माध्यम से, यार्यपालिका स्रतीमित शक्तियो ना अपहरण नर सकती है।

इता जातिया गर अगृहण गर कण्या है।

इता जाति की तुलना, भारत सरकार वे अधिनियम १६१६ तया १६३५ वे
धन्तर्गत गवनर जनरल की ध्रध्यादेश जारी करने की वास्ति से की जा तकती है,
जिसने विदिश राज म वार्म पालिका की धरवन्त वास्तिवाली बनाया था। यद्यापि
यह सत्य है कि मारत ने सवियान के धन्तर्यत राष्ट्रपति, मंत्री मण्डल की सताहानुसार ही धन्यादेश जारी करेगा, परन्तु सवियान मे कोई प्रभावदूर्ण प्राश्यासन
मही है कि कार्यपालिका इस वास्ति का दुक्ययोग नहीं करेगी। केवल राष्ट्रपति
ही इस यात का निर्णाय है कि किन कारणों के वस धन्यादेश जारी विया
जाये। स्थायालम, राष्ट्रपति के इस वार्म की उपर्युक्ता के प्रशन की जीच नहीं
कर सकते हैं न हो इस वात की भी वि धन्यादेश जारी वरने ने लिए धायश्यकतों
भी भी या नहीं भी। न्यायालय केवल इस प्रमन की ही जोच वर सकते हैं कि
धन्यादेश सविधान द्वारा प्रदस राष्ट्रपति को वास्ति ने धनुतार लागू किया गया है
ध्रयवा नहीं।

सिवयान समा में बाद-विवाद के दौरान डा० ग्रम्बेटकर ने, यह प्रश्न रखनर, राष्ट्रपति नी ग्रम्यादेश जारी करने की शक्ति का ग्रीचित्य बतलाने का प्रयत्न

५ ए० बी० लाल-'द इण्डियन पार्लियामेन्ट, १९५६, पृ० २३।

किया, "अन परिमित्रवियों की नरूपता करने में कोई कठियाई नहीं हो समनी है, जब बतेंगन कानून किसी धकरमात एवं तत्तराह रूप से निर्मित परिस्थिति के लिए प्रयान न हो। कार्यपत्तिका तब क्या करें ? ऐती प्रणीर तमस्या का मुनावला करना होगा, और मेरे सतानुधार इस समस्या का केवल यही समापान है कि पाएदार्थित को उस्त समस्या का सामना करने के लिए कानून लागू करने की शक्त समस्या का सामना करने के लिए कानून लागू करने की शक्त स्वरूप की स्वरूप कार्यप्रति हो है।"

संविधान मे इस प्रकार के प्रावधानों का समाय जनतम के लिए हानिकारक है। भी समतक स्वयम अव्यागार (कोक समा के एक स्वयस) ने "मारत में विधि समा जनतम", विध्या पर १९४६ में माध्या देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति कि सम्पादिक ला। करने को सकि स्वयदीय पद्धति में निषेधारसक है।"

५—विंद राष्ट्रवित शतुष्ट है कि भारत की मुख्या की, युद्ध या बाह्य बाहमभ्य प्राप्तिक व्यवस्था की खतरा है, ती बहु सविवान के स्वत्येद १५१ (१) के स्वत्येत, प्राप्तुवेद कि स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत के स्वत्येत स्वत्य स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्य स्वत्य

१ वी० झार० ग्रम्बेदकर, कान्स्टीट्युएस्ट श्रसेम्बली डिवेट्स भाग म, प्र० २१३।

२. ए० श्रव्यार-'ट्रिब्यून' ग्रम्बाला, फरवरी ६, १६५६ ।

वालीन स्थिति में, ऐसा प्रतीत होता है वि सविधान स्थिति का सामना वरने वे लिए राष्ट्रपति पर निर्मेर है।

तथापि, सविधान सभा के वाद-विवादो म थी मह्तादी स्वामी प्रव्यर ने यह स्पष्ट विया वि 'सविधान में, वास्तव म, 'राष्ट्रपति' बब्द का तात्पर्य मंभी मण्डल, (वास्तविन कार्यपालिका) से हैं, जो लोकसभा ने प्रति उत्तरदायी हें "2 इस विषय पर सविधान में विद्यामान क्षतियय शूटियो वो ध्यान में रखना चाहिय।

बन्ब्देद ३४२ (२) वे बनुसार राष्ट्रपति हारा की गई मापत्कालीन घोषणा दो माह के बाद समाप्त हो जावेगी, यदि इसी वीच ससद के दोनो सदनो द्वारा वह स्वीवृत नहीं होती है। वदि घोषणा ऐसे समय हुई है, जब लोगसमा निघ-टित हो चुकी है या होने जा रही है, तब घोषणा के लिए दो माह के ग्रन्दर राज्यसमा की स्वीकृति प्राप्त फरना ग्रावश्यक है भीर तत्पश्चात नई लोकसभा की बैठक के सीस दिन के ग्रन्दर उसकी स्वीकृति होना मी भावश्यक है । यदि नई लोकसमा द्वारा घोषणा ग्रस्तीकृत की जाती है तो लोकसमा की बैठक के तीस दिन के बाद घोषणा स्वत समाप्त हो जायेगी । सविधान के अनुसार कार्यपालिका को ससद के समक्ष म्रापत्वालीन घोषणा प्रस्तुत वारने वे लिए, दो माह की लम्बी प्रविध दी गई है। जहाँ तक प्रापत्कालीन शवितयों को नार्यपालिका में निहित करने वा प्रश्न है, इसके सबध मे कोई ब्रापित नहीं है, परन्तु यह ब्रत्यावश्यक है कि इसके साथ ही इस विषय पर ससद की भूमिना को और अधिक प्रत्यक्ष, निकट तथा प्रमावशाली करना चाहिये था, जिससे आपत्यालीन शक्तियो के कार्यपालिका द्वारा उपयोग पर ससद वास्तविक रूप से अक्ष रख सक्ती है। इंग्लैंग्ड में कार्य-पालिका ग्रापत्कालीन स्थिति नी घोषणा करती है और तत्पश्चात् ससद सहमति -प्रदत्त नरती है, परन्तु बिटिय पद्धति, मारतीय पद्धति, से महत्वपूर्ण रूप मे मिल्ल है। इन्लैण्ड म प्रापत्कालीन घोषणा वा तात्वयं ससद वा स्वत पाँच दिनो मे भामितत होता है जबकि मारत में घोषणा के ससद के समक्ष प्रस्तुत होते के लिए दो माह तक रोका रखा जा सकता है। धत यह स्पष्ट है कि ससद का कार्यपालिका पर, प्रापत्कालीन घोषणा की दृष्टि से, अपर्याप्त नियत्रण है नयोरि यह तत्काल सथा प्रत्यक्ष नहीं है। इसका उपचार यह है कि ससद, विशेषकर लोकसमा, को भीर ग्रधिक शक्तिशाली बनाया जाये । जब तक सदन (लोबसमा) सत्र मे है भीर वहमत इसका विरोध करता है, कोई राष्ट्रपति सविधान वे अपूर्वेद ३५२ का

१ के॰ बी॰ राव॰—'पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया, १६६१, पृ० २३१।

२ ए० के भव्यर,--'कान्स्टीट्युएन्ट झसेम्बली डिवेट्स भाग-६,पृ० ५४५-४६।

भारतीय शासन ग्रीर राजनीति

दृष्पयोग नहीं कर सकता है और, यदि, सविधान निर्माताओं द्वारा पूर्व में, ही कूछ सावधानी के उपाय, जो निम्नलिखित हैं, विये जाते तो उचित होता।

208

एक-राष्ट्रपति की लोक्समा को भ्रामत्रित, स्थायत एव विघटन करने की गहिनयाँ ग्रापतकालीन समय भ स्थ्यति रह ।

दो-यदि ससद सत्र म नहीं है तो ऐसे समय में आपत्वालीन घोषणा होने से

ससद की बैठक सात दिन के चन्दर स्वत चामवित हो . तीय-यदि ऐसे धापतनाक्षीन समय म लोकसमा विषटित है भीर भाग भुनाव

सम्पत्र नहीं हुए हैं तो पुरानी सोवसमा स्वत पुन प्रमावी हो । मविष्य मे ऐसी भाकत्मिक स्थिति की समावना को कि राष्ट्रपति लोकसमा की मग करके प्रापत-

कालीन घोषणा करे, दूर करने के लिए यह प्रावधान भावश्यक है, चार-लीक्सभा को धपने को स्थवित करने, या घपना कार्यकाल बडाने का

मंपिकार होना चाहिये। उपर्युक्त प्रावधान सविधान के सापत्नालीन प्रावधानी का दुरूपयोग रोकने एव ससद की सार्वभौभिकता स्थायी रखने के लिए सविधान निर्मान तामी की इच्छा के भीर अधिक सनकल होये।

६—राष्ट्रपति मारतीय सेनाघो का सेनापति है। बनुक्छेद ५३ (२) के प्रनुसार राष्ट्रपति मारतीय सेनाको का सर्वोक्त प्रधिकारी है। परन्तु इस हैसियत मे राष्ट्र पति को ससद द्वारा निमित विजि के अनुसार कार्य करने होंगे। अनुक्षेद २४६ के अनुसार समय को, सातवी अनुनुवी में उल्लिखित प्रयम सुवी में दिये हुए सारे बियमो पर विधि निर्माण करने वा अधिकार है। इस सूची (सम सूची) म विषय क्रमाक १,२ भीर १५ मारतीय सेना युद्ध तथा मान्ति विषयो से सविधत हैं। इंग्लैंग्ड में यद भीयणा तथा शान्ति स्यापित करने का श्रधिकार कार्यपालिका का है, परन्तु भारत में राष्ट्रपति बिना ससद नी धनुमति के था बिना ससद

की प्रतुमति के पूर्वज्ञान के न युद्ध की बोषणा कर सकता है, न ही मारतीय सैनामी का उपयोग कर सकता है। श्रतएव राष्ट्रपति मारतीय सेनाष्यक्ष होने पर मी स्वततापूर्वक ससद की इच्छा के विरद्ध, सैम्य शक्ति का उपयोग नहीं कर संक्ता है। समीय बार्यपालिका तथा ससद के विभिन्न सम्बन्धों का सैद्रान्तिक ग्राधार पर मध्ययन करने के पत्रचात्, हमारे समक्ष प्रक्त है कि मारत के सविधान के मन्तर्गत

ध्यवहारिक दिष्ट से सधीय नार्यंपालिका तथा संसद में नया संस्वन्ध हैं ? व्यावहारिक दिन्द से सधीय कार्यपालिका तथा ससद के सबध

सैदान्तिक दरिट से समीय कार्यपालिका तथा ससद के विभिन्न सम्बन्धो का

विश्लेषण करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि ससद ऋत्यन्त शक्तिशाली है

भीर कार्यपालिका सम्पूर्ण रूप से ससद के सचीन है। परन्तु, ससदीय पद्धित की कार्यप्रणाली की व्यारपा वे फलस्वरूप, कित्यय ऐसे तरब घ्यान मे रसे जा सकते हैं। फ़लस्वरूप ससदीय पद्धित में कार्यप्रणाली की व्यारपा वे फलस्वरूप, कित्यय ऐसे तरब घ्यान मे रसे जा सकते है। फ़लस्वरूप ससदीय पद्धित में कार्यपाणिका व्यवस्थापिका वे सम्वय्यो सिस्पति चिन्दुत पत्तर वर्ष है। १६वी सताव्यी में विशेषकर रिटेन की ससदीय प्रणाली की दृष्टि से, ससद वी प्रमुखता पर वल दिया जाता था, किन्तु २०वी शताव्यी में, मंत्री मण्डल की ससीमित सत्तिया प्राय चर्चा का विषय है। इसी विषय वे सदसे में प्रोक भीरित जीत्या वा वचन है "शादित म ससद वे एक बाह्य दिखाबट के समान बतलाया पया है जो वरित्यता से, एक सिक्तासी निर्दुश तत्र को दिया सहता है। इस मत के लिए जेत कुछ तो वाग्नेस वल की गरिक्ताता के सारित किता है। तथाचि यह बतलाना उपयोगी होगा कि मंत्री मण्डल की निरद्भाता के सारोप से, मारत के बाहर भी (कीय) सुपर्यिच हैं, वे लीग जिनका यह दियार या कि स्वतन का सर्व (सरकारी) नार्यो वे सारिकााली निर्यतन ना प्रन्त होगा, उनको यह सीवला होगा कि बिटस ससदीय प्रणाली में सत्तिशाली सरकारो को प्रीतसाहन मिलता है। "

मारत में केन्द्र में, सबदीय कार्यपालिका (मशी मण्डल) की स्थिति प्रत्यस्त्र माकिशाली है। भत्रपुत्र कार्यपालिका तथा ससद के सम्बन्धों का व्यवहारिक दृष्टि से विस्त्रपण करते हुए हमारा उद्देश्य गर्हों पर उन तस्त्रों का प्रध्ययन करना है, जिनके कलस्वक्ष्य वास्त्रविक कार्यपालिका (मशी मण्डल) मारतीय राजनीतिक प्रणासी में, एक शतिगाली सस्या हो गई है।

## ससद के सबध में भन्नी मण्डल की शक्तियाँ

ससदीय प्रणाली में मंत्री मण्डल ससद के निचले सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मारतीय सविधान के अनुवार मत्रियों को ससद का सदस्य होना भावश्यक है। माधुनिक समय में मंत्री मण्डल ससदीय प्रणाली में वास्तविक कार्य-पातिका के रूप में एक अत्यन्त शक्तिशाली सस्था बन गया है।

मत्रो मण्डल के झत्यन्त शांकिशासी होने पर मी, ससद केवल एक शक्तिविहीत सस्या नहीं रह गई है। मारतीय सविधान के लागू होने के पश्चातु, नारतीय ससदीय पढ़ित की लड़ो को शक्तिशाली करने में एव सरकार के एक उपयोगी प्रम के रूप में कार्य करने में समय-समय पर ससद ने निश्चित हो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस्तैण्ड में भी ससद के प्रत्यन्त सक्तिशाली तथा उपयोगी सस्या होने

१. डब्ल्यु एच० मोरिस जोन्स-पार्लियामेन्ट इन इण्डिया, १९५७ पृ० ३२८ ।

२०६ भारतीय शासन भीर राजनीति

पर मी, मंत्री मध्येल की व्यक्तियों में वृद्धि हुई है। यद जिटिश मंत्री मण्डल के लिए यह कहा जाता है कि यह निर्मुख हो यथा है। "जब इसकी बहुमत प्राप्त

है, इसनी स्थिति विज्ञान्तियो हारा नियतित निरमुश्वता है।" । सारत में मंत्री मण्डल की शक्तियों य वृद्धि के निम्नावित कारण हैं।

१—मारत में, कावेस बन को १९७१ फरपरी-मार्च के मध्यानिय चुनाव में सोनसमा म मारी बहुमत प्रांच हुआ है। एक रावनीतिय दल के रण में नाग्रेस इस ने धरने साथता पर वा कप पारण सर निया है, तिसना पर मार्थ में इस नियाने साथ में साथता पर वा कप पारण मर निया है। ता एवं के प्रांच मार्थ में साथता एक ने निया होना पर निर्मा रहित पर निर्मा का एवं में साथता है। डा० एयं वर्ध को मार्थ का निया में में मार्थ साथता का एवं सामितियों में परी पर मार्थ सामितियों में एवं साथता का सामितियों में साथता साथता मार्थ में महार सामितियों में, तथा साथारण साथता में में परी पर निर्मा पर मार्थ करने में साथ साथ साथता साथता

दत में भनुतासन की कठोरता के परिचाम स्वरूप सदस्यों को प्राप्ती सरकार का ससद में मांता-मूंटकर धनुनोदन के विद्वान्त से, ससद में, सामान्य तीर से सरकार के पदा न बहुमत बना पहला है। इसी कारण वन श्रीतासबहादुर साव्यों पद मीमती गाने ने सरकारों के विवद अविकास प्रत्याद नाये गये, दकीय प्रत्यासन के कारण प्राप्त हुए बहुमत से वह मस्तावों को विकास कर दिया गया। सत्योग प्रमाती में दकीय बहुबात के कारणो तथा परिचामों पर मो। लास्की

ब्रिटेन में समभा जाता है, बावन्त उत्तम है ।"2

सदुसासन के कारण प्रापंत हुए बहुकत से इस प्रतास का स्वक्त कर दिया पार] । सत्तरीय प्रमाणी में बढ़ीस प्रमुखानक के कारणों तथा परिणामी पर प्रते कासकी के बिदिश क्षत्रीय पद्मित के स्वकारत करियद विचारों को, जिन्हें समान क्या से मारसीय पद्मित भो उपयोगिता-मुक्क लागू किया जा सकता है, ध्यान में रखना कामवासक होगा ।

'दल म मुन्नासन की कंठोरता म बृद्धि के कारण, साधारण नहीं हैं। कुछ माना मं, मह इस तथ्य के कारण हैं कि धायुकित किरने के लिए विस्तृत रातीय कगठन में आवस्यकता है। जुख भागा में (समान के कार्यों में) राज्य झारा हस्त-क्षेत्र की आवस्यकता के चन्नास्कर सक्तर से सरकारी कार्यों में भी बृद्धि हुई है, मीर यदि उन नार्यों को समय में ही करना है तो और अधिक क्षेत्रेय दरीय मनुगासन आवस्यक है। कुछ माना में कवाचित इससिए मी कि धायुनिक मतदाताराम, सिद्धानते पर स्पतिश्व के सन्दर्श में विचार करते हैं, में सदस्थों का निर्वाचन, उनके स्वय की मरीसा उनके नेताओं के कारण अधिक करते हैं। सम्पूर्ण दरीय स्वयनसा

१. म्रार० मूर, हाउ निटेन इच गवर्नड्, १६३८ पृ० ८१ । २. एम० पी० सर्मा—'पुर्वोवत पुस्तक, पृ० २१४ ।

ग्रावश्यक रूप से व्यावसायिक हो गई है । श्रोर उसके कार्यों के विस्तार के कारण इसको ऐसे धनुवासन की श्रावश्यकता है जो कि सैनिक श्रनुशासन के समान है।"ी

मारत में मंत्री मण्डल की स्थिति के श्वतिज्ञाली हो जान का एक कारण यही है कि दलीय अनुपासन की कठोरता के कारण, मंत्री मण्डल को ससद में सामान्यत बहुमत प्राप्त रहता है।

२—मनी मण्टल की शनितकाली स्थिति का एक खत्य कारण सामूह्त उत्तर-दायित्व का सिद्धान्त है। मनी मण्डल के एक इकाई के रूप में वार्य करने पर ही सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सफलतापूर्वक वार्यान्तित विद्या जा सकता है। लोकसान के प्रति मनी मण्डल के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त द्वारा केवल मनी मण्डल में एकता बनी रहती है, पट्यु इसी से प्राप्त बहुमत के माधार पर मनी-मण्डल सहद की वार्यवाई या निर्देशन तथा नियन्त्र कर सकता है।

३—मत्री मण्डल की शक्तिशाली स्थिति का एक श्रन्य महत्वपूर्ण कारण ससद को मग करवाने भी उसको शक्ति है। ससदात्मक पद्धति म सामान्यत राष्टा-ध्यक्ष प्रधान मनी के परामर्शानुसार ही ससद के निचले सदन लोक्सभा को मग कर सकता है। इंग्लैंग्ड मे बदि मंत्री मण्डल के विरद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो चुना है तो उसको अपना इस्तीफा देना बावश्यक है। परन्तु ससदारमक पद्धति की एक सस्पट्ट परम्परा के अनुसार अपना इस्तीफा देने के पूर्व प्रधान मंत्री ससद ने निचले सदन को मग कराने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है, जिससे भाम-चुनाव करवाये जा सकें। श्राम चुनाव से यह ज्ञात विया जाता है कि वास्तव मे, मतदातागण, ससद के मनी मण्डल के विरद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी मनी मण्डल के समर्थंक है या नहीं । सामान्यत , प्रवान मनी के प्रमुरोध पर सम्राट् ससद को मग करता है। तत्पश्चात्, यदि धाम-चुनाव म मत्री मण्डल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो बहुपुन, सत्तारूउ हो जावेगा, प्रत्यया ननी मण्डल को इस्तीपा देना ही होगा । भारत म मी चूंकि सविधान के अन्तर्गत ससदारमन पद्धति स्थापित की गई है, इसलिए उपर्युक्त परम्परा को मान्यता दी गई है। सविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को लोकसमा को मग करने का अधिकार है। विन्तु सामान्यत राष्ट्रपति इस ग्रविकार का उपयोग प्रधान मन्नो की सलाह के अनुसार ही करेगा ।

संबदात्मक प्रणाली में, संबद के निकले सदन को मम करने के लिए प्रधान मनी का राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार निक्क्य ही ऐसा एक प्रमानवाली सापन है, जिससे मनी मण्डल निचले सदन पर नियन्त्रण करता है। यदि ससद के

१. एच॰ लास्की, 'पार्लियामेण्ट-गर्वमेन्ट इन इण्डिया' १६३६, पृ० ७४।

भारतीय भागन भीर राजनीति

निचति सदन को मंत्री मण्डल के विरुद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव पारित करने का ग्रवि-कार है तो मत्री मण्डल को राष्ट्रपति को सदन भग कराने की सलाह दैने का श्रीधकार है। ससदात्मक प्रणाली के इतिहास के बध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट हो जायेगा कि मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास श्रस्ताव पारित करना एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जैसा देखा जा चुका है, कछोर दलीय अनुशासन के कारण मंत्री मण्डल को प्राय बहुमन ना समर्थन रहता है। ऐसी स्थिति में यदि मंत्री संग्रहत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का प्रयन्त किया जाता है, ती मत्री मण्डल इमना बदला सदन को मण नरने की सलाह देवर चुना सकता है, क्योंकि समद के बार होने के परिणाम कनियम सदस्यों के लिए बात्मन हानिकारक सिद्ध हो सकत हैं ! उनको जात है कि सप्तद के मग होने के पञ्चात उनको पून. धाम-बनाव का सामना करना होगा, जिसम उनकी समय और घन व्यय करना होगा, और इसके उपरान्त यह भी सम्मव है कि वे निवांचित न हो सकें। परि-यान स्वरूप, ससद को अग करने की चेतावनी, सदस्या पर एक महत्वपूर्ण अनुश है जिससे मत्री मण्डल ने विरुद्ध उनने नार्य नरने पर रोक लगती है। मारतवर्ष म परवरी मार्च १६७१ म मध्याविधि बाय-चुनाम कराने के लिए प्रधान मनी श्रीमती गामी भी सलाह पर राष्ट्रपनि श्री बी॰ वी॰ पिरि महोदय ने दिसम्बर १६७० में ससद को मन किया। बैसे तो विरोधी दल समद मग होन के पूर्व बारम्बार भ्राम-बनाद की मांग कर पह थे, दिन्तु जब ससद की प्रधान मंत्री की सलाह से राज्यति ने भ्राम-मुनाव वराने के लिए मग किया तो विरोधी दलों ने एक समा राग भलापना आरम्भ निया कि प्रधानमंत्री की संसद के मग कराने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने ना ग्रायकार नहीं था। विरोधी दलों की इस विचित्र मनोवृत्ति का कारण यह था कि धाम-कृताव बाहते हुए भी उनको चुनाव का सब था, बद्धपि चुनाव के पूर्व अपने वननव्यों से उन्होंने क्षत्रा धासा ध्यक्त की हि श्रीमती गांधी की नयी कांग्रेस को वे झासानी से पराजित करेंगे। इस मनो-कृति के कारण जब चुनाव की वास्तविकता का उनको सामना करना पदा तो चन्होंने प्रयान मंत्री घर प्रहार करना प्रारम्म किये कि प्रयान मंत्री की राष्ट्रपति द्वारा ससद मग नरवाने का कोई अधिकार नहीं या । प्रधान-मनी द्वारा मसद की मन करने से लिए राष्ट्रपति को दी गई सलाह का श्रीनित्य विशेषकर इसमें है कि ससद को मग करने का उद्देश्य धाम-बुनाब समपन्न कराके महदाहसी की इच्छा ज्ञात करना था, जिसके आधार पर नयी सरकार की स्थापना की जा सके। ससदीय प्रणाली में, सरकार के प्रति मतदातागण की इच्छा को माम-चुनाद के माध्यम से जात करने के अधिकार के सबध में कोई मत्रमेंद नहीं हो सकता है। भत्रएव यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री का, साम-चुनाव करवान के लिए राष्ट्रपति को ससद अस करने की सलाह देने का अधिकार तथा कठोर दनीय

२०६

स्रनुगासन समद में मत्री मण्डल की स्थिति को पाक्तिशाली करने म सहायकहैं।

टा० एव० पाईनर ने ब्रिटिश ससदीय पढित ने दृष्टिकोण (प्रीर यह भारतीय समदीय पढित पर पूर्वत्वा लाग्नू होता है) से, निम्नलिसित शन्या मन्पट निया है नि सि प्ररार क्यार दिनेय सदस्य, सरकार हिन्दि समर्थन पन्ता है। "अब मनी पण्डल दलीय संवेतने हारा यह सूचना प्रतापित करता है नि मामला प्रत्यिय सहस्य मुक्ता प्रतापित करता है नि मामला प्रत्यिय सहस्वपूर्ण है तय न वेवल दल ने हठीले सहस्या थे उन पर नियार पन्ता पढिता है, विन्तु विवयती दल को मी गामीरता पूर्वन विवार करता पडता है नि वास्तय म क्या मामला प्राम-चुनाय को दृष्टि है हिता सहस्त्र में है और सहस्य मान सामला प्राम-चुनाय को दृष्टि है हिता सहस्त्र में है और व्या उनके हात सररार स्थापित की जा सकने को मोई सागायता है। यदि राजनीतिक स्थित उनके प्रानुस्त मही है, ती वे पूर्वत्वा मा पुष्ट मामा म समर्थण पर देने—परस्तु जहाँ विवयती दल प्रत्यमत में है या जब सरपारी दल में फूट की समावना नहीं है यहाँ मुक्लिस है ही पेत प्रवन्त सान प्रात है। "

४—इस प्रवार मत्री मण्डल वी शित्तयों से वृद्धि वा एवं ध्रीर प्रत्य महुत्व-वृणं नारण हमारे तमक आता है वह है नि सभीय ससद में एक सगठित तथा शित्रवाणी विवशी दल वा प्रमाध । १६१० ते, जब मारत के सिष्धान वो लागू निया गया था, ससद में एक सगठित विवशीय दल के स्थान पर वह राजनीतिक दल हैं, जिनमें ससारत दल की प्रालीचना वरने वी, विन्यु उसके स्थान पर एक वैवशित्व सरनार में निर्माण वरने वी क्षमता नहीं है। यह प्रमाध बास्तव में मारतीय ससदीय प्रणाली की एन वभीर चृटि हैं, स्थोकि ससदीय प्रणाली की पर्यवालिक पर पर पर प्रमास वाली की प्रमास की सम्हान की स्थान की स्था

५—प्रत्यायोजित-विधि के रारण भी भारत से कार्यपालिका की शतितयों से वृद्धि हुई है। सामान्यतः विधि के तीन प्रकार है।

क-सर्वोच्च विधि-जो लिग्दित सविधान के रूप में देश का सर्वोच्च कानून है।

प--साधारण जिवि-जिसना निर्माण, सर्विधान में श्रन्तमंत स्थापित ब्यवस्था-पित्रा समाग्रो द्वारा सर्विधान ने श्रनुसार निया जाता है।

ग---प्रत्यामीजित विधि--साधारणतथा, विधि-निर्माण-नार्थ व्यवस्थापिया समाप्रो द्वारा निया जाता है, परन्तु श्रायुनित्र समय मे, जनताप्रित्र राज्य मे,

१ एप० काईनर-'द ध्यौरी एण्ड प्रेविटस झाफ मार्डन गर्वेमेण्ट', १६४० पृ० ६२०. १४

क्षावस्थापिका समा पर नार्वभार बहुत हो गया है। प्रत्येक सन में व्यवस्थापिका को एक बड़ी सख्या में विधेयक पारित करने होते हैं। मारतीय ससद भी, देश ने विकास के लिए अनेको विधेयको की पारित करती है। मारतीय सविधान का सरेश्रा एक लोक बल्याणवारी राज्य की स्थापना करना है। इस उरेश्य की पाँत के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होना स्वामानिक है। लोक कल्याण-कारी राज्य में विधि-निर्माण-कार्य के लिए विशिष्ट तक्तीकी निपणता की ग्रावश्य-कता है। ग्रतएव यह धावश्यक है कि तकनीकी विषयो पर नियमो का निर्माण कार्य, प्रशासकीय विशेषजो द्वारा विचार किये जाने ने लिए छोड दिया जार्ये ! परन्तु इन विशेषत्ती को तक्त्रीकी विषयो घर नियमी का निर्माण ससद द्वारा पारित विधि के क्षेत्र में ही करना होगा । चत ससद विधि की रूपरेखा प्राय. निर्वारित करती है, जिसके बन्नमंत कार्यपालिका, समय द्वारा प्रयत्न शक्ति के प्रत्सार नियमी का निर्माण करती है। इसकी प्रत्यायीजित-विधि कहा जाता है। कार्यपालिका, प्रत्यायोजित-विधि का उपयोग, सक्षद द्वारा पारित विधि के निर्वारित क्षेत्र म, नियमो का निर्माण करने के लिए करती है, जिससे ससदीय विधि को प्रमावपूर्वक कार्यान्त्रित किया का सके । प्रत्यायोजित विधि के एप मे निर्मित नियम) का प्रमाव ससदीय दिथि के संपान ही होना है और इनको न्याय-लय म तब ही चनीती दी जा सनती है जब मूल विधि, जिसके धन्तर्गत इसका निर्माण हुन्ना है, अवैवानिक हो । सतः स्वत्यक्ष रूप से, जारत में प्रत्यायीजित विधि से कार्यपालिका की शक्तियों म बृद्धि हुई है।

६—मिता महालपूर्ण वारण, जिससे मारत ये वार्यपालिया को शांतियाली मति से सहायता मिता है, प्रसासकीय न्याय है। "वृद्धि सरकार प्रमृते विभिन्न प्रकार के वार्यों को पूर्व करें, यत. प्रसासकीय न्याय वर्षों को विश्व जिला तर्वा निर्णय देन के प्रतिकार प्रदान करते ने परकरा कर गयी है।" विश्व प्रसासकीय किशापों को निर्मा को निर्मा के ने प्रतिकार के प्रतिकार प्रदान करने वे प्रतिकार को प्रमास करते के प्रतिकार को प्रमास कर प्रतिकार वार्या प्रकार के प्रमास करते के प्रतिकार के प्रवास सुराने ने जिला कि प्रमास कर प्रतिकार का प्रकार के प्रवास सुराने ने जिला किया गया है। आयकर वर्षों की न्यास विकार के प्रयास प्रदान के प्रताह के प्रसाद के प्रताह के प्रसाद के प्रताद के प्रसाद के प्रस

१, ए॰ पो॰ हस्स्मानी-'सम प्रॉबनेम्स खोंफ एडमिनिस्ट्रेटिय ला इन इण्डिया' १६६४ पु॰ ४

प्रायोग) निर्वाचन सबसी विवाद, (निर्वाचन-त्यायाधिकरण) रेसवे कर, (रेसवे कर त्यायाधिकरण) प्रादि । कमी-कमी त्यायाधिकरणो की स्थापना किसी तदर्य उद्देश्य के लिए की जाती है । इस तरह, जीवन-बीमा अधिनियम १६५६ द्वारा केन्द्रीय सरकार को एक या अधिक न्यायाधिकरणो नी स्थापना करने के लिए प्रविच्चत किया पया है, जो विभिन्न जीवन बीमा कम्पनियों के मुखाबने को, उनके स्वन्नसाय को निषम के लेने के कारण निर्वारित करेंगे।

एक प्रत्य उदाहरण प्रवासकीय-न्याय का प्रस्तुत किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा प्राधित्यस १८५७ के अनुसार विदेशी मुद्रा अधिकारी (डायरेक्टर) को यह निर्णय देने का अधिकार है कि कियी व्यक्तिने विदेशी मुद्रा सबधी नियमों का उत्कवन किया है या नहीं। डायरेक्टर की निर्मुक्त केन्द्रीय सरकार करती है। डायरेक्टर के निर्मुक्त केन्द्रीय सरकार करती है। डायरेक्टर के निर्मुक्त केन्द्रीय सरकार करती है। इस्त स्वादेश सुद्रा आयोग को, जिसका अध्यक्ष एक सदस्य होता है, अपीत को बा सकती है। आयोग के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार निर्मुक्त करती है। इस आयोग का निर्मुक्त करती है। इस आयोग का निर्मुक्त करती है। इस आयोग का निर्मुक्त करती है।

इन उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सारत से नार्यपालिका के प्रशासकीय न्याय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य है। घनत में हम इस नित्वपंपर पहुँचने हैं कि उपर्युक्त तत्वों के कारण आरत से मत्री-मण्डल (बास्तवविक नार्य-पालिका) की स्थिति क्षतिकवाली है।

# संसद के सबध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ

ययपि सिवधान के धन्तर्गत राष्ट्रपति को सबद के सबय में कतिप्त सिक्तार्य प्रदत्त है, फिर भी यह विदित रहना प्रत्यावक्ष्यक है कि इस फ्रांक्नियों का उपपोग राष्ट्रपति, सिवधान द्वारा स्वापित ससदीय प्रणाली की पार्वभूमि में ही कर सकता है। यह सत्य है कि राष्ट्रपति इन सित्यों से सबद पर प्रमाव बाल सकता है, पत्यु यह प्रमाव सक्तीय पद्धति के धनुकृत ही होना झावक्ष्यक है। ससद के सबय में राष्ट्रपति की निम्नानिस्तित शावनयाँ हैं:—

१—सर्विधान के भनुच्छेद नश् के अनुसार राष्ट्रपनि को ससद को भागित तथा स्पनित करने का अधिकार हैं।

र--मनुष्टेद १०८ (१) के अनुसार राष्ट्रपति को ससद के दोनो सदनो मे, रिसी साधारण विधेवक सवधी मतमेद दूर करने के लिए दोनो की सबुका बैठक भागतित करने का भविकार है।

१. ए० पी० हस्समानी—'सम प्रॉवनेम्स झाँफ एडमिनिस्ट्रेटिव ला इन इन्डिया' १९६४ पु० ६ ।

देने तथा सदेश मेजने वा अधिकार है। इस अधिकार द्वारा राष्ट्रपति समय को, जन करणा के तिए, अपना अपूमल तथा ज्यानितन से प्रमानित कर सकता है। राष्ट्रपति निसंगी मिलय ने दिवार के के सम अस बन ने बेदेश में उस मता है। राष्ट्रपति निसंगी मिलय ने दिवार के मता है। राष्ट्रपति के सायण देन तथा सदेश में जने के अधिकार के आतो ना करते हुए प्राय यह कहा जाता है कि ससरीय पडति की पूछत् पूषि में यह अधिकार प्रसान है। राष्ट्रपति के सायण देन तथा सदेश में अपने के प्रायय यह प्रायय में उस अधिकार प्रसान के स्वायत के स्वयत के स्वयत् के स्वयत्व के स्व

४—सत्तव ने सबय म राष्ट्रपति को एक घन्य महत्वपूर्ण प्रथिकार प्राप्त है, जिसनो नियेवाधिकार वहा जा सकता है। राष्ट्रपति ने नियंपाधिकार का वहंच्य ससद द्वारा जलदाजी म चारित विशेषक वर एक सतुतित एव जन-तानिक प्रवर्शन वर्षामा है, जिसमे सबद उक्त विशेषक पर पुत विश्वार कर सकें। जब सतद एक विभेयक को पारित करनी है, उसकी राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाना है। राष्ट्रपति उनन विभेयकप र प्रपत्ती सहमति वे सकता है, या यदि वह नाम जाता हु। उच्छुनाए जना माध्यमण रुपथा। श्रह्मात व सम्मेत हि, या मादे बहु मन विद्येश्व मही है सो ससद में पुनिच्चार में लिए वाधित सीटा सप्ता है। प्रदुष्धद १११ के प्रदुष्तार यदि ससद उत्तम विदेश को पून परित्व कर मेजती है सी राष्ट्रपति को सहसदि देना आवश्यम होगा। यन राज्यति के निर्यमाधिकार मो जनतात्रिक कहता उचित है बयोति उसके उपयोग द्वारा वह समद को जनता की इच्छा के धनकल पुनांत्रवार करन के लिए बाध्य कर सकता है। किन्त विधेयक को बहु न तो स्वय ही समाधित कर सकता है, न समाप्त ही कर सकता है। विवेयर पर ससद की जिंका अतिम है। अमरीका में, जहाँ पर सचीय सरकार की कार्यप्रणाली मिवन पृथककरण एव प्रवरोध तथा सन्तुतन के सिद्धान्तो ने भन्भुत मिश्रण पर बाधारित है, धमरीकी राप्टपति की भी, सविधान के बन्तर्गत निर्पेयाधिकार के एप में, व्यवस्थापिका सभा (कांग्रेस) का विधि निर्माण शक्ति पर एक जनतानिक अपरोध है। अमरीका में यदि कांग्रेस किसी विषेपर को पारित करती है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार किय जान के लिए मेजा जाता है। राष्ट्रपति को दस दिन के अन्दर अपनी सहसति देना चालिये ।

पारिष् भन्न आसा है। राष्ट्रपात वाहसा दिन के बादर प्रपत्नी सहसात तैना जादिंगे । जारतीय सरिवान के अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति विशेयक के सबस से प्रपत्ने निर्देगाचित्रार का प्रयोग करता है और ससद उस वितेयक को अपने दी तिहाई बहुसत से पून पारित कर देती है, तो विशेयक, राष्ट्रपति की आपत्ति के बावजूद सी मिर्फि हो जायेगा। ५—मन्त मे अनुच्छेद १२३ (१) के अनुसार मारत के राष्ट्रपति नो अध्यादेश लागू कराने का अधिकार है। जब ससद सन्न मे नहीं है और ऐसी परिस्थित मे किसी विषय पर वानून निर्माण करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारों कर सकता है। जैसा, पूर्व मे देखा जा चुका है, राष्ट्रपति की अध्यादेश लागू असी की महित सस्य की कानून निर्माण शक्ति का अध्यादरण नहीं तो उस पर स्रितंत्रकण नहीं तो उस पर स्रितंत्रकण नहीं तो उस पर

इस विषय के श्रध्ययन के अन्त में इस मूल वात पर वल देना प्रायण्यक है कि भन्य समुदीय प्रणालियों के समान, भारत में भी समुद के कार्यपालिका पर नियम्त्रण के मूल सिद्धान्त को सविधान द्वारा मान्यता दी गई है, चाहे व्यायहारिक जीवन में मंत्री मण्डल शक्तिशाली क्यों न बन गया हो। भारतीय सर्विधान के धन्तर्गत संसद तथा वायंपालिका के सबंधी का विक्लेपण करते हुए हमने देखा कि इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अवरोध के रूप में कतिपय शवितयाँ प्रदान भी गई है, जिससे संधीय सरकार के ये दोनो अग शसदीय सीमाओं मे उचित रप से नार्य कर सके। सविधान मे इस विधय पर कतिपय त्रटियाँ है, जिनको दूर बरना बावश्यक है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के महासियोग के संबंध मे भारतकी भूमिका प्रपूर्ण है, उस स्थिति से जब कि संसद के विराम-काल से राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है । इसके मतिरिक्त, राष्ट्रपति नी प्रध्यादेश लागू करने जी श्रवित भी, जुछ परिस्थितियों में गम्भीर सिद्ध हो सकती है। भारतीय ससद में एक अन्य महत्वपूर्ण बृटि यह है कि एक भोर तो काग्रेस दल को भारी पहुमत प्राप्त है तो दूसरी छोर इस भारी बहुमत को जन-ताधिक रूप से सन्तुलित वरने वे लिए कोई संगठित तथा प्रभावगाली विपक्षी दल नहीं है। ऐसी स्पिति में ससद की स्वतनता केवल सतास्य दल भी जनतत्र में मास्या पर ही निर्भर है। भस्तु, इन परिस्थितियों में, मारत में नार्यपालिका पर संसद की स्वतनता स्वापित रखने ना, विशेष उत्तरदायित्व है ।

# भारतीय संसद में प्रतिपक्ष दल

सोगतम को एक थेन्द्र परम्पण तथा ध्वास्वयनता यह है कि जममे ज़तता में। सरकार के बाओं भी जायुक्त धालोमना प्रशासीयमा करने की स्वीकृति दी जाती है, जन सोगो को नह सरकार को प्रशासिक सरके के लिए निपतित क्य से ध्वयदा एवं स्वतनता दी जाती है, जो प्रचार कार्य द्वारा धयन्त्र निर्माण करते है तथा विनक्ता उद्देश्य धानित्रकृतं तर्रोकों से जनमत को परिवर्ततत कर सरकार में परि-पर्तन ताता है।

योक्तन में सार्वमीमिकता जनता में ही निहित होती है। जनता का समिकार है कि सपने आहकों का सामिक निर्वाचन करें। सत्यवादाओं को, माम. राम. है कि सपने आहकों का सामिक कि निर्वाचन करें। सत्यवादाओं को, माम. राम. है सिवित सामिक के बाद सपने शास्त्रकों की निर्वाचन का की सिवित साम का सीका करते हुए यह प्रसिकार है कि वे निर्मंग में कि उन्हें पुन बत्ता सौंची जाये सपना नहीं? प्रमित् सामामक के सपन प्रत्येक निर्माण संक्र सदस्य को सत्यवादाओं की सामिक को चार्च पास-कुनात के सपन प्रत्येक निर्माण सदस्य को सत्यवादाओं की सामिक को चार्च का साम का सामिक करती होता है। "है पह समर्प रहनतिस्त को प्राप्त करती होता है।" में किसा देने को सामामक राम होता है।" की सामामक स्वाच्या करना होता है।" की सामामक स्वाच्या करना होता है।" की सामामक स्वच्या होता है।" की सामामक स्वच्या होता है।" की सामामक सामामक स्वच्या होता है।" की सामामक सामामक स्वच्या होता है।" की सामामक सामामक

परमु भोक्तन में सरकार के कार्यों तथा नीतियों के वांचने ना ना मारि केवल माम चुनान के दौरान ही किया नार्ये, तो सताब्द दश को दो माम चुनान के दरमान निरुक्त ननमें मामित्र ने स्वामन चुना के दरमान निरुक्त ननमें मामित्र ने स्वामन चुना के दरमान निरुक्त ननमें मीतित कार्यों के स्वामन चुना के मित्र ने मित्र ने मित्र ने मित्र निर्माण कार्यों के महत्व किया में मुक्त के स्वामन कार्यों कार्य कार्यों के स्वामन कार्यों के स्वामन कार्यों कार्यों कार्यों के स्वामन कार्यों क

१. एम० स्ट्र्फट-ब्रिटिश एप्रोच दू पॉलिटिक्स, १६३८ पृ० २१४।

२. बी॰ वार्ड-डेमोक्रोसी ईस्ट-बेस्ट, १६४६ पृ० १०।

पक्षी दल में परिवर्तित कर सकती है। अवएव एक सपठित प्रतिपक्षी दल माधी वैकल्पिक समा शासक दल हो सकता है, जिसका अस्तित्व 'सरकार पर एक भ्रावश्यक जनताविक अवरोष' में रूप में है।

ग्रत लोक्तत्र मे राजनीतिक दलो की आवश्यकता के दो कारण है।

सर्वप्रथम राजनीतिक दलो वे माध्यम से जनता ग्रथने शासको का निर्वाचन करती है।

द्वितीय, राजनीतिक दला द्वारा विभिन्न प्रवार की वैविष्य नीतियौ तथा कार्यक्रम जनता के समक्ष रखें जाते हैं, जिनसे जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है और वे यह निर्णय ले सकते हैं कि विस प्रकार की सरकार स्थापित की जायेगी।

'एक राजनीतिक दल से हमारा वार्षियं जनता के ऐसे सगठन से है जो कित्यय राजनीतिक सिद्धान्तो तथा उद्देश्यों को मानते हुए, सवैधानिक साधनों के मान्यम से एक साथ कार्य करते हैं।" को बतात्र में कोई भी राजनीतिक दल मिंद प्राम-चुनाव में जनता का विश्वास अपनी जीतियों तथा कार्यक्रमा द्वारा प्राप्त कर लेता है, तो सरकार को बागडोर को सन्हालने का उत्तरदायित्व उसे सौंपा जाता है। क्रम्य राजनीतिक दल, जो मुख्य म सरकार निर्माण करने की समता रखता है। क्रम्य राजनीतिक दल, जो मुख्य म सरकार निर्माण करने की समता रखता है। क्रम्य राजनीतिक दल, जो मुख्य म सरकार निर्माण करने की समता रखता है और जिसकी जीतियों व कार्यक्रम है, ज्यवस्थापिका में प्रतिपक्षी दल के रूप में होता।

ससद में सत्तास्ट दल नी मीतियों की सतत जाँच करने ने लिए एक प्रतिपक्ष दल की प्रावरवन्द्रा होती है, अन्यवा प्रजातन में निरुक्षता ने प्रवेश का सदैव मय बना रहेगा। म्रत सबसीय पिद्धत में राजनीतिक दक्षों की भूमिका का प्रपत्ता विधान्ट महत्त्व है। जैसा नि लाई लिल्डके का नयन है- उत्तम प्रतिनिधि सरकार के लिए म नेवल एन वित्तवाली प्रतिपक्षी दल की झावस्थकता है किन्तु उसके जिए यह भी प्रावश्यक है कि प्रतिपक्षी दल वैकल्पिक सरकार के सदूस हो। "भ

लोनतत्र म राजनीतिक दलो ना महत्व दो प्रकार का है। सर्वप्रथम, वे जनता को राजनीतिक विषयों ने सबस में शिवित तथा सजत करते हैं जो सरकार की निरकुत प्रवृतियों को रोजने के लिए आवक्षक है। दिशीय, ज्यवस्थापिता में वे निरकुत प्रवृतियों को रोजने के लिए आवक्षक है। ब्रीत विभिन्न साथनों द्वारा सरकार को उसके दासित्वों ने प्रति सजय रखते हैं। वस्तुत लोकतत्र का प्रस्तिस्व प्रतिपक्षी वसके दासित्वों ने प्रति सजय रखते हैं। जसके प्राधार पर वे सरकार की गीतियों

१. एम॰ पी॰ शर्मा—य गर्वमेन्ट झाफ इंग्डियन स्पिन्तिक १९६० पृ०२७७ । २. ए क्षे. लिण्डसेन्य इस्सेन्यत्स झाफ डेमोक्रेसी १९४८ पु० ४३-४४ ।

तया कार्यों में निहित चुटियों की धालोचना करते हैं और मतदाताओं के समक्ष बैकटियन गीरियों तथा कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकते हैं। "लोकतम की मान्यता है कि एक सगटित तथा निश्चित प्रतियक्ष सरकार के विरुद्ध हो। विना इस प्रकार के प्रतियक्ष के, निरकुणता की थीर धवशर होते हुए लोकतम का विनास होगा।"

सदि किसी राज्य में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं तो जिन दलों के हाथ में सता नहीं है, उनको प्रतिपक्षी (निर्देशी) दल की भूमिका तिमाना पहती है। प्रतिपक्षी दल का कार्य यह नहीं है कि सर्वेदा सरकार का तिरोव करे। मनेक समय नह देखा पया है कि प्रतिपक्षी दल सरकार को सपना सहयोग देते है, विगेषकर पार्टीय सुरक्षा तथा विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण सामली में।

यहाँ यह समझ तेना उपनुकत होगा कि ससरीय प्रणासी में प्रतिपक्ष की परि-मापा नया होनी ? ससरीय प्रतिपक्ष की एक उपमुक्त परिमापा श्री एत. थी. राजू (स्वतंत्र दक्ष के केन्द्रीय कार्यालय के कार्यकारिणी-सचित्र) हारा थी गई है, जो निम्नानदार है।

१. के. सी. जेना-पोलिटिकल श्रप्पोजीशन इन इण्डिया, इण्डियन रिस्यू १९४६ । पुरु ४५६ ।

२. एस० लो० 'द गर्वनेन्स धाफ इम्लैण्ड-१६३१ पृ० १२५ ।

"जिस सन्दर्भ में यहां प्रतिपक्ष छव्द का उपयोग किया गया है, उसका प्रयं एक सगिटिन समुदाय जो (क्) जनतानिक मुख्यो तथा परम्पराध्रो म प्रास्था रखते हुए सरकारी नीतियों की रचनात्वक आसोचना करता है, (ब) इस स्थित में हैं कि सत्ताहर दल से मिन बक्टियन नीतियों को प्रस्तुत कर सके, (ग) राज्य तथा नक्ष्मीय स्तरो पर आवश्यक प्रमान तथा सगठन रखता है, जिससे कि राष्ट्र के राजनीतिक जीवन म उसकी उपस्थिति महसूस की जा सके, एव (प) जिसका नमृत्व वक्षा एक सबस्थ है, जिसस न केवल उसकी उत्तम तस्बोर प्रस्तुत हो बरन् जय सत्ता की बागडोर समहान्त्र के लिए मतदाता नेमृत्व आगते है, तो नेमृत्य

धी के बीक राजू बहुत है—"इस दृष्टिसे यह स्पष्ट है कि कोई मी विरोधी दल देश म (मारत) बास्तविक प्रतिपक्ष दल (विरोधी) होने का दावा नहीं कर सकता है।' व

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में ससदीय पद्धति की स्थापना की गई है। किन्तु मारतीय समदीय पद्धति की यह एक गभीर नृटि है कि सिंवधान के लागू होने के इनने वर्षों बाद मी एक समिदित एक सकत समदीय प्रतिपत्ती कि (विरोधी) का विकास नहीं हुआ है। यह सत्य है कि सबद में, विरोधी दल है, पर-तु इनमें से एक भी समदीय प्रतिपत्ती दल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी प्रतिपत्ती दल में के किस साम में होने हैं। समाय प्रतिपत्ती हिंदी मारत पर समाय सम्बद्धां प्रतिपत्ती दल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी प्रतिपत्ती दल करने की क्षामता नहीं हैं। समायत म एक समदित एप प्रमानकासी प्रतिपत्ती दल के होने की किसनी प्रायव पर करने स्थित पूर्व के विद्वाल प्रध्यन हाथ विदित हो सकता है।

१---प्रतिपक्षी दल ने नार्य।

२-मारतीय ससद मे प्रतिपक्षी दल का स्वरूप ।

१—प्रतिपक्षी दल वे नार्य-सर्वप्रथम, राजनीतिक दलो का प्राथमिन कार्य लोकमत को सगठित वरना है । क्षाम-चुनाव के दौरान राजमीतिक दलो के कार्य होते हैं—प्रवार द्वारा मतदाताधों में अपनी नीतियों एव कार्यक्रम के प्रति विश्वास पैदा करता । राजनीतिक दलो के प्रयत्त कार्य भी हैं, जो उन्हें प्राय-बनाव के समाध्त होने पर भी करने पडते हैं । इनको ये कार्य निरन्तर करने हों है । सता- कर कर कार्य माम-चुनाव के दोरान मतदाताधों का विश्वास प्राप्त क्या है, प्रवार तथा अन्य हो, प्रवार तथा अन्य वार्यों होरा उत्त विश्वास को और अधिक दृढ बनाने के नियर

१. कें न वी० राजू- 'प्रॉवलेम्स ग्राफ ढेवलेपिंग एन श्रपोजिशन इन इन्डिया' स्टडीरा इन इण्डियन डेमोक्रेसी, १९६४, पृ० ६१७।

२. वही पृ० ६१७ ।

प्रयत्न र द्या है नयोकि वह यनने आम-मुनाव मे मुन. विवय प्राप्त करना चाहेगा। इसी प्रयाद विरोधी दल बीट अधिक सम्बन्ध, प्रचाद तथा कावीं द्वारा मवदानाओं का विकास प्रप्त करने का प्रवत्न करें। "अवस्य वह कहा जा सकता है कि सतावाद या प्रतिपक्षी दल विचायों के दलाल हैं, जो दल मी विचारणाय में निरुत्तर वर्ष्य प्रविचारणाय में निरुत्तर नयट क्रमवंद्व एवं प्रविचारित करने से सवे हैं—ये मतदाता की विज्ञा में वृद्धि करते हैं, उत्तरी स्वतावा की विज्ञा में वृद्धि करते हैं, उत्तरी मार्च सीचारणाय को क्रांता में विकास में वृद्धि करते हैं। उत्तरी मार्च सीचारणाय करते हैं। "

विद शासामी झाम चुनाव में मतदाताओं को प्रतिवधी दन की मीतियों एव विचारणार पर विकास हो जाता है, तो वे उसने सत्ता सौर सकते हैं । नि सहेत, एक लगठित तथा प्रमावधाली प्रतिवधी दस के विद्यमान होने हैं, मतदान हासों के समस एक वैकलिक सरकार विद्यमान रहती है। प्रतायन मतदाता सताक तथा प्रतिवधी दनों को मीतियों और विचारणाराधों की युत्तात्मक समीका करके निर्मय दे तकते हैं कि सत्ता निस दल को बोचा आये। वस्तुत: इस तुनमा-दमक प्रधार पर मतदाताओं के लिए यह समब है कि प्रत्येक विषय को सही परिदेश में देश का

द्वितीय-प्रतिपक्षी दक्ष का एक यन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह नास्तव मे जनता तथा सरकार में थीय की एक महत्वपूर्ण कवी है। पूर्णि राजनीतित दक्षी का उद्देश्य सक्ता की बायडोर पर करवा करना होता है, कर. इस राजनीतिक सवर्ष के परिचाम रुक्त प्रतामीति के क्षेत्र म दी विशिष्ट वर्षों का निर्माण होता है।

१ एस न्यूपेन-'मॉडर्न वोलिटिक्ल बोर्टीच' १६५६ पृ० ३१६ ।

स्थिति विगड जायेगी। जिटिश ससदासम पद्धति ने दृष्टिनोण से सर प्राइपर जैतिक ना नयन है—"सरकार प्रतिपक्षी दल नो, एन ऐसी मीटर पर प्रेन के सद्ग मानती है, जो पहाट पर चढ रही है, जबनि प्रतिपक्षी दल ना विचार है शि मीटर पहाट से उत्तर रही है।""

"नि सदेह ससदात्मन पढ़ित म प्रतिपक्षी दल ना नार्य जिटल है। प्रतिपक्षी दल, व्यवस्थापिना ना एन महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसपे नार्य धप्रत्यक्ष रूप से सरदार ने नार्यों से सविवत है। प्रतिपक्षी दल ना बहुन्य सरनार नी रवनात्मन प्रास्त ना रवे हुन्य सरनार नी रवनात्मन प्रास्त ना नार्ये हुन्य हर करने विज्ञत प्रयाप चनने ने हिए बाराय ना ना है। "व मह सामान करते हुए उक्ष ने विज्ञत प्रयाप करने ने हिए बाराय दल जनता की मीलिक स्वतप्रतामों को जुचति हुए निरमुख वन सबता है। वस्तुत, प्रतिपक्षी दल सरनार भी सजन सक्तिय तथा सजीव रवने में सहायन है। प्रतिपक्षीय दल ने सदस्य प्रमने प्रायणों हारा जनता को प्राध्यक्ष करने वा प्रयत्न करते हैं च उनने दल भी भीतियों तथा नार्यक्रम हो सर्वप्रेट हैं। यह स्वामानिक है नि सत्ताइ दल भी भावनी नीतियों तथा कार्यक्रम को जनता ने समक्र स्पष्ट इस्पे स्वाम प्रावश्य हो है। स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम के सिम् सत्ताव है। इस्ते मार्य के स्वाम पर प्राप्त कि है हिटल पढ़ित ने हैं। स्वाम ने स्वाम पर प्राप्त कि इस्पिक ना ने सहस्य स्वाम पर प्राप्त कि इस्ते मार्य सरनार के स्वाम हो महत्वपूर्ण है। यदि प्रतिपक्षी दल सरकार ने स्वाम पर प्राप्त कि साम हो महत्वपूर्ण है। यदि प्रतिपक्षी दल नहीं है तो जनता में नहीं हो समता है। इस्ते व से सहत्वपूर्ण है। यदि प्रतिपक्षी दल नहीं है तो जनता में नहीं हो समता है। इस्ते व हो सहत्वपूर्ण है। यदि प्रतिपक्षी दल नहीं है तो जनता में नहीं हो समता है। इस्ते व स्वाम सरनार के महत्व हे हुसरे स्वाम पर है। "3

प्रापुनिन गुन में ससदारमन पढ़ित म ससद नी शक्तियों में परिवर्तन हुमा है। ससद में सताहद दस ना बहुमत होता है, जिसमें से मनी मण्डल (सरवार) ना निर्माण होता है। चूंकि साभाण्यत्वा बहुमत सरकार ने पढ़ा में ही होता है प्रत. सरवार पर समद ना नियन्त्रण प्रत्यत्व नम हो गया है आपृतिन समय में ससद प्रियन्तर वाद विवाद न प्रात्येचना ने मच के रूप में ही रह गई है। सत्ताहद सके से सदस्य सरवार नो प्रात्वेचना ने मच के रूप में ही रह गई है। सत्ताहद सके सदस्य सरवार नो प्रात्वेचना बहुत कम करते हैं। यह नाथ प्रत्य प्रतिपक्षी दस्त है करते हैं। "प्रतिपक्षी दस्त से जो प्रपेद्या नी जाती है, यह है प्रमावशानी माजीचना।" प्र

१ ग्राइ जैनिग्ज-'पार्तियामेन्ट' १६५७, पृ० १६७ ।

२. प्राई जैनिग्ज-'केबोनेट गर्वमेष्ट' १६१६ पृ० १५।

३. वही पृ० ४०६।

४. प्राई जैनिग्ज-'पार्चियामेन्ट' १६५७ पुर दर ।

समदात्मक सरकार को सम्भवा के लिए यह प्रावश्यक है कि मताहर दल तथा प्रतिपक्षी दल के मध्य परस्पर विश्वास हा तथा सविधान के सिद्धानों से वे पूर्णन्या परित्वत हो, बिद्धाले व्यावहारिक बीवन में, राष्ट्रहिन के लिए इनका पातक विधा जा सके। प्रतिपक्षी दल वा दलों को प्रपन्न विशिष्ट्र, दाधित्वों को समभने हए, हितासक साधनों को नहीं प्रपन्नाना चाहिंग।

सक्षेप म, प्रतिपक्षी दल को एक उत्तरदायी प्रतिपक्षी दल होना चाहिये। क्योंकि प्रनुत्तरदायी प्रतिपक्षी दल से उत्तनी ही हानि हो सक्ती है, जितनी एक

सनुतारसाथी सरकार से।
स्वाद्वाहीर राजनीति स प्रतिवस्ती दल में सत्यविष्ठ सहार ने नारण, इस्तैष्ठ
स्वाद्वाहीर राजनीति स प्रतिवस्ती दल में सत्यविष्ठ सहाराज किया गया है
कि प्रतिवस्तीय दल में मेता को र,००० घोष्ड प्रति वर्ष मेनन मिते। नामस समा
के स्त्रीकर हारा निर्मारित निया जाता है किस व्यक्ति को प्रतिवस्त्री दल ना नेता
स्विद्ध कर यह मेता किया जाता है किस व्यक्ति की से के दिया जाता है,
जिस पर मतदान नही हो सतता है। यद्यविष्ठ इस्ति किया जाता है।
जिस पर मतदान नही हो सतता है। यद्यविष्ठ इस्ति के स्वत्यो दल के नायों ना
स्रीपनारिक हर से निर्मारण न सो कानून, हो सदन ने नियमो हारा दिया जाता
है, समस्त्री रिप्तिकालक फहरसूर्ण है। "साध्यी पा तरिवस्त्री दल के स्वत्यो

सनी है।" ससदासक पढ़ित में प्रतिपक्षी दल के बार्श तथा पूषिका के सम्बयन से पह स्पष्ट ही जाता है कि सहसीय प्रवातन का बोई मुख्य नहीं होगा पदि बहां कपुत, परिपक्त, ज्या प्रमावकाशी प्रतिपक्षी दल नहीं है। "वस्तुत गैर-सास्यवादी राष्ट्री ने प्रतिपक्षी दलों का हवान तथा शित क्यात एक उच्छ स्तर पर है।"व

#### भारतीय समद से प्रतिपक्षीय दल

यह विदित करने के लिए कि बारतीय सबद ने विभिन्न क्षिनोधे दलो ढ़ारा मारतीय सबदारमक पद्धति के व्यवस्थक तत्थे के रूप म क्षमिका निभाई वाती है या नहीं नहीं पर सावस्थक है कि इन विभिन्न विरोधो दलो को स्थित का अध्ययन विद्या जाय।

नहैं बर्प पूर्व प० नेहरू ने नावेल तथा प्रजा सोवालस्ट दलों के पारस्वरिक सहयोग के विषय पर श्री काश्रकाण नारायण स नातों करने ने वण्नात, मारत मेरी राजनीनिक स्थिति पर एक नस्तव्य दिया, को श्राव में राजनीनिक स्थिति क सवय में भी सही माना जा सन्ता है। यह दश कार है।

रै बाई जैनिग्ज—'पार्लियामेन्ट' १६५७ पू० ६७ ।

२ क० सी० जेना 'पूर्वोक्त पुस्तक' ५० ४३७

"नाभेस को छोड़कर, जो राजनीतिक दल मारत म विद्यमान है, उनवो चार वर्गों में विमाजिन विद्या जा सनता है। मुद्ध दल है जिनकी विचारनारा फ्राधिन है। प्रपंत सबस्थित सगठनों के साथ साम्यवादी दल हैं। विभिन्न साम्यदायिक दल पुषव नाम के हैं किन्तु जो सनीण माम्यदायिक जिनारनारा वा घनुगरण कर रहे हैं, फ्रीर कई स्थानीय दल और समटन हैं जिनका ग्राधार केवल प्रान्तीय विस्क स्थानीय है!"

मारत को बर्तमान राजनीतिक स्थित का अध्ययन, यदि प० नेहरू द्वारा निय गये राजनीतिक देलों के उपयुक्त वर्गीकरण के आपार पर किया जाय तो राज-नीतिक देलों को मुख्यत निस्त्रलिखित गर्गा के रखा जा सकता है।

(क) पहले वर्ष से उन महत्वपूर्ण राजनीतिर दलों को रखा जा सकता है जिनकी न केवल झार्यिक विचारधाराएँ है यरन्तु जिन्होंने जनतव तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य वा पोषण करना झवना उद्देश्य मान रखा है। उदाहरण स्तक्ष्य पाँग्रेस, सोझालिस्ट दल एक स्वनव दल।

(त) दूसरे वर्ग भ वे दल रते जा सकते है जिनकी उत्पत्ति धर्म तथा सम्प्रदाय के माधार पर हुई है। ये हैं कारतीय जनस्वय तथा शुस्लिम सीग ।

(स) तीसरे वर्ग मे उन राजनीतिक बलो को रखा जा सकता है, जो हिमा में विश्वास करते हैं, श्रीर सविजान में जिनकी श्रान्या सदेहबद है, जैसे साम्यजादी दल (भावभंवादी)।

१९५० में सविवान लागू होने के पश्चान् कई राजनीतित्र दलो की उत्पत्ति हुई। बनमान समय म निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दल हैं —

(१) काबेस-मारतीय राष्ट्रीय नावेस ना उदय सन् १००५ में हुया। उस समय दमना उद्देश्य समस्त मारतग्रसियों ने निष् एर साधास्य मच की स्थापना करना था जिससे राष्ट्रीय आयोजन नी प्रयति ही मने। बीसपी मदी के दूतर दमन में महारमा मात्री ने नेतृदर में यह एर अस्यत क्षतिनक्षासी दल अग नया। १००५-१४४७ तन राष्ट्रीय आयोजन की खामदीर, मुख्यत नावेस ने हाथों में ही रही और इस दीरान नावेस ने श्रथ्य रूप से जनता से सम्पन्न स्थापित करने ने सबसर प्राप्त हुए। अन्यूप यह स्वामाधिक वा कि जा नावेस ने इन्तन मारत नी सरनार नी याणडीर सम्हानी, जनता नो इसना स्मृतपूर्व समर्थन प्राप्त या, क्योंनि जनता नो दृष्टि नावेस राष्ट्र नी एनता तथा आपन्न साथा मारी साथीन हिंदि एस स्थापन के नावेस नी एनता नी स्थापन ने नावेस नी स्थापन के नावृत्व होने ने पश्चात तीन आम चुनावों (१६८२, १९४७, और

१ 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' सब १८,१६४३ मे प्रशासित प०नेहर का भागण ।

२२२ **मारतीय शासन इ** ११६२) में कांग्रेस को विज्ञाल बहमत प्राप्त हमा जिसके फलस्वरू

१६६२) में कांग्रेस को विज्ञाल अहुमत प्राप्त हुमा जिसके फलस्वरूप सतद एव राज्य विधान समाम्रो में (केरल को छोडकर) कांग्रेस का पूर्ण मापित्रस्य रहा। परन्तु १६९७ के ग्राम चुनावों में नावेस को महरा वरका पहुँचा, बसीक न केयल कई राज्य विधान समाम्रो में इसका बहमत समाप्त हो गया किन्तु सब ससद मे भी इसका बहमत घटकर देवल १४% ही रह गया । तत्पश्चात आतरिक इन्द्र तथा मनमेदो के कारण १६६६ म काग्रेस मे वही फूट हुई, जिसके फलस्वरूप ससद में कार्येस के एक हिस्से ने डा॰ रामसुमनसिंह के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यो का स्थान, सगठन कांग्रेस के नाम से ग्रहम किया । कांग्रेस का श्रेप परस्तु प्रमुख हिल्ला, श्रीमती गांधी के नेतृत्व मे, नई कावेश के नाम से सरकार की बागडीर विसम्बर १९७० तक, कृतियय निर्देशीय सदस्यो तथा विरोधी दक्षों ने समर्थन के 

प्रत्य राजनातिक हाना का तुलना म नह कावब का बावज राजुक्यारा है, मिस्ते जनता तथ पुक्रमा सामा है, बावा है। वह कावेब की नदीनत मार्मिक विचारकार के मीरिक पहलू, बनता की सामयकताको से प्रत्यक्ष सबय एसते हैं। एसे मार्मिक पहलू, बनता की सामयकताको से प्रत्यक्ष सबय एसते हैं। एसे मार्मिक है सहित है। इसके पति-राज के सामनी को राज्य के सामकार में होना चाहित्यू, विहित हैं। इसके पति-रित्त, निजी मार्मिक प्रत्यत्वे को भी श्रीसाहन देसे के सिद्धाल पर वस विमा गया है। नामेंद्र प्रायत्व को भी श्रीसाहन देसे के निवार के पत्त्वक समाम गया है। नामेंद्र प्रायत्व सामिक विचारपार को प्रयान है, क्योरि जतवा न दो उपनाधी नीरियो के पदा में हैं न होने राजनीतिक दलों के जी निसी निवीग राजनीतिक दल से में प्रयान होते और उनके सत्ताहतुत्वार कार्य करते हैं।

राजनातिक विचारपारा के दृष्टकाण से भी, कांग्रस को प्रास्पा लोकतन तेया धर्म-निरक्षेप राज्य में हैं। अन्य राजनीतिक दलों के इतिहास को देखते हुए, जनता को, इन राजनीतिक मुख्यों के सदमें में कांग्रेस पर अधिक विश्वास है।

सक्षप में, इन तत्वों के कारण कथिस भी स्थिति विशेषकर ससद में, म्रस्यत मनिन्नाती है। इस बात की पुष्टि कथिस डारा प्रत्येक भ्राम चुनाव में जितने स्थान लोक समा म प्राप्त हुए हैं, उनसे की था सकती है। पहला प्राम चुनाव १९५२ सोकतमा मे स्थान प्राप्त १६४ दूसरा प्राम चुनाय १९५७ सोक समा मे स्थान प्राप्त २७१ तीसरा प्राम चुनाव १९६२ सोकसमा मे स्थान प्राप्त २६१ चोषा प्राम चुनाव १९५७ सोकसमा मे प्राप्त स्थान २८१ पौचवा प्राम चुनाव १९७१ तोकसमा मे प्राप्त स्थान २४०

(२) प्रजा सोशिलस्ट दल-सितम्बर १६५२ में सगाजवादी एव किसान मजदूर दल के मिलने से प्रजा सोशलिस्ट दल की उत्पति हुई । वस्तुत सोशलिस्ट दल की उत्पति १६३४ में काग्रेस में से ही हुई, क्योंकि श्री जवप्रकाश नारायण, मञ्जूत पटवर्षन एव श्री मशोक मेहता जैसे नेतामो को काग्रेस पर पूजीपतियो या ग्राधिपत्य पसंद नहीं या। स्वतत्रता के पूर्व इस दल को काग्रेस-सोगलिस्ट दल वहा जाता था। १६४२ मे मारत छोडो भादोलन के समय इस दल के नेता मिम्यत हो गये। मार्च १६४७ में इस दल के नेताओं की बैठक वानपुर में हुई जिसमे उन्होंने काग्रेस से पूयक होकर एक स्वतत्र एवं भिन्न दल के निर्माण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इन नेताओ की राय में काग्रेस का स्वरूप एक राष्ट्रीय संयठन से बदल कर एक राजनीतिक दल का हो गया था। इन नेतामो का यह विश्वास भी था कि चुंकि स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात काग्रेस सत्तारूढ हो गई थी अत एक प्रमावशाली प्रतिपक्षी दल का निर्माण करना अत्यत आवश्यक था, जो कि सत्तारूढ दल की निरकुण प्रवृतियो पर प्रवृत्व लगा सके। इसके श्रतिरिक्त, सोशलिस्ट दल का यह विश्वास भी या कि कांग्रेस द्वारा प्रमावपूर्ण आर्थिक एव सामाजिक सुधार लाना ग्रसमेव या ।

प्रजा सोवालिस्ट दल का विश्वास लोकवाविक समाजवाद मे रहा है ग्रीर उनके प्रमुसार विकेष्टित लोकवन, जनता के सार्वजनिक मामलो में हिल्सा लेने के लिए प्रावस्वक है। इसवा उद्देश एक नियोजित श्राप्तक व्यवस्था भी स्वपाना नरता है, जिसमे महस्वपूर्ण उद्योग, जैसे—कीयला, इत्यात ग्रादि का राष्ट्रीयकरण हो। मत: प्रजा सोवालिस्ट दल तथा वाग्रेस के सिद्धान्तों में मुख्य प्रमत्तर यह है कि काग्रेस द्वारा स्वीवृत भाषिक व्यवस्था एक मिधित भाषिक व्यवस्था है, जिसमें निजी एयं सार्वजनिक व्यवस्था को समान रूप से स्थान प्राप्त था; जविक अजा सोवालिस्ट दल का विश्वास केवल ऐसी व्यवस्था ये रहा है जिसका स्वस्थ

१९४२-में किसान मजदूर दस तथा समाजवादी दल का एकीकरण हुमा, जो प्रिक नामप्रद सिद्ध नहीं हुमा । इसका मुख्य कारण यह पा कि किसान मजदूर दन का उद्देश 'सर्वोदय' प्राप्त करना था, समाजवादी दल की प्रेरणा का

भारतीय शासन ग्रीर राजनीति २२४

स्रोत मान्सवाद या। फलस्वरूप, शीझ ही दल मे दरारे पहने लगी और दल दो भागों में विभाजित हो गया।

(क) दक्षिणपथी-जो बाग्रेस के साथ सहयोग के पक्ष में थे, एव (छ) वामपथी-जो नाग्रेस से नोई सबघ नही रक्षता चाहते थे। इसलिए जब प० नेहरू ने श्री जयप्रकाशनारायण को राष्ट्र निर्माणात्मक कार्यों में प्रजा सोशलिस्ट दल के सह-

योग के लिए ग्रामंत्रित किया तो प्रजा सोगलिस्ट दल के वामपथी नेतायों में डा॰ सोहिया तथा थी मधुलिमये को यह बात पसन्द नही थाई। सरपश्चात, प्रजा सोशलिस्ट दल के बान्तरिक भतभेद स्पष्ट रूप से सामने जगर कर बाये । जब कांग्रेस ने घपने बवाडी (महास) चिधवेशन में मारत म समाजवाद स्वापित करने

के लक्ष्य को स्वीकृत किया तो प्रजा समाजवादी दल के ग्रव्यक्ष ने इस पर ग्रपना हुएँ व्यक्त किया घोर कहा कि यह लोक्ताजिक समाजवाद की प्रकृति का एक सबत था । डा॰ लोहिया ने सहयोगियों ने इसे एक वडा घोला बताया । इसी समय श्री मयलिमये ने, जो डा॰ लोहिया ने निकट के सहयोगी थे, श्री धशोक मैहता की कडी ग्रालीचना की, फलस्वकृप जनको दल से निसम्बत कर दिया गया । परन्त दल की उत्तरप्रदेश भी कार्यपालिका ने श्री लिमये का समर्थन किया धीर उनकी गाजीपुर में दल के भ्रिषेवेशन को संबोधित परने हेतु भ्रामनित किया। इस शार्यकी दलीय

धनुशासन के विरुद्ध मानते हुए समस्त प्रदेश नार्यपालिका की निलम्बित कर दिया गया। बन्त मे जुलाई १९५५ मे डा० लोहिया को दल से निप्नासित कर दिया गया। दिसम्बर १८५५ में डा॰ लोहिया ने समाजवादी दल का निर्माण निया जो

कि प्रजा समाजवादी दल के विरुद्ध था, नयोकि प्रजा समाजवादी यल का नाग्रेस से सहयोग नरने मे विश्वास था। इस दल को सयुक्त सोशलिस्ट दल (एस०एस०पी) के नाम से पुकारा जाता है। मई १९६३ में डा॰ क्षोहिया लोक्समा के लिए निर्वाचित हए। प्रजासमाजवादी दल को विभिन्न बाग-चुनाव मे न तो ससद में न ही राज्य विधान समान्नो मे मधिक स्थान प्राप्त हुए । १९५२ के ब्राय-चुनाव में लोरसमा में इसे २१ स्थान मिले। १६५७ के बाय-बुनाव में इसे लोश्समा में केवल १६ स्थान

ही प्राप्त हुए। १६६२ के धाम-चनाव में लोकसभा में वेबल १२ स्थान प्राप्त हुए भीर मार्च १६६७ के माम-चुनाव मे १३ स्थान प्राप्त हुए। मार्च १६७१ के माम-चुनाय में प्रजा सोशलिस्ट दल को लोनसमा में केवल २ स्थान ही मिले।

हा० लोहिया ने समाजवादी दल को १९६२ के ब्राम-चुनाव मे ६ स्थान प्राप्त हुए भीर १६६७ ने भाम-चुनाब से २३ स्वान मिले। १६७१ के ग्राम-चुनाव मे

इसे केवल ३ स्थान लोकसभा मे प्राप्त हए।

भारतीय जनसंध-मारतीय जनसंघ की स्थापना १९५१ में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा की गई। जनसम नो दक्षिण पथी दल माना जा सकता है। समाजवादी एव साम्यवादी दता को वामपथी माना जाता है। जनसंघ का प्रभाव मुख्यत भारत म उत्तरी क्षेत्र म है, विश्वपतर पजाव, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य-प्रदेश एव राजस्थान । १६५६ म जनसघ, रामराज्य-परिवद तथा हिन्द्र महासमा व एकी करण करने के प्रयत्न किय गय, परन्तु यह समान नहीं हुए। इन तीना दला की प्राय ग्रानोचना की जाती है कि य साम्प्रदायिक हैं।

'राष्ट्रीय स्वय सेवन सघ एक सास्त्रतिक सगठन होने का दावा करता है, परन्तु इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ जनसप द्वारा, सचालित की जाती है। डा॰ मुत्रजी एक महान राष्ट्रीय नता थे जिनका राष्ट्रीय सेवा का रिकार्ड है। जून १६५३ में उनकी दुरम्पूर्ण मृत्यु के परचात जनसम राष्ट्रीय स्थम सबके सम्बन्ध प्रमुख मन का गया। 179 यद्यपि इसकी स्थापना के बाद, जनसम के स्वरूप म परिवर्तन हुमा है, अपनी सफलता ने लिए जनसघ नो प्रावश्यक है कि ग्रपनी विचारपाराओं मो जनतात्रिक एवं धर्म निरपक्ष सिद्धान्तो पर ग्रापारित करे. जिससे प्रत्पसत्यको का विश्वास इसे प्राप्त हो सक । १६५२ के प्राम चुनाव म जनसभ को लोकसमा मे ३ स्थान आप्त हुए । १६५७ के भाम-चुनाय म इसे ४ स्थान लोगसमा में मिले और १६६२ के धाम-चुनाव में १४ स्थान-लोकसमा म इसे मिले । १६६७ के बाम चुनाव म जनसप को लोकसमा मे ३३ स्यान भौर १६७१ मार्च ने भाम-चुनाव मे २२ स्थान लोनसमा म मिले ।

१६६२ ने माम चुनाव ने पश्चात् जनसम की लोकप्रियता म मोडी युद्धि हुई है बिन्तु एव बास्तविक प्रतिपक्षी दल के रूप म विकसित होने के लिये, जनसय वा लोकतानिय एव धर्म निरपेक्ष स्वरूप को ध्रपनाना होगा।

४-स्वतंत्र दल-स्वतंत्र दल की उत्पत्ति १६५६ में एक लोकतातिर भनुदार दन ने रप म हुई है। स्वतन दल ने उद्देश्य तथा नीतियों का उल्नेस श्रीमती ऐलन रॉब ने निश्नलिखित रूप से निया है, "हुगारी राय है नि सामाजिन न्याम तथा लीव गल्याण को तथाकथित समाजवाद के साधनी के धलाबा ग्रम्य निश्चिन् एव उपयुक्त साधनी द्वारा प्राप्त विया जा सकता है। सामाजिक न्याम और लीव बल्याण को हिंसा या राज्य मक्ति द्वारा नहीं लाया जा सकता है--निन्तु इनवी स्थापना गांधीजी द्वारा प्रतिपादित न्यास-पद्धति वे द्वारा की जा सनती है। सरवार की भैदाणिक गतिविधियों प्रत्यक्ष या ध्रप्रत्यक्ष इस प्रवार की होनी चाहिये जिससे इस बात पर बल दिया जाये कि जिन लोगों के पास धन है, वे इसको समाज की घरोहर के रूप म रखे, और जीवन के ऐसे सिद्धान्त पर भी जी इस नैतिन वर्तव्य पर बाघारित है, इसके बजाय कि ऐसे सामाजिक

१ एम० जी० गुप्ता, 'पूर्वोक्त पुस्तक' पु० ४८० 8 %

वृद्धि होती गई है। १९७१ के थाम चुनाव में मारतीय साम्यवादी दल (सी० पी० आई०) को २३, भारतीय साम्यवादी दल (मावसँवादी) (सी० पी० एम) को २५ स्थान लोकवमा में मिले हैं।

चपर्युनत निवरण से भारतीय ससद में निचले सदन (लोकसमा) म मुख्य राजनीतिक दतो की स्थिति स्पष्ट होती है और यह विदित होता है कि इनमें से किसी दल को 'सास्तिकल स्वतिय प्रतिपक्षी दम्द की सजा नहीं दी जा सकती है। परण्डु रुन पुरुष राजनीतिक दली के प्रतिरिक्त लोकसमा में बुद्ध प्रत्य स्थानीय एव छोटे दलो का प्रतिनिधित्य रहा है, जो निम्मिकस्तित हैं —

१—गणतत्र परिषद-१६६२ के ज्ञाम-चुनाव म लोकसमा में इसे उडीसा से ४ स्थान प्राप्त हुए।

२—किसान एवं मजदूर दल-१९६२ में इसको लोकसभा में कोई स्थान प्राप्त नहीं हमा, परन्त १९६७ में २ स्थान प्राप्त हुए । यह दल महाराष्ट्र का है।

२ — मुस्लिम लीग-१८६२ मे इसे २ और १८६७ मे ३ स्थान प्राप्त हुए । इसका प्रमान प्रमुख रूप से केरल मे है।

५—फारवर्ड ब्लाक-१६६२ में इसको २ स्थान सोकसमा में प्राप्त हुए, और १६६७ में में २ स्थान प्राप्त हुए। इस दल का प्रमाव मदास भीर पश्चिम बगाल म है।

बगाल महा

६—द्रविष्ठ मुनेत्र कडगम-१८६२ के श्राम-चुनाव में इसे लोकसमा में ७ स्थान मिले, भीर १८६७ के श्राम-चुनाव में इसे २५ स्थान लोकसमा में मिले। इस दल का प्रमान महास (तमिलनाडु) से हैं।

७--फारलण्ड दल-१८६२ के ग्राम-चुनाव म इसे लोकसभा मे ३ स्पान मिले । १६६७ के ग्राम-चुनाव मे इसे कोई स्थान नहीं मिला । यह दल विहार प्रान्त का है।

६-हिन्दू महासमा-१८६२ में इसे लोकसमा में केवल १ स्थान मिला, परन्तु १८६७ में इसे कोई स्थान नहीं मिला।

६-राम राज्य परियद-१६६२ के साम-चुनाव में भव्यप्रदेश तथा राजस्यान में २ स्थान कीनसभा में प्राप्त हुए।

१०-रिपब्लिकन दल-उत्तरप्रदेश से इस दल को लोकसभा मे १६६२ के ध्राम-युनाव मे ३ स्मान प्राप्त हुए भीर १६६७ मे इसे केवल १ ही स्थान प्राप्त हुमा।

११--१६६२ में सोकसमा के लिये २७ निर्देशीय खदम्य निर्वाचित हुए। २२=

१६६७ में ४२ निर्देशीय संदश्य लोकसमा से निर्वाचित हुए ।

१२--पात इन्डिया हिल सीडर्स वाफेन्स-१८६७ में घसम से इत दल ने सोक्समा के लिए ? स्थान प्राप्त विया था।

१२--मह्तुनुबरात जनना परिपद-११६७ में गुजरान से इस दल को लोक

१४--नेशनन बाकेम-१६६७ से जन्तू तथा काश्मीर मे १ स्थान लोकसना समा के लिए ? स्थान मिला था ।

के लिए मिला।

१४---नामा नेशनल बारणनार्श्विशन-१६६७ में झाम-चुनाव में इसकी नामा-

क्षेण्ड से लोक्समा में १ स्थान प्राप्त हुआ या । उपर्युक्त सम्प्रयन से यह लाग होना है कि प्रसिपकी दलों से से किसी की भी स्थिति इस प्रकार नहीं है कि उसने एक वास्तविक समदीय प्रनिपक्षी वल नी न्तारा था ना कर । विशास बहुमन प्राप्त हुआ है । अनत्व केवल कुछ समय को छोडकर, सरिमान भाग होने से बाज तक लोकसमा से वामेस का एक प्रतीय वास्परम रहा है, जब राज्य प्राप्त विश्वती बनो को केवन जान साथ के स्थान प्राप्त हुए हैं। सनोबैतानिक क अरुपा प्रस्ति सरदीय चढित की कार्यप्रणाली पर इसका हानिकारक प्रकास हो सकता है; बमोकि जब कई विश्वतीय दल हैं और इनमें से किसी को सविष्य का करता थे। में सरकार निर्माण करने की उम्मीद नहीं है तो स्थावहारिक जीवन में ऐसे दल भागः प्रतुत्तरवाग्री होतर सरवार की नवाराम्यक क्य से प्रातीयना में लगे रहते है, बोर उनना उहैं व नेवल यह ही हो जाता है कि किसी प्रकार सलद में हुआ कोर स्थान प्राप्त नर सें । क्योंकि, वे मती-मीनि जानने हैं कि सरकार के निर्माण करते का प्रवसर जनको नहीं दिल सकेगा। इससे यह प्रतीन होता है कि प्रनक विपक्षीय दली के स्थान पर बंदि एक या अधिक से प्रविक सो दल हो, तो इनम सार्वज्ञीनक विषयी के सम्बन्ध के ससद म एवं ससद के बाहर, टोस उत्तरवाधिक की जावना आगृत हो सदेगी। इतको नीतियो तथा कार्यक्रमो मे पृथकता तथा स्पष्टता लागी जा सकेगी जिससे मतदानाधी को भी सतदान के कार्य में सहाल-यत होगी ।

बस्तु स्थिति यह है कि लोक्सना में जब नई कांग्रेस का प्रकार बहुमत है तो वर्दै विद्यान दलो के पृथक सस्तित्व के कारण एक 'वास्तविक सप्तदीय प्रतिपत्त का विकास समय नहीं है। इस प्रमाय की दृष्टि से मारतीय ससदीय पड़िन के सम्बन्ध में एक उपमा दी जा सकती है कि यह एक ऐसी मीटर गाड़ी के सद्ग है को बारो में उतर कर बा रही है, बीर जिसके श्वेक में त्रृदियों हैं। सप्तरीय प्रति- पशी दा एवं 'क्षेत्र' वे समान है, जिससा वार्यस्तरार रूपी मोटर गाउँ। पर भावरार जिल्लाक रुरा हैजिसने बिजासररार जिल्लाम से बाहर हो रिरस्युजना की भोर भयसर हो समती है।

चयित माराध्य सबद भे प्रतिवक्षी दाो भे वई पृष्टिगी है भीर 'समदीय प्रतिवक्ष' या स्वरूप ससल्तोवजान है पिर सी बट नहीं वहा जा सबता है ति सरनार पर दा दाो का कोई प्रमाव नहीं दहा है। वह बुख हर तक सरकार पर एवं जागोत्तिय सबरोध वे रूप मे हैं। मुख्यत दो प्राप्त के ऐसे साधा है जिसके सामार पर पतिपक्षी दा सरनार पर एवं जागोत्ति सारोध का कार्र करते हैं।

१—सरनार के दिरंद मिलवास परवार पारित करो का उस सामा । परन्तु मह पर सर्व सामान्य सामन करों है, सिसंवे मिलवी दल प्रति दिस सरकार का सिन्निक करों है।

२---कतिपर ऐसे साधन है, जिस्से अतिपत्नी दा सरवार वर दैशिर शियन्त्रण वरते हैं। ये दैनित साधन, शिनासियित हैं १

- (क) समिति प्रणानी पास ससद को विशिष्ठ समितियो पर प्रतिपत्नी दसो के प्रतिनिधि होते हैं। निस हेंद्र ता सरकार के कारों से सकरित समिनियो का सेनाधिकार है, पनिष्यी दस समितियो से सको प्रतिनिधियो के साध्यम से सरकार की सनिविधियो पर जिस्ताव रहा है।
  - (त) ससदीय प्रश्न,
  - (ग) ससदीय प्रस्ताव,
  - (घ) याद विवाद,

(इ) स्पना परााज आदि, ये ऐसे साथा है, जिनवे माज्यम से परिपद्मी दा सररार पर नियन्तर दैनिय नियन्त्रण रस्स सदो है।

 के सम्बन्ध म दिवसीय दल के तेना ने १८३२ में नहा—"वार्यि यह सरनारी नियेयक है परन्तु इसना निर्माण सरन ने सदस्यों ने सहतीय से हुमाँ है नहीं पर बुद्ध सदस्य निद्धानतों पर विभेयन ना विरोध करते हैं फिर भी वे उसनी जियानित

धन्य मामला में भी, जो राष्ट्रीय हितों से सर्वायत है, प्राय प्रतिपत्ती दत्ती का सहयोग सरकार वो मिलना चाहिये १६६१ तथा १६७१ में पाविस्तानी मात्र-मणों में दौरान प्रतिपत्ती दसा ने सरकार को धपना ठोम सहयोग दिया ।

इसके वावनूद मी कि मास्तीय संसद में प्रतिश्व द्वारा सरकार पर पुष स्थानित का मामानामां मोक्सियोय प्रतिश्व के विकास नहीं होता है, तक तक बारित तथा मानामां मोक्सियोय प्रतिश्व के हि मास्तीय संसद में पर नागित एवं प्रसादवाली नोक्सियोय प्रतिश्व की सावववता, यी एयं आरं गानी में एवं प्रसादवाली नोक्सियोय प्रतिश्व की सावववता, यी एयं आरं गानीम मीडिक को के प्रतिक का को समयों जा मक्ती है, "मेरे विचार से नारतीय मीडिक को के प्रतिक वहत्य को यह स्थाद हो या होगा कि साववात्य अतत्व प्रमाववाती मही हो सकता है यदि एक प्रमाववाली प्रतिश्व का प्रसाद है। बहतून, माप से वि निहोंने को एक एम करान की प्रतिक प्रमाववातीय मह कि पर प्रतिश्वी वस की एक एम करान क्वारियों में मुख क्वीटी यह है कि पर प्रतिश्वी वस कीर विकास सकता क्वारियों में मुख क्वीटी यह है कि पर प्रतिश्वी वस कीर विकास सकता क्वारियों में मुख क्वीटी वह है की से सिक्सन कताविक नहीं है सकता है, यह क्याहर सिक्सन सताव्य कर के प्रमाव कीर बता सरकार की बागवीर के को तथार नहीं है। करवीन सही था ""

जारतीय सविधान में विचारी की सिन्यांकि की स्वन्ता का स्विधनर मार्घारण को विधा निया है, जिनके पसंदक्ष्य के सरदार की साजोनना कर सकते हैं। मताय स्विधान के स्वतंत्र संवदीय प्रतिपक्ष के विकास के तिय पर्योग मारार हैं। यन नेहल ने कहा है कि—"देश विधानस पूर्णत्या ऐसी सरकार में है, किसके भानीचक निजर हैं, और जिसको विदोध का सामना करना है। विना मार्थीयना के जनता तथा सरकार लायरवाह हो आती है। समस्त समरीय प्रणानी, रस कार गाँ भालोकना पर सामारित है—मैं ससद में (सरकार भी) मार्शोकना महात हैं।"

रै. ए॰ बी॰ कीच-'द ब्रिटिश फेंबोनेट सिस्टम', १९५२ पृ० २४२-२४३ । २. एम॰ मार॰ मसानी--'पार्टी पासिटिक्स इन इंग्डिया,' (इन बाईटस

एम० प्रार० धसानी—'पार्टी पासिटिक्स इन इन्टिया,' (इन बार्टिस स्पीनेन एण्ड डाय्युमेन्टस झाफ द डे) जुलाई, १४, १९४२ मु० ४६६ ।
 ५० नेहरू—'नेहरून स्पीनेन' साम-३ धगस्त १९४७ मु० १४२ ।

पव्यक्तिकानः विविजन, भिनीस्ट्री आफ इन्कारमेशन एण्ड बादिशांस्टिंग ।

प्रवर्ष मूल प्रका यह है कि भारतीय संसद में एक संगठित एव प्रभावणाती लोकतत्रीय प्रतिवस के विकास में कौन-कौन सी बाषाएँ है, और उनको किस प्रकार दर किया जा सकता है।

(१) सारत स राजनीतिव नेतृत्व की सुस्य तृटि यह है कि यह नकारात्मक तथा वाल्पनिक प्रमावो तो मुक्त नहीं है। सोगतात्र स राजनीतिक नेतृत्व का विकास एव प्रासान बागं नहीं है वसील इसने लिए ससीम पैर्य एव जित की सियरता की प्राययम्तता है। इसने मतिरिक्त नेतृत्व के लिए मारान-विल्वान की माययम्तता होती है, जिसने जनता पर उचित्र प्रमाव है सने । परन्तु मारत से यह देशा गया है कि राजनीतिक दलो के कई सदस्यों ने अपने प्रमाति में पारण जल्द ही वैसे सो दिया है और सतास्व दलो के कई सदस्यों ने अपने प्रमाति में पारण जल्द ही वैसे सो दिया है और सतास्व दलो के सिर्यस्थता छोड़कर कार्यस्थ में प्रवेश के तिया। इसके मतिरिक्त, कई विषयी दलो वा नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों ने महाय में है जो पूर्व में कार्यस्थे सामित्री से प्रयेश की प्रवेश के सामित्र के सन में स्वामाविक स्था में सुर्य सामित्रों ने सामित्र से से से अवत्य एवं सामित्र ने सामित्र से से से अवत्य स्था सामित्र के सन में स्वामाविक स्था से सुर्य ने नार्यसे से छोड़कर विषयी दलों में सदस्यता ग्रहण को है। 'यह कोई स्थान्यमं नहीं है कि जनता इनने अध्यावहारिक, अवती या ससन्तुष्ट नेतायों के स्था मानती है। जनता प्रयान मित्रस्थ ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में छोड़ना सुरिप्तत मही समक्रती है। 'यह नी प्रवास मही समक्रती है। 'यह नी सुरिप्तत मही समक्रती है। 'यह मारान्य स्थान्य प्रेस स्थानयों के नेतृत्व में छोड़ना सुरिप्तत मही समक्रती है।'

कई राजनीतिक दलों के नेतृस्य में झान्दरिक कलह तथा भगडे हैं जिससे उन दलों के सदस्यों में झसलोंप की भावना बढ़ती है और साथ ही जनता पर बुरा प्रभाव पहुँचता है, जैसा डा॰ सोमजी, प्रवा सोभितस्ट दल के लिए कहते हैं "नेतृत्व है विद्यालें में इसको अपने सस्याजकों की समायिक राजनीतिक सेवा निवृत्ति होने से और अन्य सदस्यों के स्पत्तिगत भेद-माल तथा भज्ञदों के बरायण अधिक हानि सहनी पड़ी है। "व यह सत्य है कि यदि आरम्म सही विषक्षी दलों का जिसत नेतृत्व तथा कार्यक्रम होता, तो गवाचित ससद में एक समिद्धत लोगवाजिक प्रतिपक्ष के विकास कार्यक्र होते होता, तो गवाचित ससद में एक समिद्धत लोगवाजिक प्रतिपक्ष के विकास स्वाद्धत सामग्रदायिक अधिक सामग्रदायिक आपार पर विमाजित होने में कई पठिनाइयों दूर हो सकती थी। पर-तु जी सा स्पर्ट है मार्स में विनाइ सामग्रदायिक आपार पर विमाजित होने के अतिरिक्त आपार आपार पर विमाजित होने के अतिरिक्त आपार आपार पर विमाजित होने के अतिरिक्त आप आपार पर विमाजित होने के अतिरिक्त आप आपार सामारिक स्वाद्धी से उलक्षेत होते हैं, जिसके

१. जी० धी० कान्तिकर—'प्रोवलेम्स झाफ श्रपोजीशन इन इण्डिया इन स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी' १६५ पु० ६२६।

२. ए॰ एवं० सोमजी-'मोटिबेशन्स एण्ड प्रोपेगेण्डा इन सेमीनार' ३० फरवरी १९३२।

पलस्वरूप लोकतत्र का मूल उद्देश्य-लोक कल्याण, इनकी दृष्टि से स्रोमल हो जाता है। "एक प्रमावशाली प्रतिपक्ष वा निर्माण ऐसा कार्य है, जिमके लिए घैँयें की, विशेषकर मारत-जैसे बार्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछडे हुए देश के लिए ब्रावश्यवता है । निरन्तर विरोध में रहना, प्रतिपक्षी दल का उद्देश्य नहीं हो सकता। एक प्रमादणाली प्रतिपक्ष को सताहड दल का कडा विरोध करते हुए, मतदाताग्रो मे विश्वास की मावना का निर्माण करना है कि वह सरकार की बागडोर सम्हालने के लिए तैयार है। इस युद्धिकोण से प्रतिपक्ष को वैकल्पिक सरकार के सद्दा कार्य करना है। इस बात पर बल दिया जाना भाषस्यक है कि एक प्रभावशाली दल के निर्माण के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। इसने पूर्व कि उसके द्वारा लेक्ट सरकार की स्थापना की कई ब्रिटिश लेक्ट (मजदूर) दल को प्रतिपक्ष म कई बर्घों तक पहना पद्या। दुर्मोग्यदश वह सहनशीलता तथा धैमें जो एक प्रमावकाली प्रतिपक्ष के लिए आवश्यक है, आरत के बलों में नहीं है। प्रतिपक्ष की सदस्यना छोडकर सत्तारुढ मे प्रवेश करना मुख्यत पैर्य की कमी का सूचक है, मद्यपि कई बार यह दर्शाया जाता है कि यह विश्वास से प्रेरित होकर किया गया है।"<sup>25</sup>

(२) केवल निष्ठाबान एव उत्तम नेतरव ही एव प्रमावशाली लोक्तांत्रिक प्रतिपक्ष के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्यों कि अनता की प्रभावित करने के लिए एक घन्य तस्य चावस्यक है।

इस तच्य को इंप्टि से बोमल नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्रता 🖹 पश्चात् भाषिक भत्तमानता, मावश्यक वस्तुमो के दामो मे वृद्धि, प्रशासन मे लाल पीता-शाही तथा अञ्चाचार के कारण जनता में बसन्तीय बढा है। परन्तु यह एक विडम्बना है कि इन सब कारणों के होते हुए भी जनता ने लगातार, सिवधान लागू होने के पश्चात् केवल एव ही दल (वाग्रेस) को वेन्द्रीय सरवार की बागडोर सौंपी ! इस विवित्र राजनीतिक घटना के नया कारण है यहाँ पर दो कारणी का उल्लेख किया जा सकता है।

सर्वप्रयम, कई प्रतिपत्नी दलो हारा पाश्चात्य राजनीतिक, भाषिक एव सामा-जिक झादशों या नमूनो को अपनाया गया है। परन्तु आरम्म से ही काग्रेस में मी इसी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धान्तों की ध्रपनाया है। प्रनएव एक साधारण नागरिक के लिए कभी-कभी यह समझना कठिन है कि 'तोकतानिक समाजवाद' की घोषणा करने वाले इतने अधिक राजनीतिक दल

१ एम० भार० दण्डवते—प्रोबलेम्स ग्राफ ग्रपोजिशन इन दृष्टिया इन स्टडीज इन इण्डियन ढेमोक्तंसी, १६६५, ६३८।

मणे हैं, जबिक कार से ने इस सिद्धान्न की घोषणा वी है और इसकी कार्याग्वित करने वा दावा करती है। "केवल यह कहना कि हम वही चाहते हैं, जो सत्तारड दत बाहता है जिन्तु हम उसे वेहतर रूप में करने, जनता वो धानवरत करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"" उदाहरण स्वरूप, प्रजा सोधानिस्ट दत का धानप्र प्रदेश में सासन, साम्यवादी दत का केरल म धानम, उत्तर प्रदेश में सपुन्त विचायन दत का गासन, सम्यवादी दत्त को केरल म धानम, उत्तर प्रदेश में सपुन्त विचायन दत का गासन, स्वरूप विचायन दत का गासन, स्वरूप विचायन दत का गासन, स्वरूप विचायन दत्त को गासन, स्वरूप विचायन दत्त की शासन, प्रति हैं। ये ना स्वरूप प्रजासन देने की शासना रहते हैं। "धामान्यत जनता में सामत प्रकानित्तों के प्रति एक प्रकार की शासना रहते हैं। "धामान्यत चनता में है । उनकी निवास है के दिन स्वरूप प्रचासन की हो । उसकी प्रवास है के दिन स्वरूप प्रचासन नहीं होगा। इसिलए के चने तथा प्रजास समान की समर्थन है। स्वरूप स्वरूप स्वरूप में तथा प्रजास समर्थन है। स्वरूप स्वरूप

दितीय, सत्तास्ठ दल (काग्रेस) की नुटियों के कारण उसके प्रति प्रसन्तीय होते हुए भी जनता को यह विदित है कि इसके मलावा कोई वैकल्मिक राजनीतिक दल नहीं है जो उनका एक इड़, समझ एक स्वस्य प्रधासन देने की स्थित म हैं। प्रत्य व विद्या है जिसकों दामाना करने के लिए वननों जनता के समझ स्थनी एक प्रमावचाली तत्वीर रखनी होगी। यह प्रतिपक्षी दलों के रचनात्मक कार्यों से ही समय है। उदाहरण स्वरप, विद्या कर सहकारिता के क्षेत्र मे राजनीतिक दल योजनायों की सफलता के लिए प्रपना योगदान दे सकते हैं और जनता के समझ समझ प्रतिपक्षी वन्न मंस्कृतीयों मे प्रशासन एव प्रवन्य-सवयों समस्याग्नों के समझान करने की समना है। प्रत्य विद्या समस्याग्नों के समझान करने की समना है। प्रत्य विद्या समस्याग्नों के समझान करने की समना है। प्रत्य विद्या समस्याग्नों के समझान करने की समना है। प्रत्य व्यवस्थ समस्याग्नों के स्वाहिये जनता में उनके प्रतिवश्वास की भावना जागृत हो सके।

१६६७ के झाम-चुनाव के बाद विभिन्न प्रतिपक्षी दलों ने, विभिन्न राज्यों में समुक्त सरकारें स्वापित की। ये समुक्त सरकारें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश में स्थापित की गई थीं।

परन्तु सिवाय आन्तरिक क्ष्मडों में घपना समस्त समय व्यय करने के इन सरकारों ने जनता के हिन में कोई विश्लेष कार्य नहीं निया। "इनके प्रनिरित्त, कई राज्यों में, विभान समामों के कई सदस्यों ने राजनीतिक नेतिकता को ठुकराते हुए भन्ने स्थायों नो प्रीत के लिए दल-बदन और दलीय निष्ठा में परिवर्तन साम सम्बन्ध दलों का निर्माण किया जैसे बनाल में पीपुल्स टेमोक्रेटिक क्ष्मट और विहार

१. जी॰ बी॰ कान्तिकर-पूर्वीतत पुस्तक पृ० ६३२ ।

२ वही प्र॰ ६३२ ।

में सोधितरहत । ऐने विधादकों के बारण को उचित्र या धार्तुकत माधनों से मंत्री यह हुएते च ही प्रायमित रूप से प्रचि रुवते हैं—एक सामान्य ब्यक्ति की समझीत कतनत में ब्रास्था श्वममा गई है और जीवनत्व के ब्रान्तित्व को ही डर हो गया है।"

232

(2) जब तक राजनीनित दलों नी मन्या प्रायधिक रहेगी और वे साम्यदा-पित्र, ज्यानीम या प्रस्त नित्ती मतीचें तन्त्रों से प्रमादिन होतर वर्षों करेंगे, प्रह्म रहते हैं ति इस्ते इस्तर मत्तर में वोई नित्ती प्रमादमारी मीक्नाविक प्रीत्तक्ष के निर्माण की समादमा नहीं है। "राजनीनिक दलों को मन्यात कुन्द्र कारता के प्रसाद पर सोरक्त कई दलों को पैदा दिस्सा है। एक ऐसा देश जहां पर प्रतिदाश दम नितंत है, इस प्रकार का राजनीनिक विमाजन नहीं बहन कर सत्तरा है। बिक्त जैसे देश में, सेवर दल में मान्यित्य सित्याता होने के बावजूब मजहर दल के नेना भी एम्युरिक बेकन समान वाम पत्ती उस नेनामी ने कमी भी सेवर दन को विमाजित कर एक नमा क्यान स्थापित करने का प्रयत्न नहीं हिस्सा। विद्यान स्वेष्ट चक्त हास प्रमुख सकक सारत के प्रतिपक्षी दलों की दृष्टि में कमी प्रीमान नहीं होना चाहिये हैं"

१. वें ॰ सी॰ सबनेना-'विटर इंग्टियन डेमोर्ड सी' इन सोसनिस्ट कांग्रेसमेन, न्यार्च २५, ११६८ ।

२. एम॰ शार॰ दण्डवते पूर्वोक्त पुस्तक, पृ॰ ६३६-६३७ ।

ित तरेह, इस प्रकार के सस्यायी समझौत, विभी शीमिन जहेगा की पूरि के लिए सरन नहीं हो सबने हैं। "सादसी की एक्सा, सम्द्रन, प्रमुतासन एवं टोस मेतृब सत्तरक दल के लिए बितने सादस्यक हैं, चलने प्रनिष्ण दन के लिए भी मादर्स है। इन गुणों को सस्यापी निर्वाचन सक्यों समझौती के माध्यम से दिनकी निर्वाचन के बाद तक विद्यान बहने की समावना नहीं रहती है, प्राप्त नहीं किया वा सत्ता है।"

सह समारा स्वता आवश्यन है कि प्रतिपत्ती दलों के समान प्रस्माती तथा प्रस्मान सम्भानि नरने वो प्रवृत्ति नाम्ने (भारास्त्र) दल ने भी मारत के नतियय राज्यों में प्रदित्ति नो है । १,१४५० में कार्य में ने सनाली दल से सममीता निया। ने स्ती प्रवार केला में थी गुरु एनन डेवर के नेनृत्व में नाम्ने मान्यादी र त से सहयोग करने के प्रयत्न दिये । प्रवत्त यह नहीं या नि साम्भवादी सरकार मन्द्री मा बुरी भी, किन्तु प्रवन जोश्यादिक तथा धर्म निरमेश धादधों ना है, प्रयान् नवा एक तीन्द्राज्ञिक, प्रमें निरमेश दल को एक ऐसे दल के साम सहयोग करना प्रवाहिये जो एक जनगाविक संविधान हारा प्रवत्त स्वत्रवा ना लाम मृत्युत्त रूप से तेने हुए, स्वत्य सविधान तथा जनतक के विचाय करने पर तसरह है

सभैप में राजनीतिक दलो हारा समम्भीने किये जाते हैं, उनके लिए निम्न-

निकित मुद्दो पर ध्यान रखना झावच्यन है।
(ह) राजनीतिक सममीते समान विचारवारा, नीतियो एव उद्देश्यो पर

(क) राजनातक समझात समान विचारधारा, नातवा एवं उद्देशी पर माधारित होने चाहिये, तब ही वे स्थायी एवं नामप्रद हो सकते हैं।

(द) समझीन वा नहेश्य नेवल सकारूड दल को पराजिन करने का नही, परन्तु रक्तात्मक नीतियो एव कार्यक्रमों के भ्रामार पर एक बैकलिस्क सरकार को स्थापना करना होना चाहित। यदि जारतीय रावनीतिक जीवन में विकेश रूप में हन वो मुद्दों पर प्यान रखा जाये तो इसने सतदीय सोकतव की नीव को दृढ़ होने में साराया स्तिति।

(४) प्राप्त में एक सागित्र एक प्रभावभावी कोक्तजीय प्रतिपत्ती दल के विकास में जो एक धौर उल्लेखनीय रक्ताबट है, धीवकाम करना की निरासरणा है, लगमण -४ प्रतिद्ध भारत की जनगा निरासर है, जिबको जनगर के मार्ग में रोज कहा जा सकता है। उद्योग प्रीप्ता करका, वहुर पाजनीतिमा द्वारा परीप्ता करका, वहुर पाजनीतिमा द्वारा उत्योजना पूर्ण मापणो से जनता की प्रमानित कर, इनने कन प्राप्त करने में सफलता कि जाना करने के सफलता कि जाना करने के सफलता कि जाना करने के सफलता कि जाना करने हैं। इसके धारितरक्त, विमान प्रकार के तथा कथित सामाजिक,

१. एलीटिएयो सोधारेज-धार्लियामेन्टरी धपोशीशन, इन द इन्डियन रिस्पू नव० १६४१ पुरु ४२०।

साजिक, सामित प्रलोमतो, यात्रपंणो द्वारा मी निरक्षर मतदाताया को योडे से समय के लिए मग्नावित कर उनने मत हृडपे जा सनते हैं। प्रिटेन म मताजिकार यर्ग-तन दिया गया, जबिन भारत म एक ही बार यह प्रविकार नारतीय नागरिकों को सिवतान द्वारा दिया गया है। खताय, बिटन म मताजिकार पर्य निवास त्यार दिया गया है। खताय, बिटन म मताजिकार प्रदक्त करने के पूर्व प्रिटेश नागरिकों को पर्वाप्त राजनीतिक विद्या प्राप्त हुइ है। मारत म, इतके विल्लुल विरास हुइ है। मारत म, इतके विल्लुल विरास हुइ है। मारत म, इतके विल्लुल विरास हुइ स्थान मारतीय नागरिक को चत्र कुछ सीमा तक राजनीतिक विकास मिली है। लाक्तन म बिदित नागरिक को महत्वपूर्ण पूमिका है। एक जिसिक नागरिक को नाम सकता है। एक जिसका नागरिक को समस्याधों को सरस्ता प्रदत्त समाजित स्थाने द्वार को निवास करता है। किन्तु एक निरक्षर या प्रत्य का नागरिक को लिए यह समय नहीं है। यत नागरिक को बिला विवेषय र प्रतनीतिक-गिक्षा पर लोकतनीय थयकस्या में विषेष स्थापक विश्व से धिए उनने मत के प्रमू की मामको की प्रकास में कि पान स्थापक निरक्षर त्या प्रतन्न के का मामको की प्रकास का का निवास के स्थापक निरक्षर त्या प्रतास की स्थापन की स्यापन की स्थापन की स्थाप

एक मध्याविध चुनाव के दौरान लेखक को व्यक्तिगत रूप से ज्ञात हुमा कि
यह कितनी चतुराई से विया गया। प्रतिदृत्दी दल के समर्यक एक नमूने के
मतदान पत्र एव रवर नी मुहर जिस पर × चिह्नित या लेकर प्रचार कर रहे थे।
जब कभी भी वे यह देखते थे नि मतदाता मुख्य विषद्ध है, तो वात-चपनता से एसे
मतदाताभी को कहते कि किसी प्रताशी के लिए × चिन्ह का उपयोग उसके प्रति
जनकी प्रतिकृति का सुचन या, श्रत्यात जब कोई प्रत्याक्षी उनकी पसन्द नहीं था
यो उनकी क्षतक्षीत का सुचन या, श्रत्यक्ष उसकी सामते × श्रवित कर है।"\

थीं एस० थीं। राजू एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह विदित होता है कि निरक्षर मतदाता ने मत का अनुचित लाम किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। "उदाहरण-स्वरूप मेनूर के एक निर्वाचन क्षेत्र म, जहाँ पर लेखक भे जाने का प्रसर प्राप्त हुमा, उन्होंने देखा कि कितनी भी कितनाइयों ने बावजूद सत्ताख्य कांग्रेस दस विजयी होता था क्योंकि उननो बैल तथा जुँगा, का निर्वाचन चिन्ह मात्त या और इस निर्वाचन क्षेत्र से बहुमत उन व्यक्तियों का या जो वैल की पूजा करते हैं।"

यह सत्य है कि चुनावों के दौरान निर्वाचन चिन्ह प्रणाली से निरक्षर मतदा-ताम्रो के लिए काफ़ी सुविघा हो गई है, किन्तु जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों ते

१. एस॰ मी॰ राजू 'यूर्वोक्त वृस्तक', वृ॰ ६२४-६६ ।

२ वही पृत ६२६।

उस राजनीतिक दल के सद्दण होगा जो स्केण्डीनीविया से स्पेन तथा यूगोस्लाविया तक कार्यरत है। परन्तु इसके अतिरिक्त, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दूँ मतदाता निरक्षर है। इसका यह तारायं नहीं है कि वे, उनकी तुलना में जो पढ तथा जिल सकते हैं, कम बुद्धिमान है, परन्तु इसका यह अर्थ अवस्य है नि वे आपका (राजनीतिक दल का) घोषणा पन पढने में असमर्थ है।

(राजनातिक दल का) वारणा पन पठन कसरान है।

इसका यह परं है कि ससद से चिये गरे आपणो को भी वे नहीं पढ सकते

है जो उन तन शब्दो ढारा नहीं पहुँचाये जा सकते हुँ, और आवागमन के साधन
भी अरयन्त सीमित है। यदि टेलीविजन होता तो इस समस्या का समाधान किया
जा सकता है। परन्तु पारत के बामो में टेलीविजन एक दूर का सपना है।

अतत्व यह प्रवश्यमावी है कि राजनीतिक दल जनता कर पहुँचने में कठिनता
का सामना करें। ऐसी स्थित में विचारधारा का नम महत्व होता है। सगठन
का और अधिक महत्व होता है। १९६२ के आम-चुनाद ने अस्य आम चुनादो
के समान निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर नही हुआ
था, यह निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर नही हुआ
था, यह निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर
नही हुआ
था, यह निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर
नही हुआ
था, वह निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम होता हुए तो वह इस-कारण कि इसका
भगठन तन किसी अस्य राजनीतिक दल के सगठन-तत्र की अधिक प्राचीन, शक्तिआकी और व्यापक है।

सगठन तत्र के उच्च कोटि के होने के स्रतिरिक्त, काग्नेस को विसीय साधनों की कमी नहीं है, जिसते उसकी रिश्वति सौर वृढ होती है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि काग्नेस सत्तास्त्र वस है। १९६१ से पिछले पाँच माम-चुनाव के मनुमय पर कहा जा सकता है कि साम-चुनाव में विवय प्राप्त करने के लिए प्रया्त वित्त होना सत्यावस्त्र है। निवांचन प्रायांचा द्वारा प्रकाशित 'मिनुप्रस प्राप्त वित्त होना सत्यावस्त्र है। निवांचन प्रायांचा द्वारा प्रकाशित 'मिनुप्रस प्राप्त वित्त होना सत्यावस्त्र है। क्युरिस्पात स्त्र है कि सामा-चुनाव में प्रत्येक प्रत्याची द्वारा कर्च की जाने वाली प्राच्या की सीमा १५,००० च्यये तक निवांदित की गई है। वस्तुदिवति यह है कि सामारणत्या एक प्रयाची के लिए इतना व्यय करना उसकी व्यक्तिगत सीमा के बाहर है। तथापि जो राश्चि वास्तव में व्यय की जाती है, वह २५,००० क्यये से कई गुना प्राप्तिक होती है। यह इसिलिये समय है कि उपर्युक्त सीमा, एक प्रत्याची द्वारा प्रतिक के किये गये व्यय पर है, जबकि प्रत्याची के लिए उसके दल द्वारा किये गये व्यय पर है, जबकि प्रत्याची के लिए उसके दल द्वारा किये गये व्यय पर कोई सीमा नहीं है। इस कारण एक प्रतिवक्षी रल के तिए यह एक कठिन समस्या हो जाती है, क्योंकि न तो उसके पास प्रत्याचित वित्त ही है न ही ऐसे सामन, जो सत्याख्य हक की प्रपत्त प्रत्याची वित्त ही है न ही ऐसे सामन, जो सत्याख्य कर की प्रपत्त प्रत्याची वित्त ही है न ही ऐसे सामन, जो सत्याख्य कर की स्वत्य द्वारा प्रदा्व के कारण उपलब्ध होते हैं। श्री रजनी कोठारी का कथन है—''काग्रेस द्वारा प्रदत्त सरसण्य

१. एम० मार० मसानी-'पूर्वोक्त पुस्तक' पु० ४९६ ।

हा जाल हरना हूट धीर धविन भैन गया है कि इनने दायरों में महनारी सिमिता, प्रमादन, समुदार-विनास प्रधानन, समस्त धर्म, सरदारी संस्यार्ट, वेश भोजता, दिवस, प्राच्य नात्री में सर्वान्त है समस्त सस्यार्ट, तितना सबय पर्राट्ट, नोटा, व्यापारिक मध्, शैक्षपित सन्यार्ट, एवं नार्वास प्रधानारिक से है—सो धा जाने हैं। इस तब नो प्रमाद रूप में नावेस सगठन ना ट्रिम्बा बतानर एक प्रदेश में प्राच्य स्थाणि निया जाता है।

िन्यों सीमा तक तत्त्राक्त दल को वितित्व बहायना महत्वपूर्ण उद्योगिक प्रतिदान्ता में प्राप्त होनी है, यह दिस्की (IISCO) एव एक्ते (IISCO) हार पूर्व में करिय को यो में वितित्व सारत्या के बात हो मनती है। ये वेशों द्वारा को बात हो मनती है। ये वेशों द्वारा को सीमा प्रतिप्त नत्त्वपूर्ण है। १११० के साम चूनाव में 'दिस्कों' ने कावेस निषि को रे०,००० रण्य दिस्ते। यह उत्लेखनीय है कि श्यापात होना हो कर साम को वित्ती सामिता की है। त्यापार्ट्स को सामिता मानिकाना की है। त्यापार्ट्स काव मानिकाना की है। त्यापार्ट्स काव मनत्रा में दिस्ते में सामिता काव काव मानिकाना की साम प्रतिप्ता मनत्रा काव काव प्रति व व मारत्य में व वदाल मनाविकान का प्रति हो काव काव मानिकान की साम प्रतिप्ता मनत्रा है और जब मारत्य में वदाल मनाविकान काव प्रति हो काव मानिकान की मानिकान की मानिकान की मानिकान काव मानिकान काव मानिकान की निष्य को मानिकान की मानिकान की निष्य काव प्रति व हुंचा काव स्वत्य हो कि यह स्वीकार करना की की कि प्रतिविद्या मानिकान स्वत्य होगा ववित्त की सीमिता मीनिकान की सीमिता की सीमिता की सीमिता की साम निकान की सीमिता की सीमि

दित का प्रमाय मनदान पर किस सीमा तक होता है, इसनो स्पष्ट करने के लिए मी पी० सी० चीपती एक उदाहरण प्रसूत करने हैं, जो विद्वते एक मध्या सीव जुना में सहित हैए मिंद्री हो पति होती उदाले सारम्यान के पहल्य मीव जुना में सहित होती होता है। एक मध्याविष चुनाव में एक नाग्रेस प्रत्याची था धीर इसरा प्रतिकारी देशों हार सम्मित्त था। उस समय बत्तमय धाया करने के नेपीय मित्री मी धामतित दिना या का कि में पहले प्राप्ताची ने लिए भागण देने विद्या प्रस्ता के में स्वाद करने विद्या प्रसार करें। एक मनी विशेष हवाई बहुत से धाने। एक या दो मनी विशेष रूप से किंगी पर सिंगी हवाई बहुत से धाने से एक या दो मनी विशेष रूप से किंगी कर साम पर अवाद करने होता उद्देश एक धानिकार, स्वतस्थान के सनका प्राप्त स्वाद करें, इस धान पर अवाद करने होता है। एक धानिकार, स्वतस्थान के सनका पर अवाद करने होता इस्ते । एक धानिकार प्रवस्ता हक, इस काम पर अवाद करने होता इस्ते । एक धानिकार प्रवस्ता हक, इस साम पर अवाद करने होता हता है। एक धानिकार प्रवस्था देश साम धाना करने साम प्रविकार साम होता से साम होता हो।

१. भार-कोरी-डेबनेपिय पोलिटिक्ल पेटर्न, (इन सेमोनार, सस्या ३० फरवरी १९६२ प्र० १८) ॥

वे प्रश्याशी को एव स्थानीय यक्षीस था विसीय दृष्टिकीण से काफी हाति हुई। उसरा पर्ता था ति वांग्रेस प्रत्याशी देशमम्ब ३,००००० रूपमे व्यय विमे जयि उसको उपस्का राशि का एक दशाश साम भी उपलब्ध करी था।"

सक्षेप से सह निवन्ये निराला जा सकता है कि चुताब में राष्ट्रो तथा जीती ने तिए था अस्य र शायश्यव है और प्रत्येव बोध्य बृद्धिमार एव विष्ठापूर्ण व्यक्ति को यह मुक्तिमा उपलब्ध मही रहती है। इस पुटि को दर करो का उसम उपाय मही है ति सत्तारू दा अपो पर विश्वय आवश्यव रोग समामे रहे भीर योगं दक्ष्मानुबंग पामा गरे।

(६) जैसा देशा जा नुवा है गारत की ससदीय पढ़िया मे एक मोर सो गामेरा गा विशास बहुमा है सो दसरी भोर प्रशिषक्षी दस बहसरमा में है जिससे भारतीय सराधीय पत्नी में एव प्रवाद वा राज मिश बस पुरा बा रहता है। ' राग्रेस के एक सरकी आधिपत्य प्राचा, वह चाजवीतिक स्थापित स्थापित विमा गया होगा जो स्वानता के ब्रायम्बन वर्षों मे भारत के लिए ब्रायक्यक था, जैसा रि प्रो॰ पार रे बतलावा है, स्ति इसरे द्वारा एक स्वस्य रामातिक दलीय प्रणानी का जिनास रोग दिया गवा है। "%

धाएव पटौं पर गुरा प्रशा बहु है जि सामाच्या एवं मरादाता की क्या भीगता होती चादिये जिसके द्वारा वह उपर्वतः विवास राजातिक धस सरात को पर गरी एए एमं गुदढ एवं अभावशासी अधिपक्ष के निर्माण में सहायसा पर्वे गाये १

चींन ससदीय पद्धति की सक्तता के लिए दो या अधिक से अधिक सीन राजातिय दरा ही हो । चाहिये, यह मस्यायस्यव है कि मरादासा धर्मा गरा केयस उ ही दत्ती के प्रश्वाशियों को दें, जो शोकरान, विकासवादी समाजवाद एवं धर्म िरपेक्षणा मे विषयात करते हैं और जो भारतक मे राष्ट्रीय स्तर के दत हैं। इसके उपरान भी गायाता को यह जात करना धावस्थक है कि ऐसे राजनितिक दर्ता में से बीन कीन से दल उपमुक्त हैं सर्मान् यदि दो से सधित देशों की विधारधाराए तमा। है तो वेयत उसी दरा को मा दिये जायें, जिसी भ्रवपारा में अप ही प्रति-शामी वो ति स्वार्थ भाग से पूरा वरों के लिए रच सस्मव प्रवश्त किये हैं। साम राजाीतिक दत्त स्वत ही समाध्य हो जायेगे, बयोबि उत्तवी जाता का समर्थन ाटी भिोगा। पर सुपूर्व मे यह बातताचा चुवा है ति यह क्या मसदासायी शिक्षा तथा राजातिक विषयो से संबंधित ज्ञा पर निर्भर है, क्योंकि विभिन्न

१. पो० सी० चौघरी, पूर्वोक्त पुस्तक पूर २३ । २ एग० की० पामर-पूर्वोक्त पुस्तव पु० १८४ । ₹ €

राजनीतिक दलों के सिद्धान्तो, नीतियो तथा कार्यक्रमो मे समानता या धसमानता तथा गुण-दोप मनदाता तब ही जात कर सक्तेंगे, जब उन्हे राजनीतिक विपयो का पर्याप्त ज्ञान है !

सक्षेप मे, मारत में एक लोकतत्रीय एव प्रमानशाली प्रतिपक्ष के विकास के लिए निम्नलिखित समान दिये जा सकते हैं ---

(१) सरकारी एव गैर-सरकारी स्तर पर जनता के प्रशिक्षण के लिए विगेष कर राजरीतिक मामलो के सन्दर्भ भे, कदम उठाये जाने घाडिये.

(२) सरकार को शोध्र ऐसी मीतियो तथा कार्यक्रम को क्रियान्त्रित करना चाहिये जिससे जनता को साधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके क्योकि साधिक ,स्वनंत्रता हो बास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता का साधार है।

(३) विभिन्न प्रनिपक्षी दलों का, जो बहुबस्या में हैं, जनता तथा राष्ट्र के प्रति करेब हैं कि समान विचारपार एकने चाने दलों को निवाकर, मारतीय राजनीव में वे या अधिक से अधिक तीन दलीय प्रणाली को जन्म में जिनका सापार स्पष्ट कम से सोकतानिक तथा चर्न निरपेख हो !

(४) सत्तारूड दल का एक विशेष उत्तरदायित्व है कि विमिन्न क्षेत्रों में रवनात्मक प्रयत्नो द्वारा एक जोनतानिक प्रतिपक्ष दल के विकास में सहायता करे।

(५) धन्त म, मारत थे लोनतंत्र ना घरितरण भारतीय जनता पर निर्मर है। निर्वाचन के समय जनता को अपने मत इस प्रकार विमाजित करने चाहिये जिससे थो दलीय अणाली को प्रोत्साहन मिले। 1

१. एम० के॰ रेडडो—'योलिटिक्ल यार्टीज इन इक्टिया' (इन द इक्टियन रिच्यु, नवम्बर १९६४ पुरु ४२२) ।

# भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

मारतीय सवियान एक जनतानिक सवियान है धत इसमें दो विशेष मुद्दों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। सर्वप्रयम, विभिन्न सीमाएं जिनम सरकार के तीन प्रगो (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभा तथा न्यापपालिका) को सवियान द्वारा स्थापित समीय व्यवस्था में कार्य करना है। इस सब्दें में सर्वेषण्ट न्यापालय में प्राप्तिका एक सतुननक के सानान है, व्यक्ति कहाँ सरकार ने प्रम्य प्रगं जनता की उत्तरित मायना से प्रमावित हो सकते हैं, वहाँ वेचल सर्वोच्च न्यापालय हो सरकार का एक ऐसा ध्यम है जो निष्पक्षता एव वान्तिपूर्वक सरकार के कार्यों की व्याद्या सिकार के सतुनार करने, कार्यों की व्याद्या सिकार के सिकार के सार्वोच्च स्थापालय की स्थापाल की स्थापाल से सिकार के सार्वोच्च स्थापालय की एक विषय प्रमित्त सरकार के सिकार के सार्वोच्च संवच्च स्थापालय की एक विषय प्रमित्त उपसे कर सामने प्राप्ती है। वह यह है हि सर्वोच्च न्यायालय की सवियान की व्याद्या एव सरकार करने का प्राप्ती है।

हमारे सविधान-निर्माताओं ना यह विश्वास था कि सोमित सरकार जनतन के लिए पत्यावस्थन है। "परन्तु सविधान में उन्होंने उस सिद्धान्त नो समावेशित किए प्रत्यावस्थन है। "परन्तु सविधान में उन्होंने उस सिद्धान्त नो समावेशित किए। जिसकी (प्रमारोका के) मुख्य न्यायाधीक मार्शक ने सीमित सरकार ना प्राव- स्वक तव्य माना है कि सविधान द्वारा व्यवस्थापिका नी शक्तियो पर लागू नी गई सीमाधी का धादर किया जाना चाहिये और ग्रीर परि व्यवस्थापिका इन सीमाधी का उत्थान किया ने का प्रति किया जाना चाहिये और ग्रीर प्रति व्यवस्थापिका इन सीमाधी का उत्थान करती है तो उसके कार्य प्रवेध हैं। यह प्रावधान स्थप्ट रूप से हमारे सविधान के प्रमुच्छेद १३ में बालत है।"

सिवपान के धनुन्देद २५४ (१) में यी धवैष कथ्य का उपयोग किया गया है। इस धनुन्देद के अनुसार यदि किसी राज्य विचान समा द्वारा समझी सूची में उल्लिखित किसी विष्णण पर तिर्मित कानून किसी संघीय कानून के विषद है, ऐसी स्थिति में राज्य विचान समा द्वारा निमित्त कानून धवैस होगर।

१ डी० डी० बधु-कमेन्ट्री झान द कान्स्टीट्युशन झाँक इण्डिया, भाग--१ १६६५ पृ० ११६-५९ ।

गय राज्य में सर्वोच्य न्यायालय का विशेष महत्व होता है। वह सविधान का रक्षक है। सविधान के किसी आवधान से सर्वधित शका की दूर करने के लिए सर्वोच्न न्यायालय को सविधान की व्यारवा करने का अधिकार है। इसके अति-रिक्त, मारत में समवाद के विकिष्ट स्वरूप के दिन्दिकोण से सर्वोन्न न्यायालय की मुमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय संघीय व्यवस्था भे, जैसा देखा जा चका है, तीन व्यवस्थापन सचियों का उल्लेख किया गया है । वे है-सप, राज्य तथा समवर्ती सुविवा, जिनके द्वारा सच और राज्य सरवारों के पृषक-पृथक व्यवस्थापन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है। यह कहने म बौई भ्रतिशयोक्ति नही है कि किसी भी शक्ति विमाजन की प्रक्रिया में क्षेत्रायिकार के प्रश्न को लेकर सघ तया राज्यों म बाद-विवाद पदा होता स्वामाविक है। छदा-हरणार्य-शनित विमाजन की मापा धस्पष्ट होने के कारण दोनो पक्षो मे किसी विषय के सम्बन्ध में विवाद पैदा हो सकता है। "प्रतएव ऐसे सारे विवादों का समायान सविचान के जो सर्वोध्व कानून हैं, और जिसम शक्तियाँ केन्द्र तथा इकाइयाँ के मध्य विभाजित हैं, सन्दर्भ में किया जाना चाहिये । साथ ही न्याय मी माँग है कि इस तरह के विवादों का समाधान एक स्वतन तथा निष्पक्ष सत्ता द्वारा शिया जाये । सधीय सविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायासय इस प्रकार का एक न्यापालय है। प्रस्तु यह सभीय व्यवस्था का एक वायस्था माग है। यह सिवपंत की व्यास्था करने वाती सर्वोच्य सस्या है, और सथ तथा इनाइयों के विचायों के समावान के लिए प्रनित्य न्यायाधिकरण है। वारतीय सविधान द्वारा स्थापित सप व्यवस्था मे, मारतीय सर्वोञ्च न्यायालय ना यह एक सब से महत्वपुणे कार्य है।""

द्वितीय, राज्य एक नागरिकों के सन्तवाती के सान्यत्वी में, सर्वोच्य न्यायास्त्र में, सियाना के मतुचार नागरिकों के विशिव्य पूल-पांचिकारों के स्वत्यान का यह कार्य, सियाना की सहस्त्र में साम्यत्वात्त्र का यह कार्य, सियाना की सोमां में राज्य स्त्रा तथा नागरिक स्विवकारों ने मध्य समर्थ की स्थिति में, कनतानिक सहुवन स्थापित करना है। मुख स्विवकारों तथा सामाजिक नियाना में सामाज्य तथा सहुवन स्थापित करना वर्षण एक प्रस्तान करिय पांचे हैं किर मी मारतीय सर्वोच्य नागरिकारण, हमारे स्विवायन के वो मुख्य सामारों, मूल स्विवन स्थापित की स्थारण करेंगा। यात्र स्विव करना हमें स्विवायन की स्थारण करेंगा।

१. एम॰ बी॰ पायसी--'इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन, १६६२ पू० २१६।

### सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

संविधान के अनुन्छेद्र १२४ के अनुसार सर्वोज्व न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया है, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और जब तक ससद कानून बना कर सख्या मे वृद्धि नहीं करती है, सात अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोज्व न्यायालय अधिनियम १६५६ हारा, न्यायाधीश को सख्या सात से दस कर दो गई है। मुख्य न्यायापीश सदद को पूर्वानुमति से किसी उच्च न्यायातय के न्यायाधीशों मे संवद्ध न्यायाधीशों मे तह्य न्यायाधीशों में निवृतिक की आवश्यवस्तानुकार सर्वोज्व न्यायालय में न्यायाधीशों में निवृतिक की आवश्यवस्तानुकार सर्वोज्व न्यायालय में न्यायाधीशों के कारण कर सकेंगा।

मुख्य न्यायाघीत्र की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद १२४ (२) के प्रन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाघीत्रो से विचार-विमर्श करके करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रन्य न्यायाघीको की नियुक्ति इस प्रक्रियानुसार राष्ट्रपति करता है, परन्तु इसके साथ भुख्य न्यायाधीक से परामर्थ सेना घावस्यक है।

संविधान के अनुच्छेद १२४ (३) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नीचे दश्ये अनुसार अहंताएँ आवश्यक होगी ।

# १—वह मारतीय नागरिक हो ।

२—िम्सी उच्च व्यायालय का कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाणीय रहा हो या कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अभिमापक रहा हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार प्रसिद्ध विधि-साक्ष्मी हो ।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायापीश का कार्यकाल ६५ वर्ष की प्राप्नु पर्यन्त माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायापीश को राष्ट्रपति द्वारा ससद के दोनो सदनों में सम्पूर्ण सदस्यता के एव उपस्थित तथा मतदान करने वालो के है बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर, परच्युत किया जा सकता है। सविधान के अनुक्छेद १२४ (४) के अनुतार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दो कारणों से परच्युत किया जा सकता है; वे कारण इस प्रकार है—सिद्ध दुर्व्यवहार तथा प्रस्तमता। यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को परच्युत करने की प्रक्रिया कठिन है; इस कारण न्यायाधीश की प्रपत्ते कार्यो के लिए आवस्यक स्वतत्रता प्राप्त होती है। उनके कार्यकाल के सम्बन्ध में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका प्रतुपित प्रमाव नहीं डाल सकती हैं।

मुख्य न्यायाधिपति का वेतन ४,००० रू० प्रति माह भीर सन्य न्यायाधीशो का वेतन ४,००० रू० प्रति माह है। प्रत्येक न्यायाधीश को रहने के लिए निःशुस्क निवास स्थान भीर सपने कार्यों को करने के लिए यात्रा संवधी मुविधाएँ प्राप्त होगी। साधारणतया, न्यायाधीशों के वेतन तथा मत्तों में जनके लिए प्रहितकारक परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति हारा अनुष्येद ३६० के अन्तेगत धीर्याद विसोध सबरकासीन विचति से न्यायाधीओं के बेवन तथ्य मती में कारी से आ सकते हैं। न्यायाधीओं के बेवन उक्तुबेद ११२(वे)औं(१)के प्रत्योत विधिष्टम से भारत को शवित निधि में रखें क्ये हैं। सविचान के ये विभिन्न आवधान जो न्यायाधीओं की निवर्षित, हटाने तथा बेवन एवं भत्तों से बसधित हैं, सर्वोष्ट

### सर्वोच्च न्यायालय का लेत्राधिकार एवं कायं।

विदित्त राज्य के समय पारतीय सरकार प्रविश्विय १८३१ के प्रार्तने एक सचीय स्वायालय की स्वापना की नई यो । परन्तु इस जायालय के निगंधी के लिए विदित्त प्रिक्ते-गरिवर के पार्थीन की जा सकती थी। १ इस पर्य में इस सचीय ग्यायालय की १८३५ के प्रविश्वय के प्रत्नेगत, सविधान की व्याव्या करने का प्रार्थिकार प्रार्थ था। सचीय ग्यायालय के उद्यादन के प्रवत्त पर, सर मार्रस्त ग्याय ने इस ग्यायालय की प्रतिक्षण पर प्रकाश सम्बद्ध हुए मिनाविधिक्य रिहासिक ग्रायद ने इस ग्यायालय की प्रतिक्षण रहे एति निर्माशिक रिहासिक ग्रायद कहे वो प्राप्त भारतीय क्षत्रीय क्षत्र पर महिलायों के स्वार्य भी प्रयुक्त ग्रामें का सकते हैं .—"व्यवकार एव दर्शों के स्वतन, एव जीतियों के उत्तर-पश्चाव की मार्गाल प्रतिकृति हुए, इसका प्राध्यक्तिक कर्मण स्विधान से आपता करता है कीर मतमेदी का जो एक स्वतन तथा निष्यत्व पत्र की ब्रमुसिस्थित मे उत्तिव्य क्या हिस्सात्मक करात है। इसाराय पह तमें प्रवत्त होणा कि पार्यंक स्वतियाल की, वत्तके बर्तमात करात है। इसाराय पह तमें प्रवत्त होणा कि पार्यंक स्वतियाल की, वत्तके वर्तमात करात है। इसाराय पह तमें प्रवत्त होणा कि सहस्व देखना है, दिसने गरिय परस्य एक कीवित तथा कास सेने वाले प्राणी के सहस्व देखना है, दिसने गरिय

माने बनकर उनका बहुता है—"मेरा निश्चित गत है कि समीप न्यायावय संविधान ती व्याव्या, जोई भीषचारिक या रूबी कानूनी माबना से प्रेरित होकर मही करेया । में भाषा करता हूँ, यह त्यायावय, कि उन राजनीतिक ममावी तथा प्रवाहों को जिनके द्वारा संविधान को जीवनसंवित प्राप्त होनी है, बानून के दायरे में स्ववज्ञा पूर्वक कार्याविन्त होने देशा ।"

सर मारिस गायर ने उपर्युक्त क्वन, मारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी सही है, विशेषकर जबकि भारतीय सर्विधान द्वारा श्रमरीनी सरिधान के विपरीत

१. एम० नायर-एफ० सी० ब्रार० भाग-१ पुन्द, १६३८ ।

२ वही पुरुष ।

ग्यायिक सर्वोच्चता (जिसको प्रमधीकी सविधान में 'कानून की वैधिक प्रक्रिया' के सिद्धान्त पर माना गया है। की प्रधेशा व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता (जिसको मारतीय, सविधान में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धान्त पर माना गया है) को मान्यक्ष दो गई है। इस विधय पर विस्तृत रूप से प्रव्ययन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरक्लोकन के प्रथिकार के धन्तगँत किया जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न कार्य इसके विभिन्न क्षेत्राधिकार में निहित हैं, जो प्रयोलिखित है।

१--प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार---धनुःखेद १३१ के ग्रन्तगैत सर्वोच्च न्यायालय का निश्नलिखित मामलो पर प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

क--सघ सरकार तथा एक या एक से मधिक राज्यो के मध्य निवाद, या

ख—सम सरकार तथा एक याएक से मधिक राज्य एक पक्ष मे एव दूसरे पक्ष में एक याएक से अधिक राज्य , या

ग—सप के दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद । ऐसे विवाद में किसी ऐसे कानून या तथ्य का प्रक्त निहित हो, जिस पर कोई कानूनी प्रधिकार स्राधारित है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार का आरत से समीय व्यवस्था की दृष्टि से विदेश महत्व हैं। सधीय राज्य का मूल सिद्धान्त शक्ति विमाजन का सिद्धान्त है, जिसके धनुसार सथ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के मध्य प्रात्त्र के तिव हैं। तथा है विद्यान करते हुए विशिष्ट कोंचों का निर्वारण किया जाता है। शक्तियों के विनाजन के फलस्वरूप सथ तथा राज्यों के क्षेत्रधिकारों की पित्रता को कासम रखने के लिए सर्वोच्च न्यायासय की भूमिका अस्पिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति के विमाजन के सबध में उत्सव विवादों पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च नयासालय की सर्वायान में जिल्ला व्यवस्थान के सारे प्रावधानों की सुश्च व्यवस्थान के सर्वाया हो विवाद है। "इन सारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि सथ के दोनों पक्षी के लिए न्याय के तराजू के दोनों पत्रहों की समान रहे। श्री वश्ली टेक्चनर का सर्वोच्च न्यायालय की स्थाप व राज्य ध्यवस्था का प्रात्त्र वश्ली वश्ली कर्यों का प्रात्त्र की स्थाप व राज्य ध्यवस्था का प्रात्त्र वश्ली कर्यों कर्यों का प्रात्त्र की स्थाप व राज्य ध्यवस्था का प्रात्त्र व्यवस्था का प्रात्त्र कर के इन्हें वहना उचित ही है। " व प्राप्त का स्थाप का प्रात्त्र के स्थाप का स्थाप का प्राप्त का स्थाप का

२—घपौलीय क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के लिप्प्रिप्त उच्च न्यायालयो भीर न्यायाधिकरणो के निर्णयो के सम्बन्ध में प्रगील सुनने का मधिकार है। सविधान के अन्तर्यंत सर्वोच्च न्यायालय, दीवानी, फीजदारी एवं

१ एम० पो० शर्मा-'द गर्वमेन्ट आँक द इण्डियन रिपश्लिक' १९६० पु०२१४।

सबैधानिक मामलो में अपीस सुनने के लिए देश का सर्वोच्च एव अन्तिम न्याया-लय है। सर्वोच्च न्यायालय का अपीसीय क्षेत्राधिकार निम्नलिश्वित प्रकरणो के सब्द में है।

स—दीवानी प्रकरण-दीवानी प्रकरण के सबस से, सिवधान के घतुण्डेंद्र १३३ के सम्पर्तत वर्षि एक्च व्यावास्त्रय यह प्रमाधित करता है कि प्रकरण धरील करने के सिंद प्रवृत्ति है को उच्च क्यावास्त्रक के निष्कृत किसे, मा प्रतिक्त पारेशित पारेश के संबंध्य न्यायास्त्रय के घरील की वा वनती है। यदि एक्च न्यायास्त्रय प्रमाधित करता है कि प्रवरण निर्मित प्रथा र नहस्तर है कम नही है पार्निय है वसी तत तम्भित है, तो सर्वोच्य

न्यायातय को अपील की का सकती है। गर्—फीजवारी प्रकरण अनुस्केद १३४ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायासय को, किसी उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्वेश अन्तिय बाटेश या संस्ट है अपील की

षा सकती है, यदि वह किसी निस्न न्यायासय के बरी करने के प्रादेश पर

१—प्रपील होने पर, उस झादेश को रह करके असियुक्त को मीत ना दण्ड देता है, ज़ा

र-क्सी श्रमीन न्यायासय से मुकदमा सेकर श्रमियुक्त को मौप का दण्ड देता है, या।

३—प्रमाणित करता है कि मुक्टमा सर्वोच्च न्यायालय मे प्रगील करते के लिए उपयुक्त है ।

सनद को, अनुरुदेद १३८ के अन्तर्गत सर्वोन्च न्यावालय ने अपीलीय क्षेत्रा विकार में विधि 'डारा किसी भी ऐसे विधव ने सबच में जो कि सचीय सुनी मे त्यासालय ने पराममंदिने से इन्कार नहीं निया और न ही विशी मामले में जब मी इस कहार का पराममंदिन राष्ट्रपति की दिया मना उसने उसना पराममंदिन निया मना उसने उसना पराममंदिन निया मना उसने उसना पराममंदिन निया मना उसने पराममंदिन पराममंदिन मन्द्रपति है। निया मना उसने पराममंदिन मन्द्रपति है। निया मना पराममंद्रपति है। निया मन्द्रपति है। स्वर्धि मन्द्रपति है। स्वर्धि में विशेष मन्द्रपति है। स्वर्धि में विशेष मन्द्रपति है। स्वर्धि मन्द्रपति होने से सम्पर्धि सामने स्वर्धि है। स्वर्धि मन्द्रपति होने से सम्पर्धि सामने स्वर्धि है। स्वर्धि मन्द्रपति सामने सम्पर्धि सामने स्वर्धि सामने सामने स्वर्धि सामने सामने सामने स्वर्धि सामने सामने

यहाँ पर कतिपय, ऐसे मामलो के उदाहरण लिये वा सकते है, जिनमें राप्टपनि ने सर्वोच्च न्यादालय की सलाह सी ।

(क) २ जितनकर १९१७ को, केरल नियान समा ने एक विधेयक (केरल राज्य प्रामा विधेयक) प्राप्ति वर केरल प्राप्त ने विद्या स्वयस्थ्य मा पुत्रपति कर के मा प्राप्त किया । विधेयक के विद्याप्त प्राप्तपानी हारा प्राप्त परिता । विधेयक के विद्याप्त प्राप्तपानी हारा प्राप्त परिता । विधेयक के विद्याप्त प्राप्त परिता । वृद्धि, विधेयक मे विद्याप्त के प्राप्त प्राप्त

१. द दिल्ली लाज एक्ट, १९१२, ए० ब्राई० ब्रार० १८५१, ए० सी०

के प्रमन पर नई मतमेद पैदा हो बये। फ्लस्करूप राष्ट्रपति से मागकी गई कि विषेयक पर प्रपत्नी स्वीष्टति न दे, तथोकि इसने बुख प्राववान, यह नहा गया, प्रवैद्यानिन थे।

राष्ट्रपति ने यह मामला, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ने लिए मेजा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श दिया वह इस प्रकार है।

१—मूल प्रधिवारों के क्षेत्र को निर्वारित वरने के लिए न्यायालय राज्य मीति-निर्देशक तत्वों से धनीमझ रहकर निर्णय नहीं दे सकता है, परन्तु उसको दोनों (मूल प्रधिकारो तथा राज्य नीति निर्देशक तत्वा के बीच) में सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न वरना चाहिये।

२--- मनुष्टेद ३०(१) में उल्लिखित सरकाण वानिन तया भाषा सबधी मरूप सस्यको की सारी मिखा सस्याची ने लिए हैं। इसके प्रतिरिक्त, यह सरकाण प्रमुख दान प्राप्त सस्याची ने लिए भी हैं।

३--- प्रतुच्छेद २०(१) ने प्रस्तर्यंत प्रदत्त प्रुत प्रधिकार क्षेत्र का निर्धारण, शिक्षा सस्याके दुष्टिकोण से ही किया जा सकता है। सविवान ऐसी शिक्षा सस्या में पढाये जाने वाले विषयों के सवय में कोई सीमा नहीं सवाता है।

Y—वास्तय में अनुच्छेद ३० (१) का उद्देश्य अस्य सख्यकों को, बहुसरपकों से उनने सरक्षण ने लिए एक डाल प्रवान करना है न कि एक सलवार, जिसके बस से वे बहुसरपकों से मुख्य प्राप्त कर सके।

- (ग) १६५ में मारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मित्रयों ने एक समफ्रीता किया, जिसके फलस्वक्य भारत ने पाकिस्तान की घपनी भूषि का कुछ हिस्सा दिया। ससद में तथा बाहर इस समफ्रीते की तीब प्रातीचना हुई। राष्ट्रपति ने इस मामने को सबाँच्य ग्यायात्य की सम्मति जानने के लिए मेंगा। सबौंच्य ग्यायात्य की सम्मति जानने के लिए मेंगा। सबौंच्य ग्यायात्य की सम्मति-प्रमुखार, भारतीय भू-माग को, नियी विदेशी राज्य की हस्तान्तरण के लिए सविधान में सक्षोधन करता धावश्यक है।
- (य) एक ग्रम्य मामला वो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्ग के लिए सेना मना उत्तरप्रदेश की विधान समा एक न्यायपालिका के मध्य हुए समर्थ से सर्वाधत है। समानवादी दत वे एक वायंवती त्यों केशवदेवसिंह को विधान समा के प्रस्था द्वारा, विधान समा में उपस्थित होते को कहा गया, परन्तु प्रों केशवसिंह ने ऐसा नहीं विधा । धाराप्त प्रथम द्वारा श्री केशवसिंह को दिनास से लेकर विधान समा में प्रें विधान समा में विधान समा के श्री केशवसिंह को सात होता होता होता समा ने श्री केशवसिंह को सात होता होता होता होता होता समा ने श्री केशवसिंह को जमानत पर दिहा करने का श्रादेश स्था के सलनक खण्ड के श्री केशवसिंह को जमानत पर दिहा करने का श्रादेश

दिया। उत्तरपरेश विधान सना ने उच्च न्यायालय वे इम धारेश को धारो विभोगा
रिकारो का उत्तरपर माना। उत्तराकात् विधान समाने सारेश दिया हिन्न
न्यायानीमों ने भी वेचकिंद्व की दिव्य करते ना धारेश दिया का उने में दिसक में लेकर सदन के समस्त अस्तुत किया जाये। परन्तु न्यायामीमों के विद्युत मोरे विधारण प्रारोग नहीं लगान बचे थे। उच्च न्यायालय के २० न्यायामीमों एक अरू के दिल्ये का विधान समाने के उच्चुंक धारंश को बार्चिटिंग होने से रोक दिया। दिनान समा ने न्याय मूर्ति वेच तथा बहुनान के दिसानत में लेने सबती प्रधान के धारेश को स्वाप्त के तिल्य किया के स्वाप्त के पहले तथानी किया कि उप्युत्त न्यायामीमा ने उच्चे वचान के तिल्य निव्य के पहले तथाना नुनार प्रवास दिया जाये। इच्चे क्लावकर इनाहाबाद उच्च व्यायालय के ११ न्यायानीमा के सक्तवेठ ने धारेश जाये किया कि विभावसमा हाए पारित

उत्तर प्रदेश विधान समा तथा न्यायपालिका के मध्य संघर्ष के तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे ।

१--त्यायपानिका तथा विधानसभा के अधिकार और शक्तियों का सथर्ष । २--विधानसमा के अधिकार तथा शक्तियाँ।

तररश्वान् की जबसुबनात हायी (राज्यमत्री, शृह-मत्रानय, मारत सरकार) ने सोकसमा म घोषित विचा नि राष्ट्रपति ने उपयुक्त भामते की, सर्वोच्च न्यायालय

भी सम्मति प्राप्त नरने के लिए मेर्ब दिया है। नितम्बर ३०,१६६४ नो मुख्य न्याप्राधीत श्री गडेन्द्रयटनर ने सर्वोच्च न्याया-

स्वतन्त्र २०, १९६४ ना सुन्य न्यायायीय श्री सकेन्द्रयटनर ने संबोच्च न्याया-स्वय की बहुमन द्वारा दी गई राय को निम्नलिखित रूप से घोषिन किया।

१—उत्तरप्रका उच्च न्यायात्व के ललनऊ खण्डपीठ को श्री केमर्वीस्त की याचिका, जिसस अन्द्रीत विचान समा द्वारा उनको दिने गम दण्ड को चुनौनी दी, सुनने का पूर्व प्रियकार था।

२—श्री सोनोमन को, यो नेशवींतह की तरफ से उच्च न्यायात्य को याचिका देने का प्रधिकार या और श्री नेशवींतह को, निशान समा के निर्णय के दिच्छ उच्च न्यायालय को प्रयोत्त करने का प्रधिकार था।

२-- जानावच का अवात कर का आवकार था । र--- जानावच का समा का दो न्यायाचीको तथा थी सीतीमन को प्रपते समझ पेस करवान का अधिकार, विवान सना के क्षेत्र में नहीं था । विवान समा

को उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का कोई स्रविकार नहीं था।

४—इलाहाबाद उच्च न्यायातय के खण्डपीठ को दोनो न्यायाधीशी की याचिचा गुनने का तथा विधान समा श्रम्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध जारी विधे हुए वारट को स्यगित करने वा पूर्ण श्रमिकार था।

मुख्य न्यायाधीश्च ने इस विषय पर श्रीधक बल दिया कि यदि विधान समा के किसी न्यायाधीश्च के विरुद्ध वारट जोरी नरने के दाने को, मान्यता दो जाती है तो इसने परिणाम स्वरूप न्यायपातिका नी स्वतत्रया को प्रतुन्धिद दान ने गहरा धक्का लोगा। अनुष्केद २२ के वन जन न्यायालयों को प्रतुन्धिद राने अन्तर्भाव सर्वोच्च न्यायासय की शक्तियों के सन्वय में कोई अपवाद नहीं हैं। यह तर्क प्रस्तुत करता कि नासरित अपने मुल-परिकारों की रखा करने के लिए न्यायालय की श्वरण नहीं के सकता, व्यर्ष ही होगा। अतएव, जत्तर प्रदेश की विधान समा तथा न्यायपातिका के सथपं के सन्वय में सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चय ही एक पूल विद्यात की महत्ता पर धपने परामश्चे द्वारा बल दिया है कि न्यायपातिका सरकार कार्य प्रगी (व्यवस्थापिका सभा तथा कार्यश्वितन) से स्वतत्र रह कर ही धपने कार्य जीवत रूप से कर सन्नेगी।

मूल ग्रधिकारो के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

भारतीय सविधान के ब्रध्याय तीन में भारत के नागरिकों के सात मूल-प्रिय-कारों का उत्तेख है। अनुच्छेद ३२ के अनुसार सर्वोच्च ग्यायालय को मूल-प्रियकारों की रक्षा करने के लिए ब्रादेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। यह रिट निम्नलिखित प्रकार की है:—

१—परमादेश (मेन्डेमस), २—बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेबियास कारपस),

३—प्रतियेय (प्राहितिगत), ४—उत्प्रेषण (सर्राट्योरेरी) और ४—प्राप्तकार पृच्छा (क्वो बारप्टो) वास्त्रय में अनुच्छेद ३२ द्वारा नागरिको के मूल प्रिमेकारों का प्रतिकृतन होते की स्थित में नागरिकों के लिए उपधार की व्यवस्था की गई है। यदि किसी नागरिक के मूल प्रयिकार का हनन होता है तो वह सर्वोच्च नामालय की सहायता से सक्ता है।

सविधान के अनुन्धेद १३ के अनुवार कोई भी कानून यदि मूल प्रधिकारों का हनन करता है तो उसनों धवेष माना जायेगा। श्रतः यह स्पष्ट है कि अनुन्धेद १३ तथा अनुन्धेद २२ के अनुवार नामरिकों के मूल प्रधिकारों के सरकाण की दृष्टि संसर्वेच्च न्यायासय की विशेष प्रधिकारों के प्राप्त प्रधिकारों हो जाती है, जब कि स्वयस्पिका ने कोई ऐसा कानून या कार्यपासिका ने ऐसी स्थार पारित किया है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। ऐसे कानून या प्रार्थेष को अने अधिक स्थार है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। ऐसे कानून या प्रार्थेष को अधिक स्थारित करते की प्रस्तिम जिन्मेदारी सर्वोच्च न्यायासय की ही है। "रमेश थापर

बनाम महास राज्य' मे सर्वोच्च न्यायालय का यह मत या कि प्रमुच्छेद ३२ द्वारा गागरिको ने मूल प्रविचारो वी रक्षा करने के लिए एक प्राव्यासित उपचार दिया गया है, धीर इस उपचार के प्रविकार को स्वय सविधान में एक मूल प्रविकार गया है। इस तरह यह न्यायालय भूल प्रविकारों का सरक्षण तथा ग्राव्यालय है। १

स्वावर्गिरक पृष्टि से बरि सर्वोच्च न्यायालय का उपमुंक भूमिना का गरीक्षण विमा जाये, तो यह बात होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में घपनी माकियों ना सुप्रयोग, मार्गार ने मूल मिक्कारों के सरक्षण के नियर विमा है। गीपालन बनाम महास राज्य पुण्डले से सर्वोच्च न्यायालय में इस उद्देश्य से निवारक निरीध मिनितम के तत्व १५ को बर्चेच माना। 'ब्याब्दें बनाम बन्दर्ड निशा समाने पृश्यम में साप्त सरक्षणे के सास्कृतिक तथा में मिक्क मिक्कारों में हाता समाने नियर सर्वोच्च न्यायालय में निर्में दिया। में है। पुत्र सर्विचारों को सर्वेचारी में सर्वेचारी के सत्वयों में सर्वोच्च न्यायालय में निर्में प्रथा से में नार्गारिकों के पुत्र अधिकारों की रखा की है। पुत्र सर्विचारों के सर्वेचारी के सत्वयों में सर्वेचारी के सत्वयों में सर्वेचारी के सत्वयों में सर्वेचारी के सत्वयों में सर्वेचारी में स्वर्मा में स्वर्मा मिक्स प्रथा सर्वेच स्वर्मा मिक्स में प्रवाद सर्वेचा। परवृत्य मुख्यमा प्रश्ला में सर्वोच्च स्वर्मा मिस प्रयाद में स्वर्मा मिस प्रयाद में स्वर्मा मिस प्रयाद में स्वर्मा मिस प्रयाद में स्वर्म स्वर्मा मिस हारा दिया स्वर्मा में स्वर्म माम्यालय होता दिया सर्वोच्च सर्वोच्च स्वर्माम में स्वर्म स्वर्मा मिस हारा दिया सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च स्वर्मा में स्वर्म स्वर्म में सर्वोच्च स्वर्म स्वर्म मिस सर्वोच्च स्वर्म स्वर्म माम्यालय में मह स्वर्म माम्यालय में स्वर्म सर्वोच्च सर्वोच्च स्वर्माम सर्वेच सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वाच्च में सर्वोच्च सर्वाच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वाच्च में सर्वोच्च सर्वाच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच सर्वेच सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वेच सर्वोच्च सर्वेच स्वेच सर्वेच सर्वेच सर्वेच सर्वेच सर्वेच सर्वेच सर्वेच सर्वेच सर्व

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूनरवलोकन की शक्ति

सस्तृत न्यायिव पुत्रस्तीकन वा श्रापितार ही सर्वोच्च न्यायालय को मारतीय सरियान के सन्तर्थत एक सन्तुतन चक्र वी भूमिना प्रदान वरता है। मारतीय सरियान के सर्वर्थ के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक संश्लेखन तीन प्रकार के मानती मे स्पर्यित किया जा सक्ता है.—

१---मूल भविकारो तथा राजसत्ता के सवधी म ।

२-संघ तया राज्यों के सवधों से ।

सरकार के तीन धनों के एक दूसरे के सवधों में ।

प्रत: हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि न्याधिक पुनरवलोकन के सिद्धान्त का नया प्रयं है रे श्री टी डी बसु के अनुसार—"पुनरवलोकन ना टिक्शनरी सर्थ—किसी

१. रमेश यापर बनाम सदास राज्य-ए. ब्राई. बाट. १६४० हस.सी. १३४।

कार्यं का पुन धवलोकन करना है, जिससे गलती दूर की जा सके। इस शब्द का प्राथमिक कानूनी अर्थ एक उच्च न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालयों की दण्ड की आजा या दिकी का पुन' धवलोकन करना है। "" आयों उनका ही क्यन है— "-यायिक पुनरवलोकन को अमरीका के कानून में एक और तवनीकी महत्व है, जो इन्लेण्ड में हमें प्रया जाता है। यह दो कानूनों सायारण एक मूल कानून के सिद्धान्त से उत्तर होता है। जैसे ही यह मान लिया जाता है कि एक मूल कानून है जो राजनीतिक प्रधाली में सारी व्यवस्थापन सत्ता का प्राथार क्या होते हैं, कलस्वरूप यह किसी भी साआरण विश्व निर्माण सस्या का मार्य मूल कानून के प्रावधानों के चिरुद्ध है, वो वह अर्थ होता। अपेट इस तरह के अवस्थापन मार्य की प्रवेद भीपित करने के लिए किसी अग को प्रधिकार होना चाहिए। अमरीकी न्यायपालिका ने सामान्य सहमति से यह कठिन कार्य धारण कर लिया है। यह न्यायिक पुनरवलोकन का प्राथमिक क्या है। सह न्यायिक पुनरवलोकन का प्राथमिक कार्य है। सह न्यायिक पुनरवलोकन का प्राथमिक कार्य है। सह स्था की स्थापिक पुनरवलोकन के प्रवर्तक साने जाते हैं, ने इसी प्रयं की प्रहण

'सार्वजनिक वानून में क्यायिक पुनरवलोकन केवल व्यवस्थापिका के कार्यों के पुनरवलोकन तक ही सीमित नहीं है। जब सविधान को एवं दार देश का सर्वोच्च कानून मान लिया है और सरकार के सारे अयो की शक्तियों को इसके प्रावधानी द्वारा सीमित समक्र लिया गया है, परिणाम स्वरूप न केवल व्यवस्थापिका साम के किन्तु कार्यपालिका के वे सारे प्रवासकीय कार्य प्रविच होगे जो सविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और न्यायालयों द्वारा उनकों प्रविध मानना होना है'।

सक्षेत में जैसा श्री इ एस कारबीन का कहना है, "स्यायिक पुनरवलोकन स्यायालयों की शक्ति है जो उनके साचारण क्षेत्रायिकार में पाई जाती है जिससे वे व्यवस्थापिका के कार्यों की सबैधानिकता पर उनको लागू करने, या ऐसे (कानूनो) को जिनको वे प्रवेष पाते हैं, लागू करने से इंन्कार करने का निर्णय लेते हैं। "भ

जब एक लिखित सिवधान द्वारा सधीय व्यवस्था तथा नागरिको के मूल प्रधिवारों के लिए प्रावधान किया जाता है तो वास्तव से सविधान से उन धारों

१ डो० डो० बसु पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १५६।

२ वही पृ० १४६।

३ ई० एस० कारबीन-'ऐसे झान बुडिसियल' रिल्यु (इन व एनसायकसोपिडिया माफ सोराल साइन्सेस, भाग⊶द पृ० ४४७) ।

४. वही पुरुष्ठ्या

को स्वापित किया जाता है जिनके तिए एक सर्वोच्च न्यायालय पावस्यक है। संबद्धाद तथा नागरिको के मूल मधिकार किसी मी लिखिन सक्षियान के स्वरूप नो देश के सर्वोच्च नानून के रूप में निर्धारित नरने के लिए प्रयोग्न हैं। यदि स्वय सर्वितान में विशिष्टरूप से यह लिखा भी नहीं गया है कि सर्विधान देश का सर्वोच्च कानून है, परन्तु सविधान में सधवाद व मूल अधिकारों को रखा गया है। भौर यदि सविधान ने संशोजन करने का एकाधिकार केवल सबद म निहित म होनर, ससद तया राज्य विधान समाधो दोनो को समान रूप से प्राप्त है हो यह कहना सन्य होगा कि सर्विधान देश का सर्वोच्च कानून हैं। सर्विधान की सब्देंच्चता नायम रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की मावश्यकता है, को क्लि कानून या कार्यया आदेश के सविधान के विरुद्ध होने की स्थिति म सक्त कानून या कार्यया आदेश को सर्विध घोषित कर सके। अनएव सविधान ही सर्वोचना के पारण ही सर्वोच्च न्यायासय को न्याधिक-पुनरवर्ताकन-प्रक्रिकार स्वत प्राप्त होना है। "यह प्रधिकार संद्रान्तिक दुन्तिकोण से हमारे सर्वितान का प्राप्तार पुत सिद्धान्त है। यह सर्वोच्च न्यायासय द्वारा गोपासन के प्रकारण में स्वीष्टत किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि धनुष्येद १३ की केवल मत्यिक सावधानी के लिए ही रखा गया और दिना इस प्रकार के दिसी प्रावधान के भी स्थिति वैसी रहती ।""

मारत के सर्विधान में ब्रमधीकी सर्विधान के विपरीन सर्विधान की सर्वोच्चना के लिए कोई विशिष्ट प्रावयान नहीं है, किन्तु चूँकि समयाय तथा मूल मधिकारी के सिद्धान्तों को भारतीय सविधान में स्वीइत विया गया है, भीर सविधान में संशोधन करने का संसद को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, यह अधिकार संसद तथा राज्य विधान समाधी दोनी म निहित हैं, इनसे सविधान स्वत ही देश ना सर्वोच्च कानून हो जाता है। क्यकि जिस सर्विधान में सथ तथा राज्या के मध्य शक्तियों के विभाजन द्वारा सरकारों को सीमित शक्तियाँ प्रदक्त की जाती है, और पुषक क्षेत्राविकार स्वापित किये जाते हैं, वहाँ सविधान की सर्वोद्यक्त भी स्वत निर्मारित ही जानी है अन्यथा समवाद का कोई मूल्य ही नही रहेगा। सपबाद के परिणाम स्वरूप सीमित सरकारों की स्थापना होती है, जो प्रपत-

सेत्राधिकार के वाहर कार्य नहीं कर सकती हैं।

इसने भविरिक्त सविवान में मान्यवा प्राप्त किये मूल ग्रविकार भी सरकार पर एक प्रतिबन्ध के रूप में हैं, जिनके विरुद्ध निर्मित कानन को न्यायपालिका ग्रवैय योदिन कर सननी है। ग्रवरीका में इसी मुद्दे वा स्पष्टीकरण करते हुए, 'मारवरी बनाम मेडीसन' प्रकरण से निर्णय देते हुए न्यायिक पुनरवतीकन के

१. डी॰ डी॰ बसु॰--पूर्वोक्त पुस्तक, प्र॰ १५७।

सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य न्यायाधीश मार्शत ने मारवरी की, परमादेश जारी करन के लिए दो गई याचिका की प्रस्तीवृत कर दिया। जनवा तमें या वि भारवरी की परमादेश सवधी याचिका, जो १७६६ ने न्यायपालिका अधिनियम पर आधारित थी. श्रमान्य थी नयोकि १७८६ का स्यायपालिका ग्राधिनियम स्वय ग्रावैध या । मार्श्वत का क्यन था-"व्यवस्थापिका की शक्तियाँ परिमापित एव सीमित हैं और चूँकि इन सीमाओ के सबध मे कोई गलती न हो या उननो मुला न दिया जाय ग्रत सविधान लिपित रसा गया है। यदि सीमायो का उस्तवन उन लोगो द्वारा होता है, जिनको रोकने के लिए इन सीमामो को रला गया है तो उन सीमामो को लिखित रूप देने का क्या खहैश्य है ? सिवधान या तो एक उच्च मूल कान्न है, जिसको साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तिन नही विया जा सक्ता है या यह साधारण कानूनो के स्तर का है ग्रीर ग्रन्थ नानुनो ने समान परिवर्तनशील है, जब मी व्यवस्थापिका ऐसा परि-वर्तन वरना चाहती है। यदि पहला विकल्प सत्य है ती एक कानून जो सविधान में विरद्ध है, वानून नहीं है। परन्तु यदि दूसरा विकल्प सत्य है तो लिखित सविधान उन लोगों ने मुख्तापूर्ण प्रयत्न है जिनके द्वारा विसी माक्ति नो जो स्वरूप में ब्रसीमित हैं सीमित निया जाता है।"1

न्यायिक पुनरवलोक्त के अधिकार का भौकित्य बतलाते हुए, मुस्य स्थाया-धीश मार्शत ने तर्क प्रस्तुत किया या कि जहाँ वही भी लिखित सर्विधान है, ग्रीर ऐते सनिधान द्वारा सीमित शक्तियों की सरकारें तथा व्यवस्थापिकाए स्थापित की गई है, जैसी एवं सघ राज्य में होती हैं, और यदि सविवान में उपयोग मे लाई मापा ऐसी है, जिसके अनुसार निर्धारित सीमाझी को लागू करना प्रति-मावश्यन है, तो समक्तना चाहिये कि न्यायालयों की यह मादेश प्राप्त है कि इन निर्मारित सीमाभ्रो को लागू करें और त्यायाधील सर्विधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ग्रपनी प्रतिज्ञानुसार विधित है, जो देश ने 'कारनून की सर्वोच्चता' मा प्रथम तत्व है।<sup>३</sup>

ग्रमरीकी सर्वियान मे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरवलोकन ने मधि-नार ना विशिष्ट रूप से नही उत्तेष नही है, परन्तु मुख्य न्यायांघीश मार्शल द्वारा दिये गये 'भारत्ररी बनाम मेडीसन' प्रकरण में निर्णय के श्रनुसार सर्वोच्च न्यापालय को न्यायिक पुनरवलीयन का ग्राधिकार प्राप्त हुआ है । इस शक्ति के ग्रनसार

१ जे० मार्शस का उद्धहरण- जे ब्राइस द्वारा, द श्रमरीकन कामनवेल्य 4 \$464 90 28X 1

२. एस॰ सी॰ डेश, 'दी द्विडयन कान्स्टीट्युशन' १९६०, पृ० ३३६ । ŧ٥

सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून, या धन्य प्रिपिकारी द्वारा दिये प्रादेश या टिकी का, जिनको धमरीकी सर्विधान के विरुद्ध बतलाया गया है, पुनरवलोकन करने का घषिकार है।

"एक विदान धरेब को एक कहानी है, तिससे यह सुनकर कि सर्वोच्च त्यापान स्वाप्त के पर्वच को पर्वच की पर्वच के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के

मारत म सर्वोच्च न्यायासय पुतरवत्योकन के अधिकार का भाषार धमरीकी सर्वोच्च न्यायासय की पुतना में, सविधान में धिक दृद रूप से हैं, विशेषकर महिद्यात के दो प्रावधानी में यह भाषार विद्वित है।

सर्वत्रमम, मून मिकारो नी दृष्टि से मृत्कुद १३ के मृतुसार यदि किसी कानूद द्वारा किसी मून अधिकार का उत्तक्षण होता हैतो उस कानून को मर्बक मीधित किया जा सरवा है। सविषाल के मृत्कुदेश ३२ के मरावार्त मरने मूल मीदकारों का उत्तक्षण होने पर बोई भी नामरिक स्वैषानिक उपचार प्राप्त करने के किए सर्वोच्च न्यामालय की सरण से सन्तता है। प्रवार्ण सर्वोच्च न्याया-त्वा किसी भी कानून या सारेश ना पुनरवनीकन, सविषान नो व्यास्त्रा करते हुए मूल मीवनारों के वास्त्रण के लिए कर सनवा है।

२. जे॰ ब्राइस-पूर्वोस्त पुस्तक, पृ० २४१--४२।

३. वही

ह० २७२—६३ ।

द्वितीय, प्रनुब्छेद २५४ के बनुसार भारतीय संपीय व्यवस्था मे शक्ति विभाजन प्रणाली के मन्तर्गत सघ तथा राज्यों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को, जो विसी राज्य द्वारा प्रपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्मित किया गया है, सर्वेष घोषित कर सकता है। अनुच्छेद २४४ मे यह प्रावधान किया गया है नि समवर्ती सूची मे उल्लिखित निसी विषय पर यदि किसी राज्य विद्यात समा द्वारा निर्मित वानून सघ ससद द्वारा विसी कानून से समर्प मे है, ऐसी स्थिति मे राज्य कानून को अविद्य माना जायेगा । अतएव, यह स्पष्ट है कि मारत में सर्वोच्च न्यायालय को सर्विधान के अन्तर्गत किसी भी विधि या नियम या प्रादेश का पूनरवलोकन करने का अधिकार है, जिससे यह निर्धारित विया जा सके कि वह विधि या नियम या बादेश सविधान के बनुसार है या नहीं है। इसी मुद्दे पर बल देते हुए मुख्य न्यायाचीश पातजलि शास्त्री ने 'मद्रास राज्य बनाम रीव' नामक प्रकरण में कहा-'हम सोवते हैं कि यह उचित है कि यहाँ यह बतलाया जाये, जिस पर कभी व्यान नहीं दिया जाता है, कि हमारे सविधान में विधि के सविधान के अनुकुल होने के प्रश्न के लिए, न्यायिक पुनरवलोकन के लिए अमरीका के विपरीत जहाँ पर सर्वोज्य न्यायालय ने व्यवस्थापिका के नायों के पुनरवलोकन करने के लिए विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, विशिष्ट प्रावधान हैं।" सक्षेप मे, न्यायिक पुनदवलोकन का अधिकार साधारणतया, प्रत्येक शुज्य मे सर्वोच्च न्यामालय को लिखित सविधान की सर्वोज्यता के सरक्षण के लिए प्राप्त होता है। श्री बसु का कहना सत्य है कि "जैसे मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने ग्रमरीकी सविधान के लिए कहा है, हमारे सविधान द्वारा भी इस सिद्धान्त को जो कि सारे लिखित सर्विधानों के लिए आवस्यन है, स्थापित तथा दृढ किया जाता है कि कोई मी कानून जो सर्विधान के विरुद्ध है, अवैध है।<sup>22</sup>

सतएन, मारत के सविधान की सर्वोच्चता के तीन कारण हैं, जो निम्मलिखित हैं १—सविधान में, सधवाद के विद्यान्त की, अनुच्छेद २४६-२६३ के अन्तर्गत मान्यता प्रदक्त कर सम तथा राज्यों के लिए पृषक क्षेत्राधिनार निर्मास्ति करना।

२—सर्विधान के झप्पाय तीन ये नागरिकों के मूल श्रीयकारों को मान्यता देना और समुख्देद १३ के बाचार वर इस बात पर बल देना कि यदि कोई कानून मूल प्रियकारों से कभी करता है या मूल श्रीककार समाप्त करता है, तो बह भर्वय होगा !

१ पी० शास्त्री-मदास राज्यबनाम रोव, १९४२, एस० सी० धार० ५६। २ बी० डो० बसु-पूर्वोत्त पुस्तक पु० १५६।

३--सिवंचान द्वारा ससद को सिवंचान-सबीधन का एक प्रियकार न देते हुए, सतद् तथा राज्य विचान सवाक्रों को यह अधिकार देना (उन विधयो पर जो, दोनों सच तथा राज्यों के विए महत्वपुण हैं)।

इन कारणे द्वारा प्राप्त बारतीय सर्विधान की सर्वोज्वता को स्थिर राजने के लिए सर्वोज्ज व्यायालय को न्यायिक पुनरवलोकन का प्रधिकार स्वत. प्राप्त इसा है।

मारत तथा प्रमरीकी सर्वोच्च न्यायाचयो के न्यायिक पुनरवत्तीकन के साथि कारों का तुननात्मक प्रत्ययन करने पर यह स्वच्छ हो जायेया कि मारतीय तर्वोच्च स्थायाव्यय के न्यायिक पुनरवत्तीकन का अधिकार हतना विस्तृत नहीं है, जितना स्वमीकी सर्वोच्च न्यायात्मय का न्यायिक पुनरवत्तीकर वा अधिकार है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरवलोकन के अधिकार पर सर्विभान हारा स्थापित सीमा के दो पहलू हैं । सर्वप्रथम, सरकार के शीन धरो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सौर ज्यायपालिका के सवधो तथा सम तथा राज्यों के सवधो की इंटिट से, मारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरवलीकन की शक्ति का क्षेत्र, समियान में इन विषयों पर विस्तृत प्रावयान संघा स्पन्धीकरण होने से सीमित है। भारत के सविधान में न शिर्फ सरकार के तीन अभी के संघठन कार्यों तथा शक्तियों का विन्तुत उपलेख है, विन्तु सथ तथा राज्यों के अध्य तीन कृषियों हारा निस्तृन क्षत्र के सेमारिकार का उक्तेख किया जया है। धमरीका के सविधान में इत तरह सेनायिकार का विस्तृत उपलेख नही है, केवल १= विषयों पर सम सरकार को समिकार प्राप्त है, जबनि कीय समिकार राज्यों को प्रवस्त हैं। इस नारण समरीकी सबॉन्च न्यायालय ने सविधान की व्याख्या करते हुए निहित शक्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके सथ सरकार को ऐसी शक्तियो पर श्रथिकार प्रदत्त किया है जो इन १व मक्तियों में सो निहित हैं परन्तु सविधान में उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सविधान नी निस्तृत रूप से व्याख्या अरने का प्रविकार प्रमरीनी सर्थोंच्य म्यायासय का एक महत्वपूर्ण श्रविकार है। श्रमरीकी सर्वोच्च न्यायासय भवने 'बौदिक मापदण्ड' से सविधान की विस्तृत व्याख्या कर सकता है। मारतीय म्यायपालिका को सविधान की व्याख्या करने के लिए अपनी भीति की उपयोग में लाने का ऐसा कोई माधिकार नहीं है। चुँकि दोनो (समीय तथा राज्य) ध्यव स्यापिका समामो ने क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से, साथ ही एक विस्तृत क्षेत्र पर समवतीं अधिकारो का उल्लेख किया गया है, और धविणट शक्तियाँ सथ ससद मे निहित की गई हैं, शत, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को पृथक करने वाली रेखा मे परिवर्तन करने का कोई अधिक अधिकार नहीं है। "भारत मे, एक निहित शक्तियों के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का प्रधिकार प्रत्यन्त सीमित है, क्योंकि एक विषय की विस्तृत व्यास्था करने से किसी विषय से धन्य स्वान पर सपर्य हो सनता है। धतएव न्यायपालिका की बौदिन कसरत को सवियान द्वारा निर्धारित सीमाझा भ हो दिसाना चाहिये। सारत म विधि का न्यायिन पुनरवलोकन धनुच्छेद २४६, जिसके धनुसार अपने क्षेत्र मे प्रत्येक व्यव-स्यापिक्त समा सार्वमीम है, के धन्तगैत ही विया जा सकता है।"

भ्रमरीका में सविधान का सामान्यता के ग्रतिरिक्त, वैधिक प्रक्रिया (इस प्रोसेस ग्राफ ला) के उपवन्य को ग्रपनाने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय को सर्विधान की विस्तृत व्यार्या करने का अधिकार प्राप्त है। अमरीकी सविधान म सारे विषयी पर सारत के सविधान के विपरीत, विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप समरीकी सर्वोच्च न्यायालय को, अपने 'बौद्धिक मापदण्ड' का उपयोग करते हुए सविधान की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करने का प्रधिकार प्राप्त हमा है। मतएव ममरीनी सर्वोच्च न्यायालय ने भमरीनी समाज की बदलती हुई सामाजिन, राजनीतिन एव मायिक परिस्थितियों के मनुसार, सविधान की व्यास्या 'वैधिक प्रक्रिया' (इय प्रोसेस धाक ला) के धाधार पर की है। परन्त मारत का सविधान एक विस्तार पूर्वक लिखा सविधान है, जिसकी ब्याख्या करते समग्र सर्वोच्च न्यायालय अपने बौद्धिक भापदण्ड का उपयोग प्रत्यन्त ही सीमित रूप से कर सकता है। "हमने न्यायिक पुनरवलोकन की स्थापना की है, तथा उसको मान्यता देते रहगे नयोकि एक साधन के रूप में इसके द्वारा उस मूल जहेश्य नी प्राप्ति हो सके, जिसका समर्थन मृत्य न्यायाधीश भागेल ने किया था, प्रयात सत्ता पर मूल कानून (सविधान) द्वारा सीमाओ को लागू करना, परन्तु इस सीमा से बाहर जाकर हम, एक व्यायिक महामानव को राजनीतिक के स्थात पर स्थापित करने को तैयार नहीं हैं, क्योकि जैसा व्यायमूर्ति चेकसन ने कहा है कि, न्यायिक अपहरण अन्य अपहरण की तरह देश के लिए एक स्थाई अच्छाई सिक्ट नहीं हो सकता है। व

भारतीय सविधान एक विस्तार पूर्वक लिखित सविधान है। सविधान स्वय जनता ही जीतित वाणी है, जिसकी अभिव्यक्ति करना सरकार के तीनो अगों भी विशेष जिम्मेदारी है। "अतपूब अमरीका के विषरीत सर्वोच्च न्यायालय को सविधान नी जीतित वाणी माना यहा है, गारत से स्वय सविधान, किसी भी समय पर, प्रपनी अभिव्यक्ति करने मे समय है। नि सदेह न्यायापीधों को सविधान की बर्तमान स्थिति अनुसार व्यास्था करना है, परन्तु यदि न्यायाधीयों को सविधान करते हैं या जनता के हितो के विस्त निर्णय देते हैं, तो यह जनता के प्रतिनिधियों

र. एस॰ सी॰ देश-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ३४५।

२. डो० डो० बसु—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४४ ।

है, ग्रर्थात् (क) सर्वावत कानून व्यवस्थापिका के क्षेत्र मे है या नहीं है, ग्रीर (स) वैधिक प्रक्रिया की सारी ग्रावस्थकताग्रो को पूरा करता है या नहीं। व्यवस्थापिका द्वारा निमित बानून उसके क्षेत्राधिकार में हो सकता है, परन्तु यदि वह 'वैधिक' प्रक्रिया' के विरुद्ध है अर्थात् मान्यना प्राप्त प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त के विरुद्ध है तो ग्रमरीकी न्यायालय उसे ग्रवैष घोषित करता है। भारतीय सविधान मे 'वैधिव प्रक्रिया' उपबन्ध की बजाय 'विधि सम्पन्न प्रतिया' का है । यह मूल प्रन्तर है और इसके द्वारा मारतीय सर्वोच्च न्यायालय को 'प्राकृतिक वानूम' प्रयात-किसी विधि मे अन्तनिहित अच्छाइयो-बुराइयो के अनुसार उसकी वैधानिकता निर्धारित करने की वसीटी की लागू करने से रोक्ता है।" विद मारतीय ससद या किसी राज्य विधान सभा द्वारा विधि का निर्माण अपने क्षेत्र में किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी विधि को मान्यता देना होगा, क्योंकि मारतीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी विधि का पुनरवलोकन इसलिए नहीं करना है कि उक्त विधि के ग्रीचित्य को उसकी अन्तरिनिहत अच्छाई या बुराई के आधार पर निर्धारित कर सके, बत्व इसलिए करना है कि यह निर्धारित किया जा सके कि उक्त विधि सवि-धान के अनुकुल है या नहीं, । सक्षेप में यह कहना उचित होशा कि अमरीकी न्यायालय ने विपरीत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 'प्राकृतिक' कानून' प्रयौत् 'वैधिक प्रक्रिया' की कसौटी का उपयोग न कर केवल सविधान को ही किसी विधि की वैधता निर्धारित करने के लिए कसीटी मानकर अपने निर्णय देशा ।

श्रमरीका म, जैता देशा जा चुका है, 'वैधिक' प्रक्रिया' के सिद्धान्त के प्रमुक्षार सर्वोच्च प्रवासन प्रवर्ष 'वीदिक मायदण्ड' का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करता है। पद्यपि वहीं 'वैधिक प्रक्रिया' को परिनाधित नहीं किया सवा है, इसके विभिन्न सर्वित पूर्व स्पट हैं।

सामान्यत 'वैधिव प्रश्निया' वा तास्ययं वैधानिकता, तक्ष्यूणंता, तथा निप्पक्षता से हैं प्रयांत जो निर्मुख, अताकिक तथा पक्षपातपूर्ण नहीं है। प्रस्येक मामले भे समरीवा भे स्वामाधी ही अनितम रूप से निर्मारित करते हैं कि क्या कोई विधि, निपम, या प्रादेश, निरमुख अर्धानिव या पक्षपातपूर्ण तो नहीं है। इसके परस्व-रूप प्रमानिव में 'त्यायपातिवर, को सर्वोच्चता के सिद्धान्त' को उत्पत्ति होती है भीर सविधान वा प्रर्व त्यायाधीकों की व्याख्या पर निर्मुद हो जाता है। मारत में त्यायपातिवर के सर्वोच्चता के स्वाच्चता को प्रयास सविधान की सर्वोच्चता पर व्यव दिया गया, है। प्रसाद प्राप्तिक को प्रमाणित को प्रमाणित सर्वोच्चता पर व्यव दिया गया है। प्रसाद प्राप्तिक साध्यक्ष के प्रमाणित स्वाचना की सर्वोच्चता पर व्यव दिया गया है। प्रसाद वीदिक साध्यक्ष को प्रपत्ति से सामन क्षपने वीदिक साध्यक्ष को प्रपत्ति से सान को से समान कान नहीं है।

१. एम० पी० शर्मा-'पूर्वोक्त पुस्तक' पृ० २२१ ।

सक्षेप में, भारत के सविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सीभित न्यायिक पूनरवलोकन के प्रविकार के कारण निम्नलिखित हैं

१—सिवधान का विस्तारपूर्वक लिका होना, विशेषकर संघ तथा राज्य के मध्य शक्ति विभाजन का तीन सूचियो द्वारा ध्रत्यन्त विस्तृत रूप से उल्लिखित होता।

२—सिक्यान के संबोधन प्रणासी के अनुसार सबद तथा राज्यविधान समार्थें में सदियान के रक्षण को अनिकृष कर से निधारित करने की शासि होना ! यहां ध्यान में रलना उचित है कि अवस्थित के विद्यार प्रारतीय समोप्त प्रमाती सराही सामग्री मारतीय समोप्त प्रमाती सराही सामग्री सामग

२—मारतीय सर्वोच्च ग्यायालय वेचल विधि सध्यन प्रविधा के अनुसार ही गंग सकता है। नह प्रकृतिक विधि को क्योदी को उपयोग में साने के तिए स्वतंत्र नहीं है, जबके ध्वसदें के बावेंच्च स्थायालय प्राकृतिक विधि या वैधिक प्रविद्या के प्रकृतार व्ययंत्र निर्णय वे सकता है। वृद्धि भारतीय सर्वोच्च व्यायालय को सविधान के सरक्षक के नाते एक महत्वपूर्ण भूतिका प्राच्य है, यहीं पर इस बात पर प्रकृता सामना स्वया बत देना स्थायाचिक है कि सरकार के प्रयास की है प्रपत्त को स्वतंत्र रखते हुए ही सर्वोच्च व्यायालय अपने वाधिकों का विध्ता च्य से निमा सकता है। एक जनतानिक सविधान की यह मूल प्रावस्थवता है कि यापपालिश स्वतंत्र सुर्वं के सर्वं कर स्वकं । मारत से सर्वोच्च न्यायालय की विधीवकर से महत्त्र सुर्वं के सर्वं कर स्वकं । स्वतंत्र ने का प्रविकार ने

सर्वप्रयम्, बारतीय सथीय व्यवस्था के धन्तर्गत सर्वोच्च स्थाशसय को सविधान हारा स्थापित विभिन्न सरकारा के श्रीवाधिकारों की रक्षा करना है। इस स्वर्म में, साथ सरकार एवं किसी राज्य सरकार या सरकारों में अक्षमेंट होने पर सर्वोच्च न्यायासय को इन रोनो पत्तों के सिए निष्यक्षता पूर्वक निर्णय रेना होगा।

द्वितीए, सर्वोच्च न्यापासन को नामरिकों के मूल प्रिकारों के सबय में भी निवाद की स्थिति में, निर्माण देने का स्विकार है। वास्तव में मूल प्रिवार के निवाद स्वितान में यह प्रावधान बहुत्तत के निव्युक्त व्यवद्वार पर एक निवाद सर्वोच के रूप में है। प्रवृत्व एक बनवाजिक दाज्य में को बहुत्तत पर प्रायास्ति है, सर्विवार में तुझ स्विकार, अस्मास्तकों में लिए बहुमत की निव्युक्ता के निवाद एक ठोस प्रावस्ता है। पूर्व में यह देता जा चुना है नि जहाँ तन न्यायाधीशों भी नियुक्ति, सेवा भी सतों तथा पदच्युति ना प्रका है, मारतीय सविवान द्वारा, उपयुक्त मामलो भी दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय नी स्वतत्रता बनाये रतने के लिए पर्याप्त प्रावधान निये गये हैं। न्यायपूर्ति सत्रू का कहता था—"यह देवना चिंठन है कि सर्विधान निर्माता निस्त तरह से, न्यायाधीशों नी स्वतत्रता ने विषय में बुछ श्रौर प्रयिम कर सकते से 1"भ

श्रतः यह स्पष्ट है कि 'सर्वोच्च न्यायासय' द्वारा, धपने न्यायिय पुनरवलोगन के प्रधिनार का उपयोग, जिससे व्यवस्थापिना एव कार्यपासिका के प्रयीप नार्यों पर प्रमादकासी रोच लगाई जा सने, सर्वोच्च न्यायासय की स्वतनता पर निर्मर होना पारत के सार्वेजनिव जीवन में सर्वोच्च न्यायासय की स्वतनता ना महत्व तीन प्रीर निम्निविधित कारणों से प्रस्विष्य हो जाता है।

- (१) एक सुविकसित, समठित तथा प्रमायशाली जनमत का न होना ।
- (२) ससद में कार्यपालिका का, जो एक राजनीतिक दल द्वारा निर्मित की गई है, मित किसानी होना । ग्रीर,
  - (३) ससद मे एक सगठित तथा प्रमावशाली प्रतिपक्षी दल का न होना।

परन्तु सविधान ने लागू होने के पश्चात् न्यायपालिकाम्रो ना स्वतन्नता पर सबसे गर्मीर मितन्न मण, क्षमर्थक्षस्य से स्मीर मितन्न मण, क्षमर्थक्षस्य से स्मायांचीयों के नार्यवाल और सेवा निवृत्त होने के पश्चात् प्रवाद निवंद सहस्वानाखाएँ है। सविधान से नोई प्राव्यान नहीं है, जितकी न्यायपीयों को विद्यों एते पद के सिए उन्नीद परने से रोन क्षा सचता है जो नार्यपालिना नी निवृत्ति के प्राव्यात नार्यपालिना होंगे ने क्षप्रचात् नार्यपालिना होंगे के प्रवचात् नार्यपालिना हारा सहत्वपूर्ण पदो पर निवृत्त नियायया। उदाहरण स्वस्य सेवा-निवृत्त होंने के प्रचात् मार्यपालिना हारा सहत्वपूर्ण पदो पर निवृत्त नियाया। उदाहरण स्वस्य सेवा-निवृत्त होंने के प्रचात् भी सीठ सीठ विद्यास को पहले अस्पसर्थनों ने मामलो का मन्नी भीर बाद से विधि मन्नी निवृत्त किया गया। यी सैवट फलनवाती नो उद्दीसा वा राज्यपात हर्श्वर में निवृत्त निया गया। यी बीठ एन० राव से १९४६ में समुक्त-राष्ट्र सप में भारत का मुद्ध प्रतिनिधि निवृत्त किया गया; यो एग सीठ

१. पी० एन० सप्रू-जनरल झाफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, प्रवद्० १६४८, पृ० ६७ ।

२. के॰ यी॰ राव—'पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया', १९६१ पृ०-२१४।

भारतीय शासन धीर राजनीति २६६

छापला नो १६५८ म धनरीना म भारत का राजदूत और तत्पश्चात् शिक्षा मत्री नियुक्त किया गया। कार्यपालिका के इस अपत्यक्ष श्रतिक्रमण से न्यायापालिका की स्वतत्रता की रक्षा ररने के लिए, सविधान मे विशिष्ट रूप से यह प्रावधान जोडा जाना

चाहिये कि सेवारत तथा सेवा-निवृत न्यायाधीश, न्यायिक कार्यों के झलावा किसी

श्रीर प्रकार के कार्यों को सपन हाथों में नहीं ले सकेंगे।

#### राज्य-सरकार

मारत एक सम राज्य है। मारतीय सविधान के झन्तर्गत दो प्रकार की सरकारों के लिए प्रावधान किया गया है. १— क्षम (केन्द्रीय) सरकार तथा २— राज्यों की सरकारे। सविधान को २६ जनवरी १९४० को लामू किया गया, उस समय से १९५६ में राज्य पुनर्गठन सिविधियम पारित होने तक, मारत में सम की इकाइयी (राज्यों) को पार शेषियों में रखा गया था —

(क)—इस श्रेणी मे उन राज्यों को रखा गया था, जिनकी जिटिश राज्य ने दौरान ब्रिटिश-मारतीय-प्रान्तों के नाम से पुकाय जाता था। प्रत्येक ब्रिटिश-मारतीय प्रान्त का सासन एक गवर्नर के अधीन होता था। इन राज्यों के नाम इस प्रकार थे — उत्तरप्रदेश, महास्त, बन्वई, बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, पजाब, तथा असम। इन राज्यों को 'क' भाग के राज्यों के नाम से पुकार जाता या। इस्ट से माया के आभार पर एक नये राज्य का निर्माण हुआ, जिसका आन्द्र प्रदेश नाम प्रया साथा के अन्तर्गत हुआ,

(क्ष)—द्वितीय, श्रेणी में वे राज्य रक्षे बये बे, जिनका निर्माण देशी रियासती के प्राथार पर हुमा था। इन राज्यों के नाम इस प्रकार थे —हैदराबाद, मैसूर, राजस्यान, सीराष्ट्र, मध्य भारत, पेप्सू, ट्रावनकोर-कोचीन और जम्मू-काशमीर। प्रावस्यान, सीराष्ट्र, मध्य भारत, पेप्सू, ट्रावनकोर-कोचीन प्राप्त अन्यस्था भारत प्राप्त के साम प्राप्त का माग 'ख' के राज्यों का नाम दिया वया था। इन राज्यों के नाम दिया वया था। इन राज्यों के नाम दिया वया था।

धम्यक्ष राजप्रमुख कहलाते थे।

(ग)—कतियय छोटे राज्यो को, या जिनको पूर्व में चीक कमिशनर द्वारा प्रधा-चित किया जाता था, भाग 'ग' के राज्यो की सजा दी गई। इन राज्यो के नाम इस प्रकार में —-दिल्ली, अजमेर, कुर्गे, कच्छ, भोषाल, हिमाचल-प्रदेश, मणीपुर त्रिपुरा, कच-विहार, और विष्य-प्रदेश।

(ए)—इस स्रेणों मं धण्डमान तथा निकोबार द्वीपों को रखा गया। नेवल एक साधारण मिन्नता को छोड़कर, मान 'क' एव' 'ख' के राज्यों की सरकारों का सगठन एक समान था। मान 'क' के राज्यों के ध्रम्यक्षों को राज्यां (गवर्नर) की सजा रो गई थी, जब कि मान 'ख' के राज्यों का ध्रम्यक्ष राजप्रमुख कहलाता दी रोगे इस प्रकार के राज्यों में सस्तीय सरकार की स्थापना की गई थी। प्रतः दोनो प्रकार के प्रध्यक्ष नाम मात्र के प्रधान थे, वास्त्रविक नार्यपालिना मधीमण्डल के रूप में ही थी जिसना प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व राज्य विद्यान समा के प्रति होता था।

१८५६ में राज्य-पुनर्गठन झायोग के युकाष पर, मारक सब के राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गगठन प्रीवित्तम १६५६ द्वारा एक नये जाबार पर किया गया। राज्यों के 'क' 'ख' 'या 'यू 'क' शिलायों से बर्बीकरण को समारत कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम १८५६ के सुकाब के मनुवार राज्यों को सब केवल दो श्रेणियों से राजा। ये जिस्म श्रेणियों हैं

१-सम 🖩 राज्य तथा २-सभीय भू-माग ।

१—सभ के राज्यों के नाम इस प्रकार थे—सान्ध्रप्रदेश, ध्रसम, निहार, सम्बद्ध, केरल, मध्यप्रदेश, महाल, मैसूर, उबीखा, पजाय, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिमीवगाल, तथा जम्मु और कस्त्रीर ।

२-सपीय भू भागों के नाम इस प्रकार थे-दिल्ली, हिमाचल प्रवेश मणीपुर, निपुरा, मण्डमान सक्कादीन एव मिनिकाय द्वीप ।

१६५६ में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी, कतियय नये राज्यों की स्थापना की गई जो इस प्रकार है

का गर था इस प्रकार ह १---१९६० मे बम्बई राज्य को विमाजित करके, गुजरात एव महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई।

२--१६६२ में नागालैण्ड राज्य की स्थापना की गई।

३—१६६६ में पजाब राज्य को विमाजित करके पत्राब तथा हरियाणा राज्यो की स्थापना की गईं।

४—१९७१ में असम राज्य के कतिषय पहाडी क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। ५---१६७१ में मणिपुर तथा त्रिपुरा को सम्र वे राज्यों के रूप म मान्यता की गर्दे।

पाण्या इसी प्रकार १९५६ के बाद सधीय क्षेत्रों की सस्याम मी वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है।

१---१९६२ मे बोबा, डमन् तथा ड्यू को सघीय क्षेत्र बनाया गया ।

२-१६६३ मे पाण्डुचेरी को सघीय होत्र के रूप मे सम्मिलित किया गया। ३-१६६६ म चण्डीगढ को सघीय क्षेत्र बनाया गया। परन्तु १६७० म चण्डी-

३--१६६६ म चण्डोगढ को संघाय क्षत्र बनाया गया। परन्तु १६७० म चण्ड गढ को पजाब में मिला दिया गया।

४ -- १९७१ म घरणाचल (नेफा) तया मिजोराम को समीय क्षेत्र बनाया गया है।

### राज्य कार्यपालिका

सपीय कार्यपालिका के समान, राज्यों को कार्यपालिका का भी स्वरूप सप्तदा-रमक है। राज्य-कार्यपालिका वे दो भाग है। (क) राज्यपाल-जो नि राज्य नार्यपालिका का नाममान प्रधान है। (स) मत्रीमण्डल-जिसको वास्तविक कार्य-पालिका ने समान माना जा सकता है क्योंनि राज्य-सरकार की नीतियो तथा कार्यों के लिए, सनियान के मनुमार मनीमण्डल राज्य विधान समा ने प्रति उत्तर दार्थों है।

#### राज्यपाल

सब के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रािकार सिवधान के अनुक्खेद १५५ के प्रत्यतेंग उत्स्वितित है। राज्य-पाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, किन्तु प्रीप्तवारिक दृष्टि से राज्यपाल पाल का कार्यकाल पांच के प्रतास्त्र देखार प्राप्त का प्रतास कार्यकाल को राज्यपाल को राज्यपाल को राज्यपाल को राज्यपाल को राज्यपाल को राज्य की किन्ति के प्रतास्त्र कार्या राज्यों रोगों ने अध्यक्षाराज्य अध्यालों के लाधू होने के फलस्वरूप प्रमरीकी सब में राज्यों के राज्यपाल नाममान के नहीं, परस्तु वास्तविक धासक होते हैं, प्रौर इस कारण उनका निर्वाचन राज्य की जनता करती है।

मारत सप के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति बरता है, इसते, धालोक्तों का बहुता है कि मारतीय राजनीति म कई बुराइयों पैदा हो गई हैं। उदाहरण स्वरूप धालोक्वों का बहुता है कि राज्यपाल वों नियुक्ति करने का राष्ट्रपति का धालोक्वों का बेल्द्र में सतास्त्र के सा धाक्तार है, जिससे केन्द्रीय सरकार राज्यों से राजनीतिक परिस्थितियों नो, कुछ सीमा तक धपनी इच्छानुसार मोड सकता है। इस सन्दर्भ में, विशेषकर १९१७ ने दूसरे धाम-चुनाव के बाद, केरल राज्य में १९१६ में धामतुकातीय स्थिति की घोषणा करने राज्य-सामत को केन्द्र सरकार द्वारा धपने हाथों में लेने का बढाहरण अस्तुत किया बात है, क्योंकि उस समय केरल विशोज सबा में धाम्यवादी सरकार को, स्पाट बहुमत होने हुए भी, राज्यपाल रामइष्म याव की संवारिक पर कि राज्य में सर्वधानिक तत्र समाण हो गई थी, वर्षास्त्र कर दिया गया।

कभी-कभी सतास्त्र दल के सेवा-निवृत या निर्वावनों ये हारे हुए सदस्यों भी राज्यपात निवृत्त कर दिया जाता है। यह समन्व है कि जो ज्यांतर प्रयोज जीवन से शोक्षणत कर निवा राज्योजित रूस हा सदस्य यहा, है, यह राज्यपात निवृत्तत होने पर निरुक्त नहीं रहे हैं, विशेषणर ऐसी परिस्थित में बद कि राज्य में सर-कार की वाग्योर ऐसे दल के हावों में हो, विशाव हर व्यक्ति राज्यपात निवृत्तत होने के दूर्त करत्य नहीं रहा है। वेण्ट से सवस्य हर व्यक्ति राज्यपात निवृत्त होने के दूर्त करत्य नहीं रहा है। वेण्ट से सवस्य तर सवस्य कि निवृत्ति राज्यपात के पद पर हुई है, जनमें के कुछ के बाम इस प्रवार है—ती मत्रित्तवाद जैत, की बील और निर्दित की हारिज मोहम्मद इसाहींग, की सत्य-नारायण सिवृत्ता हुं साहमा हुं साहित्य । क्षी-कारी के साहम्मद व्यक्तिया । क्षी-कारी के साहम्मद व्यक्तिया ।

कमान्तमा सर्वा । जबूत सान सर्वा आध्यकार्य राज्यपाल के पद पर । जनुक चिये जाते हैं। कार्यरतः प्रशासन के प्राधिकारियों के लिए यह एक लोग के सदृश है, जिससे प्रशासन पर चुरा प्रजान पर सन्ता है।

राज्यपाल की नियुक्ति के सान्वन्य में कभी-कभी सवस्ति राज्य संस्कार भी इच्छा की सब्हेलना की गई १६६७ में पन्तिम बतात में श्री वर्गनीर की, तथा विहार में भी नानुकरों की नियुक्ति राज्यपाल के यद पर नी एके जबकि स्वाल तथा विहार के सबुक्त मंत्री मण्डती ने इन नियुक्तियों ना तीव विरोध दिया।

प्रतएव इत बीधों को समाप्त करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के सबध में केन्द्र सरकार के लिए निम्नलिलित परम्पराधों का पालन करना आवश्यक होगा ।

कन्द्र सरकार का लए निम्नालासत परम्पराधा का पातन करना आवश्यक हाना । एक—राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वायत राज्य की सरकार की सलाहानुसार की जाये.

दी—राज्यपाल के पद पर सेवा निवृत या चुनाव में हारे हुए व्यक्तियों भी निमृत्ति न भी जाये,

तीन—सम्पान पद पर, किसी घन्य राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति की निपुक्त किया नाने, क्योंकि, वह स्थानीय राजनीति से क्यर होगा धौर निप्यतता पूर्वक प्रश्ने नाये करेगा। व्यवहार में इस परम्परा का पातन किया गया है, तिवाय बार एवंट मीठ कुर्वा नो निवृत्ति के, यो प्रपने राज्य, परिचम बंगात, के ही राज्यात निवृद्ध निवे यूपे थे।

## राज्यपाल के पद की योग्यताएँ

मारत के सविधान के अनुसार राज्यपाल के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्मारित की गई हैं .—

१-मारत का नागरिक हो,

२--- ३५ वर्षों से कम भायु का न हो,

३—राज्यपाल को ससद या विसी राज्य की विधान समावा सदस्य नहीं होना चाहिये।

४—वह सम सरकार या किसी राज्य सरकार के म्रघीन लाम ने म्राय पद को पहण न करता हो। दो या दो से मधिक राज्यों के लिए एन ही राज्यपाल निमुक्त निया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के बेतन तथा भतो ने मार को राष्ट्रपति द्वारा निर्वारित नियमों के मनुसार उन राज्यों को उठाना होगा।

राज्यपाल के बेतन व मरी .—राज्यपाल का येतन सविधान के अनुसार १,४०० क० मासिक होना, जब तक कि ससद द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसके अतिरिक्त राज्यपाल को वे भन्ने प्राप्त होंगे जो भारत में गवने से को सविधान लागू होने के पूर्व दिये जाते थे। ससद कानून द्वारा राज्यपाल के वेतन, मती एव विशेष सुविधाओं को निर्धारित कर सकती है। राज्यपाल के कार्यकाल में उसके बेतन तथा भन्नों मे कमी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल को निर्धारक से उसके सेन तथा भन्नों में कमी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल को निर्धुत्क प्रावास की सुविधा उपलब्ध होंगी।

राज्यपाल के पद प्रहण करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाचीश या उसकी प्रमुपस्थिति मे सबसे विरिट्ध न्यायाधीश के सम्मुख यह प्रतिज्ञा लेला प्रावश्यक है कि वह प्रपने पद तथा कर्तव्यो का पालन, सविषान तथा कानून की रक्षा और जनता और जनता की सेवा करेगा।

राज्यपाल को शांकतयों एवं कार्य—यह जात है कि सम तया राज्यों में ससदीय पढ़ित जी सिवान के अन्तर्गत स्थापना की गई है। अत भारत के राज्यपालों की सर्वधानिक रिव्यतियों में, कतियय अपवादों की होडेकर, समानता गाई जाती है। सर्वधाय पढ़ित के सन्दर्ग में दोनों नाममान के शांसन हैं। यदिष्यान के अनुच्छेद १६३ (१) के अनुआर राज्यों के लिए एक मंत्री परिपद का प्राथमान किया गया है, जिसका कार्य, सिवाय उन मामलों के जिसके सवध में सविधान द्वारा राज्यपाल को स्विविक के उपयोग करने ना अधिकार दिया गया है, राज्यपाल को स्विविक के उपयोग करने ना अधिकार दिया गया है, राज्यपाल को स्वविक को उपयोग करने ना अधिकार दिया गया है, राज्यपाल को बतके कार्यों में सहायता एवं परामर्थ देना होगा। सिवियान में इन विषयों के, सिवाय कि सहम के सीमवादीं सेत्री ने प्रशासन के लिए राज्यपित के अधिकारीं सेत्री ने प्रशासन के लिए राज्यपित के अधिकारीं सेत्री ने प्रशासन के लिए राज्यपित के अधिकारीं स्थान के सुमुक्ति

क्षेत्र की जिला परिषद के मध्य धानिज से प्राप्त बाय सवधी विवाद में निषटारे के लिए, राज्यपाल की 'स्वविवेक' सबधी शक्तियों को परिमापित नहीं किया गया है। विसी विषय के सबय में राज्यपाल अपना स्वदिवेक उपयोग में सा सकता है या नही, यह निर्णय सेने का प्रथिकार स्वय राज्यपाल को ही है। धनुष्द्रेद १६३ (४) वे धनुसार जो कार्य राज्यपाल ने अपने स्विविकानुसार किया है, उसकी वैपता ने सन्दर्म में कोई प्रथन नहीं उठाया जा सकता है । परन्तु व्यवहार में ग्रमी तर इस परम्परा को ही भाग्यता दी गई है कि असम के राज्यपाल के सिवाय भीर उसको मी देवल बसम के सीमावर्ती क्षेत्र तथा खनिज पदार्थी सबभी गुल्क विवयो, पर ही, मन्य राज्यों के राज्यपासों को साधारणतया स्वविवेत के मनुसार कार्यं करने का मधिकार नहीं है। "एक सीमा तक, अनुच्छेद १६३ में इन शब्दो को (स्वविवेकानुसार) रखना प्रारम निर्माण-सवधी एक ध्रव्यवस्था है।" क्योकि केन्द्र ने सदश राज्यों म भी ससदात्मक सरकार की सविधान द्वारा स्थापना मी गई है, और इस सन्दर्भ में राज्यपाल की स्विति राज्यों की सबैधानिक व्यवस्था मे नामभात की होनी चाहिये । तबापि, वह स्मरण रखना बावश्यक है कि सरियान निर्माण के दौरान विवाद में इस विषय पर बस दिया गया कि राज्यों में संसदात्मक पढ़ित के होने के बावजूद भी राज्यपाल वह कड़ी है जिसके माध्यम से राज्य की केन्द्र से सर्वायत राजा सकता है और जिसके प्रतस्वरूप सम्पूर्ण भारत म सर्वधानिक एक्टा समव हो सकती है। यह स्पष्ट है कि वेन्द्रीय सरकार तथा पाग्य सरकारों के सबैधानिक सबधो की मुख्य कडी राज्यपाल ही है। जैसा विदित है, भारतीय इतिहास से सबक लेकर, सविधान सभा में बार बार इस विषय पर स्थान प्राकृषित किया गया था वि केन्द्रीय सरवार अथ-जब शिथिल हुई, देश की एकता की मामात पहुँचा, ब्रतएव देश में एकता सथा स्थायित्व के लिए राज्यपाल को सम तया राज्य के मध्य एक महस्वपूर्ण सर्वेद्यानिक वडी की भूमिका सर्विधान द्वारा प्रदत्त की गई। इस विषय पर अपने विश्वार प्रकट करते हुए प० नेहरू ने सविधान समा में कहा—"एक निर्वाचित राज्यपाल बुख सीमा तक, पृथककारी आन्तीय प्रवृतियो को प्रोत्साहित कर सकता है और केन्द्र से सबध कम हो जायेंगे।" अतएव सबैधानिक एकता तथा स्थायित्व बनाये रखने के लिए राज्य-पान के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व के लिए सविधान में दो मूख्य-माघार स्थापित किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं १-अनुच्छेद १५५ के अन्तर्यंत राज्यपाल भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तथा २—राज्यपाल कार्यकाल अनुच्छेद १५६ (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद-पथन्तै रहेगा। अनुच्छेद २५६ के अनुसार, यदि विसी राज्य

१. बी॰ बी॰ बसु—'कमेन्ट्री धन द कान्स्टीट्युवान झाफ इण्डिया 'पृ०४७५ । २. कान्स्टिटीएष्ट झसेम्बली डिबेटस, मा—इ. गु०४५५ ।

में सबैधानिक यत्र (सरकार) को सविधान के अनुसार चलाया जाना समय गरी है, तो राज्यपाल यह सुबना राष्ट्रपति को मेंबेगा। राष्ट्रपति उक्त राज्य में राज्य पाल के प्रतिवेदन पर सनटकालीन स्थिति की घोषणा करेगा। इसी प्रकार अनुष्ठेद १६५ के अनुसार संघीय सरकार को यह प्रिकार है है न राज्य सरकारों को उननी कार्यपालन संदों होता है तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, सनटकालीन स्थिति की घोषणा कर सबता है। यह समय है कि यदि राज्य में किसी ऐसे राज्यभित के सरकार है, जो केन्द्रीय सत्ताव्ह दल से नित्र है सो वह राज्य सरकार है, जो केन्द्रीय सत्ताव्ह दल से नित्र है सो वह राज्य सरकार करार है, जो केन्द्रीय सत्ताव्ह दल से नित्र है सो वह राज्य सरकार करार है, जो केन्द्रीय सत्ताव्ह दल से नित्र है सो वह राज्य सरकार करार है, जो केन्द्रीय सत्ताव्ह दल से नित्र है सो वह राज्य सरकार करार है हो इसिक सहस्र प्रवाद स्थाप के प्रतिवेदन से प्रतिवेदन से प्रविद्या सरकार के निव्यंत्रों का पालन करने के लिए स्वविवेद की गिक्त का उपयोग कर सकता है।

राष्ट्रपति हे सद्द्व, राष्ट्रपति के केवल राजनियक सैनिक तथा प्रापत्कालीन प्रिमिश्तरो, को छोडकर, राज्यपाल की शक्तियों को पाँच श्रेणियों में रखा जा सहता है।

१—कार्यवालिका सवधी, २—व्यवस्थापन सवधी, ३—वित्तीय सवधी, ४—ग्याय सवधी १—श्रन्य बक्तियाँ। इन समस्त शक्तियों को राज्यपाल मशीमण्डल के, जिसको विधान सभा में बहुमत है, परामर्शानुसार ही प्रयुक्त करेगा।

१-कार्यपालिका सबधी शांवितवां—राज्यपाल राज्य-कार्यपालिका का प्रमुख है। राज्य की समस्त कार्यपालिका क्षत्रयो ब्रातियो ना उपयोग राज्यपाल में नाम के ही होना है। यदाचि राज्य की सारी कार्यपालिका सर्वाचित शांतियों राज्यपाल के ही होना है। यदाचि राज्य की सारी कार्यपालिका सर्वाचित शांतियों राज्यपाल में निहित है, बास्तव में, इन वाकियों ना उपयोग राज्यपाल में निहित है, बास्तव में, इन वाकियों ना उपयोग करने ना प्राविकार है। स्वीत्य स्वत के प्रमुख्य मुख्यमंत्री से सार्यपाल को मंत्रीमण्डल के निर्णयों सर्वाची समस्त जानकारी प्राप्त करने ना प्रविकार है। स्वीत स्वत्य में सर्वाच्याल के सोर मुख्यमंत्र करारे वचा प्रवासन सर्वाची विषयों पर वह सारी जानकारी राज्यपाल को प्रयत्त करारे वचा प्रवासन सर्वाची विषयों पर वह सारी जानकारी राज्यपाल को प्रयत्त करारे वचा प्रवासन के स्वीत के निर्णय को प्रत्रीमण्डल के समस्त राज्यपाल हारा सुर्वाचारों को किसी मंत्री के निर्णय को प्रत्रीमण्डल के समस्त प्रविचार विषयों के लिए एवले को कहा जा तनवा है। राज्यपाल के सार्य पाणिका सवयों बातियों का दायरा उतना ही है, जितना राज्य-सूची में उत्ति विषयों पर विषय पर विधि निर्माण नरते का दायरा राज्य विषयान समा नो है। प्रयत्ति राज्यपाल की नार्यपालिका सवयों ब्रातियों राज्य-सूची में उत्ति विषयों पर विधि निर्माण नरते का दायरा राज्य विषयान समा नो है। प्रयत्ति राज्यपाल की नार्यपालिका सवयों ब्रातियों राज्य-सूची में उत्तिवाल विवालिक सिंत्यों का स्वाच राज्य-सूची में उत्तिवालिक सिंत्यों का स्वाचित राज्य-सूची में उत्तिवालिक सिंतियों राज्य-सूची में उत्तिवालिक सिंतियों राज्य-सूची में उत्तिवालिक सिंतियों राज्य-सूची में विललिक विवालिक सिंतियों राज्य-सूची में विललिक सिंतियों सिंतियों राज्य-सूची में विललिक सिंतियों राज्य-सूची में विललिक सिंतियों राज्य-सूची में विललिक सिंतियों राज्य-सूची में विललिक सिंतियों का स्वाची सिंतियों सिंतियां सिंतियों सिंतियों सिंतियां सिंतियों सिंतियों सिंतियों सिंतियों सिंतियां सिंतियां सिंतियां सिंतियां सिंति

राज्यपाल को कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्तियो करने का श्रीवकार है, जो निम्न-लिखित हैं —

- (१) राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमत्री के पर पर नियुक्त करता है।
- (२) मुख्यमत्रो के परामशं पर अन्य मित्रयो की नियुक्ति करता है।
   (३) अनुच्देद १६५ के अनुसार राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति
- करता है। (४) प्रमुच्छेद ३१६ के बन्तर्गत राज्यपाल लोकसेवा बायोग के सम्यक्ष एव
- सदस्यों की नियुक्ति करता है।
  (५) उच्च न्यायालय के न्यायायीयों की नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से

(र) उपने प्राथमित के स्वायावाया का निवृद्ध करने के साथ र निविधास से प्राथमित से प्राथमित से प्रायम के राज्य मे सकटकासीन स्थित की बोधणा करने के सन्दर्भ में मनक्टर ३५६ के मन्तर्वत, मुख्य भूषिका अदान की गई है। जब राज्यपान को

स्तुच्यद ११६ क सत्तत्वत् , मुख्य भूषका स्वयन कंप स्ट्रा वर्ष राज्यसात के सिवास हो जाता है कि राज्य संक्रार का स्वयन्त्र सिवास के प्राथमाने के स्वयुक्तार समय नहीं है, तो यह राज्यति को इस विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुव करता है, और पदि राज्यत्रीत हम सामार पर राज्य से सन्दकारीन स्थिति सीपित करता है तो राज्यत्राल को केशीय करकार के समिवता के कप मे राज्य-सामन चलाने के लिए कहा जा सन्ता है।

प्रचुच्चेद १७१ (१) द्वारा, राज्यति की सादेव द्वारा पतान सवा साम्यन

नुष्युद्ध (४) (१) होता, उन्हेशन के भवित आप जात तहा प्राप्तान प्रतिकृति होता, उन्हेशन के भवित काण जाति जाति व्यावित करने का मितकार है तथा यह एक क्षेत्रीय समितियों के उन्हित रूप के सार्थ करने के वित्य राज्यात के वित्रेष्ठ व्यावदात्र का मान्यान कर सकता है। धानमान्येक तथा पजान में इन धेनीय समितियों हारा उनके की नामिकार में उन्हित्य वित्याप पर विचा गया परामर्थ, सरकार तथा राज्य विधान सकता को साधारणत्या स्वीहत करना होगा, किन्तु सार्थ श्रीय समितियों तथा वास्त्र हो तथा है हो राज्य है हो स्वावित हो सार्थ स्वीहत करना होगा, किन्तु सार्थ श्रीय समितियों तथा वास्त्र हो, इस सन्दर्भ में मतनेद हो जाता है हो राज्यात को संवित्र निर्मय देने का सम्बत्य है।

२-व्यवस्थापन सवधी शक्तियाँ-राज्यपाल को व्यवस्थापन सवधी कतिपथ महत्वपूर्ण शक्तियाँ सनिधान द्वारा प्रदत्त हैं।

१— राज्यपात को राज्य विधान-मण्डल के धविवेशन धाधानित करने का प्रांतिकर है, किन्तु को अधिवार को इस अवार उपयोग में साना होगा कि अन्तिम प्रांतिकर के अन्तिम दिन को गया प्रांतिकर के अन्तिम दिन के प्राया प्रांतिकर के अन्तिम दिन के प्राया प्रांतिकर के प्रावार कि प्रांतिकर के प्रांत

है। साधारणतमा, जब विवान समा में मत्रीमण्डल नो बहुमत प्राप्त है, इन मिलियों का उपयोग राज्यपाल मत्रीमण्डल की सम्मति के अनुसार ही करेगा। किंग्य का मंग्रीमण्डल को विवान समा में बहुमत ना समर्थन नहीं रहा है तब राज्यपाल इन मिलियों के उपयोग के लिए अपना स्विवेन ना उपयोग कर सनता है। इसने उदाहरण १६६७ में हुए चीचे धाम-चुनार ने परवात कई राज्यों में देखने नो मिले। जब इन राज्या के मुख्य मत्रियों ने, जिननो विधान समा में बहुमत का सम्पर्य नहीं रहा उब राज्यपाल को नियान समाभी को मग करते नी सलाह दी, किन्तु परिस्थितियों नो देखते हुए राज्यपाल ने स्विवेन से ही नियंग जिया।

२---राज्यपाल को विधान मण्डल को सबोधित करने का प्रधिकार है। ग्राम-चुनाव के परकात् विधान मण्डल को पहली बैठक तथा प्रतिवर्ष प्रथम बैठक को राज्यपाल संगोधित करता है।

३—राज्यपाल विधान मण्डल के किसी सदन के समक्ष विकारार्थ विषेपक के सप्य में उक्त सदन को सदेश मेज सकता है और उस सदन का यह क्लैंब्य होगा कि सदेश में उल्लिखित नियय पर शीघ्र विचार करें।

४—जब एन विमेयन राज्य विधान-मण्डल के एक या दोनो सदनो (जिस राज्य में एन सदन है तो एम सदन इता, तथा जिस राज्य में वो सदन है, तो दोनो सदनो हारा) पारित हो गया हो, तो उसे राज्यपाल के समझ उसकी सहमित के लिए प्रस्तुन रिया जायेगा। राज्यपाल विदेयन को, यातो भपनी सहमित दे सकता है या उस पर प्रपनी सहमित रोन सकता है, या तिष्यप को राज्यपाल प्रमान पर्पा प्राचित के विचान पर्पा प्राचित के सिवान पर्पा प्राचित के सिवान समझ से प्राचित के सिवान समझ से प्राचित राज्यपाल से स्वा प्रसान से प्राचित राज्यपाल में प्राचित राज्यपाल में प्राचित राज्यपाल में प्रपनी सहस्ति हैना हो होगा।

४--राज्यपाल जिन विधेवको को राष्ट्रपति को सहमित के लिए सुरक्षित रखना है वे निम्नलिखित विषयों से सबचित होंगे।

क-जो निजी सम्पति के भनिवायं श्रिवयहण के लिए है, या
 ख-जो उच्च न्यायालय की भनिवयों में कभी करने के लिए हैं।

६—राज्यपाल विधान परिषद के लवाम है सदस्यों को ऐसे लोगों में से मनोगीत करता है जिन्होंने साहित्य, क्ला, विज्ञान, समाजसेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में विज्ञिष्टता प्राप्त की है।

७---राज्यपाल, राज्य विधान समा के लिए ब्राज्न-बारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों नो मनोनीत कर सकता है, यदि उसके विचार में इस सम्प्रदाय का विचान समा म पर्यान्त प्रतिनिधित्व नहीं है ।

--- राज्यपाल, विधान मण्डल के निसी सदस्य भी ब्रयोग्यता की स्थित में, निविचन ग्रायोग के परामर्शानुसार निर्णय दे सकता है।

 राज्यपाल को, अनुच्छेद २१३ के अन्तर्गत जब राज्य विधान मण्डल का ग्रधिवेशन नहीं हो रहा हो, प्रध्यादेश जारी करने का ग्रधिकार है, जो कि विधान मण्डल की नई बैठक के प्रारम्भ होने से ६ सप्ताह तक वैध होगे, यदि इसके पूर्व इनको विधान समा द्वारा समाध्य नहीं कर दिया जाता है। प्रत्येक मध्यादेश की शक्ति कानून के सद्ग होगी , परस्तु यदि बुद्ध ऐसे विषयो से सविधित सध्यादेश लागू करना है, जिन पर विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मावस्पक है तो, विना राष्ट्रपति के निर्देश के इन विषयो पर मध्यादेश लागू नही किये जा सकेंगे।

३-विसीय शक्तियाँ-राज्यपाल की विसीय शक्तियाँ निम्नलिखित हैं -

(१) राज्य विधान समा में किसी विश्त-विधेयक की विना राज्यपाल की अनुशसा के राज्य विधान सभा मे अस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधेयको के वित्तीय मामली से सवधित संशोधन के लिए राज्यपाल की सहमति प्रावश्यक है। परन्त राज्यपाल की सहमति विसी कर को कम या समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत संशोधन के लिए भावस्थक नहीं है।

(२) राज्यपाल का यह उत्तरदायित्य है कि राज्य के वित्तीय वर्ष के लिए. विधान समा के समक्ष राज्य का वाधिक झाय-व्ययक प्रस्तृत करवाये। बिना राज्य-पाल की धनुमति के अनुदान की गाँग नहीं की जा सकती है,

(३) राज्यपाल विधान मण्डल से पूरक, प्रतिरिक्त या विशेष प्रनुदान की

माँग भी कर सकता है।

(४) धनुच्छेद २६७ के धनसार राज्य-बाकस्मिक निधि को उपयोग में लेने का भविकार राज्यपाल को ही है। राज्यपाल किसी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए आकस्मिक निधि में से अग्रिम निधि दे सकता है।

४-न्याधिक शक्तियाँ-राज्यपाल को न्याय के क्षेत्र में कलिएय शक्तियाँ प्रदन्त की गई हैं, जो राज्य वार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में काननों से सर्वधित हैं। इन काननों ने दिख्ड मपराम करने वाले भपरामी के दण्ड को दह कम कर सकता है, स्यगित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, तथा उसे क्षमा प्रदान कर सकता है।

५--राज्यपाल की ग्रन्थ शक्तियाँ-(१) राज्य लोक सेवा भागोप द्वारा ग्रपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित क्या जाता है जो उसकी राज्य मंत्री परिषद के समझ उसके दिचारायें प्रश्तुत करवाता है। मंत्री परिषद की टिप्पणिया उक्त राज्य-सरकार २७७

विषय पर प्राप्त होने के पक्तात् राज्यपाल दोनो लेखों को विधान समा के प्रध्यक्ष के पात भेजता है, जिससे उनको विधान समा के विचार विभन्न के लिए रखा जा सके।

- (२) इसी प्रकार राज्यपाल राज्य के झाय व्यय पर महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर मी विचार करता है।
- (३) यदि किसी राज्य ने राज्यपाल को निनटवर्ती सधीय क्षेत्र (मू-माग) का प्रशासक नियुक्ति निया गया हो तो ऐसी स्थिति म उनत सधीय क्षेत्र के सबय में राज्यपाल मत्री-मध्हत से स्वतंत्र रह नर घपने नार्यों ना सवासन कर सकता है।
- (४) नागालैच्ड के राज्यपाल को सविधान के १३वे सजीधन के ग्रन्तर्गत दस वर्षों तक पिछडे हुए टु-यान-सान ग्रादिम वासी क्षेत्र के प्रधासन का उत्तरदायित्व सीपा गया है।

ग्रन्त में, राज्यपाल नो स्थिति तथा शक्तियों नी दृष्टि से यह निष्कर्षे निकाता जा सकता है कि मारतीय राजनीतिक प्रणाली में राज्यपाल की एक प्रस्यिक महत्वपूर्ण मूर्मिन है। राज्यपाल ने बेबल राज्य ना प्रश्यक्ष है, कहाँ सवदीय प्रणाली को स्थापित किया गया है, परन्तु नई मासती ये केन्द्रीय सरकार का ग्रामिनतीं भी है, श्रत राज्यपाल को निष्यक्ष एवं निष्ठावात होना प्रस्थावस्यक है।

राज्यों में सस्सदीय प्रणाली होने के कारण राज्यपाल, राज्य का सबैधानिक प्रमान है। यदाप नितयस मामली में राज्यपाल को स्विविव के उपयोग करने की मिल है नियु इस शक्तियों का प्रयोग जनित्त को देखते हुए ही किया जायेगा। प्रणन ता उच्च स्थायालय ने राज्यपाल की स्थिति पर त्रवाश डालते हुए "सुनीक- एकनता उच्च स्थायालय ने राज्यपाल की स्थिति पर त्रवाश डालते हुए "सुनीक- मुमार को स्वाम प्राथ सिव्य में महा — "वर्तमान सिव्यान के प्रस्ता में प्राथ में महा— "वर्तमान सिव्यान के प्रस्ता मिल मिल सिव्यान के प्रस्ता त्रवाश मिल सिव्यान के प्रस्ता त्रवाश की सिव्यान है। स्था सिव्यान के प्रस्ता त्रवाश करने वर्तमान सिव्यान के सम्पर्यंत स्विव्यक से या व्यक्तियत प्राथ र कार्य करने वी उसकी श्रातिक को से सिव्या गया है। धीर इससिव्य हु प्रपियों की सलाह से ही वार्य करेगा।"

१८६७ में चीये धाम-नुनाव के बाद भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, कई राज्यों में कावेब का बहुमत समान हो गया। प्रत इस परि-बर्तित स्पिति में राज्यपान की मूमिका से सुवधित कई महत्वपूर्ण प्रकन सामते आये हैं। इनमें से मुख्य निम्मितित हैं।

१—विपान सभा ने सत्र नो बुलाने ने ग्रायकार ने सर्वय में नवस्वर, १६६७ में पश्चिम बगान में राज्यपान तथा मुख्यमंत्री के सच्च विचार उत्पन्न हुन्ना । राज्यपान विधान समा की बैठक को पहले आमंत्रित करने के पक्ष में थे, जबकि मुस्यमंत्री का मत वा नि बैठक को कुछ समय पत्रवात् ही धामतित निया जाये। इस सस्यों में केटीय विधि मधालय ने धानुखेद १७४ (१) के परवर्षत यह सम्पोकरण दिया कि संवैधानिक तथा सैंद्वानिक रूप से यह शक्ति राज्याल को सी गई है निस्तु धानिस निर्धेष दस विषय पर मुख्य मनी का ही होगा।

म्रप्रैल, १६७०, में इसी विषय पर पनाय में राज्यपाल तथा मुख्यमनी वादल के मध्य मतमेर पैरा हुमा। मुख्यमनी बादल की इच्छा के विरद्ध राज्यपाल नै विधान समा की बैठक प्रामित जी।

२—विधान समा को भग करने के सक्षय में गढा राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पराममांनुसार विधान समा सन करना चाहिये? क्या इस विधय पर वह स्वतवता पूर्वक निर्णय से सकता है।

१---वया राज्यपाल को मुत्रीमण्डल को ऐसी परिस्थिति में भी जवनि मनी मम्बर को वियान समा में बहुत्या प्राप्त है, वर्षोस्त करने ना अविकार है? विमेक्क सह प्रत्न को राज्यपाली डाएं विमेक्क सह प्रत्न को राज्यपाली डाएं अपने मनी मोलको को वर्षोस्त करने के फलस्वक साथने आया है।

११४६ में केरल में थी नम्बूरीपार की लाम्यवादी सरकार को, जिसकी ' विधानकार में स्थार कुमत आपना, बर्वास्त नरेंच, प्रस्तुपति सासत लायू किया गया। परिवाद काला के राज्यपात की पर्मविद में थी प्रवासुन्ति की करी-मण्डल को रिसास, १६५७, में बर्जास्त कर की पी॰ बी॰ भीच को मुख्यमंत्री मिचुक स्थित। श्री पर्मवीद को यह प्रतीत हुआ कि पुश्यमंत्री मुख्यों के मनी-मध्यल की विधान तथा का विस्ताद नहीं था। उन्होंने भी मुख्यों को मनी-मध्यल की विधान तथा का विस्ताद नहीं था। उन्होंने भी मुख्यों को हिएत विधान समा की बेटक की, यह हात करने के लिए सामित्र करने भी कहा कि उनकों स्वादान समा की सामित्र तहीं विधा, श्री धर्मवीद ने सर्वी सण्डल की स्थानस पर सामारित मंत्रीपण्डल सानवर बर्वास्त कर दिया। यह कार्य भी धर्मवीद से स्विधान समा की सामित्र कार्य के श्रीवाद कर स्वादा स्वाद कार्य भी

स-महुन्धेद १६३ (१) के मनुसार राज्य ने लिए एक मनीमण्डल होगा, जितना कार्य राज्यमान नो उसके नार्यों य सहायता तथा परामझे देना होगा, निवाय उन मामको के जिनके लिए उसनो सनियान के मनुसार बणनी स्वेच्छा से नार्ये, करना है।

तपापि श्रीधर्मबीर द्वारा मृत्री मण्डल नौ सर्वास्त विसे जाने के फलस्वरूप विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुई। केन्द्रीय विधि भृतालय ने श्रुल्पस्त भृत्रीमण्डल को बसांस्त करने के राज्यपाल के इस कार्य को सबैधानिक माना । किन्तु धालीचनों का यह कहना या कि मन्नीमण्डल को पदच्युत करने का अधिवार नेवल विधान समा थे तिहित है और विधान समा के इस अधिकार को राज्यपाल नहीं हुइप सकता है। धतएव यह आवश्यक है कि राज्यपाल नी स्थित तथा नार्यों के सवध मे स्वरूप सतरीय परस्पराधों का विकास होना चाहिये। इसने धितरित, यह मी छित होगा कि राज्यपाल के स्वैच्छापिनारों को स्पष्ट रूप से सविधान में परि-

## राज्य-मनी परिपद

मारतीय सविधान के सनुष्टेंद १६३ (१) के अनुसार राज्यों के लिए एक मन्नी परिपद का प्रावधान विधा गया है जो राज्यपास को उसके कार्यों में सहायदा तथा परामर्थी देगी, सिवाय वन मामलों के जिनके सबस में सविधान के धन्तर्गत वह 'स्विविक' से नार्ये कर सक्ता है। सिवधान में 'स्विविक' शब्द को परिमापित नहीं किया गया है, किन्तु केवल ससम के राज्यपास में सम्बन्ध में सिवधान में उत्तिलित है कि यह स्विविकानुसार राज्यपास में प्रावधान के स्वविधान में प्रतिकार के प्रावधान के स्वविधान में प्रतिकार के प्रतिकार का प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार का प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार का प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार का प्रतिकार के प्रतिकार क

केन्द्रीय सरकार के समान राज्य सरकार भी ससदीय प्रणाली के मूल सिद्धान्तो पर माधारित हैं। ससदीय प्रणाली का मूल सिद्धान्त यह है कि मनी-परिपद (बास्तविक कार्यपालिका) प्रयस्त रूप से व्यवस्थापिना के निवसे सदन के प्रति उत्तरदायी है तथा अप्रयस्त रूप से सदताता गण के प्रति उत्तरदायी हैं। सिवान के मनुष्टेद १६४ (१) के अनुसार राज्य के मनी पण्डल का सामृहिक उत्तरदायित राज्य विधान से स्वा पण्डल का सामृहिक उत्तरदायित राज्य विधान से विधान के मनी पण्डल का राज्यपाल को मनी परिपद के परामर्शानुसार कार्य करना होया।

सांपारणतया, ध्राम चुनाव के पश्चात् धनुन्धेद १६४ (१) के प्रन्तर्गत बहुमत दल के नेता नो राज्यपाल मृत्यमत्री के पद पर नियुक्त करता है। तरफ्वात् राज्यपाल भन्य मनियो नी नियुक्ति मृरयमत्री के सलाह के धनुसार, करता है। यह स्पन्ट हैं कि जब धाम चुनाव में किसी दल नो विधान समा में बहुमत प्राप्त हुमा है तो राज्यपाल उसी दल के नेता को मृत्यमती नियुक्त नरेगा धीर उसके प्रमुक्त में स्वित्त के उत्ययोग में साने की कोई धादस्यकता नहीं होगी। किन्तु जब विसी दल नो विधानस्था में स्पन्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्य-पाल विसिन्न दल के नेताधो से धनी मण्डल के सतन के लिए चर्चा करके मुख्य-

मत्री की नियुक्ति ग्रपने थिवेक के ग्रनुसार कर सकता है। ग्रनुच्छेद १६४ (१) के प्रन्तर्यंत मंत्री प्रपने पद पर राज्यपाल के 'प्रसाद पर्यन्त' तक रहेगे। मंदि मत्री के पद पर नियनत किया गया व्यक्ति विधान मण्डल का सदस्य नहीं है तो उसको ६ माह के बन्दर विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना भावत्यक है, मन्यया उसको मशी पद पर से हटना पटेगा। प्रपंता पद ग्रहण करने के पूर्व प्रत्येक मन्त्री की पद के सबध में राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मतियों के बेतन तथा मत्तों का निर्धारण राज्य विधान-मण्डल निर्धारित मरती है। अनुच्छेद १६३ (३) के अनुसार इस प्रश्न पर कि मत्रीमण्डल द्वारा राज्यपाल को नोई सम्मति या किस प्रकार की सम्मति दी गई, किसी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। इस कारण मतियों की सम्मति सर्वधित कीई प्रश्न न्यायालय में नहीं लाया जा सक्ता है।

सविधान द्वारा राज्य सत्री-मण्डल के सदस्यों की सख्या निर्धारित नहीं की गई है। ब्रह्मण्य विभिन्न राज्यों में मतियों की सरवा मिन्न-मिन्न है। यद्यपि सविधान से मित्रयों की विभिन्न श्रेणियों को भी उल्लिखित नहीं किया गया है। फिर भी व्यवहारत: चार श्रेणियो में मित्रयों की वर्गीकृत किया जाता है. जो निम्नानुसार है —

(क) केबीनेट स्नर के मनी,

(ख) राज्य मधी,

(ग) उपमत्री, तथा,

(घ) समदीय सचिव,

इन चारी प्रकार के मनियों से मिलकर मंत्री-परिषद का गठन होता है। केवल केवीनेट स्तर के भन्नी ही मनिमण्डल मे होते हैं। प्रत्येक केवीनेट स्तर के मत्री किसी न किसी मतालय का अध्यक्ष होता है। अन्य श्रेणियों के मत्रियों का कार्य विधायी तथा श्रशासकीय क्षेत्रों में केबीनेट स्तर के मतियों को सहायता देना है।

मत्रीमण्डल के कार्य तथा ग्रविकार-भत्रीमण्डल का कार्य राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण करना है, जिनके आधार पर राज्य शासन का संवासन किया जाता है । यह स्वामाविक है कि नीति-निर्माण का कार्य उन विषयों से सविधत होगा जो राज्य तथा समवर्ती सूचियो में रखे गये हैं। इन नीतियों के लिए विधान समा की सहमति बावस्थक है । प्राय. इन नीतियों को बाननी रूप देना प्रावश्यक हो जाता है। साधारणतया मत्रीयण्डल को विधान समा मे बहुमत प्राप्त रहता है, यत मत्री-परिषद की नीतियों को विधान समा में सरलता पूर्वक सहमति प्राप्त हो जाती है ।

मधीमण्टल का इसरा प्रमुख कार्य है, प्रशासन के विभिन्न विमागों के मध्य आवश्यन सहयोग तथा समन्यय स्थापित नरना, जिससे समस्त प्रशासन को एक इनाई के रूप में सचानित दिया जा सके। प्रशासन के विभिन्न विमाग अपने में पूपन, स्वतन तथा आस्तानिर्मर नहीं हो सन्ते है। उनमें विभिन्न विपयो पर पारस्परिक सहयोग एव समन्यय होना अस्यावश्यन है। इस सहयोग पर ही राज्य मो प्रपति निर्मर है।

राज्य वायेपालिका तथा प्रशासन पर नियमण रखना मंत्री मण्डल का नायें है। चूंलि नायंपालिका एव प्रशासन को चूंण्टि से मंत्रीमण्डल राज्य विधान समा के स्वार ति सामृहिक रूप से उत्तरदायी है यह नियान समा में बहुमत का विश्वास प्रयोग प्रति वृद्ध बनाये रखने के लिए मंत्रीमण्डल को सासन कुणलता, दसता एव तोककरूयाण के आधार पर सवासित करना चाहिये। अतएव यह स्वामाधिक है कि मंत्री-मण्डल समस्त कायंपालिका तथा प्रशासन सबयी कियागो पर निगरानी रखे। यदि शासन में दोप उत्पन्न हो जाते है तो मनियो को इसके लिए विधान समा के समस्त जवाब देना होगा।

मनीमण्डल ना एन प्रत्य महत्वपूर्ण नार्य यह है नि वह राज्य के वित्त प्रशासन को सुपाद रूप से समाधित करने ना प्रावधान नरे। यह राजनीति विज्ञान का एन सत्य है कि समस्त प्रशासन की सफलता ने लिए न केवल पर्याप्त वित्त होना प्रावध्यन है किन्तु एन वृढ क्रार्थिक व्यवस्था के सिए वित्त प्रशासन का समासन सही रूप से हो। उत्तम प्रशासन का उत्तरवायित्व मनीमण्डल का है प्रतः मनीमण्डल का सह भी उत्तरवायित्व हो जाता है नि पाज्य का वित्त-प्रशासन मी उत्तम हो। राज्य भी राजस्व सवयी नीति ना निर्धारण तथा वायिक झाथ-स्थयक मा निर्माण हेतु राज्य वित्त मनी नी ही जिसमेदारी है।

सक्षेत्र में, राज्य मशीमण्डल राज्य शासन की धुरी है। राज्य शासन की सफता मुप्पत मशीमण्डल पर ही निर्मार रहती है। इस कारण मित्रयों को सम्बद्धीय प्रणाली के अनुकृत प्रपन दायित्वी को सम्बद्धात प्रणाली के अनुकृत प्रपन दायित्वी को सम्बद्धात वाचा निर्माण प्रत्यावस्थक है। समीय मशीमण्डल के सन्दर्भ में अध्ययन किया जा चुका है कि ससदीय पद्धति में मित्रयों के जार प्रकार के उत्तरदायित्व होते है। जो इस प्रकार है।

१—मित्रयो के तकनीकी या श्रीपनारिक उत्तरदायित का सिद्धान्त ससदीय पदित से मित्रयो का श्रीपनारिक उत्तरदायित्व राज्याण्यक्ष के प्रति होता है। मारत सम के राज्यों से मनीमाण श्रीपनारिक रूप से राज्यपात के प्रति उत्तरदायी होते। मनुख्येद १६० के सनुवार मृख्यमत्री का यह उत्तरदायित्व है कि—(४) राज्यपात को राज्य प्रशासन, व्यवस्थाएक के समस्त मामलो से सर्विषत राज्य मनी-परिपद के निर्णयों से प्रवणत करायें।  (त) राज्य के प्रधानन तथा व्यवस्थापन सबयी मामलो के सबय म राज्यपाल को वह समस्त जानकारी दे जो राज्यपाल बाहना है।

(म) यदि राज्यपान की ऐसी इच्छा है तो मनीमण्डल के विचार-विमर्ध के सिए ऐसे मामल का प्रस्तुत करे जिस पर निर्णय किसी मंत्री ने तिया है कि सु जिस

पर मनीमण्डल ने विचार नहीं किया था।

२—मिश्रयो न पारावरित उत्तरदायित का विद्वानत—मनी-मण्डल एन इनाई के समात है। इसके सदस्यो वो एक सर्वाद्ध्य प्रमावधाती तथा एनवापूर्ण इनाई के रूप म कार्य करना धारवणक है। यह बहुने म कोई प्रतिकाशीतित नहीं होगी मिग्न पर प्राथित व प्रतिकार विद्यालय कार्य एनता की माद-मामा पर धारतित हज्या है।

इसने विपरीत, यदि मत्रीमण्डल में भगडा और एट है तो निश्चम ही वह

स्यामी नहीं रह संदेगा।

२—रविश्वा उत्तरदायित का सिद्धान्त—प्रत्यक मनी प्रपने विमाग के निर क्रात्मिगन र न से उत्तरदायित का सिद्धान्त मनी प्रत्ये तिमाग के निर क्रात्मिगन र न से उत्तरदायों है। वदानि विश्वाद स्थाने के निर्देश स्थानियान कर से राज्य विधान स्थाने के निर्देश र विद्यान स्थाने के निर्देश स्थानियान उत्तरदायों दे हिए भी प्रात्मदा कर से अधिनान के महुनदे ११४ (१) म निद्धित है, जिनके महुनद्वार पश्ची प्रत्ये द पर राज्यपत के मानुवार पश्ची प्रत्ये पर पर राज्यपत के मानुवार न पश्ची प्रत्ये पर राज्यपत के मानुवार प्रत्ये है। व्यव्यव नहीं प्रतिकार के मानुवार प्रत्ये है। व्यव्यव नहीं प्रतिकार कर से मुक्तमनी ने प्रति उत्तरदायों होगा। यह उत्ति होता है नि सिष्धान में मानुवी स्थान समा के प्रति उत्तरदायों होगा। यह उत्ति होता है नि सिष्धान में मानुवी स्थान समा के प्रति उत्तरतायों व्यव्यान है सिद्धान समा के प्रति उत्तरतायों व व्यवस्थानियत के सिद्धान समा के प्रति उत्तरताय उत्तरदायित है सिद्धान को मान्यता प्रदान के स्थान स्थान के प्रता व्यक्तियाल के स्थान स्थान स्थान के प्रता व्यक्तियाल के स्थान स्थान के प्रता व्यक्तियाल व स्थानियाल के स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थानियाल स्थान स्था

४—संसदीय पढ़ीन ना मुल धावार—जनीमण्डल ने सामूहिन उत्तरसाधित्व का निद्धाल्य है। सविधान ने सद्भुद्ध ११५ (१) में बरीमण्डल राज्य विधान कान के प्रति प्रपत्ती नीतियो तथा नामों के निष्य उत्तरसाथी हाथा। १म सिद्धाल्य ने मतुसार मत्त्रीनण्डल का सिन्तल वत तक बना यह सत्ता है उत्त तन विधान समा म बहुमन का विश्वास उत्तने प्रति है। दूतरे घाटा में, यदि बहुमत का विश्वास विधान समा म मतीमण्डल के प्रति न यह, वा एसी स्थिति म यह प्रशी-मण्डल मा ही बाया। प्रतिक दश में मत्त्रीमण्डल की निवान समा ने समम प्रस्ता विश्वास बनाय रसन पर ही स्थितता प्राप्त होगी।

### मुख्यमत्री

भारतीय सविधान के अनुच्छेर १६३ (१) के अनुसार मुख्यमंत्री मनीमण्डन का . हत्या है। मुख्यमंत्री की निकृतिन चित्रवान करता है। परन्तु मुख्यमंत्री के पद पर केवल उसी राजनीतिक दत्त के नेता को नियुक्त किया जाता है जिसको ग्राम-चुनाव में राज्य विघान समा में बहुमत मिला है। यदि ग्राम-चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल बुछ हद तक मुख्यमत्री की नियुक्ति में स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है।

मुख्यमध्रो के प्रमुख कार्य — १-मत्रीमण्डल के ब्रध्यक्ष होने वे कारण वह मत्री-मण्डल का गठन करता है। मुख्यमध्री की सम्मित पर ही राज्यपाल प्रत्य मिन्यों की नियुक्ति करता है। यनीमण्डल के सगठन में मुख्यमध्री को प्रधान मत्री के समान सत्यिष्ट सन्तियों प्राप्त है। यह उसकी इच्छा पर निर्मर नरता है कि नौन व्यक्ति मधीमण्डल में रहे था न रहे।

२—मनीमण्डल के अध्यक्ष के नाते, मुख्यमधी मनीमण्डल की बैठको की प्रध्यक्षना करना है। मनीमण्डल के निर्णयो पर मुख्यमनी का महत्वपूर्ण प्रमाव होता है।

३— मुश्यमनी राज्यपाल तथा मनीमण्डल के मध्य सबैधानिक कडी के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद १६७ के अनुवार मुख्यमंत्री राज्यपाल को, राज्य-धासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी मनीमण्डल के निर्धायों से अवस्त कराता है। इसी प्रकार यदि राज्यपाल राज्य प्रशासन या प्रशासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी किसी वियय पर खानकारी चाहता है तो मुख्यमंत्री का यह वर्तव्य है कि यह जानकारी उसे प्रतक्त करे।

४—मुस्यमनी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। समस्त प्रवासन पर उसको निरीक्षण करने वा प्रायकार प्राप्त है। वह बासनक्यी गाडी का चालक है, जिसके नेतृत्व मे बासन का सचालन होता है। मंत्रीमण्डल से सवधित विभिन्न विवादों के निरदारे की जिम्मेदारी मुख्यमत्री की ही है।

५ — मुख्यमंत्री विधान समा वा नेतृत्व भी करता है। विधान समा में सर-वारी नीतियो तथा वार्यों की धोषणा और स्पन्दीकरण करते का उत्तरदायित्व मुत्यमंत्री पर ही है। वह विधान समा में किसी मंत्री द्वारा असतीयपूर्वक उत्तर विधे जाते की स्थित में, सवधित विधय पर सदस्यों की शका को दूर करता है। वह सरकार का प्रमुख प्रवनता है और उसके वन्तव्या तथा आभ्वासन प्रतितन रूप से प्राधिकारक माने जाते हैं।

यह स्वामाविक है कि मुख्यमती की स्थिति राज्यों में सबसय केन्द्र सरकार में प्रधान मनी की स्थिति के समान है, नयोंकि दोनो क्षेत्रों में सबदीय प्रणाशी स्थापित की गई है। मृत राज्य में मुख्यमती की महत्ता वास्तविक बासक के रूप में है। राज्य का पूरा प्रशासन तन उसी के सकेतो पर सवालित होता है। वह राज्य मन्नीमण्डल का 'क'वान' है। यत मन्नीमण्डल से उसके निर्णयों का प्रस्पिक महत्व होता है।

### महाधिवक्ता

सविधान के धनुक्देद १६५ के धन्तगँत सम में प्रत्येक राज्य के लिए महाधि-बता का प्रावधान क्या गया है। महाधिवता की नियुक्ति राज्यपाल हारा, मती-मण्डल की सलाह के बानुसार, की जाती है। केवल उस व्यक्ति की महाधिवकता

नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्च न्वायालय के न्यायाचीश के पद के योग्य होता है। महायिवदना का कार्यकाल राज्यपास के 'प्रसाद पर्यन्न' तक रहेगा।

उसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित क्या जाता है। महाधिवकता के कार्य राज्य के सम्बन्ध में लगभग केन्द्रीय सरकार से संबंधित महान्यायवादी में नायाँ ने समान हैं।

महाभिवनता राज्य सरकार को उन समस्त विषया पर कानूनी सम्मति वैहा है जो उत्तरो प्रेपित किये गये हैं । इसके अकिरिस्त, नातृत हारा उत्तरे का निर्मारण किया जा सकता है। इसके अकिरिस्त, नातृत हारा उत्तरे का निर्मारण किया जा सकता है। इसके अकिरिस्त, नातृत हारा उत्तरे का निर्मारण किया जा सकता है। इस्थ की घोर से उच्च न्यायालय में बहु उत समस्त मामलों में पैरवी करता है, जिनमें राज्य एक पड़ा म है। राज्य की तरफ में वह जन्य न्यामालय के समक्ष अपीलीय या पीनदारी मामलो मे पैरवी करता है। महा-पानात्व क कमन अवात्व का पानाव्य वा नाव्यत्व न पान करात्व व कर्मा करात्व है । विश्व पियक्ता ग्रंपने कार्यकाल में पात्र्य के विरद्ध किसी सामसे में कार्य नहीं कर सकता है। वह भोजदारी मामलो से ग्रामकुक्त का क्याय नहीं कर सकता है। महाधि-वक्ता ऐसे प्रकरणो म, जिनमे उसे सरकार के पदा में पैरवी करना है, किसी प्रत्य निजी पक्ष के लिए पैरवी नहीं कर सकता है। वह किसी कम्पनी में डायरेक्टर के पद को बिना सरकार की अनुमति के स्वीकृत नहीं कर सकता है। प्राय सरकार के परिवर्तन के साम ही महाधिवक्ता का नावेदान समाप्त हो जाता है क्योंनि उसनी निमुन्ति राजनीतिक साधार पर की जाती है।

# राज्य विधान मण्डल

मारतीय सविधान के धन्तर्गत जारतीय सध के प्रत्येक राज्य के लिये व्यव-स्थापन कार्यों के लिए एक विधान-मण्डल को स्थापना की गई है। साधारणतथा, व्यवस्थापिका समा के सगठन की दो पढ़ितयों होती हैं। सर्वप्रयम, दिसदनारमक, पढ़ित के प्रन्तर्गत, व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, उच्च सदन तथा निम्न सदन, दितीय, एक सदनारमक पढ़ित में व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन होता है।

विधान-परिपद--मारतीय सब के कुछ राज्यों में द्विसदनारमक पढिति है मौर ग्रन्थ राज्यों में एक सदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई है। ग्रतएव कुछ राज्यों में विधान मण्डल का निर्माण राज्यपाल तथा दो सदनों से होता है, भीर कुछ राज्यों में राज्यपाल तथा एक सदन द्वारा होता है। जिन राज्यों में दो सदन है. वहाँ उच्च सदन (द्वितीय सदन) को विधान परिषद की सज्ञा दी गई है. श्रीर निम्न सदन (प्रथम सदन) को विधान सभा कहा जाता है। भारम्म मे, जिन राज्यो म दिसदनात्मक पद्धति को भ्रपनाया गया, उनके नाम इस प्रकार है-बम्बई, विहार, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बगाल, पजाव और मैसूर। तत्पश्चात सवि-धान संशोधन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनात्मक पढित की स्थापना की गई--माध्यप्रदेश, विहार, वस्वई, मध्यप्रदेश, मद्रास. मैसर, पजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बगाल ग्रीर जम्मू-काश्मीर । चार राज्यो राजस्थान केरल, मासाम, तथा उडीसा मे एक सदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई। सविधान के ग्रमुच्छेद १६६ (१) के ग्रनुसार विधान परिपद (उच्च सदन) समाप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनके अनुसार यदि राज्य विधान समा के समस्त सदस्यों के बहमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के है बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह माँग की जाती है कि विधान परिपद को समाप्त निया जाये, या जिस राज्य में यह सदन नहीं है, उपर्युक्त माधार पर विधान समा प्रस्ताव पारित करती है कि उक्त राज्य मे प्रधान-परिपद स्थापित की जाये तो ससद कानन द्वारा राज्य विधान-समा के प्रस्ताव के ग्रनुसार विधान-'परिपद की समाप्ति या स्थापना के लिए प्रावधान करेगी। यह स्पष्ट है कि

विद्यान-परिषद को स्थापना या समाप्ति मस्यत उक्त राज्य की विद्यान सभा की इच्छा पर निर्मर है।

राज्य विधान-परिषद का संगठन राज्य विधान-परिषद के सदस्यों की संस्था उक्त राज्य की विधान-समा के सदस्यों की सस्या की है से अधिक नहीं होनी चाहिये, परन्तु किसी स्थिति मे विधान-परिषद के सदस्यों की सहया ४० से कम

नहीं होनी चाहिये : विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार से होगा । (क) एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन एक निर्वाचन-भण्डल द्वारा होगा, जिसके सदस्य स्थानीय स्वशासन सस्यामी (नगरपालिका, जिला मण्डल या ससद

द्वारा निर्धारित प्रत्य स्थानीय सस्याएँ) के सदस्य होंगे । (ख) एक बार्ट्स ब्रह्म (क्रि) सदस्य राज्य में रहने वाले स्तातको द्वारा निर्वा-

चित किये जायेगे। (ग) एक बारह अश (पुँद) सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्षों के **प्रनुप्रव** के शिक्षक करेंगे जो राज्य में कम से कम माध्यमिक विद्यालयों ने पड़ा रहे हैं।

(थ) एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन निषान-समा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा ।

(ह) शेष सदस्यो को राज्यपाल मनोनीत करता है, जिन्होंने साहित्य, विधि. सहकारिता मान्दोलन तथा समाज सेवा क्षेत्र में ज्ञान या मनमद प्राप्त

क्याहै। कार्यकाल-राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य

प्रति दो वर्ष में सेवा निवत होते हैं. इसका तात्पर्य है कि अर्थक सदस्य का कार्य-काल ६ वर्षका है।

### सदस्य की योग्यताएँ

१-प्रत्येक सदस्य को भारत का नागरिक होना भावश्यक है।

२-कम से कम ३० वर्ष की बाय का होना चाहिये।

३- भन्य योग्यता, जो ससद कानून द्वारा निर्घारित करती है।

कोई सदस्य राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनो का सदस्य नहीं हो सकता है भौर न ही दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल का सदस्य हो सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की बैठको से ६० वा उससे अधिक दिनों बिना सदन की धनुमति के धनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त माना जायेगा ।

निम्नलिखित भाषारो पर किसी ध्यक्ति को विधान परिषद की सदस्यता के भयोग्य ठहराया जा सकता है :---

राज्य विधान मण्डल २५७

१---यदि मारत सरकार या निसी राज्य सरकार के खधीन लाम के पर पर है। यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय या राज्य के मित्रयो तथा नानून द्वारा निर्धारित किसी प्रत्य पर पर लाग नहीं होता है।

२ - यदि वह न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया है।

३--यदि वह दिवालिया है।

४—यदि वह मारत ना नागरिक नहीं है या उसने निसी अन्य राज्य नी मागरिकता ग्रहण कर ली है या वह निसी भी अन्य देश ने प्रति राज्य मिक्त रखता है।

५—यदि यह किसी ससदीय कानून के अन्तर्गत अयोग्य होता है। उवाहरण क्वरूप १६५१ में ससद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १६५१ के अन्तर्गत -यायालय ने उन व्यक्तियों को अयोग्य धायित क्या है जो न्यायालय द्वारा दण्डित हुए हैं, या जिनको निर्वाचन के सबय में अध्य या अवैधानिक पार्यों के लिए दोपी पार्या गया।

राज्य विधान परिषद की बैठको के लिए गण पूर्ति की सस्या उसके पुल सदस्या का सस्या के एक दक्षाण सरवा कुके या १० होगी। (इन दोनो म से को मी सरया प्रधिक होगी, वह गणपूर्ति की सस्या होगी)।

विधान परियद का एक झम्बद तथा उपाध्यक्ष होता है, जिनना निर्वाचन विधान परियद ने सदस बरते हैं इनको १४ दिन के नीटिस पर विधान परियद बहुमत से प्रस्ताव पारियत कर पदच्युत नर सकती है। दोनो पदाधिकारियों को वेतन तथा नते मिलते हैं और इनके कार्य सगमग सधीय राज्य समा के झम्बद तथा उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सहस हैं।

### विघान परिपद के कार्य तथा प्रविकार

वियान परिषद के विमिन्न कार्यों तथा अधिकारों को तीन श्रीणयों में रखा. जा सकता है।

१—स्पबस्यापन सबधी कार्य—द्वितीय सदन के नाते राज्य विधान परियद को बानून निर्माण करने के सवय में सिवधान द्वारा कुछ कार्य प्रदत्त किये गय हैं। साधारण—निषेधन (विस्त विधेयक को छोड़कर) को किसी मी सबन म प्रस्तुत्र किया का सबता है जो रोक्तो सटकरो द्वारा परिस्त होने पर हो, राज्यपाल नी सहमित से वामून वन सकेगा। यदि दोनो सदनो में विधेयक पर मतबेद हो जाता है तो विधान समा द्वारा उसी सत्र में या नये सत्र में विधेयक पर मतबेद हो जाता है तो विधान समा द्वारा उसी सत्र में या नये सत्र में विधेयक पर मतबेद हो जाता है तो विधान समा द्वारा उसी सत्र में या नये सत्र में विधेयक को कानून माना जायगा।

यदि विषेयन विधान समा द्वारा पारित नर दिया गया है भीर विधान परियद के विचार-निमर्क के निए गया है निन्तु नियान परियद उस पर मोड़े तर्मयातम नार्यवादी नहीं नरती है तो विधेयन को विधान परियद में मस्तुन नरत के तीन मातृ तप्रवात नियान समा उसे पुत्र पारित नर सन्ती है। तस पुन-उत्तर विधेयन को विधान परियद ने समझ सदुन निया जानेगा निन्तु मिदि विधान परियद विधेयन को सार्योग्डन करती है या ऐसे बाधोन नरती है जो विधान समा हो समान्य है ता विधेयन को उस हानत में पारित माना जानेगा, जैसा नि मृतत. विधान सन्ता ने पारित होने के पत्रवात नी काई स्थान नहीं वैदी तो परियद ने समझ पिथेयन मन्तुन करते ने एक मातृ पत्रान्त नियंयन का दोनो द्वारा पारित माना वायेगा। सन्त सारास्य विधान ने सहय में विधान परियद, विधान नहीं वैदी तो परियद ने समझ पिथेयन मन्तुन करते ने एक मातृ व्यान्त नियंयन का दोनो द्वारा पारित माना वायेगा। सन्त सारास्य विधान में सहय में विधान परियद, विधान नहीं की स्व

२—विसीय कार्य—विसीय मानतो में विचान परिणद के प्रीयकार सममा एग्या समा के प्रीवकार सममा एग्या समा के प्रीवकार से नमान ही हैं। विसा या वर्ष विग्रेय को विद्याद को विद्याद समा वर्षाद होने के प्रवाद किया निवेश्यक को विधान विराध के विचार विभाज के प्रवाद किए में का जाना है। विग्रान परिषद को प्रयोग मुमानो को १४ दिनों में वेले चाहिए प्रयाद विस्त विवेशक विना विद्याद परिषद के मुमानो को १४ दिन के प्रवाद कुमान के विवेशक विद्याद परिषद के मुमानों के १४ दिन के प्रवाद कुमान के व्याप्ता । प्रकृत्येद १६६ (व) के प्रमुतार विधान समा विग्रान परिषद के मुमानों को प्राप्त क्षा विपान परिषद के मुमानों को प्रवाद क्षा विग्रान परिषद के मुमानों को प्रवाद क्षा का विग्रान परिषद के मुमानों को प्रवाद का विग्रान परिष्य के मुमानों के प्रवाद क्षा के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद का विग्रान परिष्य के मुमानों को प्रवाद का विग्रान परिष्य के मुमानों के प्रवाद के प्याप के प्रवाद के प्रव

६—हार्ष पालिका सम्बन्धी शक्तियो—सराधीय प्रणागी ये मशीनपटल का उत्तर-सायिल स्वयनसाधिका सम्म के निवंति सवन के प्रति होगा है। गर्याप उच्च सवन इत्तर मानीवन्त को सानीवना कर तो से स्वतार (मनीस्टरल) को प्रशास हनीया देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तथापि इनका प्रमास नगच्य नहीं ही सकता। घतः प्रयोगील्या (मनीवच्छत) के नियरण के निवंद उच्च सदन से प्रमास के सवस्य अर्थक स्वतं के तथा के तथा प्रशास के स्वतं के

#### राज्य विधान सभा

राज्य विधान मण्डल का निम्न सदन विधान समा है। यह राज्यो मे जनता का प्रतिनिधि सदन है। इस दृष्टि से यह सधीय ससद के निम्न सदन लोकसमा के समान हैं।

सगठन---राज्य विधान समा के सदस्यों की सख्या सबधित राज्य की जनसंख्या के सदर्म मे ५०० से अधिक तथा ६० से क्म नहीं होनी चाहिये। प्रध्येक जन-गणना के पश्चात, प्रत्येक राज्य की विधान समा के सदस्यों की सख्या को भीर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों में विमाजन पुर्नेनिधारित किया जाता है। अधिकतर निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्य हैं । प्रस्येव निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य निर्वाचित होता है। सदस्यो ना निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पद्धति के भनुसार होता है। संविधान द्वारा अनुसूचित जातियो तथा श्रादिम जातियो के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद ३३२ के अनुसार अनुसूचित जातियो तथा धनुमुचित बादिम जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के बनुपात में प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। असम की विधान सभा मे स्वायत्त ग्रादिम जिलो के प्रतिनिधियो के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये है। विसी भी राज्य का राज्यपाल विधान समा में झारल भारतीय समाज के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है, यदि उसके विचार में इस समाज को विधान समा मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। प्राय्म्य मे धनुसूचित जातियो, धनुसूचित ग्रादिम जातियो तथा धारल भारतीय प्रतिनिधियो के लिए विधान सभा में स्थान सुरक्षित करने के सर्वेद्यानिक प्रावधान सर्विद्यान के लागू होने के समय से दस वर्ष के लिए थे किन्त सविधान मे ब्राठवें संशोधन (संशोधन अधिनियम १९५६) द्वारा इसमे दस वर्ष की वृद्धि की गई है।

विभिन्न राज्यो की विधान समाश्रो के सदस्यो की सख्या निम्नानुसार है :--

१--म्रान्ध्र प्रदेश-२८७:

२--- प्रसम-१२६,

<del>१--</del>बिहार-३१८; ४---गुजरात-१६८,

५--हरियाणा-५१:

६--जम्मू-वश्मीर--७५;

७--केरल-१३३;

५—-मध्यप्रदेश--२१६: ६--मद्रास-२३४:

१०---महाराष्ट्र-२७०:

```
११—मैसर-२१६;
१२--वडीसा-१४०:
१३-पजाब-१०४,
१४--राजस्यान-१६४;
१५---उत्तरप्रदेश-४२५:
१६--पश्चिम बगाल-२८०,
```

१७--दिल्ली-१६;

१ प-- हिमाचल प्रदेश-६०:

१६--मणिपुर-३०;

२०-- त्रिपरा-३०;

कार्यकाल-सामान्यत राज्य वियान समा का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है। जब देश में सक्टकालीन स्थिति चौपित हो चुकी है तब विधान सभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए कितनी भी बार ससद के कानून द्वारा बढाया जा सकता है। परन्तु सक्टकालीन उद्योपणा के समाप्त होने पर किसी भी स्थिति मे विधान सभा का कार्यकाल ६ माह से व्यधिक समय तक नहीं बढाया का सकता है। यदि विधान समा म भन्नीमण्डल को बहमत का समर्थन समाप्त हो जाता है, तथा ग्रन्य कोई राजनीतिक दल वैकल्पिक सरकार निर्माण करने में असमर्थ है तो विधान समा को पांच वर्ष पूर्व भी राज्यपाल द्वारा भग किया जा सकता है।

विधान सभा के सदस्यों के लिए जो योग्यदाएँ निर्धारित की गई हैं वे निम्न-

लिखित हैं ---

(१) वह मारत का नागरिक हो ।

(२) उसकी मामुकम से कम २५ वर्ष की ही ।

(३) ससदीय कानून द्वारा निर्घारित श्रन्थ योग्यताथी को पूरा करता हो। मनुन्देद १७२ के अनुसार कोई व्यक्ति दोनो सदनो का सदस्य नही हो सकता

है, भीर न दो या दो से अधिक राज्य विधान मण्डलो ना सदस्य हो सनता है।

निम्नलिखित कारणो के धाधार पर कोई व्यक्ति विधान समा का सदस्य नहीं हो सक्ता :--

१--यदि वह मारत सरकार या किसी राज्य सरकार के ध्रयीन लाम के पद पर है।

२--यदि वह न्यायासय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है।

३-यदि वह दीवालिया है।

Y---यदि वह मारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी नागरिकता को पहण कर लिया है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या भिवन रक्तर है ।

प्र---यदि ससद के विसी वानून ने अन्तर्गत अयोग्य है।

राज्य विभान सभा ना निर्वाचन वयस्य मताधिकार वे सिद्धान्त पर सम्यन्त्र होता है। प्रयांत् प्रत्येव नायरिक वो जिसकी आयु २१ वर्ष से कम नही है, मत-दान वा प्रयिकार है। यदि वह उस क्षेत्र वा निवासी है, पागल नही है, म्रोर जिसको अटट या प्रविधानिक वार्य के लिए दिष्टत न विया गया है।

विधान सभा के दो महत्वपूर्ण पदाधिनारी हैं-(म्र) मध्यक्ष (स्पीन र),(व)उपाध्यक्ष (डिस्टी स्पीनर) । ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनो ना निर्वाचन विधान समा द्वारा होता है। ग्रह्मक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत करने का अधिकार विधान-समा को है। इसम हा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पा परचुत करने वे लिए १४ दिन वा नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि विधान समा बहुमत से यह प्रस्ताय पारित वर देती है तो मध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत माना जायेगा । यदि सप्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की सदस्यता छोड देता है तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा। यदि ग्राध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष द्वारा ग्राध्यक्ष के कार्य किये जायेंगे। यहि ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ने पद रिक्त हैं तो राज्यपाल ग्रस्थाई रूप से विद्यान समा ने निसी भी सदस्य नो उस पद पर नियुक्त करगा । यदि श्रध्यक्ष तथा जुपा-ध्यक्ष दोनो सदन की बँठक से अनुपस्थित हैं तो सदन के नियमों के अनुसार, मार्चवाहन मध्यक्ष सदन की कार्यवाही सचालित करेगा । सदन की जिस बैठक मे ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदच्यूत करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा है वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, तथापि उसे सदन में उपस्थित रहने, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने तथा प्रस्ताव पर मतदान करने का प्रियार है। प्रध्यक्ष तथा उपाध्यस को विधान मण्डल द्वारा पारित कानून के झन्तर्गत वेतन तथा मत्ते मिलते हैं। ये बेतन तथा मत्ते राज्य की सचित निधि मे से दिये जाते हैं। राज्य विधान समा ने प्रध्यक्ष तथा नायों की स्थिति लोक्समा ने प्रध्यक्ष के सदम है। लोरसमा ने प्रध्यक्ष के समान विधान समा के प्रध्यक्ष को स्वतंत्र तथा निप्पक्ष होना झावश्यव है।

विधान समा के श्रध्यक्ष के निम्नलिखित कार्य हैं।

१-वह सदन की अध्यक्षता करता है।

र-सदन मे प्रश्नो तथा प्रस्तावो के रखने के लिए उसकी धनुमति ब्रावश्यक है।

३--- मध्यरा द्वारा ही सदन की कार्यवाहियों के लिए समय निर्धारित किया जाता है।

Y—प्रप्यक्ष सदन ने नेता ने परामश्र से सदन नी नार्यवाहियों का क्रम तथा भाषणों ने लिए समयाविध निर्धारित नरता है।

१—वह सदन में शान्ति, व्यवस्था तथा धनुशासन बनाये रखता है स्रोर विसी सदस्य नौ सदन के निषयों के उल्लंधन वरने पर उसे निष्मायित कर सकता है। सदन मे गमीर श्रज्ञान्ति की स्थिति में श्रष्ट्यक्ष सदन को स्थागित कर सकता है।

६ — प्रध्यक्ष सदन की विभिन्न समितियों के अध्यक्षों की सूची तैयार करता है। वह सदन की प्रवर एवं अन्य समितियों के लिए अध्यक्ष मनोनीत करता है। अ—सदन के निवासों की आवश्य करते का अधिकार अध्यक्ष की ही है। उसके

७—सदन के नियमों को व्याख्या करने का अधिकार अध्यक्ष को ही है। उसके निर्णयों को चूर्नानों नहीं दी जा सकती।
=—किसी विषेधक के सबस म कि वह विषेधक, किस विषेधक मा साधारण

द—। वसा विषयक के सबध में कि वह विषयक, विसे विषयक या साधारण विषयक है प्रध्यम का निषय अन्तिम है।

सहोपे म, विधान सवा का अध्यक्ष सदस्यों के अधिकारों का सरहार है। ति सहेद प्रध्यक्ष की वह भूमिना इस पर निर्मार है कि वह अपने कार्यों में सवत्र क क्यां निप्पाल है जा नहीं। अध्यक्ष के पत्र को असिटका की बनारे पत्र ते ना उत्तर-वाधित नुख मात्रा में स्वय अध्यक्ष का है, और कुछ नाना में सदन के सदस्यों पर निर्मार क्यां है। इस सम्बर्ध म, बढ़ी तक अध्यक्ष की पूर्णिक का प्रत्य है, भारत के कई राज्यों ने अध्यक्षी ने पत्र को अधिका को अपने सर्वीव नागों से महरा सक्ता पहुँचामा । यहाँ हाल ही के वो अवाहरण अस्तुत किये जा स्वकृत हैं।

(१) दिसम्बर १६९७, ये राज्याल भी पर्यविश्त ने बुल्बनरी जी स्वयन मुज्जी के मनी मण्डल में ब्रव्हांस्त कर दिया क्योंकि की मुक्ती ने विचान समा की बहुक में बुलाने में भीर यह जात करने में कि बातवार में जनके नमीमण्डल को विधान समा न बहुमत झाल वा बा नहीं, हिष्वित्याहर विवाई । अताद श्री वर्मवीर को यह लगा कि भी मुक्तीं की सरनार को विधान समा का समर्थन प्राप्त गई। या। भी मुक्तीं नमी मण्डल को बहुस्त कर उन्होंने थी की वहि को मुख्य मनी निमुक्त किया । तत्थवात जब विधान समा की देठक धामित्रस भी गई विधान समा के प्रभावत श्री विवय कुमार वर्द्धीं ने, विकर्ती प्रध में भी गी। सीत वेशों के माने मान्यक को निर्माण विधानिक था, विधान समा को समर्थी मान स्वार्धीत करा है प्रस्तु होत्य स्वितित वर दिया । यह विदित रहे कि विधान समा के सम्बन्ध का कार्य सदन भी कार्यवादी ना स्वारान करना है ।

२—दूसरे मामले में पत्राव की विधात सन्ता के अध्यक्ष में विधान समा का अक्साल स्थिति कर दिया, जिसके पत्तस्वरूप विधान समा द्वारा वार्षिक माम व्यापक पारित नहीं किया जा सका। इसका नतीका यह हुआ कि राज्यपाल ने व्यापके दारा विधान सन्ता को बैठक आमितन न र माम-व्यापक पारित करवाया। उस प्रवास पर विधान समा को बैठक आमितन न र माम व्यापक पारित करवाया। उस प्रवास पर विधान समा को पुलिस का सरक्षण दिया गया था।

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कतिएय सामतों म स्वय ध्रव्यक्षी ने पद सी प्रतिकापर अपने अवैधानिक कार्यों द्वारा आधात प्रतेवाया है। इसके विपरीत कई राज्यां की विचान समाधी म मुख सदस्या ने अपने अमद्र व्यवहार से अध्यक्ष पर का अनादर निया है। उदाहरण स्वरूप १९४८ म उत्तर प्रदेश विधान समा म विधान समा मार्शन नो अव्यक्ष के आदेशानुसार सक्तरत पुनिस की मदद निर्मा है। विद्यान समा समान को अव्यक्ष के सादेशानुसार सक्तरत पुनिस की मदद के बाहर जाने ने प्रारंग का उत्तरा उत्तरी सदस्यों ने अध्यक्ष द्वारा उनने सदन के बाहर जाने ने प्रारंग का उत्तरा निया । इसी अवार सितान्यर १९४६ म परिवम वयान की विधान समा म स्थिति ने यह रूप निया कि नावेस दल तथा विरोधी दन (साम्यवादी दन) के सदस्यों ने अहसदिय साथा वा प्रयोग नरते हुए एवं इसरे पर जूते हुने । व्यविन्यसारण यव मत्री मण्डक के सदस्यो की और के नाये। इसरे पर जूते हुने । व्यविन्यसारण यव मत्री मण्डक के सदस्यो की और के नाये। इसरे प्रतिह्ता हो सदस्यों ने पत्र को किए साम महाया पाई की। प्रारंग के प्रति हो स्वरूप की स्वात्र करने के लिए विधान समा की स्वरूप वा स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप वा समा मा स्वरूप की स्वरूप वा सम्बर्ध स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा सम्बर्ध स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा सम्बर्ध स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा सम्बर्ध स्वरूप वा समा मा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा सम्बर्ध स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप वा स्वरूप की स

राज्य विषास सभा के अधिकार—राज्य विवान समा ने विभिन्न कार्यों की

१--व्यवस्थापन समधी कार्यं,

२--वित्तीय वार्यं,

३--नार्यपालिया तथा प्रशासन ना नियन्त्रण तथा,

४---राष्ट्रपति थे निर्वाचन सबग्री नार्य ।

१-ध्यस्थापन सबधी वार्य-राज्य विधान समा वा प्रमुख वार्य विधि निर्माण करना है। राज्य विधान समा वो राज्य सूची म उल्लिखित विषयो पर विधि निर्माण करने वा अधिवार है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधान समा वो समवती सूची म उल्लिखित विषयो पर मी नानून बनाने वा अधिवार है। वस्तु विधान सम्बद्धी सूची म उल्लिखित विषयो पर भी नानून बनाने वा अधिवार है। वस्तु विधान सम्बद्धी में उल्लिखित विषयो पर नानून निर्माण करने वा अधिवार है। विस्तु इस सूची म उल्लिखित विषयो पर नानून निर्माण करने वा अधिवार है। विस्तु इस सूची म उल्लिखित विधान पर निर्मात कार्य विधान समा द्वारा निर्मात वानून का समर्थ की विद्याप पर निर्मात समीय बानून है, हो अपने अधिवार समा वार्य वानून वा समर्थ समीय कानून हो वेच माना जायेगा और जिल हुद तर राज्य वानून वा समर्थ समीय कानून हो, उस हुद तक उसरो अवंग माना जायेगा वावा। तथापि यह राज्य विधान समा द्वारा पारित वानून वो राज्य वानून वो सहमनि वे लिए सुरिक्षन रसा गया पा और राज्य कानून वे की राज्य कानून वेव होगा।

सविपान द्वारा राज्य विधान मण्डलो पर विधि निर्माण के सबध में निम्न-निश्चित सीमार्थ लगायी गई हैं।

- (क) कितपय नातृन जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित क्ये में हैं, विवा राज्यति की धनुमित ने बंध नहीं माने जा सनते हैं। उदाहुत्कर नरस्त मृज्येद ३० के कतुसार सम्प्रीत प्रविद्यहम करने के लिए वानृन क्युटेद २१४ के का सार समवर्ती कुषी च उद्दिल्विक क्रिडी विषय पर पारित कानृन निजना सपर्, ससद द्वारा उसी विषय पर पारित, निशी कानृन से हैं। अनुष्येद २६६ के धनु-सार ऐसे राज्य कानृन जिनने द्वारा ऐसी वम्मिन के क्रम-विश्य पर नर लागू विचा गया है, वो समद ने वानृन द्वारा सार्वजनिक व्यवन के लिए साक्यक निशीति नी है।
- (त) क्षिप्रय विषयेक राज्य विधान मण्डल के क्रिसी भी सदम म विना राज्यति की पूर्व सम्मति के प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरण स्वकर, मतुष्येद १०४ (वी) के अनुसार ऐके विधेयन जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित में राज्येद के स्वद स्था वाहर ब्याचार वाणिज्य सा सेम-वेन करने की स्वतनता पर प्रतिकाल क्षणाना है।
- (ग) साधारणतथा जारतीय सविधान में सम्बाद के सिद्धान्त नो धर्माने के फलास्वरूप राज्य सुन्नी में उन्तितिक विषयों पर नेवल राज्य विधान मण्डल ही विधि निर्माण कर सकते हैं। किन्तु सविधान मं उसके कविषय परवाद मी हैं, विको धरूरोंत सब समय राज्य सुन्नी में विजित विश्य पर कानून बना सनती है। ये परिविधियों का अगर हैं 'से परिविधियां का अगर हैं 'से स्विधियां का अगर हैं 'से स्विधियां का अगर है 'से स्विधियां का अग
- (१) धनुष्येत २४६ के धनुतार वर्षि सत्तव का उच्च सवन (राज्य समा) दो तिहार्ष बृत्तमत के आधार पर यह अस्ताव धारित करती है नि पाड़ीय दित म राज्य मुक्ती ने प्रत्निवित किसी नियय पर सत्तव को कानून नताने ना धापकार कीया।
- (२) मदि देश में सकटकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति ने की है तो धनुष्येद २५० के धनुसार सबद राज्य सूची में वणित किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है।
- (३) यदि सम के किसी राज्य की सरकार को सविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सक्ता है तो राज्यपित अनुज्येद ३५६ के अन्तर्गत राज्य निवान मण्डल को स्वर्गित कर उसकी शक्तियाँ ससर में निहित कर सकता है।

राज्य विधान संसा में साधारण तथा थन विधेवक दोनो प्रस्तुन निजे जा यक्ते हैं। यस्तुत व्यवस्थाल बत्यमी कवित्या विधान समा में ही निहित है। क्योंकि यदि एक विधेवक विधान समा हारा पासित हो जाना है एस्सु विधान धर्मण्य (शिंद राज्य में विधान परिचय है) उतका विरोध करती है ती विधान समा के उसी था नवे सन में विषयक की पुनः पारित करने से तथा राज्यपाल की सहमति के पहचात् वियेगक को बानून का रूप प्राप्त हो जामेगा। यदि निषी विदेशक को राज्य सभा डारा पारित कर विधान परिपद के विचार-विमां की लिए मेंजा गया है थीर विधान परिपद उस पर वोई निर्मयास्यव वार्मवाही नहीं करती है तो विधान सभा उस वियोग की विधान परिपद में प्रस्तुत करने की तिथि के तीन माह पश्चात् पुन पारित कर सकती है। सत्यप्रवात् वियेगक की विधान परिपद में प्रस्तुत करते की विधान परिपद में प्रस्तुत करते की विधान परिपद विधेगक को महाने परिपद है प्रस्तुत करती है जो तथान समा को प्रसाग है, तो विधेयक को उसी दिखान परिपद विधेगक को महाने का स्वाप्त की प्रसाव को स्वाप्त प्रसाव की स्वाप्त परिपद विधेगक को स्वाप्त परिपद की समक समाय है, तो विधेयक को उसी है विधान परिपद विधेगक को समाय है, तो विधेयक को उसी है विधान समा ने पारित विधा था। यदि विधान-परिपद विधेगक पर, विधान समा ने पारित विधा था। यदि विधान-परिपद विधेगक पर, विधान समा ने पारित विधा था। विदेश के समक विधेगक पर, विधान समा ने पारित विधान परिपद के समक विधेगक परित विधे एक माह पश्चात, विशेग के समक विधेगक माह विधेगन में ती विध से एक माह पश्चात, विधेगत के सोने सहतो हारा पारित मागा जानेगा।

२—विसीय सिक्तथों—विधान सभा को राज्य की सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था पर रित्यसण रहता है। वित्त विसेयको वो केकल विधान समा थे ही प्रस्तावित किया का सकता है। यदि विसी राज्य मे विधान परिष्य ( उच्च सदन) भी है तो वित्त-विपेयक विधान सभा में पारित होने के पक्षत्व विधान परिष्य के सम्प्रक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। परन्तु विधान-परिष्य के वित्त विषेयक के प्राप्त होने के चौदह दिनों में, उसको प्राप्त विधेयक वर विचार कर विधान समा को वापिस मेजना होगा। यदि इस समयाविष में विधेयक को विधान परिषय वापस नही करती है या विषेयक पर जो प्राप्त विधीयक को विधान परिषय वापस नही है तो विषेयक को दोनो सदनो द्वारा पारित मान निया जावेगा।

प्रत्येक हितीय वर्ष के धारण्य में वाधिन साम-ध्ययन को विवान समा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ध्यय के समस्त प्रस्तावों का विवान समा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ध्यय के समस्त प्रस्तावों का विवान समा के समक्ष रक्षता प्रावच्या है उस पर पर नेवलाय निवार विमार्थ हो सकता है, परण्तु मतवान नहीं किया जा सकता है। प्रम्य ज्या सबयी प्रस्ताव विचान समा ने समक्ष प्रमुत्तान मांगे के स्थों में प्रस्तुत विचे जा सकते हैं। घतुतान सबयी मांगी पर मतदान करने का प्रावचार नेवल विधान समा अनुदान की राश्चि को प्रस्तुत विचान समा अनुदान की राश्चि को मांगी है है। विचान समा अनुदान की राश्चित के प्रमुत्तान की प्रमुत्तान स्वाम की प्रमुत्तान की प्रमुत्तान

(३) कार्यपालिका तथा प्रसासन पर नियत्रण—मारतीय सथीय सरकार की मांति राज्यों ने भी ससदीय प्रणाली सांगू नो वई है। दोनों स्वर पर नार्यपालिका तथा प्रसासन की व्यवस्थापिका (निमासदन) के प्रति चयानदारी माना पाया राज्यों ने नार्यपालिकाएँ मित्रीभण्डका प्रपत्ने कार्यों चया गीरियों ने तिए विधान समाधी के इति उत्तरदायों हैं। ससदीय पद्धित की एक विशेषण महि है कि कार्यपालिका (मर्यासप्टक) के बदस्य व्यवस्थापिका सना के सदस्य मी होते हैं, इस कारण, व्यवस्थापिका कार्यपालिका को स्वरास प्रयोग हरा सरसता पूर्वक तथा प्रसास वालाली कर से नियत्रक में रख सरवी है।

माथ जिन सायनो हारा विशान समा कार्यपालिका को अपने नियमण पे एसती है, वे प्रक्त, पूरक प्रका, स्वापन, प्रस्ताव, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन पिषवसास प्रस्ताव के रूप में हैं। सत्येष में राज्य दिवान सभा कार्य-पालिका तथा श्यासन पर नियमण रखकर, उसे स्वस्थ तथा सक्षम बनाने में सहायक है।

राज्य विधान मण्डल के कार्यों का शब्दम्यन करते हुए यहाँ उपयुक्त होगा कि राज्यों ने निर्धि निर्माण का भी मध्ययन किया कार्ये। विधि-निर्माण-कार्य की प्रकार के निर्धेयकों से सर्वाचित हैं। साधारण विधेयक तथा विस्त विधेयक।

(१) साधारण विधेवल-साधारण विधेवको को विधान मण्डल के किसी मी सदन मे प्रस्तुत किया जा सत्ता है। विधेवक के विधि के रूप में पारित होंने के लिए प्रत्येक सदन में तीन बरणो से निकलना होता है। इन शीन बरणो को सदन हारा विधेवक को तीन वाचनो के रूप में देला वा सकता है।

विषेयक का प्रथम बाबन तब होता है, जबकि सदय में उते प्रवृत्त किया जाता है। विषेयक का सदय में प्रवृत्त करता एक प्रोपशरित्र कार्य है। से स्वत्य में प्रवृत्त करता है, वह एक सिज्य भाषण के सा देवा में प्रवृत्ति करता है, वह एक सिज्य भाषण के ता है। परप्यापुत्राप इस नियंपक पर कोई नहस नहीं होनी है। यदि सदय विषेयक को प्रवृत्त करते हैं। यदि सदय विषेयक प्रवृत्त कर रहां है, वह वहना है "सहोदय । में तियंपक प्रवृत कर रहां हैं। यदि सदय नियंपक मंद्र कर रहां हैं। यदि सदय नियंपक प्रवृत्त कर रहां हैं। यदि सदय नियंपक काला करने के प्रदात का निरोध किया जाता है तो सदय का मध्यक्ष विषयक को प्रवृत्त करने की सदाय का निरोध क्या जाता है तो सदय का मध्यक्ष विषयक को प्रवृत्त करने की प्रवृत्त करने की प्रवृत्त करने की प्रवृत्त करता है। इसके साथ ही स्थिपी सदय स्था प्रयूत्त करने की प्रवृत्त करने की प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति करने साथ ही स्थापी सदय स्थापी प्रपत्ता करना के प्रवृत्ति करने साथ ही स्थापी सदय स्थापी प्रपत्ता करना के प्रवृत्ति करने साथ ही स्थापन स्यापन स्थापन स

में प्रकाशित किया जाता है। गजट में विधेयक के प्रकाशित होने पर विधेयक का प्रथम बाचन समाप्त हो जाता है।

दितीय साथन में विधेयन पर दो प्रकार से विचार विमर्श किया जाता है। सर्वप्रथम, विधेयक पर सामान्य रूप से विचार-विसर्श किया जाता है। यहाँ पर जिस सदस्य ने विषेयक का प्रवर्तन किया है, वह निम्नलिखित विसी एव प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है।

(क) विधेषक पर तुरन्त या भविष्य में किसी तिथि से विचार-विमर्श प्रारम्म किया जाये।

(ख) विधेयक को सदन की प्रवर सामित के समझ रखा जाये ।

(ग) यदि राज्य मे दो सदन हैं तो विधेषक को सदन की सयुक्त समिति के समक्ष रखा जाये. या।

(ध) विधेयक को जनमत ज्ञात करने के लिए प्रसारित किया जाये। इस चरण में विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य विधेयक के उद्देश्यों की स्पष्ट करता है, तथा विधेयक सबधी भावस्थक जानकारी सदन को देता है। बहुस विधेयक के सिद्धान्ती तक ही सीमित रहती है। इस स्तर पर विषेत्रक में कोई संबोधन नहीं हो सकेगा।

दितीय, विधेयक पर विस्तार पुर्वक विचार-विमर्श किया जाता है। प्रपति विधयक के विभिन्न लण्डो. भागों, सनमचियो, तथा संशोधनो पर एक-एक कर विचार विमर्श किया जायेगा । विधेयक को सटन की प्रवर सीमति के समक्ष प्रस्तत किया जा सकता है। प्रवर समिति के प्राय १० से १५ तक सदस्य होते है। सदन के प्रध्यक्ष द्वारा समिति के प्रध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। प्रवर समिति का कार्य विशेषक के विभिन्न खण्डो, तथा आगो का गहराई से परीक्षण करना है। इस सन्दर्भ मे समिति प्रावश्यक कायनात तथा साध्य प्राप्त कर सकती है। समिति उन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को भी धामत्रित कर सकती है जिनके हित विधेयक से सविधत हैं, अन्त में समिति का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तत रता है। तरपश्चात् सदन मे विधेयक का नृतीय वाचन भारम्म होगा।

तृतीय वाचन-यह विधेयक का धन्तिम चरण कहलाता है । इस स्थिति मे यह प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक को पारित किया जाये। साधारणातया, इस चरण में कोई संशोधन प्रस्तावित या प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। बहस इसी विषय पर सीमित रहती है कि विघेयक को स्वीकृत या प्रस्वीकृत किया जाये। जब विघेयक सदन द्वारा पारित हो जाता है, तो उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, यदि राज्य में दूसरा सदन है। उसमे विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया पहले सदन की प्रक्रिया के समान ही होगी। दोनी सदनों से निधेयक के पारित होने के पश्चात.

उसे राज्यपाल की सहमति के लिए घेज दिया जाता है। राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने पर विधेयक को सरकारी अबट में पान्य विधान अब्बल के कानून के एम प्राप्त का का होता है। जिन विधेय विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की सान्यप्रकात होती है, वे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर ही जानून बन सकते।

(०) विस्त विद्येषण-विद्य विद्येषण नेवल पान्य विधान मण्डल के तिषक्षे सहत मे ही प्रयुत्त किये जा सनत हैं, व्ययंत्त विद्या विद्येषण को विधान परिप्रक किया जावन हैं, व्ययंत्त विद्या विद्येषण को विधान परिप्रक विद्या विद्येषण की तिष्योण विद्या विद्येषण किया विद्येषण किया विद्येषण किया विद्येषण की विद्या विद्येषण की विद्या क्या में पान्यवाल की पूर्वापूर्तिक की विद्या जा सकता है। प्रयोग विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या के प्रयोग किया विद्या विद्

१--राज्यपाल के वेतन तथा असे तथा उसके पद से सर्वधित भ्रम्य स्थ्य ।

२—राज्य विधान समा के अध्यक्ष स्था उपाध्यक्ष सथा विधान परिषद के

३--राज्य पर मारित ऋण तथा उसका व्याख, निक्षेप निधि व्यय ।

र--राज्य पर मारत ऋण तथा उसका व्याव, निक्षप निध व्यय ४---जच्च न्यायालय के व्यायाचील के बेतन तथा सन्ते ।

५—वह पन राशि को किसी स्वायालय या विवासन स्रपिकरण के निर्णय स्रा डिकी के सन्तर्गत देना है।

६--प्रत्य कोई व्यय जो सविधान या राज्य सविधान यण्डल द्वारा इस निधि मै समावैशित व्यय चौचित किया गया है। इसके प्रतिरिक्त सविधान द्वारा निम्न

लिखित अपय राज्य सचित निधि में से किये जायेंगे । १--- प्रमुच्छेद २२६ (१) के प्रमुसार उच्च न्यायालय के प्रकासकीय व्यय जिसमें

र-अतु-पद १९६ (२) क अनुसार जन्म न्यायालय के अगासकाथ ज्यम ।असम जन्म न्यायालय के अधिकारियो और कमंचारियो के वेतन, यसे एव सेवा-निवृति भी सम्मिलित हैं।

२--- अनुच्छेद ३२२ के अनुसार राज्य लोन सेना आयोग द्वारा किये गये व्यय सर्वधित पन राजि जिससे आयोग के कर्षचारियों के वेतन, मन्ते भौर सेवा-वृति भी शामिल है।

ना बात्मल ह । यद्यपि राज्य की सचित निधि में उल्लिखित व्यय पर राज्य विधान मण्डल भे मतदान नहीं किया जा सकता हैं। परन्तु राज्य विधान समा में सचित निधि भे उल्लिबित व्यय के अनुमानो पर बहुत की जासकती है। अप्तय व्यय को विधार समागे अनुदान को मौंगो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विधार सभा को अनुदान की मौंगो पर विभार विभन्न गरने और इनको स्वीहत या प्रस्तीहत या कम करने का अधिकार है। तथापि विधान सभा को नये अनुदान के प्रस्ताव कराने का या अनुदान की मौंगो से वृद्धि करने का अधिकार नहीं।

प्रापेक वित्तीय वर्षे वे घारम्य मे राज्य विधान समाय वित्त मधी यापिर प्राय ब्यवन प्रस्तुत करता है। बुद्ध दिनो तक इस पर बहुत नी जाती है। विधान समावे तदस्यों नो इस समय सरहार तो नीतियों वे परीत्रण वर्षत या घनसर मी प्राप्त होता है।

तरमध्यात् घानुवानो की मान पर मतदान किया जाता है। प्रत्येव विमाग के लिए सबिपत मभी द्वारा पृषक धनुवान की मौन की जाती है। यह रनामधि ह है कि यह एक ऐसा धनसर है जब विधान समा ने सबस्य विमाग की नीतिमी तथा कार्यों का सुरुम परीक्षण वरते हैं। कोई मो सदस्य धनुवान की मौग को कम या झस्बीहत करने का प्रताब प्रसुत कर सक्वी है।

मनुदान की मागो पर मतदान होने वे पक्ष्यात् राज्य विधान समा द्वारा स्वीवृत्त मागो तथा सचित निर्मि ने निहित क्या के भाषार पर वार्षिय विनियोग विषयेष कार्या जाता है। इस विययन को विधान समा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विध्येष कार्यो आधुदान वे उद्देश्य में परिषर्तन करने का बोद्दे स्वीवृत्त में विद्या जाता है। इस विध्येष में विश्वा कार्यो है। इस विध्येष में विश्वा कार्यो है। विनियोग विध्येष को मोनून निर्माण प्रविद्या के विधिन्न वर्षों संसकता हुँ। विनियोग विध्येष को मोनून निर्माण प्रविद्या के विधिन्न वर्षों संसकता पूर्वक निकलने पर विधान समा द्वारा परित्य भागा जायेगा और यदि उक्त राज्य में विधान परित्य (उक्क त्वरान) है तो विधान समा के सप्याद द्वारा उक्त विध्येष में विद्या विध्येष प्रमाणित करके विधान परित्य के विधान समा के सप्याद द्वारा उक्त विध्येष में विद्या विध्येष प्रमाणित करके विधान परित्य के विधान में विद्या विध्येष माणित

मन्त में विभान सभा द्वारा वित्त विधेयन पारित किया जाता है। यित्त विधेयक पारित करने का उद्देश्य राज्य की आय के उन साधनो को निर्धारित वरना है, जिनने द्वारा आनामी वर्ष के अयन ने लिए प्रावधान किया जा सने।

#### राज्य-ऱ्यायपालिका

भारतीय सच के प्रत्येक राज्य में सविचान के घन्नार्वत एक उच्च न्यायालय भी व्यवस्था की पहें हैं। सविचान के घन्नार्वत सबद को यह सी ध्राधिकार है कि ये या दों से ध्राधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च ज्यायालय की स्थापना करें। राज्य की व्यायिक प्रकाशी में उच्च ज्यायालय का स्थान प्रिताद पर है।

वण्य व्यापात्य का समझन-अयोक कृष्य ग्यापात्म में एक पुत्य ग्यापा-त्या कुछ प्रत्य ग्यापात्रीच होते हैं, तिवनने क्या राष्ट्रपति एक भारेका हारा निर्वाणित रुत्या है। मुक्त ग्यापात्रीच में निर्वुकि राष्ट्रपति मारत के सर्वेष्ट्य ग्यापात्म ने मुख्य ग्यापात्रिका ने निर्वुक्त राष्ट्रपति पात्म के स्पानतिवृत्तार करता है। स्मय ग्यापात्रीको में निर्वृतिक राष्ट्रपति राज्य उष्य ग्यापात्रक में सुक्त ग्यापात्रीक से एयमन्तिवृत्तर करता है।

सविधान संबोधन धार्थिनवम १९१६ द्वारा राज्युपति को घरमायों, प्रतिरिक्त सर्वासहरू न्यायप्रीधों को नियुक्ति करने ना धार्थिकार दिया गया है। धार्मित्तिक न्यायप्रीधों की नियुक्ति राज्युपति द्वारा यो वर्ष से धार्थिक समय के नियु नहीं वी जा तकती है। निसी स्वाधी न्यायाधीय वी धानुरस्थित में, या जब बहु न्यायाधीय, नुक्त न्यायाधीय के पत पर कार्य कर रहा है, राज्युपति उक्ते स्थान पर कार्यवाहुक न्यायाधीय नियुक्ति कर सकता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ—१—मारत का उसे नागरिक होना चाहिये ।

२—भारत में किसी न्यायायिक यद वर कम से कम दस वर्ष तक रहा हो या उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से नम दस वर्ष तक ववासत वरने का भन्नव हो।

कार्यकाल-पूत्रता सविचान से यह प्रावचान था कि एक न्यायाधीश प्रपते पर पर (० वर्ष पी आधु तक रहेता। परन्तु शिवधान के परहतु संस्थापन शिवधान कार्यापन श्वधिनियम १८६३) द्वारा उस आधु से वृद्धि नर दो नार्यो एव यह आधु ५२ वर्ष कर दो संबी है। यदि समय दो तिहाई बहुमत से निसी न्यायाधीश के विरद्ध तक्के दुरानार या अक्षमता के कारण अस्तान करती है तो राष्ट्रपति उनन न्यायाघोश को पदच्युत करेगा । नोई भी न्यायाघीश राष्ट्रपति को ग्रपना त्याग-पन प्रस्तुन कर पद-स्थाग सकता है ।

न्यायाधीमों के बेतन—उन्न न्यायालय के मुख्य न्यायाधीम की चार हजार 
रमंगे तथा ग्रन्य न्यायाधीमों को तीन हजार पांच सी रुपये प्रतिमाह वेतन दिया 
आता है । ससद विधि द्वारा न्यायाधीमों के मत्ते छुट्टियाँ तथा सेवान्तृत्ति सबधी 
नियम निर्मारित नरती है। त्यायाधीमों के कार्यकल में उनके वेतन, मसे भादि 
क कटौनी नहीं को जा सकती है। इतके वेतन मत्तों का व्यय राज्य-सचित 
निधि से से होने के कारण न्यायाधीम स्वतनना पूर्वक अपने नार्य कर सकते हैं, 
बयोकि विधान समा में सचित निधि में उत्तिनित विधयो पर मतदान नहीं हो 
सकता है। प्रतप्त ससद तथा राज्य विधान समा न्यायाधीमों के वेतन में कमी 
कही नर सकती है। तथापि, विसीय सकट काल की स्थिति में न्यायाधीमों के 
वेतन में कटौनी की जा सकती है।

न्यायाचीशी की स्वतंत्रता-उत्तम न्यायिक प्रशासन के लिए यह अति भाव-

, श्यक है कि न्यायाधीश श्रपने नायों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें।

सर्वियान में उच्च न्यायालयों के न्यायाचीशों की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान क्ये गये हैं। वे निभ्नतिखित हैं।

सर्वप्रयम, नियुनित नी दृष्टि से व्यायाधीशो की नियुनित सविधान द्वारा निर्मारित योग्यतानुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायान्त्य के मुख्य न्यायाधीय नी नियुनित राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायान्तय के मुख्य न्यायाधि-पति के परामर्ग पर करता है, तथा अन्य न्यायाधीशो की नियुनित उच्च न्यायान्त्य ने मुदर न्यायाधील के परामर्ग द्वारा नरता है।

हितीय, नार्यकाल की दृष्टि से न्यायाघीषों को सिवधान के अनुसार ६२ वर्ष भी बाधु तक परने पर पर रहने ना सिवकार है। सिवधान में स्पष्ट रूप से दो कारणों का उत्केख है, जिनने आधार पर ही निधी ग्यायाधीय को परच्युत किया जा सनता है। इन कारणों के आधार पर राज्युति स्पन्ने पारेषों हारा क्षित्री न्यायाधीय को परच्युत कर सकता है किन्तु राष्ट्रपति का प्रारेण सत्तर होरा दो सिहाई बहुमत से पारित प्रस्ता वपर आधारित होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि म तो राज्युति नो में न ही ससद को किसी न्यायाधीश नो परच्युत करने ना स्वाधित हो थे।

नृतीय, न्यायापीको के वेतन सविषान द्वारा निर्पारित है, भीर इनका ध्याप राज्य-सवित निधि पर भारित है। इसके प्रतिरिक्त, न्यायापीको के मसे तथा दृष्ट्रियों भीर सेता-चृत्ति सवयों प्रशिकार ससदीय कानून द्वारा निर्पारित निये जाते हैं, भीर उनके कार्यकास में उनकी हानि की दृष्टि से इनमें कोई परिकर्तन नहीं दिया जा सकता है।

चतुर्यं, राज्य उज्य-न्यामालय के प्रशासकीय व्यय भी राज्य सचित-निधि पर भारित हैं।

उपर्यंक्त तथ्यों के भाषार पर यह कहा जा सकता है कि वे भपने वार्य क्षेत्र मे पर्णंत स्वनत्र हैं।

जन्म न्यायालयो के कार्य तथा क्षेत्राधिकार

साधारणन एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधत राज्य तक सीमित है। परन्तु सविधान के सातवें संशोधन से (संशोधन अधिनियम १६५६) दो या दो स ग्राचिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है भीर इस स्थायालय के क्षेत्राधिकार को सर्वधित संघीय भ भाग मे लागु किया जा सकता है। १६५६ के सशोधन व्यथिनियम के बन्तगैत कलकता उच्च न्यामालय के क्षेत्राधिकार की अण्डमान-निवोबार द्वीपों के सबध में, केरल उच्च न्यामालय के क्षेत्राधिकार को लक्दीब, मिनीक्त्राय तथा समीन दीवी दीवी के सबध में तथा पजाब उच्च स्थायालय के क्षेत्राधिकार की दिल्ली के सबक्ष में लागू किया गया। १६६० में दिल्ली के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित निया गया। उच्च न्यायालयो के दो प्रकार के क्षेत्राधिकार है।

१--- प्रारम्भिक तथा २--- वर्षालीय ।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-(क) उच्च ग्यायालयो को केवल निम्नलिखित विषयी के सबस में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

१--जल सेना विमाग (एडमिरलटी)

२-वसीयतः

३--विवाह सवधी,

४--व्यापालय अपनान तथा.

५---कम्पनी-कातन ।

था •

(म) परन्तु कलकत्ता, बम्बई तथा महास के उच्च न्यायालयों को ग्रपने क्षेत्रों में दीवानी तथा फीजदारी सामलों में बारम्मिक क्षेत्राधिकार बाप्त हैं। सर्विधान के अनुच्छेद २२५ के अनुसार उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वैसाही होगा, जैसा कि १९५० में सविधान लागू होने के पूर्व था। सविधान लागू होने के पूर्व कतरता, वस्वई तथा महास उच्च न्यायालयो को प्रारम्भिक तथा प्रपीलीय

क्षेत्राधिकार, दोनो प्राप्त थे । प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार इन न्यायालयो को निम्नलिखित मामलो में प्राप्त (१) ऐसे दीवानी मुकदमे इनमे प्रारम्भ किये जा सकते थे जिनका मूल्य दो.
 हजार रुपये से प्रमिक होता था।

(२) ऐसे फीजदारी मुकदमें जो प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटो द्वारा मेजे जाते थे, इनके द्वारा मुने जा सकते थे। मारतीय सविधान के अन्तर्गत इस स्थिति में कोई परि-वर्तन नहीं किया गया है। अलएव इन तीन उच्च न्यायालयों को उपर्युक्त मामली, में प्रारम्भिक अधिकार प्राप्त है।

 (ग) मारतीय सविवान के अनुच्छेद २२५ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को राजस्व तथा उसकी बसूती से सबयित प्रवारणों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में

सुनने का प्रधिकार मी दिया गया है।

(प) सिंदधान के अनुरुदेद २२६ के झन्तर्गत उच्च न्यायालयों के मूल प्रिय-कारों के सरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के झादेश या खेख लागू करने के झिषकार प्राप्त हैं। विभिन्न लेख इस प्रकार के हैं ——(१) वस्ती प्रत्यक्षीकरण, (२) परमा-देश, (३) प्रतियेष, (४) उद्योगण, (४) झिषकार-पुच्छा।

उच्च न्यायालय द्वारा ये लेल अपने क्षेत्राधिकार से सवधित राज्य में किसी भी जाबिन, सता या सरकार ने विषद्ध जारी किये जा सकते हैं।

ध्यरेशिय क्षेत्राधिकार—ध्योलीय क्षेत्राधिकार मे उच्च व्यायालय को दीवानी, क्षोत्रदारी तथा मालगुजारी मुकदमो पर निस्न श्रेणी के व्यायालयो के निर्णय के विरुद्ध धरील मे स्वीकार करने का प्रधिकार है। इसके प्रतिरिक्त प्राय-कर, विक्री-कर, आदि प्रकरणो के लिए स्थापित व्यायाधिकरणो के निर्णयो के विरुद्ध उच्च न्यायालयों को प्रपील की जा सकती है।

सविधान के अन्तर्भंत उच्च न्यामालयों को अन्य भी कुछ कार्य सीपे गये हैं जो निम्मलिखित हैं।

मनुष्टेंद्र २२७ के मनुसार अधीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रियक्तर के सन्दर्भ में उच्च व्यायाक्त्य को अपने अधीनस्थ न्यायाक्त्यो सथा न्यायाध्वरणो का (सैनिक-न्यायाध्वरणो को छोडकर) अधीक्षण (निरीक्षण), करने का प्रियक्तर है। इस अधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायाज्य निन्न कार्यं कर सकता है।

१--उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय के कार्यों का विवरण उससे भांग सकता है।

२---उच्च न्यायालय ग्रपने अधीन न्यायालय की कार्य प्रणाली की निर्धारित करने के लिए नियम बना सकता है।

२--- उच्च न्यायालय प्रपने प्रघीन न्यायालयों के श्रीमलेखों तथा कागजाती के रखने के लिए प्रादेश दे सकता है। ४—उच्च न्यायालय विमो प्रवरण को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को विचार या निर्णय के लिए मेज सकता है। ४—उच्च न्यायालय अपने मुमीन न्यायालय म केरिक, जिड़िक तथा भ्राय

स्वित्रारियो तथा वनील भीर भिन्नायनो ने जुल्ह निश्चित नर भनता है। भनकोद २२६ ने भनसार यदि तच्च न्यायालय नो निश्चय हो जाता है हि

हिसी निम्न प्रेमी के न्यायालय के समझ ऐसा प्रकरण है जिसमें स्विधान की क्याक्या के लिए कोई कानुनी प्रक निहित है हो यह स्वय उस प्रकरण पर विधार करके निर्णय के सकता है, या उक्त कानुनी प्रकर पर निर्णय केर धरने निर्णय की एक प्रति ध्योनस्य न्यायालय को येनेवा। ऐसी स्थिति में धयीनस्य न्यायालय प्रपता निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय के धनुसार ही देशा।

मारत के सर्वोड्य थायालय के समान प्रत्येक राज्य का उच्च ज्यायालय मी एक प्रत्येक ल्यायालय है। एक प्रत्यिक ज्यायालय के नाते उच्च ल्यायालय के प्रत्येक्त प्रत्य ज्यायालयों के समन्त्र तात्र्य के रूप म प्रतुष्ठ क्यिया सकते हैं। किसी ल्यायालय से प्रसुष्ठ किये जाने पर उच्च ब्यायालय के प्रतिसंस्त्रों की बैया-निकता पर सर्वेह नहीं व्यक्त विद्या जा सक्ता है।

उल्क व्यापालय के श्रीवकारियों तथा क्ष्मैवारियों की निमृष्ठि मुख्य न्याया-श्रीश या उसके इत्ता श्रीवृत्त कोई सन्य न्यायावीय करता है। उक्त न्यायावय के कर्मेचारियों की लेवा संती का निर्धारण मुख्य न्यायाधीय ही करता है। यरण्डु इनके बेतन मस्ते, घटनाथ तथा वेदा वृत्ति के सदय में नियमी के लिए राज्यपाल की ह्योड़िया पालवस्क है।

सिवधान के मतुष्टिद २३५ के प्रमुक्तार जिला स्वायालयों और उनने प्रधी-मस्य स्वायालयों के निवाजण का प्रधिकार राज्य के उच्च न्यायालय में निहित हैं।

पतुण्हेद २.६ के प्रमुखार न्यायिक वर्षों को दो वेचियों में रक्षा गया है, जो दिस्मलिवित हैं ()-ज्या वेचों में जो वह रहे वहे हैं, वे हह प्रमार है— दिला न्यायाधीम, सकन्यायाधीम, दीवारी व्यायालक के न्यायाधीम, सहायक किया त्यायाधीम, सहायक किया तथा तथा कि न्यायाधीम किया है कि प्रमुख प्रेसीडेन्सी न्यायाधीम (मिनस्ट्रे) । इस वेची के न्यायाधीकों में निवृत्तित राज्याया हारा स्वायाधी किया कि निवृत्तित के क्यायाधीम के उत्ति हों पर की की वेचे हिंदी हम केची में उत्तित्व किया के उत्तर्भ वार्षों के इस केची में उत्तित्वित कियी वद पर निवृत्तित के लिए यह मानस्वत्व है कि उसकी कम से कम सात वर्ष वकानत का मनुष्य हो वाप उसका नाम निवृत्तित के लिए उच्च न्यायालय हो ।

(n) निम्न खेली में जो पद रखे गये है, वे समस्त न्याधिक पद जो जिला न्यायाचीत, सत्र न्यायाचीत, दीवानी न्यायालय के न्यायाचीत, सहायक न्याया- धीन्न, तथा सत्र न्यायाधीन, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीत्र एव मुख्य प्रेमीडेन्सी न्यायाधीत्र के पदो से निम्न स्तर के हैं। इस दूसरी श्रेणी म न्यायिक पदो पर नियुक्ति राज्यपाल राज्य सोक सेवा श्रायोग तथा सबधित राज्य के उच्च न्याया-सय के परामर्थ पर वरता है।

उच्च न्यायालय के स्रधीनस्य न्यायालय

राज्य में उच्च न्यायालय के ब्रधीन तीन प्रकार के न्यायालय हैं। वे इस प्रकार हैं  $\longrightarrow$ 

१—कोजदारी न्यायालय २-दोवानी न्यायालय, तथा २-मालगुजारी न्याया-सय ।

१—कीजदारी व्यायालय—प्रत्येक जिले में उच्च श्रेणी का कीजदारी व्याया-सम् सम् (त्रेग्रस) व्यायालय हैं। इस व्यायालय के व्यायालीय की समन्याया-चीग कहते हैं। समन्यायाधीण की सहायता के लिए सहायक समन्यायाधीण होते हैं। समन्यायाधीण के प्रधीन तीन प्रकार के व्यायाधीय होते हैं। प्रयम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट तथा हतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट ।

प्रमम प्रेणी मजिल्हुंट दो वर्ष तक का कारावास और एक हजार रुपये का दण्ड दे सकता है। द्वितीय श्रेणी का अजिल्हुंट छ, माह का कारावास और तीन सी रुपये का दण्ड दे सकता है, और तृतीय श्रेणी का भजिल्हुंट एक माह का कारावास तथा प्रचास रुपये का दण्ड दे सकता है। सन-व्यायाधीय प्रथम श्रेणी के मजिल्हुंट के निर्णयो के विकद्ध प्रपीत सुनता है। सन-व्यायाधीय को मृत्यु दण्ड स्विकार है, किन्यु उच्च न्यायासय द्वारा मृत्यु दण्ड का प्रनुसोदन होना माव- प्रमा है।

२—दीवानी ग्यायालय—प्रत्येक जिले के उच्च श्रेणी ना दीवानी ग्यायालय, जिला ग्यायाणिय का ग्यायालय (डिल्ड्डिट कोर्ड) होता है। वस्तुस्थित यह है कि एक ही आफित प्रत (डिक्डिट कोर्ड) मायायाणिय तथा जिला ग्यायायोगिय कहालात है। किये रहता है। कौजवारी प्रकरणो को मुनता है तथ यह विला-ग्यायायोगिय कहालात है। एउन्हु जब दीवानी प्रकरणो को सुनता है तथ यह विला-ग्यायायोगिय कहा जाता है। जिला-ग्यायायोगिय के न्यायालय को दीवानी समस्तरी से प्रारम्भिक तथा कर्या कर्मरितेष्ठ्य दोनी प्रवार के दीवाधिकार प्राप्त हैं। और विलेग कानूनो के सवय से, जैसे-चत्तप्रिकार कानून, प्रमिमावक और प्रतिपाल्य कानूनो, विवाह-विच्छेद कानून तथा प्रान्तीय दिवालिया कानून के सत्त्यों में हसे विस्तृत चिलाय ग्राप्त है। जिला न्यायालय को दीवानी मामतों से क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रधीनस्थ ग्यायालयों के निरीक्षण करने का व्यवकार है।

जिला न्यापाधीश के न्यायालय के नीचे सिविल जब, मुसिफ, लघवाद न्याया-लय, तथा पचायती घदानतें होती हैं।

३-मालगुजारी न्यायालय-रेवन्यु बोर्ड राज्य मे सबसे उच्च मालगुमारी न्यायालय होता है। इसके द्वारा कमिश्नरी के निष्यो के विरुद्ध ग्रंपील मुती जाती है। कमिश्नर के ग्रमीन, जिलामीश चया सहायक जिलामीश के स्यायालय होते हैं, भीर इनके अधीन तहसीलदार तथा नामक तहसीलदार होते हैं। इस न्यापालय

द्वारा भृति या सवान सबधी प्रकरणो पर निर्णय दिया जाता है।

### संघ तथा राज्य-संबध

भारतीय सविधान के लालू होने के पूर्व कारत सरवार श्राधिनियम १९३५ के झन्तर्गत सारत मे त्रिटिश राज्य के शीरान, तीन प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ भी। प्रथम—ग्यारह बिटिश भारतीय प्रान्त थे। इनके नाम इस प्रवार हैं—महास, स्ववंद, बताल, ससम, उत्तरप्रदेश, पजाय, उत्तर-पिक्सी सीमानर्ती प्रान्त, बिहार, मस्प्रान्त, तिन्य तथा उड़ीसा। प्रस्थक विटिश भारतीय प्रान्त वा प्रशासकीय प्रमुत प्रराण्यात होता था।

दितीय—पुछ मारतीय नरेशो की रियासते, जिन्होंने १६३५ ने प्रियिनियम के भन्तगंत मारतीय सच मे सम्मिलित होना स्थीपुत वर सिया था।

तृतीय—६ मुख्य भायुक्त भाग्त थे । उनके नाम इस प्रवार हैं—'ब्रिटिश यसूचि-स्तान, दिल्ली, भ्रजमेर-मेरवाडा, हुगं, भ्रष्टभान निवोबार द्वीप भौर पस्त∹ पिपलोटा ।

भारतीय सविधान के अनुस्केद ३ के अनुसार भारत एक सम है । जब १६६० में सविधान लागू विधा गया तब भूततः चार प्रकार की राजनीतिक इकाइयो की स्थापना की गई। ये निम्नतितित हैं।

१—माग 'क' वे राज्य सतम, झांझ, विहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मझात, उद्देशा, पजाब, उत्तरप्रदेश, परिचम तकाल । बाहत में में राज्य पूर्व में किटिशा मारतीय प्रान्त में । मारतीय प्रान्त में । मारतीय प्रान्त में । मारतीय प्रान्त में । प्रान्त मंग्रास्तीय प्रमृत्य राज्य मां प्रमासनीय प्रमृत्य राज्य मां प्रमासनीय प्रमृत्य राज्य मां प्रमासनीय प्रमृत्य राज्यभाव होता था ।

२—मार्ग 'त' के राज्यं—हैदराबाद, जम्मू कश्यीर, शष्य-मारत, मैसूर, पेस्सू, राजस्थान, सीराप्ट्र, नाबणकोर कोचीन थे। सविधान सामू होने से पूर्व ये राज्य देवी रियासतो वे रूप मे थे। भारतीय सविधान ने सन्तर्यत साम 'त' के प्रत्येक राज्य वा प्रशासकीय प्रमुख राजप्रमुख वहुवाता था।

३—माग 'ग' वे राज्य--'ग्रजमेर, भोपाल, वुगँ, हिमाचल-प्रदेश, बच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विन्ध्य प्रदेश ।

 चपराज्यपाल या मुस्य-कार्युक्त या विसी राज्य सरवार के माध्यम से किया काला था।

बद मार्टीय सविवास का निर्माण हो रहा था तब सनिधान समा के मध्यक्ष द्वारा एक समिति निवृत्ति की पई । उस समिति की 'दर-समिति' की सहा दी गई थी। इस समिति को यह कार्य सींवा क्या था कि सारत में राज्यों की भाषा के माभार पर पुनरेंठन के प्रका की जीव करे ! १६४= में 'दर-समिति' ने भाषा के साभार पर राज्य के पुनर्गञ्ज के विरुद्ध अवना प्रतिवेदन दिया। संपरकान् कार्रेस में १६४= में अपने जयपुर अधिदेशन में एक समिति की नियुक्ति की, जिसमे सीन सदस्य थ, प० जवाहरलाल नेहरू, सरबार बल्लमनाई पटेल, तथा डॉ॰ पट्टामि सीनारामैया । अपने प्रतिवेदन में १६४९ में इस समिति ने कहा 'सिमिति राज्यों ने पुनर्गठन ने लिए आया ने बाबार नो स्वीवृत नरनी है।' किन्तु राज्यों का पुनगंठन उस समय उपदुत्र नहीं या, तदापि चारस्परिक समझौती के आधार पर निर्धापित क्षेत्रों में लंगे पालको का निर्धाण किया जाता समय पा। इस धाधार पर दक्षिण भारत के काक्ष्य क्षेत्र के नये राज्य का अयापना करना संक्रम था। परन्तु कृद्ध कारणवर, जैसे-"राज्यानी" के प्रथन पर कोई निश्चित समसीणा गहीं हो सबा और बाध्न के निमांच को स्थापन कर दिया गया। परन्तु जनमा के भान्दोलन तथा भी रामूल के उपवास करने के प्रसत्यहण मृत्यू हो जाने पर भाध अदेश की स्थापना १६४३ में हुई।

भदर का स्थापना १८८२ जडूद । १९४२ में क्षात्रप्रदेश की स्थापना होने से कापा के घाषार पर राज्यों के

कुमर्राज के प्रान्दोतन को प्राप्ति यनि मिती।

वित्तन २२, ११४६, को प्रयान मंत्री यह नेहरू में सहद से पीपमा की कि
सामी हे नुस्तर्क के प्रत्य को निर्माणना पूर्वक जोकी के लिए एक उन्क स्तरीय
सामीम निवुक्त किया जानेगा निरम्पतान दुवक इस प्राप्तीय कि स्वया थे। भी तीरव
विवाद माना। डांक हृदयनाय दुवक इस प्राप्तीय के स्वया थे। भी तीरव
वेदा पाना हात्रा के एमक पीचकर एस प्राप्तीय के प्रयाद थे। भी तीरव
वेदा पाना पुर्वक्ति माना में में भारत सरकार की ध्यमा प्रतिवेदन के प्राप्त से प्रत्या
दे! पाना पुर्वक्ति माना में माना सरकार की ध्यमा प्रतिवेदन के प्राप्त से प्रत्या
देश भी प्रस्तुत निरम। भारति के वन स्ति। धारति वे एक माना, पर पान्य
वेदा पत्त्रीयना पर स्त्रिक एक ते वन स्ति। धारति वे एक माना, पर पान्य
वेदा पत्त्रीयना पर स्त्रिक एक ते वन स्ति। धारति वे एक माना, पर पान्य
सह भी था कि माना कर स्त्रीत हमतीहन किया। धारति वर एक पर प्रतृत्यो सुनाय
सह भी था कि माना सभ की पत्त्रतीविक हमाना दिना कि सारक तम की केवल दो
दर्शन सीहित, की सिन्तरिविक है.—

१—विमिन्न राज्य, सम नी इवाइयो के रूप से।

२—वे भू-माग जो केन्द्र द्वारा मासित होगे।

राज्य पुनगंठन श्रायोग के विभिन्न सुकावो पर राज्य पुनगंठन श्रीयनियम १९५६ तथा सवियान संवोधन अधिनियम (सातवा संयोधन) ससद द्वारा पारित जिया गया।

राज्य पुनर्पटन ग्राधिनियम १६४६ तथा सविधान संबोधन स्थितिमम १६४६ (सातवें सकोधन) के झन्तर्गत मारत सथ में राज्यों ना पुनर्गटन करने ने फलस्व-रूप १४ राज्यों तथा ६ संघीय सू-मागों की स्थायना की गई। य १४ राज्य निम्नालिखित थे .—

१—धान्ध्रप्रदेश, २-ध्रस्त, ३-विहार, ४-वन्धई, ४-वेरस, ६-मध्यप्रदेश, ७-महास, द-मैसूर, ६-उडीसा, १०-पनास, ११-राजस्थान, १२-उत्तरप्रदेश, ११-पश्चिम बसाल, तथा १४- जम्मू-कश्मीर ।

इनके झतिरिक्त ६ सधीय भू-माग इस प्रकार थे।

१ — दिल्ली, २-हिमाचल प्रदेश, ३-मण्पिट्र, ४-विपुरा, ५-प्रण्डमान-निकोबार द्वीप तथा ६-लक्क्टीप-मिनववाय तथा धमीनदीवी द्वीप ।

१ मई १६६० को मारतीय राजनीतिक नक्से में पुन. परिवर्तन हुमा जब बम्बई की दो राज्यो—महाराष्ट्र और पुनरात में विमाणित कर दिवा गया। साराम्यात ए भे पुने तक राग्ये गये दो क्षेत्री—नावदा नगर-वृत्तिकी तया नोबा-क्यान-वृत्तिकी तया नोबा-क्यान-वृत्तिकी तया नोबा-क्यान-वृत्तिकी तया नेबा-क्यान-वृत्तिकी तया नेबा-क्यान-वृत्तिकी त्या नेबा-क्यान-वृत्तिकी त्या नेबा-क्यान-वृत्तिकी त्या नेबा-वृत्तिकी क्यान-वृत्तिकी त्या है। १६६२ म एक नये राज्य नागालिक का निमाण क्यान क्यान दिवाण क्यानित क्यान नेबा-वृत्तिकी निमाणित करेत दो राज्य पजाव तथा हरियाणा स्थापित किये नचे और इनिके साथ ही बुद्ध समय के लिए चर्डागढ को केन्द्र-प्रवापित केम में प्रवाप नेवित्तक नोवित्तक निमाणित क्यान क्यानित क्यान क्यान दिवाणा स्थापित क्यान का दिवाणा प्रवाप नेवित्तक ना क्या दिवाणा प्रवाप नेवित्तक नेवित्तक ना क्यान वित्तिक नेवित्तक निव्तिक निव्यत्तक निव्यत्तिक निव्यत्तिक निव्यत्तिक निव्यत्तिक निव्यतिक निव्यतिक निव्यत्तिक निव्यत्तिक

निहा, इपि, सहकारिता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, यातायात, गृह उद्योप, न्याय तमा राजस्व । ग्राय विषय, जैसे—सिवाई, विजनी, बाद नियन्त्रण, बढे च्योग, जल-परिवाहन, बढे मार्ग ग्रादि ग्रासम राज्य के क्षेत्र ग्राधिकार मे छोड विसे गर्म। जनवरी २५, १६७१ में हिमाचल प्रदेश को सब के एक राज्य के रूप में मान्यता दो गई। दिसम्बर १६७१ में २७वें सविवान सबोधन द्वारा तीन नये राज्यों की स्वापना की गई है। वे हैं—मेघालय, मणिपुर तथा निपुरा।

इनके प्रतिरिक्त, २७वें समोपन धांपनियम १६७१ के प्रत्यांत दो सपीय भू माग भी स्थानित किये गये। ये हैं—भित्रोराम तथा घरणायल प्रदेश। भन्न मारत सुप में निम्मलिखित राज्य हैं:—

१-मारम्प्रवेस, २-मामम, ३-विहार, ४-महाराष्ट्र, ४-मुजराह, ६-वेस्त, ७-माम्य प्रवेस, ८-तमिलनाह, १-मीमूर, १०-वडीमा, ११-पत्राव, ११-वत्तर प्रवेस, १३-हिमाचल प्रवेश, १४-पश्चिम वशाल, १४-राजस्थान, १६-यनमू-

कामीर, १७ हरियाना, १६-मेपालस, १६-माणिपुर, तथा २०-निपुरा । इसी प्रकार समीय मून्यायो ये वृद्धि हुई है; और वे निम्नतिवत हैं :— १-विस्ती, २-मध्यमान-विकोबार द्वीप, १-वश्राव, मिनीक्बाय, तथा समीनदीबी द्वीप, ४-वश्रावर नगर हवेती, २-योबा-क्यन्-वृद्धु, ९-याच्चेपी, ७-विजोक्ता, तथा एन-विजोसार, तथा एन-विज्ञास प्रविद्या ।

सधीय भू-भागो का प्रशासन सधीय सरकार द्वारा क्या जाता है। किन्तु सम के राज्यों को सविधान द्वारा प्रयक्त क्षेत्राधिकार प्रवत्त किये गये हैं।

मारतीय सविधान के घनतांत संघीय व्यवस्था को मान्यता प्रवत्त की गई है। इस सन्दर्भ में, सविधान द्वारा दो प्रकारी की सरकारी-संघीय धीर राज्य सरकारों की स्थापना की गई है। धोनो प्रकार नी सरकारों के पूषक प्रस्तिरत संघा पूषक क्षेत्राधिकार हैं। परंखु सविधान के प्रत्यवैत संघ तथा राज्यों के सबयों को तीन मारती में विभाजित किया जा सनता है।

१—सम सथा राज्यों के व्यवस्थापन सम्बन्ध, २—सम सथा राज्यों के प्रशासकीय सम्बन्ध, और 3—सम सथा राज्य के विक्तीय सम्बन्ध ।

#### १-सघ तथा राज्यो के व्यवस्थापन सम्बन्ध

सप तथा राज्यो के व्यवस्थानन सम्बन्ध मा घष्ययन सविधान में उत्तिविधि तीन विनिन्न व्यवस्थानन सम्बन्धी मूचियो के दूरियोध से करता प्रावश्यक है। सपवाद के मून सिद्धान्त (विकि विभावन के सिद्धान्त) को, मारतीय सविधान में तीन व्यवस्थान सम्बन्धी सूचियों के साधार पर टीस रूप दिया गया है पर्माद इन सीन मुचियों हारा सच और राज्य सरकारों के मच्च शवित विभावन विचा बया है जिससे इन सरकारों के क्षेत्रामिवार स्पष्ट रूप से निर्मातिक स्टि येथे हैं। ये तीन मूचियों निमान निस्तित हैं:—

- (क) सप सूची—सप सूची मे १७ विषय हैं, जिन पर कैवल सप-साद कानून यना सनती है। इनमे मुख्य विषय हैं—प्रतिरक्षा, चैदेषिव सवध, सिषयी, युढ, शान्ति, सशस्य सेना, प्रणु धनित, रेल, समुद्रीपप, बाधु मार्ग, ठान-सार धीर देली-कोन, सपीय लोन च्छण, मुद्रा धीर उत्तक्षा निर्माण विदेश से ख्यापार, प्रगर्दरिय-व्यापार घोर वाणिज्य, मारतीय रिजर्व वैन, वित्तीय निषम, बीमा, स्वान प्रौर लिंकिज दर्श्य नित्र क्या निव्यत्व, सुधीम लोन सेवाएँ, निर्माण, सुधीम, सुक्त ने उद्योग, नमक्ष उद्योग, हिल्ली, वनारम धौर खलीगढ़ विक्वविद्यालय, सुध प्रौर राज्यो या लेखा-परीक्षण धीर लेखान , राष्ट्रीय महत्व ने वैद्यानिक और तक्षनीकी सस्यान, ऐति-हासिक स्मारण, मस्त्य, अफीम, समाचार पुत्र के विक्रव्यनर झासि।
- (ज) राज्य गूची—राज्य सूची मे ६६ विषय हैं। राज्य सूची मे उत्लिखित विषयों पर साधारणत्या सचयाद के सिद्धान्त के प्रमुक्त राज्य विधान सण्डली को मानून निर्माण करने हा अधिकार प्राप्त है। वितय विधेष परिस्थितयों मे जिनका रुपेल स्वार्य रूपे से सिद्धान में विजय गया है, सव सत्तद इन विषयों पर कानून बना सकती है। परन्तु सण्याद के सिद्धान ने आधार पर साधारणत्या इन विषयों पर राज्य समार एक साधारणत्या इन विषयों पर राज्य विधान मण्डलों का ही क्षेत्राधिकार है। राज्य सूची में छुछ मुख्य विषय इस प्रमार हि—पाज्य लोक प्रमुक्त माण और तीत, सार्वजनिक कानून भीर व्यवस्था, प्रतिस और त्याय व्यवस्था, जत, शिक्षा, स्थानीय स्ववासन, सार्वजनिक स्वास्थ विविधाल, पणु इपि, प्रमुणासन, त्विचाई, जन उद्योग और वाण्यि, प्राप्त सुमार मनोरजन कर, छित्तमूह, राज्य सोक सेवाएँ, राज्य बोक सेवा भागोग, भूमिकर, इपि माम कर, सिवास समावार पत्रों के श्रन्य वस्तुयों पर विषयकर, वाहन कर, पष्ट मों मारे पर कर, व्यवसाय तथा जीविका पर कर, विद्यत कर,
- (प) समयती मुद्री—समयती सूची में ४७ विषय उस्ति खित हैं। इन विषयों पर समयती मुद्री—समयती सूची में ४७ विषय वस्ति खित हैं। इन विषयों पर समयती मुद्री में समयती स्वाप में समयती सिंपा सम्ति हम सूची में उस्ति किसी विषय पर सावीय समयत वाम किसी राज्य विषान मण्डल द्वारा स्नृति निम्त दिया जाता है और दोनों कानूनों से सम्पं हैं तो जिस हद तक राज्य वानून वा समीय बानून से सम्पं हैं तो जिस हद तक राज्य वानून वा समीय बानून से सम्पं हैं तो उस्ति हम स्वत् माना जायेगा। परन्तु यदि समीय ससद के विस्ती विषय पर वानून निर्माण वरने ये पश्चात यदि कोई राज्य विषय मण्डल द्वारा उसी विषय पर कानून निर्माण वरने पश्चात यदि कोई राज्य विषय मण्डल द्वारा उसी विषय पर कानून निर्माण वर्गन हो साथ है। स्वत् को राज्यति वे विषया दे विष्य सूरिकित रखने के पश्चात उसकी सहस्रति मिल गई हैं तो राज्य वानून मान्य होगा। परन्तु समीय

ससद तत्पन्नात् उत्तर राज्य कानुत को परिवर्तित या समाप्त कर संकती है। टा॰ एम॰ पी॰ धर्मा ने एक सुन्देर उदाहरण प्रस्तुत किया है। "हम मान लें रि एक राज्य कानुन, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश विधान सभा का कानुन, जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिवय संगाये गये हैं, कानून की पुरनक में रखा जाना है। सधीय ससद एक कानून पारित करती है जिससे यह प्रतिबन्ध हटा दिये जाते हैं । अब सधीय कानून लागू होगा और उत्तर प्रदेश का नानून जिस सीमा में संघीय कानून से विरोध में है, उस सीमा तक प्रवेध होगा । तत्रश्चात्, उत्तर प्रदेश विधान सभा एक और वानून पारित करती है, जिसके द्वारा उन प्रतिवन्यों को जो संघीय कानून द्वारा हटा दिये गये थे, पून सापू कर दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के कानून की राज्यपान द्वारा राष्ट्र-पति के विचार के लिए सुरक्षित रखना होगा । और यदि राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की परिस्पितियों को देलते हुए अपनी सहमति देना है तो यह कानून (उत्तर प्रदेश का) पहले संशीय कानून से संवर्ष में होन के बावजूद भी बैच होगा । यदि संधीय सबद उत्तर प्रदेश म प्रेस को स्वतन करने के लिए पुन एक कानून पारित

करना चाहनी है तो वह ऐसा कर सकती है। "" समवर्ती सूची में मुख्य विषय इस प्रकार है।

इण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, निवारक निरोध (नवरवन्दी), दीवानी प्रक्रिया, विवाह तथा विवाह विच्छेद (तलाक), दिवालियापन, उत्तराधिकार, सम्मत्ति का (सिवाय कृषि सबधी) हुस्तान्तरण, सविदा, शाच पदायों तथा अन्य धस्तुमों मे मिलाबट, पागलपन, साहब तथा प्रतिक्षा, श्रीपवियां तथा विष, श्रीपवियां तथा मन्य वस्तुएँ, मार्थिक तथा सामाजिक परियोजनाएँ, व्यापार सम, श्रम विवाद भीर श्रम कल्यान, कानून, चिकित्सा तथा ध्रन्य व्यवसाय, समाचार पत्र तया प्रेस, पुस्तकों, जीदन मरण के स्रांकडे, सौद्योगिक वस्तुएँ, खाद्य-पदार्थ, पशु-मोजन कच्ची दई, दई के बीज तथा कच्चे जूट का उत्पादन तथा वितरण, धन्यत्र जाने

बाले शरपाधियो की सम्पति बादि ।

मारतीय सविधान में श्रविधान्ट शक्तियों ने लिए श्रनुच्छेद २४६ में प्रावधान किया गया है। अविधय शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं, जो उपयुक्त तीन मुचियों में उल्लिखित नहीं हैं। मारत में घवशिष्ट शक्तियों को संघीय सरकार में निहित क्या गया है । अमेरिका, आस्ट्रेलिया, तथा स्वीवरसँग्ड मे ध्रवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्राप्त है, जबकि केनेडा में ये शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित हैं।

१. एम० पी० शर्मा- द वर्वमेन्ट आफ द इण्डियन रिपल्लिक, १६६१ 90 50 1

मारतीय सविषान में सामवाद के सिद्धान्त को ध्रपनाने के फलस्वरूप सथ ग्रीर राज्य सरकारों के श्रेषाधिकार धलम-प्रालग निर्पारित क्रिये समें हैं, तथापि कतियम ऐसी परिस्थितियों का सिक्षान में उल्लेख निया गया है जिनमें सथ साहर राज्य सूत्री ने विषयों पर कार्नून निर्माण कर सदेगी। ये परिस्थितियाँ निम्मिलिशित हैं

१—सल ससद राज्य-सूचो मे लिल्लाखन किसी विषय पर मनुष्ठीद २४६ के प्रत्यत्तेत कानून निर्माण कर सकती है, यदि राज्य विधान समा न दो तिहाई बहुमत से मत्तान किया है वि उक्त विषय का महत्व राष्ट्रीय हो गया है। राज्य विधान समा का यह प्रत्याव एक वर्ष तक रहेगा। राज्य सम इस प्रचार के प्रत्याव को मेनेक वार पुर्विनियत कर सकती है। सम ससद हारा एस प्रकार के जो मानून पारित किया जाते है, वे राज्य विधान समा हारा पारित प्रस्ताव की समयाविधि मे समाप्त होने के ६ माह बाद तक वैच माने लियों।

२-- प्रनुच्छेद १४२ के प्रकार्गत राष्ट्रपति हारा जय सक्टकालीन उद्घोषणा की आयेगी तब सधीय सबद, प्रनुच्छेद २५० के अनुसार, किसी भी विषय पर, (राज्य सूत्री म उदिजीकत विषयी सहित) भारत या तक किसी प्रदेश के विष् कानून निर्माण कर सकेगी। सबद हारा पारित इस प्रकार के कानून सकट-काफीन उद्घोषणा के समाप्त होने के ६ माह के बाद समाप्त हो जायेगे।

२ — मनुष्देत २५२ वे धनुसार यदि दो या दो से घषिक राज्य विधान मण्डलो ने प्रस्ताव पारित विधा है कि ससद उस राज्यों के लिए राज्य सूची में उस्तिवित किसी विधय या विधयों पर कानून निर्माण करें तो ससद को उन राज्यों के सबय में राज्य सूची म उस्लिखित विषयों पर कानून निर्माण करने का प्राप्तिता श्री पर कानून निर्माण करने का प्राप्तिता प्राप्त होगा।

४— प्रमुच्छेद १५३ के अनुसार समीय ससद को किसी सिंप समक्कीते या उपसींग, जी समीय सरकार ने किसी विदेश या विदेशों से की हैं या किसी अन्तरांष्ट्रीय सम्मेतन, समुदार या अग्य सहया ने निर्णय के क्रियान्ययन के लिए कानून-निर्माण चरने का प्रियान है। इस प्रकार ससद हारा निर्माल कानून सप के किसी भी राज्य या समस्य भारत में साम होगा।

४—यदि मनुब्देद ३४६ के धन्तर्गत सम के किसी राज्य में उनत राज्य में सबैपानिक मन के ध्रसक्त होने के नारण राष्ट्रपति बासन लागू किया गया हो, तो राष्ट्रपति व्यवधायणा द्वारा सबस को उनत राज्य के लिए राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण करने के लिए प्रिष्ठिक कर सलत है। ससद स्वय इन चित्तमों ने उपयोग करने के विषया प्राप्ति को धनुब्देद ३५७ (१) स (२) के प्रत्येत यह वाकि प्रदान कर सकती है और उसको प्रविद्धत करने.

सकती है कि किसी यन्य प्राधिकारी की जिसका राष्ट्रपति उल्लेख करता है, यह मिल प्रदत्त की जाने।

६—सप के विजिल राज्यों में राज्यपास एवं करी के कम में हैं, निर्मास संधार तथा राज्य जासनों को निर्मास स्वरूपण निषयों के स्वरूप में जोड़ा जाता है। राज्यपाल को यह मुंगान उस समय विजिल्ट रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जर राज्य सरनार को समियान ने प्रावधानों के अनुसार नहीं चतायां जा सकता है। राज्य विधान-पर्वती द्वारा पारित्त करिया विधान, उसहरार सक्य लेश समयों पूर्व में वे दिस्तित कि तिवित विधान को साधीय विधान से साधीय विधान को समयों पूर्व में के दिस्तित कि तिवित के साधीय विधान से साधीय विधान को साधीय विधान के साधीय कि साधीय

सरियान के उपर्युक्त प्रावधान भारत मे सवीय सरकार को सानियानी रखते में सहायक हुए हैं। इनके बारण जीवधान के सम्वतंत वसवाद के विद्याना होने के सरमारा भी हुए ब्रायक्त प्रवृत्तिकों को मारतीय राजनीति ये एम महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। प्रावध्यवतानुसार सभीय ससर को राज्य पूची में उत्तिशित विदयों पर कानून क्याने ने लिए फाँबइत करने के प्यतस्वकर इन प्रावधानी का प्रमास पर होता है कि इससे भर राज्ये की एम प्रमु पहिन जो, बो बासती ने बताई है, विद्यानय म लाया जा सक्या है। वह है—'केशीय सरकार को घरिन विद्यानक के कारण देश के आग्तरित तथा बाह्य मामली के प्रवस्य करने के सबस में

#### २--सघ तथा राज्यो के प्रशासकीय सबध

सबिप सपीप व्यवस्था म अस्तियो ना निवाजन करते हुए दो प्रकार मि प्राचित के प्रकार के प्रकार के स्वाचित के सिंद्र वेशीयहरार पूचन किये प्रति हैं, स्ववाद का उद्देश, जीता <u>की, कामली हैं, पार्ट्रे</u>म एकता तथा पार्ट्यों में स्थापतता को हासिल करता है। सम्बाद के अन्तर्वत हो राट्ट्रोय एकता तथा प्राच्यों को स्थापता को सामल हो बकते हैं। पाट्ट्रोय एकता तथा प्राच्यों की स्थापता या आधारत तथा समान बहुत वहात है। किन्द्र प्राच्यों के स्थापता ने दावे उस हद तर स्थीष्टत नहीं निसे जा सर्वेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता पर आयात पहुँचने की सभावना होगी। राष्ट्रीय एकता के सत्यमें म यह कहना सत्य है कि समस्य राष्ट्र को एक प्रकासकीय इकाई कानते हुए ही राष्ट्रीय एकता की भीव दढ़ की जा सबती हैं।

मारतीय सविधान ने मातगैत समीय तथा राज्यों ने प्रणासनीय सवधी ना विषयेपण परने पर यह स्वष्ट हो जायेगा नि राष्ट्रीय एवना की दृष्टि से सधीय सरकार को राज्यों ने सबध में कतियब प्रणासनीय णस्तियाँ प्रदक्त की गई हैं जिनका प्रध्यपन दो विषयों ने खाखान पर किया जा सनता है।

- (क) राज्या पर प्रशासकीय नियमण हेतु सचीव सरकार के साधन, भौर
- (त) प्रातरीज्यीय सहयोग तथा सच सरकार की भूमिका
- प राज्यो पर प्रशासकीय नियम्प्रण के लिए संघीय संस्थार के साधन

सामा बत सपीय सरकार राज्यों नी सरकार पर वांच साधनों से प्रशासनीय निम्न पण उपयोग म ला सबसे हैं।

सर्वप्रथम सविधान द्वारा संघीय सरकार को राज्यों की सरकारों की निर्देश देने का प्रधिकार दिया गया है। सविधान के अनुच्छेद के २५६ के प्रमुसार राज्य सरपार या यह वर्तव्य है कि ससद द्वारा पारित विधि की मान्यता दें। इसी प्रकार प्रमुख्छेद २५७ वे प्रमुखार राज्य सरकारो का यह भी कर्तव्य है कि प्रकी क्षेत्र म सघ की नार्मपालिका शक्ति के उपयोग में न नोई स्वावट डाले और न कीई परापात करे । उपर्युक्त अनुक्छेदो ने अनुसार सथ सरकार द्वारा राज्य सर-कारों को निर्देश दिये जा सकते हैं। सविधान के अनुच्छेद ३६५ में यह स्पष्ट प्रावधान है वि यदि सथ की कायपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये कि ही निर्देशी का अनुवर्तन करने म या उनकी प्रभावी करने में कोई राज्य असपल हुआ है तो वहाँ, राप्ट्रपति वे लिए यह मानना विधि सनत है वि ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई है जिसमे राज्य या शासन सविधान के प्रावधानों वे समुकल नहीं चलामा जा सनता है। इसना यह अभिप्राय है नि जब नोई राज्य, सघ नी नार्यपालिना द्वारा दिय निर्देशा का पानन नहीं करता है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद ३५६ के म तगत यह उद्योपणा वर सवता है वि राज्य का सवैधानिक-यत्र समाप्त हो पुता है भीर इसने फनस्वरूप राज्य की सरकार के समस्त या कुछ कार्यों वो स्वय से सकता है।

सघीय सरनार राज्यो की सरनारों नो धानुच्छेद २१७ (२) के धानुसार राज्यों म राष्ट्रीय या ग्रेनिक के महत्व व सकार साधनों के निर्माण करने घीर बनाये रहाने के सिए निर्देश दे सकती हैं । सजार साधनों एक ऐसा विषय है, जिसका उस्सेरा पदम, राज्या को सक्षीय सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है नथािन राज्यों की ब्राय के विभिन्न स्रोत उनकी जित्तीय आवस्यक्ताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राज्यों को वित्तीय अनुदान देने के लिए अनुच्छेद २०५ के अनुसार सपीय सबद को कानून निर्माण करने का अधिकार है और इस प्रकार राज्यों को प्रदत्त वित्तीय अनुदान का व्यय सारत की सचित निधि में से किया जायेगा। इसके अविक्ति, सवियान म दो प्रकार के विकार अनुदानों का उल्लेख है, को निम्निनियत हैं।

१—मारत सरकार को सहमति से किसी राज्य द्वारा धनुसूचित जातियों के करवाण या प्रमुक्तित क्षेत्रों के प्रकासन के स्तर को उन्नत करने के लिए प्रमुक्त गई योजनाओं के लिए अनुवान जिसका व्यय भारत की सचित-निधि पर मारित होगा।

२--- ग्रसम म भ्रादिम जनजाति थ विनास क लिए ग्रनुदान ।

वित्तीय ध्रनुदान में माध्यम से सधीय सरकार राज्यां पर प्रमावशाली नियन्त्रण रखती है।

## ख ग्रन्तर्राज्यीय सहयोग तथा सघ सरकार की भूमिका

िमती भी सभीव व्यवस्था म इनाइयो (राज्यो) म पारस्परिक सहयोग होना मति मानव्यक है। सद्यपि राज्यो को सत्ता की दृष्टि से पृषक क्षेत्राधिनार प्राप्त होते हैं, तथापि राज्यो एकता के लिए राज्यों को पारस्परिक सहयोग तथा सह मित्रत्व के सिद्धान्तों के भाषार पर वार्य करना होगा। भारतीय सविधान में राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए निक्नतिसित विषयों पर विशेष रूप से यह दिया गया है।

१----मण तथा राज्यो की सार्वजनिक क्रियाधो, धिवलेखो तथा न्यायिक कार्यवाहियों की दिव्यति अनुरुद्धेद २६१ (१) वे अनुसार मारता के राज्य क्षेत्र में सर्वज, सय की और अरवक राज्य की सार्वजनिक विवाधो, धर्मिलेखो, धर्मिन मंत्रवंत्र होता कार्यवाहियों को पूरा विश्ववास और जूरों मान्यता दो जायेगी। परन्तु कार्यमा अर्थित होता को स्वाधिक कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति धरेर झर्जों तथा उनके प्रसाद का निवास्य ससद निमित-विधि द्वारा उपप्रचित्त रीति के मनुसार होगा। इसने इतिरिक्त सारत की के विसी भाग के न्यायासवा द्वारा दिये गर्थ अर्थित निवास कार्यक सारत राज्य के में कही भी नियमदन योग्य होगे।

२—प्रन्तर्राजीय नदी या नदियों ने जला ने सवय में विवाद—प्रमुख्छेद २६२ (१) ने प्रमुसार ससद विधि द्वारा निसी धन्तर्राज्यीय नदी या नदियो के जल के प्रयोग, विजयण या नियन्त्रण के बारे में किसी विजाद या प्रार्थना पर न्याय निर्णयन का प्राथ्यान कर सकती है। इस प्रचार के निवाद के सबय में सद्यद विशि द्वारी यह प्राय्यान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायानय, न प्रयास कोई न्यायानय प्रथमा क्षेत्राधिकार प्रयोग य लेगा।

३—एन्टरांग्यीय परिषद—धनुन्देद २६३ के धन्तर्भव राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक धनतरांग्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपत को प्रतीत होता है कि जनाईत में धावस्थक है तो वह धन्तरांग्यीय परिषद के स्वापना करेगा । इस धनतरांग्यीय-परिषद के निम्नलितित काय होते ।

एक — राज्यो के मध्य विवादो का परीक्षण करना तथा उन पर परामशै देना।

दो—ऐसी जाँच तथा विवेचना करना जिसमे कुछ या समस्त राज्य या सभ या कुछ राज्यो का सामान्य हित निहित है।

त्तीन —ऐसे विषय पर कुश्रव देना और विशेषकर ऐसे विषय के सबस में ' भीति तथा कार्यों में बेहतर सम्मव्य के लिए सुकाय देना । राष्ट्रपति, जब इस प्रकार की अन्तर्राज्यीय परिवद की क्यापना करता है वह उसके कार्यों, सगठन तथा कार्यप्रणाणि की निर्धारिक करेजा ।

Y—लेत्रीय परिषद—राज्य पुनर्वटन अधिनयम १८५६ ने अन्तर्गत सम्पूर्ण मारत सम के तिए सोत्रो की एक परियोजना को प्रत्येक क्षेत्र में सामू दिया गया। क कतियम राज्य हैं, जिनके लिए एक श्रीत्रीय परिषय है। सम्पूर्ण भारत के लिए निम्मलितिल पॉच क्षेत्र निर्माहित किये गये हैं—

१—उत्तरी क्षेत्र—पजाव, राजस्यान, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली संघा हिमाचल प्रदेश है।

२-- मध्य क्षेत्र--- उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश ।

३-पूर्वी क्षेत्र-विहार, पश्चिम बगास, वडीसा, मणिपुर भौर त्रिपुरा ।

¥—पश्चिमी क्षेत्र—महाराष्ट्र, युजरात तथा मैसूर क्षेत्र ।

५—दक्षिणी सेत्र—ग्रान्ध्रप्रदेश, मद्रास, तथा केरल ।

प्रतिन क्षेत्र के तिम् एक होत्रीय परिषद है निम्मे एक सभीय मत्री रहेगा तो राष्ट्रपति द्वारा मतीनीत दिया जायेगा। क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमत्री, क्षेत्र, के प्रतीक राज्य में हे दे अपत्री जी राज्यपाल द्वारा मनीनीत दिये जायेंगे तथा क्षेत्र के प्रतिक सभीय मुन्याय हो दो व्यक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा मनीनीत किये जायेंगे, क्षेत्रीय परिवद के सदस्य होगे। धौर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेषकर भादिम जाति क्षेत्र के लिए राज्यपाल का परामर्ख दाता भी उनत क्षेत्रीय परिपद मे सम्मिलत किया जायेगा। क्षेत्रीय परिपद मे सधीय मत्री क्षेत्रीय परिपद का भव्यक्ष होगा, धौर प्रत्येक मुख्य मत्री एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष रहेगा।

क्षेत्रीय परिपद में कतिपय परामर्घ दाताओं को भी सिम्मलित किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं—योजना धायोग का प्रतिनिधि धौर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव धौर विकास धायुक्त । इन परामर्थ दालाओं को विवाद में माग क्षेत्र का प्रियकार है, किन्तु वे सतदान नहीं कर सकते हैं।

क्षेत्रीय परिपद की बैठक तथा स्थान प्रध्यक द्वारा निर्धारित निया जाता है। परिपद की बैठक का स्थान, क्षेत्र के किसी राज्य में ही होना चाहिये। परिपद प्राप्ते कार्यों के सम्पादन के लिए सिमितियों का निर्माण कर सकती है। परिपद के सिखालय के प्रधिकारियों के स्थय का मार, सचिव के देतन के सिबाय, केन्द्रीय सरकार पर है। खेत्रीय परिपदों के कार्य जन समस्त विपयों से सब्धित होंगे जिनमें क्षेत्र के के समस्त विपयों से सब्धित होंगे जिनमें क्षेत्र के कार्य जा अध्व राज्य या सच चौर एक या प्रधिक राज्य शंच रकते हैं। क्षेत्रीय परिपद, सख सरकार या क्षेत्र की किसी सरकार को ऐसे विपयों पर परामणें देती है। कुश्यत क्षेत्रीय परिपद निम्मतिखत प्रश्नो पर विदार विमाय करती तथा परामणें देती है।

एक—मार्थिक तथा सामाजिक योजनाझी से सर्वावत कोई सामान्य हित का विषय ।

दो—सीमा विवाद, मापा पर भाषारित श्रह्म सस्यक, धौर अन्तर्राज्यीय भाषागमन से सबधित कोई विषय ।

तीन—राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत राज्यों के पुनर्गठन से सवधित कोई भी मामला ।

सतेप मे परिपदो की स्थापना का उद्देश्य संधीय सरकार के सहयोग से अन्तर्रोज्यीय विवादो का समाधान करना है।

५—सप मौर राज्यों म व्यापार वाणिज्य और लेन देन—सिवान के मुनुत्वेद ३०१ के भनुसार मारत राज्य क्षेत्र मे सर्वेत्र व्यापार वाणिज्य भौर तेन-देन की स्वतंत्रता है। परन्तु अनुन्देद ३०२ के अनुसार ससद विधि द्वारा एक राज्य भीर दूसरे राज्य के बीच धमवा मारत राज्य क्षेत्र के किसी माग के भीतर व्यापार वाणिज्य व होन-देन की स्वतत्रता पर ऐसे प्रतिवन्य लगा सकेगी, जो लीकहिन मे भमेशित हैं।

स्तुन्हेंद्र २०३ (१) के प्रतुवार संविधान की सातनी धनुमूकी मे लिहित तीन सूचियों में (स्व. राज्य तथा समकती) वे किही में ब्यामार-जाणिनम सक्ती हिनी विदास के वायार पर न तो सबद को धीर न राज्यों ने विधान मण्डात नो कोई ऐसी विधि बनाने की जांकि होंगी, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से सांध्यात देती है ध्या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच नोई निमंद करती है। यरन्तु अनुन्देद २०१ (२) के अनुमार सबद नो ऐसी विधेष परिस्थाति में यह मिथिनार होंगा कि कोई ऐसी विधि बनाये जिससे किसी राज्य को यह सीमान दिया जायेगा या एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच विषेद होगा, जब सबद जक विधि-द्वारा यह चीरित कर कि मारत राज्य कोन के विधी माप में बहुसी की दुर्वनता के नारण जवन हुई सिवीच के निकरते के अपोवन के तिस्त ऐसा करना धावध्यत है। यह स्वरण रचना सावस्यक है कि जबकि सनुन्देद २०१ (२) के धनुसार सबद को बहुओं थी दुर्वनधा के परण ऐसी विधि निर्माण करने सावस्यत हिसी किसी राज्य को हुनरे राज्य के सिवीचन किसता है वा दो राज्यों में विवेद होना है, किसी राज्य कियान के ब्यापार तथा वाणियन की दुद्धि है है

धानुष्टित २०४ (क) के धानुशार राज्य का विशान मण्डल, विधि हारा साय राज्यों से सामात थी गई कस्तुमी पर फोर्ड ऐसा कर लगा सकता है, जो उसे राज्य में निर्मात या ज्यादित की ही विश्वाद्ये पर स्वाना हो किन्तु हम प्रकार कि जसेते इस करंद्र मामात की गई वन्तुमी तथा ऐसी निर्मात राज्य कराशित कन्तुमी से श्रीक कोई निर्मेत न हो। मानुष्टीत २०४ (क) के धानुसार राज्य विसान मण्डल में, विधि द्वारा उस राज्य के साथ या उससे व्यापार सायित्य और रोल-देन भी स्वतन्ता पर ऐसे बुलियुक्त जिले-यन नामते ना स्विकार है जो लोकाहित में स्वीतित है। परजु इस उद्देश्य से किसी भी विषयक या सारीयन की विधान-मण्डल से दुत स्वारित्य करीत के लिए राज्यति की युवांनुताति सायस्यक हो। परत में सम्पर्टामीय व्यापार-व्यापित्यन से स्वविद्य विधानक का सामायन की स्वापान

चरत ने सम्मराज्यीय व्यापार-वाणिक्य से सबसित सविधान के प्रावचानी के क्रियान्यम के तिए अनुब्देद ३०७ के अन्तर्गत सक्त एक प्रापिकारी की नियुक्ति करेगी तथा उत्तको ऐसी वाल्यों और नतंत्र्य सीच सनतो है जो वह आवस्यन समझे।

#### ३-सध तथा राज्यों के वित्तीय संबंध

संपीय व्यवस्या में, संपीय तथा राज्यों नी सरकारी में सवियान के मन्त्रयत चिक्रयों का बेंटवारा ब्रावण्यक हैं, निन्तु शक्ति के बेंटवारे के साथ विसीय सांचयी ना बेंन्साम से मत्यक सावश्यक हैं। क्योंकि बिना ययांका वित्तीय सांचयी के विनिन्न शक्तियो वा कोई धर्य नहीं होगा। घत साधारण्यता प्रत्येक सधीय अवस्था सब मे तथा राज्यो की सरकारो का, अपने वित्तीय साथनो पर स्वतंत्र और पुष्क नियन्त्रण होता है जिससे वे अपने क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को स्वतंत्रत वृत्तेक कर सकें। सधीय वित्तीय अवस्था नो भारदा प्रणाली सह होगी जिसमे स्थट रूप से राजस्व के सोतो का विभाजन सथ तथा राज्यों के मध्य प्रणाली के स्वतंत्र विभाजन सथ तथा राज्यों के मध्य स्था कि विभाजन सथ तथा राज्यों के स्वतंत्र वाला के स्वतंत्र स्वतंत्य

बस्तुत व्यवहार में समीय देशों में सम और राज्यों के वित्तीय सबमों के दृष्टिकोण से मोई एक सामान्य पद्धित को नहीं घपनाया गया है। विनंतु प्रत्येक समीय राज्य में देख की मुविधा के अनुसार घपनी पद्धित का विकास हुआ है। यद्याप क्रिसिटमां ने सह तथा राज्यों के लिए पृथक वित्तीय कोती का प्रावधान है, विनंतु वहां पर भी राज्यों को समीय प्रमुदान देने की भाववयनता पैसा हुई। के कैने वात्या सार्द्शिला में समीय (क्रिटीय) सरकार राज्यों की सिर्वाट को स्वतीय के सार्वाट की स्वतीय का सार्द्शिता में समीय भिज्यों के साथ के साधन पर्योच्त नहीं हैं।

मारतवर्ष म सिवधान के अन्वर्धत सथ तथा राज्यों के अध्य तीन सूचियों द्वारा मिक्त विमाजन ने साथ जो आय के साथनी वा विमाजन किया गया है, वह न तो पूर्णत्या स्पष्ट है और न सम्पूर्ण है। इससे राज्यों को उननी आवश्य-कताओं से बहुत कम दिया गया है, और सिवधान के धनेक सन्य प्रावधाना द्वारा, जिनका उद्देश्य सथ के छोतों के मुख मांग की राज्यों की विभिन्न रूप मे हस्तास्त-रित करना है प्रयक्तित तथा पूरा निया जाता है।

मारतीय सम के राज्यों को पूर्ण रूप से उन करा से प्राप्त स्वाय पर स्रविचार है, जो राज्य सूची म उरिलिखित हैं। सम सरकार को उन करों से सारी साथ प्राप्त होती है जिनका उत्सेख सम सूची मे विया गया है। इसके मितिस्त, सम सरात होती है जिनका उत्सेख सम सूची में विया गया है। स्वाव किस किस सूची म नहीं किया गया है। समवर्ती सूची म करो वा थोई उद्सेख नहीं है। राज्यों का राज्य सूची के प्रत्येत लगाय करा की स्वाय रउते का स्विकार है, सम सरकार में सम सूची के प्रत्येत स्वाय ये पूचे उत्ते का स्विकार है, सम सरकार में सम सूची के भारत स्वयों ये ये युद्ध करों की साथ की पूर्णतया या कुछ प्रमा म राज्यों को देना होगा।

सप तया राज्या के वित्तीय सम्बाना ग्रब्ययन निम्मिलिखित ग्रामारो पर कियाजासकता है।

१. वही पृ० ६६

कः सच तथा राज्यों के मध्य राज्यव का वितरथ—सथ सरवार को पालीय सविवान के प्रत्यंत चार प्रकार के करो से प्राप्त पाय को पूर्ण हथ से या कुछ प्रश्न मे राज्यों को देना होयी। यह निम्मलिखित है। अनुकोर १६० के प्रनुतार।

१—सप सरकार हाय लगाये, किन्तु राज्यो हारा सगुरीत तथा विनियोजित गुरू विनिमय पत्र, चेक, प्रायेसरी नोट्स, माल, प्रस्तवाव वा माल, हुष्टिया, बीमा धारि पर स्टाम्स जुरूत तथा स्वादयो भीर ऐसे श्रुवार सायन जिनके निर्माण में यस का उपयोग होता है।

२—सप द्वारा नवाये और सगृहीत परन्तु राज्यो नो विये जाने वाले कर-सन्तर्वेद २६६ के सनुसार ये निन्निविस्ति हैं —

(एक) इपि-मूनि के प्रतिरिक्त, प्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर।

- (दो) कृपि भूमि के श्रतिरिक्त, अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुरुक ।
- (हीन) रेल, समुद्र तथा बायु हारा माल बीर यात्रियों को ले जाने पर सीमान्त कर।
  - (बार) रेल सथा वस्तुधो के भाडे पर कर।
- (पीच) शेयर बाजार तथा सटटा बाबार के क्षेत्र देन पर स्टाम्प शुल्क ला स्रतिदितन सन्य कर।
- (छ)समाचार पत्रों के क्रय विक्रय झीर उनमे प्रवाशित विकायनो
- पर कर ।
- (सात) घन्तर्राज्यीय व्यापार तथा नाणिज्य ने सिलसिने म माल के क्रय विक्रय पर कर :

१—सप द्वारा लगाये व सबहीत धावकर विनवन विमामन सम प राज्यों के मध्य म होता है। अनुन्छेद २७० के अनुसार समीय भू-भागों के नियं निर्धारित राशि तथा सपीय ०२४ को काटकर केप धावकर की राशि का विभागन सम व राज्यों में राष्ट्रिय निर्दाशित को स्विध सायों के प्रतिवेदन पर विचार परंते के परणात् जादेश के प्रतिवेदन पर विचार परंते के परणात् जादेश करता है।

भनुष्टेद २७१ के मनुसार संसद विभिन्न करों की जो कि मनुष्टेद २६६ व २७० में उन्लिखित हैं। सच के उद्देश्यों को पूर्व करने हेतु अधिकार द्वारा वृद्धि कर सकेगी।

४—सप द्वारा समावे गये तथा समहोत कर जिनका विभाजन सप व राज्यों के मध्य होता है —ये कर इस प्रकार के हैं—स्वाई और म्हलूगर सबधी बस्तुमों को छोठकर धन्य बस्तुम्मों पर समाये उत्पादन गुल्कः । सा. संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायक अनुदान—भारतीय सविधान में सथ सरकार के राजस्य स्रोत से तीन प्रकार के सहायक अनुदान राज्यों की दिये जाते हैं।

१—मनुब्हेद २७३ के अनुसार असम, विहार, उडीसा तथा पिचम वगाल को जूट घीर जूट से निमित्त वस्तुघो पर नियत्ति कर के उदिने में सम सरवार द्वारा प्रनुदान दिया जाता है। पास्प्रति चनुदान की राशि नियारित करता है। इस राज्यों को अनुदान जब तक दिया जावेना, जब तक भारत सरकार द्वारा जूट या जूट से निमित वस्तुघो पर जुल्क लगाया जाता है, या सिवधान के प्रारम से दस वर्ष तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, उसके होने तक।

२—सनुष्टेद २७५ के सन्तर्गत ससद को यह स्रिषकार है कि सम के किसी राज्य को जिसको किसीय अनुदान की सावश्यकता है, सहायक अनुवान प्रदान करें। किस मात्रा में यह सनुदान दिया जाना चाहिये, इसका निर्धारण करने का प्रिकार सस्त को है। सभीय सरकार का यह असिरिस्त कर्त्तव्य है कि राज्यों द्वारा अनुस्थित सादिम जातियों थे कस्थाण हेतु प्रारम की गई योजनाओं को प्रदान करने के सित्य और अनुस्थित सोवों के प्रशासनिक स्तर को ऊँचा करने हेतु सहायक समुदान प्रदान करें। सिवान द्वारा असन के सादिम क्षेत्रों के विवास हेतु विशेष सहायक प्रदान के किया प्रवास किस क्षायक स्वास के स्तर की किया सादा असन के स

३— अनुष्येद २०२ के अन्तर्गत सधीय व राज्य सरकारों को यह प्रियकार है कि निस्ती भी सार्वजनिय उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहायक अनुसान प्रदेश करें। इसके बावजूद भी नि बह विषय ससद व राज्य विधान मण्डल के अ्यवस्थापन के सायरे में न हो।

ग. पारस्परिक करों से सध तथा राज्यों की खुक्ति—१---- प्रनुक्केंद्र २८५ के अन्तर्गत जय तन सहद कानून द्वारा कोई प्रावधान न करे, राज्य सरकारें सच की सम्पति पर कर नहीं लगा सन्तरी हैं।

२ — मनुस्थेर २०० के बनुसार भारत सरकार या रेल ढारा उपयोग में ली जाने वाली बिजली पर बिना ससद की बनुमति के राज्यों द्वारा किसी प्रकार का ग्रन्थ नहीं संगाया जा सकता है।

१--भनु-छेद २०० के भ्रत्यर्थत विना राष्ट्रपति की ध्रुतुमति के कोई राज्य, ऐके प्रांपिकरण द्वारा दिये गये या नियन्त्रित धानी या विजली पर शुक्त नही समा सनता जो भ्रत्यराज्यीय नदियो या नदी-दुनी (पाटियो) के विनास या विनियम के | जिए स्वामित निया नवा है ।

Y-प्रनृच्छेद २८६के धनुसार सध सरकार को राज्यो की सम्पत्ति तथा प्राय पर वर सगाने का प्रधिकार नहीं हैं। परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा किये जाने बाते व्यापार या व्यवसाय को सभीय करों से मुक्ति तब ही मिल सहेगी, जब ससद बातून द्वारा यह पोषित करती है कि एसा व्यापार या व्यवसाय राज्य सरकार के कार्यों का मार्ग है ।

प सच तथा राज्यों की क्ष्म वेते की शक्ति—सविधान के चनुपोद १६२ के बतुतार सरीय सत्तराद भी मादव की सचितियिंच नी प्रतिभूति पर फ्राम कीने ना प्रतिकार है। हिन्दु देश विध्य पर सबस वानून हाद सीमाएँ त्या सन्तरी है। राज्यों को मारतीय प्रदेश में राज्य सचित निधि की प्रतिभूति पर क्षम लेने ना प्रतिकार है। राज्या ने क्षम जैने के सचिनार पर सविधान हारा हुछ सीमाएँ रखी रही की देश प्रवार हैं—

१--राज्यो द्वारा मारत म ही ऋण सिया जा सरता है।

२-यदि राज्य सरकार ने अपना पुराना ऋण सम सरकार के प्रति चुना न दिया है तो नवे ऋण सेने के लिए सप सरकार की सनवति ग्रावदवन होगी ।

द्यम हता तथ अन्य सन व लिए सेय सरकार के अनुवाद अवस्थन होता। ३--राग्म विधान मण्डल राज्य सरकार के ऋष क्षेत्र के अधिकार पर सीमाएँ संया सकती है।

अनुकोद २१३ के अनुकार सधीय सरकार राज्यों को सबद द्वारा निर्धारित सती के मनुसार ऋण दे सकती है।

ह. विस्तीय सबय कालीम उद्योगिका :- अनुच्छेद १६० के अनुसार राष्ट्रपति
सो विश्वास हो ब्याला है कि ऐसी स्थित थेदा हो शई है, जिससे सारत सथा
लक्ष किसी राज्य की न के निसी शाव का विस्तीय स्थानियत्व या प्रायय सन्दर्भ है
तो वह विसीय सकरकालीन उद्योगिया कर सकता है। इस सन्दर्भ से सपसरकार राज्यों की सरकारों को विस्त व्यवस्था के सन्दर्भ से सार्थ्य प्रायोगिया निर्देश से
सरकार राज्यों की सरकारों को विस्त व्यवस्था के प्रशासन के सार्थ्य मार्थ्य मार्थ्य है
हो । सम पर्वार, स्था वार्या राज्यों के प्रशासन के सम्बाध मार्थ्य मार्थ्य स्थानिया है
हो । सम पर्वार स्थानिया स्थानिया स्थानिया है
हो स्ती तथा बेतन म नदीतों के सिए बादेश दे सकती है। इस सन्दर्भ मे
राज्य विसार सम्बनी द्वारा पारित यन-विषयकों के लिए सीस सरकार यह
स्थाने व सन्दर्भ है कि उनको राज्य की सम्बन्ध के लिए सीस सरकार राज्य

च-प्रता में, सब तथा राज्यों के वित्तीय सबधों की दृष्टि से, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की भूमिता जी सल्लेखिक महत्त्वपूर्ण है। नियन्त्रक तथा महालिखा परीक्षक की नियंत्रक टाएप्ट्रित करता है तथा सबद द्वारा उसकी राज्यों के लेखा के सबसे में कार्य तथा कि लेखा के सबसे में कार्य तथा कि लेखा पर नियन्त्रम सामित्रक साहित्य परीक्षण का पूरा नियन्त्रम रहता है।

संघ तथा राज्यों के विभिन्न सवशे का ब्राच्ययन करने के पश्चात् यह निष्टपं निवाला जा सकता है कि तीनो, व्यवस्थापन, प्रशासकीय तथा विसीय क्षेत्रों में सद्य सरकार को राज्य सरकारों की अपक्षा अत्यधिक अधिकार प्राप्त हैं। सर्विधान निर्माताओं ने समीय सरकार नो सशक्त रखने के लिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त शक्तियाँ दी है। सधीय सरकार की स्थिति, उन स्थितिया म और अधिक शक्तिशाली हो जाती है, जब केन्द्र तथा राज्य सरकार एक ही राजनीतिक दल द्वारा स्थापित है। भारतीय राजनीति मे १९६७ के चतुर्व ग्राम-चुनाव के पूर्व लगभग सभी राज्यों में (केरल को छोडकर) कांग्रेस सरकारें थी। केन्द्र में भी कांग्रेस दल मत्ताहद या | केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों की नीतिया में एक्ट्यता थी, भीर यदि किसी राज्य तथा केन्द्र में विवाद उठता था तो उसकी दसीय प्रमुशासन के ग्राधार पर राजनीतिक स्तर पर सुलकाया जाता या। परन्त चौषे ग्राम-धुनाव के पश्चात पद राज्यो म गैर-काग्रेसी सरकार स्थापित हुई। कई बार गैर-काग्रेसी सरकारों ने केन्द्रीय सरकार पर उसके प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार मा माराप लगाया, विशेषवर दूसरे माम चुनाव (१६५७) के बाद जब केरल में थी नम्यूद्रीपाद भी साम्यवादी सरकार को, जिसे वर्खास्त किये जाने के मन्तिम क्षण तक केरल विधान-मण्डल मे बहुमत प्राप्त था, केन्द्र सरकार ने बर्खास्त भरके राष्ट्रपति शासन लागू विया । वेन्द्रीय सरकार वे इस वार्यं की देश म वडी धालीचना हुई। इसी प्रकार जब पश्चिम बगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने १६६७ में श्री अजय मुकर्जी की सरकार को बर्जास्त किया तब उसकी मी ग्रालोचना हुई ।

इस सन्दर्भ म विरोधी दली द्वारा राज्यपाल की भूमिना नी विरोध रूप स नदी प्रालीचना की गई। राज्यपाल की भूमिका के सदय म यह नहा गया नि राज्यपाल ने चेन्द्र में सत्तारूढ दल ने हितों को ध्यान म रखते हुए, राज्य सरमार ने विरुद्ध पक्षपात पूर्ण व्यवहार निया।

प्रन्त में यह बहुना उचित होगा नि विसी भी संपीय व्यवस्था की सफलता के सिए सम सरवार तथा राज्यों को सरकारों से सभी क्षेत्रों में पारस्परिक सहमाग होना प्रति प्रावस्थक है। सम्बाद जैवा पूर्व के कहा जा चुका है, राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों (इनाइयों) की स्वायतता के समन्यद तथा सामजस्य पर प्रापात तित एक सिद्धान्त है। राष्ट्रीय एकता की चृद्धि से सक की इकाइयों का यह कर्लन्ग है कि क्षित्रकार के मन्द्रमाल क्षम को क्षमण्ड कराये रखते ना मानता के सार्व्य में में दूसरों भीर के के सरवार का यह दायित्व है कि वह राज्यों की स्वायत्तता का सार्व्या के मन्द्रमाल के मन्द्रम

सप एव राज्यों में, राज्यपानी की नियुक्ति के विषय पर केरदीय सरकार की ममीरता-पूर्वक विचार करने के पत्तवात, ही राज्यपास को नियुक्त करना वाहिये। बसाव परपरासी को स्थापित करने के लिए राज्यपास के पर दिविधित या तैवा-निवस राज्योगिक्की का स्वपन्धान न बना विधा जाये। राज्य-

ानकारात या धवा-ानपुत्त पतनागता वा जारणस्थान न बना दिया जाएँ । राज्य-यास के यर पर, निष्ठावान निष्पत्त, तथा उचन वीडिक तथा नितंक स्तर के क्ष्तिच्यों को ही मनोनीत करता चाहिले, क्योंकि, वीधे मान-सुनाव के पत्त्रमात परिवर्तित राजरीति में राज्यपास को दुख परिवर्धातियों के घवने स्वेत्याधिदारों को उपयोग में साना होगा। प्रवासकीय मुखार आयोग ने सब तथा राज्यों के सवस के निषय पर प्रथमे प्रविदेश ने राज्यपालों के स्वेत्याधिदारों के सबस में पुकात दिया है, कि धूंकि सविधान से प्रज्यास ने स्वेत्याधिकारों को परिवाधित नहीं क्या गया है, इसलिए यह कार्य प्रज्याधिव परिवर को सीपा जाना चाहिये।

सय तथा राज्यों के विसोध सबकों के सन्दर्भ में श्विष्यान में राज्यों के प्राप्त के सामन सीमित है। बत राज्यों को विशोध सहस्यात के लिए सम सरकार पर निर्मर रहता पहला है, विशेषकर राज्यों नो पवचर्यीय योजनाओं के तिए अशास-कीय सुभार सामोप ने भुगाय दिया है कि प्रत्येत पवचर्यीय पोजना के भारम में राज्य के माम के सातों को सुभ और राज्यों के मध्य बायसकतानुसार विमाजित

करने के लिए एक बित्त प्रायोग की नियुक्ति होनी चाहिये। प्रारतीय प्रविधान के दायरे से सथ तथा राज्यों के स्थय पारस्परिक सहयोग के लिए पर्याप्त प्रायान है, जिससे प्राथार पर सचवाद के दोनों सहयों —पार्चीय एकता तथा राज्यों की स्थावता को प्राप्त किया वा सकता है।

## लोक सेवा ग्रायोग

मारतीय सविधान में अनुच्छेद ३१५ ने अनुसार सच के लिए एक लीक सेवा द्यायीग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लीर सेवा द्यायीग का प्रावधान किया गया है। परन्तु यदि दो मा दो से ग्रधिक राज्यों के विधान-महलो द्वारा ससद को जनके लिए एक सबूत लोग सेवा बायोग स्थापित बरने का प्रस्ताव पारित कर ध्रिष्ठित विया जाता है, तो ससद इन राज्यों के लिए एक संयुक्त लीक सेवा आयोग की स्यापना करेगी । किसी राज्य के राज्यपाल के निवेदन पर, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होते में पश्चात सधीय लोग सेवा आयोग उस्त राज्य के लोक सेवा आयोग मे बार्बी को करेगा।

सदस्यो की नियुक्ति व कार्यकाल-सब लोग सेवा आयोग तथा सयुक्त लोग सेया ग्रामोग के प्रध्यक्ष भीर सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रकृति करता है। राज्य लोक सेवा भागोग के ग्रध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सप लोक सेवा ब्रायोग तथा राज्य लोग सेवा ब्रायोम ने बाघे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरवार या विसी राज्य सरवार वे अधीन वम से वम दस वर्ष तव सेवा-

रत रहे हो।

सम लोग सेवा बायोग तथा सयुक्त बायोग के सदस्यों की सख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। सथ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सात सदस्य है। राज्य लोग सेवा बाद्योग वे सदस्यो की करवा राज्यपाल निर्धारित करता है। सापारणतया राज्य लोग सेवा भायोग ने तीन सदस्य होते हैं जिनम से एक प्रध्यक्ष होता है।

सप तथा राज्य लोग सेवा भायोगो ने सदस्यो का वार्यवाल 💵 यर्प वा या सम लोग सेवा आयोग ने सदस्यों ने ६५ वर्ष तथा राज्य लोग सेवा आयोग के सदस्यों के लिए ६० वर्ष की भायु प्राप्त होने तक (जो भी इनमें से पहले हो वह लागू होगा) का है।

सध भौर राज्य लोक सेवा बायोग के सदस्यों की यदस्यति—सघ भीर राज्य लोन सेया भागोग ने भध्यक्ष तथा सदस्यो नो राष्ट्रपति दुराचार ने नारण भ्रादेश द्वारा, जबनि इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच नरके राष्ट्रपति को प्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, पदच्युत कर सकना है। आँच ने दौरान राष्ट्रपति सदस्य को निसम्बत कर सकता है।

स्रोक सेवा झायोग के प्रध्यक्ष तथा किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निम्त-विश्वित किसी कारण के घाषार पर भी पदच्युत क्या जा सक्ता है, यदि,

क—वह दिवालिया हो, या

ल—वह प्रपने कार्यकाल मे कोई घन्य सबैतनिक कार्य स्वीकार कर लेता है, या ग—रास्ट्रित की सम्मति मे वह व्यक्ति मानसिक या बारीरिक दुवंलता के

कारण वयने पर वर कार्य करने ने सत्तमयं हो गया है । प्रमुच्छेद ११७ के बनुसार यदि मारन सरकार या किसी राज्य सरकार हारा या इनके बारते क्लिय मेंचे किसी सबिदा या कच्छर से लीक वेदा प्रायोग के प्रस्था या सदस्य ना सन्वरंग्य हो तो इसको दुराचार समझा जायेगा, और इस सामार वर उसको परच्या किया जा सकेगा।

सथ लोक सेवा धायोग के सम्यक्ष को, सनुष्टेद २१६ के घनुतार, उसके कार्य-काल के समाय होंगे के पक्षवांस सम या कियो राज्य सरकार के समीन निकी पत्र पर पुन नियुक्त कही विधा वा सकता है। सब कार राज्य कोर को सायोग के सरायों को उनका कार्यकाल समाय्त होने के पक्षवांत्र के सरसारों को नार्यकाल नहीं किया जा सरवा है। परन्तु सम सीक देवा धायोग के सरसारों को नार्यकाल समाया होने पर उनको उपन्य नीकि देवा धायोग के सम्यक्ष के पर नियुक्त किया जा सरवा है। किसी राज्य नीकि सेवा धायोग के सम्यक्ष के पर नियुक्त किया जा सरवा है। किसी राज्य नीकि सेवा धायोग के सम्यक्ष के प्रति का काल के समाय्त होने पर स्थ लोक तेवा धायोग के स्थयक्ष या सदस्य के रूप नियुक्त किया जा सरवा है या उनको किसी ध्यम राज्य नाह देवा धायोग के समस्यों स्थान या सरस्य नियुक्त किया जा सरवा है। राज्य तोक सेवा धायोग के समस्यों पी, उनका नार्यकाल समाय्त होने के पत्रवा हु या लोक देवा धायोग के समस्य या सदस्य के पर पर नियुक्त विधा वा सरवा है। सिवाय इन निर्मुक्तवा के सम सेवा राज्य तोक तेवा धायोगों के सदस्य किसी ध्यम पर पर नियुक्त नहीं निये

सोक सेवा झावीन के कार्य-विकियों तथा क्षेत्रविकारों के विमानन के स्वार एवं सांभी राज्य में, दी प्रकारों की सरकार होती है, केटीय (सांधी सरकार) वार पान्य सरकारों है अपने विमान वालों है समाजन के तिहा दोनों प्रमान के तिहा दोनों प्रमान की सरकारों के तिहा दोनों प्रमान की सरकारों के तिहा दोनों है। प्रमान की सरकारों के तिहा पूर्वक चीक केवाओं की सावस्वत्रका होती है। प्रमादीय तिवारों के सरकारों के तिहा या है। यह निज्ञानुकार है—

स्यापना घरमा आवश्यन है।

१ समीय (केन्द्रीय) लोक सेवाएँ—सपीय लोक सेवाएँ सपीय विषयों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। बुद्ध सपीय विषयों के उदाहरण इस प्रकार है—विदेशी मामले, प्रतिदक्षा, घायकर, डाक तथा तार ब्यवस्था, रेल प्रादि। इन सेवाप्रों से सबित प्रियोग की नियुक्ति, परीनित, प्रतिप्राण, प्रतुवासन, सेवा-निवृत्ति प्रादि से सम्बन्धित प्रमिया समल मामले केन्द्रीय (सपीय) सरकार के नियथण में हैं। पुरुवत इन विषयों के सबय में केन्द्रीय सरकार सप लोक सवा के प्रायाग से कार्य करती है।

२ राज्य लोक सेवाएँ—राज्य लोक सेवाधी को स्वापना का उद्देश्य राज्य से सवधित विषयो का प्रकासन करना है। राज्यों के लेत्राधिकार मे बुद्ध विषयों के उदाहरण निम्नलिदित हैं—राजस्व, ष्टिंग, वन, विका, स्वास्थ्य, पणुपालन, वुलिस प्राधि। इन राज्य-सेवाधों से सवधि अधिकारियों की नियुन्ति, पदीनित, प्रविक्षाल, प्रनुवासन, सेवा निवृत्ति स्राधि समस्त राज्य सरकार के नियमण में हैं। इन विषयों के सवय में राज्य सरकार राज्य-लोक सेवा ध्रायोंग की परामणे से काम करती है।

सधीय (वेश्कीय) यथा राज्य सेवाधी के घ्रतिरिक्त, सविधान मे प्रितिक मारतीय सेवाधी के लिए धनु-चेद ३१२ वे घरगँत प्रावधान विधा गया है। ये प्रतिवन मारतीय सेवाधी के लिए समान रूप से हैं। ये प्रतिवन मारतीय सेवाधी का उदलेत हैं (1) मारतीय प्रावधान सेवाधी का उदलेत हैं (1) मारतीय प्रवासकीय साता प्रतिवा (11) घारतीय पुलिस सेवा। सविधान वे घनु-चेद ३५० (1) के घनु-सात समय प्रतिव मारतीय सेवाधी की स्वापना पर सक्ती है, मिंद वह वे बहमत से यह प्रसाव पारित वरती है कि राष्ट्रीय हिन में ऐसी सेवा की

भारतीय प्रकासकीय सेवा भी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके प्रकि कारी 'सामान्यता-प्रधान' प्रवासकीय अधिकारी होते है प्रवर्षत, उनकी योगदााप्रो तथा सामान्य दक्षना की दृष्टि से उनसे यह प्रपेक्षा की जा सकती है कि वे विभिन्न प्रकार के पदी पर नार्य करने में सक्षम हैं। उदाहरण स्त्ररूप मारतीय प्रशासकीय सेदा के प्रधिकारियों की नियुक्ति कभी कानून व्यवस्था, कभी राजस्व कभी ब्यापार-वाणिज्य, कसी विभिन्न जनकत्वाणकारी शिक्षा मादि में सर्वाधन पदी पर होती है।

मारतीय सविधान के अनुच्छेद ३२० के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के नार्य

निम्नानुसार होगे-र सम तया राज्य लोड मेवा ब्रायोग मय तया राज्यो के प्रयोग विभिन्न

सोक सेवाको म गरनी करने के लिए परीक्षाको का बाबीजन करेंगे। रे दो पा दो से अधिक राज्यों ने अनुरोज पर उनने जिए लोक सेवाफ्री में विशेष योग्यना प्राप्त प्रत्याशियों की मस्ती के लिए सथ लोक सेवा प्रायोग द्वारा

सयुक्त योजनामी का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना । इ. निम्नलिखित विषयो पर सच लोड भेवा बाबोग तया राज्य लोड सेवा

ग्रामीम सम तथा सद्यान राज्य सरकार को सनाह देंथे।

(क) ऐमा कोई भी विषय जो अमैनिक पदो पर समैनिक लोक मैवा में मरती ने निए उनको प्रेपित किया गया हो। 🗻 🔹

(ख) उन मिद्धातो के सबय में जिनके बायार पर नियुक्तियाँ, पदीयति तथा

एक सेवा से अन्य सेवा ने स्थानान्तरण करता है।

(ग) लोक सेवाझो मे अनुशासन-सवयी मामले । (प) सरकारी वर्मवारियों के उन दावों के सबस म जिनके मनुसार उनके

विरद्ध सरनारी नायों ने नरने ने नारण की गई वाननी जारेवाई के पलस्वरूप व्यय बहुन करना पडता है।

(छ) निसी सरकारी कमेंचारी द्वारा असैनिक पद पर कार्य करते हुए यदि तिमी क्षति का शिकार होना पडता है तो सेवा निवृति सबनी उसका दावा ।

भी सेवामी के सबय में ब्रन्य कोई कार्य जो सनद द्वारा सथ लोक नेवा आयोग

भीर राज्य वियान समा द्वारा राज्य शोक सेवा मायोग को सींपा गया है।

धत. सम लीन सेवाओ ने लिए सम लीन सेवा मानीम तथा राज्य लीक सेवाओं ने लिए राज्य लोन सेवा आयोग से सवधित सरकार को मर्झी, नियत्ति.-परोजित, स्थानान्तरेष, अनुशासन, दावों भादि मामलों में परामर्श लेना मान-भ्यक है।

मनुच्छेर २२० वे मनुसार सविधान राष्ट्रपति तथा राज्यपालो को ऐसे नियम बनाने के लिए अधिहत करती है, जिनमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिन

पर सोक संबद आयोग से परामर्थ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह.

ग्रनुच्छेद २२० के प्रनुसार, पिछडे वर्षों, घनुसूचित जातियों के पक्ष में नियुक्तियों या पदी को सुरक्षित करने के लिए लोक सेवा शायोग से परामर्थ तेने की कोई प्रावश्यकता नहीं हैं। परन्तु अनुच्छेद २२० के धन्तर्गत यह आवश्यक है कि इस प्रवार के नियमों को जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जन विषयों को निर्धारित करने में लिए चनाये जाते हैं जिनके सबय म लोक सेवा शायोग से परामर्थ लेना प्रावश्यक नहीं है तो उन्हें सविवत व्यवस्वापिका (सव के लिए सतद तया राज्य के लिए विधान सभा) के समझ रखा जाये। ससद या राज्य विधान समा को ऐसे नियमों म परिवर्तन करने वा पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

सविधान के अनुष्ठेद ३२३ वे अनुसार सम आयोग तथा राज्य आयोग का यह कर्तव्य है कि प्रतिवर्य अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रस्तुत करें जिससे उनको अपने कार्यों का विवरण देना होगा। तरायचात राष्ट्रपति और राज्यपाल तुरत ऐसे प्रतिवेदन को ससद तथा राज्य विधान मडन के समक्ष एक स्मरण लेख के साथ रखेण जिसमें कारणों सहित उन प्रकरणों का उन्हेल होगा, जिन पर लोक सेवा आयोग के सुम्माव स्थीहत नहीं कियें गये।

सोक सेवा ध्रायोग के सबस्यों को स्वतत्रता—सोन सेवाधों में नियुक्ति प्रत्या-धियों की भोग्यताधों के ब्राधार पर हो भी जानी चाहिए, जिसने प्रणासन में स्व-ब्रुता तथा दक्षता प्राप्त को जा सने । यदि प्रवासन म योग्य ध्राधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती है तो प्रणासन म इसने फलस्वरूप उर्रमत हुई शुदियों से समस्त राष्ट्र भी प्रगति श्रवरुद्ध हो सवती है। प्रत्युत, प्रवासकीय प्राधिकारियों की योग्यता के घ्राधार पर अरती, नियुक्ति तथा पदी-ति घादि के लिए एक स्वतन निष्पुत्त तथा गिरुज्यान सस्या का होना ध्रतिप्रावय्यक है जी वाह्य प्रमानों से स्वतन रहकर, निष्पुत्त तथाने कार्यों को कर सकेगी। मारतीय सिंधान निर्माताधों ने इन गुद्दों की दृष्टिकोण से लोक सेवा ध्रायोग के सदस्यों की स्वतन्नता के लिए निम्मलिव्रत प्रावधान किये है।

ी सदस्यों का कार्यवाल सविधान द्वारा निर्धारित है, और किसी सदस्य की

पुन वसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

२ लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य को सिवधान में निर्धारित प्रक्रियानुसार ही पदस्युक किया जा सकता है। अनुस्थेद २१७ (१) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च यायानय को लोन सेवा आयोग के कियो सदस्य के दुराचार के मामले की प्रेषित किये जाने पर यहि सर्वोच्च न्यायानय लीच करने के उपरात राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन देता है जि उक्त सदस्य पर लगाया दुराचार का प्रारोध सत्य है, तो राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा उस सदस्य को पदस्युत कर सकता है।

रे. किसी भी सदस्य के पद से सबधित शतों को उसके कार्यकाल मे उसके पुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है। लोक सेवा झारोग के सदस्यों के वेतन तया मत्ते घीर प्रशासकीय व्यय सचित निधि पर मारित हैं। मतएव सप ग्रीर राज्य लोक सेवा ग्रायोयों के सदस्यों ने बेतन तथा मत्तों के सवध में ससद तया राज्य विचान मडलो मे मतदान नहीं किया जा संगता है।

४ सघ ग्रीर राज्यों के लोक सेवा भाषोंगों के भ्रष्यकों भ्रीर सदस्यों की कुछ ग्रपवादा को छोडकर, पुन उसी पद या किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया

जा सकता है । ये घपवाद निम्नानुसार हैं ।

(क) राज्य सोक सेवा का अध्यक्ष, सब लोक सेवा बायोग के बाध्यक्ष या

सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है !

(स) किसी राज्य लोक सेवा ग्रायोग के सदस्य को मध सोक सेवा ग्रायोग के प्रध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, या उसे उसी या क्षान्य राज्य लोक सेवा आयोग के बध्यल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

(य) संघीय लोक सेवा धायोग के सदस्य को संघ सोक सेवा सामीग मा

किसी राज्य लीक सेवा बायोग का ब्रध्यक्ष नियुक्त किया जा सक्ता है।

श्रीक सेवा भाषोगो डारा अपने कार्यों को निष्पक्षनापूर्वक तथा स्वतनता-पूर्वक करने के लिए सविधान निर्माताओं ने इनके सदस्यों की परिपक्तता पर भी वल दिया । इस कारण उन्हाने सथ स्रोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा प्रायोग के सदस्यों के लेवा निवत होने की ब्रायु क्रमण पसठ और साठ वर्ष निर्घारित की है।

मारत में लोक सेवा प्रायोगों के लिए सुविधान म प्रावधान करने से इनको एक विशेष महस्व प्राप्त हुमा है। इन्सैण्ड तथा प्रमरीका म लोक सेवा प्रापीगी की स्थापना व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून के बाधार पर हुई है। तथापि, भारतीय सविधान मे, लोक सेवा थायोगा के सवय मे कतियय यहत्वपूर्ण झहतींश्रों के स्पष्ट उल्लेख की मनुपरियति म, लोक सेवा आयोग विशेषकर विभिन्न राज्यों में, स्वतंत्रता एव निष्पक्षतापूर्वक नार्यं करने में सफल नहीं हुए हैं। सनिधान म लोव सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यनाओं के सबय म कोई प्रावधान नहीं है। कई राज्य सरकारों ने इसका पूरा लाम लेते हुए, इच्छानुसार लोक सेवा ग्रायोग के सदस्यों की नियुक्ति की। यह ग्रारोप लगाया गया है कि कमी-कभी राजनीतिज्ञों को अपने दल की सेवा करने के लिए सत्तास्ड दल द्वारा पारिसोपक के रूप म, लोक सेवा सायोग के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रतएव यह ग्रावश्यक है कि सवियान में संशोधन करके, लोक सेवा आयोग ने सदस्यों की याग्वता तथा नियुक्ति-प्रणाली पर, कतिपय निश्चित यावचान जोडे जायें ।

# ग्रन्थानुकर्माणका भद्रवर एस० पो० एण्ड श्रीनवासन बार०—'रट्डीज इन इण्डियन डेमोर्रेसी'

प्रक्तेभः बरोविष सी० एव०-'वा स्टीटयूशनल डेनलपमेन्ट इन इण्डिया'

बेनजीं ए० सी०--'दी भेकिंग ब्रापः व वान्स्टीट्यूयन जित्द-२ (ए० मुनर्जी एण्ड वो० वासवसा, १९४८) बेनजीं डी० एन०--'सम ग्रास्पेवट्स ग्राफ द इण्डियस वान्स्टीट्यूयन

(धलाइड पब्लिशसं, बम्बई, १६६४)

(भावसफोडं यूनि० प्रेस, १६५७)

(दी वरडे प्रेस, बलकता, १६६२) बेनजीं डी॰ एन॰—'झवर फण्डामेन्टल राईट्स' (द वहडं प्रेस, कलकता, १६६०) बसु डी॰ डी॰-'वमे-टी झान दि वान्स्टीट्यूबन झाफ इण्डिया, जिल्द--१, २, (एस० सी० सरवार एण्ड सन्स वलकत्ता १६६४) भाग्भरी सी॰ पौ॰--'पविनक एडमिनीस्ट्रेशन' (जय प्रवाशनाय एण्ड वी० १६६०) बाइस लाई जे०-'माडर्न डेमोग्रेसी, जिल्द--- २, (भेगमिलन एण्ड नो, न्यूयार्व १६२६) बाह्स लार्ड जे०-'दि श्रमेरिकन कामनवेत्य, जित्द-१', (मेवमिलन एण्ड को, न्यूयार्क, १८६८) चागना एम॰ सी-'द इनडिविज्युल एण्ड द स्टेट' (एशिया पब्लिशिंग हाऊस, १६५६) कारवित हैं। एस०-द डोक्ट्राइन भाफ ज्यूडिशियल रिस्यू (प्रिन्सटन, १६१४) कार्राधन ई० एस०-'द मोटं मोनर दि नानस्टीट्यूशन' (पिन्सटन, ११३८) दास एस॰ सी॰-'द कान्स्टीट्यूशन भाफ इण्डिया, ए कम्प्रेटिव्ह स्टेडी, (चैतन्य पब्लिशिंग हाउस, मलाहाबाद, १६६०) वपाल एस॰—'दि भान्स्टीट्यूशन धाफ इण्डिया' ~ / (मलाहाबाद ला एजेन्सी, १६६४)

```
( ££8 )
```

रायसी ए॰ थी॰—'ता बाक दि कान्स्टीट्यूयन' (भेकमित्रन एक्ड की, निमिटेट, सन्दन, १६३८)

फाईनर एच०-ध्यौरी एवड प्रेनिटस ब्राफ माटन गर्बनेन्ट

(हेनरी होन्ट एस्ट को॰ न्यूपार्क १६१०)

ताडीतन हो। बार--दिन्द्रवन प्यानिक एट प्यानिक समीवन (हरान्य लामनी इन्टीट्यूट बार पानिटिक्स सादस्य

बहमदाबाद, १६१८)

प्रोत्रपहरूर पो॰ बो॰—'ता तिवर्टी एन्ट सोश्चित्र अस्टिम' (एतिया पश्चितिम होउस बस्वर्ट, १८६४)

यार्नेर के॰ डस्प्यू--पीलिटिक्च साइन्य एक वर्वेपेन्ट

(धमरीकन वृत्त क्यानी, न्यूवार्क, १६३२)

गेरेल धारक सीक-पोलिटिका साइन्य

(द वन्डे प्रेस नमनता, १६१४) स्पेडहित ए०—'दि रिपन्तिक ब्राफ इंग्डिया'

हित ए॰—'दि स्पिन्तक बाफ होन्डवा' (तन्दन, १६११)

(तन्तन, १८९१) ग्रीस्स एव० ग्रार०—'द त्रिटिंग काल्सीट्यूयन'

प्राप्त एच० भारक-- द । बाँडन काल्स्टार्च्यन (बार्व एचेन एट्ट धनदिन सिमि० सन्दर, १६३८)

गुप्ता एम० बी०—'ग्रान्मेंबर्म बारु दि इंडियन सामग्रीर्युक्तन'

(सन्द्रल दुत्र डीपो, क्षताहाबाद, १८६४ एवं १६५६ दोनो) हास्त्रपा औ॰ ए॰—'टिनेमाम साऊ डैमोडेटिस पालिटिस्म एन इंग्डिया'

(सानक पेरेल, बस्बई, १६६६) हुस्सूमनी ए॰ पी॰--'सन प्रोन्नेस्य ब्राफ एडमिनीस्ट्रेटिव सा दल द्रान्डियाँ

हस्मूमनो ए॰ पी॰--'सन प्रोत्नेम्म ब्राफ एडमिनीन्ट्रेटिव सा दन दन्दिया (एनिया प्रतिक्षित हाउन बम्बई, १६६४)

हिशायन उन्लाह एम॰—'ैमीकेमी इन इंटिया एस्ट दि व्यूटिशियल प्रीतेस' (एकिया पब्लिशिम हाउम, बन्दर्स, १८६४)

तेना बी॰ बी॰--'पानियायेन्ट्री वयेटीब इन इंडिया' (माइन्टिस्टि दुव एवेन्सी, वतवसा, १९६६)

(माइन्टाक्त दुर एउन्सा, स्तरता, १९६६) बैनिय सर कार्ड-पानियासेन्ट

(क्वेम्बिज युनिवर्मिटी प्रेम, १६५३)

(क्रेम्बिज युनिक प्रेस १६१६)

जोशी जी० एन०—'ब्रास्पेन्ट्स ब्राफ इण्डियन कान्स्टीट्यूशन ला' (बनिसिटी ब्राफ वम्बई, १९६५)

जोशी जी० एन० - दि बास्टीट्यूशन धाफ इण्डिया

मेकमिलन एण्ड को० १६५२)

कारजी एम० सी० जे०—'वानस्टीट्यूशन श्राफ इण्डिया'

(मेट्रोपोलिटन वुर कम्पनी, देहली १६५८)

कपूर ए० सी०—'सेलेक्ट बान्सटीटयूशन्स'

(बाद एण्ड को० देहली, १६६०)

कश्यव एस॰ सी॰—'दि पालिटियस ब्राफ डिफोरबान' (पज्लिण्ड बण्डर दि मास्पीसिस ब्राफ इन्स्टीट्युट)

लाल ए॰ बी॰—'दि॰ इण्डियन पालियामेन्ट'

(चैतन्य पव्लिशिंग हाउस ग्रलाहाबाद १६५६)

ास्त्री एवं जे॰—'रिवलेवशस्य ग्राम दि वान्स्टीट्यूशन' (मेमचेस्टर युनि प्रेस, १६५१)

सास्की एच० जे०—'ए ग्रामर ग्राफ पालिटिक्स'

(जार्ज एलेन एण्ड धनविन लिमि० लम्दन, १६३०)

लास्की एव० के०-पालियामेन्ट्री गर्वमेन्ट इन इस्लिण्ड'

(जार्ज एलेन एण्ड मनविन लिमि० सन्दन १६३८)

सी सर० एस०—'द गवंभेन्ट शाफ इंग्लैंग्ड' (श्ररकेस्ट वेन शिभि० लन्दन, १९३५)

मैकाईवर भार॰ एम०—'द माडनें स्टेट'

(मानसफोर्ड प्रेस, लन्दन, १६२६)

मे सर्व टी॰ इ॰—'ए॰ ट्रीटीज साम दि ला, प्रिनिलेख, प्रोसिडिंग्ख एण्ड युजेज साफ पालियाभेग्ट'

(बटरवर्थं लन्दन, १२वा सस्करण)

नित नै॰ एस॰—'मान रिपजेन्टेटिव्ह गवर्मेन्ट'

(लागमेन्स ग्रीन एण्ड नो० लन्दन, १६६१) मिस जे० एस०--'श्रान लिवटी'

(बेसिल ब्लेक्बेल, धाक्सफोर्ड, १९४८)

कार्नेनिक बी॰ बी॰—'कीयं जनरल इलेक्शन प्रोक्लेम्स एण्ड पोलिसीज'

(सालवानी पश्लिशिय हाउस, १९६७) मीरिस जोन्स रुल्यु० एव०—'पालियामेन्ट इन इण्डिया'

सायमेन्य ग्रीन एवड की० सन्दन १९५७)

```
5-1982 (111)
               म्पर भार०-- हाऊ विटेन इज गवनंड'
                            (लन्दन, १६३८)
               मशी के॰ एम॰—'दि प्रेसिडेण्ट बण्डर दि इण्डियन कान्सटीट्यूगन'
                              (भारतीय विद्या भवन, बम्बई, १६६३)
               नरसिंह चार के॰ टी॰—'दि क्वीन्टइसेन्स ग्राफ नेहरू'
                                    (जार्ज एलेन एण्ड धनविन, लिमि० लम्दन,
               व्यमेन सिगमण्ड-'मार्डन पोलिटिकल, पार्टीज'
                               (यूनिवसिटी बाफ शिवागी, प्रेस, १६४६)
               पासमर एन॰ डो॰—'दि इण्डियन पोनिटिक्ल सिस्टम'
                                  (जाज एलेन एण्ड धनविन, लन्दन, १६६१)
               पायली एम॰ बी०-'इण्डियाज कान्स्टीटयुशन'
                                  (एशिया पस्तिशित हाउस, बस्वई, १६६२)
               राय के० बी०-'पालियामेन्टी डेमोजेसी घाफ इण्डिया'
                             (दि बल्डं प्रेस, कलकत्ता, ११६०)
श्लेडहिर
               सम्यानम के -- 'टान्सीशन इन इण्डिया'
                             (एशिया पब्लिशिय हाउस, बय्बई, १६६४)
धीव्स ए
               शर्मा एम० पी०-'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ध्यौरी एण्ड प्रेक्टिस'
                               (किताब महल धलाहाबाद, १६६०)
गुप्ता ए
               एम । यो । सर्मा-'दि गर्वमेन्ट प्राफ इण्डियन रिपालिक'
                               (किताव महल, मलाहाबाद, १६६१)
हाल्लपा
                शर्मा एस॰ बार॰—'वि सुत्रिम कोर्ट इन वि इण्डियन कान्स्टीट्यूशन
                                  (राजपाल एण्ड सन्स, देहली, १६५६)
 हस्सूमन
                श्रीनिवासन एन०—'डेमोक्रेटिक गवमेंस्ट इन इण्डिया'
                                 (द वर्ल्ड प्रेस लिमि॰ कलक्ता, १६५४)
 हिदायत
                स्टेबर्ट एम॰—'बिटिश एशीच टू पालिटिक्ल एनेलीसिस'
                             (जार्ब ऐतन एड धनविन लिमि० लम्दन, १६३६)
```

सूरी एस०-१९६२ इलेक्शनस ए पोलिटिक्स एनेलीसिस मुवा पब्लिकेशनस, न्यू देहली, १६६२)

(बाक्सफोर्ड युनिवसिटी प्रेस, लन्दन, १६५६)

टोपे टी॰ के॰—'दि कानसीटयुशन आफ इण्डिया' (पापूलर प्रकाशन, वम्बई, १६६३)

क्टियर के ब्री - 'फेडरल गवर्मेन्ट'

दावसी ।

फाईनर

गाडगिल

गजेरद्रगा

गार्नर है

गेटेल प्र

जेतर व

जैतिक

जे निम्ज

जैनिग्ज

## संदर्भ ग्रिभिलेख तथा मूल स्रोत

ग्राप उण्डिया रिपोर्टर । बारम्टीटवाण्ट ग्रमेम्प्रली डिपेटम १६४६-४६ । हापट कान्स्टीटयुणन आफ इच्डिया

इलेक्सन वसीसन्स रिपोर्ट आन दि पस्ट जनरल इलेक्सन इन इण्टिया, जि॰ १-२ (१९५१-१६५२ न्यू देहली, १६५५)

इस्टीमेट बमेटी (सेन्टन) स्पिट न० २ (१६५०-५१)

इस्टीमेट रमेटी (सेन्टल) स्पिट न० ६. (१६५३ ४४) इस्टीमेड बमेटी (मेन्ट्ल) रिपोर्ट न० २० (१६५७-५६)

इण्डियन देलेब्यान कमीशारम, रिवोर्ट ग्रान द सेकेंग्ड जनग्ल देलेक्यरस इन देण्डिया इन १६४७-४ = देहली

नेहरज स्थीचेत्र, १९५६-१९५७, जित्द-३,

(द पब्तिकेशन डिविजन मिनिस्ट्री खाफ इन्फारमेसन एण्ड

ब्राडरास्टीम मर्बमेन्ट म्राफ इण्डिया १६४८) से गरह फाइप इयर प्लान--डाप्ट ब्राख्ट लाइन, फरपरी, १६५६

सुन्निम बोर्ट रिपार्टस

दि नाम्स्टीट्युसन माप इण्डिया १६६३ दि इण्डियन प्रोविजनल पालियामेण्ड डिवेट्स १६५०-१६५२

इण्डिया बीट्स-ए सीर्स बुक मान इण्डियन इलेक्शन्स. (सम्गादिल-ग्रार चन्दीदास)

डब्ल्यू मोर हाउस, बलार्क एण्ड ब्रार फान्टेरा पापुलर प्रशासन बम्बई १६६=

## सन्दर्भ पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र

ए'सी, प्रतं सी०-मिनिस्ट्रीयल रिसपान्मिनिटीज दि प्रण्डियन रिट्यू, जनवरी, १६६०

वैनर्जो दी॰ एत॰-'पोजिसन ग्राफ द प्रेसिडेण्ट ग्राफ इडिया'

(माडनं रिव्य दिम० १६५०)

चौधरी पी॰ सी॰-"इथिनस एण्ड इलोन्टोरल उमोद्रेसी" (दन सेमानार न० ३० परवरी १६४६) जेना के॰ सी॰-'पोलिटिकन यारोजीशन इन इण्डिया' (दि इण्डियन रिव्यू मिनम्बर १६५६)

डायसी १

काईनर मसाती एम० एल०-'पार्टी पोलिटिवन इन इण्डिया' (दि बाइटल स्वीचेज एण्ड हानगुमेन्टस ग्राफ दि है । जित्द-र गाडगिल

न० १८ जुलाई, १४, १६६२) रेडी एम० के०--'पीलिटिक्न पार्टीज इन इण्डिया'

(दि इण्डियन रिव्यू नवस्पर १६६४)

राजेण्ड्या रोच के॰ बार॰—'इण्डियाज १६५७ इलेक्शन्य-पार इस्टर्न सर्वे, २६, मई १६५०।

सबसेना के व सीव-'विवर दृष्डियन हैमोबेसी सोजिये रिस्ट कार्यसमेन' तार्वर वे (जिल्द ७ मार्च २४, १६६८)

सत्र पी० एन०-'इन दि जरनल स्नाफ पब्लिक एटमिनिस्टेसन' रोटेल घ

(शस्टबर, १६४८)

सोमजी ए॰ एव॰-'मोटीवेशन एण्ड श्रोपेगण्डा' **। लेड**हिर (सेमीनार नं० ३०, फर० ११६२)

बर्मा के०-'मनी एण्ड वोटम' (सेमीनार नं० ३२ फरवरी, १६६२)

ग्रीव्स ए

गुप्ता ए

हस्लिपा हस्सूमन

हिंदायर

जेता वं जैनिक

जैतिग्ज

र्ज निग्र



KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two
weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DIATE	SIGNATURE
}		
		•
	•,	
}		(
}		
ار		1